

कांग्रेस का इतिहास

१८८५—१९३५

२८ दिसम्बर १९३५ को मनाई गई कांग्रेस-स्वर्ण-जयन्ती पर कांग्रेस
द्वारा प्रकाशित तथा डॉ० वी० पट्टाभि सीतारामैया लिखित
History of the Congress
का अनुवाद

भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद की प्रस्तावना सहित

हिन्दी-सम्पादक
श्री हरिभाऊ उपाध्याय

सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली
शाखा : लखनऊ

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री,
नस्त्रा साहित्य मण्डल, दिल्ली

— मस्करण —

दिसम्बर १९३५ २५००
अप्रैल १९३६ • २०००
नवम्बर १९३८ • ३०००

मूल्य
टाई रुपये

मुद्रक
इलाहाबाद का जर्नल प्रेस,
इलाहाबाद

समर्पण
सत्य और अहिंसा के चरणों में

जिनकी भावना ने कांग्रेस का माण्य-सञ्चालन
किया है और जिनके लिए हिन्दुस्तान के
असंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी
अपनी मातृभूमि की मुक्ति के
लिए महान् त्याग और
बलिदान किये हैं ।

लेखक की ओर से

कोई उद्देश निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मैंने नहीं उठाया था। इस वर्ष ग्रीष्म-ऋतु में बेकारी की घड़ियों में कलम-बिसाई करते-करते यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया। बात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे मामले में मुझसे योही एक बात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपति को इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गई। राष्ट्रपति ने यह मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निदर्शक वाक्य दिये हुए हैं उनपर विह्वल-दृष्टि डालने से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी। प्रथम तीस वर्षों के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इसीलिए इस काल की घटनाओं का वर्णन विषय-वार और व्यक्ति-वार किया गया है। हा, पिछले बीस वर्षों का विवरण साल-ब-साल दिया गया है।

भिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धृत नहीं किये गये हैं। क्योंकि ऐसा करते तो पुस्तक का आधा आकार तो योही पूरा हो जाता। लेकिन इसके बिना भी पुस्तक आघातीत रूप में बढी हो गई है। पुस्तक में दोष भी बहुत रह गये हैं। मैं उनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ। योजना और लेखन की ये त्रुटियाँ ऐसी हैं कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो इनमें कुछ कमी तो जरूर की जा सकती थी। परन्तु काम बहुत ही थोड़े समय में करना पड़ा, और जल्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता। फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस पुस्तक को दो बार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और सशोधन के कार्य में जो परिश्रम करना पड़ा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधान-मंत्री आचार्य कृपलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णदास को छापने के लिए सारी सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा है। अतः वे भी देश के धन्यवाद के पात्र हैं।

मछलीपट्टन,
१२ दिसम्बर, १९३५ }

पट्टाभि सीतारामैया

सम्पादक की ओर से

हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रबाबू ने मुझे पत्र-द्वारा सूचित किया था कि डॉ० पट्टाभि सीतारामैया-लिखित कांग्रेस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-संस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित किया जाय; इधर भाई श्री देवदासजी गांधी ने प्रेम-पूर्वक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेवारी मैं खुद लूँ। मेरा कांग्रेस-भक्त हृदय इस आग्रह को भला कैसे टाल सकता था ? जिम्मेवारी ले तो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया तैसे-तैसे बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों से घिरता गया और यदि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए न दौड़ पड़ते, तो दो महीने के अन्दर इतनी बड़ी पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन असम्भव होता। ईश्वर को धन्यवाद है कि अनुवाद समय पर तैयार हो गया है।

अनुवाद को सरल, सुवोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेष्टा की गई है। फिर भी मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समझता कि यह अनुवाद इसमें अपवाद हो सकता है।

मूल अंग्रेजी प्रति थोड़ी-थोड़ी करके मिलती रही है—इसलिए सारी पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ जाने पर अनुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहाँ तक कि अनुवाद का कितना ही अथ छप चुकने पर महासमिति के दफ्तर से कुछ सद्योचन मिले और अभी तक मिलते चले गये, जिनमें से कुछ को तो चिप्पिया लगा-लगाकर भी जोड़ना पड़ा है। समय कम मिलने के कारण मूल की यन्त्र-पुनर्वक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। मैं मानता हूँ कि यदि समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी बन सकती थी और यह अनुवाद भी इससे बढ़कर हो सकता था। इन तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, पुस्तक का अन्तरंग और बहिरंग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है।

पुस्तक के गुण-दोषों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं। यह मेरा काम है भी नहीं। मेरे जिम्मे हिन्दी-संस्करण तैयार करने का कार्य था—वह यदि पाठकों के लिए सन्तोष-जनक निकला तो मैं अपनी जिम्मेवारी से

वरी हुवा । जल्दी के कारण इस सम्करण में जो थुटिया रह गई है उन्हें दूसरे सम्करण में दूर करने का यत्न किया जायगा ।

मैं अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तव्य को समाप्त नहीं कर सकता । सबसे पहले मुझे भाई मुकुटविहारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुल-लालजी असावा का नामोल्लेख करना चाहिए, जिनकी बहुमूल्य सहायता और जी-तोड़ परिश्रम के बिना यह नस्करण किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकता था । इसी तरह भाई रामनारायणजी चौधरी (अध्यक्ष, राजस्थान-हरिजन-नेवक-मध), श्री खनारायणजी अग्रवाल, भाई कृष्णचन्द्रजी विद्यालकार (सम्पादक साप्ताहिक 'अर्जुन') श्री हरिवचन्द्रजी गोयल और भाई शिवचरणलालजी धर्मा से भी समय-समय पर बड़ी सहायता मिली, जिनका कृतज्ञता-पूर्वक उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है ।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इन पुस्तक को नुन्दरता के साथ थोड़े समय में छापने की सुविधा मण्डल को कर दी । वे सब सज्जन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-नस्करण को तैयार करने में सहायता पहुँचाई ।

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-स्मरण, कांग्रेस-माता का यह दूध पाठको के जीवन को पवित्र, तेजस्वी तथा वलिष्ठ बनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की वलिबेदी पर अपने आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा ।

चन्दे-भातरम् !

गांधी-आश्रम
हण्डवी (अजमेर),
१५ दिसम्बर १९३५

हरिभाऊ उपाध्याय

दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांग्रेस के इतिहास का पहला संस्करण किस जल्दी और परिस्थिति में निकाला गया था, यह उसमें बताया जा चुका है । मित्रों की सहायता और ईश्वर की कृपा ने हम उसे समय पर सर्व-साधारण के सामने रख सके, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी । लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी सस्था है कि हमने उसकी

जो ढाई हजार प्रतिपा छपवाई थी वे बहुत कम साबित हुई, और छपते के साथ ही न केवल वे सबही समाप्त हो गई बल्कि बहुत-सी मांग बनी ही रही। उत्सुक पाठकों के तकाजे और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे। इधर जिन-जिनने पुस्तक देखी, छोटे से लेकर बड़े-बड़े तक नै, उसको सब तरह सराहा और हमें जल्दी दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। फलत, लखनऊ-काग्रेस के इस शुभावसर पर, हम उसका दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के सामने पेश करते हैं।

हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको बहुत बारीकी से सशोधित किया जाय, लेकिन काम इतना बड़ा था और समय इतना कम कि वह सम्भव नहीं हुआ। फिर भी श्री हरिमाळजी ने एक बार सारी किताब को दोहरा लिया है और यथावसर कुछ सशोधन भी किये हैं। प्रूफ में तो पहले भी सावधानी रक्खी गई थी, इस बार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायेंगे। हमें आशा है कि जैसे पहला संस्करण हाथो-हाथ बिका था वैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम शीघ्र नये संस्करण को लेकर उपस्थित होंगे।

प्रकाशक

प्रस्तावना

हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोड़े-से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, बम्बई में हुई थी। जो लोग वहां उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहे जा सकें, परन्तु वे सच्चे जन-सेवक। वस, तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन हमेशा इसने शासन के ऐसे प्रजातंत्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेवार हो और जिसमें इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो। इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता और ब्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे उठेंगी और ऐसी सत्थाओं की अस्थापना करेंगे जो सचमुच प्रातिनिधिक हो और जिनसे भारतीय जनता को भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन करने का अधिकार मिले। कांग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस अद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और भाषणों से ही भरा हुआ है। कांग्रेस की जो मार्गें हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्या तो सुधार होने चाहिए और कौनसी आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ बन्द होनी चाहिए, और उन सब का आधार यह आशा ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों की इच्छा का भलीभाँति पता लग जाय तो वे गलतियों को दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत बखशीष दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड में ब्रिटिश-सरकार ने जो कार्रवाइयाँ कीं उनसे यह आशा और विश्वास धीरे-धीरे पर सम्पूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैं। ज्यों-ज्यों हमारी राष्ट्रीय जागृति बढ़ती गई त्यों-त्यों ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया। ब्रिटिश-शासन की सदिच्छाओं पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लॉर्ड कर्जन के, जिन्होंने बंगला को वियक्त कर दिया था, शासनकाल में घक्का लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महान् आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही द्योतक था, जोकि बीसवीं सदी के आरम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से कुछ कम

प्रभावित नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों पर से हमारा विश्वास बिल्कुल उठ नहीं चुका था, इसलिए महायुद्ध के समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि बग-भग रद्द हो जाने से फिर सजीव हो गया था, और कुछ सारी परिस्थिति को अच्छी तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-साम्राज्य के सकट के समय उसे सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत ने इस सकट-काल में जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों ने सराहना की, और भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध प्रत्यक्षत राष्ट्रों के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त तथा प्रजातन्त्री-शासन को सुरक्षित करने के उद्देश से लड़ा जा रहा है उसके फलस्वरूप भारत में भी उत्तरदायी-शासन की स्थापना हो जायगी। १९१७ में ब्रिटिश-सरकार की ओर से भारत-मन्त्री ने जो घोषणा की, जिसमें थोड़ा-थोड़ा करके स्वशासन देने का आश्वासन दिया गया था, उसपर हिन्दुस्तानियों में मतभेद उत्पन्न हुआ, और जैसे-जैसे भारत-मन्त्री व वाइसराय-द्वारा की गई इस सम्बन्धी जाचो का परिणाम और उस बिल का स्वरूप, जोकि आखिर १९२० में भारतीय-शासन-विधान (गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट) बन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतभेद भी उत्तरोत्तर तीव्र होता चला गया। बिल अभी बन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश-सरकार की जीत रही। तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न हो गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चूँकि अब वह दूर हो गई है, हिन्दुस्तान के प्रति उसका रुख बदल गया है और पहले से कहीं खराब हो गया है। खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति विश्वास-घात कहा गया, और (देशव्यापी सर्व-सम्मत विरोध के होते हुए भी) उन बिलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जोकि रौलट-बिलों के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वारा जन-साधारण को स्वतन्त्र नागरिकता के मौलिक अधिकारों से वंचित करनेवाली भारत-रक्षा-विधान की उन कठोर धाराओं को फिर से अमल में लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय ढीला छोड़ दिया गया था, इस भावना को और भी पुष्टि और दृढ़ता मिली। इन बातों से स्वभावतः देशभर में जोरदार हलचल मच गई और दक्षिण-अफ्रीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के छोटा व. चम्पारन जिलों में जिस सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा अन्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य-

वश इस सिलमिले में पञाब और अहमदाबाद में जनता की ओर से कुछ उत्पात हो गये, जिनसे लोगो के जान-भाल का मुकसान हुआ और जालियावाला-वाग-हत्याकाण्ड व पञाब में फौजी शासन के भीषण दृश्य सामने आये। स्वभावतः देशभर में इसमें हलचल मच गई और रोष छा गया। इन दुर्घटनाओ की जाच के लिए हण्टर-कमिटी नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हलचल और रोष को शान्त न कर सकी, उल्टे पार्लमेण्ट में उस रिपोर्ट पर जो बहस हुई उससे वह और भी प्रबल हो गया। तब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ। इसमें एक ओर तो मरकाही उपाधियो के त्याग और सरकारी कौंसिलो, सरकार-द्वारा स्वीकृत शिक्षणालयो, अदालतो तथा विदेशी कपडे के बहिष्कार का कार्यक्रम रखा गया, और दूसरी ओर जगह-जगह कांग्रेस-कमिटियो की स्थापना, कांग्रेस-सदस्यो की भर्ती, सिलक-स्वराज्य-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, राष्ट्रीय शिक्षणालयो की स्थापना, ग्रामवासियो के झगडे निपटाने के लिए पंचायतो की स्थापना तथा हाथ की बनाई-बुनाई को पुनर्जीवित करते हुए क्रमशः सविनय-अवज्ञा और लगान-बन्दी तक पहुँच जाने का कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस-विधान में परिवर्तन करके कांग्रेस का लक्ष्य 'शांतिपूर्ण और उचित उपायो से स्वराज्य-प्राप्ति' रखा गया। इससे देशभर में जागृति की लहर छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-बक्र जारी कर दिया। देखते-देखते १९२१ के अन्त तक हजारो स्त्री-पुरुष, जिनमें देश के कुछ अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता भी थे, जेलखानो में जा पहुँचे। सरकार के साथ समझौते की बातचीत भी चली, पर वह सफल न हुई। मगर इसी बर्षियान युक्त-शान्त के चोरीचोरा स्याम में भयकर उत्पात हो जाने के कारण, बारडोली में करबन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्थगित कर देना पडा। इसके बाद एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी बातें भी स्थगित कर दी गई और कांग्रेसवादी कौंसिलो में प्रविष्ट हुए।

१९२० के शासन-विधान के अमल की जाच के लिए ब्रिटिश-पार्लमेण्ट ने जो कमीशन नियुक्त किया, जोकि साइमन-कमीशन के नाम से मशहूर है, उसमें हिन्दुस्तानियो के न रखे जाने से देश में फिर हलचल मची। तब, अन्य सार्वजनिक सभाओ के साथ मिलकर, कांग्रेस ने सरकार की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का लक्ष्य ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य उपनिवेशो के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रखा गया। लेकिन सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया। तब दिसम्बर १९२९ में, लाहौर के

अपने अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनैतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा तथा कर-बन्दी का आन्दोलन सगठित किया। इंग्लैंड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में एक परिषद् का आयोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए कुछ हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आर्बिनेन्सो-सहित बमनकारी उपाय अस्तियार किये गये। मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉर्ड अर्बिन और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थगित कर दी गई और १९३१ के आखिरी दिनों में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शामिल हुए। लेकिन, जैसा कि बताया था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की शुरुआत में ही कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा। १९३४ में वह फिर स्थगित कर दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों में हजारों स्त्री-मुख्य और बच्चे तक जेलों में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कष्टों को उन्होंने सह्य, और अपनी सम्पत्ति का नुकसान भी बर्दाश्त किया। बहुत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड़ पर चलाई गई गोलियों के कारण, मारे भी गये। सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने सगठन और कष्ट-सहन की अद्भुत शक्ति का परिचय दिया और मारी-से-मारी उत्तेजनाओं के बीच भी, झुल मिलाकर, पूरी तरह अहिंसक ही रहे। कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद कायम रहकर सिद्ध कर दिया कि वह निर्जीव नहीं है और अपने को समयानुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त क्षमता है। यह ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उत्तरा है।

कानूनी के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों को उनके कुछ मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोषण का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतंत्रता में भ्रूषो मरनेवाले करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश हो, और भाषण, सम्मिलन, ज्ञान-माल, धर्म तथा

अन्तरात्मा के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई है। यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी झगड़ों के फैसलों के लिए उपयुक्त सगठन और बुढ़ाये, बीमारी व बेकारी के आर्थिक सकटों से सुरक्षण तथा मजदूर-सब बनाने के उनके अधिकार को कायम रखने के रूप में उनके हितों का खयाल रक्खा जायगा। किसानों को इसने आश्वासन दिया है कि यह लगान-मालगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक जमीनों की लगान-मालगुजारी माफ़ कराकर तथा छोटी-छोटी जमीनों के मालिकों को उस कमी के कारण जो नुकसान होगा उसके हिसाब से उचित और न्याय्य छूट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को हलका करेगी। खेती-बाड़ी से होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने क्रमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही एक निश्चित रकम से अधिक आमदनी-वाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर लगाने, मौज्जी व मुल्की शासन के खर्चों में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनखाह ५००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए कहा है। इसके अलावा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विदेशी कपड़े का वहिष्कार, देशी उद्योग-वन्धों का सुरक्षण, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का निषेध, बड़े-बड़े उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण, कास्तकारों का कर्जदारी से उद्धार, मुद्रा और विनियम की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन और राष्ट्र-रक्षा के लिए नागरिकों को सैनिक शिक्षण देने का निर्देश है।

कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्टूबर १९३४ में बम्बई में हुआ था, कॉंसिल-प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया है और देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रक्खा गया है जिसमें हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन एवं पुनर्जीवन देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी दस्तकारियों (गृह-उद्योगों) की उन्नति करने, आर्थिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से ग्रामीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृश्यता का नाश करने, अन्तर्जातीय एकता की वृद्धि करने, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का सगठन करने और कांग्रेस-सगठन को मजबूत बनाने की बातें भी हैं। कांग्रेस-विधान का संशोधन करके, नये विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर

कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हो उनके अनुपातानुसार कर दी गई है; साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कांग्रेस-कमिटियो के सब निर्वाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने और आदतन खादी पहननेवाले हों ।

इस प्रकार कांग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढ़ती गई है और राष्ट्रीय हलचल के हरेक क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर लिया है । इस समय यह रचनात्मक कार्य में लगी हुई है जिससे न केवल जन-साधारण की माली हालत ही ठीक होगी, बल्कि उसको पूरा करने से उनमें यह आत्म-विश्वास भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी सत्ता के रूप में आरम्भ होकर अब यह इतनी प्रशस्त हो गई है कि सारे देश में इसकी शाखाएँ हैं और देश के सर्व-साधारण का विश्वास इसको प्राप्त है । इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; और इसके कार्यों व इसकी सफलताओं का राष्ट्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ऐसा सगुण है जो हमारे राष्ट्र की एक महान् पाती है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए । स्वतन्त्रता की उस लड़ाई में, जो अभी भी हमें लड़ना बाकी है, निश्चय ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी । यह समय सुस्ताने या विश्राम करने का नहीं है । अभी तो बहुत-सा काम करने को बाकी पड़ा है, जिसके लिए बहुत सन्न के साथ तैयारी करने, लगातार बलिदान करने और अदृष्ट दृष्ट-निश्चय की आवश्यकता है । पूर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम वर्गिण सन्तोष न करेंगे । जाइए, उन सब जाने-बेजाने स्त्री-पुरुष और बच्चों के आगे हम अपना सिर झुकायें, जिन्होंने इसके लिए अपनी जान तक कुरबान कर दी है, तरह-तरह के सकट और अत्याचार सहें हैं, और जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करने के कारण अब भी कष्ट पा रहे हैं ।

साथ ही, कृतज्ञता और सन्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवकों का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने कि इस शक्तिशाली सत्ता का बीजारोपण किया और अपने निस्स्वार्थ परिश्रम एवं अपनी कुरबानियों से इसका पोषण किया । पचास साल पहले जो छोटा-सा बीज बोया गया था वह अब बढ़कर एक मजबूत वटवृक्ष बन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ इस विशाल देश-भर में फैल गई हैं और अब अगणित नर-नारियों की कुरबानियों के रूप में उसमें कलिया फूटी हैं । अब जो लोग बाकी वचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरबानियों से इसका पोषण करें, ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल लें और उनसे भारतवर्ष स्वतन्त्र एवं समृद्ध देश बन जाय ।

आगे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामलों और व्यक्तियों के बारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत है। स्वयं उन्होंने भी, उसकी प्रगति के पिछले हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन वह एक दूर बैठे हुए इतिहासकार नहीं है, जो खाली घटनाओं का ज्यो-का-स्यो उल्लेख करके निर्जीव तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते। उन्होंने तो यह अपनी आँखों देखा है और इसके लिए खुद काम भी किया है। खाली जानकारी से ही उन्होंने काम नहीं किया बल्कि अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया है। अतएव उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं और जो मत व्यक्त किये हैं, वे इनके अपने हैं, उन्हें हर बात में कांग्रेस की कार्य-समिति के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश कर रही है, निष्कर्ष और मत न समझ लेना चाहिए। फिर भी, आशा है, इसमें घटनाओं और तथ्यों का विश्वसनीय उल्लेख है और वर्तमानकालीन इतिहास के विचारार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी।

—राजेन्द्र प्रसाद

१२ दिसम्बर, १९३५]

विषय-सूची

भाग १

सुधारों का युग—१८८५ से १९०५

स्वशासन का युग—१९०६ से १९१६

१—कांग्रेस का जन्म	१
२—१८८५ से १९१५—कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह	२४
३—कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका	६८
४—ब्रिटेन की दमन-नीति व देश में नई जागृति	७८
५—हमारे अंग्रेज हितैषी	८७
६—हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग	९३

भाग २

होमरूल का युग—१९१७ से १९२०

१—फिर मेल की ओर—१९१५	१२५
२—संयुक्त कांग्रेस—१९१६	१३१
३—उत्तरदायी शासन की ओर—१९१७	१३८
४—माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना—१९१८	१५२
५—अहिंसा मूल-रूप में—१९१९	१६३

भाग ३

स्वराज्य का युग—१९२१ से १९२८

१—असहयोग का जन्म—१९२०	१९१
२—असहयोग पूरे खोर में—१९२१	२२०
३—गांधीजी जेल में—१९२२	२४३

४—कौंसिलो के भीतर असहयोग—१९२३	.	२६७
५—कांग्रेस चौराहे पर—१९२४	.	२८०
६—हिस्ता या साक्षा ?—१९२५	..	२९२
७—कौंसिल का मोर्चा—१९२६	३०९
८—कांग्रेस का 'कौंसिल-मोर्चा'—१९२७	..	३१७
९—भावी संग्राम के बीज—१९२८	..	३३०

भाग ४

पूर्ण स्वाधीनता का युग—१९१९ से १९३५

१—तैयारी—१९२९	.	३४६
२—प्राणों की बाजी—१९३०	..	३६८

भाग ५

युद्ध-काल

१—गांधी-अहिंस-समझौता—१९३१	.	४३५
२—समझौते का जंग	..	४७५

भाग ६

पुनर्संगठन-काल

१—जवाबान की ओर	.	५२३
२—संग्राम फिर स्थगित	..	५५७
३—अवसर की खोज में	.	५८८
४—उपसंहार	.	६२६

परिशिष्ट

१—'१९' का आवेदन-पत्र	.	६४९
२—कांग्रेस-लीग-धोखा	..	६५५
३—करीबपुर के प्रस्ताव	.	६६२

४—क्राँदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र . . .	६६५
५—हिन्दुस्तानी मिल्स के घोषणा-पत्रक . . .	६६८
६—जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव . . .	६७१
७—साम्प्रदायिक 'निर्णय' . . .	६९०
८—गांधीजी के आभरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-मैकट . . .	७०५
९—१९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि . . .	७२०
१०—कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मंत्रियों इत्यादि की सूची . . .	७२४

: १ :

कांग्रेस का जन्म

कांग्रेस का इतिहास मच पूछो तो उस लड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है। कई सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ है। उस समय वह जिस गुलामी में फँसा हुआ है उसका आरम्भ भारतवर्ष में एक व्यापारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ है, और उस गुलामी ने देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रयत्न करती चली आ रही है।

पूर्व परिस्थिति

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौरा भारत में कोई भी वर्षों तक रहा। इसी बीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और व्यापारी की जगह अब एक राजसक्ति बन गई। १७७२ के बाद ब्रिटिश-पार्लमेण्ट समय-समय पर उसके कामों की जाच-पड़ताल करने लगी और जब-जब उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब-तब पहले ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जाच कर ली जाती थी। चूँकि उसका व्यापारिक कार्य पीछे पड़ता जा रहा था, यह जाच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होते लगी। परन्तु इससे यह दयाल करना तो ठीक न होगा कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही हो। हा, ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रश्नों का गहुराई के साथ अध्ययन करते थे। वे कम्पनी के कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आखें खोलकर देखा करते थे और उसे पार्लमेण्ट की निगाह से गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चौथे चरण में एडमण्ड बर्क, शेरिडन और फॉक्स नामक सज्जनों ने इस विषय में बड़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्टों के कारनामों की ओर लोगों का ध्यान खिंच गया। हालांकि वारम्ह हेस्टिंग्स पर चलाये गये मुकदमे का

उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को लोगों की निगाह में ला दिया। नया चार्टर देने के पहले जय-अव जाच-पड़ताल की गई तब-तब उसके फल-स्वरूप दूरगामी परिणाम लानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तों का निरूपण तो जरूर किया गया, परन्तु वे सिर्फ कागज में ही लिखे रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की सीमा बढ़ाने की कोशिश न करें, परन्तु हरबार कोई-न-कोई ऐसा मौका आ जाता था या पैदा कर लिया जाता था कि जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढ़ती ही चली गई। यहाँ उस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरफ से भारत को हथियाने समय की गई दगाबाजियों और काली करतूतों से भरा हुआ है, जिसमें क्षुद्र और लोभी मानव प्रकृति ने अपना रंग खूब दिखाया है और जिसमें सन्धिया और शर्तनामे कदम-कदम पर तोड़े गये हैं, और न यहाँ इसी बात की जरूरत है कि हिन्दुस्तानियों ने जो आपस में दगाबाजियाँ और नमकहरामियाँ की हैं उनका वर्णन किया जाय, न कम्पनी के एजेण्टों के द्वारा काम में लाये गये उन साधनों और तबलीरो पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल पर उन्होंने न सिर्फ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरो को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी जेबें भी भर लीं। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने अदृढ़ वन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली, जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूँजी का काम दिया और जिसके बल पर इंग्लैंड, स्टीम एंजिन चलाने में तथा १९ वीं सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्थापित करने में सफल हो सका।

१७७४ में रेग्युलेंटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स (संचालक-सभा) के ऊपर बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सहित एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति हुई। तब गोया ब्रिटिश-पार्लियमेंट ने पहले-पहल हिन्दु-स्तानी इलाकों के शासन की कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। धीरे-धीरे यह नियंत्रण बढ़ता गया और १७८५ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७९३, १८१३, १८३३ और १८५३ में तहकीकात करने के बाद नये चार्टर दिये गये। १८३३ में एक कानून बनाया गया कि "पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के कोई प्रजाजन, जो वहाँ रहते हों, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के कारण कम्पनी में किसी स्थान, पद या नौकरी से वंचित न रह सके जायेंगे" और कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स ने इसको महत्व को इस प्रकार समझाया —

"इस बारा का आशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन

करनेवाली जाति न रहेगी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसौटिया रखी जाये, जाति या धर्म का कोई भेद-भाव नहीं रखा जायगा। बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाति के हों, बेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही वंचित रखे जायेंगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों।”

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उठा दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने आ गई।

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उठ खड़ी हुई। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले अंग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-मदति की नींव पड़ी जो कि भारत में आज तक प्रचलित है।

उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखबार न थे। इनमें भी बाज-बाज अखबारवालों को देश निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखबारों के लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी सर चार्ल्स मेडफोर्ड ने अखबारों पर से पाबन्दिया उठा ली। फिर, लॉर्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी में रहे—सिर्फ १८५७ के गदर के जमाने को छोड़कर।

लॉर्ड डलहौजी की नीति व गदर

१८३३ और ५३ के दरम्यान पंजाब और सिंध जीत लिये गये और लॉर्ड डलहौजी की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बड़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आज तक चला आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासतें जम्मा कर ली तथा अबक की रियासत भी शासन ठीक न होने का सबब बताकर ब्रिटिश भारत में मिला ली। इसके सिवा आधिक शोषण भी जारी था, जिससे लोग दिन-दिन कगाल होते गये। इधर रियासतें छिन गईं और उनकी जगह विदेशी हुकूमत कायम हो गई। यह बात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कूट रहे थे। नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्न किया। हा, इस दगावत में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूँकि एक ओर

दिल्ली के नामधारी सम्राट्, जो कि अकबर और औरंगजेब के वंशज थे, और दूसरी ओर पूना के पेशवाओं के वंशज, इन दोनों के झण्डे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सी वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाएँ घटती रही, उनके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं बल्कि वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृतिक अभिलाषा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों के द्वारा शासित हो, दूसरों के द्वारा हर्गिज नहीं। हालांकि गदर बेकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट इंडिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरकार का शासन-सूत्र सीधा ब्रिटिश ताज अर्थात् ब्रिटिश-पार्लियमेंट के हाथों में आ गया। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जो कुछ अशान्ति बच रही, अब उसका कोई सहारा बाकी नहीं रह गया था। राजा और खास करके नवाब विलकुल तहस-नहस हो चुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह गया था कि जिसके आसपास लोग जमा हो जाते और आगे १८५७ की तरह कोई उत्पात सड़ा कर देते। अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और लोग उसी उदासीन और अलिप्त भाव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है।

ब्रिटिश-पार्लियमेंट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार की गति-विधि पहले की ही तरह जारी रही, हा, एक बात जरूर हुई कि उसका शासन २० साल तक थिला खरजसा जारी रहा। इस बीच कोई युद्ध वगैरा नहीं हुआ।

परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-झगड़ा और कोई अशान्ति भी ही नहीं। ब्रिटिश-शान्त में बड़ी बड़ी सराविया थी जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अंग्रेज अफसर दिखाया भी करते थे और कोसिख भी किया करते थे कि वे दूर हो।

जैना कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन तमाम जगहों पर लेने के काबिल करार दिये गये, जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते थे। १८५३ में, जबकि चार्टर विचाराधीन था, पार्लियमेंट में यह बात खुले आम कही जाती थी कि १८३३ के कानून ने हालांकि भारतवासियों को नौकरिया देने का रास्ता खुला कर दिया है, फिर भी उनको अभी तक वे कोई जगह नहीं दी गई है जो कि इस कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थी। जबकि १८५३ में सिविल सर्विस के लिए प्रतियस्पर्धी परीक्षाएँ जारी की गईं तब इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि उनमें हिन्दुस्तानियों के गस्ते में बड़ी रमावटें पैदा आयेंगी, क्योंकि उनके लिये डब्लैंड में

आकर अंग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में बाजी मार ले जाना असम्भव होगा। और यह भी उन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर बहुत दुर्लभ थी। परन्तु इस बाधा के रहते हुए भी आखिर कुछ हिन्दुस्तानी समुद्र-भार गये ही और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। इतने में ही तकदीर से लॉर्ड सेल्सवरी ने परीक्षा में बैठने की उम्र कम कर दी। इससे हिन्दुस्तानियों को लेने के देने पड़ गये। क्योंकि उधर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान और इंग्लैंड में साथ-साथ परीक्षा ली जाने की पुकार मचा रहे थे, इधर लॉर्ड लिटन ने देशी-भाषा के असवारों का मुह बन्द कर दिया, जो कि मेटकॉफ के समय से लेकर अवतक अंग्रेजी असवारों के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक शस्त्र-कानून भी पास किया, जिसके अनुसार न केवल भारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया बल्कि हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच एक और जहरीला मेद-भाव पैदा कर दिया।

फिर अकालो का भी दौर-दौरा होता रहा। अनाज की कमी उतनी नहीं थी जितने कि उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालों से देश में हजारों-लाखों आदमी काल के गाल हो गये। इसके अलावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसने बड़ा खर्च उठाना पड़ा। इधर तो एक ओर अकाल और मौत का दौर-दौरा हो रहा था, उधर दिल्ली में एक-दरबार करने की तजवीज मुनासिब समझी गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने भारत-सम्राज्ञी की उपाधि धारण की।

ह्यूम साहब की दूर दृष्टि

किसान भी पीड़ित थे। उनके कुछ कण्टो का वर्णन मि० ह्यूम ने सर ऑकलैंड कोलविन को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में किया है। उनकी गहरी शिकायतें ये थी— (अ) दीवानी अदालतें असुविधाजनक और खर्चीली हैं। (आ) पुलिस घूसखोर है और बड़ी ज्यादातिया करती है। (इ) तरीका लगान सस्ता है। (ई) शस्त्र और जंगल कानून का अमल चुमनेवाला है। इसलिये लोगो ने प्रार्थनाये की कि (क) न्याय सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी हो कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका लगान ज्यादा लचीला हो और किसानों के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जंगल के कानूनों का अमल कम सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मजूर नहीं हुई। सन् १८८० की शुरुआत के लगभग दरअसल ऐसी हालत थी। यहा तक कि सर विलियम वेडरबर्न कहते हैं कि नौकर-शाही ने न केवल नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कमर नहीं रखी,

वल्कि जव-जव सीका मिला पिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये, जैसे कि प्रेस की स्वामीनता, सभार्यों करने का अधिकार, म्युनिसिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता। सर विलियम लिखते हैं—“एक तो ये अशुभ और प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन। इससे लॉर्ड लिटन के समय में भारत में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यूम को ठीक मौके पर सूची और उन्होंने इस काम में हाथ डाला।” इतना ही नहीं, वल्कि राजनैतिक अशान्ति अन्दर-ही-अन्दर बढ़ रही है, इसका अकाद्य प्रमाण मि० ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टों की ७ जिल्लें लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर बग़ावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न-भिन्न गुप्तों के कुछ शिक्षों का बर्माचार्यों और महत्तों से जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके आधार पर वे तैयार की गई थी। यह हाल है लॉर्ड लिटन के सासन के अन्त समय का, अर्थात् पिछड़ी सन्धी के ७० से लेकर ८० साल के बीच का। ये रिपोर्टें जिला, तहसील, सब-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई थी और शहर, कस्बे और गाव भी उनमें शामिल थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सुसंगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे, जिससे सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि संभव है “लोग जगह जगह हथियार लेकर टूट पड़ें और जिनसे वे नफरत करते थे उनकी खून-खराबी करने लगे, सेठ-साहूकारों के यहा चोरी और डाके डालने लगे और बाजारों में लूट मार करने लगे।” यो तो ये कार्य सिर्फ कानून की खिलाफतों करनेवाले हैं। परन्तु यदि आवश्यक बल और सङ्गठन का सहारा मिल जाय तो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बग़ावत के रूप में परिणत हो सकते हैं। बम्बई इलाके के दक्षिण प्रान्त में किसानों के ऐसे दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहब ने इस अशान्ति को प्रकट करने का एक सरल उपाय बूढ़ निकाला, जो कि हमारी यह वर्तमान कांग्रेस है। इसी समय उनके विभाग में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय और उन्होंने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक पत्र लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाला था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदमियों की माग की थी जो, भले, सच्चे, नि स्वार्थ, आत्म-सयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हित करने की तीव्र भावना रखनेवाले हों। “यदि सिर्फ ५० भले और सच्चे आदमी स्थापक के रूप में मिल आयें तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है।” और इन लोगों के सामने आदर्श क्या पेश किया गया? यह कि—“सभा का विधान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में परे हों, और उनका यह सिद्धान्त-बचन

हो, कि जो तुममें सबसे बड़ा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो।" पत्र में उन्होंने गोल-मोल बातें नहीं की, बल्कि साफ शब्दों में कह दिया, कि "यदि आप अपना सुख चैन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमुच मौजूदा सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है।"

इस स्मरणीय पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है —

"और यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्बल जीव हैं, या अपनी स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न हैं कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण कार्य नहीं कर सकते, तब कहना होगा कि वे सही और बाजब तौरपर ही दबाकर रखें और पद-बलिष्ठ किये गये हैं, क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक वैसी ही सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य वह होता है। यदि आप, जो देश के चुनीदा लोग हैं, जो बहुत ही उच्च शिक्षा-प्राप्त हैं, अपने सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देश्यों को नहीं छोड़ सकते और अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके देशवासियों को अधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो, वे अपने घर का प्रबन्ध करने में अधिकाधिक हिस्सा लें, तब मानना होगा कि हम, जोकि आपके मित्र हैं, गलती पर हैं, और जो हमारे विरोधी हैं उनका कहना ही सही है, तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके हित के सम्बन्ध में जो उच्च आकाशार्थ हैं, वे निष्फल होंगी और वे बुराई ठहरेंगी, तब कहना होगा कि प्रगति की तमाम आशायें अब नष्ट समझनी चाहिए और हिन्दुस्तान सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है। और यदि यही बात सच है तो फिर न तो आपको इस बात पर मुह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि हम जजीरो में जकड़ दिए गए हैं और हमारे साथ बच्चे-कासा व्यवहार किया जाता है, और न आपको इसके विरोध में कोई बल ही खड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप अपनेको इसी लायक साबित करेंगे। जो मनुष्य होते हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अब से आप इस बात की शिकायत न कीजिएगा कि बड़े-बड़े ओहदों पर आपकी वनिस्वत अग्रेजों को क्यो तरजीह दी जाती है, क्योंकि आपमें वह सार्वजनिक सेवा का भाव नहीं है, वह उच्च प्रकार की परोपकार-भावना नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशो-आराम को छोटा बना देती है, वह देशभक्ति का भाव नहीं है जिसने कि अग्रेजों को वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज हैं। और मैं कहूँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह

तरजीह पाते हैं और उनका लाजिमी तौर पर आपका खासक बन जाना भी ठीक है, बल्कि वे आगे भी आपके अपसर बने रहेंगे, और आपके कन्धों पर रखना यह जुआ तब तक दुखदायी न होगा जबतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं कर लेते और इसके अनुसार चलने की तैयारी नहीं कर लेते कि आत्म-बलिदान और निःस्वार्थता ही सुख और स्वातंत्र्य के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं।”

पहले के महान व्यक्ति और संस्थाएँ

कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफ्तीली बातों का बयान करने के पहले, यदि हम कांग्रेस-काल के पहले के उन बड़े-बूढ़े लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित नहीं होगा, जिनके क्रिया-कलाप ने एक तरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद डाली है।

सबसे पहले बंगाल के ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन का नाम आता है। १८५१ में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह संस्था है जिसके नाम की छाया में डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र और राममोपाल बोस जैसे व्यक्ति बीसो साल तक काम करते रहे। यह एसोसिएशन खुद भी कोई पचास साल तक देश में एक सजीव शक्ति बना रहा। बम्बई में सार्वजनिक कार्य की संस्था थी बाम्ने एसोसियेशन। बंगाल के एसोसिएशन के मुकाबले में वह थोड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी उसी तरह जोर-शोर से किया। उसके नेता थे—सर मंगलदास नाथूभाई और श्री नीरोजी फर्देजी। स्वर्गीय बादाभाई नीरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ ने उसकी स्थापना की थी, परन्तु बाद में पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मदरास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत ‘हिन्दू’ के द्वारा हुई, जिसके कि संस्थापकों में एम० बीर राघवाचार्य, नाननीथ रंगैया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और एन० मुन्नाराय पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूना की सार्वजनिक सभा का जन्म प्रायः उसी समय हुआ जब कि ‘हिन्दू’ का हुआ था और उसके द्वारा राव-बहादुर नुल्लू और श्री चिपलूणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वजनिक कार्य करते रहे।

बंगाल में, १८७६ में, इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण मुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मंत्री थे आनन्दमोहन बसु। यह ध्यान में रखा होगा कि उन कांग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सार्वजनिक जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया था तथापि उमरा अगर अधिकारियों पर होने लगा था। हा, असवार डम जीवन था एक जोरदार हिम्मा था। १८५७ में कोई ४७५ असवार थे, जिनमें

से अधिकांश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्हीं दिनों देश के सुदैव से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सिविल सर्विस से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब और मुक्त-प्रान्त में राजनैतिक यात्रा की। वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्ली दरबार में भी सम्मिलित हुए थे और वहाँ देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे। यह माना जाता है कि उसी दरबार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य-मान्य लोगों को एक जगह एकत्र देखकर ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि एक देश-व्यापी राजनैतिक संगठन बनाया जाय। १८७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बम्बई और मद्रास प्रान्त की यात्रा की, जिसका उद्देश्य यह था कि लॉर्ड सेल्सवरी ने सिविल सर्विस की परीक्षा की उम्र बढ़ाकर जो १९ साल की कर दी थी उसके खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-समा में पेश करने के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय।

लॉर्ड रिपन की सहाजुभूति

इसी समय लॉर्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनके जमाने में (१८७८) बर्नार्डिल्लर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बड़ा खर्चाला दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन का दौर हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह करके, बर्नार्डिल्लर प्रेस एक्ट को रद्द करके, स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ करके और इलवर्ट बिल को उपस्थित करके एक नये युग का आरम्भ किया। यह आखिरी बिल भारत-सरकार के तत्कालीन लॉ मेम्बर मि० इलवर्ट ने १८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर से यह रुकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुकदमे फैसल नहीं कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने विगड़े कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेन्ट-हाउस के मन्त्रियों को मिलाकर वाइसराय को जहाज पर बिठाकर इंग्लैंड भेजने की एक साजिश ही कर डाली। इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था, जिन्होंने यह सकल्प कर लिया था कि यदि सरकार ने इस बिल को आगे बढ़ाया तो वे इस साजिश को कामयाब बना कर छोड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि उसकी विल उसी साल करीब-करीब हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा-जब को ही ऐसा अधिकार रहेगा। अब लॉर्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोगों ने उन्हें हार्दिक

विदाई दी। अंग्रेजों के लिए वह एक ईर्ष्या का विषय हो गई थी, किन्तु उससे बहुतेरे लोगों की आँखें भी खुल गई थी।

राजनीतिक संस्थाएँ

इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो सफलता मिल गई, उससे हिन्दु-स्तानी जाग उठे और उन्होंने बहुत जल्दी इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी आतियों का प्रभुत्व है और वह सदा रहेगा। इसने भारत के तत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्त्व का पाठ पढ़ाया और उन्होंने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलवर्ट-हॉल में एक राज-नैतिक परिषद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्दमोहन बसु दोनों उपस्थित थे। इस सभा में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने आरम्भिक भाषण में खास तौरपर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्ली दरबार ने उनके सामने एक राजनैतिक सन्धा, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमूना पेश किया था। इस विषय में बाबू अम्बिकाचरण मुखसदार ने अपनी 'दी इण्डियन नेशनल इन्सुमुशन' नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है—“परिषद् का दूसरा अद्वितीय था। मेरी आँखों के सामने उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का दृक्चित्र आज भी खड़ा है। जब परिषद् खतम होने लगी तो मानो हरेक आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई रोगनी और एक अद्भुत स्फूर्ति प्राप्त हो रही थी।” इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्गण्ठीय परिषद् हुई जिससे कि, पादरी जान मुर्छों साहब का मत है, अखिल-भारतीय कांग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा मिली। १८८१ में मदरास-महाजन-सभा की स्थापना हुई और मदरास में प्रांतीय परिषद् का अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को महता, तैलंग और तैयबजी की मशहूर मंडली ने मिलकर बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन कायम किया।

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट आलूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसी अखिल-भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो अभी तक एक रहस्य ही है कि अखिल-भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क में निकरी। १८७७ के दरबार या कलकत्ते की अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा थियो-सोफिकल कन्वेंशन का भी नाम इन विषय में लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४ में मदरास में हुआ था। वहाँ १७ आदमियों की एक ज्ञानगी सभा हुई, जिसमें यह कल्पना मौजूद गई। मि० एलेन ऑस्टेवियन ह्यूम ने सivil सचिव से अवसर प्राप्त

करन के बाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी कांग्रेस के जन्म का एक निमित्त बतलाई जाती है। खैर, कोई भी इस कल्पना का मूल उत्पादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो, हम इन नतीजों पर जरूर पहुँचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रही थी और ऐसे सगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० जो० ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदम बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अबतक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पलक फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने आ गई।

राष्ट्रीय स्वरूप

कांग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियाँ और राजनैतिक गुलामी का भाव ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रसिपादन करनेवाली सस्था भी थी।

राजा राममोहन राय

कांग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्षों से, भारत में राष्ट्रीय नव-यौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन यो ठेठ राजा राममोहन राय के काल से लेकर विविध रूपों में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं। उनका वर्णन बड़ा विस्तृत और दृष्टि-बिन्दु व्यापक था। यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धार्मिक अवस्था थी, वही उनके सुधार-कार्यों का मुख्य विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दुःखी हो रहा था, उनका भी उन्हें पूरा भान था और उन्होंने उनको क्षीघ्र मिटाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु क्रिस्टल में १८३३ में। भारत के दो बड़े सुधारों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है—एक तो सती या सहगमन-अथा का मिटाया जाना,

और दूसरा भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, १८२५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ टाइनरेंट में की सिफारिश के खिलाफ दिया, उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खुद पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे एवं तत्कालीन लोकमत पर उनका बड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लैंड गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रबल था कि जब वह 'केप ऑफ गुडहोप' को पहुँचे तो उन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया किनपर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते थे कि उस झण्डे का अभिवादन करें और ज्यों ही उन्हें उस झण्डे के दर्शन हुए उनके मुँह से झण्डे की जय-ध्वनि निकल पड़ी। हालांकि वह इंग्लैंड में मुख्यतः मुगल-सम्राट के राज-भूत बनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की कमिटी के सामने भारतवासियों के कुछ जरूरी कष्ट भी पेश किये। उन्होंने वहाँ तीन निबन्ध उपस्थित किये थे—पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शानन पर, और तीसरा भारत की भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक भोज देकर सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लैमेंट में पेश था, उन्होंने यह प्रश्न किया था कि यदि यह बिल पास न हुआ तो मैं ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूँगा और अमरीका जाकर बस जाऊँगा। अपने समय में ही उन्होंने अखबारों पर और छापेखानों पर हुआ बहुत बुरा दमन देख लिया था। "लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले समय की कड़ी सजावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल सर्विस के एक सदस्य के बोहे समय के लिए गवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरें और वादलों से टकने लगे थे।" फल यह हुआ कि मि० बकिंघम नामक कलकत्ते के एक अखबार के सम्पादक दो महीने की नोटिस देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर बिठा दिया गया। यह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचलित आसन की कुछ बालोचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेस आर्डिनैन्स पास किया गया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों अखबारों पर जबरदस्त सेंसर बिठा दिया गया और पत्र के प्रकाशकों और मालिकों के लिए गवर्नर-जनरल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आर्डिनैन्स, तत्कालीन कानून के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया गया था।

राजा राममोहन राय ने नुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंने

दो वकील अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहाँ कामयाबी न हुई तो इंग्लैंड के वादवाह के नाम एक सार्वजनिक दरस्वास्त भेजी। परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला। लेकिन इस समय जो बीच वह वो चुके थे उनका फल १८३५ में निकला, जब कि सर चार्ल्स मैटकाँफ ने फिर से हिन्दुस्तानी पत्रों को आजाद करा दिया। जिन दिनों वह इंग्लैंड थे उन्ही दिनों सती-अथा के उठाये जाने के खिलाफ की गई अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हें मिल गया था।

अब गदर को लीजिए। यह लॉर्ड डलहौजी की नीति का परिणाम था। उन्हो-ने किसी राजा की विधवाओं को गोव लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जब्त कर ली गई थी। यह तो सबको पता ही है कि गदर दवा दिया गया। उसके बाद १८५८ में, विधवा-विद्यालय कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें भारत में बनाई गईं। गदर के कुछ पहले ही विधवा-विवाह-कानून बना था, जो कि समाज-सुधार की दिशा में एक कदम था। उसके बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ़ता गया। पश्चिमी कानून-संस्थाएँ और पार्लैमेंटरी तरीके बाखिल हुए, जिससे कानून और कौन्सिलो के क्षेत्र में एक नये युग का जन्म हुआ। इधर पश्चिमी सभ्यता का ससर्ग भारत के लोगों के विश्वासों और भावनाओं पर गहरा असर डाले बिना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के अमाने में धार्मिक सुधार के जो बीज बोये गये थे वे थोड़े ही समय में अपनी शाखा-अशाखायें फैलाने लगे। राममोहन राय के बाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिम्मेवारी आ पड़ी। उन्होंने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया और उसके मतों पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होंने मद्यपान-निषेध के आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लैंड के मद्यपान-निषेधको के साथ मिलकर काम करने लगे। १८७२ के 'ब्रह्म मेरेज एक्ट—३' को पास कराने में उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन लोगों को जो ईसाई नहीं थे अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी।

आर्य समाज व प्रार्थना समाज

बंगाल के ब्रह्मसमाज का प्रतिपात सारे भारत में हुआ। पूना में प्रार्थना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू हुआ। यही रानडे समाज-सुधार आन्दोलन के जनक थे, जो बर्षों तक कांग्रेस का एक आनुपंगिक अंग बनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की अज्ञा और प्राचीन परम्पराओं और विषयों के प्रति बग़ावत के भाव भरे हुए थे और इसका

कारण था पश्चिमी सत्स्थाओं का जादू एव उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिष्ठा। अब इसकी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी—सुधार कार्य होना था, क्योंकि इन सुधार-आन्दोलनों के कारण देश में राष्ट्रीयता-विघातक भावनाये फैलने लगी थी। उत्तर-पश्चिम में आर्यसमाज और मद्रास में थियोसोफिकल आन्दोलनों ने इस आवश्यक सुधार का कार्य किया तथा अपने धर्म, आदर्श और सस्कृति से दूर ले जाने वाली स्प्रिट को, जो कि पश्चिमी शिक्षा के कारण पैदा हुई थी, दबा दिया। यों तो ये दोनों आन्दोलन चकट-रूप में राष्ट्रीय थे, फिर भी आर्यसमाज में देशभक्ति के भाव बहुत प्रबल थे। आर्यसमाज वेदों की अपौरुषेयता और वैदिक सस्कृति की श्रेष्ठता का जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हमारी पूर्व-परम्परा और आधुनिक वातावरण दोनों के श्रेष्ठत्व का सामंजस्य था। जिस तरह कि ब्रह्म-समाज ने बहुदेव-वाद, मूर्ति-पूजा और बहुविवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसी तरह आर्यसमाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित दुराद्यों और हिन्दुओं के धार्मिक अन्ध-विश्वासों से लड़ाई लड़ी। यहाँ भी, जैसा कि भय था, आर्यसमाज में दो दल खड़े हुए—एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्थी। गुरुकुल-पन्थी ब्रह्मचर्य और धार्मिक सेवा के वैदिक आदर्शों को मानते थे, और वे जो आधुनिक ढंग की शिक्षा-सत्स्थाओं के द्वारा एक हद तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का संचार करके समाज में नवजीवन डालना चाहते थे, कालेज-पन्थी कहलाये। एक के प्रवर्तक थे अमर शहीद स्वामी अद्भानन्दजी, और दूसरे के थे देश-धीर लाला लाजपत राय। थियोसोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विश्वव्यापी सहानुभूति और अभ्ययन की विशेषता थी, तो भी पूर्वीय सस्कृति में जो कुछ महान् और गौरव-मय है उसके आविष्करण और पुनरुज्जीवन पर उसमें खास जोर दिया जाता था। इसी प्रबल भावना को लेकर श्रीमती बेसेण्ट ने भारत के पुण्य-भूमि काशी में एक कालेज शुरू किया। इस तरह थियोसोफिकल प्रवृत्तियों के द्वारा एक और जहाँ विश्व-बन्धुत्व की भावना बढ़ने लगी तहाँ दूसरी ओर पश्चिम के बुद्धिवाद की श्रेष्ठता का दौरा-दौरा कम हुआ और उसकी जगह सस्कृति का एक नया केंद्र स्थापित हुआ, जहाँ कि फिर से इस प्राचीन भूमि में पश्चिमी देशों के विद्वज्जन खिच-खिंच कर आने लगे।

राष्ट्रीय पुनरुत्थान का अन्तिम स्वरूप जो कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भारतवर्ष में दिखाई दिया, वह है बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस का युग। स्वामी विवेकानन्द इनके पट्ट-शिष्य थे, जिन्होंने इनके उपदेशों का प्रचार पूर्व और पश्चिम

दोनों जगह किया। रामकृष्ण-मिशन न तो कोरे योगसाधकों की और न केवल भौतिक-वादियों की सत्ता है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श रखनेवाली सत्ता है जो कि लोकसंग्रह या समाज-सेवा के महान् कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती। उसने ससार के विभिन्न राष्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को मुलझाने के लिए कृजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलचलें, सब पूछिए तो, भारत की राष्ट्रीयता के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूतों के समान हैं, और भारत का यह कर्तव्य था कि इनमें से एकसा सामंजस्य पैदा करे जिससे कि पूर्व-दूषित विचार और अन्ध-विश्वास दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की सफाई हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और नवीन युग के राष्ट्रधर्म से उसका मेल बैठ सके। कांग्रेस का जन्म इसी महान् कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। अपने ५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमें कहा तक सफल हुई है, इसका विचार हम आगे करेंगे।

पहला अधिवेशन

जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णन ऊपर हो चुका है। मि० ह्यूम का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसिएशन, बम्बई के प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन और मद्रास के महाजन-सभा जैसी प्रांतीय सत्तायें राजनैतिक प्रश्नों की ह्राय में लें और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामाजिक प्रश्नों में ही ह्राय डालें। उन्होंने लॉर्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो कि हाल ही में वाइसराय बन कर आये थे। उन्होंने जो सलाह दी वह उमेशचन्द्र बनर्जी के शब्दों में इस प्रकार है,—

“बहुतों को यह एक नई बात मालूम होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तरह हुआ और जिस तरह वह तब से अवतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लॉर्ड डफरिन का काम था, जब कि वह भारतवर्ष के वाइसराय होकर यहाँ आये थे। १८८४ में मि० ह्यूम के दिमाग में यह खयाल आया कि यदि भारत के प्रधान-प्रधान राजनीतिज्ञ पुरुष साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करें और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें तो इससे, बड़ा लाभ होगा। वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे, क्योंकि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अन्य भागों में राजनीतिक मण्डल थे ही, और उन्होंने यह सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा होकर राजनैतिक विषयों पर चर्चा करने लगेंगे तो इससे उन प्रांतीय सत्ताओं का महत्त्व कम हो जायगा।

वह यह भी चाहते थे कि जिस प्रान्त में यह सभा हो वहा का गवर्नर उसका सभापति हो, जिससे कि सरकारी और गैरसरकारी राजनीतिज्ञों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो। इन खयालों को लेकर वह १८८५ में लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले। लॉर्ड डफरिन ने उनकी बातों को ध्यान से और दिलचस्पी से सुना और कुछ समय के बाद मि० ह्यूम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, कि गवर्नर सभापति बने, उपयोगी न होगी क्योंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं है जो इंग्लैण्ड की तरह यहा सरकार के विरोध का काम करे—हालांकि यहा असवार है और वे लोकमत को प्रदर्शित भी करते हैं, फिर भी उनपर आधार नहीं रखता जा सकता, और अंग्रेज जो हैं, वे जानते ही नहीं कि लोग उनके और उनकी नीति के बारे में क्या खयाल करते हैं। इसलिए ऐसी दशा में यह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित दोनों का हित है, कि यहा के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या-क्या भुटिया है और उसमें क्या-क्या सुधार किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिर न करें। मि० ह्यूम को लॉर्ड डफरिन की यह बलील जैची और जब उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा तो उन्होंने भी लॉर्ड डफरिन की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके भूताविक कार्रवाई भी शुरु कर दी। लॉर्ड डफरिन ने मि० ह्यूम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक मैं इस देश में हूँ तबतक इस सलाह के बारे में मेरा नाम कहीं न लिया जाय। मि० ह्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया।”

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की छुट्टियों में देश के सब भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गई। इन बैठक के लिए एक गस्ती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश नीचे दिया जाता है —

“२५ मे ३१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक परिपद् ली जायगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रदेशों के अगरेजीवाँ प्रतिनिधि, अर्थात् राजनीतिज्ञ, सम्मिलित होंगे।

“इस परिपद् के प्रत्यक्ष उद्देश्य यह होंगे—(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में गोन-बीन में गजनेतिक कार्य अंगीकार किये जायें इसकी चर्चा करके निर्णय करना।

“अतएव अत्र ये सप्त दक्षिण एव सन्ति वा भेदः तां तावत्प्रायश्चित्तं धर्मेण
 और यदि दूसरा कोई सप्त दक्षिण के धर्म का प्रमाण देता है तो मैं इस आक्षेप का
 उत्तर देकर कहूँ कि जिसका नाम दक्षिण है वह वास्तव में दक्षिण नामान्वयियों के बिल्कुल
 समान है। दूसरी दक्षिण के धर्म का प्रमाण है इनके वर्णन पृष्ठा में ही की जाय या
 दक्षिण नामान्वयियों के धर्म का प्रमाण है ये प्रमाण-वचन नामान्वयियों में की जाय।
 तावत्प्रमाण है जिसका धर्म दक्षिण के धर्म का प्रमाण है, मन्त्राय और ब्रह्मण में कोई धर्म-
 धर्म प्रमाण नहीं है और यदि यह प्रमाण-वचन और प्रमाण में।”

इस तरह करने से - 1) पाठ समाप्त होने पर छात्रों ने सुनिश्चित करने का काम साहजिक रूप से हो जाता है कि - 1) पाठ समाप्त होने पर छात्रों ने सुनिश्चित करने का काम साहजिक रूप से हो जाता है कि - 1) पाठ समाप्त होने पर छात्रों ने सुनिश्चित करने का काम साहजिक रूप से हो जाता है कि -

इस पार्श्व अधिष्ठाता ता चण गोपक जंगन बानी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर प्रोडम' नामक पुस्तक में श्रीमती बेनेट ने लिखा है, जिमने नीचे लिखा मश यहा चढा निपा जाता है :-

"नेविन पटना प्रतिनिधन पूना में नहीं हुआ, क्योंकि वड़े दिन के पहले ही पक्षा हैजा शुरू हो गया और पटना छोड़ गमना गया कि पारसगढ़, जिसे अब फारुख कहते हैं, बम्बई में ही जाय। गोमूदरान नेजपाल मन्त्रालय फारुख और छात्रालय के व्यवस्थापका ने जमाने विद्यालय नवन फारुख के आगले हफ्ते दिये और २७ दिसम्बर की सुबह वग भागनीय गच्छ के प्रतिनिधियों के स्वागत करने की पूरी तैयारी हो गई। जो व्यक्ति उस समय वहाँ उपस्थित थे उनकी नामावली पर एक निगाह डालते हैं तो उनमें में निम्न ही आगे पढ़ कर भारत की स्वाधीनता का प्रयत्न करते हुए बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। जो मज्जन प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे उनमें थे सुधारक दीवान-सहायदुर आर० रघुनाथगन, टिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, फ्रीमिल के सदस्य और जज ग्माल कौज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर बम्बई-हार्डकोर्ट के जज हो गये और जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला वैजनाथ, आगरा, जो बाद की एक प्रख्यात विद्वान् और लेखक प्रसिद्ध हुए; और

अध्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल भाडारकर। प्रतिनिधियों में नामी-नामी पत्रों के सम्पादक थे, जैसे—‘ज्ञान-प्रकाश’ जो कि पूना सार्वजनिक-सभा का त्रैमासिक पत्र था, ‘भराठा-केसरी’, ‘नव-विभाकर’, ‘इण्डियन-मिरर’, ‘नसीम’, ‘हिन्दु-स्तानी’, ‘ट्रिब्यून’, ‘इण्डियन-यूनियन’, ‘स्पेक्टेटर’, ‘इन्दु-प्रकाश’, ‘हिन्दू’, ‘त्रेसैंट’। इनके अलावा नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे— ह्यूम साहब, शिमला, उमेशचन्द्र वनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता, बामन सदा-शिव आपटे और गोपाल गणेश आगरकर, पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ, दादामाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग, फिरोजशाह मेहता, बम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशाह एदलजी वाचा, बहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चन्दावरकर, बम्बई, पी० रणया नायडू, प्रेसिडेण्ट महाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आनन्दा चार्णू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, एम० बीर राघवाचार्य, मदरास, पी० केशव पिल्ले, अनन्तपुर। इनमें वे लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए जप चुके, और वे भी थे जो अब भी कायम हैं और उसके लिए यत्नशील हैं।

“२८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ बजे गोकूलदास तेजपाल सस्कृत कालेज के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आवाज सुनाई पड़ी ह्यूम साहब की, माननीय एस० सुब्रह्मण्य ऐयर की और माननीय काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग की। ह्यूम साहब ने श्री उमेश वनर्जी के समापत्तित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था और शेष दोनों सज्जनों ने उनका समर्थन और अनुमोदन। वह एक बड़ा गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा सम्मानित अनेकों व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया।

“कांग्रेस की गुस्ता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस का उद्देश इस तरह बतलाया —

(क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देख-रहित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्टता और मित्रता बढ़ाना।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष सैन्यी-व्यवहार के द्वारा बल, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी तमाम पूर्वदूषित सत्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लॉर्ड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काल में उद्भूत हुई, पोषण और परिवर्तन करना।

(ग) महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित

लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हो उनका प्रामाणिक सग्रह करना।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देश-हित के कार्य करें।”

इस प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मांगों के बनने की शुरुआत होती है। पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की जाच के लिए एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गई। दूसरे के द्वारा इण्डिया कौंसिल को तोड़ देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा बारा-सभा की श्रुटियाँ दिखाई गईं, जिनमें अबतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देने की, युक्तप्रान्त और पंजाब में कौंसिल कायम की जाने की और कामन्स-सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की गई—इस आशय से कि कौंसिलों में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय। चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ हो और परीक्षाधियों की उम्र बढ़ा दी जाय। पाचवा और छठा फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता था और सातवें में अपर वर्गों को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलित करने की तजवीज का विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आवेग किया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जायें। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्डलों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली सशोधनों के बाद वे बड़े उत्साह से पास किये गये। अन्तिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई।

कांग्रेस का दावा

जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार महान् सस्थाओं का आरम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हैं, परन्तु ज्यों ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं त्यो-त्यो उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं त्यो-त्यो उनमें सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी लागू होता है। उसे अपना रास्ता बड़ी-बड़ी बाधाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रखे, परन्तु ज्योंही उसे समस्त भारतवासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने

अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हूल-चलों का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अवस्थाओं में उसके कार्यों में एक विस्म की हिचकिचाहट और अका-कृशकाये दिखाई देती थी, परन्तु जैसे-जैसे वह वालिग होती गई तैसे-तैसे उसे अपने बल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि व्यापक बनती गई। अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मा-बलम्बन की नीति ग्रहण की। इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने लगे, जिससे देशव्यापी संगठन बन गया—यहाँ तक कि सीधे हमले तक का कार्य-क्रम बनाना पड़ा। शिकायतों और अपने दुःख-दर्दों को दूर कराने के उद्देश से शुरुआत करके कांग्रेस देश की एक ऐसी मान्य संस्था के रूप में परिणत हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी भागों को पेश करने लगी। हालांकि शुरुआत के बस-पाच वर्षों में जानल-सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की एक सीमा बनी हुई थी, फिर भी शीघ्र ही वह भारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की एक जबर-दस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक बन गई। उसका दरवाजा सब वर्गों और सब जातियों के लोगों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि शुरुआत में वह उन प्रश्नों को हाथ में लेती हुई मकोच करती थी जो सामाजिक कहे जाते थे, परन्तु उचित समय आते ही उसने इस बात को मानने में इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रश्नों को सामाजिक और राजनैतिक सीमाओं में बाँध देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहाँ से वहाँ तक, एक और अविभाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है, जहाँ नू चिटिख-भारत और देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का। उसमें न उच्च वर्ग या जनता का भेद है, न शहर और गाँव का, और न गरीब-अमीर का भेद है, न किसान-मजदूर का; जात-पात और भेदभाव का भेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधी जी ने दूसरी गोलमेज-परि-षद् के समय फंडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने जो जबरदस्त वक्तृता दी थी और जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अंश नीचे दे देना उचित होगा —

यदि मैं ग़ुलामी नहीं करना हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है। मैंने खन्दार गगन ५० वर्ष की है, और इस अर्थ में वह बिना किसी विरासत के बगल अपने दायित्व अधिदेशन करती ग़ुलामी है। मन्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह ग़ुलामी ग़ुलामी, वर्ग या ज़िन्दी ज़िन्दी हिन की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय

हितो और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे बड़ी गूढ़ों की बात है कि उन्हीं उपज आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओवटेवियन छूम हो कांग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान् पारसियो ने—फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने—जिन्हें सारा भारत 'बृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ से ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे, बल्कि मुझे यो कहना चाहिए कि इसमें सब धर्म, सम्प्रदाय और हितों का खोटी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। स्वर्गीय बदरुद्दीन तैयबजी ने अपने आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और पारसी भी कांग्रेस के सभापति रहे हैं। मैं इस समय फम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री जमेशचन्द्र बनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सीमाव्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को कांग्रेस के साथ एक कर दिया था। मैं, और निस्सन्देह आप भी, अपने बीच श्री के० टी० पाल का अभाव अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, वह अधिकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, फिर भी वह पूरे राष्ट्र-बादी थे।

“जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय श्री० मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी आज यहाँ अभाव है, कांग्रेस के सभापति थे, और इस समय कांग्रेस की कार्य-समिति के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रिया भी हमारी कांग्रेस की अव्यक्त रह चुकी हैं—पहली श्रीमती एनी बेसेण्ट थी और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्य भी हैं, और इस प्रकार जहाँ हमारे यहाँ जाति और मजहब का भेद-भाव नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं है।

“कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में ले रक्खा है। एक समय था जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सामाजिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामों में एक काम बना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी शक्तियाँ समर्पित की थी। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद् के कार्यक्रम में अछूतों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। किन्तु सन् १९२० में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम आगे उठाया और अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को राजनैतिक मध्य का एक आधार-स्तम्भ बनाकर राजनैतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सब जातियों के परस्पर ऐक्य, को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह

स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को दूर करना भी अनिवार्य समझने लगी। सन् १९२० में कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी बनी हुई है, और इस प्रकार कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि महाराजागण भुले आज्ञा देंगे तो मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही कांग्रेस ने उनकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति 'भारत का बुद्ध पितामह' ही था, जिसने काश्मीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया था और मैं अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए कम ऋणी नहीं हैं। अब तक भी उनके धरेलू और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कांग्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस सक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया जाना मैंने आवश्यक समझा, समिति और जो कांग्रेस के दावे में विलचस्पी रखते हैं, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक कांग्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, ७,००,००० गावों में बिखरे हुए करोड़ों मूक, अर्ध-नग्न और मूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है, यह बात गौण है कि ये लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात् देशी-राज्यों के। इसलिए कांग्रेस के मत से प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मूक प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हा, आप समय-समय पर इन विशिष्ट हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं। परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो मैं कांग्रेस की ओर से बिना किसी सकोच के यह बता देना चाहता हूँ कि इन लाखों मूक प्राणियों के हित के लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान कर देगी। इसलिए यह आवश्यक रूप से किसानों की सस्था है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित् इस समिति के भारतीय सदस्यों को भी, यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस ने आज 'अखिल भारतीय चर्खा सघ' नामक अपनी सस्था द्वारा करीब दो हजार गावों की लगभग ५० हजार स्त्रियों को (अब यह संख्या १,८०,००० है) रोजगार में लगा रक्खा है, और इनमें सम्भवतः ५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियाँ हैं। उसमें हजारों अछूत कहानेवाली जातियों की भी हैं। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गावों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,०००

गावों में, प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप कांग्रेस को इन सब गावों में फैली हुई और उन्हें चर्चों का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे।”

कांग्रेस कैसी महान् राष्ट्रीय सरया है, उसका बहुत अच्छा वर्णन सक्षेप में गांधी जी ने किया है। यदि कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया तो कम-से-कम इतना जरूर किया है कि उनमें अपना गन्तव्य स्थान खोज लिया है और राष्ट्र के विचारों और प्रवृत्तियों को एक ही बिन्दु पर लाकर ठहरा दिया है। उसने भारत के करोड़ों निरीह और बेकस लोगों के दिलों में एक जागृति पैदा कर दी है; उनके अन्दर एकता, आशा और आत्म-विश्वास की गजीबनी डाल दी है। कांग्रेस ने भारतवासियों के विचारों और आकांक्षाओं को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिनके द्वारा उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय माहिती को, अपने सर्व-सामान्य धर्मों, कारीगरियों और कलाओं को, महात्मा कि अपनी सर्व-सामान्य आकांक्षाओं और आदर्शों तक को खोज निकाला है। परन्तु यहाँ कहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अबाध और आसानी से नहीं बीते हैं। उसमें कई उतार-चढ़ाव आये हैं। उसमें लोगों की आशा-निराशाएँ, उनके आन्दोलनों और प्रयासों में मिली सफलता-असफलता, सब का इतिहास छिपा हुआ है। इन पक्षों में हम इस तेजस्विनी, बलवती और पुरुषार्थिनी सत्था के जीवन की अर्द्धशताब्दी की घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम की कथा सुनावेंगे; उसके जन्म-दाताओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और पालकों की सेवाओं का स्मरण करेंगे, उसका जीवन-पिण्ड बनते समय जिन-जिन देश-भक्तों ने उसका लालन-पालन किया उनके कार्यों का दिग्दर्शन करावेंगे, अपनी किशोरावस्था में यह जिन उतार-चढ़ावों में से गुजरी है उनका चित्र खीचेंगे, जैसे-जैसे वह जवानों की ओर कदम बढ़ाती गई तैसे-तैसे उसे मिले यश की महत्ता और गौरव का एंव उसे जिन सन्ताप-परिस्थितियों और शर्मिन्दगीयों का भी सामना करना पड़ा उसका परिचय करावेंगे, और उन सब अवस्थाओं का सिद्धान्तलोकन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और आदर्श, विश्वास एवं मान्यताएँ गुजर चुकी हैं और अन्त में जाकर उसने (कांग्रेस ने) तमाम शान्तिमय और उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया है।

कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह

[१८८५—१९१५]

हर एक साल के कांग्रेस-अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इरादा नहीं है। एक-के-बाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि लगभग १९१५ तक कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहा। क्योंकि इसके बाद तो एकदम नई नीति और थोड़े-बहुत भिन्न उपाय काम में लाये जाने लगे हैं। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्त्वपूर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न हिस्सों में बाँटकर हमें क्रमशः विचार करना होगा।

इण्डिया कौंसिल

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-मन्त्री की कौंसिल (इण्डिया कौंसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय। बाद के दो अधिवेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। वसवों अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मन्त्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और १९१३ में कराची-कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन सशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह है —

“इस कांग्रेस की राय है कि भारत-मन्त्री की कौंसिल, इस समय जिस तरह सङ्गठित है, तोड़ दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनर्सङ्गठन किया जाय—

(क) भारत-मन्त्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाय।

(ख) कौंसिल की कार्यक्षमता और स्वतन्त्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उनके कुछ सदस्य नामजद हो और कुछ चुने हुए।

(ग) कौंसिल के सदस्यों की कुल मर्यादा ६ से कम न हो।

(घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कल सख्या के कम-से-कम $\frac{1}{4}$ हो, जो गैर-सरकारी भारतीय हो और बड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुने गये हो।

(ङ) कौंसिल के नामजद सदस्यो में कम-से-कम आवे ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हो जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेष नामजद-सदस्य वे अफसर हो जिन्होंने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक न हुए हो।

(च) कौंसिल सलाहकार हो, शासक नहीं।

(छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पाच वर्ष का हो।”

इसके बाद के कुछ अधिवेशनो में जो सशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है कि अब कौंसिल को तोड़ने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं रही, बल्कि यह भावना है कि अब कि इसके जल्दी तोटे जाने की कोई सम्भावना नहीं है तब इसका कुछ सशोधन ही भले हो जाय। यह कौंसिल निरूपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १९१७ में शासन-सुधारो की जो योजना बनाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा गया है।

वैज्ञानिक परिवर्तन

शुरू से लेकर बहुत समय तक कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, कि उस पर शायद ही कोई ‘गरम’ या ‘अधिनयी’ होने का आरोप लगा सके। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ भागा गया वह यही कि “बड़ी और मीजूदा प्रान्तीय कौंसिलो का सुधार और उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यो की सख्या का अनुपात बड़ा दिया जाय और सयुक्त प्रान्त तथा पंजाब के लिये भी ऐसी कौंसिलो की स्थापना हो। बजट इन कौंसिलो में विचारार्थ पेश किये जाने चाहिए और उनके सदस्यो को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कौंसिलो के बहुमत को रद करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कभी इन कौंसिलो के बहुमत को रद करे तो, उनके (कौंसिलो के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के बाजाब्ला विरोधो को सुनने और उनपर विचार करने के लिए कामन-सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए।” इसका मतलब यह है कि—बाद में जैसे असेम्बली में बहुतायत से देखा गया है—सरकार बहुमत से स्वीकार की गई

गैरसरकारी भागों को अपने 'विशेषाधिकारों' से अस्वीकृत और बहुमत से अस्वीकार की गई गई सरकारी भागों को 'सर्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने लगती है। नौकर-शाही के ऐसे कृत्यों के खिलाफ १८८५ में कांग्रेस ने पार्लेमेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की। इसमें कौंसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था। कहा गया कि प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों का चुनाव तो म्युनिसिपल और लोकल बोर्डों, व्यापार सघों तथा विश्व-विद्यालयों के द्वारा हो और बड़ी कौंसिल का चुनाव प्रान्तीय कौंसिलों के द्वारा हो। यही नहीं, बल्कि सरकार को कौंसिलों के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार देने की बात भी इसमें मान ली गई, बशर्ते कि प्रान्तीय कौंसिलों की अपील भारत-सरकार से और बड़ी कौंसिल की अपील कामन-सभा की स्थायी समिति से करने का अधिकार रहे। अस्वीकृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्य-कारिणी समितियों को अपनी कार्रवाई का जवाब अपील-संस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, १८८८ और १८८९ में भी यही प्रस्ताव दोहराया गया। १८९० में कांग्रेस ने 'इण्डिया, कौंसिल्स एक्ट' में संशोधन करने के श्री चार्ल्स ब्रैंडला के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होंने पार्लेमेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की राय में जिससे काफी मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे। लेकिन यह बिल बाद में छोड़ दिया गया। १८९१ में कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की फिर से ताईद की, कि "जबतक हमारे देश की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होंगे तबतक भारत का शासन सुचारु रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता।" १८९२ में कौंसिलों के सुधार-सम्बन्धी लॉर्डे कौंस का 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास हो गया। तब और बातों को छोड़ कर भारत-सरकार के नियमों और प्रान्तीय सरकारों द्वारा अपनाई हुई, प्रथाओं पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, कांग्रेस ने अपना हमला शुरू किया।

यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि १८९२ के सुधारों में कौंसिलों के लिए प्रतिनिधि चुनने का कोई विधान नहीं था। म्युनिसिपल और लोकल बोर्ड आदि स्थानीय मस्याओं और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कौंसिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त था वह सिर्फ नामजद करने के ही रूप में था। यही नहीं, बल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना न करना सरकार पर ही निर्भर था। परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी।

बन्तुन बात यह थी कि लॉर्ड लैमडोन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी लागू न होने देने की कोशिश की। इस बड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसीके अनुसार की गई थी। उगमे सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कौंसिलो (मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और मुक्तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के लिए रखी गई थी।

१८६२ में कांग्रेस ने 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' को राजभक्ति के भाव से तो स्वीकार किया, परन्तु साथ ही उस बात पर खेद भी प्रकट किया कि "स्वतः उस एक्ट के द्वारा लोगों को कौंसिलो के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है।" १८६३ में एक्ट को धार्य-रूप में परिणत करने की उदार भावना के लिए सरकार को बन्धुवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया कि यदि वास्तविक रूप में उग पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन करने आवश्यक है। साथ ही पञ्जाब में कौंसिल स्थापित करने की माग की भी ताईद की गई। १८६४ और १८६७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८६२ के सत्रोचन से १८६३ में कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १८६५ में कांग्रेस ने प्रश्न-कर्त्ताओं को प्रश्नों के आरम्भ में प्रश्न पूछने का कारण बताने का अधिकार भी देने के लिए कहा, लेकिन आज तक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके बाद १९०४ तक कांग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया। १९०४ में प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-सभा में भेजने और भारत-वर्ष में कौंसिलो का और विस्तार करने एवं आर्थिक मामलों में उन्हें भिन्न मत देने का अधिकार देने की भी माग की गई, हालांकि कौंसिल का निर्णय रद्द करने का अधिकार गवर्नर के मुख्याधिकारी पर ही छोड़ा गया। साथ ही भारत-मन्त्री की कौंसिल में और भारत के प्रान्ती की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया। १९०५ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों पर पुनः जोर दिया और १९०६ में राय ब्राह्मि की कि "ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है वही भारत-वर्ष में भी जारी की जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षाएँ केवल इंग्लैंड में होती हैं वे भारत-वर्ष में और इंग्लैंड में साथ-साथ हो, (ख) भारत-मन्त्री की कौंसिल में तथा बोइसराय और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयों का काफी प्रतिनिधित्व हो, (ग) बड़ी और प्रान्तीय कौंसिलें इस प्रकार बड़ाई जायँ कि उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और देश के आर्थिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों में उनका आर्थिक नियन्त्रण रहे, और (घ) स्थानीय तथा म्युनिसिपल बोर्डों

के अधिकार बढ़ाये जायें।" १९०८ में समय से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य में होने-वाले शासन-सुधारों पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया। उसने प्रस्तावित सुधारों का हार्दिक और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आशा प्रदर्शित की कि उसकी तपस्वीली वार्ते तय करने में भी उसी उदार भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना बनी है। लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बढ़ी थी। प्रतिनिधित्व की बात तो एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १९०६ के शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वीकृत हुए उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले अपने खरीते में प्रदर्शित की थी। इसपर से हमें इसके बाद की उन घटनाओं का स्मरण होता है जो अभी हाल में ही हुई हैं। १९३०-१९३३ की गोलमेज-परिषद ने किस प्रकार लॉर्ड अविन की घोषणाओं का रूप बदल दिया, बाद में गोलमेज-परिषद् की योजना किस प्रकार श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, जिसे क्वाइंट पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन-सुधारों का बिल तो उससे भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून बना वह तो उस बिल से भी बिलकुल गया-गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं।

यह भी जान लेना आवश्यक है कि मार्ले-मिण्टो के नाम पर दस साल तक जिन शासन-सुधारों का दौर-दौरा रहा वे थे क्या? इन सुधारों के अनुसार बनने-वाली बड़ी (सुप्रीम) कौंसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, और बाकी ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियों की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके द्वारा नामजद होते थे जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित सदस्यों में भी बहुत कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाते थे—जैसे सात प्रान्तों में जमीदार-पाच प्रान्तों में मुसलमान, एक प्रान्त में (पर सिर्फ़ बारी-बारी से) मुसलमान जमींदार और दो व्यापार-सब के प्रतिनिधि, इनके बाद जो स्थान बचते उनका चुनाव भी प्रान्तीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होता था। और लॉर्ड मार्ले ने इस बात को बिलकुल छिपाया भी नहीं कि "गवर्नर जनरल की कौंसिल की रचना इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और निर्बाध रूप से अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जो कि वैधानिक रूप में सम्राट की सरकार एवं पार्लियामेंट के प्रति उसका है तथा सदा बना रहना चाहिए।" स्वयं शासन-सुधारों के बारे में लॉर्ड मार्ले का कहना था—"यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-

सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पार्लमेण्टरी (प्रातिनिधिक) शासन-व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, तो कम-से-कम मैं तो इनसे कोई वास्ता नहीं रखूँगा।” लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टेफोर्ड) रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी अधिक असन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण है—“इनसे (मॉर्ले-मिण्टो-सुधार से) भारतीय जनता का सन्तोष नहीं हो रहा है। इनको और जारी रखा गया तो सरकार और भारतीयों (कौंसिल के सदस्यों) के बीच खाई और घड़ेगी और गैर-जिम्मेदाराना टीका-टिप्पणी में वृद्धि होगी।”

इसके पहले कि हम इस विषय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय की घटनाओं को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि धिन्न अधूरा न रह जाय।

मॉर्ले-मिण्टो शासन-सुधारों से इस विषय का दूसरा दरवाजा खुल गया था। इसके अनुसार दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १९०७ में इण्डिया-कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये गये, एक को १९०९ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, और एक-एक भारतवासी १९१० में मदरास बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साल बंगाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गया। बाद को जाकर वह प्रान्त प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया और स-कौंसिल गवर्नर के मातहत हो गया। बिहार-उड़ीसा को मिलाकर, १९१२ में म-कौंसिल लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर के मातहत एक पूयक् प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहा की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।

१९०९ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पाम किये। पहले प्रस्ताव में मजहब के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी जाहिर की गई और (क) एक विशेष मजहब के अनुयायियों को अनुचित रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देने, (ख) निर्वाचकों और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच अन्यायपूर्ण, र्पिस्पद और अपमान-प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कौंसिलों के लिए चले होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विन्तुत, मनमानी और अनुचित अयोग्यताये रखने, (घ) नियम-पत्रों (रेगुलेशन) के आग-तौर पर दक्षिण के प्रति अधिकदास के भावों से भरे होने, तथा (ङ) प्रान्तीय कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों की नया एक प्रकार असन्तोषजनक रखने पर, कि किन्हीं उनके बहुमत का कोई असर ही न हो और वे कोरी बागबानी न कर सकें, सम्बन्ध प्रकट

किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बंगाल, आसाम और ब्रह्म-
देश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थ कार्यकारिणिया बनाने की प्रार्थना की गई।
तीसरे प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जानेवाले शासन-सुधारों को असन्तोष-प्रद
बताते हुए कहा गया कि (क) कौंसिल के सदस्यों की जो सख्या रक्खी गई है वह काफी
नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की सख्या बहुत कम और बिल्कुल नाकाफी है, (ग)
अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो सिद्धान्त रक्खा गया
है वह पंजाब के गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं किया गया है, और (घ)
नियम-मन्त्र जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमली तौर पर पंजाब के
गैर-मुसलमान बड़ी कौंसिल में न पहुँच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार
में कौंसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमींदारों और जिला व म्युनिसिपल
बोर्डों की ओर से बड़ी कौंसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यों के निर्वाचन से बरार
को महत्त्व रखने पर असन्तोष प्रकट किया गया।

१९१० और १९११ में अमली तौर पर कांग्रेस ने शासन-सुधारों-सम्बन्धी
अपनी १९०६ की आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक् निर्वाचन के
सिद्धान्त को म्युनिसिपल व जिला-बोर्डों पर भी लागू कर देने का विरोध किया।

१९१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमिया दूर न की
जाने पर निराशा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा
समस्त प्रान्तीय कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत
लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए सजा पानेवालों को
जिनमें नैतिक दोष न हो, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और
अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार कौंसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय।
पंजाब में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय सत्याजों के लिए भी पृथक् निर्वाचन
लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के शासन-
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि "जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो
जसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।"

सरकारी नौकरियाँ

सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम में
भरहूर हैं, भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्त्व दिया है।

भारतवासियों ने हमेशा यह मतान्तरा किया है कि वे परीक्षाएं इन्ट्रिंस और

भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयों की कुछ तो कठिनाई दूर हो जाय। अपने पहले ही अधिवेशन में कांग्रेस ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षा होने की आवाज उठाई थी।

अब जरा विस्तार से हम इस विषय पर विचार करें। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि पहले-पहल १८८५ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभी से उसने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं दोनों देशों में साथ-साथ होने की माग रखी है, हालांकि वो यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है। यही नहीं, बल्कि १८६१ में इण्डिया-कौंसिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश की थी कि यदि भारत के साथ न्याय करना हो और पार्लियामेंट द्वारा किये गये वादों को पूरा करना हो तो ऐसा करना आवश्यक है।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस सम्बन्धी विस्तृत व्याख्यान तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं भारतवर्ष और इंग्लैंड में साथ-साथ हो और सम्राट के सब प्रजाजन बिना किसी भेदभाव के उसमें भाग ले सकें, योग्यता के अनुसार नियुक्तियों की क्रमागत सूची तैयार की जाय, प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेच्युटरी सिविल सर्विस' बन्द कर दी जाय, परन्तु वे-सनदी नौकरियों तथा उपयुक्त पदों के लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिक्त जितनी नियुक्तियाँ हों वे सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं लेकर की जायें। उस समय प्रचलित प्रथा यह थी, कि कुछ नवयुवकों को चुन कर बस सीपा डिप्टी-कलक्टर बना दिया जाता था। जीबे अधिवेशन तक जाकर कहीं इस सम्बन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलता मिली। सरकारी नौकरियों (पब्लिक सर्विसेज) के कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी गारंटी ने तारीफ की, परन्तु उन्हें अपर्याप्त बताया। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस के इच्छानुसार इण्डियन-सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए बय-मार्गवा १६ से २३ कर दी गई, 'रेजिन्ट इंगरी' तरह से कमीशन की सिफारिशों पर जारी की गई सरकारी आपा ने म्युनि और भी खराब हो गईं। क्योंकि उससे भारतीय उच्चाधिकायियों के लिए दो ही उपाय रह गये—या तो जिस स्थिति में स्टैच्युटरी सर्विस के मानहून वे उस समय में उनी में देने रहें, या प्रान्तीय सर्विस में सम्मिलित हो जायें उनके मदत्यों के लिए मान्य वे मद उच्च पदों पर ताला उल दिया गया था। इन मन्द्य में श्री गोरे ने, गोर ने पावर्ज अधिवेशन में, बहुत विचार कर एक भाग्य दिया था। उन्होंने कहा—“१८८३ के फाब्रुन की भाषा और १८५८ की योजना दोनों स्पष्ट हैं कि जो जो उच्च मान्य

दिये गये आश्वासनों के अनुसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दो में से एक बात, और वह भी बड़े दुःख के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, कि या तो वे भक्कार हूँ या दगा-बाज, उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि इंग्लैण्ड ने जब वे आश्वासन दिये थे तब उसने ईमानदारी से काम नहीं लिया था, या यह कि अब वह हमारे साथ वचन-भंग करने पर आमादा हो गया है।" स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाये होती थी, दूसरे स्टेम्पुटरी सनदी सर्विस भी जिनकी १ नौकरिया १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के लिए रक्षित थी, तीसरे सनदी नौकरिया भी जिनमें भारतीय ही भारतीय थे। १८६२ में कांग्रेस ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत-सरकार के प्रस्ताव पर असन्तोष प्रकट किया और उसके बारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र भेजा। बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१ नौकरियों में १ पद १५८ भारतीयों के लिए रक्षित गये थे, परन्तु पब्लिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिए और भारत-भत्री ने उस 'चाहिए' शब्द को भी बदलकर 'दिये जा सकते हैं' कर दिया। और असलियत तो यह है कि १५८ में से, जो कि भारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से भी सिर्फ ६३ ही १८६२ में भारतीयों को दिये गये।

इसके बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई। भारत-सरकार के इस नम्रन्वी प्रस्ताव की भारत-भत्री ने अपने खरीते द्वारा पुष्टि कर दी। फलतः १८६४ में जाति-भेद के आचार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित सुहर लग गई, क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम-से-कम इतने अयोग्य अफसर तो रहने ही चाहिए। २ जून १८६३ को कामन-भभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-भाव परीक्षाये होने का क्रम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए, उसका इससे तात्मा हो गया। शिक्षा-विभाग की नौकरियों के लिये, जिसमें कि किसी भी ओहदे पर भारतवानी बिल्कुल अयोग्य के नमान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया कि "अविष्य में वे सब भारतवानी, जो कि शिक्षा-विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, आमतौर पर भारतवर्ष में ही और प्रांतीय सदिय में नौकर लयें जायेंगे।" इस प्रस्ताव शिक्षा-विभाग के पुनस्तगठन की योजना में, शिक्षा-विभाग की नौकरियों के सम्मिलित में, भारतवानियों के साथ एक और अन्याय किया गया। भारतवानियों को इस विभाग की ऊँची नौकरियों ने महत्त्व का दिया

गया। शिक्षा-विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में बांट दिया गया— बड़ी अर्थात् आई० ई० एस्० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात् पी० ई० एस्० (प्रान्तीय)। बड़ी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रक्खा गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय बंगाल में उच्चपदस्थ भारतीयों और अंग्रेजों को एक-समान वेतन मिलता था। दोनों का प्रारम्भिक वेतन ५०० रुपये होता था। पर १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३ कर दिया गया और १८८६ में २५० ही रह गया हालांकि भारतवासी थे इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों के ही प्रोफ़ेसर। भारतवासियों के लिए अधिक-से-अधिक वेतन १८६६ में ७०० था, चाहे कितने ही समय की उनकी नौकरियों न हो जाय, परन्तु अंग्रेजों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,००० मिलने लगते थे। नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कॉलेजों के प्रिन्सिपल होने से भी महसूस कर दिया जो अंग्रेजों की पढाई के लिए रक्षित थे। इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाब से नौकरशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लज्ज और नग्न होता गया है।

१८६६ और १८६७ में कांग्रेस ने बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणियों में भारतवासियों को भी स्थान देने की भाग की। सिविल मेडिकल सर्विस (बान्दरी नौकरियों) पर भी इन तथा इनके बाद के वर्षों में ही कुछ ध्यान दिया जाने लगा। १९०० में कांग्रेस ने पी० डब्लू० डी०, रेलवे, अफ़्ग़ान, चुगी (कस्टम) और तार-विभाग की ऊँची नौकरियों पर भारतवासियों के न रखे जाने तथा क़रार के इज़्ज़ीनियरिंग (हिल) कॉलेज से पास-शुदा सिर्फ़ दो ही भारतवासियों को नौकरी के योग्य समार करने के प्रतिबन्ध की निन्दा की।

सैनिक समस्या

इस समय तक, इन तीस वर्षों में, कांग्रेस ने कोई दो सौ विषयों पर विचार किया। इन विषयों में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती रही कि वर्षों तक वह सालाना विषय बना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भी न तो तत्सम्बन्धी शिकायतें दूर हुईं और न उसमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सैनिक-स्वर्च की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, “यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले तो फिर से तट-कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी लोगों पर

लाइसेन्स-टैक्स लगाया जाय जो इस समय इससे बरी है, किन्तु इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि कर निर्धारित करने की निम्नतम सीमा काफ़ी ऊँची हो।” अगले वर्ष इस विना पर भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई क्षतरनाक वक्त आ जाय तो वे (ब्रिटेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तीसरे साल भारत की राजभक्ति और १८५८ की घोषणा में महाराणी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन के आधार पर, सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी खोलने का मतालबा किया गया। इसके लिए कांग्रेस ने देश में सैनिक-कॉलेज की स्थापना करने के लिए कहा। चौबे और पाचवें अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई। छठे में कोई विचार नहीं हुआ, पर सातवें में इस पर चर्चा हुई और सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह ‘भारतीय लोकमत का सम्मान करके भारत-वासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा कर सकें’ मतालबा किया गया कि वह सस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा सशोधन करे कि वे धर्म, जाति या वर्ण के भेद-भाव बगैर सब पर एक-समान लागू हो, साम्राज्य के जिस-जिस भाग में अधिक सैनिक-प्रवृत्ति के लोग हों वहां-वहां अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धति प्रचलित करके उनका संगठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्यालयों (कॉलेज) की स्थापना एवं सैनिक-स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रथा प्रारम्भ की जाय। इन प्रार्थनाओं और विरोधों के होते हुए भी सैनिक-व्यय में उल्टे असाधारण वृद्धि हुई, तब आठवें अधिवेशन में कांग्रेस को यह भाग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हिस्सा इंग्लैण्ड को भी बरदाश्त करना चाहिए। नवें अधिवेशन ने उस विषय के सामाजिक पहलू अर्थात् भारत की फौजी छावनियों में होनेवाली बेक्यावृत्ति एवं छूत की वीमारियों पर विचार किया, और दसवें अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १८६४ में वेल्लिकमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक-व्यय को इंग्लैण्ड और भारतवर्ष के बीच विभक्त करनेवाला था। ग्यारहवें और बारहवें अधिवेशनों में इस सम्बन्धी कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि इस व्यय में इंग्लैण्ड को भी हिस्सा बटाना चाहिए। चौदहवें अधिवेशन ने भी ऐसा ही निष्पत्ति किया। परन्तु पन्द्रहवें अधिवेशन ने इसके एक नये पहलू को स्पर्श किया और कहा, “चूँकि सैनिकों की एक बड़ी मख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाना उचित समझा जाता है, इसलिए इस काम के लिए रखे जानेवाले २०,००० ब्रिटिश-सैनिकों का

सर्व ब्रिटिश-सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए।" सीमाप्रान्त की लड़ाई खतम हो जाने पर, सोलहवें अधिवेशन में, कांग्रेस फिर सैनिक-विद्यालय के प्रश्न पर ही आ पहुँची। १९०२ के सत्रहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने, अपने पन्द्रहवें अधिवेशन के ही आधार पर, सैनिक-व्यय को भारत और इंग्लैंड के बीच विभक्त करने की माग रखी। आखिर १८९४ के वेल्चीकमीशन की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मिली। परन्तु ब्रिटिश-सैनिकों की तनखाहों में ७,८६,००० पाँच सालाना की बढ़ती करके उससे भी ज्यादा भारी नया बोझ भारत के सिर लाद दिया गया। अठारहवें अधिवेशन में इसका विरोध किया गया।

उन्नीसवें अधिवेशन में इस प्रश्न पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया और बताया गया कि १८५९ में सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए कहा गया कि 'देवी बुधमनो से रक्षा करने या सीमा पर के लड़ाकू लोगों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि पूर्व में ब्रिटिश-सत्ता को बनाये रखने के लिए वह बरती जा रही है और भारत की सेना में $\frac{1}{3}$ सख्या ब्रिटिश सैनिकों की है, इसलिए इंग्लैंड को उसके जर्ब में अवश्य हिस्सा बटाना चाहिए।' लॉर्ड कर्जन की सिम्बत पर चढ़ाई करने की उग्र नीति इस समय अमल में आ रही थी। हालांकि १८५८ के कानून में भारतवर्ष का स्वयं भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाहर विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के सिवा दूसरे किसी काम में पार्लमेण्ट की स्वीकृति बगैर खर्च न करने का नियम था, परन्तु लॉर्ड कर्जन ने सिम्बत की चढ़ाई को 'राजनैतिक कार्य' बताकर उसकी भी उपेक्षा कर दी। और अब, १९३५ में, हम देखते हैं कि भारतीय शासन-सुधारों के कानून ने बहुत साल से प्रचलित नियम के इस भग को बायज करार दे दिया है। बीसवें अधिवेशन में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन की इस करतूत का विरोध किया और बताया कि सेना का पुनर्संगठन करने की लॉर्ड किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक करोड़ पाँच का अतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक-व्यय बढ़ते-बढ़ते असहनीय होता जा रहा है। लॉर्ड कर्जन के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के आखिरी दिनों में (१९०५) लॉर्ड किचनर और उनके बीच इस बात पर तीव्र मतभेद हो गया कि सेना पर गैर-फौजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि नियंत्रण रहे और लॉर्ड किचनर इसके सख्त खिलाफ थे।

वनारस के अपने श्वकीसवें अधिवेशन में (१९०५) कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर-फौजी

अर्थात् मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय और एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यहा का सैनिक-व्यय पूर्व में ब्रिटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रखने की ब्रिटिश-नीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सेना पर मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है जब कि कर-दाताओं को उस नियंत्रण पर असर डालने की स्थिति में रक्खा जाय। १९०६ के राष्ट्रीय नव-चैतन्य के समय भी साल-दर-साल सामने आनेवाले इस दुस्साध्य विषय को भुलाया नहीं गया। उसमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि पिछले बीस वर्षों में भारत का सैनिक-व्यय १७ करोड़ से बढ़कर ३२ करोड़ सालाना, अर्थात् करीब दुगुना हो गया है—और यह वह समय है कि जिसके अन्दर भारत में ऐसे सत्या-नाशी दुर्भिक्ष पडे कि जैसे पहले सायद ही कमी हुए हो और कम-से-कम २ करोड़ २२ लाख व्यक्ति भोजन के अभाव में काल के भ्रास हुए।

१९०८ में कांग्रेस ने जोरो के साथ ३०,००० पौण्ड के उस नये भार का विरोध किया जो रोमर-कमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोष पर लाद दिया था, और ब्रिटिश-सरकार से प्रार्थना की कि "इतने दिनों के अनुभव की सहायता से १८५६ की सेना को मिलाने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि इस सम्बन्ध में एक उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोष पर से इस तरह का अनुचित भार उठ जाय।" १९०६ और १९१० में साल-दर-साल बढ़ते जानेवाले सैनिक-व्यय की आलोचना की गई। १९१२ और १९१३ के अधिवेशनों में सेना-विभाग के उच्च पद भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया।

१९१४ में कांग्रेस ने अपनी इस माग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग की ऊँची नौकरिया भारतवासियों को भी मिलनी चाहियें, सैनिक स्कूल-कॉलेज खोले जायें और भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक बनाया जाय। ड्यूक ऑफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किया। लॉर्ड किचनर कहते हैं, भारतीयों को भेजर तक के पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही आशा की गई कि १९११ में सन्नाट इसकी घोषणा कर देगे। वैसे सैनिक-स्वयंसेवक बनने की उन दिनों भारतवासियों के लिए कोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल यह प्रश्न उठा तो श्री एस० वी० शकरम् ने बताया था कि वह सैनिक स्वयंसेवक है। स्वयं श्री वी०

एन० डर्मा भी, जो १९२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक-स्वयमेवक थे। परन्तु १८९८ में भारतीय स्वयमेवक के नाम खारिज कर दिये गये और १९१४ में केवल ईसाइयों को ही स्वयमेवक बनाने का नियम रह गया। इस तरह भारतवासियों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया। लेकिन १९१७ में भारत-वासियों पर से सेना की 'कमीषन्ट' जगह मिलने की वादा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी जगह दी भी गई, जिससे उस अन्याय की आंशिक पूर्ति हुई।

कानून और न्याय

कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊँचे दर्जे के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा है। इस-लिए सर्व-साधारण के कानूनी अधिकारों की ओर स्वभावतः उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक अनुभव और न तीकरशाही दमन, किसी ने भी हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचाया है कि हमारे देश में जो कानून और अदालतें हैं, वे ऐसे हैं कि जैम किनी देश की साधारण दशा में ठूँटा करते हैं और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब लोगों में जागृति होकर उन्हें इनसे प्राप्त होनेवाले अधिकारों का भान होता है, अर्थात् जब देश या जाति की निम्ना समाप्त होकर उसमें राष्ट्रीय चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तब उनके बाहरी रूपों और कार्य-विधियों का खोललापन तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। यही बात उस समय हुई, जब कि मुकदमों में जुरी-द्वारा विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के बाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह बन्दिश लगा दी कि जुरी का मत अन्तिम निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके वरी करने के फैसलों को रद्द कर सकेंगे। दूसरी ही कांग्रेस में (कलकत्ता, १८८६) इस बन्दिश को हानिकारक बताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा गया। साथ ही न्याय-प्रथा में प्रस्तावित अन्य उत्पत्ति-विरोधी फेरफारों का भी विरोध किया गया। इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, लेकिन नतीजा आज तक भी कुछ नहीं निकला।

जुरी के अधिकारों का प्रश्न तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता घासन और न्याय-कार्यों के पृथक्करण की थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों कार्य रहने से वही तो शासक होता है और वही निर्णायक—वही मुकदमा चलाता है और वही जुरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न बन जाता है।

ब्रिटिश-भारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के समय

शुल्क हुआ, जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विषय में भी एक आवेदनपत्र पार्लमेण्ट में पेश किया था और एक पार्लमेण्टरी कमिटी में गवाही देने के वाद अम्मी वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड में ही जिनकी मृत्यु हुई। इस सम्बन्धी इतिहास से यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं कर सकते। और तो और पर गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन, भारत-मन्त्री, लॉर्ड क्रॉस तथा लॉर्ड किम्बरली, और भारत-सरकार के होम मेम्बर सर हार्बर्ट एडम्सन ने भी मुस्तलिफ समयों में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात् न्याय और शासन-कार्यों को एक दूसरे से पृथक् करने) का औचित्य स्वीकार किया है; और सर हार्बर्ट एडम्सन ने तो सरकार की ओर से १९०८ में यह वादा भी किया था कि परोक्षा के तौर पर यह आजमाया जायगा। लेकिन अबतक भी न्याय और शासन-कार्य सम्मिलित रूप में एक ही अफसर के सुपुर्द हैं। राजा राममोहन राय के वाद उत्साही कार्यकर्ताओं के एक दल ने, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी मन्ने प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया; और इसके लिए बंगाल, बम्बई व मदरास में मध्व बनाये गये, जिनमें बनीय राष्ट्र-मंडल खास तौर पर उल्लेखनीय है। शिक्षा-प्रचार के माध्यम-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर बढ़ा, और १८८५ में कांग्रेस ने इस प्रश्न को अपने हाथ में ले लिया।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और न्याय-कार्यों का शीघ्र एक-दूसरे से पृथक् होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा करने में रुचि बटाना पड़ता हो तो भी इसमें देरी न की जाय। अगले साल यह विषय और जूरी-प्रथा का प्रश्न, दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि एक सर्वाधीन प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेश हो जायगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८९३ में तो यहाँ तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यों का सम्मिश्रण "भारतवर्ष के ब्रिटिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश-भर के समस्त जाति और समाजवाले लोगों को बेहद तकलीफ उठानी पड़ती है।" यही नहीं, "किसी दूसरे जरिये की आशा न देखकर, न अत्रापूर्वक भारत-मन्त्री से प्रार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें।" मला कांग्रेस कितनी शोली-शाली थी, अथवा कहना चाहिए कि आपे ने बाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार करने को ही तैयार नहीं थी, उससे भी यह आशा की कि वह उस सुधार-सम्बन्धी विन्तुत योजना को तैयार करने के लिये कमिटी बनायेगी! इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी

धून्यता अनुभव करने लग गये थे और उनकी आँखों के सामने कैसा अँधेरा छा गया था। १९०८ तक कोई अमली तरक्की नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि बंगाल प्रान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है—लेकिन, बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया, 'क्योंकि अमली कार्रवाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई।' इसके बाद लगातार दो अधिवेशनों में इसी निराशा का राग अलापा गया।

जरी के अधिकार कम करने और न्याय व शासन-कार्य सम्मिलित रखने के पुराने वाद अभी हरे ही थे और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, कि १८९७ में एक नया वाद और फर दिया गया। १८९८ का तीसरा रेग्युलेशन (बंगाल), १८९९ का दूसरा रेग्युलेशन (मयरास) और १८९७ का पञ्चीसवाँ रेग्युलेशन (बम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश में आये, जिनके मातहत हर किसी को मुकदमा चलाये और ही जलावतन किया जा सकता था। सरदार नाटू-बन्धुजी पर इस शास्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८९७ के कांग्रेस-अधिवेशन होने के वक्त ५ महीने से अधिक समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखकर दग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनको बैसा नोटिस भी नहीं दिया गया था जो कि इन रेग्युलेशनों के मातहत भी देना जरूरी था।

१८९७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे हुए नहीं थे। पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहें फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) धाराओं में ऐसा सखोशन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गईं। कांग्रेस ने सर्वसाधारण के अधिकारों पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत् विरोध किया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी विशेष शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था —

“अंग्रेजों ने अपने लिए मैग्नाचार्ट और हैवियस कार्पस प्राप्त किये हैं। इनके द्वारा उन्हें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे सिद्धान्त-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित हैं। पर मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा भी पैदायशी हक है। हम, ब्रिटिश-प्रजा हैं, इसलिए! ब्रिटिश-प्रजाजनो! को! जो विशेषाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार हैं। इन अधिकारों को हमसे कीन छीन सकता है? हमने निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी, आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेंगे। इस समा-भवन से निकल

कर उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता में फैलेगी कि हम इस बात के लिए तैयार हैं, इस बात पर जोर देने में हम किसी भी वैध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छत्र-छाया में ब्रिटिश-प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वही अधिकार हैं जो अन्य ब्रिटिश प्रजाजनो के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।”

दायमी बन्दोबस्त, आवियाना, गरीबी और अकाल

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है, इसलिए यह स्वामाधिक ही है कि कांग्रेस ने सबसे पहले नहीं तो भी अपनी शुरुआत में ही थोड़े-थोड़े समय के लिए होनेवाले जमीन के बन्दोबस्त पर ध्यान दिया, जिसमें सबा लगान-बृद्धि होती रहने से रैयत को बड़ी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में (१८८८) होनेवाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी (स्टैंडिंग) समिति को यह काम सौंपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८९ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। १८८९ में बाबू बैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने दायमी बन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-भर में भी १८६२ के अपने तरीके में मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी तो लगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से भी बढ़ जाती है जैसा कि मि० (बाद में सर) ऑकलैण्ड कॉल्विन के सामने आये एक मामले से मालूम पड़ता है। डॉ० बेसेण्ट ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी यह मनो-रजक उदाहरण दिया है :—

“वर्तन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था, परन्तु अब उसमें पानी निकलने के एक की जगह छ छेद हो गये हैं।

“हमारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की और उनकी तन्दुरुस्ती के लिए आवश्यक नमक की भी बहुतायत है, परन्तु अब जंगलात के बहुकसे ने सारी जमीन पर कब्जा कर-लिया है, जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहे और यदि मूखो मरते पशु चारे की जगह अनाज के खेत में भटक कर खले जाते हैं तो उन्हें काजीहाउस में बन्द करके हम पर जुर्माना किया जाता है।”

“अपने मकानों, हलो तथा हर तरह के खेती के सभी कामों के लिए हमारे पास लकड़ी की बहुतायत है, लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा हुआ है। जहां हमने उसे बिला इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी गिकंजे में आये

नहीं। अब तो हमें एक भी लकड़ी चाहिए तो उसके लिए हफ्ते-भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जगह खर्च-ही-खर्च करना होगा, तब कहीं जाकर वह मिलेगी।

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुँचानेवाले जंगली जानवरों को हम मार या भगा सकते थे, पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विधान है, जो विदेशों से यहाँ आनेवाले एक हथ्थी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसानों को अपने गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत है उन्हें कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता।”

१८६२ में कांग्रेस ने लगान को मिश्रित और स्थायी करने के लिए कहा, “जिसमें कि देश की कृषि को उन्नत करने के लिए पूँजीपति और मजदूर मिलकर काम कर सकें,” और कृषि-सम्बन्धी बैंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल भारत-मंत्री द्वारा दिये गये उन वचनों की पूर्ति करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने अपने १८६२ और १८६५ के पत्रों में दायमी बन्दोबस्त के लिए दिये थे। १८६९ में कांग्रेस ने अपने कल को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा बन्दोबस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फामला तो रखा ही जाय—अर्थात्, मियादी बन्दोबस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। २२ दिसम्बर १९०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृषि-विभाग के द्वारा, इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके चौथे पैरेग्राफ पर प्रकट किये गये भारतीय सरकारों के विचार प्रकाशित करने के लिए कांग्रेस ने कहा। १९०३ में कांग्रेस इससे भी आगे बढ़ी और लगान अधिक न लगाया जाय, इसके लिए कानूनी व अदालती रकावटें लगाने के लिए कहा। १९०६ में कांग्रेस ने लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन की नीति से, जो उन्होंने क्रमशः १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में प्रतिपादित की थी, १९०२ में एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित लॉर्ड कर्जन की नीति की तुलना करके दोनों को परस्पर-विरोधी बताया और इस विचार का विरोध किया कि भारतवर्ष में जमीन का लगान ‘कर’ नहीं बल्कि ‘किराया’ है। १९०८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश होकर अपने आप कांग्रेस ने इस विषय को छोड़ दिया।

१८६६ के दुर्भाग्य की परिस्थिति के कारण कांग्रेस को सरकार की आर्थिक नीति का सिंहावलोकन करना पड़ा। उसने सरकार पर अन्धाधुन्ध सैनिक-व्यय करने

का बोप लगाया और दुमिस्को को, उस खर्च की पूर्ति के लिए, लोगो पर लगाये जाने-वाले अत्यधिक कर और भारी लगान का बाइस बतलाया। दूसरा कारण सरकार की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-धंधो का प्रायः नष्ट हो जाना बतलाया गया। सरकार से कहा गया कि वह अकालरक्षक कोष बनाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी बन्दोबस्त और कृषि सम्बन्धी बैंको तथा कला-कौशल-सम्बन्धी स्कूलो की स्थापना को गरीबी दूर करने का असली उपाय बतलाया गया। इसके बाद ही एक अकाल-कमीशन बँठाया गया। इसी बीच अकाल-पीडितों की सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुई उदारतापूर्ण रकमों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए कांग्रेस ने १,००० पाउण्ड की रकम लन्दन के लॉर्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक बना दें। यह १८६८ की बात है। लेकिन ऐसा करते हुए, कांग्रेस ने उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रही थी, और १८६६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्यो की उत्थति की जाय, और जमीन का लगान तथा दूसरे करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की माँग पेश की गई कि भारत-वासियों की आर्थिक अवस्था की जाच कराई जाय। इसके बाद के अधिवेशनों में हम इस विषय पर और कुछ नहीं पाते हैं, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था।

कानून जंगलात

जंगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझा है। उनका मुकाबला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगो पर असह्य बोझ डाल दिया। जैसा कि १८६१ के नागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर पिल्ले ने बताया था, कलम की एक ही रण्ड में सरकार ने दैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके ग्रामीण समाज-व्यवस्था में उलट-मलट कर दी। जैसा कि डॉ० वेंसेण्ट ने कहा, इस बात में सन्देह की बहुत कम गुणाइश है कि देहातियों को ब्रिटिश-शासन के वसिलफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने नहीं। एक उत्तरी आर्काट के ह्री जिले में, १८६१ में, नौ महीने के अन्दर ३,००,००० पशु मर गये। दैयत को प्रकृति के द्वारा मिलनेवाली सर्वोत्तम सौगर्त उनके द्वारा

उनसे छिन गई। “आपकी जमीन है तो पहाड़ी पर, पर आप वहाँ के झाड़-झड़ूको—जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते—यहाँ तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तियाँ तक आप की नहीं हैं।”

१८६२-६३ में बड़ी नम्रता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात के कानूनों से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं—खासकर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में—उनकी जाय करवाई जाय। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये थे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नवें अधिवेशन में प० मेघनराम ने उन्हें ‘अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य सरकार के लिए कलक-रूप’ बतलाया। इनके अनुसार अगर कहीं आग लग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिक हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेवार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काबिज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो उसने जान-बूझकर कानून की परवाह न की हो। जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों पर पैदा होनेवाली बास और लकड़ी ही सब-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का वारोमदार था, उनके लिए उसे छेने की मनाही कर दी गई। यहाँ तक कि जंगल में तापने के लिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्टूबर १८६४ को भारत-सरकार ने न० २२ एफ का एक गश्ती प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें जंगलों के प्रवच में रैयतों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रश्नों को कम महत्त्व देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था।

इसपर कांग्रेस ने, अपने दसवें अधिवेशन में, आप्रह किया कि “तीसरे और चौथे वर्ग के जंगलों में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजें, मकान और खेती के औजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जंगली चीजें आदि—उचित प्रतिबन्धों के साथ—दूर हालत में मुफ्त दी जायें, और जंगलों की सीमारें इस तरह निश्चित की जायें कि जिसमें किसानों को इस महकमे के कर्मचारियों से तग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों के उपभोग करने की छूट रहे।” ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया कि जंगलात के कानूनों का उद्देश जंगलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं बल्कि किसानों और उनके पशुओं के लिए उन्हें रक्षित रखना है। लेकिन १८६९ के बाद के अधिवेशनों में, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सिर्फ एक बड़ा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था।

वात असल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के तो लोग आदी ही हो चके थे, उनके अलावा जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, फिर बीसवीं सदी की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकार की थी। अलावा इसके, बोवर-युद्ध और रूस-जापान की लड़ाई ने भी अवश्य ही कांग्रेसवालों के दृष्टिकोण को बदला और जगलात व आबियाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकर्षित कर दिया।

व्यापार और उद्योग

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्याएँ हैं, उनके खास-खास मुद्दों को कांग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञों ने भली-भाँति समझ तो लिया था, परन्तु वे समस्याएँ ऐसी थी कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था। यह बात वे जान गये थे कि लकाशायर के मुकाबले में भारतीय हित छोटे और गौण समझे जाते थे; साथ ही यह बात भी उन्होंने बखूबी जान ली थी कि ग्रामीण दस्त-कारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और खापर्डे के साथ लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे, बम्बई में हुए कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन (१९०४) में इस विषय पर मि० आर्थर वालफोर के आयलैंड पर दिये एक भाषण का नीचे लिखा अंश उद्धृत किया था —

“एक-के-बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोट दिया गया, या उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इंग्लैण्डवालों के हित में उसे नियंत्रित कर दिया गया, और जबतक कि सम्पत्ति के तमाम स्रोतों को सीमेंट लगाकर बन्द नहीं कर दिया गया और सारा राष्ट्र खेतों के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तबतक यही क्रम जारी रहा।”

इसने अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण यह जवाब है जो मुसलमानी-राज में ब्रिटिश-राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था—“रक्षा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से तो अंग्रेजी राज्य अच्छा है, मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज में मुसलमानी-राज्य हमसे अच्छा था, क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन गये थे जिन्होंने हिन्दुस्तान की दीन्त हिन्दुस्तान में ही रही, लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ का घन देश में बाहर ले जाने हैं।” यही बात कांग्रेस के नवें अधिवेशन में, राजा

रामपालसिंह ने अपने मजाकिया ढंग पर, इस प्रकार कही थी, कि “अंग्रेज सिविलियनो ने तो हिन्दुस्तान को मौज-मजा करने का अपना शिकारगाह बना रक्खा है।”

१८६४ में कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “इस कर का निवचय करते वक्त लकाशायर के हितों के सामने भारतीय हितों का बलिदान किया गया है।” इसमें सन्देह नहीं कि अन्यायी कानून के आगे सिर झुकाकर उसकी सस्तियों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोवृत्ति देश में सदा रही है। अतः इस विषय में भी कांग्रेस ने कहा —

“यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करनेवाला बिल कानून बन जाय तो, उस हालत में, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार बिना विलम्ब के बिल के अनुसार मिले हुए अपने उन अधिकारों से काम लेने की भारत-मन्त्री से अनुमति ले जिसके द्वारा २० से २४ नं० तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से बाहर हो जाता है।”

ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० नं० से नीचे के भारतीय सूती माल को कर से मुक्त रखने पर लकाशायरवालों ने जो आपत्ति की है वह बे-बुनियाद है। १६०६ में, दादाभाई नौरोजी के समापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें ५० भवन मोहन मालवीय ने कहा, कि “हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों की रक्षावावस्था में करते हैं।”

लो० तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे ज्यादा क्षति मध्य-अंग्रेजीवालों में ही है। उन्होंने कहा, “हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृढ़-निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए।” स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर, और १६०६ तथा उसके बाद के वर्षों में अहिंसा-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुनर्जीवन की ओर खिंचा। १६१० में श्री सी० बाई० चिन्तामणि ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्धरण दिया —

“भारतवर्ष इंग्लैण्ड का ऐसा बगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा करके ब्रिटिश एजेंटों की मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिटिश मजदूरों और ब्रिटिश पूँजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेंटों द्वारा

भारत के ब्रिटिश-व्यापारियों के पास उसे भेज दिया जाय।”

गांव और उनके उद्योग-वधो एव खेती की बरबादी की ओर भी भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। १८६८ में ही प० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रखना था, कि “सरकार को देशी उद्योग-वधो एव कला-कौशल की उन्नति करनी चाहिए।” और यह बात तो इससे भी पहले (१८६१ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कानूनों ने गांववालों को बड़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। सारे ग्रामीण-समाज में उथल-पुथल होगई है, गांव की कारीगरी नष्ट हो गई है और पशु मर रहे हैं — ३ लाख तो सितम्बर १८६१ में ही मर चुके थे। १८६१ की नागपुर-कांग्रेस में, उर्दू में भाषण करते हुए, ला० मुरलीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बड़ी जोरदार अपील की थी।

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८६३) प० मदनमोहन मालवीय ने अपनी स्वाभाविक धौली में कहा था —

“आपके जुलाहे कहाँ हैं ? वे लोग कहाँ हैं जिनका निर्वाह भिन्न-भिन्न उद्योग-वधो एव कारीगरियों से होता था ? और जो कारीगर साल-बर-साल बड़ी-बड़ी ताबाद में इंग्लैण्ड तथा दूसरे यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे, वे कहाँ चले गये ? ये सब मूल-काल की बातें हो गईं। आज तो यहाँ बैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के बने कपड़ों से ढका हुआ है और अहा कहीं भी आप जायें, सब जगह विलायती-ही-विलायती माल आपको दिखाई देगा। लोगों के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि खेती-बाड़ी के द्वारा बरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-माज का व्यापार बाकी रहा है उससे टका-धेला पैदा कर लें। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो कुछ मिलता था अब उसका सौवा हिस्सा भी हमारे देशवासियों को नसीब नहीं होता। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है ?”

यह विषय कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर ने हार्डिगोट की जमी से अवकाश ग्रहण करने के बाद १९१४ में ‘गांवों के पुनर्जीवन और कर्जा-संस्थाओं की आवश्यकता’ पर बहुत जोर दिया था। १८६६ में ला० लाजपतराय की प्रेरणा पर कांग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एव उद्योग-वधो के विचार में लगाया और इसके लिए एक उप-समिति कायम की। इस सब कार्रवाई के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता-कांग्रेस के साथ १९०१ में हुई। इसके बाद क्रमशः इसमें उन्नति होती गई और अब सहर एव स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग-वधो की ओर

कांग्रेस का ध्यान १८६४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही आकर्षित हुआ, जिसका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन हम देखते हैं कि स्वयम्भुवन-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाना नहीं गया। उसे ठठाना तो दूर, उल्टे लॉर्ड सेल्सवरी ने यह निर्देश किया बताते हैं कि “भारतीय माल की प्रतिस्पर्धा से ब्रिटिश माल को बचाने के लिए उपाय किये जायें।” गावों की गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ व्यक्तियों को रोज एक बक्क खाना नसीब होता है, यह सिर्फ ख्याली बात नहीं है। श्री बाबा और मुँधोलकर ने बड़ी चिन्ता के साथ गौरे शासकों के उद्धारणों से इस बात को सिद्ध कर दिया है। सर थॉर्न ईलियट के कथनानुसार, “भावे किसानों को शाल की शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नहीं होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते हैं।” लगान का यह हाल था कि एक छोटे-से जिले में १८६१ में ६६ फी सदी बढ़ा, दूसरे में ६६ फी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया, और कुछ गावों में तो ३०० से १५०० फी सदी तक बढ़ा, जब कि इसके साथ-साथ फौजी खर्च भी बेधुमार बढ़ता रहा है।

जर्मनी में फी सैनिक १४५ सालाना खर्च पड़ता है, फ्रांस में १८५ और इंग्लैण्ड में २८५, परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अथवा सैनिक पर ७७५ सालाना खर्च किया जाता है, और यह उस हालत में जब कि फी आदमी की औसत-आमदनी इंग्लैण्ड में ४२ पौण्ड, फ्रांस में २३ पौण्ड और जर्मनी में १८ पौण्ड है और हिन्दुस्तान में सिर्फ १ ही पौण्ड है। ये अंक १८६१ के हैं।

अकाली के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए हैं और मजदूरी के सिलसिले में सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ में ही प्रस्ताव किया जा चुका है।

. स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य

१८०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उभर छोर तक फैल गया था उसका मूल कारण वग-भग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह जागृति इस वग-भग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर गर्म में बढ रही थी। पुण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वा अधिवेशन १८०५ ईसवी में हुआ तब उसमें वग-भग पर विधिवत् विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद्द कर दिया जाय। कम-से-कम उसमें ऐसा सन्तोषजनक ज़रूर कर दिया जाय जिससे सारा बंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वग-भग आन्दोलन

को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था, क्योंकि एक ओर जहाँ, उसके द्वारा बंगाल में जारी किये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परतापूर्वक विरोध किया गया, तथा साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बंगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ा और बंगाल के लोगों की प्रार्थना और विरोध का सवाल न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेद करने पर जिस तरह तुली थी, उसे, ब्रिटिश-लोगों के ध्यान में लाने का, जब एकमात्र यही बंध उपाय रह गया था ।” इससे यह साफ नहीं मालूम होता, और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी माल के बहिष्कार को पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय बाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय बल के लोगों को बड़ी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे भी कम स्पष्ट होता। परन्तु जैसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपत राय ने एक बुलन्द आवाज उठाई, “हमने अब गिड़गिड़ाने की नीति छोड़ दी है। हम उस साम्राज्य की प्रजा हैं जहाँ लोग उस पद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, लड़-झगड़ रहे हैं।” १९०५ में जिस साहस का अभाव था वह १९०६ में जा गया। बग-भग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने बहिष्कार-आन्दोलन का भी समर्थन किया। “यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहाँ के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है और वे सरकार से जो प्रार्थनाएँ करते हैं उनपर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि बग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय-संगत था और है।” इसके बाद कांग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया। बस, गाड़ी यही रुक गई। स्व-शासन की कल्पना कुछ शासन-मुधार-विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी, जैसे—परीक्षाओं का भारत और इंग्लैंड में साथ-साथ होना, कौंसिलों का विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिधियों की सख्या का बढ़ाया जाना, भारतभर की नया भारत की कार्यकारिणी कौंसिलों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति की जाना। बस, १९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का आत्म आशी में हो जाता था। दूसरे साल मूरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दृढ़-वाली कांग्रेस ने तो आगे के सालों में बहिष्कार को कतई छोड़ दिया, मिर्फ स्वदेशी को कायम रखा, और स्व-शासन सम्बन्धी प्रस्ताव उन्नते-उन्नते मिर्फ मिट्टो-मॉर्न मुधार-

योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १९१० में नये वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग आये। उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैंदियों को छोड़ने की अपील उनसे की। दूसरे साल फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १९१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसने साहस करके सरकार से यह मतालवा किया, कि “तारीख २५ अगस्त सन् १९११ के खरिदे में प्रान्तीय पूर्णाधिकार के सम्बन्ध में जो वचन दिया गया है उसे पूरा करे, और भारतवर्ष को सघ-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जायें।”

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न आजकल ही खड़ा हो गया है। नहीं, सर ऑकलैंड कॉल्विन (१८८८) जब सयुक्तप्रांत के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर थे तबसे इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। उस समय यह विज्ञान की कोशिश की गई थी कि मुसलमान कांग्रेस के विरोधी हैं। यहा तक कि ह्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इसके विषय में एक कम्पा जवाब उन्होंने सर ऑकलैंड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों की सफलता ने नौकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम लेफ्टिनेन्ट गवर्नर महोदय ने कर दिया। मुसलमानों पर भी इस विचार का असर दुरन्त ही हुए बिना न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियों का बुजुर्गाना रवैया जरूर बखरा होगा, जैसा कि एक घटना से बाहिर होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी हुआ। उनमें शोक रजाहुसेन का ने मि० यूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के हक में एक फतवा पेश किया, जो कि लखनऊ के सुत्रियों के सम्मुख उत्पत्ता से प्राप्त किया गया था। उन्होंने बडल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक—सरकारी हुनकाम—हैं जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं।”

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खयाल ने मूर्त-रूप धारण किया। हा, इससे पहले लॉर्ड कर्जन ने जरूर जान-बूझकर बग-भग के द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें कि मुसलमानों का बहुमत हो, यह कलुषित जाति-गत भावना जाग्रत की। यद्यपि लॉर्ड मिण्टो उस छोड़े को आराम पहुँचाने के लिए भेजे गये थे जिसपर लॉर्ड कर्जन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीब-करीब निकाल चुके थे, फिर भी जाति-गत भेद

और अलगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन सवार रहते थे, बोड़े की पीठ पर ज्यों-की-त्यों कायम रही। मिष्टो की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-समूह की तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही सयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ज्यों-का-त्यों कायम रक्खा गया था। सकीर्ण बुद्धि के राजनीतिज्ञों ने उस समय यह बताया कि बंगाल, आसाम और पंजाब की छोटी हिन्दू जातियों को ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया गया। परन्तु यह तो असल में सही रास्ता छोड़कर भटक जाना था। जो बड़ी अजीब बात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न मतधिकार रक्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी वाला जहा मतदाता हो सकता था वहा एक गैर-मुस्लिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था। मुसलमान प्रेजुएट को मतदाता बनने के लिए यह काफी था कि उसे प्रेजुएट हुए तीन साल हो जायें, परन्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन लाख रुपये। एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल। जबतक कोई सार्वजनिक बालिग मतधिकार नहीं मिल जाता है तबतक हम अक्सर ऐसे मतावलम्बी की प्रतिम्बनि सुना करते हैं। मुसलमान दोनों जातियों के लिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न स्टैण्डर्ड चाहते हैं जिससे कि मतदाताओं ने ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे।

१९१० में हालत बहुत नाजुक हो गई। सर बबल्यू एम० वेडरबर्न कांग्रेस के समापति हुए थे। आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिषद् की जाय, जिससे इस जातिगत प्रश्न पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियों और लोकल-बोर्डों में पृथक् निर्वाचन का तरीका जारी होने की बात चल रही थी। युक्तप्रात में, जहा कि पृथक् निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि सयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की सख्या कुल आबादी की $\frac{1}{2}$ होते हुए भी जिला-बोर्डों में मुसलमान १८६ और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिसिपैलिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२। यहा तक कि सर जॉन ह्यूबर्ट जैसा प्रतिपायी सयुक्तप्रात का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर भी उस प्रात में दोनों जातियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के हक में नहीं था। हा श्रीयुत जिज्ञा ने जरूर स्थानिक सस्थाओं में पृथक् निर्वाचन प्रचलित करने की निन्दा की थी। एक 'वर्न' सरक्यूलर निकला था, जो कि स्थानिक सस्थाओं में जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था कि मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन के अलावा सयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे तात्सुकात कायम रखने में मदद

मिलेगी। इसपर प० विद्यानारायण दत्त ने, जो कि १९११ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति थे, कहा था कि “मेरे इतना ही कहूँगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना है।” उन्होंने यह भी बताया, कि “जब सर डब्ल्यू० एम० वेडरबर्न और सर आगाखा की सलाह के मुताबिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस उद्देश्य से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जायें, तब एक गोरे अखबार ने जो कि सिविल सर्विसवालों का पत्र समझा जाता है, लिखा था कि ‘ये लोग क्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिफत की जाय?’ उसका यह वाक्य भारत की राजनैतिक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है।”

१९१३ में नवाब सय्यद मुहम्मदवह्दादुर ने, जो कराची कांग्रेस (१९१३) के सभापति थे, “यूरोप में तुर्क-साम्राज्य की नींव उखाड़ने और ईरान के दम घोटने के प्रयत्नों” की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य को लगे उस घनके को जिस दुश्मन के साथ मुसलमानों ने महसूस किया उसीको उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किया। अन्त में उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को अपनी मातृभूमि के लिए कन्वे-से-कन्वा लड़ाकर काम करने पर बहुत जोर दिया। यह हमें १९२१ के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-मुसलमान-सम्बन्धों पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के रोगी (१९वीं सदी तक के तुर्किस्तान को यही कहा जाता था) ने अबतक हिन्दुस्तान की राजनीति की गति-विधि को बनाने में बड़ा भाग लिया है। ये स्थितियाँ थी जिन में १९१३ की कराची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानों के बीच मेल एव सह-योग का भाव बढ़ाने के मुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। कांग्रेस ने मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलों पर मिलकर एक साथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगों से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति में हर तरह से सहायता करें।

उस समय कांग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उन वक्ताओं के भाषणों की बड़ी-बड़ी भाषा से लगता है जो कराची में (१९१३) इस विषय के प्रस्ताव पर बोले थे। स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ बसु के भाषण के कुछ अंश हम

यहाँ उद्धृत करते हैं—“हम हिन्दू-मुसलमान सबको अपना ध्यान एक ही ओर—मयूक्त आदर्श की ओर—लगाना चाहिए, क्योंकि आज का हिन्दुस्तान न तो हिन्दुओं का है, न मुसलमानों का, और न अघगोरो का। तब यूरोपियनों का तो और भी दूर। बल्कि यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमें हम सब हिस्सा रखते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलतफहमिया हुई हो, तो हमें अब उन्हें मूल जाना चाहिए। भविष्य-काल का भारत अबमें ज्यादा बलवान्, ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्, ज्यादा ऊँचा, होगा, नहीं-नहीं, वह तो उस भारतवर्ष से भी कहीं उज्ज्वल होगा जिसे अंग्रेजों ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था और अकबर ने अपने मनोरंजन में जैसा कुछ चित्र भारत का लीच रखा था उससे भी कहीं बेहतर वह भारत होगा।”

एक बार जहाँ घाव हुआ कि फिर उसमें से मवाद बहुत ही रहा। अगर हिन्दुओं ने चुपचाप और राजी-रजामन्दी ने मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न कभी का हल हो गया होता। हा, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाने जायेंगे बैसे-बैसे भूख बढ़ती जायगी, परन्तु उसके साथ यह भी मल्य है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा खायेंगे त्यों-त्यों भूख मरती जाती है। जानिगत प्रतिनिधित्व-सबन्धी मिष्टो-मॉल्ल-योजना हिन्दुस्तान के अत्ये जबरदस्ती मठ दी गई थी। लोगों से इनके बारे में कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया। इसलिए १९१६ में, जब सुधारों के नये टुकड़े देने की तजवीज चल रही थी, देश में मोचा कि हिन्दू-मुसलमानों का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों के प्रतिनिधि (नवम्बर १९१६) कलकत्ते में इरियन एमोनियेशन के स्थान पर मिले—इस उद्देश्य के कि १९१५ में कांग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार भाषमी ममझीने और रजामन्दी ने प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाए। इसी समय मुस्लिम-लीग ने स्व-आसन की जगह उद्देश्य बना लिया था। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की भावनायें बगल-बगल में गयी थी। यूरोपीय युद्ध की मुद छोटे और पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए ही पड़ा जा रहा था। ऐसी दशा में बगल में में जो बात हो गयी थी उसने गिना बानाकरण अनुत्तर था। परन्तु कांग्रेस के लक्ष्य में जो बचे-वृद्धे लोग थे वे अपनी तरफ से कुछ करने में शक्ती-शील्य करने दे। परन्तु यह काम यूरोपीयों पर आ गया। अतएव इस में सबसे छोटे लोगों ने, जो उस समय मौजूद थे, अपने बदन बचाया। यह मोद अमर ने कहा था—“हिन्दू और मुसलमान हिन्दुस्तान हैं दो आदम हैं। और दो में से एक मरने की माता का बचन बचाव है।” और जो देन-दो की भावना में लिख दूँ। फिर

प्रान्तों की सख्या १५ फी सदी से कम हो उनमें कम-से-कम १५ फी सदी प्रतिनिधि कौंसिल में रखना तय हुआ। अब रह गये पंजाब और बंगाल। हमेशा की तरह इनका मामला है तो पेचीदा, परन्तु १९१६ में लखनऊ में सुलझाया गया।

प्रवासी भारतवासी

जहाँ भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, तहाँ दक्षिण-अफ्रीका-स्थित भारतीयों की हालत बड़ से बड़तर हो रही थी। १८९६ ई० में यह कानून बना कि नैटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के घर्तवन्द प्रवासी अपने इकरारनामे की अवधि के समाप्त होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नये सिरे से शुरू करावें—कुली बनने का इकरारनामा फिर से करें, या अपनी वार्षिक आय के आधे भाग के बराबर मनुष्य-कर (पोल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर डॉ० मुजे के शब्द दोहराना असंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १९०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्बुलेंस-कोर के साथ की गई अफ्रीका-यात्रा के बाद बहा से आकर कहे थे—“हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते।” इसी प्रसंग में श्री बी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी कि साम्राज्य ने एक जाति की उन्नति या प्रभुता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने कापी की २१ वी कांग्रेस (१९०५) में कहा था—“यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े बड़े दार्शनिकों, महान् राजनीतिकों और वीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली जाति छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के पाव नहीं पड़ सकती।”

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने सबसे पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहाँ के पूरे समाचार यहाँ की जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ष इसी उद्देश से जाते थे। अपने नारंगी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी छाठी के कारण वह कांग्रेस में कभी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में वुडापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति को उठा दिया है। दक्षिण-अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुतः पहला विरोध १८९४ में हुआ, जब कि अध्यास ने उस मासिक का प्रस्ताव पेश किया कि औप-निवेशिक-सरकार का वह विल रद्द कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मतधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्त्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि “हमें किस तरह बिना पास के यात्रा करने की और ९ बजे रात के बाद घूमने तक की आजादी

नहीं है, किस तरह हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा जाता है जहाँ कूड़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेलों के पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने की इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से बाहर निकाल दिया जाता है, फुटपाथ से धक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से बाहर रक्खा जाता है, सार्वजनिक वाग-वगीचों का लाभ हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर शूका जाता है, हमें धिक्कारा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं और उन अपमान्य तरीकों से अपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य धीरता-पूर्वक सहन नहीं कर सकता।”

१८९८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा चुके थे और उसी समय गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें भी सबसे अधिक अफसोस की बात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड एल्लिन ने इन कानून के पास होने पर सहमति दी थी और उस समय के भारत-मंत्री लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन हमें ‘अगलियों की जाति’ कहकर सतुष्ट हुए थे। १९०० में भूतपूर्व बोअर जनतन्त्र ब्रिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १९ वें अधिवेशन (१९००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र बोअरों पर नियन्त्रण करने में सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए अब नेटाल में प्रवेग-सम्बन्धी पाबन्दियाँ और डीलर्स लाइसेन्स-कानून उठा देने चाहिये। १९०१ की १७ वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका-अवासी लाखों भारतीयों की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था १९०२ में भारत-मंत्री से इस प्रश्न पर एक सिफ्ट-मदल भी मिला, लेकिन कोई गतीबाज निकला। कांग्रेस ने १९०३ और १९०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया। ब्रिटिश-सरकार के ज़िम्मेवार हलकों में बोअर-युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक यह भी था कि “ब्रिटिश सम्राट् की भारतीय प्रजा के साथ जनतन्त्र में दुर्व्यवहार किया जाता है” और यह माग की गई थी कि “भारतीय प्रवासियों के साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय।” कांग्रेस ने इस वक्तव्य की ओर भी सबका ध्यान खींचा। लेकिन १९०५ में हालत और भी खराब हो गई। बोअर-शासन में जिन कानूनों का मक्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शासन में और भी मक्ती से होने लगा। कांग्रेस ने इसका भी तीव्र विरोध किया और शर्तवन्दी कुली-अथा तबा अन्य प्रतिवधक कानूनों को हटाने की माग की। सरकार ने ट्रांसवाल में इस आर्डिनैस को ‘फिलहाल’ चालू करने की आज्ञा नहीं दी। इसने भारतीयों को नतोप हुआ। लेकिन १९०६ में दक्षिण अफ्रीका के लिए जो शासन-

विधान स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट समावना थी। १९०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्षिण-अफ्रीका के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि इसको बनाते हुए भारतीय हितों की भी पूरी रक्षा की जाय। १९०८ की २३वीं कांग्रेस (मदरास) में श्री मुशीरहसेन किदवाई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेशों में उच्चकुलीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया था और यह बतावनी भी दी गई थी कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के हितों को भारी हानि पहुँचेगी।

१९०९ में कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि का कोई परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की कांग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए "अधिकारियों के विश्वास-घात और गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-संग्राम" का वर्णन किया। अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान् संग्राम शुरू हुआ। उसी स्थान पर १८,०००) का भन्दा भी इकट्ठा हो गया। इसके आलावा सर जमशेदजी ताता के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २५,०००) दिये। कांग्रेस ने २४ वें अधिवेशन (लाहौर १९०९) में इस उदारता के लिए श्री रतन जे० ताता को धन्यवाद दिया। कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १९१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का संग्राम अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। कांग्रेस ने ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्याग की प्रशंसा की, जो अपने देश के लिए वीरतापूर्वक कैद भोगते हुए, अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी, अपने प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्ण और स्वार्थहीन लड़ाई लड़ रहे थे।

कांग्रेस का २७ वा अधिवेशन (१९११) जबकि आशामय वातावरण में सम्पन्न हुआ, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन और गिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों को रद्द कराने पर ट्रान्सवाल के भारतीय समाज और गांधीजी को हार्दिक धन्यवाद दिया जा सका था। लेकिन कांग्रेस ने "हाल ही में हुए प्रान्तीय वस्तियों सम्बन्धी भावी कानून की समावना में" यह प्रस्ताव पास किया था। अगले साल (१९१३) में भी गिरमिट-कानून की अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने बच्चों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश सम्राट् से कांग्रेस ने इस कानून को रद्द कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिंग

बाइसराय थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई का रुख लिया और उन्हें और अधिक बलशाली बनाने के लिए कराची कांग्रेस ने १९१३ में चार्टरबंदी कुली-प्रथा को नष्ट करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद अग्रेजी ही यह प्रथा तोड़ दी गई और कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक समझौते के लिए लॉर्ड हार्डिंग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १९१६ और १९१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार करना पड़ा। कराची-अधिवेशन में गांधीजी तथा उनके अनुयायियों के वीरतापूर्ण प्रयत्नों और भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रशंसा में एक प्रस्ताव पास किया गया।

कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने 'लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा देकर भी भारत के लिए एक मनोरंजक समस्या उत्पन्न कर दी थी। कराची-कांग्रेस ने १९१३ के २८ वें अधिवेशन में इस आधार पर इसका विरोध किया।

"कनाडा की प्रिवी कौंसिल के हुक्म (न० ६२०) के अनुसार जो आमतौर पर 'लगातार यात्रा-धारा' कहलाता है, बहा जाने की जो मनाही है उसका यह कांग्रेस विरोध करती है, क्योंकि उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही हो जाती है जो बहा रहने न लग गया हो। क्योंकि दोनों महाद्वीपों के बीच कोई सीधा जहाज नहीं आता-जाता और जहाजवाले सीधा टिकट देने से इनकार करते हैं, जिससे बहा रहनेवाले भारतीय अपने बाल-बच्चों को नहीं ला पाते हैं, इसलिए यह कांग्रेस साम्राज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युक्त 'लगातार यात्रा-धारा' रद्द कर दी जाय।"

गत महासम्मेल छिड़ने के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास में एक मजेश्वर, नवीन और अद्भुत घटना हुई। आनेवाली सतति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए। कनाडा की इस धारा को तोड़ने के लिए बाबा गुरुदत्तसिंह नामक एक सिक्ख सज्जन ने 'कोमागाटामारू' जहाज किराये पर लिया और हागकाग या टोकियो बिना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्खों को कनाडा ले गये।

कोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को भारत में छोटना पड़ा। बापसी पर यात्रियों को वजबज से, जहाँ वे उतरे थे सीधा पंजाब जाने की आज्ञा दी गई और दूसरी किमी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियों ने सीधे पंजाब जाना पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी बात तो सुन ले, हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता है और इसमें हमें आर्थिक हानि भी बहुत होगी। सीधे पंजाब जाने के बजाय उन्होंने गिरफ्तार हो

जाना अधिक अच्छा समझा। कोमागाटामारु के आदमियों की, जिनमें सिन्ध के प्रो० मनसुखानी (अब स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, घेब कहानी—दगा कैसे हुआ, कितने आदमी मारे गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तसिंह ७-८ साल तक कैसे गुम रहे और उड़ीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड़ और सिन्ध में किस तरह १९१८ तक घूमते रहे, उसके बाब कैसे बम्बई जामर महाल बन्दर में बल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर हो गये, कैसे वह अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १९२१) में गांधीजी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी, कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी १९२२ को वह लाहौर-जेल से उस आर्डिनेन्स की अवधि समाप्त होने पर छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे, आदि—इस पुस्तक के क्षेत्र के वाहर की चीज है।

नमक

१९३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति में खास तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-कमीशन की सिफारिशें जानते हैं, उन्हें यह ज्ञान कर बहुत आश्चर्य होगा कि १८८८ में कांग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात-व्यापार को बढ़ाना था, बल्कि इस आधार पर किया, कि “नमक-कर में हाल ही में की गई वृद्धि से गरीब लोगों पर भार और भी बढ़ गया है, और इसके द्वारा सरकार ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोष में से खर्च करना शुरू कर दिया है, जो खास भीको के लिए साम्राज्य की एकमात्र निधि है।” १८९० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई वृद्धि को वापस लेने की—न कि नमक-कर को हटाने की—मांग की। आठ दूसरे भीको पर कांग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ के दर को और एक दफ्तर १८८८ के दर को कायम रखने की मांग की। १९०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम बार विचार करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा, कि “इस समय जो बहुत-सी नीमारिया फँस रही हैं उनका एक खास कारण (नमक-कर के कारण) नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है।” इसके बाद ‘नमक’ कांग्रेस ने उठकर काँसिलो में पहुँच गया और वहाँ श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहे।

शराब और वेश्यावृत्ति

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उसपर ध्यान दिये बिना न रह सकी। शराब की बढ़ती हुई खपत को देखकर समय और मध्य-निवारण की भाग की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और १८८६ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। कांग्रेस ने भी कामन-सभावाले प्रस्ताव को 'कार्य-रूप में परिणत करने' का अनुरोध किया। १८६० में कांग्रेस ने शराब पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराब पर कर लगाने, बंगाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा मदरास-सरकार के (१८८६-९०) ७,००० शराब की दूकानें बन्द करने पर हर्ष प्रकट किया, लेकिन इस बात पर खेद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के खरीते की इन हिदायतों पर अमल नहीं किया कि "स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्न किया जाय और मालूम होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय।" इसके बाद दस साल तक कांग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया। १९०० में आकर कांग्रेस ने सस्ती बिकने के परिणाम-स्वरूप शराब की बढ़ती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना की, कि "बहु अमरीका के भेग लिकर-लॉ के समान कोई कानून बनावे और सर विलफ्रीड लॉसन के 'परमिसिबिल' या 'लोकल आफ्फन एक्ट' के समान कोई बिल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगावे।" इस प्रसंग में यह याद करना उचित होगा कि कुमार एन० एम० चौधरी ने कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश-सरकार जहाँ हमारे लिए शीक्सपीयर और मिल्टन लाई है वहाँ शराब की बोतलें भी लाई हैं।

राज्य-नियमित वेश्या-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विषय था। यह सब जानते हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों में या युद्ध-यात्राओं में स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गईं तो बहुत भीषण मालूम हुईं, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सहवास बढ़ने लगा त्यों-त्यों क्षोभ कम होता गया। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता में उन भारत-हितैषियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की ओर से बननेवाले कानूनों और नियमों को पूर्णतया रद्द कराने के लिए इंग्लैंड में कोशिश कर रहे थे। कॅप्टन वैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि २,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कुत्सित उद्देश से

इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असयत जीवन बिताने की प्रोत्साहित हुए। इलाहाबाद में हुए आठवें अधिवेशन (१८६२) में कामन-सभा को “भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पवित्रता-सम्बन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए” धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित जनैतिक कार्यों का विरोध किया गया।

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-कमिटी के पार्लमेण्ट के सदस्यों ने ध्यावनियों की बेक्यावृत्ति तथा छूत रोगो-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और प्रथाओं के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वर्णित कारनामों और आज्ञाओं कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थी और इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एकमात्र उपाय, स्पष्ट कानून, बनाने की मांग की।

स्त्रियों और दलित जातियों

मि० माण्टेगु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का दावा भी देश के सामने पेश हुआ—और, वस्तुतः यह बहुत आवश्यकता है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। कलकत्ता-कांग्रेस ने १९१७ में यह सम्मति प्रकट की थी, कि “शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित-संस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार खड़े होने की, स्त्रियों के लिए भी, वही शर्तें रखी जायें जो पुरुषों के लिए हैं।” इसीसे मिलते-जुलते दलित-जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार किया —

“यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पूर्वक कहती है कि परम्परा से दलित जातियों पर जो रुकावटें चली आ रही हैं वे बहुत कुछ देनेवाली और क्षोभकारक हैं, जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयों, संक्षिप्तियों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए न्याय और अलमसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बन्धनों उठा दी जायें।”

विविध

इस अवधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की ओर ध्यान दिया। शिक्षा के विविध पहलुओं—प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कौशल-

सबधी शिक्षा में कांग्रेस ने बहुत दिलचस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चासी-कर, आयकर और विनियमदर के मुआवजे आदि आर्थिक विषयों पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानिक स्वराज्य-संस्थाओं और विशेषतः मदरास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के सबध में प्रतिगामी कानूनों से कांग्रेसी बहुत रुष्ट हुए। स्वास्थ्य और विशेषतः प्लेग और क्वारण्टीन-सबधी, बेगार बगैरा पर भी कमी-कमी विचार हो जाता था। राजभक्ति की शपथ भी कई बार ली गई। १९०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १९१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर कांग्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम के (१९०५ में युवराज और १९१० में सम्राट् की हैसियत से) स्वागत-सबधी प्रस्ताव भी पास किये गये।

ब्रह्मदेश

आज हम देखते हैं कि बर्मा के पृथक्करण को लेकर एक बड़ा सबर्ष-सा चल पड़ा है। एक क्षण के लिए हम फिर उस वर्ष में चले जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली कांग्रेस (१८८५) ने बर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था—“यह कांग्रेस उत्तरी बर्मा के ब्रिटिशराज्य में मिलाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में—यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे मिलाने का ही निश्चय कर ले तो—पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी बाइसराय के कार्य-क्षेत्र से अलग रक्खा जाय और एक शाही उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीलों के अनुसार वह इस देश के शासन से अलग रक्खा जाय।”

कांग्रेस का विधान

कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-सबधी इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी की तरह ‘आर्टिकल्स’ या ‘मैमो-रेण्डम आफ एसोसियेशन’ बनाकर या १८६० के २१ वें कानून के अनुसार ‘रजिस्टर्ड सोसाइटी’ की तरह पहले से ही नियमादि बनाकर नहीं हुई है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊँचे उद्देश की प्राप्ति नैतिक बल से ही कर सकती थी। इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल में अपने आकार-प्रकार और शक्ति में वृद्धि प्राप्ति की है। और इसी नैतिक बल पर इसने अपने महान् उद्देश की पूर्ति का

वारगेमदार रक्का है। शुरू में १८८६ में कांग्रेस के मंचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर गंभीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए कमिटी तो बना दी गई, लेकिन विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जब तक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय तथा वह अन्य प्रान्तों में भी घूम आवे। १८८८ में कांग्रेस के प्रतिनिधि उत्तरी भारी सभा में आये कि कांग्रेस को प्रति दस लाख जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिनिधियों की संख्या सीमित कर देनी पड़ी। भारत में कांग्रेस का एक महायक-सत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की कमिटी को भी एक वैतनिक सत्री दिया गया। इस पद पर पहले-महल सुप्रसिद्ध मि० टर्नर, सी० आर्ट० ई० नियुक्त हुए।

यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८८) था, जब यह निर्दिष्ट किया गया कि "जिस प्रस्ताव के उपरिचय किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्वसम्मति में या लगभग सर्वसम्मति में आपत्ति करेंगे, वह विषय-समिति में विचार के लिए पेश नहीं किया जा सकेगा।" यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगड़े के बाद १८०८ में बनाया गया था; फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व सम्मति के बजाय ३ कर दिया गया। प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८८ में पास हुआ, लेकिन अमल में यह दूसरे वर्ष (१८९० में) ही लाया गया।

इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह हमने मालूम होता है कि १८९२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश-कमिटी और कांग्रेस के पत्र 'इंडिया' के पत्र के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८९६) में भी इसी ही रकम पास की गई थी। १८९८ में कांग्रेस के विधान को बनाने का नया प्रयत्न किया गया। वस्तुतः यदुगल-कांग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक कमिटी भी नियत की। दूसरे साल (१८९९) लगनरु में एक सम्पूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १८०८, १८२० और १८२९ के वर्षों में कांग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना बड़ी मनोरंजक होगी। लगनरु में कांग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित हुआ था —

"वैध उपायों से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हित को बढ़ाना अंग्रेज-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा।"

सारी वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकने के लिए पाठकों को १९०८

में स्वीकृत मस्यारो जैसे स्व-शासन, १९२० में समर्थित शान्तिपूर्ण और उचित उपाय तथा लाहौर (१९२६) में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। लसनऊ-विधान के अनुसार कार्य-संचालन के लिए कांग्रेस-द्वारा निम्बिन, ४५ सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई। साल के खर्च के लिए ५०००] स्वीकृत किये गये। स्थायी कांग्रेस कमिटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनों के आयोजन द्वारा कांग्रेस का काम नारे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रस्तावों के मतविदे बनाने का काम इंडियन कांग्रेस कमिटी करती थी। सात दृष्टियों के नाम पर कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोष भी स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रान्त में एक-एक ट्रस्टी कांग्रेस नियुक्त करती थी। १९०० में ४५ सदस्यों वाली इंडियन कांग्रेस कमिटी और बड़ी कर दी गई। पद की हैमियत से इतने व्यक्ति और सदस्य मान लिये गये—समापति, मनोनीत समापति, जिन दिन में नामजद किना जाय, पिछली कांग्रेसों के समापति, कांग्रेस के मंत्री और सहायक मंत्री तथा स्वागत-मिति द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मंत्री।

लन्दन में कार्य का मगठन १९०१ में शुरू किया गया। 'इंडिया' पत्र को और सुचारु रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापिया बिकने का इस तरह प्रबन्ध किया कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत सख्या में 'इंडिया' सरोदे। 'इंडिया' और ब्रिटिश-कमिटी का खर्च पूरा करने के लिए १९०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अलावा १०] और लेने का भी निश्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनों कांग्रेस भारत और इंग्लैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न करती थी। दम्बई के २० वें अधिवेशन (१९०४) में यह निश्चय किया गया कि पार्लियेमेंट के चुनाव से पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए १०,०००] इकट्ठे किये जायें। काशी में (१९०५) कांग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी बनाई गई। १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश एक शब्द में रख दिया—"हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्वराज्य (जैसा इंग्लैण्ड या उपनिवेशों में है) में आ जाता है।" तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप में रखने का प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। कांग्रेस का प्रस्ताव यह था—"स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है, वही भारत में भी जारी की जाय" और इसके लिए अनेक सुधारों की भी मांग की गई।

कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लबालब था, इसमें

सन्देश नहीं, इसलिए राष्ट्र को समर्थित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया और निश्चय किया गया कि —“प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी में उस तरह से प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का संगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय। कांग्रेस के तमाम विषयों में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम बराबर चलाते रहने के लिए जिला-संस्थाएँ संगठित करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।” कांग्रेस के सभापति की निर्वाचन-प्रणाली भी बदल दी गई। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत-समिति अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापति चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना बहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४६ सदस्यों की बनाई गई नई समिति) इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करे।

विषय-निर्वाचन-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। कमिटी के ८५ सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि क्रिये जायेंगे जिसमें कांग्रेस हो। उस वर्ष के सभापति, स्वागत-समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनो के सभापति और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मंत्रीगण और कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने पद के अधिकार से विषय-निर्वाचनी समिति के सदस्य माने गये।

कांग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुतः युग-अवर्तक था। सूरत के झगड़े के कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद में ‘कन्वेंशन’ खड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विधान बनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित सभापति बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डॉ० रासबिहारी बोप के चुनाव पर ही बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद लोगों के विचार का वास्तविक विषय था—कांग्रेस का क्रीड यानी ध्येय। सूरत-कांग्रेस के भग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१९०७) को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया—“कांग्रेस का उद्देश है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगों के लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों में सम्मिलित होना।”

१९०८ के विधान के अनुसार विभिन्न प्रान्तों से महासमिति (आल इंडिया कांग्रेस कमिटी) के सदस्य इस तरह चुने जाते थे —

(१) मद्रास १५, (२) बम्बई १५, (३) संयुक्त बंगाल २०, (४) संयुक्त प्रान्त १५, (५) पंजाब या सीमाप्रान्त १३, (६) मध्यप्रान्त ७, (७) बिहार

उड़ीसा* १५, (८) बरार ५, (९) बर्मा २,

यह भी तय हुआ कि यथासम्भव कुल सख्या का ५ वा हिस्सा मुसलमान सदस्य चुने जायें।

इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले कांग्रेस के सभापति और प्रधान-मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जायें। कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका भी प्रधान मंत्री समझा जाय।

इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी बहुत बढ गई। महा-समिति के सभी सदस्य और कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे।†

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गये—(१) वैध उपाय का अवलम्बन, (२) वर्तमान-शासन प्रबन्ध में क्रमशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय एकता को बढाना, (४) सार्वजनिक सेवा की भावना को उत्तेजना देना, और (५) राष्ट्र के बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक साधनों का संगठन व विकास। १९०८ के विधान में पहली बार यह धारा भी रखी गई कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिनके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि हों। पुराने कांग्रेसी देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन होता था। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ १८९६) में 'पंजाब लैण्ड एलीनेशन बिल' की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था। यह बिल उन दिनों बड़ी कौंसिल के सामने पेश था और इसका आशय यह था कि किसानों के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न बन्धक रखी जा सके। लेकिन आगामी १६वें अधिवेशन (लाहौर, १९००) में हिन्दू-मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विषय-समिति ने इस कानून

* इस विधान में बिहार, जो अबतक पश्चिमी बंगाल का भाग माना जाता था, पहली बार एक पृथक् प्रान्त के रूप में माना गया। १९०८ में ही बिहार की पहली प्रान्तीय परिषद् श्री० (पीछे सर) सैयद अलीइमाम की अध्यक्षता में हुई।

† महा-समिति की सख्या पीछे और भी बढा दी गई। १९१७ तक इसके सदस्यों का चुनाव इस तरह होता था—१४ मद्रास, ११ आंध्र, २० बम्बई, ५ सिंध, २५ बंगाल, २५ युक्तप्रान्त, ५ दिल्ली, ३ अजमेर-मेरवाड़ा, २० पंजाब, १२ मध्य-प्रान्त, २० बिहार व उड़ीसा, ७ बरार व ५ बर्मा। विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त की ओर से इतने ही सदस्य और प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे।

(विल अब कानून बन चुका था) पर विचार करना स्थगित कर दिया, ताकि एक साल तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय।

संयुक्त-बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने कांग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो इलाहाबाद (१९१०) में एक उप-समिति को सौंपे गये। १९११ में कलकत्ता के अधिवेशन में इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और आगे सशोधनों के लिए वह महासमिति के सुपुर्द किया गया। इसके बाद ५ सालों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १९१४ में जब यूरोप का महासमर छिड़ गया, तब श्रीमती एनी बेसेण्ट ने अपना महान् राजनैतिक आन्दोलन अ० मा० होमरूल-लीग की छत्रच्छाया में आरम्भ किया।

१९१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मांगें

भारत की राष्ट्रीय मांग केवल भावनात्मक नहीं हैं, उसके पक्ष में प्रबल और व्यावहारिक युक्तियाँ हैं, और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए यहाँ उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेखमात्र कर देना काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिनपर ३२ साल से भारत-सरकार ने व प्रांतीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और १९१८ तक भी वे हमारी मांगें बनी रहीं —

- (१) इण्डिया काँसिल तोड़ दी जाय (१८८५)
- (२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनों जगह परीक्षाएँ ली जायें (१८८५)
- (३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-अध्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८५)
- (४) जूरी-द्वारा मुकदमों का सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६)
- (५) जूरी के फैसले अन्तिम समझे जायें (१८८६)
- (६) बारम्बट वाले मामलों में अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा मजिस्ट्रेट के सामने पेश न होकर वीरा-जज की अदालत में पेश हो (१८८६)
- (७) न्याय और शासन-विभाग अलगाव किये जायें (१८८६)
- (८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में शर्तें किये जायें (१८८७)
- (९) सैनिक-अफसरों-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की जाय (१८८७)
- (१०) शस्त्र-कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८७)

(११) औद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमली नीति काम में लाई जाय (१८८८)

(१२) लगान-नीति में सुधार किया जाय (१८८९)

(१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८९२)

(१४) स्वतंत्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८९३)

(१५) विनिमय-दर मुआवजे का बन्द करना (१८९३)

(१६) बेगार और जबरदस्ती रसद की प्रथा बन्द करना (१८९३)

(१७) 'होम-वार्जेज' में कमी करना।

(१८) सूती कपड़े पर से उत्पत्ति-कर हटा लिया जाय (१८९३)

(१९) बकीलो में से ऊँचे न्याय-विभाग के अफसर नियुक्त किये जायें (१८९४)

(२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति (१८९४)

(२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन (१८९१) वापस लिया जाय (१८९४)

(२२) किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जायें (१८९५)

(२३) तीसरे वर्ग की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८९५)

(२४) प्रान्तों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाय (१८९६)

(२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के साथ न्याय हो सके (१८९६)

(२६) १८९८, १८९९ और १८९७ के क्रमशः बंगाल, मदरास और बम्बई के रेग्युलेशन वापस लिये जायें (१८९७)

(२७) १८९८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विषय में (१८९७)

(२८) १८९८ के तानिगत हिन्दू व जाटों की जमीनदारी के विषय में (१८९७)

(२९) १८९९ के कनकता म्यूनिसिपल एक्ट के विषय में (१८९८)

(३०) १९०० के 'पंजाब लैण्ड एलीनेशन एक्ट' को रद्द करना (१८९८)

(३१) भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति की जांच की जाय (१९००)

(३२) छोटी सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय (१९००)

(१९००)

(३३) 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पाबन्दियां उठा दी जायें (१९००)

- (३४) इंग्लैण्ड में होनेवाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व पुलिस के ऊँचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१९०१)
- (३५) भारत-स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर, ७,८६,००० पौण्ड प्रतिवर्ष का जो खर्च लादा गया, उसके विषय में (१९०२)
- (३६) इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में (१९०२)
- (३७) इण्डियन यूनिवर्सिटी एक्ट १९०४ के विषय में (१९०३)
- (३८) आफिसियल सीन्ट्रस एक्ट १९०४ के बारे में (१९०३)
- (३९) इण्डिया आफिस के खर्च तथा भारत-मन्त्री के वेतन के विषय में (१९०४)
- (४०) भारत के राजकाज की पार्लमेण्ट-द्वारा समय-समय पर जाच की जाय (१९०५)
- (४१) स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१९०५)
- (४२) १९०८ के क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेण्ट एक्ट के बारे में (१९०८)
- (४३) १९०८ के अखवार-कानून के विषय में (१९०८)
- (४४) मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१९०८)
- (४५) लेजिस्लेटिव कौंसिल रेग्युलेशन में सुधार किया जाय (१९०९)
- (४६) युक्त-प्रान्त के शासन-प्रबन्ध की जाच की जाय (१९०९)
- (४७) लॉ-मेम्बर का पद एडवोकेटो, बकीलो और एटर्नियो के लिए खोल दिया जाय (१९१०)
- (४८) राजद्रोही सभाबन्दी कानून के विषय में (१९१०)
- (४९) इण्डियन प्रेस-एक्ट के बारे में (१९१०)
- (५०) बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जाच की जाय (१९१०)
- (५१) राजनैतिक कदियों की आम रिहाई की जाय (१९१०)
- (५२) श्री गोखले के प्रारम्भिक शिक्षा-विल के विषय में (१९१०)
- (५३) सयुक्त-प्रान्त के लिए सपरिषद् गवर्नर मिलने के विषय में (१९११)
- (५४) पञ्जाब में कार्यकारिणी कौंसिल रखने के सबब में (१९११)
- (५५) इण्डिया कौंसिल में सुधार किया जाय (१९१३)
- (५६) इंग्लैण्ड में रहनेवाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१९१५)

कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

पुराने कांग्रेसियों का दृष्टिकोण व नीति

कांग्रेस को स्थापित हुए अवतक ५० वर्ष हो गये। इस कल्पे अरसे में भारत के राष्ट्रीय विकास की कई भूमिकाओं से वह गुजर चुकी है। हा, आगे जाकर उसके अन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे। परन्तु पिछला जमाना तो १८८५ से १९१५ बल्कि १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायों और विचारों के लोगो ने मिलकर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजवीज किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं हुए थे, बल्कि यह कि वे गिनती में आने लायक न थे।

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है युद्ध-क्षेत्र का चुनाव और व्यूह-रचना। दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युद्ध रोककर शत्रु को सन्धि-वर्षा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हींकी उभेड-बुन में लगे रहते हैं। युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाग परेशान रहते हैं। इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहाँ नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि आन्दोलन महज लफ्फी और कागजी हो या कुछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह निश्चय करना पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। यो तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी आँखों के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चक्कर काटते हैं, परन्तु राजनैतिक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में आकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है और जो काम पचास वर्षों की जबर्दस्त लड़ाई के बाद आज बड़ा आसान और मामूली दिखाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता। जरा खयाल कीजिए कि विदेशी माल के या कौंसिलों के, अदालतों या कालेजों के बहिष्कार या कुछ कानूनों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर फीरोज-

साहू मेहता या प० अयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष, सुब्रह्मण्य ऐयर या आनन्दा चार्ल्स, ह्यूम साहूव और वेडरबर्न साहूव के सामने रक्खा गया है। अब यह सोचने में अरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भडक उठे होते और न ऐसे उग्र कार्यक्रम, बग-भग के, कर्जन और मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियावाला बाग के हत्या-काण्ड के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्ध्रह सालों के लड़ाई-झगड़ों में जो कांग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ व्यापारी एक डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पार्लियेन्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नयी-सुली भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके द्वारा वे राष्ट्र के दु खों और उच्च आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते रहे। अब इस बात की याद करते हैं कि कितन-कितन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को बनाया और उसे प्रभावित किया, इनके विश्वास क्या थे, तब वे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते हैं जिनमें कि भारतीय राजनीतिक आन्दोलन इन पचास वर्षों में बँट गया है। वह जमाना और हालतें ही ऐसी थी कि अपने दु ख-बर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा बलील और प्रार्थना करने के और नई रिजायतो और विशेषाधिकारों के लिए मामूली माग करने के और कुछ नहीं हो सकता था। फिर वह मनोवृत्ति आगे जाकर शीघ्र ही एक कला के रूप में परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रवीण बुद्धि और दूसरी ओर खूब कल्पनाशील और भावना-प्रधान वस्तुत्व-कला, दोनों ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमें दो बातें हुआ करती थी—एक तो प्रभावकारी तथ्य और आकड़े, दूसरे अकाट्य बलीलें। उनके उद्गारों में जिन बातों पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये हैं—अंग्रेज लोग बड़े न्यायी हैं और अगर उन्हें ठीक तौर पर बाकिफ रक्खा जाय तो वे सत्य और हक के पथ से जुड़ा न होंगे, हमारे सामने असली मसला अंग्रेजों का नहीं बल्कि अश्वघोरो का है; बराई पद्धति में है, न कि व्यक्ति में, कांग्रेस बड़ी राजभक्त है, ब्रिटिश-साम्राज्य से नहीं बल्कि हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका झगड़ा है, ब्रिटिश-विधान ऐसा है जो लोगों की स्वाधीनता का सब जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश-पार्लियेन्ट प्रजातन्त्र-पद्धति की माता है; ब्रिटिश-विधान ससार के सब विधानों से अच्छा है, कांग्रेस राजद्रोह करनेवाली

संस्था नहीं है, भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन है, हिन्दुस्तानियों को सरकारी नौकरियाँ अधिकाधिक दी जानी चाहिएँ, ऊँचे पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थायें और सरकारी नौकरियाँ ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम-गाह होनी चाहिएँ, धारा-सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएँ और उन्हें प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए, प्रेस और जंगल-कानून की कड़ाई कम होनी चाहिए, पुलिस लोगों की मित्र बनके रहे, कर कम होने चाहिएँ, फौजी खर्च घटाया जाय, कम-से-कम इंग्लैण्ड उसमें कुछ हिस्सा ले, न्याय और शासन-विभाग अलहदा-अलहदा हो, प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत-भरी की कौंसिल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय, भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लैमेण्ट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायें, नॉन-रेग्युलेटेड प्रान्त रेग्युलेटेड प्रान्तों की पक्ति में लाये जायें, सिविल सर्विसवालों के बजाय इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अग्रेज गवर्नर बनाकर भेजे जायें, नौकरियों के लिए भारत और इंग्लैण्ड में एक-साथ परीक्षायें ली जायें, इंग्लैण्ड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-व्यो को तरक्की दी जाय, लगान कम किया जाय और बन्दोबस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस यहाँ तक आगे बढ़ी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण बतलाया, सूती माल पर लगे उत्पत्ति-कर को अनुचित बतलाया और सिविलियन लोगों को दिये जानेवाले विनिमय-दर-मुआवजे को गैर-कानूनी बतलाया तथा ठेठ १८६३ में मालवीयजी महाराज की दृष्टि यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्होंने ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया था।

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका एक-निगाह में सिद्धान्तलोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार हुई थी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख अल्टर किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। किन्ती भी आधुनिक इमारत की नींव में छ फीट नीचे जो ईंट, बत्ता और पत्थर गड़े हुए हैं क्या उनपर कोई दोष लगाया जा सकता है? क्योंकि वही तो हैं जिनके ऊपर भारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के डग का स्व-यामन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होनरूलर, उसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मजिले एक-के-बाद-एक बन सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट धान के

भी समयर्थन में अंग्रेजों के प्रमाण देने पड़ते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानियाँ की थीं। आज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे ऊँची पुरस्काओं की बदौलत है कि जिन्होंने जंगल-झाड़ियों को साफ करने का कठिन काम किया है। अतएव इस अवसर पर हम उन तमाम महापुरुषों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मजिलों में प्रगति की गाड़ी को आगे बढ़ाया था।

ब्रिटिश राज्य में युद्ध

कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोष के भाव आ गये हो, पर इसमें कोई شک नहीं कि ठेठ १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्याय-प्रियता पर अटल विश्वास ही। इसी भाव को लेकर १८९३ में स्वागताध्यक्ष सरदार बयालसिंह मजीठिया ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि “भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।” आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि “हम उस विधान के मातहत सुख से रह रहे हैं जिसका विरुद्ध है आजादी, और जिसका बाधा है सहिष्णुता।” कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) के प्रतिनिधि ने लॉर्ड रिपन का यह विचार उद्धृत किया था—“महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलह-नामा नहीं है, न वह कोई राजनैतिक लेख ही है, बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है।” लॉर्ड सेल्सवरी के इस वचन पर कि “प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रथा पूर्वी लोगों की परम्परा के मुताफिक नहीं है”, जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८९० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि “मुझे इस बात का कोई अन्देश नहीं है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अत में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।” बारहवें अधिवेशन (१८९६) के अध्यक्ष पद से मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने तो और भी असहिष्णुरूप में कहा कि “अंग्रेजों से बढ़कर ज्यादा ईमानदार और मजबूत कौम इस सूरज के तले कहीं नहीं है।” और जब कि उस कौम ने हिन्दुस्तानियों के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब उल्टा दमन से दिया, तब भी मदरास-कांग्रेस (१८९८) के अध्यक्ष आनन्दमोहन बसु ने जोर देकर कहा था, कि “शिक्षित-वर्ग इंग्लैंड के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। इंग्लैंड के सामने जो महान् कार्य हैं उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक मित्र और सहायक हैं।” हमारे इन पूर्व-पुरुषों ने अंग्रेजों और

इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रक्खा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है, परन्तु हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझें। डॉ० सर रास-बिहारी घोष के शब्दों में (२३ वी कांग्रेस, मदरास, १९०८) “अपने कोमल विचार उन तक में जिनहोंने अपने समय में अपने कर्तव्य का भरसक पालन किया है, फिर चाहे वह कितना ही अपूर्ण और कृटि-युक्त क्यों न हो, उनके बारे में अच्छी-दुरी रायें भी क्यों न हो। हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दबा हुआ हो, परन्तु मैं बिना शर्तों के कहूँगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे देखकर नीजवानों के दिल हिल उठते हैं और अनुप्राणित होते रहते हैं।” कांग्रेस के इतिहास में जो पहला जबरबस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षों (१९०६ से १९११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा जो उस समय जगली समझे गये। हालांकि उसमें दबर्-उबर् भार-काट भी हो गई, मगर अंत में उसमें पूरी सफलता मिली। आखिर १९११ में चाही घोषणा कर दी गई कि बगमग रद्द कर दिया गया। किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय बन गया। इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया और धुआधार वक्तृताओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा। श्री अम्बिकाचरण मुजुमदार ने कहा—“ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा-भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय आज एक तान से बटक रहा है, वह ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। हममें से कुछ लोगो ने तो कभी—अपनी मुसीबतों के अन्धकार-मय दिनों में भी—ब्रिटिश न्याय के अन्तिम विजय की आशा नहीं छोड़ी थी, उसपर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया था।”* परन्तु इसी के साथ कांग्रेसियों ने उन दुःखायी

* पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभक्ति की परेड दिखाने का शौक था। १९१४ में जब लॉर्ड गेण्टलैंड (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के पण्डाल में आये तो सब लोग उठ खड़े हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि श्री० ए० पी० पेट्रो, जो कि उस समय पर एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक शोक दिये गये और उनकी अगह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजभक्ति का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समूह भाषा में पेश किया।

ऐसी ही घटना सखनऊ-कांग्रेस (१९१६) के समय भी हुई थी, जब कि सर जैम्स मेस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था।

कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया था, जो कि १९११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे। कांग्रेस के बड़े-बूढ़ों ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने में लगाई थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय प्रश्न के अशो का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। १८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था—“स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है, प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रखी है—प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।” २० वें अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी कॉटन ने ‘भारत के संयुक्त-राज्य’ अथवा ‘भारत के स्वतन्त्र और पृथक् राज्यों के संघ’ की कल्पना की थी। दादाभाई ने मुनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्र किया था।

सरकार द्वारा कांग्रेसियों का सम्मान

कांग्रेस के पहले पच्चीस सालों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारो-मदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे। यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हैं, बल्कि स्वयं सरकार भी उनके साथ रियायतें करके और अब-जब हिन्दुस्तानियों को ऊँचे पद व स्थान देने का मौका आया तब-तब उन्हींको उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च पदों के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वाभावतः सबसे उपयुक्त था। मदरास के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में सामने आये और श्री बी० कृष्णस्वामी ऐयर १९०८ में हुई मदरास की पहली कन्वेंशन-कांग्रेस के एकमात्र कर्ता-वर्ता थे, जो बहुत कड़े विधान के मातहत हुई थी और जिसके लिए तत्कालीन मदरास गवर्नर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियों और कांग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थे कि जो अग सड़-गल कर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए। सर शकरन् नायर अमरावती में हुए अधिवेशन (१८९७) के सभापति हुए थे। और तो और पर श्री रमेशन् (सर वेपा सिनो) १८९८ से कांग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके बाद जिनका नम्बर आता है वे हैं (१) श्री टी० वी० बोधगिरि ऐयर, जो १९१० की कांग्रेस में सामने आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम् ऐयर, जो १९०८

में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छोहो मदरास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये—एक मदरास में और दूसरा दिल्ली में। इनमें से पहले (सर मुन्नहाप्प) १८९६ में कांग्रेस के समापति होनेवाले थे परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। श्रीमती वेंसेण्ट द्वारा चलाये गये होमरूल-आन्दोलन के समय, १९१४ में, यह फिर कांग्रेस के क्षेत्र में आ गये। यही नहीं, बल्कि अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही इनपर नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेंशन इन्हें मिलती थी उसे बन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्तु बाद में कुछ सोचकर फिर ऐसा किया नहीं गया। और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी कांग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की कांग्रेस में सामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के नये रजिस्ट्रार लेक्लि रहें सदा पहले से भी ज्यादा उत्साही, क्योंकि डा० वेंसेण्ट और उनके साथियों की मजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिज्ञापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे। सब तो यह है कि १९१७ और १९१९ के बीच कांग्रेसी क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज में चका-चाँक कर रखी थी। ये दोनों ही बाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही हाल सर मुहम्मद हुवीबुल्ला का हुआ, जिन्होंने पहले-महल १८९८ में कांग्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने बुद्धि-कौशल एवं वक्तृत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये। मदरास-सरकार के लॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १९०४ की कांग्रेस में बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० बी० रेड्डी तो १९१७ में जस्टिस-मार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एवं मुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रराव बहुत समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं। और असलियत यह है कि १९२१ में मदरास की कार्य-कारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्त पर विचार बदल दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अकेले मदरास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे। और हाल में टैग्गि-बोर्ड में श्री नटेमन की जो नियुक्ति हुई है उसने तो गंगामुनी क्षेत्रों में भी कांग्रेसियों के पसन्द किये जाने के उदाहरण भी बूझि हुई है, यही नहीं बल्कि सर गणेशराव चेंद्री को भी न्याय या धामन के विभागों में ही कोई पद देने के बजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी बात का

पोपक है। जो कांग्रेसमें इस तरह पुरस्कृत हुए उनमें सबसे पहले सम्भवतः श्री सी० जम्बुलिंगम् मुदालियर थे जो मदरास-कौंसिल के एक चुने हुए सदस्य थे और १८६३ में वहाँ के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे। बम्बई में श्री बदरुद्दीन तैयबजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनों, जो क्रमशः १८८७ की मदरास-कांग्रेस और १९०० की लाहौर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री काशीनाथ त्र्यम्बक तैलण बम्बई-हाईकोर्ट के जज बनाये गये। श्री समर्थ और भूपेन्द्रनाथ वसु भारत-सत्री की (इण्डिया) कौंसिल के सदस्य बनाये गये और सर भिमनलाल शीतलवाड को बाद में बम्बई की कार्यकारिणी कौंसिल का एक सदस्य बना दिया गया।

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी, जिन्होंने वग-भग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहाँ की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। १९०८ में जब लॉर्ड मिण्टो ने भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति लॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है कि, दो नाम उनके सामने थे—एक तो श्री आशुतोष मुखर्जी का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदा थे, पर वे सच्चे दिल से पुराणपन्थी, और सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा का, जिनके बारे में लॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हैं कि “उनके विचार तो सौम्य हैं परन्तु वह कांग्रेसी।” सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा १८६६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देवी नरेश को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह कांग्रेसमें को ही दी गई। इसी प्रकार १९२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई तब भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९२०) ने तो महाराजा बर्दवान को रखना चाहा पर मि० माण्टेगु ने बड़ी कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० माण्टेगु ने श्री श्री-निवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चूँकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री वी० एन० शर्मा को रक्खा—जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमृतसर-काण्ड के वक्त भी सरकार के पृष्ठ-पोषक बने रहे।

बंगाल में कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी ओहदे मिले उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मिश्र मुख्य हैं। इनमें श्री दास, जो १९०५ की कांग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रश्न पर

बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मिन महोदय बंगाल की कार्य-कारिणी के सदस्य।

युक्तप्रान्त में सर तेजबहादुर सप्रू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया गया। बिहार के सम्यद हसनइमाम १९१२ की कांग्रेस को पटना में आमन्त्रित करने के बाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सच्चिदानन्द सिंह को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहदों का देना ही नहीं रहा है। फिरोजशाह मेहता को १९०५ में 'सर' की उपाधि दी गई—और वह भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालकृष्ण गोखले ने तो 'सर' की उपाधि मजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनते—यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीधे-सादे, भारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ई० की उपाधि भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते।

श्री वी० एस० श्रीनिवास सास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉर्ड पेण्डलैण्ड ने मदरास-कौंसिल का सदस्य नामजद किया था। माष्ट-मोर्ट वासन-मुबारो का जमल शुरू होने पर उन्हें असेम्बली में नामजद किया गया, १९२१ में महाराजा कच्छ के साथ उन्हें साम्राज्य-परिषद् के लिए 'भारत का प्रतिनिधि' नियुक्त किया गया और उनके बाद ही वह प्रिवी-कौंसिलर बना दिये गये। इसके बाद वह अमरीका में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साम्राज्यान्तर्गत सभी उपनिवेशों ने उन्हें व्याख्यानो के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस मात्रा के लिए सरकार ने, ६०,०००) ६० का खर्च मंजूर किया था। १९२७ में वास्वीजी को ही दक्षिण अफ्रीका का सर्वप्रथम एजेण्ट-जनरल बनाकर सरकार ने मानो उस कमी की पूर्ति की, जो दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्राज्य का आधार-स्तम्भ बन गया।

यहाँ हमने कुछ ऐसे प्रमुख कांग्रेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार-द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। लेकिन इसपर से किसी को यह खयाल नहीं बना लेना चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च चारित्र्य का किसी भी प्रकार उनमें अभाव था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह बतलाने की ही गरज से दिये

गये हैं कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी है, और उनके राजनैतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के ओहदों के लिए नाकाबिल मान लेती ।

ब्रिटेन की दमननीति और देश में नई जागृति

भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्बी कहानी है। जब-जब कुछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब-जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तब-तब जोरो का दमन किया गया और उसमें यह नीति रखी गई कि जबतक लोग आन्दोलन करते-करते बिल्कुल थक न जायें तबतक उनकी मांगों पर कोई ध्यान न दिया जाय। लॉर्ड लिटन का १८७० का प्रेस-एक्ट जो जरूरी ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व-सूचना थी। राष्ट्र के बढ़ते हुए आत्मचेतन्य का दूसरा जवाब शास्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दुख-रूपी फोड़े को और भी पका दिया। १८८६ में इन्कमटैक्स एक्ट बना। उसका भी तीव्र विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देश की दृष्टि से देखने लगे। जिन लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनावें, किन्तु वही लॉर्ड डफरिन फिर कांग्रेस के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजद्रोही कहने लगे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर ऑकलैण्ड कॉल्विन के साथ इस विषय पर ह्यूम साहब की जो कतौ-किताबत हुई थी, वह ध्यान देने लायक है।

यद्यपि ह्यूम साहब के लिए यह आनन्द की बात है कि १८८६ में वाइमराय लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत किया लेकिन बाद के सालों में युक्तप्रान्त के सर ऑकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इमे शत्रु-भाव से देखने लग गये। इन महाशय ने कांग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी। सर ऑकलैण्ड की सम्मति में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मदरास के अधिवेशन से उग्र-रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार की निन्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में राजमत्त और देशभक्त ऐसे दो नेद खड़े हो जायेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जो

दावा करती है वह ठीक नहीं है। ह्यूम साहब ने इसका मुहताब् जवाब दिया।

इलाहावाद के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइयाँ हुईं। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली। श्रीमती एनी बेसेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के खिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,००० की जमानत माँगी गई थी। हालत तेजी से खराब होती गई और १८९० में सरकार का विरोध बहुत बढ गया। बंगाल-सरकार ने सब मंत्रियों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गस्ती-पत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि “भारत-सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओं में दखल-रूप में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग लेने की भी मनाही की जाती है।” कांग्रेस ने गवर्नर के प्राइवेट-सेक्रेटरी के पास सात ‘पास’ भेजे थे, वे भी लौटा दिये गये। २३ जून १८९१ को भारत-सरकार ने वेशी रियासतों के प्रेसों पर अनेक पाबन्दियाँ लगाने के लिए एक गस्ती-पत्र जारी किया। कांग्रेस ने १८९१ में इसका विरोध किया था।

दमन नीति का प्रारम्भ

१८९३ में काँसिलें और बड़ी कर दी गई और जनता के थोड़े से प्रतिनिधि—७ मदरास में, ६ बम्बई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ बंगाल में—उनमें ले लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की संख्या बढ जाने पर सरकार ने यह जरूरी समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जायें। (विस्तार के लिए दूसरे अध्याय का सरकारी नौकरियों सम्बन्धी प्रस्तावों के सारांशवाला प्रकरण देखें।) होम-वार्जेन का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पौण्ड से बढ़कर १३० लाख पौण्ड हो गया। १८९७ में १२४९ और १५३९ भाराये बनाई गईं। इनसे सरकार के प्रति सचमुच असंतोष पैदा हो गया। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि १०८ और १४४ भाराओं का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर ही किया गया। १८९७ में पूना के प्लेग-सम्बन्धी दंगे के प्रसंग में नातू-बन्धु बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८९९ में रिहा हो गये। फिर इसका आक्रमण बंगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये। २० वीं सदी के पहले पांच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी, सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी

नियन्त्रण में लाना जिससे शिक्षा सही हो गई, भारतीयों के चरित्र को 'असत्यभय' बनाना, बारह सुधारों का बजट, तिब्बत आक्रमण (जिसे पीछे से तिब्बत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त में बग-विच्छेद ये सब लॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई स्पिरिट पैदा हो गई।

बंगभंग

बंग-भंग ने बंगाली भाषाभाषी जनता को उनकी डक़्क़ानों के विरुद्ध दो प्रान्तों में बांट दिया था। इसके परिणामस्वरूप जहाँ जनता में एक व्यापक और जबर्दस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहाँ सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया। जुलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे—और उग्र सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़तालें होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों के नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया गया। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर बैम्फील्ड फुलर ने बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नागरिकों को बुला कर धमकी दी कि "सम्भव है खून-खराबी करनी पड़े।" इसके साथ ही पूर्वी बंगाल में गुरखा पलटन के आने की घोषणा भी की गई। यह सब तब हुआ, जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार 'जनता में हिंसा की भावना का बिह्वल तक नहीं पाया जाता था।' लेकिन जैसे-जैसे जोर से जमीन पर फेंको वह उतनी ही जोर से ऊँची उठती है और डोल को जितना ही पीटो उतना ही अधिक मादाज करता है, ठीक उसी तरह सरकार की उत्तरोत्तर उग्र और मजबूत दमन करनेवाली दमन-नीति के कारण नवजाग्रत बेतना भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी। सरकार का प्रत्येक दमन-कार्य देश में उलटा असर करता था। सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़कर आन्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया। 'क्रेनल काउन्सिलेशन बिल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता-कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी को अपना समापति चुना। दादाभाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अघगोरो की रोष-ज्वाला को और भी प्रचण्ड कर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा

राजनैतिक सभाओं व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ। केवल पूर्वी-बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाई-स्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'वंग-जातीय विद्या-परिषद्' की स्थापना की गई। बाबू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-वैतन्य का जोर शोर से प्रचार करने लगे। १९०७ में आन्ध्र देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-मज दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय सपान के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की बेरोक दमन-नीति ने देशभक्तों और वीर सिपाहियों को पैदा किया।

स्वदेशी और बहिष्कार

८२

१९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोरो से अमल भी किया। जहाँ कि बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, तहाँ स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इस बार करवे में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्थान उलटा बढ़ने लगा।

बंगाल के नेता

इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन बाबू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द बाबू भारत के राजनैतिक आकाश में बरसों तक उज्ज्वल

सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण में ही पले और अंग्रेजी स्कूलों और विषयविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। घुड़-सवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सर्विस में वह कोई जगह न पा सके थे। वह बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहाँ प्रायः युरोपियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एक बाढ़ की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई।

बंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये—कृष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, क्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनीकुमार दत्त, मनोरजन गुह, सुबोधचन्द्र भल्लिक, शचीन्द्रप्रसाद बसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। ये नेता बंगाल को और विशेषकर युवक बंगाल को संगठित कर रहे थे। पराक्रम और शौर्य उस समय के आवश्यक थे। दूसरी तरफ सर वैम्फील्ड फुलर का आदर्श 'गुरखा सेना' व 'यदि आवश्यक हो तो खून-खराबी' थे। १९०८ में स्थिति चरम सीमा को पहुँच गई थी। अखबारों पर मुकदमे चलाना एक आम बात हो गई। 'युगान्तर', 'सध्या' 'बन्देमातरम्' नई जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सब बन्द कर दिये गये। 'सध्या' के सम्पादक वेषामन्त ब्रह्मबाबु उपाय्याय अस्पताल में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से गुजरने के बाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पाकिस्तान चले गये और वहाँ आश्रम स्थापित करके रहने लगे।

पहला बम

३० अप्रैल १९०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियों—श्रीमती और कुमारी कैनेडी—पर दो बम गिरे। ये बम स्थानीय जिला जज किंसफोर्ड को मारने के लिये बनाये गये थे। इस अपराध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम बसु को फाँसी की सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलनेवाले 'युगांतर' के कालमों में हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस युवक को लम्बी सजा मिली, तो उसकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्ष प्रकट किया और 'बंगाल' की ५०० स्त्रियाँ उसे बधाई देने उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत में यह घोषणा की कि मेरे पीछे अखबार का काम सम्हालने के लिए २० करोड़ आदमी मौजूद हैं। इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूला-फला। राज-प्रोह

या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी बगीचत या छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते। 'बन्देमातरम्' में राजबिद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरविन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस सधाम में अपवाद न था। महाराष्ट्र में १३ जुलाई १९०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्ध्र में भी हरि सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकड़े गये। पाच दिनों की सुनवाई के बाद लोकमान्य तिलक को छ साल देश-निकाले की सजा मिली। १८१७ में छूटी हुई छ मास की कैद भी इसके साथ जोड़ दी गई। आन्ध्र के श्री हरि सर्वोत्तमराव को भी महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी। राजद्रोह के लिए पाच साल सजा देना तो उन दिनों मामूली बात थी। इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायब हो गया। वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह बम व पिस्तौल ने ले ली। १९०८ में राजद्रोही सभाबन्दी-कानून व 'प्रेस-एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल बाद फिमिनल लॉ एमेण्डमेंट एक्ट भी बन गया। सभाबन्दी बिल पर बहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि "युवक हाथ से निकले जा रहे हैं और यदि हम उन्हें बश में न रख सके, तो हमें दोष मत देना।"

कभी-कभी इनके-दुपके राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमें सबसे साहसपूर्ण खून १९०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन दाइली का हुआ था। यह खून मदन-लाल बिगडा ने किया था, जिसे बाद में फासी दी गई। अभियुक्त को बचाने की कोशिश करनेवाले डॉ॰ लालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फासी की सजा दी गई। लाहौर (१९०९) में होनेवाले कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के सभापति प० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओं तथा नासिक के कलक्टर मि० जक्सन की हत्या पर कुछ प्रकट किया। लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थक थे। मिण्टो-मॉर्ले सुधारों, या भारत-सरकार और मदरास व बम्बई की सरकारों की कौंसिलों में भारतीयों के लेने से भी यह बड़ा-बड़ा वैमनस्य शान्त न हुआ।

बंगाल रद्द

जबतक बग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तबतक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रोव जाता था। यदि वह आन्दोलन के

आगे एकवार भी झुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी। उसे डर था कि यदि एकवार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब बग-भग के कारण जो साप-छछूंदर की सी हालत होगई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूँढा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हाडिंग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड क्रू भारत-मंत्री बने, भारत में ब्रिटिश-नरेश जार्ज पचम के राज्याभिषेक-महोत्सव का लाभ उठाकर बग-भग रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आये।

जब यह कहा जाता है कि बग-भग रद्द कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि स्थिति यथापूर्व कर दी गई। पहले पश्चिमी बंगाल और आसाम-सहित पूर्वी बंगाल के रूप में बग-भग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। पहले बिहार को पश्चिमी बंगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और उड़ीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त बना दिया, अर्थात् आसाम के साथ पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के दो प्रान्तों के बजाय अब तीन प्रान्त हो गये—बंगाल एक प्रान्त, बिहार छोटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्याभिषेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को पृथक् प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया है। कहते हैं कि लॉर्ड हाडिंग ने दक्षिण अफ्रीका में शर्तबन्दी कुली-प्रथा को नष्ट कर तथा बग-भग को रद्द करके अपना दानम-काल स्मरणीय बना दिया, लेकिन वस्तुतः जिस घटना ने उनका शासन विस्मरणीय बनाया वह २५ अगस्त १९११ का खरीता था। यह खरीता ही भावी सुधारों का आधार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को बिना किसी न्यूनत्व के स्वीकार कर लिया था।

इन सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय कांग्रेस को था, यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस का वापिक अधिवेशन (कलकत्ता, १९११) बहुत खुशी के साथ मनाया जाता। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने, बंगाल को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च आशा प्रकट की थी कि “भारत जो अमान्य-प्राप्त राष्ट्रीय के स्वतन्त्र सघ-साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बनेगा।” लेकिन इन सब आशाओं और खुशियों में भी लोग राजद्रोही महात्वादी कानून १९०८, प्रेम-एन्ट १९०८ और ट्रिनिमल ला एमेण्डमेण्ट एक्ट (१९१०) को भूल नहीं थे। इन्हीं कागजों की आजादी की जट पर कुल्हाटा चला गया था। इन सबने बटकर १८१८ या रेग्युलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तों के रेग्युलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रु में १९०६-८

के देश-निर्वाहें जगह-जगह दिये गये थे। भारत में जननेपाले रुपये पर 'उत्सविक' भी अचानक मौजूद था। 'नारी दशरत्न' ज्ञान-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग-धंधों के दिन-रात में थे। उन सबने भी बराबर अवतक राजनैतिक कैदी जेलों में बन्द थे। 'गोमाला' निरन्तर मधुमेह रोग में ग्रस्त होकर अकेले और बिना किसी भिन्न के रैगिन दूना और धर्य के साथ मजाले के किले में कैद थे। उन समय श्री गोगले के प्रापमित्र मिधा-वित्र की बहुत चर्चा थी, जिनके पाग होने की उम्मीद बहुत कम थी। दण्डित अरुंको में भाग्यो की दुर्गी हालत थी जिनके लिए उन्नाव्यापी आन्दोलन की जरूरत थी।

१९११ में यह हाजिर थी। १९१२ में राजनैतिक गिरफ्तार कुछ-कुछ कम हो गया था। डेरिन जूनी वर्ष में एक भारी दुर्घटना हो गई। लॉर्ड हार्डिंग जब जुलूम के साथ हाथी पर नई गजघाना दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, निमीने उनपर बम फेंका, और यह मरने मरने लगे। उनपर बाकीपुर में कांग्रेस ने, महापति के भाषण के बाद, दण्डात्मक होने के गिरफ्तारों को तोड़कर, उग घटना पर दुःख तथा आक्रमण पर रोप-प्रणयन का तार लॉर्ड हार्डिंग के पास भेजने का प्रस्ताव पान किया। इस घटना के बाद प्रेम का और उद्योगता ने नियंत्रण होने लगा, जिसमें प्रेम-एक्ट को रद्द करने की लगातार आवाज ने भी १९१३ में जोर पकड़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती रही। १९०८ का प्रेम-एक्ट सबसे अधिक गराव था, जिसे १९१० में स्थायी कानून बना दिया गया। उन समय श्री सत्येन्द्रप्रमन्न सिंह भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर थे।

माण्टफोर्ड-मुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दमनकारी कानून रद्द कर दिये गये। बग-भग के रद्द किये जाने और हिसाबाद के घान्त हो जाने के बाद भी प्रेम-एक्ट में लोगों को सख्त तकलीफें झेलनी पड़ती थी। उद्योग राजनैतिक वातावरण में जो एक स्तब्धता और क्षान्ति आ गई थी, उसकी जगह १९१४-१८ के महामय की हलचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोषजनक घटना हो गई। बग-भग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदर्शों में अलग रहे थे और नीकरमाही पर अपना विश्वास जमा रखता था। १९१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वाशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" कांग्रेस ने १९१३ में मुस्लिम-लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

यूरोप में महासमर प्रारम्भ

जुलाई १९१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का दरवाजा सटसटा रहा था, लॉर्ड हार्डिंग ने वडे साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज बाहर भेज दी। इंग्लैण्ड बड़ी आफत में था। हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रखी गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की विफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या? लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया। मासेल्स में एक दिन भी आराम किये बिना ही हिन्दुस्तानी फौज फ्लाडर्स-रगकोत्र में, जहाँ अग्नि-वर्षा हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने गिगराष्ट्रो को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १९१५ के फरवरी-मार्च में उनपर आ जाती। १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया—“वर्तमान आपत्ति के वक़्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी व स्थिर बसावे और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहाँ और बाहर सजाद की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेषजनक भेदभाव है उसे दूर करे, २५ अगस्त १९११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को सय-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जरूरी हो वह सब करे।” हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं की कसा कितनी ऊँची थी।

: ५ :

हमारे अंग्रेज हितैषी

भारत के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यो और बड़े-बड़े अंग्रेजो ने भी अच्छा भाग लिया है। ह्यूम साहब ने कांग्रेस का संगठन तो बहुत बाद में किया था। इससे पहले ही पार्लमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लग गये थे। भारत के विषय में पार्लमेण्ट में जो चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भावना निस्वार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का खूब पक्ष-समर्थन किया। उन्होंने १८४७ में पार्लमेण्ट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग में बहुत उतार-चढ़ाव आये, पर ब्राइट साहब का भारत-प्रेम बराबर बना रहा। इनके बाद फॉसिट साहब की बारी आई। यह १८६५ में पार्लमेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की बड़ी-बड़ी नौकरियों की परीक्षाएँ केवल बिलायत में न होकर भारत और इंग्लैण्ड दोनों में साथ-साथ हों। १८७५ में इंग्लैण्ड में भारतवर्ष के स्वर्ण से तुर्कों के सुल्तान के लिए लॉर्ड सेल्सवरी ने जो नाच करवाया था इसकी फॉसिट साहब ने निन्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह हृदय से भारत के हितैषी बने रहें। इन्हीं विरोध से अबीसीनिया की लड़ाई का सारा स्वर्ण भारत के मत्ते न गड़ा जाकर आधा इंग्लैण्ड पर पड़ा। ड्यूक ऑफ एडिन-बर्ग ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोष से दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश युवराज की भारत-यात्रा के स्वर्ण के ४,५०,००० के भार से भी इन्होंने हमारे देश को बचाया। लॉर्ड लिटन ने कपड़े का आयात-कर बन्द कर दिया, दिल्ली में दरबार किया और अफगान-युद्ध भोल ले लिया था। इन करतूतों का फॉसिट साहब ने विरोध किया। कृतज्ञ भारत ने भी इन उपकारों का बूझदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ते की जनता ने इन्हे मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसिट साहब पार्लमेण्ट के चुनाव में हार गये तो आगामी चुनाव के लिए सहायताार्थ उन्हें १०,००० रु० से अधिक की थैली भेंट की गई।

ए० ओ० ह्यूम

ह्यूम साहब ने पार्लमेण्ट की भारत-समिति और कांग्रेस के सगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी और गैरसरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस में अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेध, देशी-भाषाओं के समाचार-पत्रों की उत्पत्ति, बाल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम किया। इन्हें किसी बात में रस था तो गांव और बंती में। इन्हें किसी बात की चिन्ता थी तो जनता की। इन्होंने घोषित किया था कि "सरकार तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतंत्र और सन्त्य सरकार की पायदारी और स्थायित्व तो इसीमें है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय।"

ह्यूम साहब के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन् १८५६ के अपने एक गवर्ती-पत्र में दिया। इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को भेजने की या पाठशालाओं की सहायतया करने की प्रेरणा न करें। ह्यूम साहब ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्क की चीज है। ह्यूम साहब का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुधार। उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को बिलकुल अलग-अलग कर दिया जाय। आवकारी के बारे में वह लिखते हैं —

"जहाँ एक ओर हम अपनी प्रजा का जागरण भ्रष्ट करते हैं, वहाँ दूसरी ओर हमें उसकी बरबादी से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता। यह सारी आय पाप की कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती है कि पाप की कमाई यो ही जाती है। आवकारी से हमें एक रूपया मिलता है तो उसके बदले में एक रूपया प्रजा का अपराधों के रूप में खर्च हो जाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लगा देना पड़ता है। अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीखती, किन्तु मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आशों से हमारे भारतीय शासन के इस बड़े भारी कलक को सच्चे ईसाई तरीके पर घुला हुआ देख सकूंगा।"

१८५६ के अन्त में ह्यूम साहब की सहायता से 'पीपुल्स-फ्रेण्ड' (लोक-मित्र)

नामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया। इसकी छ सौ प्रतिया सयुक्त प्रान्त की सरकार खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमयी के माफ़सत महारानी बिकटोरिया के पास भेजा जाता था। १८६३ में ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-गृह बनाये जायें। चुगी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुगी की लम्बी-घोड़ी रुकावटों को धीरे-धीरे दूर करवा दिया।

१८७१ ई० में ह्यूम साहब ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की। लॉर्ड मेयो की उसके साथ सहानुभूति भी थी। परन्तु वह योजना यों ही गई। मुकदमेवाजी के बारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाकों में किसानों को महाजनो की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेवारी दीवानी अदालतों पर है। उन्होंने सिफारिश की कि ग्रामवासियों के कर्ज के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहा-के-तहा निपटाने चाहिए, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गाव-गाव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के मुकदमे गाव के बड़े-बूढ़ों की सहायता से तय कर दिया करें। इन न्यायाधीशों पर कोई जास्ते या कानून-कायदे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

१८७० ई० से १८७१ तक ह्यूम साहब भारत-सरकार के मन्त्री रहे, परन्तु उन्हें वहाँ से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निन्दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई। लॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहब को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहब को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें खान-मान और राग-रस की जितनी झलक है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूसरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) बना दिया जाय। यह बात इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री लॉर्ड सेल्सवरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि ह्यूम साहब वाइसराय नॉर्थब्रुक को इस बात के लिए पक्का कर रहे थे कि कपड़े पर से आयात-कर न उठाया जाय। ह्यूम साहब ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। उन्होंने लग-भग तीन लाख रुपया पक्षियों के अजायबघर पर और लगभग साठ हजार रुपया 'भारत के शिकारी पक्षी' नामक ग्रन्थ की तैयारी में खर्च किया था।

सर विलियम वेडरबर्न

सर विलियम वेडरबर्न की सेवायें तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने

की भी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश कांग्रेस कमिटी को चलाने में वर्षों तक उन्हीं का मुख्य हाथ रहा। कांग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वार्षिक खर्च करती थी। वेटरनन साहब बम्बई में १८७६ ई० में, और इलाहाबाद में १६१० ई० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के संभापति हुए। जार्ज यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संभापति हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कांग्रेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे। इन प्रसिद्ध लोगों में से 'न्याय-निषेध के महान् प्रचारक' टल्ब्यू० एस० केडन साहब, जिसका कोई हिमायती न हूँ। उनके हिमायती चार्ल्स ब्रैडला साहब, सेम्युअल स्मिथ साहब और डाम्टर रुदरफोर्ड और क्लार्क साहब के नाम उल्लेखनीय हैं।

रैमजे मैण्डान्लड साहब तो १६११ में कांग्रेस-अधिवेशन का संभापति-पद भी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त हो जाने से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। केयरहाटी, होलफोर्ज, नाइट, मैकम्टन, कर्नल वैजवुड, वेनस्पूर, चार्ल्स रॉबर्टसन और पैथिक कोरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और कांग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८६ ई० में चार्ल्स ब्रैडला साहब का जो स्वागत किया गया वह शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने ने राजभक्ति की जो व्याख्या की वह बड़ी मार्क की थी। उन्होंने कहा, "जहाँ आख भूबकर आत्मा-पालन करने की वृत्ति होती है वहाँ सच्ची राजभक्ति का अर्थ तो यह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए कुछ करने को बाकी न रहे।" परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभक्ति की दूसरी ही है। उसके ख्याल से प्रजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए।

ब्रैडला साहब ने १८८६ में कौंसिलो के सुधार के लिए एक कानून का मसविदा (बिल) बनाया और उसे लोक-मत-संग्रह के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था और कांग्रेस ने भी ब्रैडला साहब के इच्छानुसार कुछ सूचनाये पेश की जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित होता था। आगे चल कर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पार्लमेण्ट में ब्रैडला साहब की स्थिति इतनी मजबूत थी कि लॉर्ड क्रॉस का पहला मसविदा भी ब्रैडला साहब के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मजूर हुआ जब उसमें प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सही, कौंसिलो में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

विलियम राबर्ट ग्लैडस्टन

विलियम राबर्ट ग्लैडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता। भारत में ग्लैडस्टन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी कांग्रेस आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहमति। उन्होंने १८८८ में कहा था, “इस महान् राष्ट्र की उठती हुई आकाशाधीन के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।” लगातार कई वर्ष तक ग्लैडस्टन साहब की वर्षगांठ पर कांग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ८२ वीं जयंती २६-१२-१८९१ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ के प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने आयर्लैंड की भांति भारत के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थन किया था। ग्लैडस्टन साहब भारत के एक हिताधीन समझे जाते थे और अर्बले नॉटन साहब ने १८९४ की दसवीं कांग्रेस के अवसर पर उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था—“मेरा विश्वास है कि पार्लियामेंट की अनजान में, देश को बताये बिना ही कौंसिल के एकान्त कमरों में, अकस्मात् एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता सर्वथा नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून ब्रिटिश-साम्राज्य के लिए कलक है।” जब १८९८ में ग्लैडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया।

लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८९३ के अपने नवें अधिवेशन में कृतज्ञता प्रकट की। इन्होंने पार्लियामेंट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से ‘होम-वार्जेन’ के नाम पर जो विशाल धन-राशि खिंची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय। यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख ड्यूक ऑफ आर्जाइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि “भारत में आम लोगों को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही वह कष्ट दूर कर दिया जाना चाहिए।” सार्वजनिक प्रश्न पर ड्यूक साहब बड़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। वाक्ता महोदय ने कांग्रेस के १७ वें अधिवेशन में उनके इस कथन को दोहराया था कि “प्राचीन भारत की विशाल जन-संख्या में जितना चिर-दारिद्र्य फैला हुआ है और उनके जीवन-साधनों का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाहरण पाश्चात्य जगत् में कहीं नहीं मिलता।” इन्हीं ड्यूक महोदय ने १८८८ में कहा था कि “अंग्रेजों ने अपने दिये हुए वचनों और किये हुए करारनामों का पालन नहीं किया।”

इन हिताधीनों में एक थे एल्डले के लॉर्ड स्टैनले। उन्होंने अपने जीवन का उत्तम

भाग भारत में ही व्यतीत किया और भारत के अम्युत्थान के लिए प्रारम्भ किया। १८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कौंसिल को उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यदि भारत-मंत्री पर कौंसिल का नियन्त्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा दो। यदि कौंसिल पर भारत-मंत्री का नियन्त्रण रहे तो कौंसिल को मिटा दो। यह द्विविध-शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और बाधक है।" उन्होंने भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये।

सर हेनरी काटन

इस संक्षिप्त विवरण में सर हेनरी काटन और उनकी अमर सेवाओं का उल्लेख किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। काटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सम्बन्ध रहा था। ज्योही आसाम के इन चीफ कमिस्नर साहब ने पेंशन ली त्योंही कांग्रेस ने अपने १९०४ वाले बम्बई के अधिवेशन का समापति-पद ग्रहण करने को इन्हें आमन्त्रित किया। इन्होंने पहले-पहल भारत के संयुक्त राज्य की कल्पना की थी।

हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग

कांग्रेस की नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने से पहले हमें उन महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन की शुरुआत की और कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर तैयार किया। आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत संगठन और महान् राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, हम शायद यह समझे कि यह सब हमारे ही वक्त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के कांग्रेसियों को आनन्द पसन्द भी न हो, इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता। लेकिन हमें यह हर्षित न भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी कर सके हैं और करने की आकांक्षा रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान् बलिदानों के फलस्वरूप ही। इसलिए उन बुजुर्गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं और जो ईश्वर-रूप से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं उनकी महान् सेवाओं और कुरबानियों का यथा उल्लेख किये बिना हम आगे नहीं चल सकते।

दादाभाई नौरोजी

कांग्रेस के बटे-बूढ़ों की सूची में सबसे पहला नाम दादाभाई नौरोजी का आता है, जो कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को सर्वसाधारण की शासन-सम्बन्धी शिकायतों दूर कराने का प्रयत्न करनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढ़ाते स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १९०६) के निश्चित उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिषद् पर पहुँचा दिया। १८८६, १८९३ और १९०६ में—तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए, और बराबर कांग्रेस के साथ रहते हुए इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के झण्डे को ऊँचा रखा। दूसरी बार उन्हें जो कांग्रेस का सभापति चुना गया, वह सेण्ट्रल फिन्सबरी से उनके

कामन-सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में था, क्योंकि उस समय इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख ददं दूर कराने के लिए लन्दन में आन्दोलन जारी किया जाय। १८६१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश हुआ, कि जबतक लन्दन में अधिवेशन न हो ले तबतक कांग्रेस को स्थगित रक्खा जाय, लेकिन वह अस्वीकृत होगया। ठीक इसी समय ह्यूम साहब इंग्लैण्ड जानेवाले थे, और इसी समय के लगभग कामन-सभा में भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजेजाने की भाग भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी बार कांग्रेस के सभापति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठाकर ब्रिटेनवालों को इस बात की प्रेरणा दी, कि वे "इस शक्ति (शिक्षित भारतीयों) को अपनी ओर खींचने के बजाय अपने से दूर न फेंकें—अपना विरोधी न बनावें।" ब्रिटिश-राज्य की न्यायपरायणता में दादाभाई का बहुत विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा। १९०६ में दादाभाई फलकते के अधिवेशन के सभापति हुए। उस समय हिन्दुस्तान मानो एक खोलते हुए कढाव में था, १६ अक्तूबर १९०५ को जो वग-मग किया गया था, उससे देश-भर में एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी बंगाल असन्तोष से उबल रहा था। हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाड़ा जा रहा था। विशेष कानूनों (अभिनेसों) का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी पुलिस की तैनाती का नया क्रम चला। दादाभाई ने बताया कि १८६३-६४ के बाद जन-संख्या तो १४ प्रतिशत ही बढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिशत बढ़ गया है, और १८८४-८५ से ले तब तो जहाँ जन-संख्या १६ प्रतिशत बढ़ी है वहाँ यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा है। १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अफेला सैनिक व्यय ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैण्ड में किया जाता था। इस अस्ती बरस के बूढ़े ने ६,००० मील दूर (इंग्लैण्ड) से यहाँ आकर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा कर दी, यह देखकर 'इंग्लिशमैन' इनपर उबल पड़ा था। लेकिन भारतीय भागों के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप साफ हो रहा था। १९०५ में गोखले ने स्व-शासन की ओर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १९०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर लिये गये।

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवामें अपनी सारी जिन्दगी लगा दी, भारत की मुक्ति के लिए अविश्रान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छुट्टी नहीं दी, और जिसे विद्याता ने ८५ वर्ष से अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रक्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोड़े-से स्थान में नहीं किया जा सकता। दादाभाई तो

हमारे ऐसे बुजुर्गों हि जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मबलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण, बल्कि अपनी पोतियों के रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हैं—क्योंकि, उनकी पोतियां उनके द्वारा खलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भलीभांति कायम रखे हुए हैं।

आनन्द चार्लू

कांग्रेस के पहले अविवेक में, जो १८८५ में बम्बई में हुआ था, सम्पादक जी० मुब्रह्मण्य ऐयर और श्री आनन्द चार्लू, काशीनाथ तैलंग और दादाभाई नौरोजी नरेन्द्रनाथ सेन और उमेशचन्द्र बनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रंगया नायडू, फिरोजशाह मेहता और डी० एस० ब्हाइट—इन सब प्रमुख व्यक्तियों ने, जो कि कांग्रेस के जनक और बड़े-बूढ़े थे, अपने भाषणों में उन शक्तियों का परिचय दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में, इन्हींसे भारत का नरम-दल बना। आनन्द चार्लू ने जो वाद में १८९१ की नागपुर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, अपनी विशेष वक्तृत्व-शक्ति के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर में हुए ७ वें अविवेक (१८९१) का इन्होंने सभापतित्व किया, जिसमें सभापति-पद से बड़ा जोरदार भाषण किया।

दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई ज्योति रहे। हालांकि न तो इनके अनुयायियों का कोई दल था और न यह किसी राजनैतिक मत के प्रवर्तक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्वशक्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है।

वीनशा एदलाजी वाचा

हमारे इन आदरणीय बुजुर्ग का खास विषय कौनसा था, जिसपर इन्हें विशेष प्रेम और अधिकार था, यह कहना कठिन है, क्योंकि प्रायः सभी विषयों में इनका एक समान अवाज प्रवेश था। इनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अविवेक में झलकने लगे थे, जबकि इन्होंने अपने महान् भाषणों में का पहला भाषण करते हुए सैनिक परिस्थिति का योग्यतापूर्ण विस्तृत सिद्धान्तलोकन किया। दूसरे अविवेक में इन्होंने भारतवासियों की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर साल ब्रिटेन को जानेवाले उस सराब की ओर सर्वसाधारण का ध्यान खींचा जिससे ब्रिटेन तो समृद्ध हो रहा था पर हिन्दुस्तान कगाल बनता चला जा रहा था।

“भारत की विशाल जन-महत्वा में लगातार बढ़ती जानेवाली गरीबी” का सल्लेख करके, इन्होंने बताया कि “१८४८ से बराबर इसी प्रकार रैयत की हालत विगड़ती गई है—यहां तक कि ४ करोड़ लोगों को दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन नमीव होता है, और वह भी हमेशा नहीं।” इसका मुख्य कारण, इन्होंने बताया था देश की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों में चला जाना।

बाबा इतने चतुर थे कि अपने बहुत पहले १८८५ में ही, इन्होंने लकाशायर का प्रश्न उठा लिया था। इन्होंने कहा था कि “अगर सैनिक-व्यय कम न किया जाय तो इसके लिए बाहर से आनेवाले माल पर फिर से तट-कर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मामी दरिद्रता-ग्रस्त भारत लुटा जा रहा है। और वह भी इसलिए कि माल-बार लकाशायर और समृद्ध बनाया जाय।”

१८६४ में फिर बाबा ने “लकाशायर के लिए भारतीय हितों का बलिदान करने के अभिप्राय से, भारत के मुरु होते हुए मिल-उद्योग को कूचलने के लिए भारतीय मिलों के (मूती) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय” पर नजर डाली। उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) विल का विरोध करने के लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशंसा की और भारत-मंत्री को इस अन्याय-पूर्ण कार्य के लिए दोषी ठहराया। सैनिक-व्यय की जाच के लिए नियुक्त छाह्री कमीशन के सामने, जो कि आमतौर पर बेल्टी-कमीशन के नाम से मशहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से उनकी प्रसिद्धि बढी जिसके लिए कांग्रेस और मोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी सारीफ की। १८६७ में बाबा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में सरकार की सरहद्दी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (सुखनल १८६९) में भी इन्होंने मुद्रा-नीति पर अपना हमला जारी रखा और भारत में सुवर्ण-माल जारी करने की निन्दा की। “हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कारण तो,” इन्होंने कहा, “यहां के धन का हर साल यहां से बाहर चला जाना है। फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही है। रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका मूल्य वहीं रहने दिया गया है। जहां पहले १) तोला चांदी विकती थी वहां अब सिर्फ ॥३) या ॥६) तोला विकने लगी है।” १८७१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में राष्ट्र ने बाबा को कांग्रेस का समापति बनने के लिए आमंत्रित किया।

१८८६ से लेकर १८९३ तक बाबा कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-मंत्री रहे हैं। इसके बाद उसके काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे। १८९५ की बम्बई कांग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्वागतार्थ्यक्ष थे, वस्तुतः यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये

मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक समस्या जैसे दुल्ह विषयो एव सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओं की भली-भाँति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई था ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े ही आदमी थे।

गोपाल कृष्ण गोखले

गोखले पहले-पहल १८८६ में कांग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होंने बहुतेरे तथ्य और आकड़े पेश किये थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पाच आने हो जाती है। फिर भी उनमें कटी-से-कटी बात को बहुत ही मधुर भाषा में कहने का बड़ा गुण था। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मधुर और मञ्जुल होते थे तथापि वह कहते थे बात सरी, गोलमोल बातें करना उन्हें पसन्द न था। “नगे, भूले, झुर्रियो पडे हुए, ठिठुरते और सिकुडते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मेहनत करनेवाले, चुपचाप धीरे-धीरे के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने घासको के पास जिनकी आवाज बरा भी नहीं पहुँचती और ईश्वर तथा मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी बोझ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे बिना चीन्चपड किये सहने के लिए सदा तैयार किसानों के लिए” गोखले के हृदय में प्रेम का स्थान था और इन्हीं के हित में वह हमेशा कर और खर्च के सवाल को उठाया करते थे। लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते थे जब गोखले की सयत और लोक-प्रचलित विनम्रता भी उनका साथ छोड़ देती थी और लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो ओर पडा था वह दरअसल बहुत भारी था। बग-अग, कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विश्वविद्यालय-सुधार जिसके द्वारा कार्य की शुचायता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियंत्रण कर देना और शिक्षा को खर्चीली और महुँगी बना देना, आफिगियल सिन्क्रेट्स एक्ट—इन सब ने मिल कर लॉर्ड कर्जन के सत्कार्यों को भी, जैसे उनकी अकाल-सम्बन्धी नीति, शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्मृति-रक्षा कानून, रगून और ओगारा प्रकरण में सजायें देना, घर दबाया। गोखले को बहुत दिगडकर कहना पडा था, “तो अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोक-हित के लिए नौकरशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आशाओं को नमस्कार।” १९०५ में बनारस-कांग्रेस के समापति की हैसियत से गोखले ने राजनैतिक दृष्टि के रूप

में बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रबल लोक-भावनायें इसके अनुकूल हों। गोखले सामनेवाले के साथ बड़ी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था।

१९०५ और १९०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैण्ड भेजे गये थे। हा, १८९७ में भी वह इंग्लैण्ड जा चुके थे। जनता और सरकार दोनों के बीच गोखले की स्थिति विषम रहती थी। इधर लोग उनकी नरमी की निन्दा करते थे, उधर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बन कर रहते थे। गोखले जनता की आकांक्षायें वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयाँ कांग्रेस तक।

पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यो-ज्यो गोखले की उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों वह शिकायत करने लगे कि 'नीकरशाही स्पष्ट स्वार्थसाधु और कुल्लमकुल्ला राष्ट्रीय आकांक्षानो के विरुद्ध होती जा रही है। पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था।' उन्हें पश्चिम का पूँजीवाद उतना नहीं अखरता था जितना जातिगत प्रभुत्व, धरिद्रनाश, ब्रह्म-शोषण और भारत की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या।

गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे राजनैतिक कार्य-कर्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेतन पर मातृ-भूमि की सेवा करने का प्रण लिया है।

सूरत के झगड़े के बाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया। वह दक्षिण अफ्रीका भी गये और वहाँ गाँधीजी के सत्याग्रह-संग्राम में अपूर्व सहायता की। १९०९ की कांग्रेस में तो उन्होंने सत्याग्रह-धर्म की बड़ी प्रशंसा की थी और उनके तत्त्व को बड़ी खूबी के साथ समझाया था। उसके बाद उनकी प्रवृत्तियाँ मुख्यतः बड़ी कौंसिलों के अखाड़े में ही होती रही हैं। १९१४ में जब कांग्रेस के दोनो दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने उसे पसंद किया था, परन्तु बाद को अपना विचार बदल दिया था। इस तरह उत्कट देशभक्ति, देश के लिए पड़ोस परित्यग, महान् स्वार्थत्याग और देश-मेवाभय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १६ फरवरी १९१४ को इस लोक से प्रयाण कर दिया।

जी० मुग्रमल्लय मेयर

कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव विनाने पेश किया, यः

जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मदरास के श्री जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, जो सर्वसाधारण में सम्पादक सुब्रह्मण्य ऐयर के नाम से मशहूर थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया, और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जाच एक ऐसे गाही-कमीशन द्वारा होनी चाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। पश्चात् मदरास में होनेवाली १० वी कांग्रेस (१८९४) तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के बारे में कुछ नहीं सुनते। पर मदरास-कांग्रेस में भारतीय राजस्व के प्रश्न पर यह बोले और इस सम्बन्धी जाच करने की आवश्यकता बतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-राज्यों में अन्वेषण की स्वतन्त्रता का अपहरण, जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १८९६) में इन्होंने प्रतिस्पर्द्धी-परीक्षायें इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली जाने की आवाज उठाई, और साथ ही लगान के भियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया। अगले साल, अमरावती-कांग्रेस में, सरकार की सरहद्दी-नीति का विरोध किया। १८९८ में जब तीसरी बार मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो श्री सुब्रह्मण्य ऐयर ने सरहद्दी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की और युद्ध-नीति का भी जोर विरोध किया था। परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था भारत की आर्थिक स्थिति। लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में इन्होंने बार-बार पड़नेवाले अकालों को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयों की आर्थिक अवस्था की पूरी और स्वतन्त्र जाच कराने के लिए कहा। साथ ही सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों को उनसे महत्त्व रखने की शिकायत की। १७ वें अधिवेशन में (कलकत्ता, १९०१) रैयत की बुर्दशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा—“क्या हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी जानवरों की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए है? और मनुष्यों की तरह क्या उनमें बुद्धि, भावना और छिपी हुई शक्तियां नहीं हैं? लगभग २० करोड़ व्यक्ति आज लगातार भुखमरी और घोर अज्ञान का दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न तो वे कुछ बोल सकते हैं न उनकी जिन्दगी में कोई उत्साह है, न उन्हें किसी तरह की सुविधा है न मनोरंजन, न उनकी कोई आशा है न महत्त्वाकांक्षा, वे तो दुनिया में पैदा हो गये इसीलिए किसी तरह जी रहे हैं, और जब मरते हैं तो इसलिए कि उनका शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को चारण नहीं कर सकता।” अकालों के प्रश्न पर भी इस कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया। इसके लिए कला-कौशल की सव्धार्यें कायम करने, छात्र-वृत्तियां देकर भारतीयों को

इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-वधों की भली-भाँति जाच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये।

सुब्रह्मण्य ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विशाल उनका दृष्टि-कोण था। अपने लेखों की बदौलत इन्हें जेलखाने की हवा खानी पड़ी थी, वहाँ से बीमार हो जाने पर ही इन्हें रिहाई मिली। इनमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राजनीतियों में यह अत्यन्त निर्भीक और दूरन्देज थे, जिसके लिए आवी सन्तति सदा इनकी कृत्त रहेंगी।

बदरुद्दीन तैयबजी

बदरुद्दीन तैयबजी एक पक्के कांग्रेसी थे, जो बटते-बड़ते कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन (मदरास, १८८७) के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिये हुए अपने भाषण में इन्होंने कांग्रेस के प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया। इन्हींके कहने पर इस काम के लिए एक समिति बनाई गई थी कि वह कांग्रेस में वाद-विवाद के लिए जो बहुत से प्रस्ताव आँवें उनपर विचार करके कांग्रेस का कार्यक्रम निश्चित करे। इस समिति को बस्तुतः वाद को बननेवाली विषय-समिति का पूर्व-रूप कहना चाहिए। बाद में यह चम्बई-हाईकोर्ट के अज हो गये थे। १९०४ में सरकारी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव की बहस में इन्होंने भाग लिया। १९०६ के प्रारम्भ में इनका स्वर्णवास हो गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू (उमेशचन्द्र बनर्जी) ने किया था, दूसरे के सभापति पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थे। इसके बाद तीसरे अधिवेशन के सभापति तैयबजी को बनाना खास तौर पर उचित था, क्योंकि यह मुसलमान थे।

काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग

जस्टिस काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग कांग्रेस के अत्यन्त कर्तव्यशील स्थापकों में से थे और उसके "बम्बई में, सबसे पहले डटकर काम करनेवाले मंत्री" रहे हैं। कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में इन्होंने बड़ी (यूरोपीय) और प्रांतीय कौंसिलों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक-मण्डलों की एक योजना पेश की। चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार को अपने विभिन्न कामों के लिए तो हमेशा रुपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह अपनी आनदनी का निरर्क १ प्रतिगत ही खर्च करती है। १८९३ में असमय ही इनकी मृत्यु हो गई।

उमेशचन्द्र बनर्जी 31679

यदि प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि कांग्रेस का आरम्भिक उद्देश क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के समापति उमेशचन्द्र बनर्जी के भाषण की ही ओर निगाह दी जानी पड़ेगी। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद (१८६२) के आठवें अधिवेशन में वह दुबारा कांग्रेस के समापति हुए थे। यह याद रहे कि १८६१ में सहवास-विल के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्र बनर्जी ने इलाहाबाद में अपने भाषण में बड़े कारण बताये थे जिनसे कांग्रेस ने अपने को सामाजिक प्रश्नों से अलहदा रक्खा था।

अपने देश की बहुत प्रशसनीय सेवा करने के बाद १९०६ में इनका स्वर्गवास हुआ।

लोकमान्य तिलक

लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के विना.ताज के बादशाह थे और बाद में, होम-रूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपस्वियों के द्वारा ही वह इस दर्जे को पहुँचे थे।

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। सारे महाराष्ट्र में शिवा-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्सव के साथ सभायें भी होती थी। पहली ही सभा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये थे। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८६७ को कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८६८ को छोड़ दिये गये। अध्यापक मैक्स-मूलर, सर विलियम ह्यूटर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई नौरोजी ने एक दरखवास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहते हुए साजिरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफायें नई जोड़ी गईं, जिससे कि वह कानून के शिकवे में फँसाये जा सकें।

अमरावती-कांग्रेस (१८६७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव-द्वारा जो बात न हो सकी वह समापति सर शकन् नायर और सर भुवेंद्रनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान् और विद्वान् पुरुष की बहुत

प्रशंसा की, जो कि उस समय जेल में सड़ रहा था। इससे तिलक की कीर्ति शिखर पर पहुँच गई थी।

१८९६ से ही तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती दिखलाये। १८९९ में जब वह लॉर्ड सेण्डर्स की निन्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का तूफान खड़ा हो गया था। उन्होंने दर्शकों को यह सावित करने के लिए चुनौती दी कि लॉर्ड सेण्डर्स का शासन प्रजा के लिए सत्वानाशी नहीं था। उन्होंने नौकरशाही की करतूतें साफ-साफ सामने रखीं और पूछा कि बताओ, इनमें कहाँ अत्युक्ति है? परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि समापति थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिलक ने कहा कि वह इस विना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते, और वह अपने पक्ष में अध्याय और बाराबो के उदाहरण देने लगे, तो समापति ने यहाँ तक कह दिया कि यदि तिलक इसपर अड़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा।

सूरत (१९०७) में कांग्रेस के दो टुकड़ों का हो जाना उस समय बड़ी चर्चा का विषय हो गया था। लोकमान्य तिलक उसमें सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे और कहा जाता था कि इन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की बातें कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खुद कलकत्ते में ही नरम और गरम दल के नेताओं का मतभेद प्रकट होने लगा था, लेकिन बाबाभाई नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा गया था। वही १९०७ में जाकर प्रबल हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने का कारण यही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दलवालों ने जान-बूझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के लोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक समापति हों, परन्तु नरम दल के लोग इसके विरोधी थे और उन्होंने अपने विधान के अनुसार डॉ० रासबिहारी घोष को चुन लिया। इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया। उन्होंने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से लौटकर आये हैं, जिससे उनका नाम और भी बढ गया है और वह बिना विरोध के चुन लिये जायेंगे, परन्तु लाला लाजपतराय ने उस समय बड़े आत्म-त्याग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया। जब प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तब लोकमान्य ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को बलहदा कैम्प में जमा किया। मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी, मगर गलतफहमिया बढती ही चली गई। गरम-

गुजर चुका है कि दोनों दलों की बातों पर कोई राय बनाई जा सकती है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों का दृष्टि-बिन्दु जुदा-जुदा था और हर दल उत्सुक था कि कांग्रेस उसके दृष्टि-बिन्दु को मान ले। परन्तु जिस बात पर लोकमान्य तिलक मच पर खड़े हुए वह मामूली थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कलकत्ते में स्वीकृत विधान के अनुसार स्वागत-समिति सभापति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते तो हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं उस अवस्था में कोई सशोषण या सभा को स्वगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। तब उन्होंने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा। हम यह नहीं कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गलत था। साथ ही यह कहना पड़ेगा कि महज गलतफहमी के कारण लोगों के मनोभाव बहुत बिगड़ चुके थे, क्योंकि यह भ्रम पैदा हो गया था कि कलकत्तेवाले प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे। पर अगर वे नहीं भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम बलवालों को सशोष होता तो विषय-समिति में, यदि उनका बहुमत होता, उनमें फेर-फार कराया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसने इतना भारी काण्ड होने दिया जाय। यदि दोनों दल के नेता आपस में खुलकर बातचीत कर लें तो वह दोनों की स्थिति साफ करने के लिए काफी हो जाता और तब उचित फैसला कर लिया जाता, परन्तु कुछ नरम नेताओं की तगदिली ने गायब ऐसा नहीं करने दिया। हा, घटनाएँ घटने पर तो अकल आसानी से आ जाती हैं, किन्तु जब मनोभावों पर चोट पहुँची हुई होती है तब बड़े-बड़े लोग भी अपनी समता को देते हैं। अब यदि हम लोकमान्य तिलक और गोखले जैसी के बारे में यह कहें कि इसमें किसका कितना दोष था तो हमारे हक में वह विवेक-हीनता ही होगी। और इसलिए, हम अब इस 'अव्यापारेण व्यापार' में न पड़कर, दोनों नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्वटना को छोड़कर आगे चलते हैं।

लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की मर्यादाओं को वह जानते थे। १९१८ में सर वेलेण्टाइन क्रिरोल पर मुकदमा चलाने के लिए वह इंग्लैंड गये। सर वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उनपर मानहानि का दावा किया था। इंग्लैंड में उन्होंने मजदूर-दल पर इतना भरोसा रखा कि उन्होंने ३ हजार पौण्ड मँट किया। उन्होंने मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना बल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो जायगा। इससे पहले के

राजनीतिज्ञ अनुदारदलवालो की वनिस्वत उदारदलवालो पर बहुत भरोसा रखते थे, परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझकर जबदूर-दूर को मानते थे। उस पुराने युग में एक लोकमान्य तिलक ही थे जिन्हें लगातार जेलों में तथा अन्यत्र कष्ट-ही-कष्ट भोगना पड़ा। यहाँ तक कि जब १९०८ में जब ने उनको नज़ा दी और उनके बारे में खरी-खोटी बातें कह कर पूछा कि आप-को कुछ कहना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर में स्वर्णसिरो में लिप्यकर रखने योग्य है — “जुरी के इस फ़ैसले के वाजुद मैं कहता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। ससार में ऐसी बड़ी शक्तियाँ भी हैं जो सारे जगत् का व्यवहार चलाती हैं और मभव है ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-सहन से अधिक फूल-फले।” * ऐसी ही तेजस्विता उन्होंने १८९७ में दिखलाई थी जब कि उनपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह अदालत में यह सब बात कह दें कि ये सब मेरे लिखे नहीं हैं। (१९०८ में जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कतई इनकार कर दिया और कहा—“हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जबकि हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते, बल्कि हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है।” “उन्होंने बड़ी धार्मिक और अनासक्ति के साथ इन सजावों को भुगतता और जेल में बैठे-बैठे वहाँ भव्य ग्रन्थों की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो ‘आर्यसमाज’ ‘होम ऑफ़ दी बैदाज’ और ‘गीता रहस्य’ वह सबभत राष्ट्र के लिए अपनी परम्परा नहीं छोड़ जाते। लोकमान्य जुलाई १९१८ में बम्बई की युद्ध-सभा में बुलाये गये थे और वह वहाँ गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये गये। बात यह थी कि वह लॉर्ड विलिंगडन की उन बातों का जवाब देने लगे थे जो कि उन्होंने होमरूलवालों के खिलाफ कही थी।

जब १८९६ में गांधीजी पूना गये और दक्षिण-अफ्रीका-वासी भारतीयों के

* उन्होंने किसीने इस भाव को इन कवियों में व्यक्त किया था—

“इस जुरी ने यद्यपि मुझको अपराधी ठहराया है,

तो भी मेरे मन ने मुझको निर्दोषी बतलाया है।

ईश्वर का सफेत मनोगत दिखलाई यह मुझे पडे,

मेरे संकट सहने से ही इस हलचल का तेज बडे।”

सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी। गांधीजी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान्, उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पड़े, लेकिन गंगा की पवित्र धारा की तरह, जिसमें वह बासानी से मोता लगा सकते थे। तिलक और गोखले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था, परन्तु दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी। यदि हम स्पूल आपा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले 'नरम' थे और तिलक 'गरम'। गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नीकर-शाही के साथ काम करना पड़ता था, तो तिलक की नीकरशाही से भिन्न रहती थी। गोखले कहते थे—जहाँ सभव हो सहयोग करो, जहाँ आवश्यक हो विरोध करो। तिलक का झुकाव अद्विजा-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तहाँ तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहाँ तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना। गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले उन्मत्त और वृद्धि-वादियों की तरफ देखते थे, और तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर। गोखले का अखाड़ा था कॉन्सिलमन, तो तिलक की अदालत थी गांव की चौपाल। गोखले अंग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक भराठी में। गोखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिसके योग्य लोग अपने को अंग्रेजों की कमीदियों पर कसकर बनावें, किन्तु तिलक का उद्देश्य था 'स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारत-वासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाधा की परमाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे।

पं० अयोध्या नाथ -

दुर्गात के कांग्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊँचा था। १८८८ में हुई उल्लाहाबाद-कांग्रेस के, जो मि० जार्ज यूट के मनापनिम्न में हुई थी, वह स्वायत्ताध्यक्ष थे, तभी में कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क शुरू होता है। गैर-रसी धार में जब कि से, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ (१८९२) तो तबसे भी उनका सम्पर्क बढ़ा। पं० अयोध्यानाथ का

स्मारक उनके पुत्र प० हृदयनाथ कुजूरू हैं, जिन्हें वतौर विरासत वह राष्ट्र की भेंट कर गये हैं।

• सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की भात्मा का एक प्रमुख स्थान है। ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा। भारत में कांग्रेस के भ्रम से उठी उनकी बुलन्द आवाज सम्य ससार के दूर-दूर के कोने तक पहुँचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित हुंकार, इन गुणों में उनकी वक्तृत्व-कला को पराजित करना कठिन है—आज भी कोई उनकी समता तो अलग, उनके निकट भी नहीं पहुँच सकता। उनके भाषणों का मसाला होता था अपनी राजभक्ति की दुहाई। उन्होंने इसे एक कला की हद तक पहुँचा दिया था। उन्होंने दो बार कांग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था—पहली बार १८९५ में पूना में और दूसरी बार १९०२ में अहमदाबाद में। कांग्रेस में प्रतिवर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयों पर विविध प्रस्ताव लाये जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकी पहुँच के बाहर रहता हो। फौजी विषयों में रूस १९ वीं सदी के अन्त में बरसों तक हूँवा बना रहा है। परन्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जबाब दिया वह याद रखने योग्य है—“रूस की चढाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-बीड़ा और अगम्य पर्वत नहीं, जो बीच में बनाकर खड़ा कर देना है, बल्कि वह तो सब तरह सन्तुष्ट और राज-भक्त लोगों का दिल है।” सुरेन्द्रनाथ ने तो यहाँ तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी दल को अपना विषय बना लेना चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के बाहर समझी जाती है। उन्होंने कहा—“राजनैतिक कर्तव्यों के उच्च क्षेत्र में इरलैण्ड हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है।” उनका आदर्श था ब्रिटिश सम्बन्ध के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना। उनके इन तथ्यात्मक विश्वासों, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो के वाइसराय-काल में बरीसाल में उनपर लाठी चलाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बंगाल का मंत्री बनना था, इसलिए बच गए।

पण्डित मदनमोहन मालवीय

प० मदनमोहन मालवीय का कांग्रेस-सच पर सबसे पहली बार सन् १८८६ में, कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन में, व्याख्यान हुआ था, तभी से लेकर आप बराबर

आज तक अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करते चले आ रहे हैं। कभी तो एक वित्त-सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-वर्त्ता बनकर और कभी कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शित करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर, आपने कांग्रेस की विविध रूप में सेवा की है।

सन् १९१८ के अप्रैल मास में २७, २८ और २९ तारीख को वाइसराय ने गत महायुद्ध के लिए जन, धन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, चीफ-कमिश्नर, कार्य-कारिणी के सदस्य, बड़ी कौंसिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय कौन्सिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरोपियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में शास्त्रीजी, राजा महमूदाबाद, सैयद हसनइमाम, सरदारबहादुर सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया और गांधीजी के भाषण-सम्राट् के प्रति भारत की राजभक्ति वाले प्रस्ताव के समर्थन में हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड़ ने पेश किया था।

इसके बाद प० मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करते कहा, कि “भारत के आधुनिक इतिहास से एक भिन्ना लीजिए। औरंगजेब के जमाने में सिक्ख गुरुओं ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकाबला किया था। गुरु गोविन्दसिंह ने छोटे-से-छोटे लोगों को, जो आगे बढ़े, अपनाया और गुरु और शिष्य के बीच में जो अन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। इस तरह गुरु गोविन्दसिंह ने उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशों के जो सैनिक उनके कंधे-से-कंधा मिटाकर युद्ध करते हैं उनके बराबर वे अपने को समझ सकें। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्दसिंह के उत्साह एवं साहस से काम लिया जाय।”

देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तब मालवीयजी उसने तो दूर रहे, परन्तु कांग्रेस से नहीं। नरम दलवालों ने अपने जमाने में कांग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो वे उसने अलग हो गये। श्रीमती वेसेट्ट ने कांग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर बाद में उन्होंने भी, अपने से प्रबल दलवालों के हाथों में उसे वापस दिया। लेकिन मालवीयजी तमाम उतार-

चदावों में, प्रथमा और बदनामी, किनी की भी परवा न करते हुए, सदैव कांग्रेस का पल्ला पकड़े रहे हैं। मालवीय जी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें इतना साहस है कि जिस बात को वह ठीक समझते हैं उसमें चाहे कोई भी उनका साथ न दे पर वह अकेले ही मैदान में राम ठोकर डेटे रहते हैं। एक बार वह अपनी लोक प्रियता की चरम-सीमा पर थे। दूसरी बार अवस्था यह हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुनते थे। १९३० में जब मारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था उस समय मालवीयजी यही ठट्टे रहे। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था। क्योंकि वह कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में नहीं गये थे। लेकिन इनके चार मान बाद ही दूसरा समय आया। मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन १९३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही मिलते हैं। अब मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की हैसियत में वह उन्नत विचारवाले हैं और गादी को आगे गींचते हैं। कांग्रेसी की हैसियत से वह स्थिति-पालक हैं, इसलिए प्रायः वह पिछटे हुए विचारवालों का नेतृत्व किया करते हैं। फिर भी कांग्रेस इन बातों में अपना गौरव समझती है कि वह सरकारी कांसिल और वेज की कांसिल दोनों में उन्हें निर्विरोध जाने दे। किसी समय में जो बात गांधीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती है, कि एक समय या जब वह ब्रिटिश-साम्राज्य के मित्र थे। लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने अपने को, सरकारी निरक्षुण्णता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक सत्याग्रही हैं। पहले-पहल सन् १९०६ में वह लाहौर-कांग्रेस के सम्भाषित हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें अधिवेशन के सम्भाषित चुने तो सर फ़िरोजभाहू मेहता गये थे, परन्तु किन्हीं वज्रात कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व डम मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी। १० वर्ष बाद सन् १९१८ में कांग्रेस के दिल्लीवाले ३३ वें अधिवेशन के सम्भाषितत्व के लिए राष्ट्र ने आपको फिर मनोनीत किया था।

लाला लाजपतराय

कांग्रेस के पुराने मुख्य-मुखों में लाला लाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व

भी महान् था। वह जितने बड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही बड़े परोपकारी और समाज-सुधारक भी थे। सन् १८८८ में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। उसमें वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। कौंसिलों के बढाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लालाजी की लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने पंजाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊँचा स्थान बना दिया था। बनारस-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया। सन् १९०७ में उन्हें सरदार अजीतसिंह के साथ देश-निकासी दे दिया गया था। इस साल की घटनाओं के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपत राय ही थे, जिनके चारों ओर मारा घटना-चक्र घूमा था। सन् १९०७ की कांग्रेस के समापति-पद के लिए राष्ट्रीय विचार के लोगो ने लालाजी का नाम पेश किया। यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में होनेवाली थी, परन्तु बाद को स्थान बदलकर सूरत में करने का निश्चय हुआ था। गोरेले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अगर तुम सरकार की परवाना करोगे तो वह तुम्हारा गला घोट देगी।" लालाजी ने कभी मान-प्रतिष्ठा की पगवा नहीं की। यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने में उदारता-पूर्वक इनकार कर देते थे। सूरत में सम्पत्ति की बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के समापति-पद के लिए लालाजी का नाम पेश करने हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ कहें, लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हुआ-हुआमा नहीं।

सन् १९०६ में गोरेले के माय लालाजी भी शिष्ट-मण्डल में डम्पड भेजे गये थे। बाद में मुक्ति-मुक्ति ने उन्हें इनाम सग किया कि उन्होंने विदेशों में ही टूरना ठीक मममा। गत महायुद्ध के दिनों में तो वह अमरीका ही में रहे। लोग समझते हैं कि वह त्रिग होकर ही रहा रहे थे। कांग्रेस के समापति बनने का लालाजी का मन्दर जग देने आया। सन् १९२० के मिनम्बर मास में पन्नास में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल में बाहर मछली की होनी है। प्रमत्तो-आन्दोलन के जन्मदाता और समर्थक ने उनसे विचार कभी नहीं मिते। जग ही नहीं, जग अन्तिम माय में तो उन्होंने गत मिनम्बर की भी कर दी की कि वह आगे न कर नहीं गेगा। वह बीर और मूढ-मित्र थे, मगर मन्त्रही नहीं। उनके मिनम्बर का मिनम्बर-मम का जग मन्त्र-मम के मिनम्बर और मन्त्र नहीं था। जग ममम के मिनम्बर और मन्त्रों में दीया। उनके आगे मन्त्र में गोरेलानी का मन्त्र दग देगा था, जो उनके मिनम्बर था। कौंसिल में जग मन्त्र

जौहर फिर से खिल उठा। लेकिन अफमोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरता-पूर्ण वार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय में ही चले गये। सन् १८८८ की कांग्रेस में वह उर्दू में ही बोले थे और प्रस्ताव किया था कि आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्धे सम्बन्धी विषयो पर विचार करने के लिए दिया जाय। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक प्रदर्शनियां की जा रही हैं वह उसी कमिटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय कांग्रेस ने नियुक्त किया था।

फिरोजशाह मेहता

सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में से हैं जिनका सम्पर्क कांग्रेस के साथ उसके प्रारम्भ से ही रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण में इनका बहुत प्रमुख भाग रहा है। कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) के यह सभापति हुए थे, जिसमें सभापति-पद से दिये गये अपने भाषण में इन्होंने लॉर्ड सेल्सवरी के इस बिचार का खण्डन किया कि "प्रतिनिधि-शासन पूर्वी परम्पराओं अथवा पूरव-निवासियों की मन स्थिति के अनूकूल नहीं है" और अपनी बात की पुष्टि में मि० चिसहाम एन्टे का यह उद्धरण पेश किया कि "स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है, क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारम्भ से ही वहां मौजूद रहा है।" फिरोजशाह ने कहा, "निस्सन्देह कांग्रेस जन-साधारण की सत्ता नहीं है, लेकिन जन-साधारण के शिक्षित-वर्ग का यह फल है कि वह जनसाधारण की तकलीफों को सामने लाये और उन्हें दूर कराने के उपाय सुझावे।"

"अंग्रेजों के जीवन और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनैतिक बड़ी-बड़ी कान्तिओं का प्रभाव, धीरे-धीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढ़ता के साथ, हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैंड का सम्बन्ध इन दिनों के लिए ही नहीं बल्कि सारे ससार के लिए, और वह भी अगणित पीढ़ियों के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। मैं सारी अंग्रेजजाति से अपील करता हूँ—खरे मित्रों तथा उदार शत्रुओं, दोनों से—कि इस प्रार्थना को व्यर्थ और निष्फल न जाने दीजिए।"

कई वर्ष तक फिरोजशाह मेहता कांग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप में थे। आपने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिष्ट-मण्डलों

और प्रतिनिधि-मण्डलो के द्वारा ही किया जिनके कि यह सदस्य चुने गये थे। १९०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस-कार्य में कुछ क्रियात्मक भाग लिया था। उसके बाद आप दृष्टि से बिल्कुल ही ओझल हो गये। जब आप कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के, जो कि १९०९ में लाहौर में हुआ था, समापति चुने गये तो यकायक आपने, कांग्रेस से समापति का आसन ग्रहण करने से, ६ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर ५० मदनमोहन मालवीय कांग्रेस के समापति चुने गये थे।

आनन्दमोहन बसु

यह हम पहले देख ही चुके हैं कि किस प्रकार आनन्दमोहन बसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगति में बहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म-समाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन-एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मंत्री हुए और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी रहे। कांग्रेस आन्दोलन के साथ १८९६ से पहले तक इनका कोई बनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम, पर १८९६ के १२ वें अधिवेशन में इन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनर्स्थापन की योजना से होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को शिक्षा-विभाग के ऊँचे पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद, शीघ्र ही, १८९८ के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन बसु कांग्रेस के समापति हुए। समापति-पद से दिया हुआ इनका भाषण अकाट्य युक्तियों से, और अन्त में इन्होंने कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है। इन्होंने पार्लमेण्ट में हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रक्खे जाने की बात सुझाई थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १९०६, में ईश्वर ने इनको हमने छीन लिया।

मनमोहन घोष

मनमोहन घोष का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद) के सिलसिले में सुनते हैं, जब कि इन्होंने सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात् कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) में यह स्वागताध्यक्ष हुए। कांग्रेस पर होनेवाले विभिन्न आसपों का अपने जोरदार भाषण

में इन्होंने जवाब दिया और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। न्याय वनाम शासन कार्यों के विषय का इन्होंने खास तौर पर अध्ययन किया था। पूना में हुए ११ वें अधिवेशन (१८९५) में इन्होंने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० जैम्स नामक एक कमिशनर के वक्तव्य को उद्धृत करके बताया कि, इन दोनों (न्याय व शासन-कार्य) का सम्मिश्रण ही "भारत में ब्रिटिश-सत्ता का मुख्य आधार है।" इसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया, जिसपर १२ वीं कांग्रेस (कलकत्ता, १८९६) में शोक मनाया गया।

लालमोहन घोष

लालमोहन घोष १८९० में छठे अधिवेशन में (कलकत्ता) पहले-पहल कांग्रेस मंच पर आये और उन्होंने बैबला साहब के भारत-सरकार-सबधी बिल पर प्रस्ताव उपस्थित किया था। मद्रास (१९०३) में हुए १९ वें कांग्रेस अधिवेशन के वह सभापति बनाये गये थे। कांग्रेस-मंच से अबतक जितने योग्यतम भाषण हुए हैं उनमें उनके भाषण की गिनती होती है। उनके भाषण से कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं —

"हालांकि इसमें ऐसा कोई भी ख़रस न होगा जो ब्रिटिश-सरकार के प्रति सच्चे दिल से बफादार न होगा, तो भी वह यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के कामों की आलोचना करने का हक हमें है, जैसा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन को है। ऐसी दशा में क्या हम अदब के साथ अपने शासको से यह नहीं पूछें—और इस विषय में मैं मिला-मिला ब्रिटिश राजनैतिक दलों में कोई भेद नहीं करना चाहता—कि आपकी जिस नीति ने बरसों पहले हमारे देशी उद्योग-धंधे नष्ट कर दिये हैं, जिसने हाल ही में उस दिन उदार शासन के नाम पर बेगैरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति-कर लगा दिया, जो करीब दो करोड़ स्टलिंग तक हर साल हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री विलायत को दुबता के साथ बहा ले जा रही है, और जो किसानों पर भारी बोझ लाद-कर बार-बार और के अकाल देश में लाती है—अकाल भी ऐसे कि पहले कमी देखे न सुने—क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा? क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यों की बदौलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मगल-मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं?

"हमारा राष्ट्र स्व-शासित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपना शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्णतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णय पर अपना

आधार रखना पड़ता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिल्कुल सही है कि हमारी भारतीय नीकरसाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूखी बनती जा रही है। क्या आप खयाल करते हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रान्स, या संयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशों पर इतना खर्च करने का साहस करते, जबकि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और इस घृष्टतापूर्ण आनन्द-मगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसार रहे थे ?

“महानुभावो ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, जिसकी आवाज अखबारों और सभाओं में—दोनों ही तरह—उठाई गई थी, दिल्ली में जो बड़ा भारी राजनैतिक आडम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया था, उसे एक साल हो गया। और उसका विरोध किया किस लिए गया था ? इसलिए नहीं कि विरोध करनेवाले लोग सम्राट् की, जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह होनेवाला था, राजभक्ति में किसीसे कम थे, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, अगर सम्राट् के मन्त्री अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्राट् के सामने उनके अकाल-पीडित भारतीय प्रजाजन की कष्ट-कथा का ह्रमहू वर्णन करते तो दीन-दुःखी लोगों के प्रति सम्राट् की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वयं वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूखो-मरते लोगों के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही दरबार का) बड़ा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्धाधुन्धी से फजूलखर्ची की गई कि कुछ न पृच्छिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली-दरबार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल-पीडितों की सहायता में लगाई जाती तो भूखो मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चे मौत के मुह से निकल आते।”

चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य

सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हैं, यहाँ तक कि १८८७ के ३रे अधिवेशन (मदरास) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद लखनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८९९) में और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इण्डियन कांग्रेस कमिटी के सदस्य बनाये गये।

२२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६) में इन्होंने दायमी बन्दोबस्त का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि कर (ल्हान) वतौर किराया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हींकी है जो उसमें पैदा हुए हैं, जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती है—राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओं के बदले में किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय नहीं बल्कि पश्चिमी है।

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तुतः यह कांग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल की कांग्रेस से इन्हें सन्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये सत्रागण से गरम दलवालों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें आगये और १९१८ में हुए विधेयाधिवेशन (बम्बई) तथा १९१९ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया। अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद ही इन्हे नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहाँ बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ इन्होंने कार्य सम्पादित किया।

राजा रामपालसिंह

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी क्षेत्र में बड़ा प्रमुख रहा है। यह जानने लायक बात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वय-सेवकोंवाला प्रस्ताव राजा रामपालसिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, कि "ब्रिटिश-शान्ति (पैक्ट्स प्रिटेनिका) कितनी ही मशहूर क्यों न हो, ग्रेट ब्रिटेन की आकाशायें कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, और उसने हमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा, और बजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बात पर दुःख ही होगा कि इंग्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा। यह बात बहने में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना को कुचलकर, और उसको आत्म-रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के योग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्ति नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी छोटे-आप नजर डालिए, चारों ओर आपको बड़ी-बड़ी फौजें और नदरों के भयानक सम्प्राप

दृष्टि-गोचर होंगे। सारे सम्य ससार पर कोई आपत्त आना निश्चित-प्राय है। अभी या कुछ ठहरकर भयकर फौजी हलचल शुरू होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रण-क्षेत्र में फौजी हजार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता—जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैं। अतः जब ऐसा मौका आ जायगा तब इंग्लैण्ड को इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए लाखों भारतीयों को दक्ष बनाने के बजाय उसने उनके मुकाबले के लिए अपनी ही थोड़ी सेना यहाँ रख रखी है।” अपने पोते कालाकाकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका हाल ही में असामयिक स्वर्गवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने भानो सच्चे देशभक्त और कांग्रेस के—जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था—पूजारी बनकर फिर से जन्म लिया था।

कालीचरण बनर्जी

कांग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आमतौर पर यह प्रथा रही है कि जो आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बड़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे। और साल दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी होती—अर्थात् जो उस समुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का भलीभाँति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८६ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलचस्पी ली थी और १८६० में ब्रिटिश-जनता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ६ वी कांग्रेस (लाहौर, १८६३) में उन्होंने न्याय और शासन-कार्य की एक-दूसरे से पृथक् करने का प्रस्ताव पेश किया।

१८०१ में, कलकत्ता की कांग्रेस में, वह प्रस्ताव रखता कि हिन्दुस्तानी मामलों की सुनवाई (अपील) के लिए प्रिवी कौंसिल की जो जुडीसियल कमिटी बनती है उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी रखे जाने चाहिएँ। बाबू कालीचरण बनर्जी यदि अधिक समय तक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के समापति बनते।

नवाब सय्यद मुहम्मद वहादुर

कांग्रेस के मंत्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा

१९१४ की मदरास-कांग्रेस से बुरू हुई, जिसमें नवाब सय्यद मुहम्मद वहादुर और श्री एन० सुब्बाराव मंत्री चुने गये थे। लेकिन नवाब साहब तो इससे पहले, १९१३ की कराची-कांग्रेस में, सभापति-पद को भी सुगोभित कर चुके थे। वह पहले कांग्रेसी थे, इसके बाद मुसलमान। १९०३ में हुई मदरास-कांग्रेस (१९ वा अधिवेशन) के वह स्वागतार्थ्यक्ष थे और १९०४ की कांग्रेस (२० वा अधिवेशन, बम्बई) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रक्खा गया था। वह ऐसे देशभक्त थे जिनमें मजहबी सकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। कराची-कांग्रेस के सभापति-पद से उन्होंने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को अलग-अलग टुकड़ों में बटने के बजाय सयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये गये प्रयत्न का, जो कि मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित की गई इस आशा से प्रकट होता था कि 'सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनों जातियों के नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने स्वागत किया। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि कराची में नवाब साहब ने ऊँची देशभक्ति और शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो बीज बोया था वही फलकर आगे हिन्दू-मुस्लिम-एकता और लक्ष्मण की कांग्रेस-लीग-योजना के रूप में सामने आया।

दाजी आबाजी खरे

कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी बन्दोबस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहौर में हुए ६ वें अधिवेशन (१८९३) में श्री दाजी आबाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १९०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत कुछ भाग १९०८ में बननेवाले विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत भाग लिया था। १९०९ से १९१३ तक, श्री दीनशा बाचा के साथ, यह कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और १९११ में इन्होंने भारतीय सूती माल पर लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के मृती बन्ध-व्यवनाय के प्रसार में रुकावट पड़ती थी। १९१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-भारे ने ही प्राप्त होगा।

शुंशी गंगाप्रसाद वर्मा

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुम्भात के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के शुंशी गंगा प्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कांग्रेस को तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद में यह कांग्रेस-समितियों के विभिन्न पद ग्रहण करते रहे और १९०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-समिति के सदस्य भी बन गये थे।

रघुनाथ नृसिंह मुधोळकर

शुम्भात के कठोर परिश्रम करनेवाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ नृसिंह मुधोळकर का स्थान किसीसे कम नहीं है। वह पहली बार इलाहाबाद में होनेवाले कांग्रेस के अधिवेशन (१८८८) में शामिल हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था—“पुलिस के सिपाही का तो फर्ज है कि वह भ्रजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे घुणा का पात्र बन गया है।” २४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (बाकीपुर) का सभापति चुना। श्री सी० बाई० चित्तामणि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते रहे और बाद में अपनी प्रचण्ड बुद्धि शक्ति के बल पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे।

सी० शंकरन् नायर

सर सी० शंकरन् नायर अपने वक्त में एक समर्थ पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप कांग्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८९७ में, अमरावती-अधिवेशन का सभापति चुना। बम्बई के बन्दावरकर और तैयबजी की तरह शंकरन् नायर को भी पीछे मदरास के हार्डकोर्ट-बेंच का सदस्य बना लिया गया और वहां से १९१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १९१९ में मार्शल-लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन ‘गांधी एण्ड अनार्की’ नामक पुस्तक में गांधीजी पर उन्होंने निराधार आरोप किया। इसी पुस्तक के कारण पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा चलाया और सर शंकरन् को मानहानि व खर्चों के लिए तीन लाख रुपये देने पड़े थे।

पी० केशव पिल्ले

दीवानवहादुर पी० केशव पिल्ले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। १९१७ में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी सालों में वह कांग्रेस के मंत्री और श्रीमती एनी बेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे।

विपिनचन्द्र पाल

विपिन बाबू का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मशहूर वक्ता थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय विद्या के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी वक्तृत्व-शक्ति का सिक्का जमा दिया था। उन्होंने १९०७ में मदरास में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-जनरल (सर) बी० भाष्यम आयंगर ने उन्हें भडकानेवाले—राजद्रोहपूर्ण नहीं—समझा था और वह मदरास अहाते से निकाल दिये गये। लार्ड मिण्टो के समय उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्ता जब 'वन्देमातरम्' के संपादक की हैसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द बाबू के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सख्त कैद की सजा उन्होंने बड़ी खुशी से भुगत ली। उन्होंने इंग्लैण्ड में 'हिन्दू रिब्यू' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें बम के कारणों पर विचार किया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफी माग ली। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने आपनों और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखों-द्वारा उस समय के युवकों पर बहुत जादू कर दिया था।

अम्बिकाचरण भुजुमदार

बाबू अम्बिकाचरण भुजुमदार एक वकील थे और १९१६ में कांग्रेस के समापति बनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्तृता की उड़ान बहुत कम वक्ताओं में मिलती है। उन्होंने 'इण्डियन नेशनल इवाल्याशन' नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताब भी लिखी है।

भूपेन्द्रनाथ वसु

भूपेन्द्रनाथ वसु कलकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब

चलती थी। यह बड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थे। यह एक बड़े अच्छे वक्ता थे। इनकी वक्तृत्व कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में यह बड़े कुशल थे और अपना काम बड़ी योग्यता से संपादन करते थे। १९१४ में मदरास-कांग्रेस का समापति-पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-शासन की मांग के प्रसंग में उन्होंने कहा था—“मौज उठानेवालों के दिन गये। ससार समय के साथ-साथ बड़े जोर से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युद्ध एक के बहुतो पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मध्यकाळीन शासन के अंतिम अवशेषों को भी ठोकर मार देगा। पश्चिम के द्वार से पूर्व के शान्त समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े भारी प्रवाह की तरह बह रही है, उसे अब वापस ले जाना गैरमुमकिन है। यदि भारत में अंग्रेजी शासन का अर्थ नौकरशाही का गोला-बारूद ही है, यदि इसका अर्थ पराधीनता और हमेसा का संरक्षण है, भारत की आत्मा पर बढता हुआ भारी भार ही है, तो यह सम्मति का आप और मनुष्यता पर कलक ही है।”

मौ० मजहबुलहक

मौ० मजहबुलहक कांग्रेस के, सार्वजनिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से, एक महारथी थे। वह पक्के राष्ट्रवादी थे और बिहार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें घिड़ थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन में (१९१०) जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपने एक योग्यता-पूर्ण भाषण दिया, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा की। यह याद रखने की बात है कि मिण्टो-मैल्ले-शासन-सुधार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कौंसिलों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया गया था। मुसलमानों से, जो कि अपनी कामयाबी और सफलता के लिए फूलकर कुम्पा हो रहे थे, यह कहना, जैसा कि मौ० मजहबुलहक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी और साहस का ही काम था, कि उन्हें जो कामयाबी मिली दरअसल वह दोनों महान् जातियों की सम्मिलित भलाई के लिए बड़ी घातक है, देश को जरूरत इस बात की है कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।

१९१४ में जब कांग्रेस का सिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो मौ० मजहबुलहक भी

उसके सदस्य बनाये गये। इसके बाद आपने कांग्रेसी मामलों में कोई क्रियात्मक रस नहीं लिया, लेकिन रहे अन्त समय तक पक्के राष्ट्रवादी। जीवन के आखिरी दिनों में आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ, और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी। वस्तुतः आपका आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था।

महादेव गोविन्द रानडे

महादेव गोविन्द रानडे, जो आमतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। बहुत बारीकी में उत्तरें तब तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह बम्बई-सरकार के न्याय-विभाग के एक उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसों तक वह पीछे से कांग्रेस का सूत्र-संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे।

कांग्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की। उनका जैना कद, चेहरे का मूर्तिवत् बनाव और उनका अपना रंग-रंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे हैं। अर्थशास्त्री और इतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय हो गये हैं और 'महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान' एवं 'भारतीय अर्थशास्त्र पर निबन्ध' के रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये हैं। समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और बरसों तक समाज-सुधार-सम्मेलन, जो कांग्रेस की एक सहायक-संस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है। १८९५ में, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस समाज-सुधार के मामलों और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो, जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया। प्लेग की महामारी के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, और न उस सके वर्णन का अभी समय ही आया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और कांग्रेस का काम करते हुए, १९०१ में, अपनी ऐसी स्मृतियाँ छोड़कर रानडे हमसे विदा हो गये जो सदैव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी।

प० विशननारायण दर

प० विशननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिज्ञों में से हैं,

जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है।

१९११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का सभापति बनाया गया। इस कांग्रेस के सभापति मि० रैम्जे मैकडानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया और श्री विधाननारायण दत्त अकस्मात् ही सभापति बना दिये गये। वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापति बने थे, जब वय-भग के रद्द कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत बड़ी चोट पहुँची थी।

विधाननारायण दत्त ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह अहा सुन्दर चित्र है, वहा उतना ही तीक्ष्ण भी है —

“हमारे सब दुःखों का मूल कारण यह है कि हमारी नई महत्त्वाकांक्षाओं और आशाओं के प्रति सरकार की सहानुभूति-शून्य और अनुदार भावना बढ़ती जा रही है। यदि इसमें सुधार न किया गया, तो भविष्य में भयकर आपत्तियाँ आये बिना न रहेंगी। जब नवीन भारत धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है, तब सरकार का रुख भी मन्द होता जा रहा है और एक नाजूक हालत पैदा हो गई है। एक तरफ पडे लिये लोग नये राजनैतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शासन-मंडति की वेडियों और हथकड़ियों से जकड़े जा रहे हैं जो पहले के लिए कभी अच्छी होगी, अब तो वह अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसी रफ्तार पर जा रही है। वह न अपने स्वार्थों को छोड़ती है, न अपनी कठोर शासन की आदतों को, और न पुराने तथा निरकुश अधिकार की पुरानी प्रथाओं को। शिक्षा और ज्ञान को वह सदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय पृथक्ता के कारण रियायत से वह दूर भागती है। वह उसी-शासन विधान से चिपटे हुए है, जिसके मातहत हमने अवतक अधिकार व धन का मजा लिया है, लेकिन जो आज के नैतिक उदार आदर्शों के कतई खिलाफ है।”

रमेशचन्द्र दत्त

गत घताब्दी के अन्त की कांग्रेस-राजनीति में श्री रमेशचन्द्र दत्त एक और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन-काल में फ़ेमिनिस्ट के ऊँचे पद तक चढ़ चुके थे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एन० के अफमर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने मार्वाजनिक प्रश्नों पर जो अमिश्र अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ कांग्रेस को पहुँचाया। उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी

और ब्रिटिश कारखानों की खूली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण वधो का विनाश ही दुर्भिक्ष के कारण है। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० साल पहले ग्राम-शासन (पंचायतो) का संगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरों तथा जनता के बीच की घुणित शृंखला-द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुर्भिक्ष तथा अन्य आर्थिक प्रश्नों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८६० में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के वह समापति बने थे। "अखबारों और समाजों में स्वतन्त्र विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नहीं है" अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये।

एन० सुब्बाराव पन्तुलु

श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पूज्य युजुर्गों में से एक हैं। वह आज ८० साल की उमर में भी सार्वजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं। उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरु में, उसके जन्म के साथ ही, हो गया था। वह कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तब से वह कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयों का कार्य-कारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फसला और वकीलों की स्थिति आदि विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब कि उनके समकालीन कांग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कमी परवा नहीं की। दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८९८ में उन्हें कांग्रेस का स्वागताभ्यक्ष चुना और १९१४, १५, १६ व १७ में कांग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही। उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने स्वर्ण पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रखा।

लाला मुरलीधर

हम पंजाब के लाला मुरलीधर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमानत पर रिहा होकर जेल से सीधे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में शरीक हुए थे। उन्हें बिना गवाही के सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्हींके शब्दों में, "मुझे राजनैतिक आन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, क्योंकि मैं अपनी राय रखता हूँ, और जो सोचता हूँ, वेचक कह देता हूँ।" इसी अधिवेशन में डेराइस्माइलखा के लाला मलिक मगवानदास ने पहले-पहल उर्दू में भाषण दिया था।

सखिदानन्द सिंह

श्री सखिदानन्द सिंह को सबसे पहले १८९१ की लखनऊ-कांग्रेस (१५ वें अधिवेशन) में लोगो ने देखा। उसीमें उन्होंने न्याय और आसन-विभाग के पृथक्करण के प्रस्ताव पर आपण भी दिया। लाहौर के अधिवेशन में इस प्रश्न पर बोलते हुए उन्होंने कहा—“सरकार को जनता के प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का बरदान जनता को दिया जाय। हम आज का न्याय—आधा दूध और आधा पानी—अशुद्ध न्याय नहीं चाहते। हम तो सच्चा और ठीक ब्रिटिश-न्याय चाहते हैं।” १७ वें अधिवेशन में ‘पुलिस-सुधार’ पर वह बोले। २० वें अधिवेशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १९०५ में आम चुनाव होने से पहले इरलेण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवेशन में उन्होंने बाबामाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जार्डिन को पार्लमेण्ट का सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १९०८ की पहली ‘नरम’ कांग्रेस में श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-कांग्रेस में श्री सिंह ने युक्तप्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माग पेश की। वह फिर मद्रास में १९१४ में शामिल हुए। इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिष्ट-मण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वश्री भूपेन्द्रनाथ बसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहबूल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय थे।

कांग्रेस में बोलनेवाली पहिली महिला श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी। उन्होंने १९०० के १६ वें अधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था।

इनके अलावा और भी बीसियों अच्छे देख-सेवक हैं—जिनमें बहुत से स्वर्गवासी हो चुके हैं और कुछ हमारे बीच मौजूद हैं—जिन्होंने अपनी तीव्र लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीयकार्य में सहायता पहुँचाई है। आगे आनेवाली पीढ़ी उनकी सदा ऋणी रहेगी।

: १ :

फिर मेल की ओर—१९१५

श्रीमती वेसेण्ट रंगमंच पर

भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १९१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगणेश करता है। यद्वा यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिये कि ज्ञापान ने इस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की जातियों में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १९१४ की कड़ाके की सर्दियों में, फ्लैण्डर्स और फ्रान्स के मैदानों में, जर्मन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फौजों ने जिस अद्भुत वीरता, वीर्य और सहनशीलता के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया उससे एशिया और यूरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी वाक बैठ गई थी। पश्चिमी देशों की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभी तक कभी नहीं थे। भारतीय फौजों द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जाग्रत हो गई थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती वेसेण्ट दूसरे दल के लोगों में। क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के मैदान में इसी आश्वासन पर लेजाया गया था कि पार्लियमेंट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे तो मि० ब्रैडला के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीबों और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस में वह १९१४ में ही सम्मिलित हुईं। उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टिकोण और सगठन का एक बिल्कुल ही नूतन ढंग लेकर कांग्रेस-क्षेत्र में पदार्पण किया। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत् में महान् था। पूर्व और पश्चिम के देशों में, नये और पुराने गोलार्द्ध में, लाखों की सख्या में उनके भक्त एवं अनुयायी

थे। इसलिए यह कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रबल भक्तों और अनुयायियों और अथक कार्य-शक्ति के होते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया।

१९१५ की स्थिति

१९१५ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी? १९ फरवरी १९१५ को गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। धीनवादा बाबा पर बृद्धावस्था-जन्य निर्बलतायें अपना अधिकार जमाती चली जा रही थी, जैसा कि उन्होंने १९१५ की दम्बई की कांग्रेस में कहा था। अलावा इसके वह एक बहुत बड़े विद्वान् थे, और मंत्रीपद के लिए ही बहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो अपनी फौज को एक विजय के बाद दूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता है। सर नारायण चन्दावरकर जजी से फारिग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे। हेरम्बचन्द्र मैत्र, मुधोलकर तथा सुब्बाराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफ्टिनेण्ट, कैप्टन तथा कर्नल थे, इससे अधिक कुछ नहीं। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी भी अनुकूल न थे।

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १९१४ को मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास सास्त्री ने, 'भारत-सेवक-समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया था, लेकिन वह सदैव रहे फिसट्टी ही। क्योंकि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उग्र प्रवृत्तियाँ और नरम विश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' और 'उपयोगिता', 'अन्तिम' और 'तात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव संघर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह भिड़ बैठने की मनोवृत्ति की प्रशंसा करते हैं फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैं। पंडित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते। न उनमें वह शक्ति एवं मानसिक दृढ़ता ही थी जिसमें कि वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते। गांधीजी तो उस समय देश में आये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निर्दिष्ट टग पर श्रीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत के अनुसार चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। काला

लाजपतराय इस समय की देश की ओर विशेषकर अपने प्रात की अवस्था से बड़े खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। (सत्येन्द्र-प्रसन्न सिंह (वाद में लार्ड) जिन्होंने १९१५ की बम्बई की कांग्रेस का समापन किया था, इस समय नई धारा के साथ विलकुल मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए बम्बई-कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्रायः राष्ट्र के हाथ से निकलकर नौकरशाही के हाथों में जा रहा था। नरम बलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीयदल अभीतक अपनेको सम्हाल न पाया था। श्रीमती बेसेण्ट का १९१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था।

१९१५ की बम्बई कांग्रेस

१९१५ की कांग्रेस केवल नरमदलवालों की ही थी। कांग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात् नवम्बर मास में सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्येन्द्र-प्रसन्न सिंह, जिनकी योग्यता और स्वभाव की सर्वत्र धाक थी, इस कांग्रेस के समापन चुने गये थे। वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके समापनत्व से बम्बई कांग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम के साथ जुड़ी रहती है।

लेकिन बम्बई की सन् १९१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग के बिना फिर से दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-क्राण्ड के बाद विलीन हो गया था। लखनऊ-कांग्रेस और उसके बाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। बम्बई की कांग्रेस में २२५९ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव तो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के सम्बन्ध में थे—अर्थात् गोपालकृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी कॉटन। चौथा शोक-प्रस्ताव मि० केमरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव भारत के बड़े मित्र थे। पाचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभक्ति प्रकट की गई थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश अल-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उसपर सतोष प्रकट किया गया था। सातवें प्रस्ताव-द्वारा लॉर्ड हार्डिंग का, जो कि उस समय वाइसराय

ये, शासन-काल बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आठवें प्रस्ताव में कांग्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का, भारतीय सैनिकों को तत्कालीन सैनिक स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूल-कालेज खोलने का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित सम्मान रखते हुए, जात-पात के बिना किसी भेद-भाव के, भर्ती किया जाय तथा स्वयंसेवक बनाया जाय। नवें प्रस्ताव द्वारा १८७८ के आर्म्सएक्ट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर अनुचित लाञ्छन लगाया था, नाराजगी जाहिर की गई। दसवें में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारत-वासियों से सम्बन्ध रखते थे, कुछ प्रकट किया गया। बारहवें प्रस्ताव द्वारा बाइसराय को उनकी उस दूरदर्शितायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होंने बड़ी कौंसिल के उस प्रस्ताव के समर्थन में दी थी, जिसमें कि शाही परिषद् में भारतीय प्रतिनिधियों-द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना भी की गई थी कि बड़ी कौंसिल को कम-से-कम दो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय। बारहवें प्रस्ताव में युक्तप्रान्त में कार्यकारिणी बनाने की मांग को दोहराया गया था। तेरहवें में कुली-प्रथा को नष्ट करने और चौदहवें में न्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक् कर देनेवाली पुरानी मांग को दोहराया गया था। १५वें में पंजाब, बर्मा तथा मध्यप्रान्त में छेदने बजों की हाईकोर्ट स्थापित करने की मांग की गई थी। १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोध किया गया था। १८ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता और विशेष कर आयात-निर्वात तथा उत्पत्ति-कर-सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सौंप दिये जायें। १९ वा प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जनता को शासन पर वास्तविक नियंत्रण मिले और वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रान्तों में कौंसिलें हैं उन्हें सुधारों और बढ़ाया जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हो वहां उनकी पुनर्रचना की जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं हैं, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय और

एक दूसरे को जो अधिकार-सम्पन्न किया जाय। इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह भी दिया गया था कि का मुबारक को एक योजना तैयार करे और एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करे जिसमें निम्नलिखित बातें और प्रस्ताव करने का कार्य समाप्त होना रहे। इसी प्रस्ताव में मुहम्मद गीसों को यह अधिकार भी दिया गया था कि इस विषय में मुहम्मद गीसों को जमीनों में भी परामर्श देने और इस विषय में अन्य नागरिक आवश्यकताओं को देखें। इसी प्रस्ताव में यह बात भी दी गई थी कि राज्य को भूमिकार किन्ना में अधिकार, उसके लिए एक उचित और सिद्धिमान नीति नियम कर देनी चाहिए, और उसके अनुसार उसके सिद्धांतों को भूमि पर सर्वेक्षण कराया अधिकार दे देना चाहिए, ताकि उसी संस्थागत प्रथा को या उन्नीयता। यदि स्थायी बन्दोबस्त न हो तो कम-से-कम ६० साल बन्दोबस्त तक होना चाहिए। २१ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-धंधों की तराफों के लिए कार्रवाई की जाय, जो गंगा तथा इन्द्रावती की निष्ठा देने की प्रकृति से, आयात-निर्यात-सम्बन्धी व्यवस्थाओं को भाग्य से जागृत स्वायत्तता दी जाय, उससे अधिक और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय जो सभी माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप में यहाँ लागू हैं, और जो उन भेदभावपूर्ण दंगों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल को भाग्य भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिनके फलस्वरूप देशी-व्यापार और उद्योग-धंधों का गन्ना गूढ़ गया है। २२ वें प्रस्ताव में इन्डियन स्टूडेंट्स टिचिंग सोसिटी में नामाङ्कन शामिल हो गई और इस बात पर अमन्तोष प्रकट किया गया कि ग्रेट-ब्रिटेन के मुद्रा-मन्त्रालय की निष्ठा-संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों को कम रकमा में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्ती कर लेने के बाद उनके साथ भेदभाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या मुद्रा-मात्र हैं जो कांग्रेस के जन्म के ले कर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे।

अध्यागन के प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, १९१५ की कांग्रेस ने अपने १९ वें प्रस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लीग की कार्य-कारिणी से परामर्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे।

१९१५ की एक बड़ी दिलचस्प घटना यह है कि गांधीजी विषय-समिति के सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए महासमिति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति में नामजद किया था।

बम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा महत्त्वपूर्ण संशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। क्योंकि यह तय हो गया था कि "उन संस्थानों द्वारा बुलाई गई सार्वजनिक सभायें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेंगी जिनकी स्थापना १८१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश्य वैध उपायों से ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना हो।" लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने तुरन्त ही इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आगिक रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सहर्ष तैयार हैं।

संयुक्त कांग्रेस-१९१६

लॉ० तिलक की होमरूल लीग

नये वर्ष का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस-कार्य के लिए और भी शुभ समय, परिस्थिति और वातावरण में हुआ। इस देश बड़े-बड़े धक्को के कारण और भी असहाय हो गया था। क्योंकि १९१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई स्थान ही नहीं था। क्योंकि बम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार उन्हें पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था। इसीके बाद वह कांग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का निश्चय किया। इस नाजुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओं और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस को एक सिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब उन्होंने २३ अप्रैल १९१६ को अपनी होमरूल-लीग की स्थापना की। इसके ६ मास बाद श्रीमती बेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खड़ी की।

लेकिन नौकरशाही तो उनकी कट्टर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को डिफेंस फोर्स (रक्षक-सेना) में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब-सरकार की ओर से उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली और पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने अपनी होमरूल-लीग के लिए कांग्रेस के ग्रीड को स्वीकार कर लिया। जान पड़ता है, इससे श्री शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई। १९१६ में उनकी अवस्था ६० वर्ष की हो गई थी। इस पछि-पूर्ति के अवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की थैली भेंट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अर्पण कर दिया। सरकार ने जितना ही उन्हें दवाया उतने ही वह ऊपर उठे और अन्त में "उन्हें जेल भेजने की

अपेक्षा सामोरा करना ही उचित समझ कर ” उनने नेकचलनी की २० हजार रुपये की जमानत भागी गई। लेकिन ६ नवम्बर १९१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फ़ैसला रद्द कर दिया। इससे लोकमान्य की लोक-प्रियता और भी बढ़ी। उनका आदर हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहाँ कहीं वह गये थैलियाँ भेंट हुईं। लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत में वित्तुत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए बड़ी भारी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जाग्रत करने और उनके मन्दिर एक प्रकार की बिजली-सी भर देने के महत्त्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में उनसे बड़ी थी, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकना नहीं जानती थी।

यह भी वषा १९१६ में भारतवर्ष की जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता था और जिसे अपने लिए एक नेता बूढ़ निकालने की आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही नाजुक समय में श्रीमती बेसेण्ट ने रणागण में पदार्पण किया। धार्मिक क्षेत्र से एक दम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ी। गियोसोफी को छोड़ उन्होंने होमरूल को अपनाया। “न्यू इण्डिया” नामक एक दैनिक और इसके बाद “कामन-वेल” नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय बनाने में उनका नम्बर प्रथम है। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफ़ान मचा दिया। वैसे १९१५ में ही “होमरूल फ़ॉर इण्डिया लीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी। क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट-रूप से उस वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा।

हिन्दू मुस्लिम एकता

बम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो आदेश दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान् जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी भी बनाई गई, जिसके सुपुर्दे यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करे और साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को धीम्र ही फलीभूत करने के लिए अन्य सारे आवश्यक प्रवृत्त करे। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित कमिटी-द्वारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१९१६) कांग्रेस और मुस्लिम-

लोग दोनों मिल कर पान करे। इसी सम्बन्ध में २२, २३ और २४ अप्रैल १९१६ को ग्लाहावार में ५० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की बैठक में नूतन वाद-विवाद हुआ था। महासमिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव फर्ने तोर पर पास हुए थे उनपर मुस्लिम-लीग की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक में जो अक्टूबर १९१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-गानानामन्वन्धी समझौता तय हो गया। केवल बंगाल और गजब के प्रतिनिधियों की गरया की समस्या हल नहीं हुई थी। द्रमका अन्तिम-निर्णय एग्नऊ अभियोजन पर छोड़ दिया गया। सम्मिलित कमिटी ने मन्त्रकत्ते में जो प्रस्ताव पान किये थे, उन्हें एग्नऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। राजनीतिज्ञों के आन्तरिक धर्म को कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस बात का पना चल गया था जो वाद को "नाइण्टीन मेमोरेण्डम" (१९ का आवेदनपत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुआ (परिशिष्ट १) और जो अमेन्वली के १९ सदस्यों के हस्ताक्षर से बाइसराय के पास भेजा गया था (नवम्बर १९१६)। आवेदनपत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदनपत्र इसलिए भेजा गया था, क्योंकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुरास लगा था कि भारत-मरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक राशीता विलायत भेजा है जो वस्तुतः प्रतिगामी थे।

जाहिर है कि श्रीमती बेसेण्ट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था उसमें सन्तुष्ट नहीं थी। कांग्रेस की प्रिटिंग-कमिटी निस्सन्देह इल्लण्ड में अपना काम कर रही थी। लेकिन यह वस्तुतः एक प्रकार से, उसीके शब्दों में कहे तो, सिर्फ निगमनी रहती थी। श्रीमती बेसेण्ट एक तेजतर्रार और जीती-जागती सस्था चाहती थी। इसीलिए उन्होंने १९१४ की मदरास-कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून १९१६ को लन्दन में एक सहायक-होमरूल-लीग की स्थापना की। भारतवर्ष में तो निश्चित रूप से पहली सितम्बर १९१६ ई० को, मदरास के गोवले-हाल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी। इस सस्था ने १९१७ भर बटाके से श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस सस्था की तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, २३ अप्रैल १९१६ को लोकमान्य तिलक की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में था। दोनों के नाम में गडबड न हो

इसलिए श्रीमती वैसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १९१७ में 'ऑल इंडिया होमरूल-लीग' रख दिया था।

लखनऊ कांग्रेस में लो० तिलक

लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्हें बम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के लोगो की एक अच्छी खासी सत्या को लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली। कांग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा था कि विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्ही की सत्या के बराबर सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जायें। लोकमान्य ने नरम-दलवालो के सामने विषय-समिति के चुने जानेवाले सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रक्खा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बम्बई के प्रतिनिधियों से जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को ही चुनवाने का निश्चय किया। अधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात् एक नरम-दलवाले का तो हमरा राष्ट्रीय दलवाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल का ही आदमी चुना गया। जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तो गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी चुन लिये गये।

लखनऊ की इस कांग्रेस के समापति थी अम्बिकाचरण मुजुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के वह एक परखे हुए मेवक थे। राष्ट्रीय कार्यों के लिए उनका जो त्याग था उसके लिए लखनऊ की कांग्रेस का समापति बनाकर उनका मान करना उनका उचित पुस्कार ही था। उनका सनापति के पद ने दिया गया नापण वक्तृत्व-कला के निहाल थे वैसा ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उन समय तक रिवाज था। लखनऊ-कांग्रेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी शासन-नुब्वारों के लिए कांग्रेस-लीग-योजना की पूर्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णतः समझौता और मेल हो जाना। (परिधिष्ट २)

कांग्रेस लीग योजना

कांग्रेस-लीग-योजना में मुख्य बात यह थी कि कार्यकारिणी कॉमिटी के अधीन

रहे। लेकिन यहाँ यह बात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कौंसिल में १/३ भाग नामजद सदस्यों का रक्खा गया था। भारत-मन्त्री की कौंसिल को तोड़ देने की बात थी। संक्षेप में उस समय के बाद की कांग्रेस की तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में विशेष सार नहीं था। फिर भी सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी। उसने इसके मुकाबले में स्वयं अपनी एक योजना तैयार की, जैसा कि हमें १९१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा।

लखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की अद्वितीय थी। एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐवम् हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और कांग्रेस के दोनों दलों में जो कि १९०७ से पृथक्-पृथक् थे, एका हो गया। वास्तव में वह दृश्य देखते ही बनता था—लोकमान्य तिलक और सापडें, रासबिहारी घोष और सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एक ही साथ एक ही स्थान पर बराबर बैठे थे। श्रीमती जेसेण्ट भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल और बाडिया साहब के साथ, जिनके हाथों में होमरूल के झण्डे थे, वहीं बैठी थी। मुसलमानों में से राजा महमूदाबाद, मजहबूल हक और जिन्नाह साहब भी उपस्थित थे। गांधीजी और मि० पोलक भी वहीं विराजमान थे। कांग्रेस-लीग-योजना पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर लगा दी।

स्वीकृत प्रस्ताव

बम्बई-कांग्रेस की भाँति लखनऊ-कांग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। अतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके भारे सारा पण्डाल खचाखच भर गया था। इसमें प्रायः वे सब प्रस्ताव पास हुए जिन्हें कांग्रेस अवतक हर साल पास करती चली आ रही थी। कांग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये थे। एक तो उत्तरी बिहार के गोरे अमींदारों और बड़ा त्नी रैयत के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में था, जिसमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियुक्त करे जो बिहार के इन किसानों के कष्टों का पता लगावे। दूसरा विद्वद्विद्यालय-सम्बन्धी बिल था जो कि बड़ी कौंसिल में पेश किया जा चुका था।

उत्तरी बिहार के गोरे अमींदार और बड़ा त्नी रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसके बाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों का पता लगाने बिहार गये थे, जिसपर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा।

भारत के स्व-शासनवाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) भारत की प्राचीन सभ्यता और शिक्षा में जो उन्नति हुई, और नार्वेजिक कामों में जो सचि प्रकट की गई है उनको मद्देनजर रखते हुए सम्राट् की सरकार को चाहिए कि वह कृपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश-नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीघ्र ही स्व-शासन-प्रणाली को जारी करे, (ब) इस दिशा में एक सीधा कदम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-श्रीग-योजना को सरकार स्वीकार कर ले और (स) साम्राज्य के पुनर्निर्माण में भारतवर्ष को अधीन-देशों की स्थिति से निकालकर साम्राज्य के बराबर के साझेदारों में, औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भांति, रक्खा जाय।

यहां यह बात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा-डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और १८१८ के ३रे रेग्युलेशन (बंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इंडिया डिफेंस एक्ट के प्रयोग में, जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो न्युक्स्त-राज्य के देश-रक्षा कानून (डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट) के अनुकूल हो।

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की प्रथा का जो श्रीगणेश बम्बई में हुआ था वही लखनऊ में भी जारी रक्खा गया। लखनऊ के अधिवेशन में स्व-शासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके बाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की कांग्रेस-कमिटिया तथा अन्य संगठित संस्थायें और कमिटिया शीघ्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने आश्चर्यजनक उत्तर दिया। एक प्रान्त ने दूसरे प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की। और मदरास ने तो श्रीमती बेसेण्ट के नेतृत्व में इस कार्य में सबसे अधिक बाजी मारी। कांग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन कोई सुगमता से समाप्त नहीं हो गया। १८६६ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर १५ वा अधिवेशन होने जा रहा था उस समय अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर सर एन्थोनी मैकडो-नल्ड ने उन सब का अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १९१६ में भी हुई थी। युक्तप्रान्तीय सरकार के मन्त्रि-मण्डल ने कांग्रेस की स्वागत-समिति को एक चेतावनी भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के नी राजद्रोहात्मक भावों को न आने दिया जाय। कांग्रेस के मनोनीत नभापति के पास भी बंगाल-सरकार-द्वारा

उसी की एक नकल भेज दी गई थी। स्वागत-समिति ने इस अकारण तौहीन का मुह-तोड़ जवाब दे दिया था और समापति ने उस पत्र की कोई वकत नहीं की थी। श्रीमती बेसेण्ट तो ठीक इन्हीं दिनों बरार और बम्बई की सरकारों से देश-निकाले की आज्ञा पा ही चुकी थी। इसलिए स्वभावतः लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही आशंकाएँ थी। लेकिन सर जैम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसीलिए कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अविकारीवर्ग-सहित सर जैम्स मेस्टन और उनकी बर्मपत्नी कांग्रेस में पधारे थे। समापति महोदय ने इनका जो स्वागत किया था उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था।

उत्तरदायी शासन की ओर—१९१७

भारतीय राजनीति के विकास में यहाँ का साम्प्रदायिक मतभेद सदैव एक बड़ा भारी रोड़ा रहा है। इसका जन्म तो वैसे वस्तुतः लॉर्ड मिंटो के जमाने में हुआ था। पर १९१७ में जब स्व-शासन की एक योजना तैयार की जाने को थी, उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो महान् जातियों में, किसी ऊपरी शक्ति के दबाव से नहीं बल्कि आपसी तौर पर, एक समझौता हो गया था। यह आगे आनेवाले राजनैतिक संघर्ष के लिए शुभ चिह्न था। १९१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चलाया गया था, उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी। १९१७ में सारे देश में बड़ी तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो विराट् आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी बहुत ही लोकप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो चीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली वह था पुलिस का दमन।

होमरूल आन्दोलन और दमन

होमरूल की आवाज देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमरूल-लीगों की स्थापना हो गई थी। श्रीमती वेसेण्ट के हाथों में प्रेस की शक्ति खूब ही बड़ी, यद्यपि प्रेस-एक्ट के अनुसार दमन-पत्र भी खूब ही चला। और लॉर्ड पेण्डलेण्ड की सरकार ने तो सरकारी आज्ञा-पत्र न० ५५६ के अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया था। उन्होंने 'हिन्दू' के सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा आयंगर को भी बुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आघ घटे की मुलाकात में गवर्नर से साफ-साफ बातें करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे बता दिया था। लेकिन श्रीमती वेसेण्ट से, जिनका 'न्यू इंडिया' नामक दैनिक और 'कामन-वेल' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था, प्रेस और पत्र के लिए २०,००० की जमानत मागी, गई, और वह जप्त भी कर ली गई।

एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का खयाल दावानल की तरह सर्वत्र फैल रहा था। "होमरूल-आन्दोलन की शक्ति", श्रीमती वेसेण्ट के

१९१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति-पद से दिये गये साधन के अनुसार, “स्त्रियो के उसमें एक बहुत बड़ी सख्या मे भाग लेने, उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियो-चित्त अद्भुत वीरता दिखाने, कष्ट सहने और त्याग करने के कारण दसगुनी अधिक बढ़ गई थी। हमारी लीग के सबसे अच्छे रंगरूट और सबसे अच्छे रंगरूट बनानेवाली स्त्रिया ही थी। मदरास की स्त्रियो का दावा है कि जब आदमियो को जुलूस निकालने से रोक दिया गया तब उनके जुलूस निकले और मदिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने नजरबन्दो को मुक्त कर दिया।” इस आन्दोलन की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि प्रारम्भ से ही भापा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तो को मान लिया गया था और उसीके अनुसार देश का प्रान्तीय-संगठन किया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल गया और सच पूछिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था।

१५ जून १९१७ को श्रीमती वेसेण्ट, बरम्बेले और वाडिया साहब को नजर-बन्दी का हुक्म मिला। उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना था। कोयम्बटूर और उटकमण्ड को इन लोगो ने पसन्द किया। अपने तीन नेताओ की नजरबन्दी के कारण होमरूल-लीग और भी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्नाह भी वाद में फौरन उसमें सम्मिलित हो गये। यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुक्म और खुफिया पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती वेसेण्ट स्वतन्त्रता-पूर्वक बराबर अपने पत्र ‘न्यू इंडिया’ के लिए लेख लिखती रही। ‘कामन-विल’ नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला। श्री पठरीनाथ काशीनाथ तैलंग ‘न्यू इंडिया’ के सम्पादक बनकर मदरास पहुँच गये। जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने दिन तक होमरूल-आन्दोलन विद्युत गति से दिन-दूना रात-बीगुना बढ़ा। देश में स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। लेकिन इंग्लैण्ड में अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था। वि० माण्टेगु ने अपनी डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सबक निकाला “शिव ने अपनी पत्नी के ५२ टुकड़े कर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ५२ पार्वतिया मौजूद हैं। वास्तव में यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती वेसेण्ट को नजरबन्द किया।”

भारतवर्ष में जब कि यह राजनैतिक तूफान उमड़ रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिषद् हो रही थी, जिसमे सारे उपनिवेशो के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा वीकानेर और सर सत्येन्द्रप्रसन्न

सिंह इंग्लैण्ड में भेजे गये थे। इन लोगों ने अपनी ज्ञान-वान और रग-ढंग तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रोव बहा जमाया कि इनका बहा खूब ही स्वागत हुआ, मान हुआ और अखबारों ने मूरि-मूरि प्रशंसा की। इसका असर यहाँ तक हुआ कि ब्रिटिश-कमिटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-मुबारो-सम्बन्धी प्रश्न को हल करने के लिए एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड बुलाया जाय, अपनी राय बदल दी और उसी समय इंग्लैण्ड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव में ७ अप्रैल १९१७ को महासमिति की बैठक बुलाई गई थी, इसलिए कि वह इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजने का और विलायत में ही कांग्रेस का अधिवेशन करने का आयोजन करे। इन महानुभावों को शिष्ट-मण्डल का सदस्य बनने के लिए कहा गया था—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रासबिहारी बोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, मदनमोहन मालवीय, सर कृष्णचन्द्र गुप्त, राजा महमूदाबाद, तेजबहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और सी० पी० रामस्वामी ऐयर। ब्रिटिश-कमिटी ने बहुतेरा प्रयत्न किया कि भारत-मंत्री मि० आस्टिन चैम्बरलेन भारत-विपक्ष सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर लें, लेकिन वह दोनों में से एक भी करने को तैयार न थे। ८ मई १९१७ को इंग्लैण्ड में एक छोटी-सी परिषद् हुई। उस समय सर सत्येन्द्रप्रसाद सिंह भी वहाँ थे। इसी परिषद् का वह निश्चय था, जिसके अनुसार भारत से शिष्ट-मण्डल भेजने की सलाह वापस ले ली गई थी।

भारतवर्ष इस समय होमरूल के सम्बन्ध में नजरबन्द हुए लोगों को छुड़ाने के लिए सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १९१७ में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौंसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव पास हुआ वह था भारत के बृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने का। सर विलियम वेडरबर्न की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय हुआ। उसके सदस्य थे—श्री जिन्नाह, शास्त्री, (यदि वह न जायें तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर), सप्रू और बजीरहसन। सत्याग्रह करने के प्रश्न पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और मुस्लिम-लीग की कौंसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्त और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करें, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं? इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी। इस सम्मिलित बैठक ने बंगाल-सरकार की उस धावलेवाजी के प्रति तीव्र विरोध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने

धीमती वैसेण्ट और मि० अरथेल व वाडिया के नजरबन्द होने के विरोध में डॉ० रासबिहारी धोप के सभापतित्व में होनेवाली एक सार्वजनिक सभा रोककर की थी। प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई थी कि "बंगाल के निवासी प्रत्येक कानूनी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।" एक बहुत ही 'युक्तिपूर्ण वक्तव्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया गया था कि यहाँ भारतवर्ष में किस प्रकार लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदमियों-द्वारा भेजे गये उस आवेदन-पत्र को बुरा-भला कहते हुए उसे "महान् आपत्ति डाल देनेवाला परिवर्तन" कहा था, और किस प्रकार इंग्लैण्ड में लॉर्ड सिडेनहम ने "भारत के खतरे" का मय दिखाकर और इस आवेदन-पत्र को "क्रान्तिकारी प्रस्ताव" कहकर इसकी निन्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीछे 'जर्मनी की साजिश' है। इसके बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गवर्नी-पत्र भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह खींचा ही पड़ा, में सर माइकल ओडायर और मदरास में लॉर्ड पेण्डलैण्ड के मुह से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने लगा। इन्होंने लोगों को व्यर्थ की आशायें न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की वमकी दी। सर माइकल ओडायर ने तो यहाँ तक कह डाला था कि सुधार मागनेवाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे है वे क्रान्तिकारी और कानून और व्यवस्था उलट देनेवाले हैं। सरकार को जिस बात की सबसे अधिक चिन्ता थी वह यह कि एक ओर तो भिमला और दिल्ली से जो गुप्त खरीते शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे उनसे पहले कांग्रेस तथा लीग और कुछ कांसिल के सदस्यों की योजना और आवेदन-पत्र विलायत कैसे पहुँच गये? प्रान्तीय सरकारों के गवर्नरों ने इस अदूरदर्शिता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि शासन-सुधार बहुत ही साधारण से दिये जायेंगे। लेकिन यदि वे अदूरदर्शी थे तो कम-से-कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि वे ईमानदार थे। हा तो उस वक्तव्य में नजरबन्दी का विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) साम्राज्य-सरकार इस बात की घोषणा करे कि वह भारत में खींचा ही ब्रिटिश-साम्राज्य की स्व-शासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) शासन-सुधारों की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मजूर करने के लिए फौरन ही आगे कदम बढ़ायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको खींच ही प्रकाशित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी।

सत्याग्रह के प्रस्ताव पर प्रान्तों के मत

३० जुलाई को भारत-भत्री, प्रधान भत्री तथा सर विलियम वेडरबर्न को इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा बिलायत भेज दिया गया। इस बीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनों में विचार किया। बरार की राय में तो सत्याग्रह करना उचित था। पर बम्बई, बर्मा और पंजाब का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थगित रहना जाय, क्योंकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सम्भावना है। युक्त-प्रान्त ने "वर्तमान अवस्था में" सत्याग्रह करना अनुपयुक्त बताया। बिहार की सम्मति में "होमरूल के नजरबन्दों—मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयो को छोड़ने के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए।" इस धी गई मियाद के बीच में बिहार स्वयं स्थान-स्थान पर समार्ये करके इस भाग का वल बढाने को तैयार था। यदि सरकार इसपर ध्यान न दे तो, बिहार के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायेंगे और उसके लिए हर प्रकार के बलिदान करेंगे और मुसीबतें सहेंगे। मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ अगस्त १९१७ को सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया।

मद्रास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इसपर सबसे पहले हस्ताक्षर करनेवाला जो व्यक्ति था वह थे सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जोकि मद्रास हाईकोर्ट के पेंशनयापता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी 'सर' की उपाधि को श्रीमती बेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक और निरभिमान देश-सेवक श्रीकस्तूरी रंगा आयंगर थे।

माण्टेगु की घोषणा

जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० माण्टेगु की घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। इसपर मद्रास-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया—“राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसे मद्देनजर रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना आगे के लिए स्थगित किया जाय। इस बात की इत्तला महासमिति को दे दी जाय।”

वह बदली हुई परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसोपोटामिया में युद्ध का प्रबन्ध अच्छा नहीं रहा। इसी सम्बन्ध में कामन-सभा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमें मि० माण्टेगु ने मि० आस्टिन चैम्बरलेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बुरी तरह आड़े हाथों इसलिए लिया कि मेसोपोटामिया में भारत से प्रचुर-मात्रा में सामग्री तथा सिपाही न पहुँचाने के कारण ही गड़बड़ हुई थी। इसीके परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मि० माण्टेगु भारत-मंत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहब विलकूल नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन फिर भी वह इससे पहले ४ वर्ष तक बराबर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १९१२ में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी कर चुके थे। मि० बोनर ला का एक कड़ा भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली हटाने और बग-मग के निर्णय को रद्द कर देने में सर्व भी अधिक हुआ है और सरकार की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचा है। इसके उत्तर में मि० माण्टेगु ने भारत के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण भाषण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी। लोगों की आशा के मुताबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय बाद २० अगस्त को मणि-मण्डल की ओर से, मि० माण्टेगु ने निम्नलिखित घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश-नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना बताया गया था —

“सम्राट्-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भारतीय-शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश-साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय।”

“मे इतना और कहूँगा”, मि० माण्टेगु ने कहा, “इस नीति में प्रगति क्रमशः ही अर्थात् सीढ़ी-दर-सीढ़ी होगी। ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होंगे। वे एक तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें कि इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को

ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होंगे उनपर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायगा।”

लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत प्रतिवन्ध को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह भारत आवेंगे और बाइसराय से परामर्श करेंगे, एव भारत के स्वराज्य की ओर बढ़ने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी बातें करेंगे। २० अगस्त की घोषणा हो चुकी थी और नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये थे।

कांग्रेस का आवेदन-पत्र

६ अक्तूबर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौंसिल की एक सम्मिलित बैठक फिर हुई। इसपर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय। श्रीमती वेसेण्ट स्वयं सत्याग्रह करने के विरुद्ध थी। इससे एक प्रभावकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुवकों में बड़ी निराशा फैली। सम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर बाइसराय तथा भारत-मन्त्री के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की बात तय की। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के हाथ कांग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युक्ति-संगत आवेदन-पत्र भी भेजने की बात तय हुई। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त की गई। श्री० सी० वाई० चिन्तामणि उसके मंत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु से नवम्बर १९१७ में मिला। उस आवेदन-पत्र का मुख्य अंग निम्नलिखित है —

“हर समय और हर परिस्थिति में केवल अधीन-देश की अवस्था बहा के लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली होती है। खासकर उन लोगों को, जो कांग्रेस के जन्मों में एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और जिन्होंने शासन तथा व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया है। जबकि एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहां के निवासी इस बात पर बल-पूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश

को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की खेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशों की भविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों में एक जोरदार आवाज होगी। अब वे वात्स्यावस्था में नहीं हैं, बल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ बराबरी का समझा जाता है। अब पांच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समूह बन गये हैं। अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पार्लियामेंट और (या) साम्राज्य की एक कौंसिल बनाई जाय और उसमें संयुक्त-राज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हों और अगर सारे साम्राज्य के मामलों को यही या यह कौंसिल तय किया करें, और मौजूदा कामन-सभा और लॉर्ड-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करें, तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों का भी शासन हो जायगा। अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा हो तो भारतवासी उसका बड़ी वृद्धता से विरोध करेंगे। और अगर उपनिवेशों का एक भारत और भारतीयों की ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी अपनी वास्तविकता की हृद को बढ़ाने के लिए कभी तैयार न होंगे। भारतवासियों के दृष्टि-कोण से अनिवार्य शर्त केवल यही हो सकती है कि यदि साम्राज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कौंसिल और (या) पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व अवश्य हो। चुने हुए सदस्यों की वही कसौटी रखी जाय जो उपनिवेशों पर लागू हो।

कांग्रेसी हलचलें

इस बीच में कांग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे कांग्रेस-लीग-योजना के लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी मजरबन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती वेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही बार मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड श्रीमती वेसेण्ट को दूर ही रखना चाहते थे। मि० माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर-भाव प्रदर्शित नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह से अपनी अलहदगी दिखलाई। इसका कारण आज तक अगम्य ही रहा है।

१९१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्ट-फोर्ड ही माण्ट-फोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का संबंध घीरा हो रहा था। इनसे विभिन्न स्थानों पर छिष्ट-मण्डल मिलते थे और ये लोगो से हर जगह मिलते थे। श्रीमती वेसेण्ट ने १९१७ के अन्त में, मि० माण्टेगु से भेंट कर लेने के

पश्चात्, अपने कुछ मित्रों से कहा था, "हमें मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए।" नरम-दल वालों ने श्रीमती बेसेण्ट के इन शब्दों की दुहाई प्रत्येक स्थान पर दी। जाहिर है कि मि० माण्टेगु का उद्देश्य यह था कि वह भारत के परम्पर-विरोधी हित रखनेवाले दलों से परामर्श करें और पार्लियामेंट में पैदा करने के लिए एक मसविदा तैयार करें। इनमें से पहला काम तो लखनऊ में १९१६ में हिन्दू-मुस्लिम समझौते ने पहले ही कर दिया था और उसे मि० माण्टेगु ने ज्यो-का-त्यो मान भी लिया था। लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो असलियत है वह तो बहुत से लोगों के लिए एक बिल्कुल ही नवीन बात होगी। वह यह कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड की यह सारी योजना विस्तृत-रूप से मार्च १९१६ में ही तैयार हो गई थी। बात यह थी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुकम पहुँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरियल फीज में मेजर थे। मार्च १९१६ में जब वह इंग्लैण्ड पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गई, जिसके साथ ही उनका नाम जोड़ा जानेवाला था। इसका पता हमें १९३४ में जाकर लगा। इसमें सन्देह नहीं कि मि० माण्टेगु श्रीमती बेसेण्ट, लोकमान्य तिलक और गांधीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी बातें सुनी। लेकिन असलियत में मि० माण्टेगु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया वह तो यह छोट लेना था कि भावी शासन में भत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और एड-वोकेट-जनरल कौन-कौन बनाने लायक हैं। वह उन आदमियों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत करते। इसकी प्रतिष्ठा नि उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पड़ती थी जिसे हम सुनते थे। वह यह कि "हमें मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए।"

१९१७ के इस काल में जब श्रीमती बेसेण्ट का होमरूल-आन्दोलन उन्नति के क्षिप्रा पर पहुँच गया था, गांधीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियों के साथ—जैसे राजेन्द्र बाबू, बृजकिशोर बाबू, गोरख बाबू, अनुपम बाबू (विहार) से और अध्यापक कृपलानी तथा भारत-सेवक-समिति के डॉ० देव को लेकर—विहार में निलहे गोरों के प्रति वहाँ के किसानों की जो शिकायतें थी, उनकी जांच कर रहे थे। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने सब साथियों को भी अलग रखा।

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे, एक बहुत ही सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस-खीग-योजना देश की आपाओ में अनुवादित करा दी जाय, लोगों को उसे समझाया जाय और उसमें

शासन-सुधारों की जो योजना है उसके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर कराये जायें। इस प्रस्ताव को ज्यों ही कार्य-रूप में लाया गया त्योंही देश ने कांग्रेस की शासन-सुधार-योजना का स्वागत किया। यहाँ तक कि १९१७ के अंत तक दस लाख से ऊपर लोगो ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-व्यापी संगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवतः पहला ही प्रयत्न था। लेकिन स्व-शासन के सम्बन्ध में देश को संगठित करने का इससे पहले भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इंग्लैण्ड में घन भी एकत्र किया गया था। १९१५ की बम्बई कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके समापति सर सत्येन्द्रप्रसाद सिंह थे, महासमिति ने यह तय किया था कि कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोष एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी। परन्तु इस दिशा में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं हुई। १८८९ में इस दिशा में एक धार कोशिस और हुई थी। ५० हजार रुपया इसलिए सजूर किया गया था कि इतनी रकम एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी कोष का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस रकम में से केवल ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल बैंक में जमा कर दिया गया था। १८९० वाली बम्बई की उधल-पुधल में इस बैंक का दिवाला निकल गया और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई।

१९१७ की कांग्रेस

श्रीमती वेसेण्ट का कांग्रेस के सभानेत्री-पद से विद्या गया भाषण, भारत के स्व-शासन पर, परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निबन्ध है। सेना और भारत की व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विचारधियों के लिए बहुत-सी सामग्री है। उन्होंने वस्तुतः १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे बिल की मांग पेश की थी जिसके अनुसार "भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज्य दे दिया जाय। वह भी १९२३ तक, या अधिक-से-अधिक १९२८ तक। बीच के पांच या दस वर्ष अंग्रेजों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में लगे। और अंग्रेजों से भारत का बर्ही सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशों के साथ है।" श्रीमती वेसेण्ट के सभानेतृत्व में कांग्रेस तीन दिन का कोई मेला हो कर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती वेसेण्ट ही कांग्रेस की सर्वप्रथम सभानेत्री कही जा सकती हैं जिन्होंने सन्-भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु कांग्रेस

के अवतक के इतिहास में किसी सभापति ने उसपर अमल किया नहीं था। कलकत्ते के अधिवेशन में, ४, ६६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे।

१६१७ की कांग्रेस के इस कलकत्तेवाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़कर पहले-के-से साचे में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलकत्ते के ए० रसूल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और नम्राट् के प्रति भारत की राजभक्ति के प्रस्ताव पास होने के बाद मि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ। मौलाना मुहम्मदअली और शीकतअली के, जो कि अक्टूबर १९१४ से नजरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा, भारतीयों को उचित सैनिक-शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भांति जोर देते हुए इस विषय में उनके साथ न्याय किये जाने की भाग की और जाति-गत भेद-भाव मिटाकर भारतीयों की सेना में कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उसपर सन्तोष प्रकट करते हुए ६ भारतीयों को सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की और इस बात की आशा प्रकट की कि अधिक नम्या में भारतीयों को कमीशन देने की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी। इस बात पर जोर दिया गया कि उनकी तनखाह आदि में वृद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा (१) १९१० के प्रेस-एक्ट-द्वारा शासकों को बहुत विस्तृत और निरंकुश सत्ता दिये जाने, (२) आर्म्स-एक्ट, (३) उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार और उनकी अमुविद्याओं के प्रति अपने विरोध को दोहराया। कांग्रेस ने कुली-अथा को पूर्णरूप से उठा देने के लिए माग पेज की। एक पार्लैमेंटरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतंत्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कानूनों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून के प्रयोग के सम्बन्ध में जाच करे। १० दिसम्बर को सरकार ने रौलट-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-द्वारा इसलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश्य दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था करना था, लोगों के कष्ट दूर करना नहीं। कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को बगाल के क्रान्तिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल जाती थी। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने १८१८ के रेग्युलेशन ३ और भारत-रक्षा-कानून के विस्तृत तौर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता और अय प्रकट किया और इन कानूनों के आखिरी सीचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो असन्तोष फैला हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर देने की प्रार्थना की।

एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, अर्जुनलालजी सेठी के प्राण बचाने के लिए, जो कि धार्मिक कारणों से बेलूर-जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार से बीच में पड़कर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में भारतीयों के प्रबन्ध में, भारतीय-बालिवर-मण्डल स्थापित करने की सिफारिश की। मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है —

“सम्राट् के भारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इसपर यह कांग्रेस कृतज्ञता-पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है।

“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना का विधान करनेवाला एक पार्लियामेण्टरी कानून बने और उसमें बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मिल जाय।

“इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।”

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था आन्ध्र-प्रान्त को एक पृथक् कांग्रेस प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में। इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १९१३ से लेकर १९१५ की कांग्रेस तक आन्ध्र में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या यो कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन बराबर चलता रहा था। आन्दोलन की बुनियाद यह थी कि आन्ध्रवाले कहते थे कि भापा के लिहाज से प्रान्तों का पुनर्निर्माण किया जाय। वास्तव में इसका बीज तो तबसे बोया गया जब से कि १८९४ में श्री महेश्वरारायण ने बंगाल से बिहार को पृथक् कराने का प्रयत्न किया था। १९०८ में कांग्रेस ने बिहार को एक पृथक् प्रान्त बना दिया। २५ अगस्त १९११ को प्रान्तीय स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता बिलायत गया था, उसमें भी यह सिद्धान्त मान्य किया गया था और उसी का यह फल था कि बिहार बंगाल से अलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों का दृढ़ विश्वास था कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनों का माध्यम उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चितरूप से माना जाता था कि स्थानीय-शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश शासन को जो असफलता मिली है, उसका कारण यह है कि ब्रिटिश भारत में प्रान्तों का विभाजन न तो बुद्धिपूर्वक किया गया है, न जातियों के निवास को ध्यान में रख कर किया गया है, बल्कि जैसे-जैसे डलाका हाथ आता गया वैसे-वैसे प्रान्त बनाते चले गये। १९१५ में कांग्रेस इस प्रश्न पर विचार करने के लिए

तैयार न थी। लेकिन १९१६ की आन्ध्र-प्रान्तीय परिषद् ने इस प्रश्न पर बहुत जोर दिया, और ८ अप्रैल १९१७ को महासमिति ने जिसके पास निर्णय के लिए १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था, मदरास तथा बम्बई की प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियो से पूर्ण परामर्श करके, इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि “मदरास प्रान्त के तेलगू भाषा बोलनेवाले जिलों का एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय।” इसके बाद सिन्ध और उसके बाद करनाटक का भी नम्बर आया। इस विषय पर १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विषय-समिति में बड़ी गरमा-गरम बहस हुई। गांधीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार धालू हो जाने तक इस मामले में धरै रहें। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस बात को अनुभव किया कि वास्तविक प्रान्तीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रान्तों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेत्री श्रीमती बेसेण्ट ने भी इसका खूब विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रों ने भी बहुत जोर से मुखालिफत की। इस विषय पर बहस करते-करते दो घण्टे बीत गये। अन्त में रात के १०^१/_४ बजे आन्ध्र का पृथक् प्रान्त बनाना तय हो गया। ६ अक्टूबर १९१७ को महासमिति ने सिन्ध को भी पृथक् प्रान्त मान लिया। उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, नागपुर-कांग्रेस के बाद, प्रान्तों के पुनर्निर्माण में, उसीके अनुसार काम किया गया। इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ प्रान्त हैं जब कि ब्रिटिश-सरकार के केवल ६ प्रान्त ही हैं।

राष्ट्रीय मण्डल

कलकत्ते में श्रीमती बेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेक्रेटरी बनाने की बड़ी इच्छुक थी। इसलिए कांग्रेस-विधान में ससंशोधन करके वह तीन भवियों की नियुक्ति पर जोर देती थी। यह बात स्वीकार कर ली गई और श्री सुब्बराव पन्तुलु ने, जो कि मभी चुने जा चुके थे, तुरन्त ही अपना त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती बेसेण्ट के सभापतित्व में, कलकत्ता-कांग्रेस में, होमरूल-लीग और कांग्रेस एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गई। कलकत्ता की कांग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि उसमें पहली बार राष्ट्रीय झण्डे का सवाल बाजान्ता उठाया गया था। वास्तव में होमरूल-लीग तो पहले ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपूर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित करे। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भी उस कमिटी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी

नहीं हुई। अन्त में होमरूल का झण्डा ही कांग्रेस का झण्डा बन गया। बाद में उसमें चरखा और जोड़ दिया गया था। वह १९३१ तक रहा, फिर झण्डा-कमिटी ने उसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया।

: ४ :

माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना—१९१८

महासमिति की बैठके

१९१७ की कांग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर की महासमिति की पहली बैठक में, कांग्रेस के लिए स्थाई कोष जमा करने के प्रश्न पर विचार किया गया, और प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो से अनुरोध किया गया कि वे भारत और इंग्लैण्ड में शिक्षा और प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना दें। इसके बाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने में ही व्यतीत हुए। विशेषकर मदरास में तो लाखों नोटिस छपवाकर वितरण कराये गये, जिनमें कांग्रेस-लीग-योजना पर प्रकाश डाला गया था। और जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुँचे उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, ६ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराके दिये गये।

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में २३ फरवरी १९१८ में हुई। उसमें सर विलियम वेडरबर्न की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव पास करने के पश्चात् वाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया है उसे असूख कर दें। शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला, लेकिन निरर्थक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु शासन-सुधारो-सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासमिति ने यह निश्चय किया था कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहाबाद में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। उसने इंग्लैण्ड को एक शिष्ट-मण्डल भेजना भी तय किया था।

३ मई १९१८ को महासमिति की तीसरी बैठक हुई। उसमें सीलोन (लका) और जिब्राल्टर से दोनो होमरूल-लीग के शिष्ट-मण्डलो को, जो इंग्लैण्ड को जा रहे थे, वापस लौटा देने पर सरकार का सूब विरोध किया गया। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकारपूर्ण घोषणा कर दी जाय कि लडाई खतम होने पर भारत

को उत्तरदायी शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नहीं बढ़ेंगे।

१९१८ के प्रथम पांच मास में श्रीमती वेसेण्ट ने अथक परिश्रम किया। श्रीमती मारगरेट कजिन्स और श्रीमती डोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती वेसेण्ट को पत्र लिखकर, कांग्रेस-लीग-योजना में, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध किया था इरलैण्ड से मि० जोन स्कर ने उन्हें लिखा था कि कांग्रेस, जून १९१८ में होनेवाली मजदूर-परिषद् को निमन्त्रण दे कि वह अपने भाईचारे के नाते १९१८ की कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजें। महासमिति ने ऐसा ही किया था। यह विचार लोगों को तथा सस्याबो को पसन्द आया और फैलने लगा। और यह प्रजासत्तात्मक सस्याबो के लिए उपयुक्त भी था। "दोनो होमरूल-लीगो ने, दूसरे मास में ही, मि० बैपटिस्टा को, भाईचारे के नाते, अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिषद् में भेजा" श्रीमती वेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये भाषण में कहा, "और मेजर ग्राहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहाँ आ रहे हैं।" वह ब्रिटेन और भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की दृढ़ पक्षपाती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी कल्पना उन दिनों में होमरूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी, यद्यपि १९२६ के उपनिवेशों के दर्जे से उस समय के उपनिवेशों का दर्जा कम था और निश्चित-रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेशों से तो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, श्रीमती वेसेण्ट बीघा ही इस बात को महसूस करने लगी कि उनकी विचार-धारा का मेल न तो सरकार के साथ ही खाता है और न जनता के साथ ही। सरकार उनकी उन्नता को पसन्द नहीं करती थी और जनता उनके पिछड़ेपन को। बम्बई की विशेष कांग्रेस के समय (सितम्बर १९१८) उनके बहुतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-कांग्रेस में (दिसम्बर १९१८) वह बहुत पिछड़ गई थी।

दिल्ली में युद्धपरिषद्

भारत-रक्षा-कानून का दौर देश में सर्वत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। १९१७ में ही लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब से देश-निकाश की आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह लोकप्रिय आन्दोलन दमन के इन चक्रों से भी नहीं दबाया जा सका। जब बम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के प्रश्न को छोड़ा, लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। जब वाइसराय ने दिल्ली में एक सभा

की तो गांधीजी उसमें उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था—क्योंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती वेंसेण्ट को उसमें आमन्त्रित नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त संधि करके क्रुस्तुनियुआ रुम को देने जा रहा था। वह इस विषय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधीजी को विश्वास दिलाया कि यह समाचार स्वार्थी लोगों का (रूस का) फैलाया हुआ है। गांधीजी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में जबकि युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्न न तो उठ ही सकता है और न उसपर विचार ही किया जा सकता है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधीजी युद्ध-समा में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली आने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमन्त्रण नहीं था। लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहाँ से लोकमान्य के लिए देश-निकाले की आज्ञा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जबतक यह आज्ञा भसूख न हो जाय तबतक मैं दिल्ली नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो बिगड़ जाती।

अगस्त १९१८ में लोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा प्राप्त किये बिना व्याख्यान देने की मनाही का नोटिस मिला। एक सप्ताह पूर्व लोकमान्य युद्ध के लिए रगल्ट भर्ती करने में लगे हुए थे और अपनी सदिच्छा के प्रमाण स्वरूप उन्होंने ५० हजार का एक चेक गांधीजी के पास भेजकर आश्वासन दिया था कि यदि गांधीजी सरकार से ऐसा बाबा करा लें कि भारतीयों को सेना में कमीशन मिलने लगेगा तो वह महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गांधीजी का मत यह था कि सहायता सौदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अतः उन्होंने लोकमान्य का चेक लौटा दिया था। १९१७-१८ में कांग्रेस लोकमान्य तिलक से सघन रहती थी। नौकरशाही तो निश्चित-रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती वेंसेण्ट ही उनका साथ दे रही थी।

माण्टेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

जून १९१८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक दृष्टि से वह ऊँचे दर्जे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राज-नैतिक लेखों के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष वयान था। उसमें सुधारों के मार्ग की रुकावटों का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिए। रिपोर्ट के पक्ष में एक और बात भी थी। देश की दो महान् सस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को तैयार किया

था उसमें अपरिवर्तनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी शासन की एक बड़ी ही आकर्षक-योजना थी, जिसमें मन्त्रि-मण्डल बदला जा सकता था। मन्त्रि-मण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी। यह ठीक ब्रिटिश नमूने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और चाहिए ही क्या था? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियों की राय में, कौंसिल भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीमगाह न रहकर सार्वजनिक न्यायालय हो जाती थी, जहाँ कि मन्त्रीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पड़ती और अपने साथी-सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवलम्बित रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके भुलावे में आ गये और इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। पलड़ा कांग्रेस-योजना की ओर से माण्टेगु-बेन्सफोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु की डायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती बेसेण्ट ने इस बात का वादा किया था कि सर फाकरन् नायर जो कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें ही मान्य होगा। और सर फाकरन् नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में मि० माण्टेगु कहते हैं—“मैंने स्पष्ट-रूप से उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं? वह शास्त्रीजी की चार क्सीटिया मानते हैं। मुझे भय है कि वह कभी समय-समय पर होनेवाली जाच-पड़ताल को पसन्द न करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैं वह है एक भीयाद का मुकर्रर हो जाना। लेकिन इस भीयाद के मानी उससे कहीं अधिक है जो समझे जाते हैं।” इसके बाद श्री एस० श्रीनिवास आयगर का जिक्र है, “उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वास्तव में लोग पूरी कांग्रेस-लीग-योजना की स्वीकृति की आशा नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास की गुंजायश है तो वे विशेष परवान करेंगे।” उनका कहना है कि करटिस की योजना सबसे अच्छी है। श्रीनिवास आयगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहाँ यह बता देना जरूरी है कि उस समय वह कांग्रेसी नहीं थे। इन बयानों के बाद हमें मि० माण्टेगु-द्वारा यह जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीतलवाड, चन्दावरकर और रहीमतुल्ला ने ‘सरक्षणों की योजना’ का समर्थन किया था।

एक ओर यह था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के लोगों ने मि० माण्टेगु के दिमाग में अपनी भाग के विषय में किसी भी सदेह की गुंजाइश नहीं रहने दी। “मोतीलाल नेहरू सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय।” (पृष्ठ ६२) “चित्तरजन दास को पहले ही से निश्चय था कि द्वैध शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी। वह ५ वर्ष के भीतर वास्तविक उत्तरदायी

शासन चाहते थे और उसका वादा उसी समय चाहते थे।" (पृष्ठ ६१) मि० माण्डेगु ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पटा लिया था।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आमतौर पर विश्वास था कि उसका अधिकांश मजमून सर (वाद को लॉर्ड) जैम्स मेस्टन और मि० (वाद को सर) मैरिस ने तैयार किया था और लायनल करटिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि० करटिस राउल्ड टेवलवालो में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययन की ओर विशेष थी। वह "साम्राज्य की सेवा के लिए" अनेक देशों का भ्रमण करते रहते थे। भारतीय शासन-सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। वह गलती से कहीं-का-कहीं जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह 'बॉम्बे क्रानिकल' तथा 'लीडर' में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य ने नौकरशाही की चालबाजियों का भण्डाफोड कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अधिकारी जगत् राष्ट्रीय विचारवालों के विरुद्ध क्रोध से उबल पड़ा।

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

माण्डेगोई रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही, इस बात पर भिन्न-भिन्न नेताओं ने तेजी से चर्चा होने लगी कि इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना लाजिमी थी। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। अतः बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और थोड़े ही समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेसवालों ने बड़ा तीव्र मतभेद हो गया था। बंने कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन हा, उनके आलोचना करने के डग में अन्तर जट्टर था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उग्र था, उसे विलकुल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेंगा। कांग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १९१८ को हुआ। श्री हसन इमाम सभापति थे। कांग्रेस में उपस्थिति खूब थी। ३,८४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री बिट्टलभाई पटेल स्वागन्त-समिति के सभापति थे। दीनशा वाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भूपेन्द्रनाथ बसु और अम्बिकाचरण भुजुमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के वाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपनी पुगनी योजना के आधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत

स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। माण्टेगु-योजना की उसने विस्तारपूर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। माण्टेगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो बात कही गई थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहाँ उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य-प्रारम्भ होना चाहिए—और जबतक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तबतक आवश्यक बातों में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे। साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन बातों से शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष-रूप से संबंध होगा उनमें भारत-सरकार को इन अपवादों के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और कुले तौर पर कानूनन मुकदमा चलाये बिना (सम्राट् की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतन्त्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या बोलने या समाजों में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता छीनी जायगी, (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान लाइसेन्स खरीदकर हथियार रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, (ग) छापेखाने स्वतन्त्र रहेंगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मागी जायगी, (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने बराबर होंगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर दृढ़ मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में उसी हद तक की स्वतन्त्रता रहे जिस हद तक की स्वतन्त्र साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों को है। उस प्रस्ताव में, जिसमें कि सुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मंत्री और वाइसराय के प्रत्यक्ष की, जोकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आमतौर पर ये प्रस्ताव निराशा और असंतोष-जनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में वे बातें भी सुझाई गईं जिनका होना उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने के लिए पूर्णतया आवश्यक था। जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित बातों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस जिस तरह स्वराक्षित और हस्तान्तरित विषय रखे जायें उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रखे जायें। रक्षित विषय ये होंगे—वैदेशिक कार्य (उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध; और शेष सब

विषय हस्तान्तरिक रहेंगे। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति बढ़ाया जाय और पार्लियामेंट और भारत-मन्त्री के अधिकार कम किये जायें। इंडिया-कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मन्त्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी सहायक-मन्त्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो। जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कांग्रेस ने निश्चय किया कि छोटी और बड़ी कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बही रहना चाहिए जो कांग्रेस-लीग-योजना में रक्खा गया है। स्त्रियां मताधिकार के अयोग्य न ठहराई जायें। आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पैग की गई थी उसे सरकार ने बिल्कुल अपूर्ण-रूप से स्वीकार किया था। इसपर कांग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयों को सेना में कम-से-कम २५ प्रतिशत कमीशन जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत बीरे-बीरे बढकर १५ साल में ५० फी सदी तक हो जाय। कांग्रेस ने इंग्लैण्ड में गिण्ट-मण्डल भेजना तय किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी।

इस तरह यह बीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह मस्य हो रहा था कि इसमें सुधार के विषय में फूट पड़ जायगी, वह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और गौर के साथ चर्चा होने के बाद ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतों में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश कांग्रेसियों ने पूर्ण-रूप से उनका समर्थन किया। उन्ही दिनों मुस्लिम-लीग की भी बैठक की गई थी, जिसके सभापति थे महमूदाबाद के राजा साहब। उसमें भी कांग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन भारत के दु खों का अन्त नहीं हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के साथ अपना काम कर रहा था। मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों की नजरबन्दी का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अमृतसर-कांग्रेस के पहले अली-बन्धु कांग्रेसी नहीं थे। १९१६ में रिहा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुँच थे। मुहम्मद अली "कामरेड" नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। उनके बड़े भाई शौकतअली "हमदर्द" के सम्पादक थे। यह उर्दू का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से लोगों को दिखाने के लिए बड़ी शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वेल राष्ट्री की रक्षा के लिए रुका जा रहा है। मौलाना मुहम्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम था "मित्र को खाली कर दो"। मौलाना और अली-बन्धु उसी समय

नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था में २५ दिसम्बर १९१९ तक रहे थे, जब कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये।

महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने का तरीका निहायत एतराज के काविल था। इन तरीकों की बदौलत, जिन्हें लॉर्ड विलिंगडन की सरकार ने “दवाव और समझाने के तरीके” कहा था परन्तु जो दरअसल ज़्यादातर धमकी थी, पंजाब और अन्य जगह आगे चलकर भयकर स्थिति पैदा हो गई। देहात में तो “इंटेण्ट” की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना धन मिल सकता था और फिर उसीके अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी बात को कायम रखने के लिये, “दवाव तथा समझाने” की नीति को काम में लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल करते थे। इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने क्रोध में आकर एक तहसीलदार का बगला घेर लिया और उसके बाल-बच्चों को छोड़कर उसे भय बगले के जलाकर भस्म कर दिया।

रौलट कमिटी की रिपोर्ट

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की थी। सर सिडने रौलट उसके सभापति थे और कुमारस्वामी शास्त्री और प्रभासचन्द्र मिश्र सदस्य थे। इसका काम इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक भ्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले पट्टनम फैले हुए हैं। और उनका मुकाबला करने में जो दिक्कतें पैदा आती हैं उनकी भी छान-बीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे। कमिटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह बड़ी कौंसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहलका मच गया। सब जगह विरोध-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय तक केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। कांग्रेस ने रौलट-कमिटी की सिफारिशों की निन्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और वह उचित लोकमत के बनने में बाधक बनेगा।

दिल्ली-कांग्रेस

कांग्रेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन (आनामी दिसम्बर मान में) दिल्ली में होनेवाला था। दिल्ली अधिवेशन का समापति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियो और स्वागत-समिति ने लोकमान्य तिलक को चुना था। लेकिन उन्हें वेलेन्टाइन विरोध पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाना था। अतः समापति बनने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसपर ५० मदनमोहन मालवीय को समापति बनाया गया। हकीम अजमलखा स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १९१८ की अस्थायीसन्धि के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रो को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज तथा मित्र-राष्ट्रो के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा कर दी थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो माण्ट-फोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थी, सामने रखकर कांग्रेस-आमन-नुसार-योजना पर पुनः विचार करे। दिल्ली-कांग्रेस में भी उपस्थिति बहुत थी। ४,८६५ प्रतिनिधि आये थे।

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट् के प्रति राजभक्ति प्रकट की और युद्ध के, जो कि मसार के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्म-निर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की वीरता और सासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशंसा की। तीसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की गई कि शान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशों में समझौते जिनपर स्व-आमन का सिद्धान्त लागू होगा। इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह यह बताई गई कि उन सारे कानूनों, आर्द्धिनेसों और रेग्युलेशनों को, जिनके कारण स्वतन्त्रतापूर्वक राजनैतिक समस्याओं पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरबन्द करने, रोकने, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों में बिना मुकदमा चलाये ही अधिकार दे दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी माग पेश की थी कि साम्राज्य-नीति के पुनः निर्माण में पार्लमेण्ट भी इस देश को ऐसे पूर्ण उत्तरदायी आसन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशों में है। कांग्रेस ने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि शान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियों-द्वारा हो। इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और भी हसन इमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया।

शामन-मुबारो के लिए कांग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशनवाले कांग्रेस-लीग-योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया। साथ ही यह बात भी दोहराई गई कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है और अन्तिम एव देशरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत-सरकार को हों। एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके बलावा जो मुद्दे रह गये थे उन्हें भी दोहराया गया—सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि ये हैं—(१) प्रान्तों में तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्तावित बंध सुबारों के लाभों से किसी भी भाग को वंचित न रखना चाहिए। रौलट-कमिटी की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध में भी बम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई कि इससे शासन-मुबारो को सफलतापूर्वक व्यावहारिक-रूप देने में बाधा पड़ेगी। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा-कानून, प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभाबन्दी-कानून, क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेगुलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दों तथा राजनैतिक कदियों को मुक्त कर दिया जाय।

औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके ५० भवनमोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, विचार हुआ। उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने जाणा की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में यह उद्देश्य सामने रक्खा जायगा कि भारतीय पूँजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशों की लूट से भारत को बचाया जाय। कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि टैरिफ के प्रश्न की जाँच को कमीशन की सीमा से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में उद्योग-धन्वे का पूंथक् प्रतिनिधित्व रक्खा जाय और उद्योग-धन्वों के प्रान्तीय विभाग भी हों। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता बताई जिनमें भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक सस्थाओं और व्यापारी-मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों। उसकी राय में, जिन इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट और केमिकल नौकरियों का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका संगठन निश्चित वेतन पर किया जाय और विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे। रिपोर्ट की सिफारिशों में उद्योग-धन्वों को आर्थिक सहायता पहुँचाने-वाली सस्थाओं का संगठन करने की सिफारिश नहीं की गई थी, इसपर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और औद्योगिक बैंक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताव-

द्वारा कांग्रेस ने सरकार से अली-वन्धुओं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की। युद्ध के बन्द हो जाने और अमृतपूर्व आर्थिक सकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मनोरञ्जक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्सा प्रणाली के लिए जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उन्हीं की व्यवस्था आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय।

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक ओर जहाँ इस कांग्रेस ने बम्बई-कांग्रेस के प्रस्तावों को प्रायः दोहराया, वहाँ कूट आगे भी कदम बढ़ाया। लेकिन यहाँ की कांग्रेस में वह मेल-मिलाप नहीं रहा जो बम्बई में (सितम्बर १९१८) बिछाई दिया। मद्रास प्रान्त और अन्य नरम-दलवाले तो बम्बई प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के अनुकूल था। और जब इंग्लैण्ड को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो यह निश्चय हुआ कि शिष्ट-मण्डल के सदस्य दिल्ली की मांग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे लोग शिष्ट-मण्डल में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे। शास्त्रीजी ने “निराशा-जनक और असन्तोषजनक” शब्दों को निकाल देने का सन्तोष उपस्थित किया और कहा कि १५ वर्ष की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। लेकिन बहुमत से मूल प्रस्ताव ही पास हुआ। अन्त में युवराज का स्वागत-सवधी प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया।

अहिंसा मूर्त-रूप में—१९१६

दिल्ली-कांग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १९१६ के फरवरी में रौलट-विल ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो बिल थे। एक तो अस्थायी था। उसका उद्देश था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना। वह भी युद्ध के बाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास बाद। उसमें यह विधान था कि शान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों की अदालत में पेन हो और वे भी उनका फैसला कर दें एव जिन स्थानों में शान्तिकारी अपराध बहुत हो वहां अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर सदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे किसी स्थान-विशेष में रहने और किसी काम को करने से रोका जा सके। किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जांच एक जज और एक गैर-सरकारी आदमी किया करेगा। तीसरे प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसपर उचित-रूप में यह सदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति-भंग होने की आशंका हो, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानों में बन्द कर दें और यह बता दें कि इन अवस्थाओं या स्थिति में रहना पड़ेगा। और वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से ही जेलों में हैं, उन्हें इस बिल के अनुसार लगातार जेल में रोक रखा जा सकता था। दूसरा बिल साधारण फौजदारी-कानून में एक स्थायी परिवर्तन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराध करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा हो सकती थी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियों पर रखा गया था। उन अपराधों के लिए, जिनके लिए सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये बिना मुकदमा नहीं चल सकता, जिला-मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-द्वारा उस मामले की प्रारम्भिक जांच करवा लें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने में सजा

मिल चुकी हो, जमकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नैऋतलनी की जमानत ली जा सकती थी।

रौलट-विल का गांधीजी द्वारा विरोध

रौलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरी १९१९ को, विलियम विन्सेण्ट ने बड़ी कौंसिल में, रौलट-विलो को पेश किया। पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया था और दूसरा वापस ले लिया गया। गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशों को बिल का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड़ देंगे। इसके लिए गांधीजी ने देश में गर्वज दौंग किया। उनका सब जगह धूमधाम से स्वागत हुआ। गांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया? सरकार इसका उत्तर अपनी १९१९ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है :—

“मि० गांधी अपनी नि स्वार्थता और ऊँचे आदर्शों के कारण आमतौर पर टॉल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके कारण उन्हें वह मव मान-गौरव प्राप्त है जोकि पूर्वी देशों में एक सपत्नी और त्यागी नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह अहमदाबाद में रहने लगे हैं, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दलितों और पीड़ितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये हैं। बम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सवपर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए ‘पूजा’ शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक बल से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रौलट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में सफलतापूर्वक आजमाया था।” २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे। सरकार तथा बहुमत-से भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिन्ता की दृष्टि से देखा। बड़ी कौंसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक-रूप से ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों को बतलाया था। श्रीमती वेसेण्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनोवृत्ति का अच्छा ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तिया उभर उठेंगी जिनसे

न जाने क्या-क्या भयकर बुराईया हो सकती हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट-रूप से बता देना चाहिए कि गांधीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नहीं रक्षात्मक पद्धति है। गांधीजी तो शुरू ही से पशु-शूल की निन्दा करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि वह सविनय-भंग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रौलट-एक्ट का परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रौलट-विल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है —

“सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट बिल न० १ और क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर बिल न० २ अन्यायपूर्ण हैं और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के घातक हैं। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिनपर कि भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम साधन-पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन बिलों को कानून का रूप दिया गया, तो अवतक इन्हें वापस न ले लिया जाय तबतक हम इन तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जानेवाली कमिटी उचित समझेगी, मानने से नञ्जतापूर्वक इनकार कर देंगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे।”

देश ने चारों तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया। हा, प्रारम्भ में बंगाल अलबत्ता खामोश रहा था। दक्षिण ने भी उसमें आशासीत साथ दिया। गांधीजी ने उपवास के साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १९१६ का दिन हड़ताल के लिए नियत किया गया था। इस दिन लोगों को उपवास रखने, ईश्वर-आर्चना करने, प्रायश्चित्त करने तथा देशभर में सार्वजनिक सभायें करने के लिये कहा गया था। बाद को यह तारीख बदलकर ६ अप्रैल नियत की गई। परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची। इसलिए वहाँ ३० मार्च को ही जुलूस निकला और हड़ताल हुई। गोली भी चली। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी अद्वानन्दजी कर रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसपर उन्होंने अपनी छाती खोल दी और कहा—‘ओ, मारो गोली।’ वस, गोरो की धमकी हवा में उड़ गई। लेकिन दिल्ली के रेलवे-स्टेशन पर कुछ क्षण्डा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। “६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ।” सरकार की १९१६ की रिपोर्ट में कहा गया है—“सब लोग बड़े ही उत्तेजित थे। उस समय एक बात भाकें

की दिखाई पड़ती थी। और वह था हिन्दू-मुस्लिम-भ्रातृ-भाव। अब दोनों जानियों के नेता बस इसी एकता की रट लगाये हुए थे। हर समा से यही आवाज निकलती थी। इस ओशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भुला दिये। वह भ्रातृ-भाव का एक अद्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-खुल्ला पानी छेते-देते-थे। जूल्सों के झण्डों और नारों दोनों से, हिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खड़े होकर हिन्दू-नेताओं को धोखे में भी दिया गया था।” इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात् टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वभावतः बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फैली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भावनाओं के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की।

देश ने इस नई विचार-धारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया। कांग्रेस तथा देश दोनों के लिए गांधीजी बहुत मान्य हो गये थे। १९१८ की दिल्ली-कांग्रेस में शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में श्री चित्तरजन दास का एक प्रस्ताव था। उसमें गांधीजी का नाम मूल से छूट गया था। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती ने यथोही इस ओर प्रस्तावक का ध्यान खींचा, उन्होंने क्षमा-याचना करते हुए प्रतिनिधियों की सूची में गांधीजी का नाम जोड़ दिया। इंग्लैंड के लिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल के सदस्यों में भी उनका नाम था। १९१९ के अप्रैल मास से भारतीय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

पंजाब की दुर्घटनाये

भारतवर्ष के कष्ट-सहन और सघर्ष का दृश्य अब पंजाब में दिखाई देने लगा जो कि विदेशी उद्योग-वन्धे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना हुआ है। पंजाब सिक्खों तथा भारत की अन्य सैनिक जातियों का निवास-स्थान है। क्या पंजाब को, पढ़े-लिखे और कांग्रेसी लोगों को अपने स्वराज्य-आन्दोलन के लिए इस्तेमाल करने को सखी छोड़ दिया जाय? इसलिए पंजाब का निरंकुश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन की छूत की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात पर रस्ता-कशी थी कि आया १९१९ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस पंजाब में हो या न हो। १० अप्रैल १९१९ के दिन प्रातः काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर

किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो कि कांग्रेस का सगठन कर रहे थे, अपने बगले पर घुला भेजा और वहा से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक सनसनी फैल गई। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुँच गई। और लोगो का एक झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहा उनका पता पूछने के लिये जानेवाला था, परन्तु उस चौराहे पर, जो शहर से सिविल-लाइन की ओर जाते हुए सिविल-लाइन और शहर के बीच में है, फौजी सिपाहियो ने भीड़ को रोक लिया। और अब वह इंटो के फेंकने की कहानी आती है जो सरकार की मदद के लिए हर वस्तु तैयार रहती है। भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगो की भीड़ अब शहर को वापस लौटी और मरे हुए और घायलो का शहर में होकर जुलूस निकाला। रास्ते में नेशनल-बैंक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। इस प्रकार लोगो की उत्तेजित भीड़ ने ५ अग्रेजो को मारा और बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स्वभावतः अधिकारी इन घटनाओ से आग-बबूला हो गये। स्थानीय अधिकारियो ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई। कसूर में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार और सिगनल तोड़-फोड़ डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियो को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। एक ब्राउन्च-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाला। मुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। यह सरकारी ध्यान का सारांश है। परन्तु लोगो का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी।

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उसपर पत्थर बरसाये। एक छोटे-से रेलवे-पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहा कि गाँव का एक मरा बच्चा लटका हुआ था। लोगो का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओ की भावनाओ को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-धर, डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। डाक-बगला, कलक्टरी कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये तो हुई खास-खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुई। जैसे रेल-गाड़ियों पर पत्थरों का फेंका जाना तारों का काटा जाना और रेलवे-स्टेशनों में आग का लगाया जाना।

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इनके-दुक्के हिंसा-काण्ड हुए। लाहौर में भी लूट-मार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्घटनाओं की बात सुनकर तथा स्वामी अद्वानन्द और डॉ० सत्यपाल के बुलाने पर गांधीजी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इसपर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठाकर १० अप्रैल को बम्बई भेज दिया गया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अप्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को वीरभगवान और नडियाद में भी कुछ उत्पात हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था—वहाँ गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह घायल हुए थे। बम्बई पहुँच कर गांधीजी ने स्थिति को धान्त करने में मदद की और फिर वहाँ से अहमदाबाद की ओर चल पड़े। उनकी उपस्थिति ने शान्ति स्थापित करने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला।

एक ओर यह स्थिति थी तो दूसरी ओर अमृतसर में दुर्घटनायें विकट रूप धारण करती जा रही थी। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानून जारी करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। जैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक-रूप में फौजी-कानून जारी था। सब पूछिए तो लाहौर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही फौजी-कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में वह और जारी कर दिया गया था। १३ अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के सवत्सर का दिन था, अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जालियावाला-बाग में एक बड़ी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के भकान ही इसकी चहार-दीवारी बनाये हुए हैं। इसका दरवाजा बहुत ही सकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उभरें होकर नहीं निकल सकती। बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें,

पुरुष, स्त्रिया और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घुसे उस समय हसराम नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे कि हुन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-वितर होने की आज्ञा दी और फिर इस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-वितर हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलावा दी थी। यह बात तो स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-वितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तग बरबाजे में होकर। गोली तब तक चलती रही जबतक कि सारे कारतूस खतम नहीं होगये। कुल सोलह सौ फँर किये गये थे। सरकार के स्वयं अपने बयान के मूताविक बार सौ मरे और बायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजों से चलावाई गई थी, जिनके पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब बाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे। सबसे बड़ी दुःख बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहाँ उन्हें रात-भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरों या कोई अन्य सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया, “चूँकि बाहर फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की डोढ़ी पिटवा दी गई थी कि कोई भी सया करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मैंने उन्हें एक सवक बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।” आगे चल कर उसने कहा कि “मैंने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। मैंने सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे।” उसने और कहा—“मैं तो एक फौजी गाड़ी (आरम्भ कार) ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था।”

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजायें भी देखने को मिली जिनका सपने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और विजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बँत लगाना आमतौर पर चाछू था। लेकिन ‘पेट के बल रँगने के हुक्म’ ने इन सबको मात कर दिया था। मिस शेरबुड नाम की एक पादरी लेडी-डॉक्टर पर उस

समय कुछ लोगो ने अक्रमण किया था जब कि वह एक गली में साइकिल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल रेंगकर जाने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के बल रेंगकर जाना और आना पड़ता था, हालांकि उस गली में रहनेवाले भले आदमियों ने ही मिस शेरवुड की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बड़ी कांसिल में क्वार्टर-मास्टर-जनरल हट्सन के लिए यह घटना एक हँसी का विषय बन गई थी।

रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। इससे लोगो का सफर करना आमतौर पर बन्द हो गया था। दो आदमियों से अधिक एक-साथ पटरियों पर नहीं चल सकते थे। साइकिलें सब-की-सब फौज ने अपने कब्जे में ले ली थी। केवल यूरोपियन लोगो की साइकिलें उनके पास रहने दी गई थी। जिन लोगो ने अपनी दूकानें बन्द कर दी थी उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया। न खोलनेवाले के लिए कठोर दण्ड की आज्ञा थी। चीजों की फीमन फौजी अफसरों ने नियत कर दी थी। बैलगाड़ियां उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। किले के नीचे नगा करके नव के सामने बँत लगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के अनेक भागों में बैत लगवाने के लिए टिकटिकिया लगवा दी गई थी।

अमृतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फसला किया गया था, उनके कुछ आकड़े यहाँ देते हैं। सगिन जुर्मों के अभियोध में २६८ आदमियों पर मार्शल-लॉ-कमीशन के सामने मुकदमे चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जानने के साधारण नियमों के पालन करने का भी, जिनके अनुसार आमतौर पर हर जगह मुकदमे चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था। इनमें से २१८ आदमियों को सजायें दी गईं। ५१ को फाँसी की सजा, ४६ को आजीवन कालापासी, २ को १०-१० बरस की सजा, ७६ को ७-७ बरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को ३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोड़ी मियाद की सजायें दी गईं। उनमें से मुकदमे शामिल नहीं हैं जिनका फँसला सरमरी में फौजी अफसरों ने रिया था। इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और १०५ आदमियों को मार्शल-लॉ के अनुसार मुल्की-मजिस्ट्रेटों ने सजा दी थी।

हृन्टिंग-मिडो के सदस्य जस्टिस रेनिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहाँ देते हैं —

जस्टिस रेनिन—जनरल, मुझे उस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा कीजिए, कि जानने जो-कुछ किया वह क्या एक प्रकार का अद-ग्रेशन नहीं था ?

जनरल डायर—नहीं, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तव्य था, जिसका मुझे पालन करना पड़ा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैंने सोचा कि मैं खूब अच्छी तरह गोली चलाऊँ और इतने जोर के साथ चलाऊँ कि मुझे या अन्य किसी को फिर कभी गोली न चलानी पड़े। मेरा खयाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीड़ को तितर-बितर कर देता। लेकिन वे फिर घापस आ जाते और मेरी हँसी उड़ाते और मैं बेवकूफ बना होता।

जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, जो पंजाब के गवर्नर थे, उचित ठहराया था। आपकी ओर से जनरल डायर को एक तार दिया गया था, जिसमें लिखा था—“आपका कार्य ठीक था। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सराहना करते हैं।”

उपर्युक्त बातें जो लिखी गई हैं वे तो वे हैं जिन्हें हुन्टर-कमीशन के सामने १९२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वयं स्वीकार किया था। अमृतसर की घुर्घटना के बाद, पंजाब से आने और जानेवाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी थी कि घुर्घटना का विस्तारपूर्वक समाचार कांग्रेस-कमिटी को भी जुलाई १९१६ से पहले नहीं ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो खुल्लम-खुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसो-सिएशन के भवन में जब कांग्रेस-कमिटी की बैठक हो रही थी, यह समाचार कानों-कान भरते-भरते कहा गया—फिर भी यह सावधानी रखी गई कि यह समाचार औरो से न कहा जाय। पंजाब की घुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही बल्कि लाहौर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी अत्याचार और वर्बरतापूर्ण अमानुष क्रूरों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा सुनकर खून खौलने लगता है।

फौजी कानून

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा लाहौर में फौजी कानून का बहुत जोर था। करफ्यू-आर्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति शाम के ८ बजे के बाद बाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था, बेत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता था, कैद हो सकती थी, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दूकानें बन्द थी उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा सकता और या उसकी दूकान खोलकर सारा सामान लोगों में मुफ्त बांट दिया जा सकता था।

वकील तथा दलालों को यह आज्ञा दे दी गई थी कि वे शहर से बाहर कहीं न जावें। जिनके भवानों की दीवारों पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे

उन्हें यह हुक्म दे दिया गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसी ने उन्हें बिगाड़ दिया या फाड़ दिया तो वे सजा के मुस्तहक होंगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ बराबर दो आदमियों से अधिक के चलने की मनाही थी। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह आज्ञा थी कि वे दिन में चार बार, फौजी अफसरों के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। लगर या अन्न-क्षेत्र बन्द कर देने का हुक्म दे दिया गया था। हिन्दुस्तानियों की मोटर-साइकिलों तथा मोटरों को फौज में जमा कर देने का हुक्म जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, अधिकारियों को वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई थी। हिन्दुस्तानियों के पास अपने जो बिजली के पक्षे थे उन्हें तथा बिजली के अन्य सब सामान को धरो से निकलवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए जमा करा लिया गया था। किराये पर चलनेवाली सवारियों को शहर से बहुत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखानी पड़ती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, शाम के आठ बजे के बाद, अपनी दूकान के द्वारके बाहर गली में अपनी गाय की देख-भाल करते पाया गया। वह तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया और करप्पू-आर्डर तोड़ने के इलजाम में उसके बेंत चढ़वा दिये। तागेवालों ने भी हूबताल में भाग लिया था। इन लोगों को मबक सिक्काने के लिए ३०० तागे जमा कर लिये गये थे, और यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर की घनी आबादी से बाहर, कुछ खास मुकर्रर वक्त और जगहों पर, अपनी हाजिरी दिया करें। इसमें तुरा यह था कि फौजी अफसर, चाहे जिस तागे को, चाहे जब, अपनी इच्छा पर ही रोक लेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता था। कर्नल जॉनसन ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी बहुत-सी आज्ञायें पटे-लिखे तथा पेसेवर आदमियों के लिए ही थी, जैसे बकील आदि। उसका सवाल था कि यही वे लोग हैं जिनमें से राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते हैं। व्यापारी लोग तथा अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतों पर फौजी कानून के आर्डर चिपके हुए थे, उन नोटिसों की रक्षा के लिए चौकी-महुरा बिठाना पड़ा था ताकि उन्हें कोई बिगाड़ या फाड़ न जाय। भूमविन या कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हें फाड़-फूड़ जाय। एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जब लोगों ने चौकीदारों के लिए पानों की दरग्यास्त दी ताकि वे लोग रात के ८ बजे के बाद बाहर रह कर उन नोटिसों की नगवान्दी कर सकें, तो उत्तर मिला था कि उन्हें अपने लिए पान भिन्न सबते हैं, मोनरो के लिए नहीं। १९ में २० वर्ष की उम्र के लड़कों तथा विद्यार्थियों पर विनोप-भ्य में पड़ी नज़र थी। लहौर जैसे शहर में, जहाँ कई क्रॉन्गे है, विद्यार्थियों को दिन

में चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहा हाजिरी ली जाती थी उनमें एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील की दूरी पर था। अप्रैल मास की कठाले की घूप में, जोकि पंजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबकि गरमी १०८ डिग्री से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना १६ मील पैदल चलना पड़ता था। इनमें से कुछ तो रास्ते में वेहोश हो कर गिर भी जाते थे। कर्नल जॉनसन का खयाल था कि इससे उनको लाभ होता है और वे शरारत करने से बाज रहते हैं। एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक नोटिस फाड़ डाला गया था। इस अपराध में कॉलेज के वेतनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिन्सिपल भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजी पहरे में उन्हें किले तक कवायद करते हुए ले जाया गया था, जहा कि वह फौजी पहरे में तीन दिन तक कैद रखे गये थे। किले के एक कोने में उन्हें रहने को स्थान दिया गया था।

इसना होने पर भी कर्नल जॉनसन, इन दिनों में जो कुछ भी उन्होंने किया उससे, बहुत ही प्रसन्न थे। और लाहौर के यूरोपियनों ने तो उन्हें बिदाई देते समय एक दावत दी थी और "गरीबों का रसक" की उपाधि से अलंकृत करके उनकी भूरिभूर प्रशंसा की थी। गुजरानवाला में कर्नल ओब्रायन ने, कसूर में कैप्टन डोवटन ने और शेखूपुरा में मिस्टर बॉसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार करने में खूब ही नाम कमाया था।

अमानुषिक क्रूरताएँ

कर्नल ओब्रायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि मीड जहा कहीं पाई गई वही उसपर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेंट डॉइकिन्स के चार्ज में था, एक खेत में २० किसानों को एकत्र देखा। उन्होंने उनपर मशीनगन से तबतक गोली चलाई जबतक कि वे भाग नहीं गये। उन्होंने एक भकान के सामने आदिमियों के एक झुण्ड को देखा। वहा एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए वहा उन्होंने उनपर एक बम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिल में इस तरह का कोई शक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुर्दनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्वी वह सज्जन हैं जिन्होंने लोगों के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग बलवाई हैं, जो शहर से आ-जा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए —

"लोगों की मीड दौड़ी जा रही थी और मैंने उनको तितर-बितर करने के

लिए गोली चला दी। ज्योंही भीड़ तितर-बितर हो गई, मैंने गांव पर भी मचीनगन लगा दी। मेरा खयाल है कि कुछ मकानों में गोलियां लगी थी। मैं निर्दोष और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता था। मैं दो सौ फीट की ऊँचाई पर था और यह भले प्रकार देख सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उद्देश की पूर्ति केवल बम बरसाने से ही नहीं हुई। गोली केवल नुकसान पहुँचाने के लिए ही नहीं चलाई गई थी, वह स्वयं गाववालों के हित के लिए चलाई गई थी। कुछ को मार कर, मैं समझता था, मैं गाववालों को फिर एकत्र होने से रोक दूँगा। मेरे इस कार्य का असर भी पड़ा था। इसके बाद शहर की तरफ मुड़ा। वहाँ बम बरसाये और उन लोगों पर गोलियां चलाई जो भाग जाने की कोशिश कर रहे थे।”

गुजरानवाला, कसूर और खेबूपुरा में भी अमृतसर और लाहौर के समान ही करफ्यू-आर्डर जारी कर दिया गया था, हिन्दुस्तानियों की आमदरफ्त रोक दी गई थी, एकान्त में और सड़के सामने बैठ लगवाये जाते थे, झुण्ड-के-झुण्ड एक-साथ गिरफ्तार कर लिए जाते थे और सरकारी तथा खास अदालतों से सजायें विला दी जाती थी।

कर्नल ओब्रायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर सवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाय, अगर छाता लगाये हुये हो तो उसे नीचे झुका दे। कर्नल ओब्रायन ने कमिटी के सामने कहा था कि “यह हुक्म इसलिए अच्छा था कि लोगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नये मालिक आये हैं। लोगों के कोठे लगवाये गये, जुर्माना किया गया और पूर्वोक्त राक्षसी हुक्म न मानने पर अन्य अनेक प्रकार की सजायें दी गईं। उन्होंने बहुत-से आदमियों को गिरफ्तार कराया था, जिनको बिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्ते तक जेल में रक्खा। एकवार उन्होंने शहर के बहुत-से प्रमुख नागरिकों को यकायक पकड़कर मालगाडी के एक डब्बे में भर दिया। उस डब्बे में उन लोगों को एक-के-उमर-एक करके लाद दिया। सो भी तब जब कि वे कड़ाके की धूप में कई मील पैदल चलाकर लाये गये थे। कुछ लोगों के चदन पर तो पूरे कपड़े भी नहीं थे। मालगाडी के डब्बे में भरकर उन्हें लाहौर भेज दिया था। उन्हें पाखाना-मेवाब तक करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसी अवस्था में वे मालगाडी के डब्बे में ४४ घंटे तक रक्खे गये। उनकी जो भयानक दयनीय दशा हो गई थी, उसका वर्णन करके बताने की विषेय आवश्यकता नहीं। वे जिस समय गलियों में होकर ले जाये जा रहे थे उस समय उनके साथ-साथ रास्ते-बल्लते और लोग भी थोही

पकड़ लिये जाते थे और इसलिए उनकी सख्या सदैव बढ़ती रहती थी। उन्हें हाथों में हथकड़ियां डालकर और जंजीरों से बांधकर निकाला गया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जंजीरों में बांध कर ले जाये गये थे। लोग समझते थे कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का यह मजाक उड़ाया जा रहा है। कर्नल ओब्रायन का कहना था कि यह इत्तफाक से हुआ था। यह सारी कार्रवाई किस स्प्रिट में की जा रही थी, इसे देखने के लिए इतना बतना देना काफी होगा कि नगर के एक वयोवृद्ध महानुभाव भी इस घटना के शिकार हुए थे। वह बाहर के एक बड़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक लाख रुपया सम्राट् की भारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जार्ज स्कूल को दान दिया था। बाद में रिलीफ-फण्ड और वार-लोन में भी उन्होंने बहुत कुछ रुपया दिया था।

दूसरी मिसाल, कर्नल ओब्रायन के कारनामों की, यह है कि उन्होंने एक बूढ़े किसान को गिरफ्तार किया था। वह इसलिए कि वह बेचारा अपने दो लड़कों को पेश नहीं करा सका। इतना ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली थी, और लोगों को यह चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने भी उसको अपनी फसल से मदद की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने कमिटी के सामने यह स्वीकार किया था कि बूढ़े ने स्वयं—कोई अपराध नहीं किया था, “लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके बेटे कहा हैं।”

कर्नल ओब्रायन के बड़े-बड़े कारनामों के इतिहास में से ये कुछ नमूने यहाँ दिये गये हैं। दो सौ आदमियों को सरसरी अदालतों से सजायें मिलीं। बँत की सजा या एक महीने से लेकर दो वर्ष तक की सजा का दण्ड दिया गया। कमीशन ने १४९ आदमियों को सजा दी, जिनमें से २२ को फाँसी, १०८ को आजीवन काला-पानी तथा शेष को दस साल और उससे कम की सजा का दण्ड दिया गया था। कर्नल ओब्रायन का अन्तिम कार्य यह था कि उन्हें जब यह मालूम हुआ कि कल फौजी कानून समाप्त होनेवाला है तो उन्होंने बहुत-से लोगों के मुकदमों को २४ घंटे के भीतर ही खतम कर देने की व्यवस्था की। ओब्रायन महाशय इतने आतुर थे कि जिन मुकदमों की तारीख कई दिन पहले की डाली गई थी उनको अदालत-द्वारा तत्काल ही फैसल करा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि फौजी कानून खतम हो जाय और लोग उनके न्याय में वञ्चित रह जायें।

कैप्टन डोवटन कसूर के इलाके में एक प्रकार से सर्वे-सर्वा ही थे। इस स्थान पर लोगों को खुलेआम फाँसी देने के लिए एक फाँसी-भर बनाया गया। यह स्थान, वहाँ के निवासियों के लिए, एक आतंक-गृह हो गया था। रेलवे-स्टेशन के पास एक

बड़ा पिंजटा बनवाया गया था, जिसमें १५० आदमी रखे जा सकते थे। जिन लोगों के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमें बन्द कर दिया जाता था, ताकि आम जनता उन्हें देख सके। नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड सनास्त करने के लिए कराई जाती थी।

लोगों को खुलेआम बेंत लगवाये गये। लोगों को मिर से पैर तक नगा करके तार के खम्भे या टिकटिकियों से बांधा जाता था। यह सार्वजनिक प्रदर्शन सोच-समझ के निश्चित किया हुआ था। एकवार नगा करके पिटता हुआ देखने के लिए, गहर की वेद्याओं को लाया गया था। इस घटना के लिए कैप्टन साहब को हृष्टर-कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो कुछ 'शर्म' मालूम हुई थी—ठीक उसी प्रकार जिम प्रकार कर्नल जॉनसन को एक बरात को बेंत लगवाने के मामले में कमिटी के सामने 'दुःख हुआ था।' कैप्टन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस सबइन्स्पेक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बेंत लगना देखने के लिए बुला लाने। लेकिन जब वहाँ मैंने स्त्रियों को देखा तो मैं दग रह गया। परन्तु कैप्टन साहब उन वेद्याओं को वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे बेंतों की भार देखने के लिए वहाँ-की-वहीं बनी रही।

कैप्टन डोवटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दक्ष थे। इनके आविष्कार करने में उनका एक-मात्र उद्देश यह था, उनको "इतना आसान और नरम बनाना" जितना कि उस परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनों के माल-गोदामों पर मालगाड़ियों में माल लादने और उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि जिसके अनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी।

मि० बॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होंने धोलूपुरा में फौजी-कानून का दौर-दौरा किया था। उन्होंने अपने वयान में इस बात को स्वीकार किया था कि फौजी-कानून 'आवश्यक तो न था, परन्तु मेरी राय में वह 'वाञ्छनीय' अवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सारे मुकदमों का फैसला किया था और जैसा कि अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहाँ से भी बेंत की सजाएँ दी जाती थी। और, अदालत उठने ही अपराधियों के बेंत लगवा दिये जाते थे। ६ मई से लेकर २० मई तक उन्होंने ४७७ आदमियों के मुकदमे किये थे।

फौजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के

लडके वाध्य थे कि वे दिन में तीन बार परेड करें और झण्डे को सलामी दें। यह हुक्म स्कूल की छोटी जमाती के बच्चों के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ वरस तक के बच्चे भी शामिल थे। किन्तु ही बच्चे लू लंग कर मर गये थे। कुछ मौकों पर लडकों से यह कहलाया जाता था, “मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है।”

मेजर स्मिथ से, जो कि गुजरातवाला, गुजरात और लायलपुर में फौजी-कानून के अधिष्ठाता थे, जब सर चिमनलाल सीतलवाड ने पूछा कि “आया यह हुक्म उनके सारे इलाके-भर में लागू कर दिया गया था और आया यह सब क्लासों पर लागू और छोटे बच्चों की क्लास भी उसमें शामिल थी?” मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहाँ-जहाँ फौजें थी वहाँ-वहाँ सब जगह हुक्म किया गया था। यहाँ तक कि पांच और छ वरस तक के बच्चों से भी परेड कराई जाती थी। लेकिन छोटे बच्चों को आम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया गया था।”

कर्नल ओब्रायन ने अपनी गवाही में कहा था, कि मैं एक दिन बजीराबाद में था। मैंने देखा कि एक लडका झण्डे की ओर मार्च करने में बेहोश हो कर गिर गया। मैंने फौज के अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में लिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन बार परेड कराई गई थी। इस प्रश्न के उत्तर में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई? कर्नल ओब्रायन ने उत्तर दिया, ‘नहीं’।

कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिमाग में लोगों से अफसोस बाहिर कराने की भावना अवश्य प्रबल रही थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक “प्रायश्चित्त-गृह” बनाने का था। लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि इस इमारत में दस हजार रुपये लगे थे। इन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढने के इच्छुकों को तो कांग्रेस-कमिटी के सामने दी गई गवाहिया और कांग्रेस की रिपोर्ट ही पढनी चाहिए।

दुर्घटनाओं के बाद

गांधीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप धारण कर लेने में बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने हिमालय के समान महान् मूल की है। अतः उन्होंने एक ओर तो सत्याग्रह को स्वयं गत कर दिया और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि मैं शान्ति स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हूँ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रैल १९१९ को एक हुक्म निकाला,

जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थी कि वह उत्पातों का शीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सब को लगा देगी। इसी बीच तीसरे-अफगान-युद्ध ने पंजाब की स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। ४ मई को सारी फौज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई थी। इधर फौजी कानून अपने खूनी कारनामों को ११ जून तक बराबर चलाता रहा और रेलवे के अहातों में तो यह बहुत दिनों तक इसके बाद भी जारी रहा था। फौजी कानून को अनावश्यक-रूप से एक मुद्दा तक जारी रखने के विरोध में सर चार्ल्स नायर ने १६ जुलाई को बाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय में पंजाब पर एक कठोर सेंसर बिठा दिया गया था। एण्डरूज साहब को पंजाब की भूमि में कदम रखने की मनाही कर दी गई थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया। यह मई मास के प्रारम्भ की बात है। मिस्टर ई० नाटन वैरिस्टर को, जो कि पंजाब इसलिए जाना चाहते थे कि वहाँ कैदियों की पैरवी करें, पंजाब में घुसने की मनाही कर दी गई थी। चारों ओर से पंजाब में हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक कमीशन बैठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी अदालतों-द्वारा जो लोगों को घातकी और जगली सजायें दी गई थी उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी मांग थी। लाला हरकिशनलाल को, जो कि एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी और बहुत बड़े धनिक व्यक्ति थे, आज़म काले-पानी की सजा दी गई थी। ४० लाख रुपये के लगभग उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्म दिया गया था।

सितम्बर १९१६ में बाइसराय ने हन्टर-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की, कि वह पंजाब के उपद्रवों की जांच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर को, इनडेमिटी-बिल आया, जो कि आमतौर पर फौजी कानून के साथ आया करता है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए बहुतेरा जोर लगाया, वह साढ़े चार घंटे तक बराबर बोले, लेकिन जवाब यह दिया गया कि बिल की मंशा केवल कानूनी सजा से रहित रखने की ही है—उन अधिकारियों को जिन्होंने 'भ्रान्ति और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही' सब कुछ किया था। फिर भी उनके साथ महकमे की कार्रवाई तो की ही जा सकती है।

सर दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेमिटी-बिल के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख है वह ठीक है। श्रीमती वेंसेण्ट, जो अवतक बराबर गांधीजी में लडती रही थी, बोली कि रोलट-बिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक को एतराज हो सके। "जब लोगों की नीड मियाहियों

पर रोडे बरसावे तब सिपाहियों को गोली के कुछ फेंक करने की आज्ञा दे देना अधिक दयापूर्ण है।” इस लेख के बाद ही श्रीमती बेसेण्ट के नाम के साथ यह वाक्य—“ईट के रोडो के बदले में बन्दूक की गोलियाँ”—सदा के लिए जुड़ गया था। इस समय श्रीमती बेसेण्ट की लोकप्रियता रसातल को पहुँच गई थी।

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गाबीजी को दिल्ली और पंजाब से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोध किया गया और पंजाब में किये गये अत्याचारों की जाँच करने पर जोर दिया गया। देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए श्री विट्टलमार्ड पटेल और श्री नृसिंह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ। ये लोग २६ अप्रैल १९१६ को इंग्लैण्ड के लिए रवाना भी हो गये थे। ८ जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। डचर गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रैल को ही एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पंजाब की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जुर्म हुए हों उनका मुकबला वह खास फौजी अदालत द्वारा करा सके। गिरफ्तारगुदा लोगों को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नहीं थी। देश के सारे प्रमुख पक्षों के सम्पादकों ने, श्रीमती बेसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एण्डरूज साहब से अनुरोध किया था कि वह पंजाब जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जाँच करें। पर वह वहाँ गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बैठक में इस और अन्य दूसरे मामलों पर विचार हुआ था। उसमें यह बात भी सुझाई गई कि तत्कालीन के लिए जो कमिटी नियत हो वह पंजाब जाकर इस बात की भी जाँच करे कि सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रगस्ट भर्ती करने में किन हथकण्डों और ढंगों को काम में लाया गया था, किस प्रकार ‘लेबर कोर’ में आदमियों को भर्ती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी कानून के दिनों में किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हार्निमैन को इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, कि उन्होंने ‘बाम्बे अनिकल’ में सरकार की पंजाब-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निमैन साहब को दिये गये देश-निकाले के हुक्म को मसूख कर दे।

यह इच्छया

यहाँ पर प्रसंगवश यह बात भी बता देना अनुचित न होगा कि हार्निमैन

साहू के चले जाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसकी 'यंग इण्डिया' द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ में 'यंग इण्डिया' को श्री जमनादास टारकादास ने होमरूल के दिनों में निकाला था। बाद में वह एक सस्था के हाथों में आ गया। श्री शंकरलाल वैकर इस सस्था के एक सदस्य थे। जब मि० हार्निमैन को देश-निकाला दे दिया गया, और 'बाम्बे क्रानिकल' के ऊपर कड़ा सेंसर बिठा दिया गया था, तब गांधीजी ने 'यंग इण्डिया' को अपने हाथों में ले लिया।

पंजाबकाण्ड की जाँच

हा, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पंजाब की दुर्घटनाओं की जाँच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए धन एकत्र करे। इस कमिटी में वाद को यानी १६ अक्टूबर को, गांधीजी, एण्डरूज, स्वासी अद्वानन्द तथा अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया था। नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज को तो यकायक ऐन मौके पर दक्षिण-अफ्रीका चला जाना पड़ा था। उन्होंने गवाहियों के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-कमिटी को देते गये थे। यह भी निश्चय हुआ था कि लन्दन और बम्बई के श्री नेविली और कैप्टिन को, जो कि क्रमशः दोनों स्थानों में सालिसिटर थे, इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय। महासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदनमोहन मालवीय ने प्रधानमंत्री को, एक भारत-मंत्री को, और एक लॉर्ड सिंह को दिया था, जिनमें इन लोगों से अनुरोध किया गया था कि जबतक कांग्रेस की जाँच पूरी न हो जाय तबतक फौजी कानून के अनुसार दी गई तमाम सजायें मुलतवी रखी जायें। इस समय तक सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह प्रिवी-कौंसिल के मेम्बर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और लॉर्ड हो गये थे। तभी से वह रायपुर के लॉर्ड सिंह कहलाये जाने लगे। वह उपभारत-मंत्री नियुक्त किये गये, और बाद में उन्होंने ही लॉर्ड सभा में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया बिल पेश किया था। १६ और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की बैठक फिर हुई, जिसमें विचारणीय मुख्य बात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहा किया जाय और उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा उस भाग को फिर दोहराया गया था जिसमें सम्राट् की सरकार-द्वारा जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि १६

जुलाई को ही सर अकरन् नायर ने बाइसराय की कार्यकारिणी से फौजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके इस्तीफे की बड़ी कृतज्ञता-पूर्वक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की कि वह तुरन्त ही इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो जायें और वहाँ जाकर गली प्रकार से पंजाब के मामले को रखें और उन लोगों के सारे दुःखों को दूर करावे। १० हजार रुपये की एक रकम पंजाब-कमिटी के लिए जमा की गई।

सत्याग्रह स्थगित

२१ जुलाई को गांधीजी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थगित करने का जिक्र था। वह इस प्रकार है —

“बम्बई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही बुरा परिणाम निकल सकता है। बम्बई के गवर्नर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उस समय यह चेतावनी और श्री जोर के साथ दोहराई थी। इन चेतावनियों को और दीवानबहादुर एल० ए० गोविन्द राघव ऐयर, सर नारायण चदावरकर तथा अन्य कई सम्भावकों ने जो सुले-रूप से इच्छा प्रकट की उन सबको ध्यान में रखकर, मैंने बहुत सोच-विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्भ न करूँ। मैं यहाँ पर इतना और बता देना चाहता हूँ कि उन कुछ मित्रों ने श्री, जो गरम-बल के माने जाते हैं, मुझे यही सलाह दी है, उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि इससे सम्भव है वे लोग, जिन्होंने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर बैठें। जब दूसरे सत्याग्रहियों के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अब समय आ गया है कि सविनय भंग के रूप में सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, तब मैंने बाइसराय को एक पत्र भेज कर उनपर अपना यह इरादा प्रकट कर दिया और उनसे यह अनुरोध किया था कि वह रौलट-बिल को वापस ले लें, एक जोरदार और निष्पक्ष कमिटी शीघ्र नियुक्त करने की घोषणा करें, जिसे यह श्री अधिकार रहे कि पंजाब की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दी गई सजाओं की फिर से निगरानी कर सके और बा० कालीनाथ राय (सम्पादक ‘ट्रिब्यून’) को, जिनके मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें अन्याय-पूर्वक दण्ड दिया गया है, छोड़ दे। भारत-सरकार ने श्री राय के मामले में जो निर्णय किया उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस

वात का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जाच-कमिटी की नियुक्ति के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सम्भावना के इन प्रमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमझी होगी, यदि मैं मरकार की चेतावनी पर ध्यान न दूँ। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाना है। एक सत्याग्रही कभी मरकार को विषम स्थिति में डालना नहीं चाहता। मैं अनुमत्त करता हूँ कि मैं देश की, सरकार की ओर उन पंजाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्यायपूर्वक सजा दी गई है, और वह भी बड़ी ही निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा करूँगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर दूँ। मेरे ऊपर यह डलजाम लगाया गया है कि अगर तो मैंने ही लगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना आज लगाना है, तो रोलट-कानून और उसे कानून की किताब में ज्यों-का-त्यों बनाये रखने का हठ देश में हजार स्यानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया जाय। भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन में जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनमें भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बढ़ावे और स्वदेशी के प्रचार में सबका सहयोग प्राप्त करें।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेल्वार्न की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लियामेण्टरी कमिटी की बैठक हो रही थी। अब हम यहाँ भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कार्यवाही को देखें, यद्यपि हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विठ्ठलभाई पटेल और वी० पी० माधवराव ने बड़ी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया था। इनके साथ लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्रपाल गणेश श्रीकृष्ण सापरे हैं डाक्टर प्राणवीरन मेहता, ए० रंगास्वामी आण्णर, नृसिंह चिन्तामणि केलकर, सम्यद हसनइमाम डॉ० साठवे, मि० हार्निमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रखे। श्री वी० पी० माधवराव मैसूर-राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतंत्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता की नजरो में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० वेन स्मूर (एम० पी०) जैसे ने उनकी शूरि-शूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का काम उठाकर, इंग्लैण्ड के विभिन्न

भागों में प्रचारार्थ सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन-समा के भवन में उन्हें विदाई की दावत दी और भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहानुभूति का सन्देश भेजा। स्वतंत्र-मजदूर-दल ने ग्लामगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयलण्ड और मिस्र के साथ-साथ भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 'नैशनल पीस कौंसिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारबरो में होनेवाले अपने वार्षिकोत्सव में माग की कि "अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त संरक्षण रखते हुए, आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनर्संगठन किया जाय।" पंजाब के जोरो-जुलम का तो सभी सत्यागो ने समान-रूप से प्रबल विरोध किया।

महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, ५० मोतीलाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पंजाब में हुई दुर्घटनाओं की जाच के लिए पंजाब गये। कुछ ही समय बाद दीनबन्धु एण्डरसन भी वहाँ पहुँच गये। इसके बाद ५० मोतीलाल और मालवीयजी लौट आये, लेकिन मोतीलालजी दुबारा फिर वहाँ गये। ५० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन एण्डरसन साहब के साथ हुए। गांधीजी भी, जैसे ही उनपर से प्रवेश-निषेध का हुक्म उठाया गया, १७ अक्टूबर को सबके साथ जा मिले। पंजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन ज्यों ही गांधीजी उनके पास पहुँचे त्योंही उनमें फिर से आत्म-विश्वास आ गया। लाहौर और अमृतसर में, दोनों जगह, उनके आगमन को विजय से कम नहीं समझा गया। इसी बीच सरकारी जाच की घोषणा हुई। जिन बातों की जाच सरकारी जाच-कमिटी करनेवाली थी उनकी मर्यादा कांग्रेस की जाच से बहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग करना ठीक समझा गया। चित्तरजन दास तुरन्त कलकत्ता से पंजाब आये और कांग्रेस की ओर से हण्टर-कमीशन के सामने हाजिर हुए। लेकिन कांग्रेस-उप-समिति को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनकी पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुर्घटनाओं की जाच करनेवाली कमिटी (हण्टर-कमीशन) से उसको अपना सहयोग हटा लेना पड़ा। इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक आवेदन-पत्र में अंकित है। कांग्रेस-उप-समिति चाहती थी कि मार्शल-लॉ के कुछ कैंदियों को पहले के अन्दर जाच के समय हाजिर रहने व जाच में मदद करने के लिए बुलाया जाय, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दी गई। उप-समिति ने इसपर पंजाब-सरकार के खिलाफ भारत-सरकार और भारत-मन्त्री से अपील की, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। ऐसी हालत में उन लोगों ने भी, जो कि फौजी कानून के मातहत जेलों में थे, सहयोग न करने के

निश्चय की ही ताईद की—और, वाद के अनुभव ने भी इस निश्चय को उचित ही सिद्ध किया। और तो और, पर उसकी जाच की परिधि इतनी नीमित थी कि वे घटनावे भी उसके कार्य-क्षेत्र में समाविष्ट नहीं थी, जो न्यायत अप्रैल १९१९ की घटनाओं में ही सम्मिलित होती हैं पर अनुचित रूप से उन्हें उससे अलग रक्खा गया अतएव कांग्रेस ने एक कमिटी के द्वारा अपनी जाच अलग शुरू की। गांधीजी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरजन दास, फजलुल हक और अब्बास तैयबजी इस कमिटी के सदस्य थे और के० सन्तानम् मंत्री। लेकिन इसके बाद शीघ्र ही प० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-कांग्रेस के समापति निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये। लन्दन के सालिसिटर मि० नेविली भी, जिनके सुपुर्ब प्रिवी-कौंसिल में की जानेवाली अपीलों का काम था, कमिटी के साथ थे। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जालियावाला-बाग को प्राप्त करके वहाँ शहीदों का एक स्मारक बनाया जाय, और उसके लिए मालवीयजी की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी गई। प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और राष्ट्र की ही सम्पत्ति है।

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्टें अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी। तब सोचा तो यहाँ तक गया कि सुविधापूर्वक विस्तृत-रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उसपर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि "हण्टर-कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात विलकुल निस्संदिग्ध हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निशस्त्र मर्दों और बच्चों के जान-बूझ कर किये हुए नृशंस हत्या-काण्ड के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और बुजदिल पशुता है जिसकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती।" जो हो, कुल मिलाकर १९१९ के साल की परिस्थिति न केवल निराशाजनक बल्कि बड़ी भयावह भी थी।

तिलक का प्रतिसहयोग

महायुद्ध में जो शक्तियाँ लगी हुई थी उन्हें पार्लमेण्ट की तरफ से घन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि० कायड जार्ज ने कहा था—“हिन्दुस्तान के विषय में कहूँ तो, उसने हमारी इस विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा इतना जोरदार है कि हमें अपने तमाम पूर्व-विश्वासों

और (हमारी) आशकाओं को, जो कि उसकी प्रगति के रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, दूर कर डालना चाहिए।" जहातक इस 'नये दावे' से सम्बन्ध है, अस्थायी सधि के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओं का बदला धारा सभाओं और अधिकारियों-द्वारा दमन के रूप में चुकाया है। माण्ट-फोर्ड विल ने लोगों के दिलों को और भी आघात पहुँचाया। द्विविध प्रणाली, कौंसिल में नामजद-सदस्यों का रहना, राज्य-परिषद्, 'सर्टिफिकेशन' और 'विटो' के अधिकार, ऑर्डिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली बातें उस विल में थीं। अब १९३५ के कानून में ये और भी बढ़ा-चढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं। यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड़-फोड़ करनेवाली शक्तियाँ अवश्य जोर-शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होगी। क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती रही हैं और बिदेसी-शासन में तो ये अपना जोर जताती ही हैं। खुद होमरूल-लीग में भी उनके दर्शन हुए थे। अमृतसर में वे अपने पूरे दल-बल के साथ प्रकट हुईं। लोकमान्य तिलक उस समय तक इंग्लैण्ड से लौट आये थे। सर बेल्लेण्डन विरोध पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे में उनकी हार हो चुकी थी। उन्होंने यह सुनते ही कि पार्लेमेण्ट में विल पास हो गया है, सम्राट् को भारतीय राष्ट्र की तरफ से बधाई का तार भेजा। उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होंने सुधारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आश्वासन दिया था। यह शब्द गढ़ा हुआ तो था मि० बैपटिस्टा का, और तार का मजमून बनाया था केलकर साहब ने। कांग्रेसी हलके में इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, अमृतसर-कांग्रेस भिन्न-भिन्न विचारवालों के सघर्ष का एक अच्छाडा ही बन गई।

अमृतसर-कांग्रेस

अमृतसर-कांग्रेस में श्री चित्तरजन दास प्रमुखता से सामने आये। उस अविवेशन में उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास दावू बनाकर लाये थे और सशोधन के बाद विषय-समिति ने उसे मजबूर किया था। वह इस प्रकार है —

“(क) यह कांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बातें समझी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है।

(ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-द्वारा पास किये गये

प्रस्तावों पर ही कायम दृढ़ है और उम्मीद यह है कि मुघल-शासन अपूर्ण, अस्तोन्नत और निगमापूर्ण है ।

(ग) कायम यह कायम अनुगोचर नहीं है कि ज्ञान-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भाग्यार्थ में पूर्ण अनुगोचरिता करना कायम करने के लिए पार्लियमेंट को शीघ्र तारतम्य करनी चाहिए ।"

गांधीजी ने 'निगमापूर्ण' शब्द को हटा देने और उसमें चौथा पैरा और जोड़ने का अनुरोध ऐसा किया जो इस प्रकार है —

"(घ) जनता ऐसा न ले, यह कायम शाही घोषणा में प्रदर्शित मनोभावों का जर्थात् यह है 'यह नया युग मेरी प्रजा और अधिपारी दोनों के इस निम्नत्व के साथ आरम्भ हो कि वे सबके एक स्येय के लिए मिलकर काम करेंगे', राजभक्तिपूर्वक उत्तर देनी है और सिद्धान्त रानी है कि अधिकारी और प्रजा दोनों मिलकर शासन-मुषागे को गार्हस्थित करने में सम तत्त्व सहयोग करेंगे कि जिसमें पूर्ण उत्तरदायी शासन शीघ्र स्थापित हो । और यह कायम माननीय माण्डेगु को उन मिलमिले में लिये उनके परिश्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद देती है ।"

कायम ने दास बाबू के असली प्रस्ताव और गांधीजी के पूर्वोक्त टुकड़े की जगह यह टुकड़ा जोड़कर मजूर किया—“यह कायम विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्यवाई नहीं की जाती तबतक, जहातक नभब हो, लोग सुचारो को इस प्रकार काम में लावेंगे जिनसे नाग्यत्वपूर्ण में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके । सुचारो के सम्बन्ध में माननीय माण्डेगु माहब ने जो मिहलत की है उसके लिए यह कायम उन्हें धन्यवाद देती है ।” श्रीमती बेनेट ने इसकी जाह जो प्रस्ताव रक्खा था वह गिर गया ।

फिर भी यह समझीता असदिग्ध नहीं था—हालांकि देशबन्धु ने अपने भाषण में यह भाष्य कर दिया था कि जहा कहीं सम्भव होगा वहा सहयोग और जहा आवश्यक होगा वहा अडगा-नीति काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित है । परन्तु इसमें विधि की गति तो देखिए—दास बाबू या तो अडगा-नीति चाहते थे या सुचारो को अस्वीकृत कर देना—क्या इसे हम असहयोग न कहें ? और गांधीजी वहा सहयोग के पुरस्कर्ता बने हुए थे । इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी कांग्रेस गांधीजी की ही एक विजय थी । उनके व्यक्तित्व, दृष्टि-विन्दु, सिद्धान्त और आदर्श, नीति-नियम एवं उनके सत्य और अहिंसाधर्म का प्रभाव पहले ही कांग्रेस पर पड़ चुका था । अमृतसर-कायम में ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ठेठ डॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने से लेकर कानून मालगुजारी,

मजदूरो की दुरवस्था और तीसरे दर्जे के मुसाफिरो के दुखों की जाच की माग तक के प्रस्ताव थे। खुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि थे और कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे। कांग्रेस के सारे वातावरण में मानो विजली फैली हुई थी। पंजाब और उसपर हुए अत्याचारों पर स्वभावतः ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। गांधीजी उत्सुक थे कि पंजाब और गुजरात में जो मार-काट लोगों की तरफ से हो गई थी उसकी निन्दा की जाय। लेकिन विषय-समिति में उनका प्रस्ताव गिर गया। गांधीजी को इससे निराशा हुई। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने यदि कांग्रेस उनके दृष्टि-बिन्दु को न अपना सके तो दृढ़ता परन्तु साथ ही शिष्टता और अदब के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरे ही दिन सुबह प्रस्ताव न० ५ मंजूर हुआ, जो इस प्रकार है—“यह कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि बहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समूह के लोग क्रोध से बावले हुए थे, तो भी पिछले अप्रैल के महीने में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो व्यावृत्तियाँ हुईं और उनके कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ उसपर यह कांग्रेस दुःख प्रकट करती है और उन कृत्यों की निन्दा करती है।” इस विषय पर गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह तो बड़ी उच्चकोटि का और प्रभावशाली था। उन्होंने बहुत संक्षेप में अपने सप्राप्त की योजना और भावी नीति का दिग्दर्शन कराया था। “इससे बढकर कोई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी कुंजी इसी बात में है कि हम इसके मूलभूत सत्य को समझ लें, हृदय से स्वीकार कर लें और इसके अनुसार आचरण भी रखें। जिस अंश तक हम उसके मूल शाश्वत मूल्य को मानने में असमर्थ होंगे उसी हद तक हमारी असफलता भी निश्चित है। मैं कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मार-काट न की होती—जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण हैं और उन्हें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, बीरमगाम, अहमदाबाद और बम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहाँ हमने जान-बूझकर हिंसाकाण्ड किया है—हाँ, मैं मानता हूँ कि डॉ. किचलू, डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़कर—मैं तो डॉ० सत्यपाल और स्वामीजी का निमन्त्रण पाकर आन्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा था, सरकार ने लोगों को भडकाने और गरम हो जाने का अवर्दस्त कारण दिया था—तो यह बखेडा न खड़ा होता, लेकिन उस समय सरकार भी पागल हो गई थी और हम भी पागल हो गये थे। मैं कहता हूँ, पागलपन का जवाब पागलपन से मत दो, वरिन् पागलपन के मुकाबले में समझदारी से काम को और देखो कि सारी बाजी आपके हाथ में है।” कैसे आत्मा को जगानेवाले शब्द हैं

में, जो जयसतानानों में गूँजते हैं ! परन्तु गवाह यह है कि क्या लोगों ने उम्र समय उनके पूरे राज्य को गमना होगा ? तब पूछिए तो फिर कांग्रेस में सारी बातें इसी प्रस्ताव के मुर में नूँद थीं। उम्र समय तक गांधीजी सरकार में सहयोग होने के लिए न तो राजी थे और न तैयार ही थे। इसीलिए मुबारज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहाँ पास किया गया—गोवा दिल्ली में जो बात छूट गई थी उसकी पूर्ति यहाँ की गई। यही कारण है कि अमृतसर में सहयोग के आश्रयमानवाले प्रस्ताव में जोड़ा गया टुकड़ा पाय हो गया, हालांकि समझौते के कारण वह बहुत-कुछ कमजोर हो गया था। मध्य और बहिष्ता को माननेवाले इन प्रस्ताव में मिलते-जुलते प्रस्ताव थे (१) स्वदेशी-सम्बन्धी—हाथ-भस्ताई और हाथ-बुनाई के पुराने धंधों को फिर से जीवित करने की सिफारिश करना, (२) दुधार गाय और साढ़ों का निर्यात बन्द करने सम्बन्धी, (३) प्रान्तों में आवकारी-मीनि-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा मसले-दों के मुसाफिरो के दुख दूर करने के विषय में। इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही इन के प्रस्ताव थे—बकरीद पर गोबुधों बन्द कर देने की मुसलमानों-द्वारा की गई सिफारिश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुर्की एवं सिलाफत के मसले पर ब्रिटिश-सचिवों के विरोधी रुख का विरोध करना। वर्षों के बाद इस अमृतसर-कांग्रेस ने किमानों की ओर ध्यान दिया। मजदूरों की तरफ भी उसने उतनी ही तबज्जह दी। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। शिष्टि-कमिटी को उनकी सेवाओं के बदले धन्यवाद दिया गया। उसी तरह इंग्लैण्ड के मजदूर-बल को, और खासकर बेन स्पूर को भी। लाला लाजपत राय को भी, उनकी अमरीका में की गई भारत के प्रति सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। इसी तरह कांग्रेस के शिष्ट-मण्डल को भी उन सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया जो उसने इंग्लैण्ड में की थी। मला 'प्रवासी भारतवासी' भी कैसे छूट सकते थे ? द्रासबाह-निवासियों से अवतक भी जमीन-जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। पूर्व अफ्रीका में भारतीयों का आन्दोलन अलग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतीयों के लिए की गई एण्डरुज साहब की सेवाएँ पंजाब में की गई उनकी सेवाओं से कम देश के धन्यवाद की पात्र नहीं थी। कांग्रेस ने खुले-आम इस बात को स्पष्ट किया कि क्यों उसे हफ्टर-कमीशन का बहिष्कार करना पड़ा ? लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर ने "पंजाब के जो नेता कैद हैं उनमें से कुछ को भी, कैदी की तरह हिरासत में भी, कमिटी-रूप में बैठकर अपने वकील को सहायता और सलाह देने की आज्ञा नहीं दी" इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिष्कार को योग्य और शानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी स्वतन्त्र रिपोर्ट का आदेश

मि०। कांग्रेस ने मंगलान् नामक दो स्त्रीका दे देने पर बर्षाई की और लॉर्ड चेम्स-
फोर्से को नाम चुनने, अन्य जय की जाने पर ने द्वा देने और सर माउकेल
आजान् की पंक्ति की गन्धवा में द्वा देने की माग की।

पञ्जाब में मि० गे० अन्तागा के प्रश्न पर विचार करते हुए कांग्रेस ने उस
प्रश्न को दो भागों में, जो एक-दोनों पर फर्क-फर्की लागू की गई थी, तथा फीजी
प्रश्न को साक्षात् करने और कांग्रेस के विचारों को जा मजबूत दी गई उन्हें स्व
गन्धवा की प्राप्ति की। मौलाना अहिंसके सम्बन्धी भी एक प्रश्नाव पाम हुआ, जिसने
साक्षात्-अहिंसके सम्बन्धी प्रश्नाव का बन्ध और बन्ध गया। इस प्रश्नाव को पाम कराने
के लिए गे० ने एक बड़े गे० मन्त्रालय के विमान पर विजयराधधानार्थ जोर देते रहे।
उन्नी जन् कांग्रेस ने प्रमोद और रोड-मार्ग को उठा देने और मन्त्रालय की ओर से
मन्त्रि की संज्ञा होने पर भी जो फेरी मन्त्रालय में पड़े हुए, वे उनकी रिहाई के
लिए जंगल में।

मि० शनिधन का देश-विवाद भी कांग्रेस के विरोध का एक विषय था और
उन्नी जन् पन्धर वर जोर दिया गया। यह भी जागृ किया गया कि ब्रह्मदेश को
भी मुद्रा में जाये और दिग्गि नया अजमेर-मोरपात्र को पूरे प्रान्त के हक दे दिये
जाये। उन्नी जन् प्रश्नों में आदि तथा दोनों में समा बगूल करने की कार्रवाई की
गई और अधिवेशन समा हुआ। उस अधिवेशन में इतना अधिक काम करना पड़ा
कि मन्त्रालय पण्डित मोनीलाल नेट्स् बहुत थक गये, उनकी आवाज बँठ गई। विषय-
मूर्ति की बँठने राज गन्-गन् भर चली। पञ्जाब में सर्दी भी बड़े जोरो की
पड़ी थी।

उस समय की दो घटनायें मनोरञ्जक हैं और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक
होगा। गजनेत्रिक कीदियों को छोड़ देने की बाही घोषणा हुई। कांग्रेस के अधिवेशन
के कुछ दिन पहले यह अमृतसर पहुँची और उनके साथ ही आये अन्नी-मार्ड। यस,
लोगों के उत्साह और खुशी की सीमा न रही। एक बज्र जुलूस निकला और श्री०
मुहम्मदअली ने कहा कि मैं छिन्दवाड़ा-जेल से 'स्टिर्न-टिक्ट लेकर' आ रहा हूँ। तबसे
उनके ये शब्द बहुत प्रचलित हो गये हैं। दूसरी घटना लन्दन के एक सालिसिटर मि०
रेजिनाल्ड नेविन्की ने सम्बन्ध रखती है, जो कुछ दिनों से भारतवर्ष में थे और कांग्रेस-
सप्ताह में अमृतसर ही थे। २५ दिसम्बर १९१६ को जालन्धर के तोपखाने के कोई
२० गोरे सिपाही रात को (होटल में) उनके कमरे में घुस गये, उनका अपमान किया
और पूछा कि एक यूरोपियन होकर तुमने लायर के खिलाफ काम कैसे किया? उनमें

मे एक ने कहा—“तुमने माँ को मृत को गोली से भून दिया। वह एक सौदागर
जन-मृत था। वे रजनी हिन्दुस्तानी थे।” उसने यह भी बताया कि जन्म ६
वे उन मियादियों में से यह भी पता था। बाद में मालूम हुआ कि उन सिपाहियों
मि० नेविली ने माँ की मागनी भी थी।

: १ :

असहयोग का जन्म-१९२०

खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय

१९२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में दलबन्धियों से हुआ। उदार अर्थात् नरम-दलवाले कांग्रेस से अलग हो गये थे और १९१९ के दिसम्बर में कलकत्ते में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी ताजा होनेवाली घटनाओं के कारण बाकी दल कांग्रेसियों में फूट के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृतसर में मुख्य प्रश्न था असहयोग या अडग। नये साल का आरम्भ होने के कुछ महीने बाद अमृतसर में बने दलों की स्थिति उल्ट गई। गांधीजी ने असहयोग का बीड़ा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकबार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकस्मिक परिवर्तन किस कारण हुआ? असली बात यह थी कि पञ्जाब के अत्याचार और खिलाफत के सवाल पर जनता में खलबली बढ रही थी।

१९२० की घटनायें खिलाफत के महान् आन्दोलन को लेकर हुई थी। यहा खिलाफत के प्रश्न की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है। महायुद्ध के समय प्रधान-मंत्री मि० लायड जार्ज ने भारत के मुसलमानों को कुछ वचन दिये थे, जिनके कारण भारतीय मुसलमान देश से बाहर गये और अपने तुर्की सहधर्मियों से लड़े। जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये वचनों का धुरी तरह भंग किया गया। ब्रिटिश-प्रधान-मंत्री के विश्वासघात से भारत के मुसलमानों में क्रोध की लहर फैल गई। लायड जार्ज ने स्पष्ट शब्दों में वचन दिया था, कि "हम तुर्कों को उसके एशिया-माइनर और यूस के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपों से वंचित करने के लिए, जिनकी आबादी मुख्यतः तुर्क हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।" मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुलअरब, जिनमें मेसोपोटामिया, अरबिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन और उनके सारे धार्मिक स्थान शामिल हैं, हमेशा खलीफा के सीधे अधिकार में रहना चाहिए। परन्तु अस्थायी सन्धि

की शर्तों के फल-स्वरूप तुर्की को अपने प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। घुसू शूनान की नजर कर दिया गया और तुर्की-साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ्रान्स ने लीग के आज्ञा-पत्रों के बहाने आपस में बांट लिया। मित्र-राष्ट्रों-द्वारा एक हार्द-कमीशन नियुक्त किया गया जो हर लिहाज से तुर्की का असली शासक बना दिया गया था और सुलतान एक कैदी-मान रह गया था। भारत के मुसलमान ही नहीं, बल्कि अन्य जातियां भी ब्रिटिश-प्रधान-मंत्री के इस विश्वासघात से क्रुद्ध हो गई थी। अमृतसर में प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफत नेता एकत्र हुए और उन्होंने लायड जार्ज को करारों से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त में गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय किया गया।

१६ जनवरी १९२० को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला और उन्हें बताया कि तुर्की-साम्राज्य को और सुलतान को सलीफ बनाने रखना कितना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ निराशाजनक था। इसपर मुसलमान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ सकल्प किया कि यदि सधि की शर्तें मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ गईं तो इसने मुसलमानों की वफादारी को घनका लगेगा।

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र में बराबर प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा। १९२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट-मण्डल मौलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया। इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की ओर से मि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्डल प्रधान-मंत्री से भी मिला। उसने अपने विचार शान्ति-परिषद् की बड़ी कौंसिल के आगे रखने की अनुमति चाही, पर वह न मिली।

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जैसे तुर्की तुर्की-भूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा। वत, इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट डाली। इसलिए १६ मार्च राष्ट्रीय शोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन उपवास, प्रार्थनायें और हड़तालें की गईं। गांधीजी फिर मैदान में आये; उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ सधि की शर्तें भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हों तो मैं असहयोग-आन्दोलन

शुरू करेगा। गांधीजी ने अपने विचार अपने १० मार्च के घोषणा-पत्र में प्रकट कर दिये थे, जिसमें उन्होंने अपनी असहयोग-सम्बन्धी तजवीज पहली बार प्रकट की थी। वह इस प्रकार है —

"यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोड़िए, क्योंकि यह अव्यवहार्य है। यदि मैं सबको समझा सकूँ कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायें। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग-द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु आज जो मैं हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ सो इस कारण कि परिस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिंसा बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होगी। अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औपधि है। यदि यह सब तरह की हिंसा से मुक्त रखी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामबाण औपधि है। यदि सहयोग के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे वार्षिक भावों को आघात पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिये कर्तव्य हो जाता है। इंग्लैंड हमसे यह आशा नहीं रख सकता कि हम उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हमें जब और चोटी दोनों ओर से काम आरम्भ करना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी उपाधियाँ और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें वे त्याग देनी चाहिए। जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर हैं उन्हें भी नौकरियाँ छोड़ देनी चाहिए। असहयोग का खानगी नौकरियों से कोई वास्ता नहीं है। पर मैं उन लोगों के, जो असहयोग की औपधि को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने की बात को पसन्द नहीं कर सकता। आप होकर नौकरी छोड़ देना ही जनता के भावों और असंतोष की कसौटी है। सैनिकों से सेना में काम करने से इन्कार करने को कहने का समय अभी नहीं आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं है। अब बाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान मंत्री हमें दाद ही न दें तभी हमें इस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहुत समझ-बूझकर रखना होगा। हमें धीरे-धीरे बढ़ना होगा, जिससे बड़े-से-बड़े उत्तेजन पर भी हम अपना आत्म-समय बनाये रख सकें।"

असहयोग का प्रारम्भ

अशान्ति के इस वातावरण में २५ मार्च १९२० को पंजाब के अत्याचारों पर

गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अपने कटकों का लक्ष्य बनाया। उसने शिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-बूझकर अवहेलना की थी, उसने जिस ग्यादती के साथ रंगस्टो की भर्ती और चढ़ा-सग्रह किया था और लोकमत को दबा-रक्खा था, उससे वह स्वभावतः ही जनता के अभियोग का पात्र बन गया था। १९१९ की घटनायें ६ अप्रैल से आरम्भ हुई और उनका अन्त १३ तारीख को जालिपांवाला-बाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ। अतः वह सप्ताह १९२० में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे अवतक मनाया जाता है। १४ मई १९२० को तुर्किस्तान के साथ संधि की शर्तें प्रकाशित हुईं, जिससे खिलाफत-आन्दोलन में और भी जोर पकड़ा। इसके बाद ही गांधीजी ने इस संकल्प की घोषणा की कि मैं शर्तों में सशोषण कराने के लिए असहयोग-आन्दोलन आरम्भ करूँगा। लोकमान्य तिलक ने इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं किया, पर साथ ही विरोध भी नहीं किया।

इन दोनों महान् नेताओं ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये। इसी अवसर पर गांधीजी ने होमरूल-लीग का समापनसिद्ध ग्रहण किया, और निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया—

“मेरी राय में स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भाषा मानना, और प्रान्तों का भाषाओं के अनुसार नये सिरे से निर्माण करना है। इसलिए मैं लीग को उन कामों में लगाना चाहता हूँ।

“मैं इस बात को खुले तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की किन्नी भी योजना में सुधारों का स्थान गौण है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने जिन कामों का जिक्र किया है यदि राष्ट्रीय शक्ति उनमें लग जाय तो हममें से घोर अतिवादी (extremist) भी जो सुधार चाहेगा वे स्वतः ही प्राप्त हो जायेंगे, और चूँकि इन कार्यों में लगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें राष्ट्रीय कार्य-क्रम में सबसे आगे रक्खा है। मैं बखिल-भारतीय होमरूल-लीग को किसी भी रूप में किसी खास दल की सस्था समझने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी दल से सवध नहीं रखता और न रखूँगा। मैं जानता हूँ कि लीग के नियमों के अनुसार कांग्रेस की सहायता करना आवश्यक है। पर कांग्रेस किसी दल-विशेष की सस्था नहीं है। ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में सभी दल रहते हैं। समय-समय पर एक-न-एक दल का उसपर अधिकार रहता है, पर वह किसी दल-विशेष की संस्था नहीं है। मुझे आशा है कि सारे दल कांग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय सस्था बनाना चाहेंगे जिसके द्वारा वे कांग्रेस की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से अपील कर सकें। मैं लीग की नीति को

मेगा बनाना चाहता हूँ जिनके मागे दलबन्दियों में ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद राखने में मेरे।

“अब मेरे गान की आरंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में गंभीर नृत्य और संगानदानी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मैं लीग में यह जाना नहीं सकता कि वह सत्ताग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मैं शक्ति-भर चेष्टा करता हूँ कि हमारे नारे राष्ट्रीय मामलों में गत्य और अहिंसा से काम लिया जाय। सर हम गणतन्त्र और उनके उपायों में न भयभीत होंगे न उनके प्रति अविश्वास करेंगे। मैं उन प्रश्नों पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह समय पर ही टोला हूँ कि मैंने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उसमें उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रश्नों का वह किन्तु मैंने निपटारा करता हूँ। फिरहाल मेरा उद्देश्य अपने काम के धीमे या उममें भगवत्प्रेम नीति की सत्ता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लोग के मन्दियों पर विचार करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमन्त्रित करना है।”

लोकमान्य तिलक ने अपने वाक्पथ में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट की —

“जैसा कि नाम में प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातन्त्र दल में कांग्रेस के प्रति अगाध शक्ति और प्रजातन्त्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को सुलझाने में प्रजातन्त्र के सिद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्षा के प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सबसे बढ़िया हथियार समझता है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक बंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय। इस दल का धार्मिक सहिष्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की क्षति से रक्षा करना मर्यादा का अधिकार और कर्तव्य है। यह दल मुसलमानों के उस दावे का समर्थन करता है जो सिलाफत-सम्बन्धी प्रश्नों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं और कुरान के आदेशों के अनुसार चाहता है।

“यह दल मानवता के मूल और मानव-समाज के प्रादुर्भाव की वृद्धि के लिए ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतन्त्र शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह के अन्य हिस्सेदारों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, बराबरी और भाई-भारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए

बराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहाँ यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय। यह दल राष्ट्र-संघ का, संसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों और जातियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने, और एक देश के द्वारा दूसरे देश का रक्तशोषण बन्द करनेवाली सस्था के रूप में स्वागत करता है।

"यह दल जोर के साथ प्रसिपादन करता है कि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन के सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार का हाथ स्वयं तैयार करने का और यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली भारत के लिए सबसे अच्छी रहेगी, पूर्ण अधिकार चाहता है। यह दल माण्डेगु-सुधार विधान को अपर्याप्त, असन्तोषपूर्ण और निराशाजनक समझता है और इस दोष को दूर करने की चेष्टा करने के निमित्त मजदूरदल के सदस्यों और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के अन्य भारत-हितैषियों की सहायता से शीघ्र-से-शीघ्र एक नवीन सुधार-बिल पास करायेगा जिसका उद्देश भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करना हो और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारण्टियों-सहित अधिकारों की विस्तृत बोधना करे। इस उद्देश की सिद्धि के लिए यह दल विचार रखता है और सिफारिश करता है कि भारत में और उन देशों में जो राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं खूब जोर का प्रचार किया जाय। इस मामले में इस दल का शुक्रमत्र होगा—'प्रचार, आन्दोलन और संगठन'।

"यह दल माण्डेगु-सुधारों को, जैसे कुछ भी वे हैं, सफल बनाने का विचार रखता है, जिससे देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय, और इसलिए यह दल, बिना किसी संकोच के, लोकमत को कार्य-रूप देने के लिए जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या बहिष्कार से विरोध करेगा।"

इसके बाद केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयों की एक सूची दी गई थी जिनके लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था। उनमें दमनकारी कानूनों, राजद्रोह के अभियोगों का जुरी-द्वारा निर्णय, जेल-स्थवस्था में इरलैण्ड के जैसा सुधार, मजदूरों का संगठन और सुधार, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के विकास पर नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, सैनिक-सर्व में कमी, कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरिया, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता, कर-प्रवृत्ति, प्रांतिक स्वराज्य, ग्रामवासियों को जंगलों के उपयोग करने की छूट, अनिवार्य शिक्षा, ग्राम-प्रजायत की स्थापना, नशा-निषेध सहयोग-समितियाँ, आयुर्वेद-प्रवृत्ति को

प्रोत्साहन, और औद्योगिक तथा इजीनियरी शिक्षा आदि विषयों का समावेश किया गया था।

अभी मुसलमानों का शिष्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुर्किस्तान के साथ संधि की प्रस्तावित शर्तें प्रकाशित हो गईं और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय का सवेना भी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे शर्तें समझाई गई थीं। सदेन में यह बात स्वीकार की गई थी कि संधि की शर्तों से भारत के मुसलमानों के दिलों को अवश्य ठेस पहुँची होगी, पर साथ ही उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्की सहवासियों के इस दुर्भाग्य को सन्तोष और धैर्य के साथ सहन करें। किन्तु इन शर्तों के प्रकाशन से मुसलमानों के क्रोध का ठिकाना न रहा। हष्टर-कमिटी की रिपोर्ट भी उसी समय प्रकाशित हुई थी। वस, सारे देश में आग लग गई। खिलाफत-कमिटी की बैठक बम्बई में हुई जिसमें गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १९२० की २८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र शास्त्र समझ कर अपना लिया गया। ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें हष्टर-कमिटी की रिपोर्ट और तुर्किस्तान के साथ सन्धि की शर्तों पर विचार किया गया। लम्बे-बीड़े बाद-विवाद के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया।

गांधीजी ने 'तिलक-सम्बन्धी स्मृतियाँ' नामक पुस्तक में बताया है कि असहयोग के प्रति लोकमान्य तिलक का क्या रुख था। "असहयोग के सम्बन्ध में उन्होंने मार्मिक ढंग से उसी बात को फिर दुहराया जिसे वह पहले भी मुझसे कह चुके थे, 'असहयोग का कार्यक्रम मुझे पसन्द है। पर इसने जिस आत्म-स्थाय की जरूरत है, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। मैं आपकी सफलता चाहता हूँ। यदि आप जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सकें तो मुझे आप अपना कट्टर समर्थक पायेंगे।"

गांधी जी द्वारा विभिन्न सत्याग्रह

उस समय गांधीजी चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे या करने की घमकी देकर देश को स्थायी लाभ पहुँचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने चम्पारन में सत्याग्रह किया। खेड़ा जिले में वर्षा अधिक होने के कारण फसल मारी गई थी। वहाँ गांधीजी ने लगान न देने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और जन्म में अहमदाबाद में मिल-हड़ताल का अन्त कराया। १९१८ में गांधीजी ने खेड़ा जिले के

किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभा ने शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुँचा। परन्तु उस ताल्लुके का कमिश्नर विगड़ गया और शिष्ट-मण्डल से बड़ी अग्रदत्ता के साथ पेश आया। इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनिवार्य हो गया। खेडा के मामले में भी मोहनलाल पण्ड्या पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये (शोक है कि १८ मई १९३५ को उनका देहान्त हो गया)। अन्त में खेडा के किसानों को आशिक छूट मिल गई। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-हड़ताल थी, जो १९१८ के मार्च में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता ठहराया गया, पर इसी बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्वलता और विह्वलता का परिचय दिया और मजदूरों का संगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर गांधीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने का गांधीजी का यह पहला अवसर था। पर इसके सिवा और कोई चारा न था। उन्होंने कहा—“आनेवाली पीढ़ी कहे कि दस हजार आदमियों ने उस प्रतिज्ञा को अमानक तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो यही अच्छा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से कठिनाई में डालनेवाला कहलाऊँ।” (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय के अन्त में दिये परिशिष्ट को देखिए)

कुली-प्रथा का अन्त

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १९२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १९२० की १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में धर्त-वन्दी कुली-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दी से जारी थी। जब भारत-सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुली-प्रथा का अन्त स्वतः ही हो गया, क्योंकि वहाँ मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथिवी के अन्य भागों के उपनिवेशों में धर्तवन्दी कुली-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १९१४-१५ में भारत-सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-ताछ की तो उसे पता चला कि गांव-वाले इस प्रथा के घोर विरोध हैं। १९१५ में दीनबन्धु एण्टरूज और मि० पियरसन पिजी

गये और वहा से बड़े ही बुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने वही कॉमिल मे कुली-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने उसे मजूर कर लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ समय लग ही जायगा। बाद को पता चला कि वह औपनिवेशिक विभाग से इस बात पर राजी हो गये हैं कि भारत में अभी पांच साल तक मर्ती होती रहे। एण्डरुज साहब ने भारत-सरकार को चुनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं ? और जब यह बात प्रकट की गई कि इस प्रकार के राजीनामे पर क्लाइव-हाल के दोनों-औपनिवेशिक और भारतीय-विभागों ने दस्तखत किये हैं तो सारे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। श्रीमती बेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया। १९१७ के मार्च-अप्रैल में आन्दोलन पूरे ओर पर था। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन कारणों से श्रीमती एनी बेसेण्ट को नजरबन्द किया उनमें से एक यह भी रहा होगा। लॉर्ड चेम्स-फोर्ड ने गांधीजी को बुलाया और तब उनकी समझ में स्थिति की गंभीरता आई। हरेक प्रान्त की भारतीय महिलाओं का एक शिष्ट-मण्डल लॉर्ड चेम्सफोर्ड से अपनी मजूर बहनों की ओर से मिला। गांधीजी ने ३१ मई १९१७ का दिन नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए, नहीं तो भर्ती रोकने के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १९१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की भर्ती बन्द की जाती है। पर यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठावेंगे जिनका उममे बहुत बड़ा आर्थिक-हित था। इसलिए एण्डरुज साहब गांधीजी को सलाह और श्री रवीद्रनाथ ठाकुर की हादिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाला इकट्ठा करने के लिए एकवार फिर फिजी गये, जिससे युद्ध के बाद प्रश्न उठने पर उसका उपयोग किया जा सके। वह कोई एक साल तक फिजी में रहे और पहली बार से भी अधिक भयंकर हकीकतें इकट्ठा कर लाये। उन्होंने इस प्रश्न के नैतिक पहलू पर आस्ट्रेलियन महिलाओं का ध्यान भी काफी आकर्षित कर लिया और उन्हें कुली-प्रथा को उठाने के पक्ष में प्रबल समर्थन प्राप्त हो गया। १९१८ के मार्च में उन्होंने मि० माण्डेगु से दिल्ली में भेंट की और उनके सामने सारा मामला पेश करके साबित कर दिया कि शर्तबन्दी कुली-प्रथा घोर अनैतिक है। १९१९ में सरकार ने यह घोषणा की कि अब गिरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी और जिन मजदूरों की पांच साल की मियाद

पूरी नहीं हुई है उन्हें बन्धन-मुक्त किया जायगा। फलतः पहली जनवरी १९२० को फिजी, ट्रिनिदाद-गोडना, ट्रिनिडाड, मुरीनाम और जमैका के प्रवासी भारतीयों में हर्ष का बारापार न रहा, क्योंकि वहाँ अभी तक यह प्रथा जारी थी। उन बन्धन-मुक्ति के दिन जो भारतीय गिरमिट के अनुसार यहाँ पहुँचे थे वे भी आजाद कर दिये गये। यह प्रथा १८३५ में आरम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेशों में श्रम की खेती के लिए मजदूर मिल सकें। इसके पहले अफ्रीका के ईसाई गुलाम काम करते थे, पर १८३३ में गुलामी का अन्त कर दिया गया था। इस प्रकार श्रम की खेती जारी रखने के लिए जो तरकीब सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार सर डब्ल्यू० विलसन हन्टर ने इस प्रथा को अर्द्ध-गुलामी मजदूरी कहा था, और यह वर्णन ठीक भी है।

हन्टर-रिपोर्ट

१९२० की २८ मई को हन्टर-रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा और क्षोभ की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट में सब सदस्य सहमत न थे। हिन्दुस्तानी सदस्यों का अग्रज सदस्यो से मतभेद था। मतभेद इस विषय पर था कि पंजाब का उपद्रव आकस्मिक था या पहले से निश्चित किया हुआ था? अग्रज सदस्यों की राय थी कि वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय इसके विपरीत थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फौजी-कानून की कोई आवश्यकता न थी तथा इस उपद्रव का दोष चन्दा इकट्ठा करने और रंगरूट भर्ती करने में पंजाब के गवर्नर ओडायर के जुल्म को दिया। उन्होंने सरकार को ऐसी खबरें डबाने का दोषी ठहराया, जिनसे भ्रान्त चारणा फैली। सरकार ने यह बात स्वीकार की कि "फौजी-कानून का शासन-शक्ति के दुर्नियोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्तदायित्व-हीन कार्यों के द्वारा दूषित कर दिया गया था। जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार आदमी ऐसा न करता। और उस स्थिति में जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए था, उसने उससे काम न लिया।" सम्राट की सरकार ने उन कई निर्दयतापूर्ण और अनुचित सजाओं को बिल्कुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को विचार-द्वारा तथा दूसरे उपायों से इस नापसन्दगी का खुले तौर से परिचय करा दिया जाय। परन्तु मि० माष्टेगु ने कहा कि 'जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेकनीयती के साथ काम किया, अवस्था उससे परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने में गलती

हो गई।" भारत को इस बात से कोई सान्त्वना न मिली कि मविष्य के लिए फौजी-कानून को नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गई है। न पंजाब या भारत को इस बात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी-कानून की कृतृतो के लिए जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में बड़े ध्यान के साथ जाच-पड़ताल की गई है, क्योंकि जिन अधिकारियों के आचरण को धिक्कारा गया था उनमें से बहुत से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड़ चुके थे।

हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया गया और मामले पर विचार करने के लिए विशेष कांग्रेस करने का निश्चय किया गया। लोकमान्य तिलक उस अवसर पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति में भाग न लिया क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न था। फिर भी उन्होंने देशभक्ति और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य कह दिया कि वह महासमिति के आदेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गांधीजी ने असहयोग-आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया। अवतक असहयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता था। सारे दलों के नेता २ जून १९२० को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूलों, कालेजों और अदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर १९१९ में दिल्ली में अ० मा० खिलाफत-परिपद् ने गांधीजी की सलाह के मुआफिक सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय की पुष्टि कलकत्ता और अन्य स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अप्रैल १९२० को मदरास की खिलाफत-परिपद् ने, कर दी थी। मदरास की खिलाफत-परिपद् ने असहयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, ऑनरेरी पदों और कौंसिलों की मेम्बरी तथा पुलिस और फौज की नौकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों और अपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने जलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण कर लिया। इस त्रिवारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रबल कर दिया। असहयोग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिलक तक ने महासमिति के निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधीरात को

वह परलोक सिधार गये और इस प्रकार गांधीजी एक महान् शक्ति की सहायता से वंचित रह गये।

इधर मुसलमानों ने अफ़ग़ानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, क्योंकि अब तुर्किस्तान के साथ ब्रिटेन की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आन्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमान्तप्रदेश में जा फैला। कचगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठभेड़ हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और अगस्त के भीतर-भीतर अनुमानत १८,००० आदमी अफ़ग़ानिस्तान के लिए चल पड़े। पर अफ़ग़ान-सरकार ने धीमे-धीमे इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक कष्ट झेलने और मरने-अपने के बाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन हुआ।

जब अगस्त में बड़ी कौंसिल की बैठक हुई तो असहयोग ज़रूरी था। कई सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाइसराय ने चोपणा की कि असहयोग की नीति से अव्यवस्था उत्पन्न होगी और पूछा कि क्या कोई इससे भी अधिक अविरोध-पूर्ण कार्य हो सकता है? उन्होंने आन्दोलन को "सारी मूर्खता-पूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक मूर्खता-पूर्ण योजना" बताया, परन्तु नई कौंसिल खोलने के लिए युवराज की भाव बुलाने का विचार, जिसका विरोध बम्बई लिबरल परिषद् में श्री धाल्सी तक ने किया था, अन्त में छोड़ दिया गया। अगस्त में ही डॉ० सन्नू को बाइसराय की कार्य-कारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया।

असहयोग का प्रस्ताव

असहयोग की योजना का वाक्यावदा आरम्भ १ अगस्त को हुआ। गांधीजी और अली-भाइयों ने देश का दौरा किया। गांधीजी ने जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसके उछलते हुए उत्साह को सयम में रक्ता। जैसा हमेशा से होता आया है, गांधीजी ने जब-जब अपने अनुयायियों को लताड़ बताई तो सरकार ने उसका उद्घरण भीड़ की निरकुशता मिट्ट करने में किया। कांग्रेस को अपने पुराने बैध रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। यह असाधारण बात थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधिवेशन का निश्चय मई में ही हो चुका था। यह १९२० के ४ से ६ सितम्बर तक सप्तदश में हुआ।

यह अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बंगाल गांधीजी ने पूरी तरह महसूस न

था और देशबन्धु दास तो गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकांश प्रतिनिधियों के हृदयों में कौंसिलो और अदालतों के वहिष्कार की योजना के प्रति विलकूल सहानुभूति न थी। पर तो भी ७ मत के सकीर्ण पर निश्चयात्मक बहुमत से कार्य-समिति ने गांधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने शनै शनै वहिष्कार करने की सलाह दी थी। उस समय वातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यम्भावी था। भारत-सरकार ने हष्टर-रिपोर्ट के बहुसंख्यक-पक्ष की बात ग्रहण कर ली थी और वह अधिकारियों की काली करतूतों पर अघकार का पर्दा डालना चाहती थी। बहुसंख्यक-पक्ष की राय में डायर का आचरण केवल "समझ की बड़ी भूल" था, "जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से बाहर चला गया।" उसकी राय में डायर ने जो किया वह कर्तव्य की नेकनीयती के साथ, पर गलत ढंग से अपना कर्तव्य समझने के कारण, किया। मि० माण्टेगु ने भी इन सिफारिशों को बिना भूतक किये स्वीकार कर लिया और पञ्जाब के अधिकारियों की करतूतों की ओर से एक प्रकार आखें बन्द कर ली। उन्होंने कहा कि "डायर ने कठोर कर्तव्य और नेकनीयती से काम लिया था।" कामन-सभा में डायर के प्रति किये गये अत्याचार और उसे दिये गये अन्यायपूर्ण दण्ड के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। लार्ड सभा में लार्ड फिलले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो गलत, एक पक्षीय, और शब्द तथा भाव दोनों प्रकार से झूठी बातों से भरा हुआ था। इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रता के साथ विश्वास-घात किया गया। इस वाद-विवाद और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को लेकर कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में बड़े प्रस्ताव पास किये गये।

कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बड़े जोशोशरोश के बीच हुआ। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समिति के प्रधान थे और लाला लाजपत राय, जो हाल ही अमरीका से लौटे थे, सभापति थे। पहले प्रस्ताव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कांग्रेस के गहरे दुःख को प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल एवं विशुद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका त्याग और सेवाएँ, जनता के हित के लिये उनकी तीव्र लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर सदा आदर-महित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को बल व स्फूर्ति प्रदान करती रहेगी। डॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु में देश को जो क्षति पहुँची थी, उसपर भी कांग्रेस ने अपने दुःख को प्रकट किया।

दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौधरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिग हुए ही थे, पेश किया। उसमें पंजाब-जाच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गये, हन्टर-कमिटी के बहुमत की पक्षपात तथा वर्ण-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्दा की गई, और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश-न्याय की निष्पक्षता से लोगों का विद्वान् उठ गया है।

तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के बारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश-सरकार-द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशों को ज्यों-का-त्यों मान लिये जाने पर, और उसके द्वारा पंजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को असलियत में ढर-भुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई।

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिने गांधीजी ने पेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था :—

“चूँकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश-प्रधान-मंत्री ने जान-बूझ कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा है और चूँकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई धार्मिक विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे;

“और चूँकि अप्रैल १९१९ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की बेकनूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को मजा देने में जो पंजाब की जनता के प्रति असभ्य व नैतिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है और चूँकि उक्त दोनों सरकारों में सर माइकेल ओडायर को जो अफसरों द्वारा किये गये बहुत-से अपराधों के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दुःखों व कष्टों की मरामत अबहेलना की, बरी कर दिया, और चूँकि इंग्लैण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का दुःसंपूर्ण अभाव स्पष्टतः प्रकट हो गया है और पंजाब में मुमयस्त्रि-रूप से ज़ान्ज और शम फैलाया गया है; और चूँकि बाइबल का मकने ताजी घोषणा इन बातों का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाब के मामलों पर तनिक् भी पछाने का भाव नहीं है, अतः इस कांग्रेस की ग्य है कि भारत में तबतक शान्ति नहीं हो सकती जबतक कि उक्त दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाना। राष्ट्रीय सम्मान की भर्थात जो तबतक

रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त मार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय है कि जबतक उक्त भूलों का सुधार न हो जाय और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है कि वे गांधीजी-द्वारा संचालित क्रमिक अहिंसात्मक असहयोग नीति को स्वीकार करे और अपनावें।

“और चूँकि इसकी शुरुआत उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अब तक लोकमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूँकि सरकार अपनी शक्ति का संगठन लोगों को दी गई उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित स्कूलों से, व अपनी अदालतों व कौंसिलों से ही करती है, और चूँकि आन्दोलन को चलाने में यह वाञ्छनीय है कि कम-से-कम सतरा रहे और वाञ्छित उद्देश की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह कांग्रेस सरगर्मी के साथ सलाह देती है कि—

(अ) सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और जिला और म्युनिसिपल बोर्ड व अन्य सस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हो वे इस्तीफा दे दें,

(ब) सरकारी दरबारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी अफसरों-द्वारा किये गये या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय,

(स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकार-द्वारा नियन्त्रित स्कूल व कालेजों से छात्रों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय, उनके स्थान में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना की जाय,

(द) वकीलों व मुदयिकलों-द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे वहिष्कार हो और उनकी मदद से खानगी झगड़ों को तय करने के लिए पचायती अदालतों की स्थापना हो,

(य) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करनेवाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भर्ती होने से इनकार करे,

(फ) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें और यदि कांग्रेस की सलाह के बावजूद कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट देने से इनकार करे,

(ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जाय।

“और चूकि असहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया गया है जिसके बिना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता और चूकि असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री-मुख्य व बालक को इस प्रकार के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह कांग्रेस सलाह देती है कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय; और चूकि भारतीय श्रम व प्रवच से चलनेवाली भारत की वर्तमान मिलें देश की जरूरियात के लिए पर्याप्त सूत व कपड़ा तैयार नहीं कर सकती और न ही इस बात की कोई सम्भावना है कि एक लम्बे असें तक वे ऐसा करने में समर्थ हो सकें, यह कांग्रेस सलाह देती है कि हरेक घर में हथ की कताई को फिर से और देश के इन असह्य जुलाहों द्वारा, जिन्होंने अपने पुराने व सम्मानित पेशे को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हथ की बुनाई को पुनर्जीवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति तुरन्त ही बढ़ाई जाय।”

इस प्रस्ताव पर गरमागरम बहस हुई। बाबू विपिनचन्द्र पाल ने एक संबोधन पेश किया, जिसका देशबन्धु चित्तरजनदास ने समर्थन किया। इस संबोधन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री को भारत के एक शिष्ट-मण्डल से मिलने के लिए कहा गया।

बहुत देर के विवाद के बाद, अन्त में गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया।

यहां प्रसंगवश यह भी कह दिया जाय कि गांधीजी ने पहले जिला व म्यू-निसिपल बोर्ड आदि स्थानिक सस्थाओं के बहिष्कार को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर मित्रों की मर्जी के खातिर उसे निकाल दिया। राष्ट्रीय वल भी कार्यक्रम से कुछ मतभेद रखता था, लेकिन तिसपर भी वह कांग्रेस के प्रति बफादार रहा। अमृतसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के उम्मीदवार नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव-आन्दोलन में काफी समय, परिश्रम व धन व्यय किया था, वे लगभग सब एकदम चुनाव से हट गये। मत-दाताओं तक ने, लगभग ८० प्रतिशत ने, कांग्रेस के निर्णय को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहों से तो वोट की पंचिया टांगने के बक्स रीति-के-रीति लौट गये। म्बय सरकार ने इस दात को स्वीकार किया कि “गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन में नई कौंसिलों का बहिष्कार अवश्य ही अगनें कुछ बर्षों के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस बहिष्कार के

कारण नई कांसिलो में कई लोक-प्रतिष्ठित व उग्र-विचारवादी न आ सके और नरम-दिलियो का रास्ता साफ हो गया।”

नवम्बर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा। सरकार ने कहा, “उसने प्रान्तीय सरकारो को आदेश किया है कि वह केवल उन्हीं लोगो के विरुद्ध कार्रवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलाते उस हद से भी बाहर निकल जाय जो उसके संचालको ने नियत कर रखी है और जिन्होंने लेखो व भाषणो से जनता को खुले-आम हिंसा के लिए भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की बफादारी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया है।” सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उन्ज-बर्ग के व्यक्ति व सर्व-साधारण दोनों ही असहयोग-आन्दोलन को एक श्रेष्ठ-चिन्ती की योजना समझकर रद कर देंगे। क्योंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारो ओर अशान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले बिना नहीं रह सकता और जिन लोगो के देश में कुछ भी स्वार्थ-संबन्ध हैं उनका सर्वनाश हुए बिना नहीं रह सकता। असहयोग-आन्दोलन अज्ञान और पूर्व-विश्वासो के सहारे ही टिक सकता है, और उसके उद्देश में रचनात्मक तत्वो के तो कीटाणु भी नहीं है।”

२ अक्तूबर १९२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल-भारत तिलक-स्मारक-कोप व स्वराज्य-कोप नाम के दो कोप इकट्ठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १९२० तक रद्दी की टोकरी में ही पड़ा रहा। असहयोग-आन्दोलन सम्बन्धी नये प्रस्तावो का भी बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ अच्छा स्वागत न हुआ। लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे ने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक-रूप से बताया कि किस प्रकार कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव कांग्रेस की शक्तियो को आत्मबल व नैतिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैं, लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहलू को बिलकुल भुला देते हैं। “देश की वास्तविक सरकार से हमारा सब सम्पर्क हटाकर यह आन्दोलन हमें राजनैतिक रंग में रंगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनैतिक स्वभाव बनाने से रोकता है जो एक करारी लड़ाई को शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित-रूप से और जम कर चलाने के लिए आवश्यक है। असहयोग का आन्दोलन सहनशक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सके, यह सम्भव है, लेकिन वह हमारे अन्दर वह कार्य-शक्ति, साधनशीलता व व्यावहारिक चातुर्य पैदा करने में असमर्थ है जो एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक है। कांग्रेस ने जिन तीन-बहिष्कारो

की सिफारिश की है वे बेकार है और उनमें सुदूर राजनैतिक दृष्टि का विलकुल अभाव है। आल-इण्डिया-होमरूल-लीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी जाती है) के ध्येय को बदलते समय जो विवाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा झुकाव फिर एकतन्त्र व व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बड़े-बड़े व नीतिवान् व्यक्ति को क्यों न दी जाय, है आपत्तिजनक और समय की स्प्रिट के विरुद्ध।”

इसमें होमरूल-लीग के ध्येय-परिवर्तन और गांधीजी द्वारा स्वराज-सभा बनाने की ओर ध्यान दिलाया गया। कलकत्ते में अब असहयोग का भाग्य तराजू के पलड़े पर लटका हुआ था, गांधीजी ने पुराने होमरूल-वादियों को, जिनसे श्रीमती बेसेण्ट अलग-सी हो गई थी, एक झण्डे के नीचे इकट्ठा किया और लीग का ध्येय बदल डाला। इस ध्येय को नागपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना लिया। गांधीजी ने लीग का नाम भी बदल कर स्वराज-सभा रक्खा। लेकिन इस सभा को चलने का भौका नहीं मिला, क्योंकि कलकत्ता में तो कांग्रेस ने असहयोग के मार्ग को ग्रहण कर लिया था और नागपुर में उसपर फिर दोहरी छाप लगा दी। यह बिधि के विधान में और राजनीति में कौसी घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दो बार ऐसे प्रान्तों की राजधानियों में पास हुए जहाँ कि असहयोग-आन्दोलन का प्रबल-से-प्रबल विरोध किया गया था।

नागपुर-कांग्रेस

नागपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर अन्तिम-रूप से विचार होकर निश्चय होना था। कांग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की सख्या बहुत अधिक थी। नाग-पुर के पहले या बाद की कोई भी कांग्रेस इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की सख्या नागपुर के बराबर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों की सख्या १४,५८२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे और १६६ स्त्रियां। कांग्रेस के समापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य थे। कर्नल वेजबुड, मि० हालफोर्ड नाइट व मि० वेन स्पूर ने कांग्रेस में इंग्लैण्ड के मजदूर-दल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया और मजदूर-दल की सहानुभूति को प्रदर्शित किया।

श्री चित्तरजनदास पूर्वी बंगाल व आन्ध्र से लगभग २५० प्रतिनिधियों का एक दल लाये थे, उनका दोनों ओर का सर्वा भरा और अपनी जेब से लगभग

३६,०००) इसलिए खर्च किया कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके। श्री दास के आदमियों में और उनके विरोधी श्री जितेन्द्रलाल बनर्जी के आदमियों में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम सगढ़ा या कुछ कम संगठित न था। कर्नल वेजवुड ने और मि० बेन स्पूर व मि० हालफोर्ड नाइट ने विषय-समिति की बैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेजवुड ने असहयोग के विरोध में दलीलें पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी परन्तु नतीजा कुछ भी न हुआ। छादी-सम्बन्धी धारा और भी कड़ी कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया और कांग्रेस का ध्येय "इस तर्ज से बदल डाला गया कि उसमें ब्रिटिश-सम्बन्ध व वैध-आन्दोलन का जिनमें कांग्रेस अभी तक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा।" ये सरकार के शब्द हैं। अधिवेशन में गांधीजी के व्यक्तिगत की विषय हुई।

अब हम नागपुर-कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं पर और उसने कांग्रेस के ध्येय व विधान तथा आदर्शों व दृष्टिकोण में क्या-क्या आमूल परिवर्तन किये, इसपर भी दृष्टिपात करें। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वीकार हो जाना स्वयं एक बड़ी भारी बात थी, लेकिन उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे श्री बिस्मिल्लनवास ने पेश किया और उसका छाला लाजपतराय ने समर्थन किया। नागपुर में गांधीजी को निस्सन्देह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते में केवल एक ही परले सिरे के राजनीतिक प० मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया था, और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीब जबकि गांधीजी ने नेहरूजी का यह सक्षोभन स्वीकार कर लिया कि अदालतों व कालेजों का बहिष्कार धीरे-धीरे हो।

नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीब-करीब कलकत्तावाले प्रस्ताव को ही दोहराया। एक ओर पदविया छोड़ देने की बात तो दूसरी ओर करो के न देने तक की बात उसमें शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक-सम्बन्धों को छोड़ें और हाथ की कटार्ड-बुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय सेवक-दल (इण्डियन नेशनल सर्विस) को संगठित करने और अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोष* को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर

*कोष एकत्र करने का निश्चय तो अक्तुबर में ही हो गया था, लेकिन बाद में अखिल-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिलाकर एक कर दिया गया।

जोर दिया गया। कौंसिलो के लिए चुने गये सदस्यों ने इस्तीफा देने की और मत-दाताओं से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई। पुलिस व पलटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ रहे थे उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से बर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करे और सब सार्वजनिक सभाओं में बिना डर के खुले तौर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग है। वचन और कर्म दोनों में अहिंसा का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव लोकशासन की स्पिरिट के विरुद्ध ही नहीं बल्कि असहयोग की आगे की पीढ़ियों तक पहुँचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रस्ताव के अन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक सस्थायें सरकार से अहिंसात्मक अगहयोग करने में अपना सारा ध्यान लगा दे और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लैण्ड के साप्ताहिक 'इण्डिया' पत्र बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस बात को महसूस किया गया कि भारत और विदेशियों में भारत के बारे में सच्ची बातों के फैलाने की आवश्यकता है। आयर्लैण्ड के वीर योद्धा स्वर्गीय मैकस्विनी ने जो आयर्लैण्ड के उत्थान के लिए लड़ने-मरने ६५ दिन की भूख-हड़ताल के पश्चात् अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था इसी लिए उन्हें श्रद्धाञ्जलि दी गई।

बिनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिज़र्व योनिंगे" द्वारा स्वर्ण-बिनिमय-मान-कोष (Gold Exchange Standard Reserve) कागजी-मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve) में "टूट" भगने के कारण नागपुर में जोरों से इस बात की माग पैदा हो गई कि ब्रिटिश-सरकार उन पाठे को पूरा करे। पात्रवे प्रस्ताव में तो यह भी रत्ना गया कि "ब्रिटिश मान की रिज़र्व करनेवाले व्यापारी बिनिमय की वर्तमान दरों पर अपना वादा पूरा करने में इत्कार करने के हादार हैं।" उधर आफ बनाव ने सम्मान में बिनी ग्लव न समानोद में भाग न लेने के लिए देश में जनरोज किया गया। भजपुरी को प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जगिये जगी रिने गये उनसे मुद्रा के प्रति सजानुभूति प्रदर्शित की गई। गान्धीजी ने नियान की नीती की निगम की गई। मुद्रमा बन्दाग या रिना मुद्रमा चामे रिन गजनेरि बार्दपनो में ११ निगमान गये मज दी गई उनो प्रति भी गान्धीजी निगद गई। १९३३,

दिल्ली व अन्य स्थानों में पुन प्रारम्भ हुए दमन को ध्यान में रखा गया और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धैर्य से सहें। कांग्रेस ने सब देशी-नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शीघ्र-से-शीघ्र प्रयत्न करें। हार्निमैन साहब को भारतीयों से अलग रखने की सरकारी नीति की निन्दा की गई और मि० हार्निमैन के प्रति भारत की कृतज्ञता प्रकाशित की गई। ईशर-कमिटी व उसकी सिफारिशों को भारत की पराधीनता व असहायता को बढ़ाने में सहायक मान कर उनकी निन्दा की गई और उन सिफारिशों को भी असहयोग-आन्दोलन का एक और कारण माना गया। मुसलमानों को गो-वध के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े की निर्यात को निरुत्साहित करे। निःशुल्क शिक्षा व देशी-विक्रिस्ता-मदति के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए।

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं। कांग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। कांग्रेस का ध्येय "शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना" घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रान्तीय संगठन प्रान्तों की मापा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यों तक सीमित रखना—ये मार्कों के परिवर्तन थे, लेकिन विषय-समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर दी गई। समापति, सभी व कोषाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विधान का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्रान्ति ही कर दी है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दे कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध उच्चता और बीरतापूर्ण संग्राम छेड़ने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों-द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने के लिए बाधित किया गया था, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया। सबसे अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनबन्धु एण्डरूज को धन्यवाद दिया।

अध्याय १ का परिशिष्ट

१—चम्पारन-उत्थापन

बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उसीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोरों खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। आगे चलकर इन लोगों ने वहाँ के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने हाथ कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ था। इन गोरों खेतिहरों ने अपने प्रभाव और शक्त से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त करके यहाँ पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जो कि उन्हें हुकूमत करनेवाली जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहाँ के गावों के किसानों से अपने लिए नील की खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी $\frac{1}{3}$ या $\frac{1}{2}$ भूमि पर नील अवश्य दायें। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल-टेनेन्सी एक्ट में इस बात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने की यह प्रथा आगे चलकर तीलकठिया के नाम से मशहूर हुई, जिसके मापी से एक बीघे का $\frac{1}{2}$ भाग। किसानों की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह नाममात्र की थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों के मेल से रंग तैयार होने लगे। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोक्त अवस्था में नील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय लाभ-प्रद नहीं रहा। फलतः उनके नील के कारखाने बन्द होने लगे। लेकिन इस नुकसान को अपने कंधे पर लेने के बजाय उन्होंने उसे गरीब किसानों के सिर मढ़ देने के उपाय सोचे। इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम किया। उन गावों में, जिनकी जमीन के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था; उन्होंने किसानों से लगान में बढोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के बन्धन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार के हजारों ही शर्तनामे लिखाये गये। इन शर्तनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहाँ उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहाँ किसानों से उन्होंने जैसा कि किसानों का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज ले

ली। गरीब किसानों से कोई १२ लाख रुपया वसूल किया। क्योंकि सारा चम्पारन जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुस्तलिफ टुकड़े कर लिये थे। गोरों के प्रत्येक सघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी हलकों में इतना था कि वेचारे गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मामला चलावें या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, काजीहाउसों में उन्हें बन्द करा देना तथा हजार बग से उन्हें तग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें मकानों की लूट, नाई, बोवी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उन्हींके मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछूतों को उनके घरबाजों पर बिठा देना आदि बातें भी शामिल थी, जो आये दिन बराबर उनपर बीतती रहती थी। ये लोग किसानों से अबरदस्ती अनुचित-रूप से भाति-भाति के नजराने भी लिया करते थे। जाच करने पर यह ज्ञात हुआ था कि ५० प्रकार के नजराने वसूल किये जाते थे। उनमें से कुछ के नाम यहाँ देना अनुचित न होगा। विवाह पर, चूल्हे पर, कोल्हू पर लाग लगी हुई थी। यदि साहब बीमार हूँ और पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है, तो वहाँ के किसानों को इसके लिए "पहाड़ही" नामक लाग देनी पड़ती थी। यदि साहब को सवारी के लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए "घोड़ाही", "हाथियाही" या "हवाई" नामक विशेष लाग देनी पड़ती थी। इन लागों के अतिरिक्त किसानों से भारी-भारी जुर्माने भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा जिससे साहब को या किसी दूसरे को बुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था। इस प्रकार से यह लोग एक तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम ही बन बैठे थे।

यह अवस्था थी जबकि कुछ इन किसानों के और कुछ बिहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें चम्पारन आकर स्थिति का अध्ययन करने का वचन दे दिया।

१९१७ में गांधीजी मोतीहारी पहुँचे। यह जिले का मुख्य स्थान था। गांवों को देखने के लिए वह रवाना होने ही वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुक्म को कब माननेवाले

थे। उन्होंने अपना 'कैसेरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में उनपर दफा १४४ मग करने का मुकदमा चला। उन्होंने अपनेको अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण वयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एक अपरिचित और नई स्फुरण को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे मली-भाति परिचित हो चुके हैं। सरकार ने अन्त में मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाच करने दी। इस जाच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई २० हजार किसानों के वयान कलमबन्द किये। इन्हीं वयानों के आधार पर गांधीजी ने किसानों की मांगें पेश की। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और मिलहू गोरो के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीशन ने जाच के बाद एक मत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता भी लिखा गया था जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लयान को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरो ने नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी सिफारिश को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या 'तीनकठिया' लेना मना कर दिया गया। इसके कुछ वर्ष बाद ही अधिकांश मिलहू गोरो ने अपने कारखाने बंद दिये, जमीन बेच दी और जिला छोड़कर चले गये। आज उन स्थानों के, जो कभी मिलहू गोरो के महल थे, सण्डहर ही शेष हैं। वे लोग, जो अभीतक वहाँ भीजूद हैं, नील का काम कटाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों की तरह खेती-बाड़ी करके बसर करते हैं। अब न तो उनकी वह गैर-कानूनी आमदनी ही रह गई है और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी का एक कारण थी। जिन अत्याचारों और भुसीवतों को देश के अनेक नेता और सरकार दोनों पिछले सौ वर्षों से दूर न कर सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों में मिट गये।

२—खेडा-सत्याग्रह

सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहातक प्रश्न है, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्वपूर्ण खेडा का (१९१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि धीरे-से-धीरे अकाल के दिनों में भी वे सरकार के

- लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ ऐतराज कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्थानीय कौंसिलों में प्रस्ताव करते थे। बम यहापर उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १९१८ में गांधीजी ने एक नये युग का श्रीगणेश किया। गुजरात के खेडा जिले में इस वर्ष ऐमा बुरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल धराब हो गई। अवस्था अकाल के समान हो गई थी। किसान लोग यह महसूस करने लगे थे कि अवस्था को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। अतः गांधीजी के पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने लोगों में स्वयं-सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावें। गांधीजी की अपील का अमर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वयं-सेवक बनने की आगे बढ़नेवाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आपने अपनी सासी और बहती हुई बकालत पर लात मार दी, और सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले ली। खेडा का सत्याग्रह ही इन दो महान् पुरुषों को मिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के मार्वाजनीक जीवन में प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होंने अन्तिम मिश्रण करके अपने-आपको गांधीजी के अर्पण कर दिया। किसानों ने एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को झूठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को नष्ट करके अवरोध बढाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनों को जब्त कराने के लिए तैयार हैं।

अब किसानों को एक नये ढंग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों की शिक्षा उन्हें दी गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता है कि आपका यह हक है कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतराज करें। यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नहीं, नौकर हैं, इसलिए आपको अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर डराये-धमकाये जाने की, दमन और दबाव की और उससे भी बदतर जो आ पड़े उन सबकी परवा न करते हुए अपने हकों पर ठटे रहना चाहिए, उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखना था, जिनके जाने बिना बड़े-से-बड़ा साहस-कार्य भी आगे चलकर दूषित और भ्रष्ट हो सकता है। गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और वहाँ से तीसरे में जाकर

किसानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मवेशियों तथा अन्य वस्तुओं के कुर्क किये जाने, ज़र्याना और जमीन जब्त होने की घमकी के मुकाबले में भी दृढ़तापूर्वक बटे रहो। इस युद्ध के लिए धन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक धन भेज दिया। इस सत्याग्रह से गुजरात को सविनय-भंग का पहला सबक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के खयाल से गांधीजी ने लोगों को सलाह दी कि जो खेत बेजा कुर्क कर लिया गया है उसकी फसल काटकर ले आवें और (स्वर्वाय) श्री मोहनलाल पण्ड्या इस कार्य में किसानों के अगुआ बनें। लोगों को अपने ऊपर ज़र्याने कराने और जेल की सजा को आमंत्रित करने की शिक्षा ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता है। मोहनलाल पण्ड्या एक खेत की प्याज की फसल काटकर ले आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों ने भी मदद दी। उन सब लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और थोड़े-थोड़े दिन की सजाएँ हुईं। लोगों के लिए यह एक अद्भुत प्रयोग था। इन सब बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटने पर उनके जुलूम निकालते थे।

इस झगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों के लगान को मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रचार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह ग़मामन एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि पट्टे लोगों के आन्दोलन के फलस्वरूप है, तीसरे भी बिना मन के, इसलिए इसने बहुत कम किसानों को लाभ पहुँचा। यद्यपि मिथानाथ सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले। उस लड़ाई ने गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का भूतपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा' में लिखते हैं—

“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज़ आया, नया उन्नात” भग गया। मजने भमसा कि प्रजा की सुक्ति या आधार गूढ़ अपने ही ऊपर है, त्याग-जगिन पर है। सत्याग्रह ने देश के द्वारा गुजरात में उज जमाई।”

३—अहमदाबाद-सत्याग्रह

गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की घोषा बढ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। उसके ऐसे मजदूर और दूरगामी परिणाम निकले हैं, जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर-समूह कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर पश्चिमी यात्री दंग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि संक्षिप्त वर्णन भी इस इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रने जा सकते हैं—परन्तु मैं यहाँ केवल इतनी ही बात लिखकर सतोष कल्ला कि गांधीजी ने इसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूप-रेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और ससार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में कितना अन्तर है।

१९१६ से श्रीमती अनुसूया बेन सारामाई मजदूरों में शिक्षा-सवन्धी कार्य कर रही थी। १९१८ में बुनकरों और मिल-मालिकों में जो झगडा उठ खडा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पडा। उन्होंने ने मिल-मालिकों को जबरबस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा उनसे पचायत के सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलन के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात थी। गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पच-फैसले की बात बीच में ही टूट गई, क्योंकि थोड़ी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हड़ताल कर दी। गांधीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज दिया। यद्यपि समझौता-भंग दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल-मालिक कुछ सुनते ही न थे। गांधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होनेवाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई और दूसरी ओर मिलों में उत्पत्ति-स्वर्च की वृद्धि—ये उनकी जाच के मुख्य विषय थे। इस जाच के पश्चात् जिस परिणाम पर गांधीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरों की मजदूरी में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। मजदूरों की माग यद्यपि इससे बहुत अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिये गये।

मिल-मालिकों ने २० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी १९१८ से मिलों में ताले डाल दिये जायेंगे। इसपर गांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा बुलाई और एक पेड़ के नीचे, जो अभी तक पवित्र समझा जाता है, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती। प्रतिज्ञा में यह बात भी थी कि वे लोग जब तक मिलों में ताले पड़े रहेंगे तब तक किसी हालत में शान्ति-भंग न करेंगे। यह प्रतिज्ञा कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्भ किया गया। श्रीमती अनसूया बेन दरवाजे-दरवाजे जाती थी। श्री शंकरलाल बैकर तथा छगनलाल गांधी भी इसी कार्य में जुट पड़े थे। नोटिस बाटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विवाद सार्वजनिक सभायें की जाती थी। इन नोटिसों को गांधीजी स्वयं लिखते थे। उनमें वह मजदूरों को बड़ी आसान भाषा में यह समझाते थे कि जिस सघर्ष में वे लोग जुटे हुए हैं वह केवल औद्योगिक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक सघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्थान होगा और साथ-ही-साथ मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी। यह सघर्ष एक पखवाड़े तक बराबर चलता रहा। लेकिन मजदूर लोग इस बात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का घाटा सह सकें, इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। उन लोगों में जो नासमझ थे वे तो यहां तक बड़बड़ाने लगे कि गांधीजी के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस बात का उपदेश दें कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, लेकिन हम लोगों के लिए, जिनके बाल-बच्चों के भूखो मरने की नीवत आ गई है, यह इतना आसान नहीं है। यह गांधीजी के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जब तक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं पा जाते तब तक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे और न भोजन ही करेंगे। यह समाचार बिद्युत् गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह आश्चर्यजनक था। मजदूरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटल था। इसपर गांधीजी ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उसपर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। गांधीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वह इन मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए धन की अपील करते, जिससे काफी धन अवश्य आ जाता, लेकिन इस तरह भिक्षा देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि मजदूरों की सारी तपस्या निष्फल हो जायगी और उसका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिक्षा-द्वारा सहायता दी जाय। सत्याग्रह-

। श्रम सावरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरों को काम मिल गयी, जहाँ कि इमारतें बन रही थी। वे आश्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से काम करने लगे। इनमें सबसे आगे श्रीमती अनसूया बेन थी, जो मिट्टी, ईंट और चूना ढो रही थी। इसका बड़ा ही नैतिक प्रभाव पड़ा। इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गये, और मिल-मालिकों के भी दिल दहल गये। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपीलें कीं। अपील करनेवाले नेताओं में डॉ० बेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों को यह तार भेजा था—“भारत के नाम पर मान जाओ और गांधीजी के प्राण बचाओ।” उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती थी और इधर मिल-मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनों ने पच-फैसला मानना स्वीकार कर लिया। पक्षों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का निर्णय किया।

मजदूरों की समस्या के शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझ जाने के कारण कांग्रेसी नेताओं और मजदूरों में एक सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसीके फलस्वरूप मजदूरों का ‘मजूर-महाजन’ नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १५ वर्षों से श्रीमती अनसूया बेन और श्री शंकरलाल बैकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस सत्त्वा की बदौलत मजदूर अवतक कितने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं और अहमदाबाद नगर को बड़े-बड़े औद्योगिक संकटों से बचाया है।

असहयोग पूरे जोर में-१९२१

पंजाब-काण्ड पर सरकार का दुस्-प्रकाश

नागपुर-कांग्रेस के प्रस्ताव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है। निर्बल क्रोध और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाव और स्वावलम्बन की स्फिरिट ले रहे थे। अब १९२० के आज़ीर और १९२१ की शुरुआत में भारत में जो कुछ घटनाएँ हुईं उनपर हम जरा धेर के लिए गौर करें। १९२० के अन्त तक नरम-दलबालो ने सदा के लिए कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। लिबरल-फेडरेशन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में श्री सी० बाई० चिन्तामणि ने उत्तम भाषण दिया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 'सर' हो गये थे। लॉर्ड सिद्ध विहार और डहीमा के पहले गवर्नर बन चुके थे। १९२१ के आरम्भ में ही नये मंत्रियों में लाला हरकिशन-लाल (पंजाब) जैसो का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले दूरे बताने जाते थे, जिन्हें बाजन्म देश-निकासे की सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट, सम्राट् पद्म बाँके के चाचा, भारतवासियों के मनो-भावों को शान्त करने और भारत में नया युग जारी करने के लिए यहा नये गये। उन्होंने एक बठिया बक्तुसा भी —

"मे अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ जबकि मेरी यही इच्छा हो सकती है कि पुराने ज़रमों को भुँकें और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिला लें। मैं भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत भूल-काल के साथ पिछली गलतियों को भी क़त्त में गाढ़ दीजिए, जहाँ माफ़ ही करना है माफ़ कर दीजिए और कच्चे-मे-कच्चा मिठाकर एकनाथ काम कीजिए, जिनसे उन सब आशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं।"

इसके बाद, जब बड़ी कौंसिल में पंजाब-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गया उस समय सरकार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विमेट्ट कर रहे थे। "उन्होंने उन अनुचित कार्यों के किये जाने पर आमकों की ओर से दिन्नी अफ़सोस जाहिर करते हुए अपना यह दृढ़ निश्चय प्रकट किया था कि जहातक मनुष्य की दृष्टि जानी

हैं अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव हो जायगा।" इतना कह चुकने के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकड़ा, जिसमें कि "सबक देने लायक सजा देने" की तलबीज थी, प्रस्तावक से वापस करा लिया। परन्तु बात दर-असल यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसलिए जो सम्भवतः पेंशन के हक से भी हाथ धो बैठा था, उसे अर्पण करने के लिए अग्रेज महिलाओं ने भारत में २०,००० पाँड एकत्र किये, क्योंकि वे उसे "अपना आता" समझती थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसे एक तलवार भेंट करके इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में उसका खुले-आम वडा आदर किया गया। उसे जो कुछ हाणि उठानी पड़ी हो उसकी जरूरत से ज्यादा पूर्ति इस तरह हो गई थी। कर्नल जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराधी था, उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने 'नुकसान' का कसकर बदला मिल गया। न तो बपूक साहब की अपील से और न होमसेम्बर सर विलियम बिसेप्ट के 'शासको की तरफ से खेद-प्रकाशन' से भारतवासियों के मनोभावों को क्षान्ति मिली। असहयोग की जड़ जम चुकी थी। परन्तु एक बात ठीक हो रही थी और वह यह कि बड़ी कौंसिल ने १९२१ की शुरुआत में एक कमिटी बैठाई थी कि वह दमनकारी कानूनों की जांच करे। और जन्त को वे सब कानून, किमिनल-लॉ-अपेण्डमेण्ट-एक्ट को छोड़ कर, १९२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम-पट्टी के होते हुए भी भारत का जन्म तो ताजा ही बना रहा, उसमें से बराबर मवाद बहता रहा और कांग्रेस को 'शाही-बोपणा-पत्रों' और 'कौंसिलों-द्वारा कानूनों को रद कराने' की पुरानी दवाओं का अवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में लेना पड़ा।

असहयोग प्रारंभ

नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगो ने काफी दिया। कौंसिलो के बहिष्कार में सराहनीय सफलता मिली। हा, अदालतों और कौलेजो के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रौज को तो गहरा धक्का पहुँचा। देशभर में कितने ही वकीलो ने वकालत छोड़ दी और दिलो-जान से अपनेको आन्दोलन में शोक दिया। हा, राष्ट्रीय-शिक्षा के क्षेत्र में अलबत्ता आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका जवाब उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ मिला। यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह खोले गये। युक्त-प्रान्त,

पंजाब और बम्बई-अहाते में यह युवक-आन्दोलन जोरो से चला। बंगाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जनवरी के मध्य में देशबन्धु दास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को छोड़कर मार दी। भाषीजी कलकत्ता गये और उन्होंने ४ फरवरी को वहाँ एक राष्ट्रीय कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह पटना भी (दोबारा) गये और वहाँ राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ का मुहूर्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ, अलीगढ़, गुजरात-विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चारों ओर खुल गये। हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय शिक्षा को देश में जो प्रोत्साहन मिला रहा था उसका यह फल था। आन्ध्र-देश में १९०७ में राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह अब फिर से तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेगुलेशन-मस्थानों से असहयोग करनेवालों की सख्या बहुत थी और आज के बहुतेरे प्रांतीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में वकालत और विद्यालय छोड़े थे।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२१ में अक्टूबर हर महीने मुस्तलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रांतों में महासमिति के सदस्यों की सख्या का बटवारा किया। जनवरी १९२१ में नागपुर-कांग्रेस के स्वागतार्थ्यक सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी रायबहादुरी की पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक-स्वराज्य-कोष में एक लाख खर्चा दिया। ३१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्य-समिति ने तिलक-स्वराज्य-कोष के उपयोग के नियम बनाये। इस कोष का २५ फी सदी भिन्न भिन्न प्रांतों की रकम से कार्य-समिति को देना तय हुआ था। किसी वकील को (१००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी और किसी राष्ट्र-सेवक को (५०) मासिक से अधिक नहीं। कर्ज का होना इन सेवा के लिए एक अप्राप्तता मानी गई। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अविस्तर पाठ्यक्रम अभी नहीं बन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भाषा और चर्चा कानना सिलाना तय हुआ और ग्राम-कार्यकर्ता के लिए एक तालीम का क्रम निश्चित हुआ। देशबन्धु दास के जिम्मे हुआ मजदूर-मगठन पर देख-रेख और श्री तेरनी आर्थिक बहिष्कार कमिटी के संयोजक बनाये गये। बेलवाडा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति को भी बैठक हुई। कार्य-समिति में सबका यही मत था कि लगानबन्दी का समय अभी नहीं

आया है। वेजवाडा में ही महासमिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोष के लिए एक करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बर बनाये जायें और बीस लाख खर्च खलवाये जायें। प्रान्त की आबादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी। पचायत का सगठन और गराव छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। हालांकि लोग ऐसे सुधार और सगठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से दफा १४४ और १०८ का दौरा शुरू कर दिया था। उस समय महासमिति ने यह ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-याचन का गुण और सगठन-बल नहीं आ गया है कि जिससे तुरन्त ही सविनय भंग जारी किया जा सके और जिन-जिनके नाम पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार आज्ञायें जारी हुई थी उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया। सच तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताह से ही जोग उमड़ रहा था। देशव्याप्त दास मैमनसिंह जाने से रोक दिये गये। बाबू राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहबुल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकूब हुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपत राय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ और लोगों के नाम भी हुक्म निकले थे। लाहौर में सभावादी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले हफ्ते में गुच्छारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए। वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलिया चलाई गईं, जिसमें लोगों के कथनानुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मौतें हुई थी। वहा के महन्त ने, जोकि राजमन्त था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तौल जमा कर रक्खे थे। एक गड्ढा खोद कर रक्खा गया था और बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी। ५ मार्च को किसी सार्वजनिक विषय पर परामर्श करने के लिए लोग इकट्ठे होतेवाले थे। कई ददमाशो ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह तो सिक्खों के दो फिरकों की लड़ाई थी। ननकाना जैसा भीषण-काण्ड, जहा कि यात्री इस तरह मार डाले गये हो और जिनमें अभी कुछ जान बाकी थी वह भी उस जलते हुए गड्ढे में डाल दिये गये हो, पहले कहीं नहीं हुआ था।

कांग्रेस की शुरुआत के सालों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र ब्रिटिश कमिटी बन रही थी और उसका खर्च-वर्च और जरूरतें बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। कई साल तक लगभग ६०,०००) साल उसके खर्च के लिए मजूर किये जाते रहे। परन्तु अब उसकी जगह भारतवर्ष आन्दोलन-केन्द्र बन गया था। इसलिए वेजवाडा में यह निश्चय हुआ कि इस वर्ष के शेष दिनों के लिए (१७,०००) मजूर किया जाय, जोकि अध्यक्ष, मंत्री और सजाची के दफतर-खर्च में काम आवे। लालाजी और

केलकर साहब की सलाह से अमरीका की होमरूल-लीग वाले वीमुत रायू को तार-द्वारा एक हजार डालर भेजे गये। ६ और १३ अप्रैल के दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाये जाने तय हुए। महासमिति में कांग्रेस-श्रान्तो के प्रतिनिधियों की सख्या का बटवारा इस तरह किया गया कि जिससे भूतपूर्व सभापतियों को छोड़कर ३५० की सख्या में गठबन्ध न हो। १० मई को जब इलाहाबाद में कार्य-समिति बैठी तो अगली बैठक के लिए तजीर और शोलापुर से उसे नियंत्रण मिले थे, परन्तु इस बैठक में कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं हुई। १५ जून को बम्बई में फिर उसकी बैठक हुई, जिसमें गांधीजी ने बाइसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया।

गाँधी रीडिंग मुलाकात

यह मुलाकात सालवीयजीने करवाई थी। उस समय लॉर्ड रीडिंग बाइसराय हुए थे। यह अप्रैल १९२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई और बुद्धिभाव को देखने का अवसर मिला। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि जुद्ध असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना युगातिव न होगा। प्रसंगवश उन्होंने अली-भाइयो के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का सङ्ग होता था। गांधीजी को बताया गया कि इन व्याख्यानों का तात्पर्य हिंसा को सूक्ष्म-रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगाया जा सकता है। गांधीजी तो ठहरे बड़े ही मुसिफ-मिजाज। उन्हें भी जेंचा कि हा इन भाषणों का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अली-भाइयो को लिखा और उनसे इस आशय का वक्तव्य निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था।

यह 'भाफी-प्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। गोरे लोग सरकार की इस विजय पर बड़े खुश थे। भाफी से लॉर्ड रीडिंग को तसल्ली हो गई और उन्होंने अली-भाइयो पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया।

असहयोग और दमन

बम्बईवाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गई। कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी और फौजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी मुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिए। सिर्फ अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए। जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोषता मिट्ट हो जाय। यदि जाला फौजदारी ती

रुसे कोई जमानत तलब की जाय तो वह उसे देने से इन्कार कर दे और उसकी एजन्स में जेल भुगत ले। आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी वकीलो को फीस लेकर या विना फीस के किसी अदालत में पौरबी न करना चाहिए। उस समय यह अन्देश था कि कहीं अगोरा में तुर्किस्तान की सरकार के साथ मिडन्त न हो जाय। इसपर कार्य-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लड़ाई छिड़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह ब्रिटिश-सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि वे इस सिलसिले में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें।

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई में महासमिति की एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। बेजवाडा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। तिलक-स्वराज्य-कोष में निश्चित से १५ लाख रुपये अधिक आ गये थे। कांग्रेस सदस्यों की सख्या आठ के ऊपर पहुँच कर रह गई, मगर चर्खे करीब-करीब बीस लाख चलने लगे थे। इसके बाद अब नुनने तथा खादी-सम्बन्धी विविध क्रियाओं की ओर देश का ध्यान गया। इस उद्देश की सिद्धि के लिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रबल देश के सामने था। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि "तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें।" बम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोध किया गया कि "वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रखें और वह ऐसी हो जिससे गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मौजूबा दरों से तो दाम हर्गिज न बढ़ाये जायें।" विदेशी कपड़े भगानेवालों से कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के आर्डर न भेजें और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग करें।

महासमिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कूदरती हक है कि वह सरकारी नौकरो पर सरकार की मुल्की या फौजी नौकरी छोड़ने-सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कूदरती हक है कि हरेक फौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की अपील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लें जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का विश्वास एव समर्थन गँवा दिया है। मद्य-निषेध-आन्दोलन के सम्बन्ध में, धराबियों को शराब की दुकानों पर न जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों-द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप की बखौलत, धारवाड, भतिया तथा अन्य

स्थानों में कुछ कठिनाइयाँ खड़ी हो गई थी। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का आदेश देना पड़ेगा। थाना के जिलाबोर्ड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए महासमिति ने भारत के अन्य जिला व म्युनिसिपल बोर्डों से थाना-बोर्ड-द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिये कहा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था, और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदुम रखना था। व्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार बन्द कर दें। पूर्ण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सतर्क थी।

दमन-वक्क बंद भयावह और विस्तृत-रूप में जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उसका बहुत जोरोशोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहुत से लोग, बिना मुकदमा लड़े, जेलों में पड़े हुए थे। उन सबको बर्षाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-सहन और सफाई या जमानत दिये बगैर जेल जाने से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के जवाब में सविनय अवज्ञा शुरू करने की मांग की थी। सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियों-द्वारा बसू में किये गये कथित अत्याचारों की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि "हिन्दुस्तान-भर में अहिंसात्मक वातावरण को और भी अधिक सुदृढ़ करने, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-माधारण के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव किसे हद तक कायम हुआ है, और देश में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोश की बात न रह कर नियमित रूप में और सुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय है कि सविनय अवज्ञा को उन वक्त तक स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम पूरा न हो जाय।" मुवराज के आगमन के सिलसिले में महाममिति ने निश्चय किया, कि "(उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तौर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हो, हरेक का यह कर्तव्य है किन तो उनमें मगीन हो और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करे।"

धारवाड में १ जुलाई १९२१ को अधिकारियों ने भीड़ पर जो गोनी-बाग किया

था उसकी जाच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने नागपुर के असहयोगी वकील श्री भवानीशकर नियोगी (जो अब मध्य-प्रांतीय हाइकोर्ट के एक जज हैं), वडोदा के अवकाश-प्राप्त जज अब्बास तय्यबजी तथा मैसूर में कुछ समय तक जज रहनेवाले श्री सेटलूर की एक समिति नियुक्त की। ३० सितम्बर से पहले-पहले विदेशी कपड़े का भली-भांति बहिष्कार हो जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जाकर विदेशी कपड़े जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियंत्रण में अलग स्वयं-सेवकों को रखने के लिए कहा। अखिल-भारत तिलक-स्वराज्य-फंड में जमा होनेवाली प्रान्त की कुछ रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कटाई का संगठन करने, हाथ-कटे सूत व हाथ-बुने कपड़े का संग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए अलग रखने को कहा गया। चकि कुछ प्रान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समिति ने उन प्रान्तों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी ही—६, ७, ८, ९ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। धारवाड-गोलीकाण्ड और मोपला-उत्पात की जाच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्पात पर कार्य-समिति ने जो प्रस्ताव पास किया, उसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं—

“मोपलो-द्वारा किये गये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निन्दा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे मालूम पड़ता है कि मोपलो को असहनीय-रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तीर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरे प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलो-द्वारा किये गये अत्याचारों का इकतरफा और बहुत अतिरजित वर्णन किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावश्यक जन-संहार किया उसको उससे बहुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुतः वह हुआ है।

“कार्य-समिति को यद्यपि इस बात का दुःख है कि कुछ धर्मोन्मत्त मोपलो-द्वारा जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तथापि सर्व-साधारण को वह इस बात से आगाह करती है कि सरकारी या जानबूझकर गड़ी गई बातों पर वे एकाएक विश्वास न करें। समिति को प्राप्त खबरों से मालूम पड़ता है कि जिन परिवारों के जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबर है वे मजदूरी के आस-पास रहते थे। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत्त-दल ने बनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है, और जहातक हमें मालूम हुआ है, अभी तक तीन ही ऐसे मामले हुए हैं।”

अली-भाइयों की गिरफ्तारी

घटनाएँ एक के बाद एक तेजी से घट रही थी। १९२१ की अखिल भारतीय खिलाफत-परिपद् में जुलाई को कराची में हुई जिसको लेकर अलीबन्धु, डॉ० किचलू, शारदा पीठ के जगद्गुरु श्री शकराचार्य, मोलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद और मोलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम भागो की तारीफ करते हुए, उस परिपद् ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि “आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम लिखाना, या उसमें मदद करना हुराम है।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार अगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरमानी (सविनय-अवज्ञा) शुरू कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहमदाबादवाले जलसे में भारतीय प्रजातन्त्र का अण्डा लहरा देंगे।

इस प्रस्ताव का मूल कारण कार्य-समिति का एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फौज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में “कलकत्ता और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र की गई थी।” १ अक्टूबर को कार्य-समिति की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया—“किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्यायपूर्ण अभिलाषाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जैसे रोलट-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग मिस्र-वासियों, तुर्कों, अरबों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।” अली-भाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आशा भी गई थी। कार्य-समिति ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उसपर दबाई दी और घोषणा की कि मुकदमा चलाने का जो कारण बताया गया है वह धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालनेवाला है। उसने यह भी कहा—“कार्य-समिति ने अब तक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों को कांग्रेस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं पर अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रबन्ध करने में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि कांग्रेस के सहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कर्त्तव्य है कि वह यदि कांग्रेस की सहायता के बिना निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे।” उन्हें बताया गया कि कसता, बुना

आदि स्वतंत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साधन हैं। देश-भर की कांग्रेस कमिटियो ने कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावें और १६ अक्टूबर को इस आज्ञा का पालन किया गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार अभी अधूरा पड़ा था। कार्य-समिति ने कहा कि जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त में सामूहिक-सत्याग्रह आरम्भ करना असम्भव है, और जबतक हाथ से कातने और बुनने का काम उतना न बढ़ जायगा कि उससे उस जिले या प्रान्त की आवश्यकतायें पूरी हो सकें, तबतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हा, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम में रुकावट डाली जाय। पर इसकी अनुमति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी से लेना जरूरी है और प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अहिंसात्मक बातावरण बना रखा जायगा। युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत में पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल मनाई जाय और वह भारत के नगरो में जहाँ-जहाँ जायें, हड़तालें की जायें। इसके प्रवन्ध का कार्य कार्य-समिति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियो को सौंप दिया। साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई कि भारत-सरकार भारतीय लोक-मत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध हो या जिन्हें वे न चाहते हों। उन पड़ोसी राज्यों को जो भारत के प्रति शत्रुता का भाव न रखते हों, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें।

इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया। जब यह पता चला कि कराची के मापण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांधीजी ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापल्ली में थे, मापण को स्वयं बोहराया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को दोहराने की आज्ञा दी। समय तेजी के साथ बीतता चला जा रहा था और स्वराज्य की अवधि में केवल एक महीना रह गया था। देश ने अली-भाइयों की और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर जिस सयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ५ नवम्बर १९२१ की महासमिति की बैठक ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो को अपनी जिम्मे-दारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में करबन्दी

भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियो पर छोड़ दिया गया। हा, इन शर्तों का पूरा होना जरूरी समझा गया—हरेक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अंश को जो उसपर लागू होता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खद्दर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पंजाब के अन्यायों को दूर करने और स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलक समझता हो। सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील को एक इकाई समझा जाय जहाँ के अधिकांश लोग स्वदेशी का पालन करते हो और वही पर हाय से तैयार हुई खादी पहनते हो, और असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते और उनका पालन करते हो। कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। कार्य-समिति यदि चाहे तो प्रांतीय कमिटी के अनुरोध पर किसी खास अर्थ को कमिटियो पर लागू न करे।

मलाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिन्दुओं के अवर्द्धती मुसलमान बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया।

चिराला की हिजरत

यहाँ अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन में दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। १९२१ में मरम्भार का मुदाबला करने की प्रवृत्ति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रांतों में अपने आपनास की स्थिति को देखकर तथा वहाँ की स्थानिक नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महासमिति की बैठक ३१ मार्च को आंध्र-प्रान्त के वेजवाडा नगर में हुई, जिनमें जनता में उत्साह की लहर आ गई। कुछ ही दिनों बाद चिराला के लोगों को अपने गांव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगल के गजधे, जो कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। अब कांग्रेस-दल भी दमकी बत्तर् निकालने के लिए आनुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि जनता म्युनिसिपैलिटी की परवा नही करती तो वह उनकी सीमा छोड़कर बाहर जा बने। गांधीजी ने यह भी चेनावनी दे दी कि

यह सब पागम के नाम पर न किया जाय। जिसका क्या जाह्यें था और उस महान् कार्य का ही उठान के लिए नेता भी गोप्य ही मित्र। आध्वर्यव जी० गोपाल-प्रसाद ने उस दिनांक की पूर्ति करने में अपनी नारी सागि लगा दी और हिजरत का अनुभव दिया। यह रिज्जान हमें मिथ के मंगलमानों की अफमानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है। गिम्मत के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक बण्ट उठाने पड़े। ये स्त्रियोगिनीयों की सीमा के बाहर १० महीनों का लोगनों में पड़े रहे। ऊपर अनेक नेताओं की गिम्मतारी गन्तव्य परके जारी रही। जिन्होंने अहमयोग नहीं किया था वे बताने-बूझने में राती हो गये और एक मात्र नरक घर-बार छोटे रहने के बाद लोगों ने स्त्रियोगिनीयों को मान दिया।

मोपला-उत्पात

यहां उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिनमें मलाबार में मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ। मोपले थे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज अरब थे, मलाबार के मुस्लिम ग़ामन पर जायज थे और यहाँ छादी-व्याद करके रहने लगे थे। साधारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या गेती-बाजी करते हैं। पर धार्मिक उन्माद की पुन में वे उतने अगिम्त हैं जितने कि प्राणा की या दारीयक गुन तक की विलकुल चिन्ता नहीं करते। मोपलों के आये दिन के दंगों में "मोपला दगा-विधान" नामक एक विशेष कानून की जन्म दिया। गगनार आरम्भ में उस बात के लिए चिन्तित थी कि "भय जाने-वाले" मोपलों में अहमयोग की चिनगारी न लगने पावे। पर आन्दोलन और सब जगहों की आनि केरल में भी पहुँचा। फरवरी में चपत्ती राजगोपालाचार्य और सी० बाबू-लाल जैम प्रमुख नेता आदियों का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। बाबू-लाल ने गामतीर में कहा था कि अहमयोग पर व्याख्यान न हुआ, परन्तु इतने पर भी उनके गिलाफ-गिपेधानमक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १९२१ को बाबू-लाल, माधन नयन, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर दिये गये। मोपले मुख्यतः वायनद और ऐरण्ड ताल्लुको में रहते हैं। सरकार ने उन नाकुरों में दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आते रण-दण ही बदल गया और मोपलों ने, जो अपने डगलों या मुल्लानों के मस्जिदों में किये गये अपमान से क्षुब्ध हो रहे थे, मारकाट आरम्भ कर दी। शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक-रूप धारण कर लिया। मोपलों ने धन्दूओं और तलवारों से लुप्त-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये। अक्टूबर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक बठोर फौजी-कानून जारी किया गया।

मोपले सरकारी अफसरो को लूटने और धरवाद करने के अलावा हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और हत्याएँ करने के भागी बने। अंग्रेजों के प्राण सकट में थे। श्री एम० पी० नारायण मेनन नामक एक कांग्रेसी सज्जन ने, जिन्होंने सारे मलाबार में कांग्रेस का सगलन करने के काम में बहुत-कुछ भाग लिया था, मोपलो को समझा-बुझाकर अंग्रेजों के प्राण बचाये। पर इसी कार्यकर्त्ता को नवम्बर में पकड़ कर पहले शाही कैदी के रूप में रक्सा और फिर सरकार के खिलाफ दगा करने के अभियोग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। यह १९३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे। इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर उनसे यह शर्त अवानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक वालनद वाल्लुके में न घुसोंगे। इन्होंने यह शर्त मचूर न की, और जान-बूझकर बीरतापूर्वक जेल में रहे। मोपला-विद्रोह ने आगे क्या-क्या रूप धारण किये, या अगस्त के बाद उसमें जो मारकाट चलने लगी, उनसे हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उनके अत्याचारों का विरोध किया।

युवराज का सफल बहिष्कार

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये। नई बढी कौंसिल को वही खोलने-बाले थे, पर १९२० के अगस्त के वातावरण को देखकर भारत-सरकार ने डफूक ऑफ कनाडा को बुलाया। १९२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश-सरकार की आन बनाये रखने के लिए भेजा गया। कांग्रेस ने पहले से ही विस्मय कर लिया था कि युवराज की अगवानी से सम्बन्ध रखनेवाले सारे उत्सवों का बहिष्कार किया जाय। यही किया गया और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। युवराज के बम्बई-पदार्पण के दिन ही शहर में केवल मुठमंड ही नहीं हुई बल्कि चार दिनों तक दगों और खून-खज्वर होते रहे, जिनके फल-स्वरूप ३३ आदमी मरे और लगभग ४०० आदमी घायल हुए। ये दगों सरोजिनी देवी और गांधीजी के रोके भी न सके, यद्यपि उन्होंने धमासान लडाइयों में घुस-घुस कर लोगों को सितर-वितर होने को कहा। इन दगों में असह्य आदमी घायल हुए। गांधीजी ने जबतक शान्ति स्थापति न हो जाय, जनता की ज्यादतियों का प्रायश्चित्त करने के निमित्त ५ दिन का व्रत किया। इन्हीं दुश्मनों को देखकर गांधीजी ने कहा था कि मुझे स्वराज्य की सहादत आ रही है। युवराज के आगमन के फल-स्वरूप देशभर के स्वयंसेवकों के दल सगठित हुए। जबतक कांग्रेस के स्वयंसेवक ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता मात्र थे जो मेलों और उत्सवों के अवसर पर यात्रियों की

सहायता करते, यन्त्रमय रोगों के फैलने पर रोगियों की ओर कोई स्थानिक विपत्ति होने पर पीड़ितों की सहायता करते और परिपदों और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर काम में आते। पर खिलाफत के स्वयंसेवक "सैनिक" ढंग के थे, जो कि सरकार के कथनानुसार "कवायद करते और वाक्यावृत्त दल बनाकर मार्च करते और बढ़िया पहनते थे।" इन दोनों सत्याग्रहों के स्वयंसेवकों ने हड़तालों का और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का संगठन किया। ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने की शर्त के साथ सत्याग्रही बन गये। हजारा की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। युवराज २५ दिसम्बर को कलकत्ता जानेवाले थे। बंगाल-सरकार ने बम्बई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेंट-एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक भर्ती करना गैर-कानूनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें देशबन्धु दास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद ही युक्त-प्रान्त और पंजाब की बारी आई। अहमदाबाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशबन्धु दास क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेंट-एक्ट के अंतर्गत या ताजिरात-हिन्द की १४४ धारा या १०८ धारा के अनुसार जेल में थे। १९२० के अगस्त में सर तेजबहादुर सप्रू बाइसराय की कार्य-कारिणी के कानून-सदस्य (ऑफ-मेम्बर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं को इन्होंने धोखे निकाला था और राजनैतिक लोगों पर लागू करने की सलाह दी थी। बम्बई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर बंगाल, युक्तप्रान्त और पंजाब ने दमनकारी कानूनों की ज़रूरत ली।

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत चल पड़ी। भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले जाते समय यह प्रबन्ध किया गया था कि बाइसराय हर साल बड़े दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेंगे। युवराज के बड़े दिन भी कलकत्ते ही बिताने का निश्चय किया गया। पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनों ने कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग की परिस्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता कराने की चेष्टा की। लॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये, चाहे २५ दिसम्बर के उत्सव का बहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक मिश्र-मण्डल वाइनगय से मिला। देशबन्धु दास कलकत्ते के जलीपुर-जेल में थे। उनसे मध्यम्यों की टेलीफोन-द्वारा बात हुई। गीध ही गांधीजी में बान-बीत कर्मा आवश्यक ममझा गया। वह अहमदाबाद में थे। तार-द्वारा सरकार इस बात पर गंजी हो गई कि सत्याग्रह

के कैदियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परिषद् बुलाई जाय, जिसमें कांग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हों। इस परिषद् में सुधार-योजना पर विचार किया जाय। देशबन्धु दास की माग यह थी कि नये कानून (क्रि० छॉ० अ० एक्ट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को छोड़ दिया जाय। समझौते के निश्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैदी और फतवे के कैदी, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली, मौलाना शौकतअली, डॉ० किचलू और अन्य नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाते। कराची के कैदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १९२१ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिषद् में, जिसमें फौजी नौकरिया छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने के अपराध में दण्ड दिया गया था। कुछ उलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फतवों में किया था। फतवा मुसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक आदेश होना है जिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में निर्देश होता है।

परन्तु गांधीजी कराची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आधिकार्य में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने माग पेश की कि फतवों के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिकेटिंग जारी रखने का अधिकार माना जाय। ये मांगें नामजूर कर दी गईं। इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार-द्वारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुँच सका—अभाग्यवश तार को रास्ते में देर लग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकत्ते से रवाना हो गये। (२३ दिसम्बर)। फलतः समझौते की बात असफल रही। श्री० जिन्ना और पण्डित मदनमोहन मालवीय मध्यस्थ थे। (१९२१ के दिसम्बर की सम्मेलन-वार्त्ता का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को श्री कृष्णदास की अंग्रेजी पुस्तक "गांधीजी के साथ सात महीने" पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ने योग्य है।) समझौते की बात असफल होने पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अवधिष्ट भारत ने भी उन्हीं प्रकार किया। कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई। कसाइयों तक की दुकानें बन्द थीं। इसमें यूरोपियनों को बड़ा क्रोध आया। १९२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद-नाग्रम हुई, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। नागपुर में अधिवेशन के बाद से राजनैतिक अवस्था में बड़े परिवर्तन न हुआ था।

सत्याग्रह की तैयारी और अहमदाबाद-कांग्रेस

वातावरण में सनमनी थी। हर एक के दिल में यही आनाये उमंग थी—
एक साल में स्वराज्य। गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि मेरे सत्याग्रह को पूरा

कर दोगे तो स्वराज्य एक साल में मिल जायगा। साल खत्म होने को था, और हर दार्म राजनैतिक आकाश की ओर ध्यान लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्वराज्य उसके चरणों में आकर सड़ा हो जाय। परन्तु हा, हर शरस अपनी तरफ से शक्ति-भर कुछ करने और जो-कुछ भी भुगतना पड़े उसे भुगतने के लिए तैयार था—इसलिए कि वह दैयो-घटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह मुदिन जल्दी-मे-जल्दी आ जावे। फोर्ड २० हजार के ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चुके थे। उनकी भरपूर भीड़ ही ३० हजार तक हो जानेवाली थी, लेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को बहुत लुभा रहा था। और वह क्या था ? उसका क्या रूप होगा ? गांधीजी ने इमका खुद कोई लक्षण नहीं बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया, न खुद उनके दिमाग में ही उनकी स्पष्ट कल्पना रही होगी। वह तो एक शोधक, एक शुद्ध हृदय के गामने उगी तरह अपने-आप खुल जाता है, उसके एक-एक कदम दिखाई पड़ते हैं, जिन तरह एक बयायान जंगल में एक आदमी चलता है और उस थके-मादे निगम मुसाफिर को घूमने-घामते अपने-आप रास्ता मिल जाता है। सामूहिक सत्याग्रह तो मृत्योय व्यक्तियों द्वारा किन्ही अनुकूल क्षेत्र में नियत शर्तों के पालन होने के बाद ही शुरू करना था। न तो उसमें जल्दी की गुंजाइश थी न थकावट की। इसके अनुसार गांधीजी गुजरात में लगानबन्दी-आन्दोलन करना चाहते थे।

अब लोग भय छोड़ चुके थे। एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो चुका था। कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही बल पर लोगों का विदवास प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की प्रतिष्ठा और रोव की भी जट बहुत-कुछ हिल गई थी और स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी ज्ञान बढ़ गया था।

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों के बैठने के लिए कुंसिया और वैन तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन में कोई ७० हजार खर्चा खर्च हुआ था। स्वागताध्यक्ष बल्लभभाई पटेल का भाषण छोटे-मे-छोटा था। कम-से-कम प्रस्ताव—कुल ६ उस अधिवेशन में पाम हुए। हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही। और कांग्रेस-कार्य के लिए जो तम्बू और टेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी।

यहा हम सक्षेप में उन सब घटनाओं को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ कांग्रेस का ध्यान था। देशबन्धु की जगह हकीम साहब इसलिए समापति चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति थे। यहा तक कि दिल्ली में हिन्दू-महासभा

के एक परिपद में वह उसके समापति चुने गये थे। देशबन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका भाषण था। देशबन्धु का भाषण उनकी भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनी देवी ने पढा। देशबन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक और व्यापक-रूप से सिद्धान्तलोकित किया। संस्कृति में ही उसकी जड़ है इसलिए उन्होंने कहा, "पक्षर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को आत्म-सात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना होगा।" इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून (गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, "इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की निफारिश मैं आप से नहीं कर सकता। मैं इज्जत को छोड़कर क्षान्ति खरीदना नहीं चाहता। जब-तक इस कानून का वह प्राक्कथन कायम है, और जबतक अपने घर का इन्तजाम हम आप करें, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने भाग्य का निर्माण आप करें, हमारे इस अधिकार को तत्सलीय नहीं कर लिया जाता, मैं सुलह की किसी शर्त पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।"

देशबन्धु के उस शानदार भाषण से अहमदावाद के मध्य प्रस्तावों को देखने की सही दृष्टि मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-क्रम पर एक खासा निबन्ध ही है। यद्वातक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस प्रस्ताव को अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी में मुझे बारीकी से पढ़ने में ३५ मिनट लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले १५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय कार्य हुए हैं उनका वह बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रस्ताव के द्वारा सुलह का रास्ता बन्द नहीं कर दिया था, बल्कि बाइसराय यदि सद्भाव रखते हो तो दरवाजा उनके लिए खुला रक्खा गया था। "परन्तु यदि उनके साथ ठीक न हो तो दरवाजा उनके लिए बन्द है। परवा नहीं कितने ही लोगों को तबाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह दमन कितना ही उग्ररूप धारण करले। हा, उनके लिए गोलमेज-परिपद का पूरा अवसर है, परन्तु वह वास्तविक परिपद होनी चाहिए। यदि वह ऐसी परिपद चाहते हैं कि जिसमें बराबरी के लोग बैठें हो और उनमें एक भी मिलावटी न हो, तो दरवाजा खुला है और खुला रहेगा। इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे विनय और विवेक रखनेवाले को क्षमिन्दा होना पड़े।" उन्होंने फिर कहा कि "यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्घाटन चुनौती नहीं है, बल्कि यह तो उन दुरुम्मत को चुनौती है, जो उद्घाटन के सिद्धान्त पर विराजमान है। यह एक नम्र परन्तु दृढ़ चुनौती है, उस दुरुम्मत को जो अपने को बचाने की गरज से गये देने और मिलने-जुलने

की आजादी को कुछ देना चाहती है, और यह दो तरह की आजादी तो मानो स्वाधीनता की शुद्ध वायु की सास लेने के लिए दो फेफड़ों के समान है।” असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहाँ पास हुआ वह इस प्रकार है —

(१) “चूँकि कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को अपने अनुभव से मालूम हुआ है कि अहिंसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, आत्म-बलिदान और आत्मसम्मान के मार्ग पर बहुत उन्नति की है और चूँकि इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को बहुत बड़ा झटका पहुँचाया है और चूँकि देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीव्र गति से हो रही है, इसलिए यह कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार करती है और वृद्ध निश्चय प्रकट करती है कि जबतक पञ्जाब और खिलाफत के अत्याचारों का निवारण नहीं हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी और भारतवर्ष का शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन सत्ता के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में नहीं आ जायगा तबतक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त निश्चय करेगा।

और चूँकि वाइसराय ने पहले हाल के भाषण में घमकी दी है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत-सरकार ने अनेक प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छृंखल-रूप से स्वयंसेवक-संस्थाओं को विच्छिन्न करके, और सार्वजनिक सभाओं और कमिटी की बैठकों की भी मनाही करके और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अनेक कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूँकि यह स्पष्ट है कि यह दमन कांग्रेस और खिलाफत के कामों को विच्छिन्न करने और जनता को उनकी सहायता से वंचित करने की गरज से चलाया गया है, इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि जहाँ तक आवश्यकता हो कांग्रेस के सब कार्य स्थगित रखे जायें। और सब लोगों से प्रार्थना करती है कि वे शान्ति के साथ बिना किसी घुम-घाम के स्वयंसेवक-संस्थाओं के सदस्य होकर गिरफ्तार होवें। ये स्वयंसेवक-संस्थायें देशभर में कार्य-समिति के बमबई के गत २३ नवम्बर के निश्चयानुसार सगठित की जावें। किन्तु जो व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वह स्वयंसेवक नहीं बनाया जायगा—

‘ईश्वर को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ।

(२) जबतक मैं सब का सदस्य रहूँगा तबतक वचन और कर्म में अहिंसात्मक रहूँगा और इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी अहिंसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा से ही खिलाफत और पंजाब की रक्षा हो सकती है और उत्तीर्ण स्वराज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त जातियों में—चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या बहूवी हों—एकता स्थापित हो सकती है।

(३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूँगा।

(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के कपड़े और बुने खट्टर का ही इस्तेमाल करूँगा।

(५) हिन्दू होने की हैसियत से मैं अस्पृश्यता को दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव अवसर पर वलित लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रखूँगा और उनकी सेवा करूँगा।

(६) मैं अपने बड़े अप्सरों की आत्माओं और स्वयंसेवक-सच, कार्य-समिति या कांग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होंगे।

(७) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ।

(८) अगर मैं जेल जाऊँ तो अपने कुटुम्बियों या जो लोग मुझपर निर्भर हैं उनकी सहायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं माँगूँगा।'

'इस कांग्रेस को विश्वास है कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वयंसेवक-सच में शामिल हो जायगा।

'सार्वजनिक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई है उसकी परवाह न करते हुए और यह देखते हुए कि कमिटी की बैठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने का प्रयत्न किया गया है, यह कांग्रेस सलाह देती है कि कमिटी की बैठकों और सार्वजनिक सभायें हुआ करें। सार्वजनिक सभायें धिरी हुई जगहों में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जावें, जिनमें सम्भव नही वक्ता अपना लिखा हुआ भाषण पढ़े जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो। हर हालत में इस बात का खयाल

रक्खा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावे और उसके फल-स्वरूप जनता के द्वारा हिंसक कार्य न हो जायें।

“आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या सस्था के अधिकारों का निरकुण, अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग किये जा चुके हों तो सशस्त्र क्रान्ति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सम्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शान्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और जिनका यह निश्चय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयों के प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी-पद से उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रह गया है, यह सलाह देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर या महासमिति की दिल्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के प्रस्ताव-ानुसार देशभर में व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का सगठन करें।

“इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या रक्षात्मक सत्याग्रह पर पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रतिबन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहाँ और जितने स्थान पर आवश्यक समझा जाय तब, वहाँ और उतने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थगित कर दिये जायें।

“यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेष-कर राष्ट्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और अध्यापकों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-सभ के सदस्य हो जायें।

“यह देखते हुए कि थोड़े समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के गिरफ्तार होने का भय है और चूँकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रबन्ध उसी तरह चलता रहे और वह जहाँ शक्ति में हो वहाँ साधारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जब तक आगे कोई सूचना न दी जाय तबतक यह कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महा-समिति के समस्त अधिकार देती है। इसमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासमिति और कार्य-समिति की बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों का प्रयोग महा-समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांधी को) मौका आ जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार रहेगा।

“यह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जानेवाले अन्य उत्तराधिकारियों को ऊपर के सब अधिकार देती है।

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांधी या उनके उपर्युक्त उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की मजूरी के बिना भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार से सवि करने का अधिकार है, और कांग्रेस के सगठन की पहली घारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के बिना महात्मा गांधी या उनके उत्तराधिकारियों-द्वारा नहीं बदली जायगी।

“यह कांग्रेस उन सब देश-भक्तों को बचाई देती है जो अपने अन्तःकरण के विश्वास या देश के लिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके वलिवान से स्वराज्य बहुत निकट आ गया है।”

(२) “जो लोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते किन्तु जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए सिलाफत और पंजाब के अत्याचारों का प्रतिकार होना आवश्यक समझते हैं और उसपर जोर देते हैं और राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित कराने पर जोर देते हैं, उन सबसे कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि वे भिन्न-भिन्न धार्मिक समानों में एकता कराने में पूरी सहायता दें, जो लाखों कृषक भूखो मरने की अवस्था पर पहुँचे हुए हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आर्थिक दृष्टि से धुनने, हाथ से कातने और बुनने का प्रचार करें और इसके लिए हाथ से कटे और बुने कपड़ों को पहनने की सिखा दें और पहनें, नशीली वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतया बन्द करने में सहायता दें और यदि वे हिन्दू हो तो अस्पृश्यता दूर करने और दलित जाति के लोगों की अवस्था सुधारने में मदद दें।”

हम उस वृहत् की ओर भी मुखातिब हो जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने शुरू किया था। उनकी तजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह की जाय—“पूर्ण स्वतन्त्रता, विदेशियों के नियन्त्रण से बिल्कुल आजादी।” इस घटना को अब इतना बरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया ?

गांधीजी ने उस समय कड़ी आपा का प्रयोग किया था, किन्तु सवाल यह है कि क्या वह बहुत कड़ी थी ? गांधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तजवीज किया और नये ढंग से हमला करने की मोर्चाबन्दी की थी। यह एक ऐसा सग्राम था कि जिसमें उद्देश और उसे पाने के लिए की गई ब्यूह-रचना स्पष्ट-रूप से

निश्चित थी। दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बड़ी मुठभेड़ हो जाया करती थी। एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिपाही आकर जनरल और सेना से कहे कि हमारे उद्देश का निर्णय फिर से होना चाहिए, तो लड़ाई की सारी रचना न बिगड़ जायगी ? लेकिन उनकी जिस दलील ने असर किया वह तो थी—“सबसे पहले तो हम शक्ति-संग्रह करें—सबसे पहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। हमें ऐसे समुद्र में न कूद पड़ना चाहिए जिसकी गहराई का पता हमें न हो। और हसरत मोहानी साहब का यह प्रस्ताव हमको अथाह समुद्र में ले जा रहा है।”

दूसरे प्रस्तावों में एक तो विधान-सम्बन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। एक मोपला-उत्पात के विषय में था, जिसमें कहा गया था कि असहयोग या खिलाफत-आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस उत्पात के छ महीने पहले ही से अहिंसा के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही वहाँ रोक दिया गया था, और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती, यदि याकूब हसन जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को वहाँ जाने दिया गया होता। जब मोपला कैदी वेलारी भेजे गये तब कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी के ढब्बे में भर दिया गया, जिससे १६ नवम्बर १९२१ की रात को बम फुटकर ७० कैदी मर गये थे। इस अमानुष व्यवहार पर रोष और सन्ताप प्रकट किया गया। १७ नवम्बर को बम्बई में जो दुर्घटनायें हुईं, कांग्रेस ने उनकी निन्दा की और सब दलों तथा सब जातियों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह दृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके बाद मुस्तफा कमालपाशा को यूनानियों पर मिली फतह के लिए जिससे सेवर की सन्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागाटामारु वाले वावा गुरुदत्तसिंह को जो ७ वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अपने-आप पुलिस के सुपुर्द हो गये थे, और उन सिक्खों को क्षम्यवाद दिया गया जो इस तथा अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों द्वारा बहुत जोर दिलाये जाने पर भी शान्त और अहिंसात्मक बने रहे।

अहमदाबाद-कांग्रेस में एक खास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक मामलों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक सत्याग्रह की धार्तों के विषय में अहिंसा पर बहुत बहस-मुवाहसा हुआ था—यह कि आया, मन, वचन और कर्म से उसपर अमल किया जाय ? यहाँ यह याद रहे कि कलकत्तावाले प्रस्ताव में सिर्फ ‘वचन और कर्म’ का ही उल्लेख था। स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा में ‘मन’ शब्द के

जोड़ने पर मुसलमानों को ऐतराज था। उनका कहना था कि यह 'शरीयत' के खिलाफ जाता है। इसलिए 'मन' की जगह 'इरादा' शब्द रख दिया गया। इन सब मामलों में अलकुरान, 'शरीयत और हदीस' के मुताबिक राजनैतिक विचारों और भावों का अर्थ और निर्णय करने में उलेमा ने बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि काँग्रेस-प्रवेश और उसके बाद की कार्रवाइयों के बारे में भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे।

मुलशीपेठा सत्याग्रह

१९२१ का विवरण समाप्त करने से पूर्व मुलशीपेठा सत्याग्रह का परिचय दे देना अप्रासंगिक न होगा। मुलशीपेठा पूना से ३० मील दूर है। ताता कम्पनी ने यहां बिजली पैदा करने के लिए इस इलाके के जलप्रपातों को बाधने के उद्देश्य से मजदूर भेजे। मुलशीपेठा के निवासियों ने अपने बाप-दादा की जमीन छोड़ने से इंकार दिया और भी कैलकर आदि की सलाह ने सत्याग्रह का निश्चय किया। इस बिजली-योजना से ५१ गांव और ११,००० स्त्री-पुरुष बच्चे जमीन-जायदाद और घरबार से हाथ धोनेवाले थे। रामनवमी (अप्रैल १९२१) के दिन १२०० सावले बन्द पर जाकर बैठ गये। मजदूरों ने काम तुरत बन्द कर दिया। एक महीने तक यह सत्याग्रह चलता रहा। दिसम्बर में फिर आन्दोलन चला लेकिन बहुत समय तक चल न सका। सावले स्वयं कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। साहूकार उन्हें और दबाने लगे। यद्यपि इसमें सफलता नहीं हुई, लेकिन इसका एक यह परिणाम तो जरूर हुआ कि उन्हें जमीनों के दाम अच्छे मिल गये। इस सत्याग्रह में १२५ सावलों, ५०० बच्च-सेवकों और नेताओं ने जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, सजा पाई। इस आन्दोलन को चलानेवाली कांग्रेस तो न थी, लेकिन कांग्रेसी नेता अप्रत्यक्ष थे।

: ३ :

गांधीजी जेल में—१९२२

सर्व-दल-सम्मेलन

अभी १९२१ अच्छी तरह खतम भी न हुआ था कि कांग्रेस के हितैषी मित्रों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही सूखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को बम्बई में एक सर्व-दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न दलों के लगभग ३०० सज्जनों ने भाग लिया।

सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आधार पर अस्थायी सचि की बात चलाई जा सके। गांधीजी ने असहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन में तो वह-बाजान्ता भाग न ले सकेंगे, हा, वैसे वह सम्मेलन की सहायता अवश्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दमन बराबर जारी है, और जबतक कि सरकार के मन में उसपर कोई अफसोस नहीं है तबतक ऐसे सर्व-दल-सम्मेलन करने से क्या फायदा? सम्मेलन के बीस सज्जनों की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रखा गया और गांधीजी ने फिर असहयोगियों की स्थिति स्पष्ट की। सर शकरन् नायर इस सम्मेलन के समर्पित थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को नापसंद किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये। उनका स्थान सर एम० विवेकेश्वरय्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-नीति को धिक्कारा गया था और साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक समझौते की बातचीत चलती रहे अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरु न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोल-मेज-परिपद् धीमा ही बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य-सम्बन्धी मामलों पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत सस्थाओं को गैर-कानूनी करार देनेवाले सारे आदेशों को और राज-

शोहात्मक सभा-बन्दी-कानून को रद्द करने और उनके सजायापता या विचारार्थी लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध करें। कमिटी के जिम्मे उन मुकदमों की जांच का भी काम किया गया जिनके नाज़द आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद सर अकरन् नायर ने ग़लत बातों से भरा एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के खण्डन में श्री जिन्ना, जयन्तर और मटराजन को मनी की हँसियत से और अन्य सज्जनों को भी अपने-अपने बयान प्रकाशित करने पड़े।

अन्तिम चेतावनी

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्मन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने अपनी ७ जनवरी की बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए मुस्तवी कर दिया गया। बाइसराय ने सम्मेलन की धारों को मन्थूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। इसपर गांधीजी ने ३-२-२२ को बाइसराय के नाम पत्र देना जिनमें उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया।

पत्र (१ फरवरी १९२२) इस प्रकार है.—

“बारडोली बम्बई-ग्रान्त के चुरत-जिले का एक छोटा-सा ताल्लुका है जिसकी जन-संख्या कुल मिलाकर ८७,००० है।

“गत नवम्बर की दिल्लीवाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उस ताल्लुके ने उनकी नारी धारों के अनुसार अपनी योग्यता साबित कर दी और गत २९ जनवरी को श्री विठ्ठलनाई जवेरनाई पटेल की अध्यक्षता में नानूटिक सत्याग्रह करने का निश्चय किया। परन्तु इस निश्चय की जिम्मेवारी मुख्यतः शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए मैं उन हालत को, जिसमें यह निश्चय किया गया है, आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार बारडोली को सामूहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र बनाने का निश्चय किया गया था जिनसे सरकार की भारत के विनाश, पचाव और स्वराज्य-सम्बन्धी संकल्प की अक्षम्य अवहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-व्यापी असन्तोष प्रकट किया जा सके।

“उनके बाद ही बम्बई में १८ नवम्बर को गोचनीय दंगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप थारडोली की पार्लवाई स्थगित कर देनी पटी।

“इस वृत्त-संस्कार की ग्यामन्दी में बंगाल, आसाम, युक्त-प्रान्त, पंजाब, दिल्ली-प्रान्त और एक प्रकार से बिहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन में ताम लिया गया। मैं जानता हूँ कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो कुछ किया है, उन्हें ‘दमन’ के नाम से पुकारने पर आपको ऐतराज है। पर मेरी सम्मति यह है कि यदि अदरत में ज्यादा कार्रवाई की गई हो तो निस्सन्देह उसे दमन के नाम से ही पुकारा जायगा। सम्पत्ति का लूटना, निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में लोगों पर पापयुक्त अत्याचार करना और उनपर कोड़े बरसाना किसी तरह भी कानूनी, सम्मान-पूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सरकारी गैर-कानूनी-जन को केवल गैर-कानूनी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

“हस्ताक्षर और पिकेटिंग के सिलसिले में असहयोगियों या उनके साथ हम-दर्दी रखनेवालों द्वारा उठाने-धमकाने की बात किसी हद तक ठीक है, पर केवल इसी कारण शान्तिपूर्ण पिकेटिंग या उनकी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिसे उद्देश और कार्य दोनों प्रकार से हिसापूर्ण हलकालों को दबाने के लिए पास किया गया था, अन्धाधुन्ध गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून का जिन गैर-कानूनी ढंगों में प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुकारा जा सकता है। रहीं प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जिस कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद्द होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

“फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम लिप्त-बोलने और सभा करने की आजादी को हम साधन से जीवन-दान देना है।

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-स्रोतों पर अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए असहयोगियों ने मालवीय-परिपद्ध से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिपद्ध का उद्देश था कि वह आपको एक भोलमेज-परिपद्ध करने के लिए तैयार करे। मैं अनावश्यक दुःख-कष्ट से लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना सकोच कांग्रेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिपद्ध की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में ज्यों

ताजिरान हिन्द या जाब्ता फौजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर गयो न आती हो—सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दे। हा, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि आप प्रेस पर मे कड़ाई उठा ले और हाल में जो जुमाने किये गये हैं उन्हें वापस करा दें। मैं जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो ससार के उन सभी देशों में किया जा रहा है जहाँ की सरकारें सम्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उग्र सत्याग्रह मुस्तवी करने की सलाह दूँगा जबतक मारे कँदी छूटकर नये सिरे में अवस्था पर विचार न कर ले। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सम्युक्त समझना और फिर निःसंकोच भाव से सलाह दूँगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित भागों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था में उग्र सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार बिल्कुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जनसमुदाय की स्पष्ट भावों को मानने से इन्कार कर देगी।”

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति बम्बई के बगो, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं-सेवक दलों-द्वारा हिंसा, बराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो अली-भाइयों के माफी मागने के अवसर पर वाइसरॉय ने बताई थी, क्योंकि उस अवसर पर वाइसरॉय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को बिल्कुल ही ख नहीं कर दिया। वास्तव में इस प्रकार की परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कार्यवाहिया बन्द कर दें। पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कही नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिंग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बन्दस्तूर जारी रहेंगे। इसके अलावा “गांधीजी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद् का काम उनके निर्णयों पर सही करना मात्र होगा।” उनकी माँगों दो श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं (१) अहिंसात्मक

आचरण के लिए दण्डित अथवा विचारयोगी सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय, (२) यह आश्वासन दिया जाय कि नरकार असहयोग-दल के सभी अहिंसामूलक कार्यों में तटस्थता की नीति बरतनेगी, फिर वे कार्य ताजिरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आते हों।

चौरी-चौरा काण्ड

पर कांग्रेस के सिर पर एक अभुन महरा रहा था। ५ फरवरी को मुक्त-प्रान्त में गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा में एक कांग्रेस-जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ मिपाहियों और एक थानेदार को नींद ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी। वे सब बाग में जल मरे। उबर १३ जनवरी को महरास में वही हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे। इस अवसर पर महरास में युवराज गये थे। महरास के काण्ड ने बम्बई जैसा विशाल रूप धारण नहीं किया। तब १२ फरवरी को बारडोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और स्वयंसेवकों का मण्डल और सभायें केवल सरकार की आज्ञा को तोड़ने के लिए न की जायें। एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ नवस्य नर्तन करना, बरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-द्रव्य-निषेध का प्रचार और पचायतें संगठित करना आदि शामिल था। उबर जिन कमिटी को गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी निराशा प्रकाशित करके लोगों ने कर अदा करने को कहा और मारा लगान १० फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पड़ेगी कि आन्ध्र-देश में फरबन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जनक कांग्रेस की निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर ५ फी नदी लगान तक बचल न किया जा सका।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

बारडोली के प्रस्तावों से देश में बड़ी प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। अतः जो ऐसे थे जो शांतिवादी और उनके निश्चय ने अहिंस-प्रणाली को मान्य मानते थे, वे भी जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य कोई नवम तथ्य से न जागृत होते। अब २४

और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई तो उसमें कार्य-समिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हा, व्यक्तिगत-रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दी गई। विदेशी कपड़े की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो वारडोली के प्रस्ताव में शराब की पिकेटिंग के लिए रखी गई थी। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम की कि यदि कार्यकर्त्ता रचनात्मक कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दे तो जिस अहिंसात्मक वातावरण की आवश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।

महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आशा या कानून का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निषिद्ध सभा जिसमें प्रवेश करने के लिए टिकटों की आवश्यकता हो, और जिसमें सबको खुलेआम आने की इजाजत न हो व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है। और ऐसी निषिद्ध सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के आ सकें, सामूहिक सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्मरक्षा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई दैनिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उग्रस्वरूप की सभा समझी जायगी।

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्थ लोगों में दिल्ली में हलचल मच गई। ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझौते की तो आशा छोड़ बैठे थे। पर साथ ही गांधीजी की गिरफ्तारी की विषय को ध्यान में चाहते थे। यदि महासमिति अब भी सामूहिक सत्याग्रह को अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह को तुरन्त शुरू किया जानेवाला कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कार्रवाई न करती। उधर गांधीजी के विरुद्ध यह आवाज उठी कि उन्होंने आन्दोलन को बिल्कुल ठंडा कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गांधीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आड़े हाथों लिया। जब महासमिति की वाक्यावधि बैठक हुई तो गांधीजी पर चारों ओर से बौछारे पड़ने लगी। आन्दोलन से पीछे हटने और वारडोली के प्रस्तावों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया गया। बंगाल और महाराष्ट्र तो गांधीजी

पर टूट ही पड़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों न जारी रखा जाय? चाहे कुछ भी हो, बंगाल तो चौकीदारी-टैक्स देने से रहा। बाबू हरदयाल नाग जैसे गांधीभक्त ने बगावत का झण्डा खड़ा किया। सत्याग्रही सहर क्यों पहुँचे? बारडोली के प्रस्तावों की एक-एक सतह की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैठक में डॉ० भुजे ने गांधीजी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों-द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध बोले थे। गांधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाँति अचल रहे।

गांधीजी की गिरफ्तारी

पासा पड़ चुका था। अब गांधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढी हुई हो। वह सत्र के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ दूटता है। ११ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में सेवानुसार सुपुर्व कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। कानूनी बहलकादो ने तीन लेख छाटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'राज-भक्ति में दखल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-सर्जन'। ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैकर ने भी अपने को अपराधी कुबूल किया। उनके बाद गांधीजी ने अपना लिखित जमान पटा, जो निम्न प्रकार है—

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को मनुष्ट करने के लिए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इंग्लैण्ड की और भारतीय जनता को यह बता दू कि मैं कट्टर सहयोगी मे पत्रका राजद्रोही और असहयोगी बनें बन गया। मैं अदालत को भी बताऊँगा कि मैं इस सरकार के प्रति जो देश में पानुनन पापम हूँ है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोषी क्यों मानता हूँ।

"मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अफ्रीका में निपन

परिस्थिति में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे कोई अधिकार नहीं है। मैंने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी हूँ।

“पर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोष एक अच्छी-खासी शासन-व्यवस्था में योही आकर घुस गया है। मैंने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

“जब १८६० में बोअरो की चुनौती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान् विपद् में डाल दिया, उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवार्थें भेंट की—बायलो के लिए एक स्वयंसेवक-दल बनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गईं उनमें काम किया। इसी प्रकार जब १९०६ में जुलू लोगो ने ‘विद्रोह’ किया तो मैंने स्ट्रेचर पर बायलो को ले जानेवाला दल संपन्नित किया और जबतक ‘विद्रोह’ दब न गया, बराबर काम करता रहा। इन दोनों अवसरों पर मुझे पदक मिले और ज़रीतो तक में मेरा जिक्र किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो काम किया उसके लिए लॉर्ड हाउडिंग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १९१४ में इंग्लैण्ड और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया तो मैंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयं-सेवक-दल बनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की। जब १९१७ में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिपद् में खास तौर से अपील की तो मैंने खेडा में रगस्ट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तफ को जोखिम में डाल दिया। मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध बन्द हो गया और आज्ञा हुई कि अब और रगस्ट नहीं चाहिए। इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक-मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार मैं साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए बराबरी का दर्जा हासिल कर सकूंगा।

“पहला धक्का मुझे रौलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की बान्धनिक स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके बाद पंजाब के भीषण काण्ड का नम्वर आया। इसका आरम्भ जालियावाला बाग के बल्ले-जाम में और अन्त पेट के बल रेंगाने, झुले आम बेत लगाने और दूसरे बयान से बाहर अपमान-

जनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधान-मन्त्री ने भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थस्थानों की एकनता बरहस्तूर रखी जायगी, वह कोरा आश्वासन ही रहेगा।

“वैने १९१६ की अमृतसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया और मेरी नीति की सार्थकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी मैं इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ प्रधान-मन्त्री ने जो वादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के अरमों को भरा जायगा और लाख नाकाफी और असन्तोष-जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। फलतः मैं सहयोग और माण्डेयु-वेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की बात पर अड़ा रहा।

“पर मेरी सारी आशायें झूल में मिल गईं। खिलाफत-सवर्षी बचन पूरा किया जानेवाला नहीं था। पंजाब-सवर्षी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर अघपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो बोझ-सा सुल-ऐश्वर्य मिल जाता है वह विदेशी शोषक की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून से निकाली जाती है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन कायम है वह इसी जनता के धन-शोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झूठे-सच्चे तर्कों से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असत्य गांधी में जो नर-कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सकता। यदि हमारा कोई ईस्वर है तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने डग का निराला अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेही इरलैण्ड की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश के कानून का उपयोग विदेशी धन-शोषकों के सुभीते के लिए किया गया है। पंजाब के फौजी कानून के सवध में मैंने जो निष्पक्ष आक्षेप की है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि १०० पीछे ६५ मामलों में सच्चा के फैसले झिझकू खराब रहे। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमों का तनुर्बा मुझे बताता है कि दस पीछे नौ दण्डित आदमी सोलह आने निर्दोष थे। इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मामलों में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में न्याय नहीं मिलता। मैं अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के

मामलों ने काम पड़ा है उसका यही तज्जुबा है। मेरी राय में कानून का दुरुपयोग जानबूझ कर सही या बिना जानेबूझे सही, घन-श्लोपक के लाभ के लिए किया जाता है।

जिस १२४ ए धारा के अंतर्गत मुझपर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की आजादी का अपहरण करने में ताजिरात हिन्द की धाराओं में सिरताज है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहत रह सकता है। यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हों, तो जबतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबतक उसे अपने अंगीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर शीघ्रतः वैकर पर और मुझपर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अंगीति फैलाना अपराध है। इस धारा के अंतर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने अध्ययन किया है, और मैं जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भक्तों को सजा दी गई है। इसलिए मुझपर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे मैं अपना सीमांत्य समझता हूँ। मैंने संक्षेप में अपनी अंगीति के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वयं मन्नाट के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझमें अंगीति का भाव बिल्कुल है ही नहीं। परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचाई है उसके प्रति अंगीति के भाव रखना मैं सद्गुण समझता हूँ। अंग्रेजों की अमलदारी ने हिन्दुस्तान में पुरुषत्व का अन्य अमलदारियों की अपेक्षा अधिक अभाव हो गया है। जब मेरी ऐसी धारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना मैं पाप समझता हूँ। और इसलिए मैंने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये हैं, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम-सीमांत्य समझता हूँ।

“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैंड और भारत जिस अप्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मति में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे पहले बुराई करनेवालों को क्षति पहुँचाने के लिए असहयोग को हिंसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हिंसा बुराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है

कि हिंसा से बिल्कुल अलग रहे। अहिंसा का मतलब यह है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर ले। इसलिए मैं यहाँ उस कार्य के लिए जो कानून की निगाह में जान-बूझ कर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्ष ग्रहण करने को तैयार हूँ। आपके, जब और असेसरो के, सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह बुरा है और मैं निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें, अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दे।”

जब ने फँसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छ वर्ष की सजा दी, और श्री शंकरलाल बेंकर को एक वर्ष की सजा और १००० जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छ मास और। गांधीजी ने गिने-चुने प्रबन्धों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जब को सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को विदा किया। बहुता की आदों में आम् भी भरे हुए थे।

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड लेकर राप्ड़ की गोद में से हटा दिया गया। यह बात अचानक हुई हो, तो नहीं। स्वयं गांधीजी ने ६ मार्च को ‘यंग इंडिया’ में “यदि मैं गिरफ्तार हो गया” शीर्षक लेख में लिखा था कि चौरी-चौरा के मामले में श्री कृष्ण की रिपोर्ट निश्चयात्मक है और बरेली से कांग्रेस-अग्री की रिपोर्ट में भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिंसा की प्रवृत्ति अवश्य मौजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और गिना कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह ‘सत्याग्रह’ नहीं, ‘दुःसाग्रह’ होगा। पर गांधीजी भी समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अश्रेय-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो मध्यम विद्रोह तक की सहायता करती आई है। अश्रेय की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-नी पीछे दिग्रा पड़ी। यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से मारे देश में तूफान आ जगा तो बड़े दुःख की बात होती। गांधीजी की इच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकर्त्ता यह दिनांक कि सन्ना

की आशका निर्मूल है, न हड़तालें हो, न शोरशुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलूस निकाले जायें। यदि वारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उससे वे तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा। गांधीजी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवी शक्ति-सम्पन्न होने के सम्बन्ध में जो चारणा फैली हुई है उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगो ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता साबित हो जायगी, और साथ ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विश्राम मिल जायगा जिसके सम्भवतः वह अधिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारों ओर शान्ति कायम रही।

जेल जाने के बाद

गांधीजी की सजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही। खदर-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया। मलाबार में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,००० की मजूरी थी। सेठ जमनालाल बजाज ने बकीलो के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। खदर के अनिवार्य 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी बकीलो, को एक-द्वार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न ले, और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे हल दातो की जाच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ—(१) मोपला-विद्रोह होने के कारण, (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया, (३) सरकार ने विद्रोह को दवाने के लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया, (४) मोपलों-द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, (५) सम्पत्ति का विध्वंस, (६) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (भराली) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम में कुछ सशोधन पेश किये। अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी योजना बनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ९ जून १९२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। अन्त में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय अग्र और सत्याग्रह के मिद्वान्त और

व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और कला का सिंहावलोकन करना। देशबन्धु दास और विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होंने असहयोग को बहुत-कुछ सकोच के बाद अपनाया और बाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी साराहना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूटकर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को विस्कारा गया और इस नीति का मुकाबला करने के लिए किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस बात को अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। तदनुसार सभापति ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्रीयुक् विट्ठलभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकर्रर किया। हकीम अजमलख़ा को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की और उनके स्थान पर श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके।

सत्याग्रह-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें मार्च महीने को एकबार फिर देख लेना चाहिए। मि० माण्डेगु ने तुर्की से की गई सर्वम की सन्धि के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद छोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १९२२ को मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय तुर्की ने यूनानियों को करारी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारो तरफ दौरा-दौरा था। पंजाब में लारेस की मूर्ति जनता के क्रोध का माजिन बन गई थी। आन्ध्र में गोदावरी में राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नौकरशाही मडक उठी थी और कन्वन्शन्-मन्डोलन भी मौजूद था ही। कानून का शासन १०८ और १४४ धाराओं का शासन गूँगम था। सरकारी कार्य-कारिणी के भारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रवृत्त करने थे— क्योंकि कलक्टर (डिप्टी-कमिशनर) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग तो अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर अमहयोगी अपील को नकार न होने

थे। लोगो के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड जॉर्ज की 'स्टील फ्रेम स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सर्कुलर नामक एक गश्ती-पत्र सारी प्रान्तीय सरकारों में भुमाया गया था। उनसे ऊँचे पदों पर भारतीय रखने के प्रश्न पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात कही खुल गई और भारत व इंग्लैंड के अफसर विगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जॉर्ज ने आपण में कहा कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-तन्त्र का फौलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में तो ऐसा कोई समय न आया जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और पथ-प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहता ब्रिटेन की भारत-स्थिति बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

बोरसद-सत्याग्रह

यह सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के मुकाबले में आपे मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ीबा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि बड़ीबा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिलकर अपराधियों का पता लगाने की एक तरफ़ीब सोच निकाली। उन्होंने देवर बाबा को पकड़ने के लिए 'मुसलमान' डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस धर्त पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सशस्त्र सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। बोर को पकड़ने के लिए बोर मुकर्रर किया गया। पर पुलिस के इस नये सगी ने अपने आदमियों और हथियारों का उपयोग तहसील में और भी धूम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अपराधों की संख्या बड़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में शाववालों की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई और एक भारी ताजीरी कर भी लोतो पर लगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इधर गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के समझौते का पता चला और श्री वल्लभभाई पटेल ने इस मामले में सरकार को

चुनीती दी। वह बोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा। जिन लोगों को डाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोळियाँ निकाली गईं तो साबित हुआ कि गोळियाँ सरकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोळियाँ और सरकारी रायफलों का उपयोग किया है। श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात-दिन चौकी पहरा देने के लिए तैनात किये। लोग-बाग कई हफ्तों से शाम से ही घरों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हें दरवाजे खुले रखने को राजी किया। गाववालों ने फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भ्रम हो जाय कि घर खाली हैं। बाहर जहाँ जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुप्पी साधकर अपने-आपको कुसूरवार साबित करती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बड़ीदा-पुलिस गावों से झटपट रिमासत में हटा ली गई। पर ब्रिटिश-पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी तो वहाँ तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। इसर बेबर बाबा वल्लभभाई और स्वयं-सेवकों के पहुँचते ही वहाँ से गायब हो गया था।

गुरु-का-बाग

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गमियो में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी सिक्खों का सुधारक-दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्ख थे वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हीं का पक्ष करते थे। सुधारक सिक्ख सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रस्ता का पारं लिया। अब सिक्खों के अत्ये अहिंसा का व्रत लिये पुलिस की दृकदियों के बीच में

से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था, जो भारत की वह वीर जाति पढा रही थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस छाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था, उसकी कला में गुरु-का-वाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गगाराम नामक एक सज्जन ने वह जगह महन्त से, पट्टे पर ले ली और अकालियों के पैठ काटने पर कोई एतराज न किया।

सत्याग्रह कमिटी की सिफारिशें

सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भग न हुआ था। कमिटी के सदस्य जहाँ कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद कलकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तीर से इसकी चर्चा की गई। कहते हैं कि इस अवसर पर पण्डित मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कौंसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं? खिलाफत-कमिटी ने भी इसी ढंग की एक कमिटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौंसिलों का बहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की सिफारिशें नीचे दी जाती हैं—

१—सत्याग्रह—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भग या किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी शर्तें पूरी होती हो तो वे अपनी जिम्मे-वारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मजूरी दे सकें।

२—कौंसिल-प्रवेश—(अ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधि-वेशनों में यह बात घोषित कर दें कि चूंकि कौंसिलों ने अपने पहले सत्र (सेशन) के

द्वारा यह दिखा दिया है कि वे खिलाफत और पंजाब-सबघी ज्यादतियों की दादरसी में रुकावट बन रही हैं, स्वराज्य की शीघ्रप्राप्ति में बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्टदायिनी साबित हुई हैं, इसलिए अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी बुराईयां न उत्पन्न हो, निम्नलिखित उपायों से काम लेना चाहिए—

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफत की ज्यादतियों की दादरसी और तत्काल-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक सख्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुँच जायें कि उनके बगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहाँ से चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।

(३) यदि असहयोगी इतनी सख्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफत और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिए।

(४) यदि असहयोगी अल्प सख्या में पहुँचें तो उन्हें वही करना चाहिए जो न० २ में बताया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिए।

नई कौंसिलों का निर्वाचन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि कांग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एक बार फिर उसमें पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कांग्रेस अपना अन्तिम वक्तव्य दे सके। (हकीम अजमलखान, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री बिठ्ठलभई पटेल की सिफारिश)

(आ) कौंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में निम्नी प्रचार का परिवर्तन न होना चाहिए। (डा० एम० ए० अन्सारी, अक़बर्तो राजगोपालाचार्य, श्री एस० कस्तूरी रंगा आययर की सिफारिश)

३—स्थानिक सत्याग्रह—हमारी सिफारिश है कि स्थिति को गहन बनने के लिए यह घोषणा करना वाञ्छनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अगली शक्ति देने के लिए म्युनिसिपैलिटियों, जिला और लोकल-बोर्डों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हो, परन्तु असहयोगी मददगारों के वहाँ आवश्यक के सम्बन्ध में अभी किसी नाम

ठग के नियम-उपनियम न बनाये जायें। हा, यह जरूरी है कि वे प्रान्तीय और स्थानिक कांग्रेस-संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम करें।

४—स्कूल-कालेजों का बहिष्कार—स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि इस मामले में वारडोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और मीजुदा जोरदार प्रचार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिचकर वहां चले आयें। हमें पिकेटींग आदि उग्र उपायों का अवलम्बन न करना चाहिए।

५—अदालतों का बहिष्कार—मजदूरों स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस और लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए।

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वे उठा दिये जायें।

६—मजदूर-संगठन—नागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव न० ८ तत्काल अमल में लाना चाहिए।

७—आत्मरक्षा का अधिकार—(अ) हमारी सिफारिश है कि कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतंत्रता सबकी दी जाय। हा, जब कांग्रेस का काम कर रहे हो, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी बात है। पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्लम-खुल्ला हिंसा की नीव न आ जाय। धर्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करने में, या लड़कों और पुरुषों पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालत में मना नहीं है। (श्री बिठ्ठलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) असहयोगियों को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए, शर्तें सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नीव न आ जाय। और किसी प्रकार की शर्तें न होनी चाहिए। (श्री बिठ्ठलभाई पटेल)

८—अंग्रेजी माल का बहिष्कार—(अ) हम इसे सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करते हैं और सिफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के सुपुर्दे करना चाहिए और उनकी विनोद रिपोर्ट कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए। (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) विशेषज्ञों के सारी बातों के संग्रह करने और उनकी जाच-पड़ताल करने

में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धान्त-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी और आन्दोलन को हानि पहुँचेगी।" (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य) .

इसपर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप से बँटे हुए थे। पर दोनों वे असहयोग के ही दल; और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान में एक दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे नौकरशाही के गढ़ कौंसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था। स्थानिक बोर्डों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशों की गईं उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। कांग्रेसियों और असहयोगियों ने म्युनिसिपैलिटियों और स्थानिक बोर्डों के लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालों में छद्म और नौकरो के लिए छादी की बंदियों के व्यवहार पर जोर देते, ऑफिसों पर राष्ट्रीय सप्ताह फहराने का आग्रह करते, स्थानिक और म्युनिसिपल स्कूलों में चर्चा और हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और यदा-कदा गवर्नरो और मिनिस्ट्रो के जागमन का बहिष्कार करने पर जोर देते। इस प्रकार इन्होंने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कार्रवाइयों से केवल उनके रक्त का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर न आता था।

महासमिति की बैठक १५ अक्टूबर को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के लिए रुक गई। उस महीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को कमिटी की ऐतिहासिक बैठकें हुईं। कांग्रेस-कमिटी की चर्चा क्या भी एक प्रकार का दूरनिष्ठ था, जिसमें अपने-अपने पक्ष के योद्धाओं को ध्यान-पूर्वक छाटा गया था। पहले दिन की बैठक इण्डियन एसोसिएशन के कमरो में हुई, पर बहा सुली हुआ न मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४th रसा रोड में देशबन्धु चित्तराजन बास के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुई। वैसे बृद्ध नेहरू और बास जैसे चोटी के नेता कौंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था, परन्तु एक तो गांधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा और भक्ति ने भी जोर लगाया, असहयोग का कार्यक्रम लड़ायक था और दूसरी ओर का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नहीं था। पांच दिन की उल्लेख-बुन, नुकसातीनी, तानाजनी और बाक-प्रहारों के बाद कमिटी ने निर्णय किया कि देश सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। पर कमिटी ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया कि यदि कोई भौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेवारी

पर सीमित-रूप में सत्याग्रह की मजूरी दे सकती है, बशर्ते कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्तें पूरी होती हों। कौंसिल-प्रवेश का अधिक जटिल प्रश्न गया-कांग्रेस के लिए मुत्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी माल के बहिष्कार का प्रश्न, स्थानिक बोर्डों में प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूलों, कालेजों और अदालतों के बहिष्कार का प्रश्न, कांग्रेस का काम करते समय को छोड़कर अन्य हर समय कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्न—ये सब भी मुत्तवी कर दिये गये। बोर्डों में प्रवेश प्रश्न को स्थगित इसलिए किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में बाधा न पड़े। इस प्रकार सत्याग्रह-कमिटी की चर्चा समाप्त हुई, जिसमें कांग्रेस के १६,०००) खर्च हुए।

गया-कांग्रेस

गया-कांग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की बैठकों का पूरा विवरण दे देना ठीक होगा। गुप्त-का-बाग-काण्ड की जांच करने के लिए एक प्रभावशाली कमिटी मुकर्रर की गई, 'अमृतवाजार पत्रिका' के वयोवृद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीलाल घोष की मृत्यु पर शोक प्रकाश किया गया, और मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता कराने के लिए एक कमिटी मुकर्रर की गई।

पिछले दो वर्षों से हिन्दू-मुसलमानों में जैसा सराहनीय झेल रहा था वह १९२२ के मुहर्रमो में मुलतान में भग हो गया, बैठा हुआ, आँसू मरे और खूब छूटमार हुई। यह बड़े शोक की बात हुई। लाख कोशिशों की गई, पर बेकार साबित हुई। 'इण्डिया १९२२-२३' नामक पुस्तक में लिखा है—“गांधीजी ने जिस इमारत को इतने परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से नष्ट हो गई।” जिस प्रकार १९१७ के सितम्बर से हर महीने की १५ वी तारीख को एनी बेसेण्ट-दिवस, जबतक एनी बेसेण्ट छूट न गई, मनाया जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के बाद से प्रति मास की १८ वी तारीख को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के सिलसिले में मिली सजा भुगतकर लौटे तो १९२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। पर उनपर मकदमा चलाया गया “घमकाने और खया बसूल करने की कोशिश में सहायता देने” के लिए। उन्होंने एक व्याख्यान में विदेशी दूकानों पर धरना देने का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का मभापतित्व भी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुर्माना

भागने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया था। मामला ताजिरात-हिन्द की ३८५ धारा के अनुसार चलाया गया। असली बात यह थी कि जनरल विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटींग करने के लिए मामला चलाया जा रहा था। उन्होंने १७ मई १९२२ को अदालत में बड़ा ही सुन्दर बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार अबसे दस साल पहले वह हैरो और कैम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए बच्चे हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के कट्टर-शत्रु (वागी) हो गये। उन्होंने कहा—“मुझे अपने सीमाग पर स्वयं ही आश्चर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा करना बड़े सीमाग की बात है। और उसकी सेवा महात्मा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना दुगुने सीमाग की बात है। परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना। किसी भारतीय के लिए इससे बढकर सीमाग और क्या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण लक्ष्य की निधि में उसके प्राण खले जायें ?”

१९२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराली थी।

प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी समस्या थी। गन्दन-वाली महासमिति की बैठक ने यह समस्या कांग्रेस के अवसर के लिए मून्वी कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बैठना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि कौंसिल-प्रवेश की दृष्टान्त दे दी गई तो असहयोग की योजना भग्न हो जायगी, इसलिए वे इस बात पर और केने थे कि कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिबन्ध न उठाया जाय। कुछ ऐसे बुद्धिगाली व्यक्ति थे, जो कहते थे, कि हम कौंसिलों में जाकर न क्षय लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस ढंग से शत्रु को पराजित कर देंगे। इसके बाद उन जोशीले राजनीतिकों की घाटी थी, जो कहते थे कि हम कौंसिलों पर कब्जा कर लेंगे, मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों को सहमजहस कर देंगे, और जो उनकी भाद में जाकर पण्डित करेंगे, उनके की मजिस्ट्रेट न देंगे और विचार का प्रस्ताव पान करेंगे, और सरकारी मज का बदला प्रमाण कर देंगे।

देसबन्धु दाम ने जो भाषण पढ़ा वह तर्क, अर्थान और व्यावहारिक भावों-वाद में अपना मामी नहीं रखता। वह प्रति असहयोग की भाव को दूसरी भाव से देने के विरुद्ध अनेक दार्शनिक जट्ट मर्द, मो मो एम० पीनिसम आदित और डॉ० मो० लाल नेहरू की प्रतिभा ने मजबूत बत नाव करने गाने चली गई। एम० पीनिसम

आयगर ने सशोधन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए खड़े हो परन्तु कौंसिलो में स्थान ग्रहण न करें। पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इसपर रजामन्द हो गये। श्रीनिवास आयगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कौंसिल से इस्तीफा दे दिया था, अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी और वधाइयों की वर्षा के मध्य आन्दोलन में पैर रक्सा था। खिलाफतवाले जर्मैयत-उल-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने फतवा निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून है, हराम नहीं है। पर गया में किसीकी न चली। गांधीवाद का चारो ओर दौर-दौरा था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुपस्थित होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कुतञ्जता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल जोष और अम्बिका-धरण भुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तो को साबुबाब दिया गया।

शहीद अकालियो की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके अहिंसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसकी सफलता के लिए वधाई दी गई। कौंसिलो का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक ऋण न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामवारी कौंसिलो के नाम पर जारी किये गये नौकरवाही के ऋण में रुपया न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महा-समिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आवसी एकत्र करने को कहा गया। कालेजो और अदालतों का बहिष्कार जारी रहा और नवम्बर में आत्म-रक्षा-सवची अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरो का संगठन करने के लिए एण्डरूज साहब, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ्रीका और काबुल की कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में क्रमशः १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

स्वराज्य पार्टी

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-कांग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उनकी जेल में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापति का

भाषण और दूसरा था समापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आशा न थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुष, पण्डित भोटीलाल नेहरू और श्री विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के आदमियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौंसिल-बहिष्कार के लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। श्री दास के जिम्मे बंगाल की प्रांतीय कौंसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली और शिमला पर घावा बोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल सतम करने से पहले यहाँ राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से जतना नहीं बचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसात्मक कार्यों के लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामले में, या सैनिकों या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या किसी को डराने-धमकाने के सिलसिले में दण्डित हुए थे। किस कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह उसके अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और चरित्र के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग रखा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अपना खाना खाने और बिछौना इस्तेमाल करने, समय-समय पर चिट्ठियाँ लिखने और इष्टमित्रों से मुलाकात करने की अधिक छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को विशद-रूप से इसलिये दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने अधिकांश कैदियों के सम्बन्ध में न उस समय किया था, न बाद की। बाद को तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने में इनकार कर दिया।

: ४ :

कौंसिलों के भीतर असहयोग—१९२३

खिलाफत का खात्मा

देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर गंदा कर दिया था। १९२२ में मुल्तान में दंगा हो ही चुका था। १९२३ के मूहर्रमों में बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अचानक अन्त हो गया था। १९२२ के अक्टूबर में मुदामिया में अस्थायी संधि हुई। २० नवम्बर को लूसान में मित्र-राष्ट्रों की एक परिषद् हुई। यहाँ दो महीने तक बात-चीत होती रही। इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्की के मुल्तान को एक अंग्रेजी जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए मालटा भागना पड़ा। उसके बिदा होते ही वह मुल्तान और खलीफा दोनों पदों में च्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अब्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया। मुल्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रजातन्त्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहबी बातों तक ही सीमित रह गई।

समझौते की कोशिश

गया में अपरिवर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपये एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयंसेवक भर्ती किये जायें। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया। उमे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई राम मीका आ पड़े तो मत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की कड़ाई को ढीला कर दिया जाय। डॉ० अन्सारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-मैकट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात समापति का त्याग-भ्रम था। उन्होंने पहले ही विषय-समिति को अपनी स्वर्गज्य-पार्टी वाली योजना बना दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक

इसका समापन चुना गया और कार्य-समिति को ६म सम्मन्वय में जल्द ही कार्यवाही करने का अधिकार नौपा गया।

भारत-सत्याग्रह

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में नहीं, दिल्ली में हुआ। पर पहले हमें उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए। इसमें नागपुर-सत्याग्रह की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई १९२३ को १४४ धारा के अनुसार सिविल लाउन्स में राष्ट्रीय झण्डे मसैत जुलूस ले जाने का निषेध कर दिया। स्वयंसेवकों ने कहा—हमें अधिकार है, जहाँ चाहें झण्डा ले जायेंगे। बस, गिरफ्तारियाँ और मजबूत आगम हो गईं। बात-की-बात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप धारण कर लिया और जिसे पहले कार्य-समिति ने, जैसा कि हम कह आये हैं, आश्वीवाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ८, ९ और १० जुलाई की नागपुर-वाली बैठक में। कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय किया और साथ ही देश को आवाहन किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी-दिवस होनेवाला है, उसे झण्डा-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों को आज्ञा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता-द्वारा झण्डे फहराये। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ बमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बर्खास्त दी। सेठजी की मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाट ले जाया गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले। नागपुर झण्डा-सत्याग्रह धीरे-धीरे एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री बरलभभाई पटेल ने १० जुलाई से उसकी जिम्मेवारी लेने का अनुरोध किया गया। देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें श्री चिट्ठलभाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साबु-बाद दिया गया और आज्ञा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर संचालक बरलभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूस-वालों को इजाजत मागनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है,

हमें अधिकार है, जहाँ चाहेंगे वहाँ किसी रुकावट के जायेंगे। एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया। बल्लभभाई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अर्थात् बल्लभभाई लगी हुई थी, यही नहीं, उसे हार ही दुबारा लगाया गया था। पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर खूब हो-हल्ला मचा। अंधगोरे अंधवार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत की दरखास्त की, और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के झण्डा-सत्याग्रह के आयोजकों और स्वयंसेवकों को अपने वीरता-पूर्ण बलिदान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से बधाई दी।

प्रवासी भारतीय

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल हुई, जिसकी जोर कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा। केनिया में अवस्था दिन-प्र-दिन बुरी होती जा रही थी। यहाँ के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से असंतोषजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आबाद हो गया उसका श्रेष्ठ भारतीय मजदूरों और भारतीय धन को बहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले बड़ा कदम आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अपेक्षा वे आबादी में अधिक थे। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलैंड्स (ऊँची भूमि) की खेती योग्य जमीनें देने की जो भुमानियत कर दी गई थी, जो युगाण्डा को जानेवाली सड़क के दूसरी ओर तक चली गई है। और जहाँ कपास की खेती में भारतीयों का काफी धन लगा हुआ है, उससे भारतीयों में बड़ा असंतोष फैला। ओपनिनिंग मंत्री चर्चिल ने १९२३ के आरम्भ में केनिया के गवर्नर को बुला भेजा। गवर्नर ने साथ अंतिम समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूनिवर्सल ओप भारतीय प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (बड़ी) कोसिल ने भी एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा, जिसके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे। एण्टस्च माहव भी साथ गये।

यह समस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि गेरेमिया, टागा-निका, न्यासालैण्ड, युगाण्डा और केनिया का एक बड़ा यूनिवर्सल जलाने की शान्ति हो रही थी। युगाण्डा के प्रवासी भारतीयों की अवस्था केनिया-प्रवासी के वि-

टारे पर निर्भर थी। "अलग रखने" का जहर इस उपनिवेष्ट में भी काम कर रहा था। कम्पला की बस्ती में यूरोपियन आबादी से दूर एक जगह एशियावालों के लिए नियत कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढी बेकार गई। १९२१ में टागानिका में लॉर्ड मिलनर के आश्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की जमीन-जायदाद खरीद ली थी। अब तीन आर्डिनेन्स "आर्थिक प्रयोजन के लिए" जारी किये गये, जिनके द्वारा भारतीयों के बराबरी के अधिकार छीनने की चेष्टा की गई। इसके सम्बन्ध में व्यापक हड़ताल की गई जो १९२२ के अप्रैल तक जारी रही। पहले वर्जों में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की गई, पर बाद को यह मुमानियत उठा दी गई।

इस विषय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है :—

"केनिदा के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह प्रकट है कि ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत के लिए बराबरी और सम्मान का स्थान मिलना सम्भव नहीं है। अतएव इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय।"

कमिटी ने बताया कि २६ अगस्त को देशभर में हड़ताल की जाय और जगह-जगह समारोहों की जायें जिनमें जनता से ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रदक्षिणी में, साम्राज्य परिषद् में और साम्राज्य-दिवस में भाग न लेने को कहा जाय।

विशेष अधिवेशन

यह अधिवेशन दिल्ली में सितम्बर के तीसरे हफ्ते में हुआ। समापति मीलाना अबुलकलाम आजाद थे जो बड़े मुसलमान मीलवी हैं। बंगाल और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है। कांग्रेस के दोनों दल इनकी बुद्धि और निष्पक्षता के फायले थे। कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करनेवाले दल ने बिना कठिनाता के कांग्रेस में अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि "जिन कांग्रेस-आदियों को कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बन्द किया जाता है।" साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में दूसरी व्यक्ति में काम लेना चाहिए। पण्डित रामभजदत्त चौधरी के स्वर्गवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नामा के जवर्दस्ती गद्दी छोड़ने और बिहार, कनाडा और बर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में महानुभूति और मय-

वेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्व सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन संगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धी हलचल को व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस के विधान में परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। सभाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलों में बटे समय से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-कमिटिया मुकदरर करने की सलाह दी गई। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक कमिटी ने जाव के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग दमन का जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एकबार फिर बधाई दी गई। सहर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया और एक कमिटी देशी माल बनानेवालों को उत्तेजन और सासकर अग्नेयी माल का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढिया उपाय निश्चित करने को मुकदरर की गई। क्षण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, सास कर लालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया।

कैमिया के सम्बन्ध में जोब और तुर्की के सम्बन्ध में हर्ष प्रकट किया गया। दो कमिटिया और भी नियुक्त की गई जिनमें से एक के सुपुर्व हिन्दू-मुस्लिम-कलह को रोकने का काम, जो अब फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुर्व बुद्धि और बुद्धि-विरुद्ध आन्दोलनों में बल का प्रयोग करने की सत्यता की जाब करने का काम हुआ। शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रसक-दल बनाने और शारीरिक बल की बुद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया।

इस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस के क्रम को फिर से निश्चित करने का मार्ग सफल हो गया। गया में जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फलित हो गई। जो लोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब कांग्रेस-वादियों में पहली बार उस कार्यक्रम के ऊपर मतभेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर बँट गया था। स्वराज्य-भाटों को किस नीति और किन सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र में रख दिया गया।

कोकनडा-कांग्रेस

कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरिवर्तनवादियों को अब भी थोड़ी-बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला,

नामाना उसे चाहे बिलकुल मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खतम हो जायेंगे, फिर भी तापिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा खड़ा रखा जायगा। मोलाना मुहम्मदअली को महापति चुना गया। कोकनडा-कांग्रेस में खूब मजमूरान रही। अपरिवर्तनवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता धारीक नहीं हुए। राजेन्द्र बाबू जम्बन्धता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न आ सके और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन टाला। श्री मल्लभभाई उपस्थित थे, परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समर्थित के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीकृति बंगाल के घृष्ट-जर्जर बाबू क्ष्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी। उन्हें देश निर्वाचन और कारावास, निर्धनता और दरिद्रता में अनेक वर्ष बिताने पड़े थे। उन्होंने कोकनडा-कांग्रेस के प्रचल समुदाय को अपने कीसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण में शर्त दिया। परन्तु पास पट चुका था। कीसिल-बहिष्कार के भाग्य का निपटारा हो चुका था। बहा का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है —

“यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये प्रस्ताव को फिर दोहराती है।

“दिल्ली में कीमिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पास किया था उसे लेकर मद्देह उठ पाछा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। यह कांग्रेस स्पष्ट-रूप से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

“और यह कांग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक-कार्य के आधार-रूप है और देश से प्रार्थना करती है कि बारडोली में निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए तैयारी करे। यह कांग्रेस सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आदेश करती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि में विलम्ब न हो।”

कोकनडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रमा आयगर और अश्विनीकुमार बसु जैसे नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश करने का अग्रिय कर्त्तव्य पालन करना पड़ा। श्री एस० कस्तूरी रमा आयगर का देश-प्रेम दादाभाई की भांति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्री अश्विनीकुमार बसु को सारा बंगाल प्रेम करता था और उनकी स्मृति का भान सारा देश करता है। विनायक दामोदर सावरकर को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्दा की गई। जो राष्ट्रीय पैक तैयार किया गया था उसे देशबन्धु दास के बंगाल-पैक के साथ वितरित करने का निश्चय किया

गया। कांग्रेस ने अखिल-भारतीय स्वयंसेवक-दल की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया। इस सस्था में बाद को रक्षक-दल भी मिला दिया गया।

दिल्ली में जो सविनय-संग-कमिटी नियुक्त की गई थी वह और सत्याग्रह-कमिटी कार्य-समिति में मिला दी गई। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बनाया गया, जिते खदूर का काम-चलाने का अधिकार दिया गया। सरकार ने गिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवचक-कमिटी के अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान संघर्ष में उनका साथ देने और उन्हें आदमी और रुपये और हर प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया।

गुरुद्वारा-आन्दोलन

यह वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, सिक्खों में सुधार-सबधी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसका थोड़ा-सा विवरण करना ठीक होगा। काली पगड़ी बांधे "उत्थी काला" का घोष करनेवाले सिक्ख और उनके उग्ररक्षाने अब कांग्रेस के जाने-भूते अंग हो गये हैं। अब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार में लेती है तो स्वभावतः ही उस देश की सारी सस्थाओं पर—चाहे वे आर्थिक हों या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे धार्मिक ही क्यों न हों—कँकड़े की नाति अपने पजे फैला देती है। अंग्रेजों ने पंजाब को १८४९ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस रहो-नदल के अवसर पर सिक्ख-धर्म के केन्द्र और गठ-स्वरूप अमृतसर के दरबारसाहब के बंदोबस्त में गड़बड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छके हुए सिक्खों की एक कमिटी को ट्रस्टी बनाया गया और सरकार-द्वारा नियत व्यक्ति सरबराह या जनि-भावक बना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथों में हर साल लाखों रुपये निकलते थे। जैसा अकसर होता है, १८८१ में यह कमिटी भग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सारे अधिकार आ गये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी और आचार-हीनता का जन्म हुआ। एक ओर मैनेजर और ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्ख-जनता में आये दिन मूठभेड़ होने लगी। सरकार परेजान थी कि क्या करे। अन्त में १९२० के अन्त में एक कमिटी बनाई गई जो बाद को गिरोमणि-गुरुद्वारा-अव्यवक-कमिटी हुई। इस कमिटी के पहले सथापति सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया हुए, जो कुछ दिनों बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक सिक्ख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारों को जन्मे

हाम में किया। तरन-तारन में प्रसाद हो गया और कई सिख धायल हुए और दो मरे। हम कहें ही आये हैं कि १९२१ के आरम्भ में ननकानासाहब में किस प्रकार निर्दोष चाँचियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों के माप प्राप्त होनेवाली क्षति और सामर्थ्य को अपने कब्जे में करने के लिए था। हम दृष्टिगतों में महन्तों को बटावा मिला। इन महन्तों में वे लोग भी थे जिन्होंने अफानियों से समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार "गुधारक मित्रों के अन्या-धुन्ध दमन पर उताऊ थी।" १९२१ के मई मास में सैकड़ों मित्र जेलों में ठूस दिये गये और प्रतिष्ठाहीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया। फलतः जहातक उस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी ने १९२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया।

सरकार जो गुरुद्वारा-धिल पास कराना चाहती थी, वह सिक्खों में नरम-दण्डवाली और मध्योक्तियों तक को मजूर न हुआ। फलतः उसका विचार छोड़ दिया गया। सिक्खों पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक बड़ी कृपासे पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये। पंजाब-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्खों को जेल से छोड़ दिया गया। शब्बा के भाई कन्तार्गसिंह और भूचड़ के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का बर्बरता-पूर्ण कारावास-दण्ड दिया गया। २८ अगस्त १९२१ को काँग्रेस के सिक्ख सदस्यों को इस्तीफा देने को कहा गया। सरदारबहादुर सरदार महतारसिंह बैरिस्टर ने गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी बकालत और पंजाब-काँग्रेस के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। १९२१ के सितम्बर के आरम्भ में उपर्युक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनों सिक्खों तथा अन्य कई को छोड़ दिया गया। परन्तु पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शार्दूलसिंह कबीधर को, जिन्हें १९२१ के जून में १२४ ए चारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरुद्वारे के अन्य कार्यकर्ताओं को न छोड़ा गया। अचानक १९२१ की ७ नवम्बर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहब की चाविया छीन ली, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट न हो सकी। सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। बस, इसके बाद से चाविया ही सारे झगड़े की जड़ बन गई और जन-समाजो-द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा। सरकार ने राजद्रोही सभाबन्दी-कानून जारी किया

और सरदार खडगसिंह और सरदार मेहतावसिंह को बड़ी कैद की सजा दी गई। गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२२ को था। सरकार ने चाविया उस समय तक के लिए सौंपने की तैयारी दिखाई जबतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में दायर किये गये मुकदमे का फैसला न हो। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी ने चाविया लेने से इन्कार कर दिया। जब २०० सिक्ख-कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियों को बिना किसी अर्त के छोड़ दिया। १९२२ की ११ जनवरी को चाविया भी सौंप दी गई। पर पण्डित दीनानाथ को नहीं छोड़ा। फलतः राजश्रीही सभाबन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १९२२ की २ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी की प्रबन्ध-समिति के सारे सदस्य एक सभा में बोले। अन्त में पण्डित दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और कोमागाटामारु (१९१४) वाले बाबा गुरुदत्तसिंह को भी छोड़ दिया गया।

अकाली काली पगड़ी पहनते थे। १९२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूरथला की रियासतों में अकाली सिक्खों को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ीवाले सिक्ख पकड़ लिये गये। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी और पंजाब-प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार खडगसिंह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया। मार्च १९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा—“कृपाण तलवारें हैं निमके बनाने के लिये लाइसेन्स की जरूरत है।” लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा बताये गये ढंग से कृपाण पहनी जायें। फौजी सिक्खों का कृपाण धारण करना ही जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की बड़ी सजा दी गई। कोमागाटामारुवाले बाबा गुरुदत्तसिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १९२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिंह को ८ साल की सजा मिली।

चारों ओर क्रिमिनल-ऑब्जेक्टमेण्ट-एक्ट का दौर-दौरा था और जमानत-सम्बन्धी धारारों उसकी सहायक थी। एक नेता ने लिखा—“सब कुछ पुलिस के हाथ में था, और पुलिस ने भी उससे खुद आनन्द उठाया।” पण्डित मदनमोहन मालवीय पंजाब गये और राजा नरेन्द्रनाथ की अध्यक्षता में कमिटी नियुक्त करवाई, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादातियों, गैर-कानूनी कार्यवाहियों और निर्दयता के सम्बन्ध में जांच करना था। १९२२ की १४ मई को पंजाब-सरकार ने एक विज्ञापन निकालकर धार्मिक-

गुप्तगणों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के "जिनका मुद्धार से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, बदामनी फैलातेवाले और गैर-माननी मामों में" अलग रहें। १५ जून १९२२ तक १,९०० से २,००० तक भिन्न गिरफ्तार किये जा चुके थे।

गुरु-का-बाग-काण्ड

उनी अवसर पर गुरु-का-बाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १९२२ की चर्चा में हो चला है। उनका ही कहना था कि सिकों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिया कि गोरी गाने के बजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते हैं वे आदर के पात्र हैं। उन लाठ के गिलसिले में जो ज्यादातरिया की गईं उनमें ज्ञान प्रज्ञा-भरफार के एक यूरोपियन मदस्य ने की। एण्डरसन साहब जैसे ज्ञानियों ने उन ज्यादातरियों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "अवगत मैंने जिनमें हयविदारक और कर्मगज्जनक दृश्य देते हैं, यह उनमें सबसे बड़कर है। अहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच जहीद हो रहे हैं।" जैसा कि पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक काटेदार शेरों के मार्ग को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुस्ठारे के द्वार पर सलाबी ले ली गई, सब बर्तन डग घरे के एक छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली।'

एक स्त्री घायल कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुझुपों की थी। एक के बरीर पर घोंडे की टाप के निशान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया तो वे बरी कर दिये गये। कुछ दर्शकों को परेशान किया गया। अक्सरों में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकाजनी और लूट-मार के अभियोग लगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेंट मि० मैकफरसन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तसदीक की —

"बहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोटें आ गई हो। जल्दों ने पुलिस का मुकाबला कभी नहीं किया और वे बराबर अहिंसात्मक आचरण करते रहे। सम्भव है, कुछ घायल वेहोश भी हो गये हो। चोटों के १५३ केस नजर से गुजरे जिनमें से २६६ ऊपर के भाग में थे, ३०० बरीर के आगे के भाग में, ७६ सिर पर, ६० फोतो पर, १६ गुदा-द्वार पर, ७ दातों पर, १५८ रगड़ के घाव, ८ बन्द चोटों के, २ छिल जाने के, ४० पेक्षाव-सम्बन्धी शिकायतें, ६ सिर फटने के, और २ हड्डियों के जोड़ टूटने के थे।"

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारियां हुईं। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ४

वाद को फरवरी में ५०० आदमियों का सहीदी जत्था भेजा गया। डा० किचलू और आचार्य गिडवानी इस जत्थे के साथ दर्शक की हँसियत से गये। जैतो के निकट इस जत्थे पर गोली चलाई गई और कुछ आदमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनों को नामा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों की सुश्रूषा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नामा जेल ही में रहे। सहीदी जत्थे बराबर जाते रहे और गिरफ्तारिया भी होती रही। इस प्रकार अकाली हजारों की सख्या में जेल में पहुँच गये। उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी खराब रिपोर्टें आईं। अकाली-सहायक ब्यूरो में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिकर ने लिया। कांग्रेस की कार्य-समिति ने जेल में अकालियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की जाच के लिए जाच-कमिटी भेजी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी। बाद को जब गुरुद्वारों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह प्रबन्ध भी तय हो गया।

: ५ :

कांग्रेस चौराहे पर-१९२४

गांधीजी की बीमारी

जब १९२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैली हुई थी। गांधीजी की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बातों को ढक दिया था।

१२ जनवरी १९२४ को महात्मा गांधी के 'अपेंडिसाइटिस' रोग से भयकर रूप में बीमार पड़ने और आधी रात में कर्नल मंडोंकहारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गई। पर गांधीजी के स्वस्थ होने लगने और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय से पहले ही बिना किसी शर्त के छोड़ दिने जाने से वह चिन्ता दूर हो गई।

पर जेल से छूट कर भी उन्हें न शान्ति मिली न विश्रान्ति। कोकनडा-कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर अपरिवर्तनवादी आशा कर रहे थे कि गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का हजम फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर सौट पड़ेगा। दूसरी ओर परिवर्तनवाधियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों को पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ बन्ना बाकी रह गया है उसे बो लिया जाय। देश के परस्पर-विरुद्ध दृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड़ चेष्टा की गई। गांधीजी ने बम्बई के निकट जुहू नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया। महा पर गांधीजी, दास बाबू और नेहरुजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे लोगों को आशा होती रही कि समझौता हो जायगा। १९२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री दास और नेहरु ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया।

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्तव्यों को देने से पहले यहाँ यह चताना ठीक होगा कि कौंसिलों में स्वराज्य-मार्गी ने क्या किया और कौंसिलों में भीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया।

स्वराज्य पार्टी ने क्या किया

स्वराज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कांसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया गया। बड़ी कांसिल में ४५ स्वराजी पहुँचे जिनमें खूब अनुशासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने का व्रत लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके कांसिल में आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके। पहली विजय तब हुई जब श्री टी० रंगाचारी ने शासन-व्यवस्था में तत्काल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह सशोधन पेश किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज-मरिपव् दुलाई जाय।

सरकार को यो तो कई बार हार खानी पड़ी, परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी हार विशेष-रूप से उल्लेख-योग्य है—कुछ राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव, १८१८ के रेग्युलेशन ३ को रद्द करने का प्रस्ताव, दक्षिण-अफ्रीका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव, और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जाच करने के लिए एक कमिटी बैठाने का प्रस्ताव। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी। जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था। हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य-पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि “हमारी भाग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दमनकारी-कानूनों को रद्द करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाने की अस्तित्व नेतावनी का रूप धारण करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करे।”

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि ‘सरकारी भागों’ की चार मवों को नामजूर कर दिया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो भानो रसद बन्द करना हुआ पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि “मिरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वन-कारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव तो देशवासियों की भिकायतो की ओर ध्यान आकर्षित करने का विलकूल वैध और वाजिव उपाय है।”

१९२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए हम अब गांधीजी, दास बानू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हैं जो शुरू के वार्तालाप के बाद प्रकाशित किये गये।

गांधीजी का वक्तव्य

“अपने स्वराजी मित्रों के साथ कांग्रेसवादियों के द्वारा कॉमिल-प्रवेध के जटिन प्रश्न पर बातचीत करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनमें महान

न हो सका। X X X देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। X X X परन्तु चेष्टा करने और इच्छा रहने पर भी मैं उनके तर्क को न समझ सका। मेरी अब भी यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार कौंसिल-प्रवेश असंगत है। हमारा मतभेद 'असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक ही सीमित हो सो बात भी नहीं है, यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से सबब रखता है, जिसके कारण महत्त्वपूर्ण समस्याओं के सुलझाने में मतभेद अनिवार्य हो जाता है। उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही बहिष्कार-अर्थ की सफलता या विफलता को जानना होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नहीं। मैं इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि देश के लिए कौंसिलों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होगा। परन्तु मैं अपने स्वराजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि मैं यह समझता हूँ कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्संदेह कौंसिल में है। हम सबके लिए यही अच्छा भी है।

"दिल्ली और कोकनडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा होने पर कौंसिलों और असेम्बली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकी हो। इसलिए मेरी राय में स्वराजी कौंसिलों में जाने का और अपरिवर्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आज्ञा रखने का अधिकार रखते हैं। उनको बहा जाकर अङ्गान-नीति धारण करने का भी हक है, क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और कांग्रेस ने उनके कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि स्वराजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे सशयशील व्यक्तियों को अपनी भूल अवश्य मालूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो मैं जानता हूँ कि वे देशभक्त हैं और अवश्य अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए मैं उनके मार्ग में बाधा डालने के काम में शारीक न होऊँगा और न स्वराजियों के कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग लूँगा। हा, मैं ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं है।

"कौंसिलों में क्या ढग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौंसिलों में तभी घुसूँगा जब शुद्ध मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकूँगा। अतएव यदि मैं कौंसिलों में जाऊँगा तो मैं सोलह आने अङ्गान-नीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा।

में उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहूँगा कि —

(१) वे सारे कपड़े हाथ के कत्ते और हाथ के बुने खदर के खरीदें।

(२) विदेशी कपड़ों पर ब्रह्म भारी चुगी लगा दें।

(३) सराव आदि की आय को ही रद्द कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दें।

“यदि सरकार काँग्रेसों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इन्कार कर दे, तो मैं सरकार से काँग्रेसों को भग करने के लिए कहूँगा और उन्हीं खास-खास बातों पर फिर निर्वाचकों के वोट हासिल करूँगा। यदि सरकार काँग्रेस भग करने से इन्कार कर दे तो मैं अपनी जगह से इस्तीफा दे दूँगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करूँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्वराजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी कसौटी बड़ी पुरानी है।”

स्वराज्य-वक्तव्य

बेणगणु चित्तरजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा —

“हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को काँग्रेस-अवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सके। हमारी समझ में यह नहीं आता कि काँग्रेस-अवेश नागपुर के कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जबकि हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा बदलते रहनेवाले रग-ढग पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय-जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में बाधा डालनेवाली नौकरशाही को सामना किया जा सके, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है।”

“हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में ‘अडगा’ शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लमेण्ट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। भातहत और सीमित अधिकारवाली काँग्रेसों में उस अर्थ में अडगा डालना

असम्भव है, क्योंकि सुधार-कानून के अंतर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने-चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अठगा बालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकाबला करने का अधिक है। 'अठगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकाबले से है। हमने स्वराज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।

"अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना मावी कार्यक्रम, जिसे हम कौंसिलों में और कौंसिलों से बाहर पूरा करेंगे, बयान करते हैं।

"कौंसिलों के भीतर हमें निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए —

१—बजट रद्द करना—जबतक हमारे अधिकारों की मान्यता के रूप में वर्तमान सरकार के विधान में परिवर्तन न कर दिया जाय, या जबतक पार्लमेण्ट और इस देश की जनता के बीच में समझौता न हो जाय, तबतक बजट रद्द करते रहना।

२—कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद्द करना—कानून बनाने के सम्बन्ध में सारे प्रस्तावों को, जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती है, रद्द करना।

३—रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव, योजनाएँ और बिल हमारे राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलतः नौकरशाही को जड़ उखाड़ने के लिए आवश्यक हों उन सबको पेश करना।

४—आर्थिक नीति—एक ऐसी निश्चित आर्थिक नीति का अवलम्बन करना जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई हो और जिसका उद्देश्य भारत में बाहर जाते हुए धन-प्रवाह को रोकना हो। इसके लिए धन-व्ययण करनेवाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है।

"इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों। हमें ऐसी सारी प्राप्ति जगहों पर तो कब्जा करना ही चाहिए, माय ही हमें हर एक कमिटी में भी जहाँ तक सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें निमग्न देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय मीटिंग-मीटिंग कर डालें।

"कौंसिलों के बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए—गठनी या

तो यह है कि हमें महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस की सत्याग्रियों के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है कि कौंसिलों के बाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के बिना कौंसिलों के भीतर हमारे काम का बल बहुत कम हो जायगा। क्योंकि हमें जिस बल की जरूरत है वह कौंसिलों के भीतर नहीं, बाहर तलाश करना होगा, और उस बल के बिना हमारी कौंसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कौंसिलों के भीतर और बाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल को, जिसपर हम निर्भर करते हैं, मजबूती आये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह-सम्बन्धी सलाह को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की स्वार्थ-पूर्ण हठबर्मी का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल कौंसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तब हम बिना किसी हीला-मुवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की सत्याग्रियों के द्वारा उनके झण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें। . . . ”

अहमदाबाद में महासमिति

अहमदाबाद में २७, २८ और २९ जून को जो निश्चय किया गया, जुहू के वार्तालाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस-सत्याग्रियों के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा और कता हुआ सूत भेजना छाजिमी कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर बर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानेवाली बात के विरुद्ध रोप प्रकट करने के लिए बैठक से उठकर चले गये। यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्मानेवाली बात हटा ली और महासमिति ने नाया करनेवालों के खिलाफ जाय्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की।

विदेशी कपड़े, अदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कौंसिलों के पक्षों प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) वहिष्कार पर जोर दिया

गया और कांग्रेस के मत-दाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को कांग्रेस की मातहत-संस्थाओं में न चुना जाय जो पाचो प्रकार के बहिष्कार के सिद्धान्त में विश्वास न रखते हो और स्वयं भी उसपर अमल न करते हो। सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्दा की गई और एण्डरूज सा० से अनुरोध किया गया कि वह आसामवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जाच करें। सिक्खों ने जैतों के अनावश्यक और निर्दयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शान्तिपूर्ण साहस दिखाया था उसके लिए उन्हें वधाई दी गई।

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आर्नेस्ट डे की हत्या के बहिष्कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की बात को, जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथ-भ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में बहिष्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की कि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध हैं, स्वराज्य के मार्ग में रुकावट डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में बाधक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर मूव बान्पुड हुआ। यह बात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबन्धु को पसन्द न आया। इसलिए नहीं कि वह अहिंसा के कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न-भिन्न अर्थों के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गांधीजी को यह देखकर बड़ा ही सन्ताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ और अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने इन प्रश्नों के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आसो में बानू जा गये। ऐसे अवसर उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं। बाताकाश में तीव्रता इसलिए और भी उत्पन्न हो गई थी कि दीनाजपुर (बंगाल) की प्रांतीय-परिषद् में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देश-भक्ति के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था।

स्वराजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर गये और उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए मजबूर तक रुकना पड़ा। जहाजक अपरिवर्तनवादियों का सम्बन्ध था, मूनवाली डन की उन्होंने आश्चर्यजनक रीति में पूरा लिया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्टूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये।

साम्प्रदायिक दंगे और गांधीजी का उपवास

परन्तु उस वर्ष की सबसे दूरी बात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों का होना, खासकर दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, साहजहापुर, इलाहाबाद और जबलपुर में। सबसे अधिक भयकर दंगा कोहाट में हुआ। कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर ही तोड़ दी। दंगों के कारणों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गांधीजी और मौ० शोकतबली की एक कमिटी नियुक्त की गई। दोनों ने रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद था कि दंगों की जिम्मेदारी किसपर है। १९२४ की ६ और १० सितम्बर की घटनाओं को बीते आज दस वर्ष से भी अधिक हुए, पर दंगों के फौरन बाद ही कोहाट के मातृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दंगा-पीड़ित-सहायक-समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमांच हो जाता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ६ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कल्ले-आम के बाद एक स्पेणल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने बाद तक राबलपिण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे।

ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जो गांधीजी ने २१ दिन के उपवास का व्रत लिया। इस क्रोधोन्माद और हत्या-अवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपने-आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया। अभी अपेण्डिसाइटिस के भयकर और लगभग साक्षातिक प्रकोप से उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गांधीजी ने व्रत गीलाना मुहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान में ले जाया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र किया गया। कलकत्ते के बड़े पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-परिपद् २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन् १९२४ तक होती रही। परिपद् के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण को निन्दा करने में कोई कसर न रखेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनाई गई, जिसके सयोजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए और हकीम अब्दुल्ला, लाला लाजपत राय, के० एफ० नरीमान, डॉ० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्दरसिंह सदस्य हुए। परिपद् ने धार्मिक सिद्धान्तों को मानने, धार्मिक विचारों को प्रकट करने और

धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने, घर्मस्थानों की पवित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध में सबका एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादों का भी निदर्शन किया। अखबारों को चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझवूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गांधीजी के उपवास के अन्तिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाय। ८ अक्तूबर जन-सभाओं द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया।

अभी गांधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ और २२ नवम्बर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके बाद ही और उसीके सिलसिले में २३, २४ को महासमिति की बैठक में जारी होना पड़ा। सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यह था कि बंगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेस्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिपद ने बंगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल-छॉ-अमेण्डमेण्ट-बिलिनेन्स के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेस्युलेशन ३ को रद्द करने पर जोर दिया। सर्व-दल-सम्मेलन ने बंगाल की अस्थान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्व स्वराज्य की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रखा गया। ३१ मार्च १९२५ तय रिपोर्टें मांगी गईं। परिपद के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे सम्भवतः देशबन्धु चित्तरजन दास की गिरफ्तारी टल गई। उस वर्ष की मूल्य घटना थी गांधीजी का देशबन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना। इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य का साराण यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित किया जाता है। हा, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेगी। यह भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक कार्य करें, और स्वराज्य-पार्टी कौंसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कांग्रेस-सदस्यों के द्वारा ११ साल के बजाय २००० गज हाथ बांधना मृत प्रति नाश दिया जाय।

बेलगांव-कांग्रेस

असहयोग के इतिहास में बेलगांव-कांग्रेस खास महत्त्व रखती है। गांधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीब-करीब अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका था। कांग्रेस अब ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहाँ से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस-वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में बंट जाना चाहिए या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो तो इस जटिल काम को गांधीजी के सिवा और कौन हाथ में ले ? केवल गांधीजी ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को शान्त कर सकते थे और कौंसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुष्ट रख सकते थे। १९२४ की कांग्रेस के सभापति गांधीजी हुए। उन्होंने अपना अद्भुत भाषण पेश किया। पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया गया। इस भाषण में उन्होंने १९२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी सस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सब तरह के बहिष्कारों को निम्न-निम्न दलों ने अपनाया। बैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन सस्थाओं का बहिष्कार किया गया उनका रोव बहुत-कुछ कम हो गया। सबसे बड़ा बहिष्कार—हिंसा का बहिष्कार था। पर अहिंसा ने असह्यायस्यता की निष्क्रियता को छोड़कर अभी साधन-सम्पन्न और परिष्कृत-रूप धारण नहीं किया था। जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर अहिंसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दबाये रक्खा। पर 'ठहरो' कहने का भी समय आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चात्ताप भी करने लगे। फलतः सब प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार—विदेशी कपड़ों का—रह गया। इस प्रकार बहिष्कार करने का अनता का न केवल अधिकार ही था, वस्तुि कर्त्तव्य भी था। उनके और स्वराजियों के मत-भेदों में समझौता हो गया था। स्वराजी झूत कात कर देने को राजी हो गये और गांधीजी ने उनके कौंसिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दंगे पर सताप प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते। चरखा, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण ये साधन हैं। 'मेरे लिए तो साधनों का जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्यायवाची

शब्द है।" इस प्रकार भूमिका बाने के बाद गांधीजी ने स्वराज्य की योजना में सम्बन्ध में कुछ बातें बताईं।

मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्त, सैनिक व्यय में कमी, सत्तान्याय, भावक द्रव्य और उससे बानेवाली चुगी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रान्तों का भाषा की दृष्टि से पुनर्निर्माण, इस देश में विदेशियों के हजारों (मोनोपली) की नये सिरों से बाध-पड्डाल, भारतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की शारङ्गी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खलक न पहुँचने का आशवासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न सत्ताओं को धार्मिक स्वतन्त्रता, देशी-भाषाओं-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय-भाषा मानना।

पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ। अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे, क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहातक सरकार के रग-डग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था। उन्होंने कहा "मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूँगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के बोप से ही उससे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूँगा। इसके बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र किया और बंगाल की अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके आपण समाप्त किया। बंगाल में लॉर्ड रीडिंग ने १९२४ का आर्डिनेंस न० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगों को जिनपर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रांतिकारी-दल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल कमिशनरों की अदालतों में उनके मामले का सरतरी में फैसला किया जा सकता था। गांधीजी ने इस बात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा है।

कांग्रेस ने बी अम्मा, सर ए० चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, डॉ० सुब्रह्मण्य ऐयर, ए० जी० एम० भुरगी और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर शोक-अकाश किया। नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही लिया गया। कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया। हिन्दुओं के कोहोट-स्थापन पर खेद प्रकट किया गया। कोहोट के मुसलमानों को मलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके

आन-माल के सम्बन्ध में आस्वासन दें, साथ ही हिन्दू मुहाजरीन को सलाह दी गई कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावें तबतक वे वापस न जायें। इसी तरह गुलबर्गा के पीडितों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। अस्पृश्यता और वायकोम-सत्पाग्रह के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की गई। वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया। अकालीदल मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलिया की गई।

प्रवासी-भारतवासियों के लिए श्री वझे, प० बनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओं की सराहना की गई। सरकार भी चुपचाप नहीं बैठी थी। वह भी केनिया के मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने "भारत-मन्त्री को चेतावनी दी कि यदि निश्चय केनिया-प्रवासियों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक् होने और उपनिवेशों के विरुद्ध बल्ले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा।" अगस्त १९२४ में उपनिवेश-मन्त्री मि० थामस ने निश्चय किया कि दूसरे देशों से आकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स बनाया गया था वह अमल में न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलैण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निश्चय है वही कायम रहेगा। यह भी निश्चय किया कि जो भारतवासी दक्षिण-अफ्रीका में आकर बसना चाहें वे निचली भूमि पर आकर बस सकते हैं और उसपर खेती कर सकते हैं। १९२४ के जून में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चैयरमैन लॉर्ड साउथवरो थे। इसके सामने भारतीय दुष्टिकोण रक्खा जा सकता था। इसी बीच दक्षिण-अफ्रीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया-विल' अपने-आप ही रद्द हो गया। साथ ही 'मेटाल वरोंज आर्डिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे।

हिस्सा या साम्ना ?-१९२५

स्वराजियों को सफलता

१९२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही। अब स्वराजियों को अपरिवर्तन-वादियों की तरफ से परेशानी न रही। क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर रखने को मजबूर थे ही। मध्यप्रदेश और बंगाल में द्वेषशासन का अन्त हो गया था। लॉर्ड लिटन के निमन्त्रण पर देशबन्धु पास ने बंगाल में मन्त्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और व हुसरो को ही बनाने दिया। वह इसी प्रकार के विध्वंस की बात सोचते आ रहे थे। जब लॉर्ड रीडिंग का १९२४ का न० १ आर्डिनेन्स समाप्त हुआ तो बंगाल-कौंसिल में एक बिल पेश किया गया जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के प्रभाव ने १९२५ की जनवरी में रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन ने उसे सही कर दिया और लन्दन सम्राट्-सरकार की मजूरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके बजट में सवियों के वेतन की गुनाहग रखने की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पड़ा। पर उन्होंने भीषण ही इस शक्ति को पूरा कर लिया। २३ मार्च को बजट पर बहस के दौरान में सवियों के वेतन ६६ रायों से रद्द कर दिये गये। पक्ष में ६३ रायें थीं। इससे बंगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मन्त्रित्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे वह भीतर से विध्वंस कर सके? बड़ी कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी १९२४ और १९२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने मिलेजट कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कमी किनी पार्टी का साथ दिया, कमी किसी का, और यदा-कदा सरकार का भी।

जब श्री सी० बोरस्सामी आयर ने बंगाल-आर्डिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ३८ और विरुद्ध में ४५ गये आर्ड। १९२५ की ३ फरवरी को श्री विट्टलभाई पटेल ने १८४० का शाही कंडियो का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १९२१ का राजद्रोही

समावन्दी कानून रद करने के लिए बिल पेश किया तो सीमान्तवाले कानून के सिवा बाकी हिस्सा पास हो गया।

श्रीयुक्त नियोगी ने अपना बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का मशौघन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना चाहते थे। यह बिल नामजूर हुआ। डॉ० ग्रीड ने बिल पेश किया कि लन्दन की प्रिवी काउंसिल में अपीलें न भेजी जाय करें, पर वह रद हो गया और स्वराजियो ने उसमें सरकार का साथ दिया। बैकटपति राजू का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विद्यालय कायम किया जाय, पास हो गया और सरकार को हार खानी पड़ी। २५ फरवरी १९२५ को रेलवे-बजट की बहस में स्वराजियो और स्वतन्त्र-दलवालों ने सरकारी सदस्यों का मुकाबला करने के बजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलतः पण्डित भोतीलाल का बजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायों से रद हो गया। पक्ष में केवल ४१ रायें आईं। इस प्रकार बजट और उसकी मदों पर उनके गुण-बोधों के अनुसार ही विचार किया गया। आरम्भ में लगातार और एकसा अडगा डालने का जो संकल्प किया गया था, उससे कहीं काम न लिया गया। पण्डित भोतीलाल का कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-सर्व वटाने का प्रस्ताव ६५ ४८ से पास हो गया। कोह्लट का दगा, सेना में भारतीयों का अभाव, मुहीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज-परिपद्, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके अनुसार बगाल-क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामलों की अपील हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बड़ी विचित्र अवस्था हुई। बिल में तीन अन्य धारयाँ ऐसी थी जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हुक्मनामे को रद किया और अभियुक्तों को बगाल से बाहर नजरबन्द रक्खा जा सकता था। स्वतन्त्र-दलवाले और स्वराजी बिल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और बाकी तीन विभागों को रद करना। सरकार की दृष्टि से बिल इस प्रकार बिलकूल अधूरा रह जाता। फलतः जब उसे राज्य-परिपद् में पास कर दिया तो लॉर्ड रीडिंग ने उसपर सही कर दी।

इस समय तक देशबन्धु दास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त वेल्हाव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशबन्धु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है, जिसका उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस बात से देशबन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये। इधर डॉ० बेसेण्ट के नेशनल कन्वेंशन ने 'कामनवेल्थ आफ

इण्डिया विल' का भविष्य भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिषद् ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह अलग भाषा-मन्त्री कर रही थी। लाला लाजपत राय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २५ फरवरी को एक प्रश्नावली प्रकाशित की। गत नवम्बर में बम्बई में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति कोई अच्छी स्वराज्य-योजना तैयार न कर सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चित समय के लिए स्थगित हो गई। १९२५ के मार्च और अप्रैल में गांधीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया। वायकोम-सत्याग्रह जोरों पर था। गांधीजी की उपस्थिति ने समझौता होने में मदद की। कुछ सास सड़कों पर से होकर अस्पृश्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कड़ाई को दूर करने के लिए आरम्भ किया गया था। वायकोम-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ बाड़े बना दिये थे और सिपाही तैनात कर दिये थे। वायकोम-सरकार को यह बात सुझाई गई कि उसके इस रवैये से वह जनता में यह धारणा उत्पन्न कर देगी कि वह वायकोम के हिन्दुओं की सकीर्णता का अपने शारीरिक-बल-द्वारा समर्थन कर रही हैं। जब सरकार ने बाड़े और सिपाही हटा लिये तो सत्याग्रहियों का शत्रु केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया।

दक्षिण से गांधीजी बगाल जानेवाले थे। दास बाबू अस्वस्थ होने लगे थे। उन्हें शाम को ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया गया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे। यह 'सफलता' की मनोवृत्ति उन सारे कार्य-कर्त्ताओं में मिलती है जिन्होंने बड़े-बड़े आन्दोलनों का संगठन किया है।

देशबन्धु की मृत्यु और उसके बाद

फरीदपुर की बगाल-आन्तीय परिषद् के अवसर पर यही स्थिति थी। देश-बन्धु ने फरीदपुर में कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही तो इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर। गांधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है, वह बिलाई नहीं पड़ता। पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन हो गया है। उन्होंने 'स्टेड्समैन' के प्रतिनिधि से कहा—“मेरे हृदय-परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेरु-जोल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। ससार सचर्य से एक पया है और उसमें मुझे सर्जन और संगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।” दास बाबू ने ब्रिटिश-

राजनीतिज्ञों को सवोधन करते हुए कहा—“आज आप ऐसी भान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-अद हो।” इन दिनों गांधीजी ने दास बाबू को अपना ‘एटर्नी’ कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौंसिलो में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे। उनकी अपने-आपको मुला देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर धैर्य भग करनेवाली अवश्य सिद्ध होती थी।

इस अवसर पर लॉर्ड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैण्ड में थे। लॉर्ड वर्कनहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विध्वंस के बजाय सहयोग करें। इन दोनों बातों ने मिलकर दास बाबू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा कर्नल बेजवुड और मि० रेमजे मैकडानल्ड भारत में समझौता कराने की चेष्टा कर रहे थे। गांधीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दास बाबू को लॉर्ड वर्कनहेड में बड़ी आस्था थी और उन्हें विश्वास था कि वर्कनहेड भारत के लिए बहुत-कुछ करेंगे।

देशबन्धु दास ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे पण्डितजी देशबन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा—“हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक बड़ी आ रही है। इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तियां काम में लग जायेंगी। इधर हम दोनों बीमार पड़े हैं। ईश्वर ही जाने, क्या होनेवाला है।” इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशबन्धु को स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १९२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास बाबू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद होकर कहा था—“उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसू बहाना बड़ा आसान है। परन्तु आसूओं से हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, मकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशबन्धु जिये और जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशमान् है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। जिस शरीर में देशबन्धु दास की आत्मा का निवास था वह नष्ट हो गया। पर उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यो, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है और इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा

या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर बनाने में सहायक होगा। हम सबमें उनके जैसी बुद्धि नहीं है, पर वह जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।" यहाँ जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए—“श्री दास में अपने प्रतिद्वन्द्वी की दुर्बलताओं को अच्छे खोज निकालने की जन्म-जात शक्ति थी। वह अपनी योजनाओं को पूरा करने में चौह-सकल्प से काम लेते थे, जिसके कारण उनका स्थान अपने योग्य-से-योग्य साथियों से कहीं ऊँचा रहता था।” महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनके प्रति जिन असह्य लोगों ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरॉपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिनने सन्देशों से जेजे उनमें भारत-भगिनी और बाइसराय भी थे। जब कौंसिल की बैठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर बयोबुद्ध देश-भक्त सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की शक्ति का उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया।

गांधीजी देशबन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह बंगाल ही में एक गये और उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक बनाया। उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया। देशबन्धु दास का जन्म १४८ रसा-रोह देश के अर्पण हुआ। इस भवन को दास बाबू की उस दृष्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होंने बेलगाव-कांग्रेस से पहले प्रकट की थी, स्त्रियों और बच्चों का अस्पताल बना दिया गया। गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंगाल में स्वराज्यपार्टी की जरू मजबूत बनाने में कोई कसर न उठा रखी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कौंसिल में स्वराज्य पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सभापति बनाने का काम उन्हींका था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू प्राण्य किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया।

गांधीजी इस्तीफे के लिए तैयार

इसपर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की अरसक चेष्टा कर रहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। स्वराज्य-पार्टी की जनरल कौंसिल का विरोध सूत देने की उम शर्त के खिलाफ हुआ था, जो बेलगाव में तय हो चुकी थी। वह विरोध बढ़ता ही गया, और जन्म में डम पन का उठा देने का फैसला महासमिति के हाथ में गौप दिया गया। महानमिति न

स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की बैठक के बाद सम्भवतः गांधीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूंकि कांग्रेस में स्वराजियों की बहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए। गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वराजियों में हलचल मच गई। पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गांधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्त उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा दे देंगे और एक अलग चर्खा-सच स्थापित करेंगे। कार्य-समिति ने सूत कातने की शर्त में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रश्न पर द्वारा विचार करने के लिए १ अक्टूबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस बीच में गांधीजी ने स्वराज्य-पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रखा। अगस्त में गांधीजी ने लिखा था—“मुझे कांग्रेस के मार्ग में और अधिक खड़ा न होना चाहिए। कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने-आपको अपढ जनता में मिला दिया है और जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर है, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में मैं बाधक बनना नहीं चाहता। मैं अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हूँ, परन्तु कांग्रेस को छोड़कर नहीं। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं रास्ते में से हट जाऊँ और कांग्रेस की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में लगा दूँ। मैं कांग्रेस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूँगा जिस हद तक शिक्षित भारतीय मुझे अनुमति देंगे।” असली बात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी लोग गांधीजी के सिद्धान्तों का अङ्गन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे।

स्वराजी प्रस्ताव

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १९२५-२६ के शिमला-अधि-वेशन से कुछ पहले ही भारतीय सैण्डहर्स्ट कमिटी में स्थान ग्रहण किया था। कमिटी का काम यह देखना था कि सम्राट् की सेना में अफसरों के पद के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हो, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत

में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं और यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लैण्ड भेजा जाय।

१९२४ में मुडीमैन-कमिटी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुई कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधार कैसे चल रहे हैं। इस कमिटी की दो रिपोर्टें थी—बहु-संख्यक और अल्प-संख्यक। बहुसंख्यक-रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों भी मानने को तैयार न थी। १९२४ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकार की रिपोर्ट को सिद्धान्त-रूप में मान लेना चाहिए। और वह सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहाँ-जहाँ आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके कल-मुर्जों में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे मशीनों को नियुक्त करना आसान हो, उनके चेतनों पर बजटों की बहस में रायें न ली जायें और वे अड़सा डालने पर भी सरकारी काम करते रहें। माण्टे-फोर्ड सुधारों में हो इस प्रकार की घटनाओं को सुधूरबर्ती सम्भावना मात्र समझा गया था पर जब तो वे कल ही की प्रत्यक्ष घटनाएँ हो चुकी हैं। स्वराज्य-पार्टी ने बड़ी कौंसिल में घुसने के कूट ही दिनों बाद पता लगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधार-योजना में क्या-क्या बातें पीछे हटानेवाली हैं। उसने १९२४ की फरवरी में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था —

“यह बड़ी कौंसिल स-कौंसिल गवर्नर-जनरल ने सिफारिश करली है कि भारत-सरकार-विधान में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई परे कि देश में पूर्ण उत्तरादायी शासन कायम हो जाय, और इस उद्देश्य में (१) और ही एक गोलमेज-परिषद् बुलाये जो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासन-विधान की सिफारिश करें, और (२) बड़ी कौंसिल को मग करने नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के लिए उसके आगे वह योजना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लियामेंट के पास भेज दे।”

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमैन-कमिटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्प-संख्यक और बहु-संख्यक दो रिपोर्टें पेश की थी। इन रिपोर्टों पर ७ मिनम्बर १९२५ को सर अलेक्जेंडर मुडीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक सम्भाव्य-मोटा मसौदा पेश किया था, जिसका सारांश यह था कि (१) मसौदा की सगंवार को पार्लियामेंट में मन्जूर हो

यह घोषणा करने का प्रबन्ध करना चाहिए कि भारत की शासन-व्यवस्था और शासन-प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायगी, (२) एक गोलमेज-परिषद् या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाय जिसमें भारतीय, यूरोपियन और अफगोरो के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे। यह बैठक अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी कौंसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे। स्वीकृति के बाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लियामेंट के पास भेजा जाय। यह संशोधन दो दिनों के बाद-विवाद के बाद सरकार के खिलाफ ४४ रायों के मुकाबले ७२ रायों से पास हो गया।

बंगाल में जहाँ स्वराजी-दल ने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव-सा कर दिया था वहाँ अब उसका प्रभाव कौंसिल में कम होता जा रहा था। कौंसिल के अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतंत्र-दलवाले के मुकाबले पर ६ रायों से हार गया। अन्तिम जोर-आजमाई के अवसर पर भी, जब दास बाबू को स्ट्रेचर पर ढालकर कौंसिल-भवन में ले जाया गया था, अवस्था सदिग्ध थी। डॉ॰ सुहरावर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़े आड़े हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने यह बड़ा अनुचित काम किया और इस तरह "अपने देश को बेच दिया।" जब डॉ॰ सुहरावर्दी ने यह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा—“मैं इस नई जो-हुकमी के आगे तिर झुकाने के बजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता हूँ।” डॉ॰ सुहरावर्दी के गवर्नर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते के अफगोरे पत्र को अपने रुख के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया और कहा —

“मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना पार्टी की अनुमति लिए सरकारी अफसरो से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम हैं वह अच्छा हैं।”

२२ अगस्त को श्री विठ्ठलभाई पटेल वही कौंसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने गये।

पटना-महासमिति

इस समय २१ सितम्बर १९२५ को पटना में महासमिति की बैठक हुई। जब हम स्मरण करते हैं कि पटने की १९३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया

गया था तो हमें यह बैठक विशेष रूप से दिलचस्प ग्राह्य होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। खट्टर का राजनैतिक महत्त्व छिन गया। हाथ-कटा सूत देने की शर्त केवल चार आना न देने की हालत में ही लागू रही। राजनैतिक काम का गार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अंग-यात्र—यह अत्यन्त जिसे रियायतें मिलें या वह थोड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के लिए औरों का मुँह ठाकना पड़े—न रही। वह स्वयं कांग्रेस ही गई। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी। कौंसिल-प्रवेश में विश्वास रखनेवाले बड़ी कौंसिल के सदस्य अब “स्वराजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, बल्कि कौंसिलो में कांग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत कातने की शर्त अब एकमात्र शर्त नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शर्त को माननेवाले कम थे।—१०,००० सदस्य मौजूद थे—परन्तु यह था कि स्वराजियों को यह शर्त पसन्द न थी। गांधीजीने छोड़ें वर्कनहेड और छोड़ें रीटिंग को करारा उत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे बाला। अब गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीराजगज के प्रस्ताव को लेकर दास बाबू की स्थिति और स्वतन्त्रता खतरे में पड़ी, और जगल-आडिनेन्स एक्ट बना, तो गांधीजी ने दास बाबू का साथ देने का निश्चय किया। बर्ष बीत गया पर वर्कनहेड की खेती मौजूद थी। गांधीजी ने बचा-बुचा असहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कौंसिलो के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके। उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया।

उस समय गांधीजी की जैसी मनोदशा थी उसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए कोई चीज सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती। गांधीजी ने महासमिति के अध्यक्ष की हँसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कौंसिल में किये गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सौहार्द-पूर्ण वातावरण में खलल पड़ता और उदारासयता की कोमा और मृत्यु बहुत-कूट कम हो जाता। जब राजेन्द्र बाबू ने गांधीजी से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरूजी के साथ कोई पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं, परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि इसग पक्ष जो कुछ मुझसे मागे, मैं दे दूँ।”

पटना की बैठक के अवसर पर और उसके बाद प्रश्न यह था कि पटना के निश्चय के द्वारा कांग्रेस की दोनों पार्टियों में साम्ना तय हुआ था या हिस्सा? कांग्रेस में

परिवर्तन बड़ी तेजी से एक-के-बाद-एक होते गये। हर बार कोई नया दृश्य, नया रंग और नई बात दिखाई देती थी। जून में कोई बात निश्चित न हो सकी। जब १९२४ के जून में अहमदाबाद में बैठक हुई तो गांधीजी अब भी अपनी स्थिति के मूल सिद्धान्तों पर अड़े हुए थे। उन्होंने सहर-सम्बन्धी कड़ाई को और भी कड़ा कर दिया और कार्य-समिति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया। सीराजगंज के प्रस्ताव के अमर नौफरवाही ने दास बाबू का अनुकरण करनेवालों को धमकी दी तो गांधीजी कांग्रेस के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तुल गये। एक डच झुकने का परिणाम यह होता है कि सोलह आने झुकना पड़ता है। यहाँ भी यही बात हुई। बेलगाव के निर्णय को पटना में रद्द कर दिया गया। पटना में कांसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और सूत कातने की शर्त को भी उठा दिया। इस प्रकार सहर के समर्थकों और कांसिल के समर्थकों में कांग्रेस का बटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। वास्तव में सहर के समर्थकों में असंतोष फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती थी। स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज-परिषद् या और किसी उपयुक्त साधन की जो मांग पेज की थी वह नाकाफी समझी गई। लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि एटर्नी ने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया है या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया है। पर गांधीजी इस प्रकार के गणित का हिसाब-किताब नहीं लगाते। वह जब कभी झुकते हैं तो पूरे तौर से झुकते हैं, जिससे न उन्हें पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को। भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फलतः पटना में जो कुछ निश्चित हुआ कानपुर में हमें उसपर सही करनी पड़ी।

कानपुर-कांग्रेस

१९२५ की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ लगे थे। जनता ज्यों-की-त्यों थी— उसमें पहले की भांति प्रबल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब "शक्ति" समुदाय उनके पास कोई जीता-जागता आदर्श, कोई फडकता हुआ कार्यक्रम ले जायें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फलतः मसाला भोजन था, पर उसकी 'शक्ति' गायब हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायों से न चलने पर उसे पीछे से ठकलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ठकेले जाने के दो-चार कदम बाद मोटर के इंजन में गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुबारा रोके जाने तक काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियता उस समय के लिए खी हुई थी और उसमें गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था।

स्थानिक सत्याजो पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को देखबन्धु दाम और बाद को श्री सेनगुप्त ने जिस सुन्दरता के साथ सुशोभित किया था, उससे आकर्षण और भी बढ गया था। देन के चार कारपोरेशन कांग्रेसवादियों के हाथ में थे। श्री वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे और १९२८ तक उसी पद पर रहे। बम्बई-कारपोरेशन के मेयर का पद श्री बिठ्ठलभाई पटेल सुशोभित कर रहे थे। प० जहावरलाल इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बनाये गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि वह वहाँ निम न सकेंगे और स्थानिक सत्याम कांग्रेसवादियों के मतलब की चीज नहीं है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद पटना-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्द-दायक न थे, फलतः वह १५ महीने के बाद ही वहाँ से अलग हो गये। मवरस के म्युनिसिपैलिटी में नेता श्री श्रीनिवास मायगर कांग्रेस के भी नेता हो गये—परन्तु सरकार की चक्की के पहिये वैसे धीरे-धीरे पीसते हैं, पर पीसते अचूक हैं। इसलिए थोड़े ही दिनों में सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह असम्भव कर दिया कि वे स्थानिक सत्याजो के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढा सकें। वे जेल हो जानेवालों को नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे, मालाजो में चरखा नहीं चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं को मानपत्र नहीं दे सकते थे और न म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों पर राष्ट्रीय गण्डा फहरा सकते थे।

स्वराज्य-पार्टी में फूट

१९२५ का साल बड़ी हलचल का साल रहा है। अब इनके समय के बार जब हम पुरानी घटनाओं पर निगाह डौडते हैं तो उन समय कांग्रेस के भीतर भिन्न-भिन्न दलों में, और दलों के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों जो में, वधमवध चल रही थी उसी ओर ध्यान गये बिना नहीं रह सकता। जब अपरिवर्तनवादी ही, जिनके ज़िम्मे गहर, अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप में बची-भूची दमोशन जाँट थी, आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवर्तनवादियों का कार्यक्रम तो नन्दा और आन्दोलनकारी समझा जानेवाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मतभेद होना क्यों पागल की बात न थी। स्वराज्य-पार्टी के मिद्वानों के विरुद्ध मन्थप्रान्त और मगान्द न स्रष्टा खड़ा किया। ये प्रान्त बंगाल के योग्य सदस्यों में और जबना देखापु मीर रहे, बंगाल के साथ-साथ चलने रहे। देशबन्धु का न्यमाव तिनो आता की मन्थ

करने का न था, वह उसे कठोरता के साथ कुचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में अनहोनी वार्ते हो गईं। मध्यप्रांतीय कौंसिल के अध्यक्ष श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया। इसपर मध्यप्रान्त और बरार के नेताओं और बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खूब घमासान युद्ध हुआ। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्बे के आचरण पर और श्री केलकर और श्री जयकर जैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी आपत्ति की और इन दोनों के विरुद्ध जान्ता कार्रवाई करने की बमकी दी और कहा कि इन्होंने "अपराध में सहायता की है।" इसपर श्री केलकर और श्री जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के लिए कहा।

१ नवम्बर को नागपुर में अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें श्री श्रीपाद दलवन्त ताम्बे की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विश्वास-घात समझी गई और उनकी निन्दा की गई। फिर पण्डित मोतीलाल नेहरू श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए नागपुर से झटपट बम्बई पहुँचे। इस बीच इन दोनों ने 'प्रतियोगी सहयोग' की आवाज पहले से ही ऊँची कर रखी थी। इन्होंने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही नहीं, इसके बाद डॉ० मुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कौंसिल से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे।

अब हम कानपुर-कांग्रेस पर आते हैं। कानपुर को पटना के निर्णय पर सही करनी थी। पटना में भी यह बात सविध समझी जा रही थी कि बेलगाव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के, मिलिक्यत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है वह महासमिति भी स्वीकार करेगी या नहीं। इसके बाद यह बात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य-पार्टी के मूडीमैन-कमिटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये सञ्चोचन में की गई भाग की पुष्टि करेगी या नहीं। कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी समानेयी भारत की कवयित्री सरोजिनी नायडू थी, इसी प्रकार के जटिल प्रश्न मौजूद थे। इस कांग्रेस की एक अजुबा बात थी पिछले वर्ष के सभापति गांधीजी-द्वारा इस वर्ष की समानेयी श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का भार सौंपा जाना। गांधीजी केवल ५ मिनट बोले। उन्होंने कहा कि "अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद मैं अपनी ऐसी एक भी बात नहीं पाता जिसे रद्द करूँ, मैं अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ जिसे वापस लूँ। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगों में जोश और उत्साह है तो मैं आज मत्प्राप्त

आरम्भ कर दू। पर अफसोस ! हाज़त ऐसी नहीं है।” सरोजिनीदेवी ने गिने-बुने शब्दों के साथ भार ग्रहण किया। उन्होंने सभानेत्री की हँसियत से जो भाषण दिया वह कांग्रेस-भवन से दिया गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय भाग की चर्चा की जो बड़ी कौंसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा—“स्वतंत्रता के युद्ध में भय ही एकमात्र असम्य विश्वास-वात है, और निराशा एकमात्र असम्य पाप।” फलतः उनका भाषण मानो साहस और आशा की प्रतिमूर्ति था। इस सुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिष्णुता के उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कुछ प्रसिद्धियों के उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें काबू करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ी, निर्विघ्न समाप्त हो गया।

कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशबन्धु बाघ, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भाष्यारकर और अन्य नेताओं की भृत्य पर शोक-प्रकाश के साथ आरम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिष्ट-मण्डल आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि ‘एरिया रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल’, अर्थात् भिन्न-भिन्न जातियों के लिए पृथक् स्थान नियत करने और आकर बसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध में पेश किया गया बिल, १९१४ के गांधी-स्मृत्य-समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि १९१४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पचासत बैठकर निपटारा करा किया जाय। कांग्रेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक गोलमेज-परिषद् की बात की पुष्टि की और सम्राट् की सरकार से अनुरोध किया कि यदि बिल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। बंगाल-आदिनेस-एक्ट और गुजरात-आन्दोलन के कथियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। वर्मा के गैर-यर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये जिलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। उसके बाद कांग्रेस का भताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९२१ के पटनावाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो अखिलभारतीय चर्खा-संघ के सुपुर्द कर दिया गया है, बाकी सारे कोष और भशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवश्यक राजनैतिक कार्य में करने को कहा गया था। कांग्रेस ने सत्पात्रह अर्थात् सविनय-अग्र में अपनी आस्था प्रकट की और

इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र पथ-प्रदर्शक समझी जाय। इसके बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनाया —

कार्यक्रम

१—देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार करने की शक्ति हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस उद्देश की पूर्ति के लिए कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय। इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चूल्हों और खदूर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐन्य की वृद्धि करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दलित जातियों का उद्धार करने और नशों की बीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक सस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजदूरो और खेतों का काम करनेवाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूरों और मालिकों, तथा जमींदारों और किसानों में सौहार्द्र स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल रहेगा।

२—देश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थिति का प्रसार करना होगा।

३—यह कांग्रेस देश की ओर से समझौते की उन शर्तों को मंजूर करती है जो बड़ी कौंसिल की इण्डिपेंडेंट और स्वराज्य-पार्टियों ने अपने १८ फरवरी १९२४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रखी थी, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय —

स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कौंसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुक्त करना चाहे, सतोप-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-द्वारा बड़ी कौंसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह वर्तमान कौंसिलों में काम न करेगी। बड़ी कौंसिल और राज्यपरिषद् के स्वराज्य-सदस्य वजट की नामजुरी के लिए वोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोड़कर चले जायेंगे। जिन प्रान्तीय

कौंसिलो की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कौंसिलो में न जायें और वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे।

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्यपरिषद् में हो, चाहे बड़ी कौंसिल में, चाहे छोटी कौंसिलो में—उनकी विनी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमिटी में शरीक न होगा। हा, अपनी जगह से खाली घोषित होने से रोकने और शान्तीय बचटो को नामजूर करने या कोई नया कर लगानेवाले बिल को रद्द करने के लिए कौंसिलो में जाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए विशेष समिति और महासमिति को अधिकार देने की बातों का भी उल्लेख इस लम्बे प्रस्ताव में था।

कानपुर-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव बिना सुनू-मै-मै के पास न हो सगा। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन भी जबरन न किया। उनका संशोधन इस प्रकार था —

“कौंसिलो में काम इस प्रकार जारी रखा जायगा कि उनका उपयोग सीधे ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके, जब राष्ट्रीय दिन की वृद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग किया जायगा, और रक्षाबट टांगने से लोगों को रक्षाबट डाली जायगी।”

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही भी जयवर ने अपने और श्री बंजर ब बों मुने के बड़ी कौंसिल से इस्तीफा देने का विक्र किया। उस वर्ष के दौरान में पण्डित मोतीलालजी पर भारतीय सैण्डहर्स्ट या स्कीन-कमिटी की मददयता स्वीकार करने के लिए भयकर आक्रमण किया गया। उन्होंने कहा—“बड़ी कौंसिल ने नाग्रीय सैण्डहर्स्ट की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, ‘अच्छा मार्ग दियाओ।’ हम लोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिनने द्वारा सरकार हमारी मांगें स्वीकार कर ले, उससे बात-चीत चलाई जाय। यदि इसी द्वारा सरकार हमसे सुधारों का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसी मांग मान्य करेंगे।”

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कार्यवाही के रिक्त हिन्दुत्ववादी भाव अपनाई गई। महासमिति को प्रवासी भारतीयों के रिक्तों की देख-भाल करने के लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक-विभाग घोषित ना अधिकांश किया गया। अन्त में अखिल भारतीय आसाम में करना तय हुआ। डॉ० मुन्शीरामजी अन्तर्गत, डॉ० रंगस्वामी आसाम और श्री के० सन्तानम प्रधानमंत्री नियत हुए। कानपुर-कांग्रेस

के कुछ ही दिनों बाद १९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि० वी० जी० हार्निमैन भारत वापस लौट आये।

कानपुर-कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमें अमरीका के मि० होल्मूस् मीजुद थे। यह वैसे अमरीकन कपड़े पहने थे पर सिर पर गाची-टोपी दिये थे। करतलध्वनि के बीच यह उठे और बोले—“कल मैंने डॉ० अब्दुलरहमान को यह दावा करते हुए सुना कि गाचीजी तो दक्षिण अफ्रीकन हैं। क्या मैं आज यह दावा नहीं कर सकता कि वह सारे ससार के हैं? क्या मैं यह नहीं कह सकता कि ‘मित्र-मण्डल’ (सोसाइटी आफ फ्रेंड्स), जिसकी ओर से मैं बोल रहा हूँ, उन्हें उसी आदर की दृष्टि से देखता हूँ जिससे आप देखते हैं और आपकी ही भांति वह भी उनके काम में विश्वास करता हूँ? मुझे कहना चाहिए कि हम लोग अपनी पाश्चात्य-सभ्यता की धुन में बहुत गलत रास्ते पर चले गये हैं। हम लोग धन और शक्ति की धोज में बहुत आगे बढ़ गये हैं। हमारी सारी पाश्चात्य सभ्यता में यह एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। हम पैसे से प्रेम करते रहे, फलतः वह एक स्थान पर एकत्र हो गया। हम शक्ति के लिए कालाशित रहे, फलतः युद्धो पर युद्ध होते गये और सम्भवतः और भी होंगे और अन्त में हमारी सभ्यता विध्वंस हो जायगी। इसीलिए हम आपकी ओर प्रसन्नता-पूर्वक मुखातिब हुए हैं। आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जहाँ हम प्रकृति और आविष्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये रखेंगे, वहाँ हम उस भावभाव का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान् पैगम्बर ने की है।”

हिन्दू मुस्लिम दंगे

इस वर्ष की समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जिक्र करना है जो बीच-बीच में १९२५ में और १९२६ में भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जिक्र करके हुए १९२५ की पहली मई को गांधीजी ने कलकत्ते के मिर्जापुर-मार्क में कहा था—“मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि ‘अरोग की औपधि’ बतानेवाले वैद्य की विशेषता भुक्तमै नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औपधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उनका आजकल मैंने इस समस्या की ओर ही उठती-सी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर लिया है। मैं यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और

यदि हमारे भाग्य में ही यह वधा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिये उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-भूठ के आसू न बहाने चाहिए, और यदि हम दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी चाहिए।”

१९२५ की जुलाई में सारे गद्दीने-भर दंगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद थे। बकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्नाबाद नामक स्थान पर भी दंगा हो गया। १९२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्खों की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है। १९२५ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पञ्जाब-कौंसिल में मुख्तार-बिल पेश किया गया और पास हो गया, साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि मुख्तार-आन्दोलन के कैदी शर्तनामे पर दस्तखत करके नये कानून को मजूर कर लेंगे और पहले की भांति आन्दोलन न करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बहुतों ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे क्रोध शान्त हो गया। बहुतसे कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-मुख्तार-कमिटी में इस बात को लेकर फूट पड़ गई। अधिकारों की भी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जेलों में ही रहे।

कौंसिल का मोर्चा—१९२६

सहयोग की तरफ

१९२६ का आरम्भ कौंसिलो के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष धुन न रहा। १९२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड़ चुका था। केवल 'मुद्र' की खातिर लगातार 'मुद्र' किये जाना कुछ थकानेवाली बात साबित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही सकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने लगे।

बान्ताव में १९२५ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निश्चयात्मक रूप से मुनाई देने लगी थी। वटी कौंसिल २० जनवरी को खुलनेवाली थी, पर उससे पहले ही बम्बई-कौंसिल की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसहयोगी-दल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर लिया था।

६ और ७ मार्च को महाममिति की बैठक राय सीना (दिल्ली) में हुई, जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एकबार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि "स्वराज्य के मार्ग में रोड़े अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे सकल्प के साथ मुकाबला किया जायगा। और विशेष रूप से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले पदों की स्वीकार न करेंगे जबतक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक उत्तर न मिलेगा।"

महाममिति की चर्चा करते हुए यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि ५ मार्च को कार्य-समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और ५०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मजूर किया था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल स्वयमेवकों का वह दल था जिसका सगठन कोरूनटा-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। इसके दो वापिक अधिवेशन हो चुके थे—एक मौलाना मौकतबली की अध्यक्षता में बेलगाव में और दूसरा थी तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में कानपुर में।

• असेम्बली में वाक-आउट

बड़ी कौंसिल में जब वक्ता की चर्चा बारम्ब हुई तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आह्वित किया कि मैं और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न लेंगे। कौंसिल-भवन की गैलरिया संचालन भरी हुई थी, क्योंकि स्वराजियों के बड़ी कौंसिल से 'वाक-आउट' करने की बात पहले से ही लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्द्य की सम्मानपूर्ण समझौते की बात का किस प्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सचवाणी से काम न लिया तो देशभर में गुप्त-समितियाँ कायम हो जाएँगी। इतना कहकर नेहरू अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कौंसिल-भवन से बाहर चले गये।

इस 'वाक-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका सक्षिप्त वर्णन करना उचित है। अम्बेडकर ने इस 'वाक-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूँकि कौंसिल की सबसे अवर्द्धत पार्टी कौंसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार कानून के अनुसार आवश्यक प्रातिनिधिक रूप इस कौंसिल का नहीं रह जाता है। अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौंसिल की बैठक जारी रहे या नहीं? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादप्रस्त कानून पेश न करें, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा—“मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के बाद मैं इस गतीने पर पहुँचा हूँ कि अम्बेडकर को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए था, और न ऐसी माया का ही व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को समझी देने के रूप में किया जा सके, बल्कि कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देपना चाहिए था कि आगे क्या होता है।” इससे सरकार की चिन्ता मिट गई।

• समझौते की असफल चेष्टा

असहयोग का जो पत्थर गया में ठेंवाई से डलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरम्भ में साबरमती में करीब-करीब नीचे आ गिरा। हम यह देख ही चुके हैं कि प्रतिअसहयोगी स्वतंत्र और राष्ट्रीय-बलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप “इण्डियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था,

शान्तिपूर्ण और बंध उपायो से (सामूहिक सत्याग्रह और करबन्दी को छोड़कर) औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौंसिलो के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति बरतने की स्वतंत्रता दी गई थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चीत के बाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ अप्रैल को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं, सावरमती में बुलाई जाय। इस बैठक में अन्य नेताओं के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपत राय, श्री केलकर, जयकर, अणे और डॉ० मुंजे भी थे। यहाँ महाममिति-द्वारा पुष्टि मिलने की जगह रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के बीच में यह तय हुआ कि १९२४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो मांग पेश की थी उसके सरकार-द्वारा दिये गये उत्तर को सतोप-जनक समझा जाय, यदि मंत्रियों को प्रान्तों में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कौंसिलो के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी की, जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री मुकुन्दराव जयकर हों, पुष्टि मिल जाना आवश्यक रक्ता गया। 'इंडिया १९२४-२६' में कहा गया है—“पर अभी इस समझौते की स्याही मुश्किल से सुखी होगी कि आन्ध्र प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के सभापित श्री प्रकाशम् ने अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि “कांग्रेस की स्थिति को सावरमती में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया।” अन्य अनेक प्रमुख कांग्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का असतोप प्रकट किया। साधारणतया यह समझा जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्र ही फिर कौंसिलो में चले जायेंगे और मंत्रि-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु ५० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके कि पद-ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्तें ये हैं —

(१) मंत्री कौंसिलो के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जायें, और उनपर सरकार का कोई शासन न रहे। (२) आय का एक उचित भाग “राष्ट्र-निर्माण” विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो।

परन्तु सारी बातें फिर छटाई में पड़ गईं। श्री जयकर ने उस मसविदे को,

जो कमिटी के सामने रखा गया, समझौते के बिल्कुल विरुद्ध बताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के सबब में सदेह और मतभेद को दूर करने के वहाने ज्यों का पूरा तरह खण्डन किया गया है। वस, इसके बाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन-मुटाव बढ़ता गया, परन्तु अभी सावरमती के समझौते का महासमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ३ मई को हुई। इस बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "चूंकि सत्रों के ठीक-ठीक अर्थ के सबब में समझौते पर हस्ताक्षर करने-वालों में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से समझौते की जो बात-चीत चला रहा था वह भग्न हो गई है, और इसलिए पैक्ट को समाप्त और रद्द समझा जाय।" वह इलैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी की और श्री श्रीनिवास आयरर ने उनका स्थान ग्रहण किया।

हिन्दू-मुसलिम दंगे

१९२६ के मध्य में हर्ष बेस की राजनैतिक स्थिति का सिंहावलोकन करने के लिए ठहर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १९२६ को लॉर्ड बर्किन भारत में आये। लगभग उसी समय कलकत्ते में बड़ा ही भयानक साम्प्रदायिक दंगा हो गया। छ मद्रास तक कलकत्ते की सड़कें हत्या-काण्ड और अव्यवस्था का अल्लाहा बनी रहीं। बगह-गणह सड़कों पर दगे हुए, ११० जगह आग लगाई गईं, नन्दिये और मस्जिदों पर हमला किया गया। सरकारी बयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ जादमी मरे और १८४ घायल हुए और दूसरी मुठभेड़ में ६६ जादमी मरे और ३६१ घायल हुए। ६ सप्ताह के विध्वंस और हत्या-काण्ड के बाद देश खालि हुआ। लॉर्ड बर्किन इन दंगों ने बड़े बेचैन हुए। उन्होंने इस विषय पर जो नापस दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी मात्सा और विद्वलता, सारी धर्म-माधना और सहृदयता रख दी। उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और धर्म के नाम पर भारत की उस सुकीर्ति को बचाओ जिसे वर्तमान वैमनस्य मिटा रहा है।

अगस्त के महीने में हिल्टन-यंग-कमीशन ने मुद्रा और विनिमय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार डाटपट १८ पेंसवाला विल पेम कर दिया। सरकार की इस अलदबाजी की निन्दा हुई और उसने १९२७ की फरवरी तक ठहर जाना मजूर कर लिया, जिससे स्नेहो और जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिले कि कीमतें १८ पेंस के अनुसार पर बाकर ठहर रही हैं या नहीं।

सितम्बर में लाला लाजपत राय और पण्डित मोतीलाल नेहरू में बड़ी

कौंसिल के काम के मन्त्र में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ। लालाजी का खयाल था कि स्वराजियों की 'वाक-आउट' की नीति हिन्दू-हितो के लिए स्पष्टतया हानिकर है। यह पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में सावरमती के समझौते की पुष्टि के पक्ष में भी थे। इसलिए उन्होंने बड़ी कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बड़ी कौंसिल की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी। नये निर्वाचन सिर पर मौजूद थे।

इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक मुसलमान की नियुक्ति की चेष्टा कर रहे थे। लॉर्ड अविन ने उसका करारा उत्तर दिया—“किसीकी नियुक्ति सार्वजनिक हितो के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के सन्ध में गवर्नर-जनरल स्वतन्त्र रहेगा।” वास्तव में लॉर्ड अविन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे।

१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मद्रास में कांग्रेसी उम्मीदवार—जब थे स्वराजी न कहलाते थे—पूर्ण-रूप से विजयी हुए। लॉर्ड बर्कनेहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवें, गोहाटी में कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवाम आयगर गोहाटी-कांग्रेस के सभापति चुने गये।

गोहाटी-कांग्रेस

गोहाटी-कांग्रेस स्वभावतः ही तनातनी के वातावरण में हुई। तनातनी का कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की बात है कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी स्कावट डालना था, उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था में जब कौंसिलों में स्वराजियों का मताधिक्य हो, करने की बात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग असहयोग के निकट आ लगा, क्या कौंसिलों की कमिटियों की निर्वाचन द्वारा प्राप्त होनेवाली जगहों के सम्बन्ध में, और क्या भारत-सरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में। अन्त में यह असहयोग सावरमती में सहयोग के आस-पास घूमने लगा, पर क्षिप्तक के साथ। कौंसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से सकोच करती थी। इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी सहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-दल, स्वतन्त्र-दल या उदार दलवालों की स्थिति अपनाने को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलबाद में उठाती थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग

और आवश्यक होने पर जड़या डालने की, और सुधारों के मामले में सहयोग करने की बात करते जल्दर थे। इन्हीं सूक्ष्म पर पूर्ण-रूप से व्यावहारिक प्रश्नों ने प्राग्ज्योतिषगुर (गोहाटी) में आपस में खिचाव पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी सुलभ-खुल्ला प्रवृत्ति करके, और अप्रत्यक्ष-रूप से उसे आमंत्रित करके, प्रलोभन दे रही थी और उन सारे हथकण्डों से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिद्विषत मस्तिष्क और भीरु-हृदय काबू में आते हैं।

स्वामी अद्वानन्द की हत्या

यह खिचाव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर दुःखान्त न था। हिन्दू अब अकस्मात् गोहाटी में यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमान ने स्वामी अद्वानन्द को रोगप्रणव्या पर, उनसे मुलाकात करने के बहाने, गोली मार दी तो वह नीर भी बग गया। जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में कांग्रेस के मन्त्राति का हाथी पर जुलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियों का देश दृष्ट, रणरिप वह कांग्रेस के सभापति का सम्मान अद्भुत और अपूर्व ढंग से करना चढ़ता था। पर जुलूस का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस दुःखदायी ग़माद में शोक छा गया।

गोहाटी के प्रस्ताव हस्तगामूक थे। स्वर्गीय स्वामी अद्वानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मोक्षाना मुहम्मदजली ने। गांधीजी ने समझाया कि मजहब की अवलियत क्या है, और हत्या के कारणों को बताया—“शायद अब आप लोग समझ जायेंगे कि मैंने अहमदगढ़ीद को नहीं मारे था। मैं तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं छ्द्रता। दोरी तो आप में थी, जिसे एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया।” केनिया ता नम्बर प्रकाश में दृग्ग था। केनिया में प्रवामी भारतीयों के विरुद्ध बानून और भी तड़ोर होग आ रहा था। आरम्भ में कर २० शिलिंग था। फिर बह मूदा-अरन्ना की—दृग्ग के दृग्ग बढ़ाकर ३० शिलिंग कर दिया गया और उसके बाद बानून के दृग्ग ४० शिलिंग—दृग्ग दिया गया। इस प्रकार वहा ब्रौपियन जिन्नों की वहा जागीर जिन्नों के दृग्ग स्वतन्त्रता के और उनकी बाकासाओं के विरुद्ध की जा रही थी। ब्रौपियन के दृग्ग के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि—

(क) जबकि सरकार राष्ट्रीय भाव का ऐसा दृग्ग न दे रही है जो भारत की या महासमिति की राय में मनोदग्ग हो, ब्रौपियन दृग्ग की दृग्ग ४० शिलिंग

या सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वयं ग्रहण न करेंगे, और अन्य पार्टियों-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेंगे।

(आ) जबतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक कांग्रेसवादी (ई) घारा में वर्णित बातों का ध्यान रखते हुए धन-सम्बन्धी मागों को अस्वीकार करेंगे और वजटो को रद्द करेंगे, जब कि महासमिति की आज्ञा कोई और प्रकार की न हो।

(इ) जिन कानूनों के द्वारा नौकरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती हो उनके सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावों को कांग्रेसवादी फेंक देंगे।

(ई) कांग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और विलों का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए, देश के आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी हितों की उत्थति के लिए, और व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा-संगठन करने और समाचार-पत्रों की आजादी और फलतः नौकरशाही को स्थान-भ्रूत करने के लिए आवश्यक हो।

(उ) कांग्रेसवादी कृषकों की दशा में उत्थति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों की मौकसी हक प्राप्त हो और जिनके द्वारा किसानों की दशा में सीधे ही सुधार हो।

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे और जमींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेंगे।

बंगाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को धिक्कारा गया। देश में और देश के बाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में, गुच्छारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पाम किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया।

गोहाटी-कांग्रेस ने ग्राम-संगठन के काम पर और दिया और उन कांग्रेस-वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हो, या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हो या कांग्रेस की किसी भी संस्था की बैठक या समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हो, खदर पहनना लाजिमी कर दिया।

इस जमाने में कांग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में लम्बे-बीड़े प्रस्ताव पास करना और कौंसिलों में मुठभेड़ करते रहना मात्र रह गया था। पर एक बात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में विशेषता धारण कर ली थी। जब से अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बना खट्टर, आमोन्नति और मितव्ययिता के पवित्र वातावरण में पनपने लगा। जिन स्त्री-पुरुषों ने खट्टर का व्रत ले लिया था वे अत्यन्त रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे। वार्षिक प्रदर्शनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी उन्नति कर दिखाई है। बिहार ने गोहाटी के अवसर पर खट्टर तैयार करने में अपनी छ-मात साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टांत-स्वरूप थी। दो-एक वर्षों को छोड़कर इधर बाकी वर्षों में प्रदर्शनियां, जो अब कांग्रेस का अनिवार्य अंग हो गई हैं, सोलह आने खट्टर की प्रदर्शनियां हो गई हैं। इन प्रदर्शनियों ने देश की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुँचाई है और लोगों को विश्वास दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है 'निर्धनो के लिए भोजन और वस्त्र'।

कांग्रेस का 'कौंसिल-मोर्चा'—१९२७

बड़ी कौंसिल में कांग्रेस का युद्ध

अब हमें भिन्न-भिन्न कौंसिलों में कांग्रेस-पार्टी-द्वारा किये गये काम का पर्यालोचन करना है। यह याद रहे कि बंगाल और मध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वैध-शासन का अंत हो गया था। १९२७ में इन दोनों प्रान्तों में यह फिर कायम कर दिया गया। बंगाल में मंत्री के वेतन की भाग के पक्ष में १४ रायें आईं, विपक्ष में ८८। मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६। १९२६ के मार्च में स्वराज्य-पार्टी बड़ी कौंसिल से उठकर चली गई। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक आने का न था। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौंसिल-भवन में आई और प्रस्ताव को अस्तुवर तक के लिए, अर्थात् वर्तमान कौंसिल सत्र होने तक, स्थगित करा दिया। जब बड़ी कौंसिल की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ पेंस की दरवाली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैठक में पण्डितजी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने सत्येन्द्रचन्द्र मिश्र की—जो जेल में बन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे—अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कौंसिल की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। अभी हाल ही में १९३५ में बड़ी कौंसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री शरत्चन्द्र बसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पास हुआ। श्री शरत्चन्द्र बसु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे। पण्डितजी का कहना था कि श्री मिश्र को जेल में बन्द रखकर सरकार बड़ी कौंसिल के हक पर और उन्हें चुननेवालों के अधिकारों पर आघात कर रही है। इस प्रश्न पर सरकार १८ रायों से हारी। पर तो भी श्री मिश्र को बड़ी कौंसिल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र न किया गया। बंगाल के नजरबन्दों का प्रश्न भी उठाया गया। पण्डितजी की याच मूल प्रस्ताव के सशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजरबन्द छोड़ दिये जायें या उनपर मामला चलाया जाय।

पण्डितजी का संशोधन १३ रुपये की अधिकता से पास हो गया। जी मित्रवाले प्रस्ताव के बाद बड़ी कौंसिल को स्थापित करने के लिए और भी कई प्रस्ताव पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था। दूसरा फिजी को भेजे गये भारतीय सिविल-सर्विस की रिपोर्टें प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं मिली। एक और प्रस्ताव रेलवे-वज्र की बहुत समाप्त होने और बड़े वज्र के पैस होने तक विविध की दरवाले प्रस्ताव को स्थापित करने के सम्बन्ध में था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पास हो गया। अन्तिम प्रस्ताव लखनपुर की और बवाल-नागपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हड़ताल की रक्षा करने के सम्बन्ध में था। इसके बाद सरकार में और विविधित सदस्यों ने कई प्रश्नों पर मुठभेड़ हुई। उनमें से एक प्रश्न फौजद-संरक्षण-विल-सम्बन्धी था। इस विषय पर दो-एक शब्द कहना अप्राप्तमिक न होगा। १९२३ के आसपास भारतीय फौजद और कोर्टों के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया। टैरिफ-बोर्ड ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के बाद इस प्रश्न पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की। यह समय बीत गया। इसके बाद इस प्रश्न पर दुबारा विचार किया गया तो टैरिफ-बोर्ड इस मतीचे पर पहुँचा कि बाहर से आनेवाले कोर्टों और फौजद के माल पर अधिक चुगी लगाई जाय, पर अंग्रेजी माल पर एकही चुगी लगे, और अन्य देशों के माल पर विभिन्न-विभिन्न प्रकार की चुगिया लगाई जायें। यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न था और लोकमत इसके विरुद्ध था। पर इस मामले पर खूब बहस करने के बाद सरकारी योजना की बड़ी कौंसिल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-माल के उपनायक भी जयकर ने सारे वज्र को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के बाद भी जयकर का प्रस्ताव ८ या ९ रुपये से पास हो गया। जब सबसे बड़ा प्रश्न १८ पेंस का आया। इसका प्रभाव भारत के मिल्-मालिकों और व्यापारियों पर ही नहीं, किसानों पर भी पड़ता था। कच्चा माल और अन्न बाहर भेजनेवालों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पीछ की दर ११) थी। अब यही १३) के बराबर हो गई। दूसरे सब्सिडी में बाहर ने माल भगानेवालों को माल भगाने का उत्तेजन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल की रूपया २ पेंस मन्ता हो गया या फ्री १६ पेंस २ पेंस कम हो गया, अर्थात् ८ या १२½% मन्ता हो गया। इसी प्रकार बाहर भेजे जानेवाले कच्चे माल के सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पीन्ड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर बेजा जाता था, और ११) में

पटता था, अब १३।७४ को पड़ने लगा, और जो कच्चा माल पीण्ड की कीमत का पहले १५) में विकता था, अब १३।७४ में विकने लगा। इस प्रकार १९२५ में बाहर भेजे जानेवाले माल का हिसाब लगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड़ के आठवें भाग का अर्थात् लगभग ४० करोड़ का हर साल घाटा होता रहेगा। यदि साल-भर में बाहर से आनेवाला माल २४६ करोड़ का था तो यह कहना कि बाहर से माल मगानेवाले देश को ३१ करोड़ का नफा रहा, उसके लिए कोई सतोष प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि अब भी वह ४० करोड़ के घाटे में अर्थात् कुल मिलाकर ६ करोड़ के वार्षिक घाटे में रहा। इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक जमा-स्वर्च उसके अनुकूल है, अर्थात् वह बाहर माल जितना भेजता है उससे कम माल मगाता है, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पड़ेगा। यही कारण था कि इस प्रश्न पर बर्मासान युद्ध हुआ, पर लोकमत को ३ रायों से हारना पड़ा और सरकार के पक्ष में ६८ रायें आईं। फौलाद-रक्षण, आर्थिक और दर-सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा होने के बाद, १९२७ में बड़ी कौंसिल की दिल्ली की बैठक में कांग्रेस के लिए और कोई महत्त्वपूर्ण काम न रहा।

यहाँ हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र करना ठीक समझते हैं। अध्यक्ष पटेल एकवार फिर अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने गांधीजी को अपने वेतन से (१६५६) मासिक देते रहने का वचन दिया और २०००) अपने व्यय और अपने पद के अनुकूल मर्यादा और आराम के लिए रख छोड़े। गांधीजी इस थाती का प्रबन्ध-भार अकेले अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओं से सलाह ली और दूसरे ट्रस्टी उसमें शामिल किये। ३१ मई १९३५ को गांधीजी ने गुजरात-प्रान्त के रास नामक स्थान पर एक बालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड के भन्ने उनके पास ४०,०००) हैं और उनके व्याज में से १०००) सर्व किया गया है।

गांधीजी ने साल-भर-क्षेत्र-सन्ध्यास का जो व्रत कानपुर में धारण किया था उसकी मीयाद पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राजनीति में जो विश्राम ग्रहण किया है और उसे जो लोग विचित्र या सनक समझते होंगे, वे इस कानपुरवाले व्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेंगे। जब कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि जिघर चाहे जाय। उन्होंने काम का आरम्भ देशबन्धु-स्मृति-कोष के लिए विहार में दौरा करके किया। इस प्रकार संग्रह किया हुआ धन सहर-प्रचार में लगाया गया। कौंसिल के काम में उनके लिए कोई आकर्षण न था। लाला लाजपत राय तक को यह काम सार-हीन

प्रतीत हुआ था। उन्होंने कौंसिल के कार्य को निस्सार और अक्षियों का अप्रत्यक्ष मात्र बताया था। सालाजी के बाद एस० बीविमान बागवर की वारी थी, जिन्होंने कहा, 'बड़ी कौंसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रांतीय कौंसिलें तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अहंता-नीति सफल हो सके।'

दक्षिण अफ्रीका

१९२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थिति बहुत ही बुरी थी और जनरल-स्मट्स 'सुरेयोशन बिल' पास कराने की बातें थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनी-देवी पूर्वी-अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रीका तक गईं और उनका बड़े जोर का स्वागत हुआ। बिल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मट्स की सरकार ने इस्तीफा दिया, इसलिए वह बिल भी त्याग दिया गया। १९२१ में जनरल हर्टजोग ने अधिकार प्राप्त किया और एक पहले में भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया। इस बिल का नाम था 'क्लास एरिजा बिल'। यदि यह यूनिवर्सल पार्लियामेंट में पेश किया जाता तो सरकार और विरोधी दल दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनबन्धु एण्डरसन से गांधीजी और कांग्रेस ने कहा जाने का अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यह जाणकारी उठाई कि यदि बिल पास हो जाएगा तो गांधी-स्मट्स-समझौता गलत हो जाएगा। बाद की सावधानी-सरकार ने पैडीसन-गिफ्ट-मण्डल जैसा, जिसकी ओर यूनिवर्सल-सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर धीरे-धीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव जो उस समय तक रोक रक्खा जाय जबतक भारत-सरकार का गिफ्ट-मण्डल, जिसे यूनिवर्सल-सरकार के साथ समझौता करने का अधिकार प्राप्त है, पहुँचकर दक्षिण-अफ्रीका-अवासी भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी तरह में बर्तान कर ले।

१६ अक्टूबर १९२६ को दक्षिण-अफ्रीका के लिए एक भारतीय गिफ्ट-मण्डल के नियत किये जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मद हुसीयुल्ला थे। १७ दिसम्बर १९२६ को एक परिषद् हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रीका के प्रधान-मंत्री जनरल हर्टजोग ने किया। यह अधिवेशन १६२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक बालू समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ।

दक्षिण-अफ्रीका की यूनिवर्सल-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की कि वह दोनों सरकारों में लगातार व कारगर सहयोग बनाये रखने के लिए एक एजण्ट नियुक्त करे।

जब प्रथम केपटाउन-परिषद् खतम हुई तो गांधीजी ने, जो दक्षिण-अफ्रीका एजण्ट मेजने के पक्ष में थे ही, भारत के समाचार-पत्रों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया। सरकार व भारतीय-जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत हो गये। जैसा हम बाद में देखेंगे, श्री शास्त्री की नियुक्ति का परिणाम अच्छा ही रहा।

हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का हल

जब गांधीजी ने अपना दौरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिल का डर तो अब निकल चुका था और उनमें से कुछ ने तो गांधीजी को बुलाना भी शुरू कर दिया। वे अब सहर को इस नज़र से न देखकर कि वह कांग्रेस-स्वयंसेवकों के फ्रीजी-दल की राष्ट्रीय-मोर्चाक है, इस नज़र से देखने लगे कि वह देश के आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी चीज है। उन्होंने गांधीजी को एक सच्चा और ईमानदार आदमी पाया, हा, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गुमराह करनेवाले और उनके राजनैतिक विचार कुछ सनकियो-जैसे मालूम होते थे। गांधीजी कुछ समय तक ही दौरा कर पाये थे कि बीमार पड़ गये। जब दम्बई में १५ व १६ मई को महासमिति की बैठक हुई, कार्य-समिति ने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का एक हल बनाकर उसके सामने पेश किया। महासमिति ने उसे मंजूर भी कर लिया। लेकिन आज इतने समय बाद जब हम उस हल को पढ़ते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अवतक कितने उलट-फेर हो गये हैं, तो यह बात हमारे दिमाग में आये बिना नहीं रह सकती कि दम्बईवाला हल वास्तविकता से कोसों परे था। उसके बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि उसने प्रान्तों व केन्द्रीय धारा-सभाओं में संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की थी और आवादी के हिसाब से जगहों का बंटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझौता हो सके तो मय पञ्जाब के सिक्खों के अल्प-संख्यक जातियों के साथ रियायत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगह दे दी जायें और जिस हिसाब से उन्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जायें वही हिसाब वही कौंसिल की जगहों के बंटवारे में भी लागू हो।

चीन की आजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की गई और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई, साथ-ही-साथ फौजों की वापसी की भी माग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन

को एम्बुलेन्स कोर मेजने का जो इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बंगाल-कांग्रेस का झगडा, मजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार ये अन्य विषय थे जिनपर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इनमें आखिरी विषय पर गौर से विचार होना था।

इस समय मई के चौथे सप्ताह में एक बड़ा अनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाष बाबू छोड़ दिये गये। लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घबराते रहते थे, अतः बंगाल के नजरबन्दों के साथ नरमी बिखाने का काम सर स्टैनले बैकसन के जिम्मे पड़ा। सुभाष बाबू का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसी वजह से सबको बड़ी फियर होने लगी थी।

गुजरात की बाढ

जुलाई १९२७ के अन्त में गुजरात प्रान्त में नीपण बाढ के आने में एक ईर्ष्या विपत्ति आ गई। चार पाच दिन में ५० इंच ने अधिक मूललावार पानी बगमने के कारण बहुत से गांव बह गये। मवेसी, झोपडिया, कपडे-जुते कुंठ व जवा, फगाग लोग बे-घर-बार हो गये। ४,००० घर बाढ की झपट में आ गये। इन गांवों में ५०-६० फी सदी और कहीं कहीं ६० फी मदी मवान तक गिर गयी। अन्नदाता म्यूनिसिपल कमिटी तथा गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष मन्नार पटेल के नेतृत्व में करीब २,००० स्वयंसेवकों ने इन बाढ में गुजब का काम किया। एक सप्ताह तक जो सरकार की शासन मशीनरी बेकार पड़ी रही। नरगाणी तर्दवानों कीकतव्य विमूढ से हो गये, लेकिन कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने पानी के द्वारा माग को चीर कर विपत्ति ग्रस्त लोगों को भोजन और बपटे की मलाया पहुंचाई। कई स्थानों तक यह सहायता-कार्य चलता रहा और किसानों को नफान उठाने, गेहूँ बोने तथा हल-चल खरीदने आदि के कार्यों में कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने मन्नार का गुण सहयोग दिया। नरवार ने १,५५,००,००० रुपया दुर्गिन नार में दिया। ५२ मस्थाओं ने भी ३ लाख रुपया एकत्र किया। सभी मस्थानों में विचार-सम्मेलन नेतृत्व में एक साल तक काम करती रही। सम्मेलन के नरवार ने १९२७ सर चुन्नीलाल मेहता ने इन स्वयंसेवकों की और २० गांवों के मन्नार के प्रशंसा की।

दंगों की वाद

सन् १९२७ की गर्मियों में अन्य सालों की भांति कोई मार्क का कानून पास नहीं हुआ, लेकिन देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की वाद-सी आ गई। सबसे भीषण दंगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये और २७२ घायल हुए। बिहार, मुल्तान (पंजाब), बरेली (युक्त-प्रान्त) व नागपुर (मध्य प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। लाहौर के बाद नागपुर का दंगा इन सबमें भीषण था, जिसमें १६ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनाएँ घटी, जो इन दंगों में कुछ का कारण बनी, इसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रंगीला रसूल'। सरकार ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी बहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रद्द कर दी और लेखक को बरी कर दिया। 'रिसाला वर्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन दो मुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १९२७ में असेम्बली में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था —

"जो कोई व्यक्ति सज्जाद की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर जान-बूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-सकैतों से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उसपर सजा व जुर्माना दोनों होंगे।"

दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभी तक २५ दंगे हो चुके थे जिनमें १० युक्त-प्रान्त में, ६ बम्बई में और २-२ पंजाब, मध्य-प्रान्त, बंगाल, बिहार व दिल्ली में हुए थे। २६ अगस्त सन् १९२७ को भारतीय चारा-सभा में आपण देते हुए वाइसराय लॉर्ड अविन ने बताया कि १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गये और २५०० से अधिक घायल हुए। वाइसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके बाद एक एकता-सम्मेलन भी किया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली। महासमिति ने भी २७ अक्टूबर १९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयंगर ने किया, और बहुत लम्बी बहस के बाद सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया —

“चूँकि भारत की किसी भी जाति को अपने धार्मिक कर्तव्यों अथवा धार्मिक विचारों को दूसरी जाति पर लागू करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चूँकि हर एक जाति व व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, हिन्दुओं को धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मस्जिद के सामने जुलूस निकालने की और बाजा बजाने की स्वतन्त्रता है; लेकिन उन्हें मस्जिदों के सामने न तो जुलूस रोकना चाहिए न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मस्जिदों के सामने ऐसे अजन गाने चाहिए या ऐसी तरह बाजा बजाया चाहिए कि मस्जिदों के इबादत करनेवाले व नमाज पढ़नेवाले दिक हो या उनके कार्य में बाधा हो। जिस शहर या गांव में मुसलमानों को गो-बध्न करने का अधिकार है, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतन्त्रता होगी, लेकिन वे गो-बध्न न तो किसी आम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्दिर के पास। और न किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ हिन्दुओं की नजर पड़ती हो। गावों को, उनका बध्न करने के लिए जुलूस में भी न निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदर्शन किया जाय। चूँकि गो-बध्न के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनाएँ बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आग्रहपूर्वक अपील की जाती है कि वे गो-बध्न इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिन्दुओं को दुःख पहुँचे।”

सम्मेलन ने उन्ही दिनों के कुछ कागज़ाला हथेलों की भी निन्दा की और हिन्दू व मुसलमान नेताओं से अपील की कि वे बेज में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महासमिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करे।

एकता-सम्मेलन के अन्त में ही २८, २९ व ३० अक्टूबर १९२७ को कलकत्ता में महासमिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर एकता-सम्मेलन के प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों पास कर दिये गये। उसके पश्चात् बंगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने आया। इन नजरबन्दों में कुछ तो बार-बार सज़ा से जेलों में पड़े हुए थे। इसलिए उनकी शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई कराने का प्रयत्न करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई।

कलकत्ते की बैठक में महासमिति ने जिन-जिन विषयों को उपयुक्त प्रस्तावों द्वारा निवेदनाय वे थे वे—अमरीका-स्थित भारतीय, भारत के हिन्द-मनन के लिए

सिनेटर कोपलैण्ड के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश, श्री सकलातबाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा-नरेश का 'राज्य-व्युत्' होना। यह प्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस विषय को श्री बी० जी० हार्निमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया।

साइमन-कमीशन

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुईं। वाइसराय अपने दोरे का कार्यक्रम रद्द करके वापस दिल्ली आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके बाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर बगलौर में थे। उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे। जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष बात न निकली। लॉर्ड अविन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री की घोषणा रख दी। जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या वस यही काम है, तो लॉर्ड अविन ने कहा, "वस, यही।" गांधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुँच सकता था। पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में ८ नवम्बर सन् १९२७ को की गई। वाइसराय उसके प्रति सद्भावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस के सिवाय भी भारत की सब पार्टियाँ साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुईं कि उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्ता गया। और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक ही था कि साइमन-कमीशन तो उसकी अघकचरी मांग के निकट भी कहीं नहीं पहुँचता। डॉ० वेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है?

श्री दिनशा बाबा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के खिलाफ एक घोषणा-पत्र निकाला। कांग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। मिस विल्किन्सन ने तो यहातक कह डाला कि अमृतसर-काण्ड के पश्चात् ब्रिटिश-सरकार के किसी भी कार्य की भारत में इतनी भारी निन्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन की निन्दा की और कर्नल बेजवुड के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

हो ? १९२७ में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और महासमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल में कांग्रेस का सभापतित्व एक मुसलमान से बटकर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों में भी डॉ० अन्सारी से बढ़कर ? डॉ० अन्सारी १८९६ या १८९९ में मदरास मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे और १९१२ में रेड-क्रॉस-मिशन के साथ बालकन-प्रायद्वीप भी गये थे। डॉक्टरों में तो आप नाम पा ही चुके थे। डॉक्टरों-मेंबे के बाहर भी अपनी नायस्तगी व विचारों की उदारता के कारण सुविख्यात थे। इसीलिए आप मदरास-कांग्रेस के सभापति चुने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रश्न को खूब जगह दी। कांग्रेस की नीति का संक्षेप में वर्णन करते हुए आपने बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो सहयोग की रही, फिर डेढ़ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौंसिलों में अटगेबाजी करने, और कौंसिल का काम ही रोक देने की। “असहयोग असफल सिद्ध नहीं हुआ,” डॉ० अन्सारी ने कहा, “हम ही असहयोग के लिए असफल सिद्ध हुए।” इसके पश्चात् आपने शाही कमीशन, नजरबन्द, भारत व एशिया तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-अधिवेशन में मि० स्प्रेट, मि० पार्सेल व पार्लमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि० मार्टी जोन्स भी मौजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई दास बात न थी। शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सच, चीन, पासपोर्टों का न मिलना आदि ऐसे विषय थे जिनपर लगभग हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव-द्वारा ‘युद्ध के खतरे’ की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने से या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल अवारी की भूल-दुबताल को ७५ वा दिन हो चुका था, उन्होंने सशस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग वजित हथियारों के साथ जुलूस निकालना था, छेड़ दिया था। जनरल अवारी को उनकी गैर-हाजिरी में ही बर्मा दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। बर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्दा की गई। स्मरण रहे कि १८८५ में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उसने बर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे सम्राट के आधीन एक उपनिवेश (Crown Colony) बना दिया जाय। कांग्रेस ने शाही कैंदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया

और उनकी शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई की मांग की। पूर्व-अफ्रीका व दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी—राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विषयों पर—एक प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया, यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था। चूकि स्वराज्य का भसविदा तैयार करने की मांग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई भसविदे पेश थे, अतः कांग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं ने मजबूत करके स्वराज्य का भसविदा तैयार करे और उसे एक विधेय कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रखे। इस कार्य के लिए कार्य-समिति को और सदस्य बटाने का भी अधिकार दिया गया। कांग्रेस के विधान में भी कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन इन वर्षों का सबसे मुख्य प्रस्ताव आही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं :—

कमीशन का बहिष्कार

“चूकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वतन्त्र-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक आही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से बहिष्कार करे। विधेय करके—

(अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-पस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन करें, और भारत के जिन-जिस शहर में कमीशन जाय वहां भी उन दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोगमन को इस प्रकार संगठित करें कि हर तरह के राजनैतिक विचारवाले भारतीय कमीशन का जोरो से बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायें।

(ब) यह कांग्रेस भारतीय कॉमिनों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व जातिवर्गों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से अनुरोध करती है कि वे न तो कमीशन के सामने गवाही दें, न सार्वजनिक अवसरों या खानपानों पर उनके साथ सहयोग करें, और न उनके सम्बन्ध में किसे जानेवाले किसी नाभारिक उत्सव में भाग लें।

(स) यह कांग्रेस भारतीय धारम-समाजों के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध

करती है कि वे (१) कमीशन के सिलसिले में बिठाई जानेवाली किसी भी "सिलेक्ट कमीटी" के लिए न तो राय दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें और (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्य जो कोई भी प्रस्ताव या खर्च की मांग पेश की जाय उसे ठुकरा दें।

(द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरोध करती है कि वे निम्न सूरतों के सिवाय धारा-सभाओं की बैठकों में भाग न लें, अर्थात् यदि उनका स्थान रिक्त होने से बचाने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डल को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की राय में भारत के हितों के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो।

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण बनाने के लिए जहाँ तक हो सके वह दूसरी सत्याग्रहों व पार्टियों से सलाह-मशविरा करे और उनका सहयोग प्राप्त करे।"

काकोरी-केस के अभियुक्तों को वर्वर्तापूर्ण सजायें दी जाने पर और उससे जनता में रोष की प्रबल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न बढ़ाई, उसपर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा कुछ प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उनके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की।

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक् प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई। इसके अनुसार यह कहा गया, "यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता है।" यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती बेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न देखी। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के लक्ष्य का यह बड़ा ही ज्ञानदार व स्पष्ट वक्तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला, जब कि वह पास हो गया।

भावो संग्राम के बीज—१९२८

कमीशन का बहिष्कार

जब १९२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोष-ही-रोष विद्यमान था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉर्ड अविन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को जान-बूझकर अपमानित करने का सम्राट्-सरकार का कोई इराधा नहीं है। पर साथ में उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सह-यता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पार्लमेण्ट उसपर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेगी।

३ फरवरी को कमीशन बम्बई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर में हड़ताल मनाई गई और कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। अखिल-भारतीय हड़ताल के अलावा ३ फरवरी को और कोई मार्क की घटना नहीं हुई। हा, मदरास में हाइकोर्ट के पास भीड़ में अवश्य कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहा पुलिस ने बुगमिंग-बश भीड़ पर गोली चला ही दी, हालांकि काम शायद दिना गोली चलाये भी चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहा-का-तही मर गया और दो बाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की मुठभेड़ हुई।

कमीशन बम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्ली आया। दिल्ली शहर में जेंते ही कमीशन के शरण पड़े कि उसका विरोधी-प्रदर्शनों द्वारा विराट् स्वागत किया गया और "गो बैक, साइमन।" "साइमन वापस लौट जाओ।" के झण्डे तथा तल्ले दिखाये गये। दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन (जो आमतौर पर जस्टिस-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है) व कुछ मुस्लिम-संस्थाओं को छोड़कर यह कहा जा सकता है कि भारत ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया।

कमीशन के बहिष्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन में यह बात आई कि अब आतंक व दबाव से काम लेना चाहिए। लाहौर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जन-समूह एकत्र हुआ। पुलिसवालों ने भीड़ पर हमला किया और कई प्रतिष्ठित नेताओं को डण्डों और लाठियों से ठोका-पीटा। लालाजी के कई जगह गहरी चोटें आईं। यह एक आम खयाल है कि लालाजी की मृत्यु इस बुझदिलाना हमले के कारण ही हुई थी। यद्यपि लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर पुलिस पर यह अभियोग लगाया गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जांच करने से साफ इन्कार कर दिया।

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र व शान्त भीड़ पर पुलिस ने कई बार जान-भूझ कर व अकारण डण्डे बरसाये। युक्त-भ्रान्त की पुलिस ने तो जवाहरलालजी तक को न छोड़ा। सब दलों के प्रमुख-अमुख कार्यकर्त्तियों पर डंडे व लाठिया बरसाने में तो मानो बुडसवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही खतम कर दी और बीसियों आदमियों को घायल कर डाला।

लखनऊ तो पैदल व बुडसवार पुलिस के कारण एक विशाल फौजी पड़ाव-सा ही बन गया। चार दिन तक पुलिस के बर्बरतापूर्ण हमले होते रहे। पुलिसवाले लोगों के घरों तक में घुस गये और "साइमन वापस चले जाओ" के नारे लगाने पर ही उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्त्तियों को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह पीटा। लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिकों को घन्य है कि वे इन बर्बरतापूर्ण हमलों व कृत्यों से तनिक भी न चबराये और अपने प्रदर्शन और भी अधिक जोशी-खरोंह के साथ करते रहे। अधिकारी-वर्ग को तो उन्होंने एकबार इतना छकाया कि वह देखता-का-देखता रह गया और सारा शहर हँसी के मारे लोट-पोट हो गया। मामला इस प्रकार था। कुछ ताल्लुकदारों ने कैसरबाग में साइमन-कमीशन को एक पार्टी दी। पुलिस ने कैसरबाग को चारों ओर से घेर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को बाग की सड़कों के करीब न आने दिया जिसपर पुलिस विरोधी-दलवाला होने का सन्देह करने लगती थी। इतना अहृत्तिगात रखने पर भी जब आसमान में सैकड़ों काली-काली पतंगें व गुब्बारे, जिनपर 'साइमन, चले जाओ', 'भारत भारतवासियों के लिए है' आदि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर बाग में गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किर-किरा हो गया।

जब कमीशन पटना पहुँचा तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ५० हजार आदमियों की एक भारी भीड़ इकट्ठी हुई। कमीशन का स्वागत करने के

लिए भी कुछ सरकारी नपरासी और मुट्ठी-भर नरकारी कर्मचारी मौजूद थे। सरकार ने आस-पास के गांवों से खारियो में भर-भरकर किसान बुलवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पो में घुमने के बजाय वे बहिष्कार-कैम्पो में जा डटे। और स्टेशन पर विराट् जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिंसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा बहिष्कार पाटियों के दल को देखकर तो सरकार की आंखें ही खुल गईं।

“भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों ने व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के पक्षचाय” — जैसा कि सर जान साडमन ने कहा था — कमीशन वम्बई से ३१ मार्च को रवाना हो गया। वास्तव में यह एक प्रकार की मिय्योन्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्टें में स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि “असेम्बली के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार करने के लिए बद्ध थे।” इसलिए सर जान साडमन और उनके साथियों का उनके सम्पर्क में जाना असम्भव था।

कमीशन के भारत आते ही सर जान साडमन ने बाइसेराम को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन एक संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक ओर कमीशन के सातों अंग्रेज सदस्य होंगे और दूसरी ओर बड़ी कॉमिल-द्वारा चुने गये सातों भारतीय। सम्मेलन के नव सदस्यों को नव वागजान देरने का अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उनमें बराबरी के बर्तों पर माने जायेंगे।

प्रान्तीय कॉमिलों ने भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटीया चुनने की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषय पर कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ बड़ी कॉमिल-द्वारा निर्वाचित मयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा तो उन प्रान्तीय कॉमिल की सिलेक्ट कमिटी काम करेगी, जिनका उन विषयों में सम्बन्ध है। समान अपनी रिपोर्टें अलग ब्रिटिश-नरकार को देना और मयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्टें अलग बड़ी कॉमिल को। इस घोषणा का भारत में कुछ अनुरोध हुआ। घोषणा के निकलने के दो-तीन घंटे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली में एकत्र हुए और यह घोषणा की कि कमीशन के विचार उनको जो आपत्तियां थीं वे ज्यों-की-सी दूर हई हैं और वे किसी भी हानि में कमीशन में मंगोना नहीं करना चाहते। असेम्बली ने भी केन्द्रीय मयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य चुनने में उत्साह दिया। इस सम्बन्ध में लाडा लाजपतगल ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि कुछ कमीशन की सदस्यता में उनमें कार्य की भांति योगदा प्रोग्रामों

को अस्वीकार है अतः वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ भारतीय उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जबकि उसमें भारतीय भी इतनी ही सख्या में नियुक्त किये जायें।” प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गया। सरकार को लाचार होकर स्वयं केन्द्रीय कमिटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े। यहाँ इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमीशन बम्बई में घूम रहा था तो ‘सर’ की पदवी धारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की। देश में बहिष्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ?

प्रसंगवश गहा यह कह देना भी जरूरी है कि जहाँ कमीशन तो एक ओर अपने काम में आकर जुट गया, तथा उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकाबले तिजारत में अधिक चाव रखते थे, इस बात के अध्ययन में लग गये कि भारत में तिजारत को बढ़ाने की किस तरफ गुजाइश है। लॉर्ड बर्नहाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य थे, देखा कि पंजाब में ब्रिटेन और भारत की तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुजाइश है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के वाजारों में ब्रिटेन की मोटरो, कारियो व ट्रैक्टरों की सपत बढ़ाने की सबसे अधिक गुजाइश है।

सन् १९२८ की खास-खास घटनायें साइमन-कमीशन का देश में भ्रमण, सर्वदल-सम्मेलन की बैठकें और वारडोली का आन्दोलन हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में फरवरी-मार्च १९२८ में सर्वदल-सम्मेलन की बैठक की गई। सम्मेलन में उपस्थित सत्तायें और कांग्रेस इस बात पर एकमत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या पर विचार ‘पूर्ण उत्तरदायी शासन’ को आधार मानकर ही होना चाहिए। दो महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ बैठकें हुईं और लगभग १५ समस्यायें शान्तिपूर्वक तय हो गईं। १६ मई को डॉ० अन्सारी के समापनत्व में फिर सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धान्तों का मसविदा तैयार करने के लिए ५० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की भिन्न-भिन्न सत्ताओं के पास भेजा जाय। २९ राजनैतिक सत्ताओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। इस विषय पर आगे विचार फिर किया जायगा।

जून के महीने में दो-तीन घटनायें ऐसी हुईं जिनका हमें अवश्य जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और ५० मोतीलाल

नेहरू का नाम उसके सभापतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह देखकर पण्डितजी ने 'एम्पायर पार्लेमेण्टरी डेलीमेशन' की सस्यता से भी, जिसके लिए उनको असेम्बली ने पिछले मार्च में अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया। पण्डितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनाओं का होना बताया। स्वयं गांधीजी ने कहा—“बंगाल को बड़े नेहरू की जरूरत है। वह सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को ग्रहण करनेवाले आदमियों में से हैं। देश को इसीकी जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय।”

बारडोली सत्याग्रह

दूसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगो का ध्यान आकर्षित होता रहा, वह है बारडोली का सत्याग्रह। बारडोली वह तहसील है जहाँ गांधीजी 'सामूहिक सविनय अवज्ञा' का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो-तीन बार इरादा बदलकर उन्होंने फरवरी १९२२ में आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। बारडोली में बन्दोबस्त, जो बक्सर २० या ३० साल में हर जगह हुआ करता है, होने-वाला था, बन्दोबस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम अवश्य होता है कि मालगुजारी लगभग २५% अवश्य बढ़ जाती है। बारडोली के आदमियों का कहना था कि उनपर मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल बढ़ी है या अच्छी हुई है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय खर्च करना पड़ा था। उनका कहना बिल्कुल यह भी नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय, वे तो केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, सहको, कीमतों व करो की जाच करने के लिए एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, और यदि हा, तो कितनी? सरकार आमतौर पर अपनी गर्जों से, चुपचाप और बिना किसी निश्चित सिद्धान्त के ही सब बातों का फंसला कर लेती है। जब कभी वह ऐसी या और कोई आर्थिक जाच करती है तो जनता की राय तक, सलाह तक, नहीं ली जाती। बारडोली में भी सरकार ने २५ प्रतिशत मालगुजारी बढ़ा दी। जाच कराने के सब वैध व प्रचलित उपायों को अमल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में चुनौती दे दी गई और करबन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया—आन्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के एक अंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानों

पैसे से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी एक गिकायत को रफा कगने के लिए। कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिपद में कर लिया था और सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व करें। डमी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को सगठित किया। सरकार ने जानबूरो की कुर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से पठान बुला-बुलाकर अन्धाबुन्ध कुर्कियाँ करने की नीति अस्तित्वार कर ली। पठानों का बुलाना सरासर ज्यादती थी। लोगों ने कुर्कियाँ होने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार के पास पशु-बल इतनी पर्याप्त-मात्रा में मौजूद था कि खुशार प्रकृति व आदतों के लोगों का बुलाना सरासर अनावश्यक था। कहा जाता है कि सरकार ने लगभग ४० पठान बुला लिये थे, बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने कहा था कि उनकी सख्या केवल २५ ही थी। सवाल सत्या का नहीं था, सवाल यह था कि पठान बुलाये क्यों गये? इसके बाद जल्द ही, बम्बई-कौंसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोध में कौंसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे। असेम्बली के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने श्री बाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात की धमकी दी कि यदि सरकार न झुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में जुट जायेंगे। आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढाई गई मालगुजारी जमा कर दी, कैदियों की रिहाई की शर्त मान ली गई, आयदाद का लौटाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय हुआ।

सरकार ने एक अदालत बिठा दी, जिसमें न्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जाच की और यह निश्चय किया कि मालगुजारी केवल ६१ प्रतिशत बढाई जाय। यह निर्णय अगस्त में हुआ और इसका फायदा चौरासी तहसील को भी हुआ। ज्ञात रहें कि चौरासी तहसील ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया था और बड़े हुए कर भी दे दिये थे, यह देखकर सरकार ने बारडोली को सम्बोधित करके कहा भी था—“जय चौरासी तहसील कर दे सकती है, तो बारडोली ही क्यों नहीं दे सकती?”

यहा यह कहना शायद अनोखक होगा कि बम्बई-कौंसिल में भाषण देते हुए बम्बई के गवर्नर ने कहा था कि बारडोली के करवन्दी-आन्दोलन को कुचलने के लिए साम्राज्य की सारी शक्तियाँ लगा दी जायेंगी। इसके कुछ दिन बाद ही फैसला हो गया। वास्तव में देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमों

में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत जाच के लिए बिठाई जाय। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह निष्पत्ति की थी कि केवल ६१% मालगुजारी बढ़ाई जाय, लेकिन जब इन सब कारणों पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानों ने पेश किया था लेकिन जिनपर अदालत को विचार करने का अधिकार नहीं था, तो वास्तव में बारडोली तहसील में मालगुजारी बिलकुल बढ़ी ही नहीं और फंसले के बाद भी अपनी पहली हद तक ही रही। समझौते की वास्तविक सफलता तो इस बात में थी कि बेची हुई जमीनें मालिकों को फिर वापस मिल गई और पटेल व त्वादित्यों को अपनी जगहें फिर मिल गई।

सर्वदल सम्मेलन

नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठक लखनऊ में फिर २८, २९ व ३० अगस्त १९२८ को हुई। नेहरू-कमिटी को उनके परिश्रम के लिए बधाई दी गई, सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई जिनका ध्येय 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' था। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढ़कर सुनाया, जिसमें यह बात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि वे उक्त प्रस्ताव में, जिसके द्वारा उन्हें तत्कालीन स्वतन्त्रता दी गई थी, गूब फायदा उठावें। इसलिए जहाँ उन्होंने प्रस्ताव या समर्थन न करने या निरवयव किया, वहाँ उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाधा न डाली। उन्होंने कहा कि उस प्रस्ताव में उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और इसीलिए वे न तो उनपर टिप्पणी करने में भाग लेंगे और न उनमें कोई संशोधन पेश करेंगे। सम्मेलन में जिस अन्य विषय पर विचार हुआ वे निम्न, प्राप्ति या वटवारा तथा सयुक्त-निर्वाह में सम्बन्ध रखते थे। इन प्रश्नों पर बोलते हुए जवाहरलालजी की इस टिप्पणी में ही महत्त्वपूर्ण है कि "महाराज व राजा समाज में जो नाट्यमय की भाँति ही रह जायेंगे, उन्हें ही हम प्रभावित नहीं कर पाएँगे। हमारा यह परिणाम हुआ कि हमें फिर भी उन प्रश्नों पर विचार करना —

‘महाराज की शक्ति के सम्यक् जो व्यक्ति जिन्हें जायसद या मान्यता प्राप्त हो, उनका ही निर्णय ही निर्णायक होगा और उनका ही निर्णय ही निर्णायक होगा।’

सम्मेलन ने उस दिशा में निर्णय उठाया कि अन्तर्गत में मद्रास, मद्रास-प्रदेश

इमाम, सर शकरन् नायर, श्री सच्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे। ये सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे।

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार किया। महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येय को दोहराया, नेहरू-कमिटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वीकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हैं उन्हें आमतौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विगत की बातों में अपने हाथ-पाव नहीं बाध दिये।

अब हम फिर कौंसिलो की ओर आते हैं। वास्तव में देखा जाय तो कौंसिलो में अड़ने की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान 'साइमन' का बहिष्कार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा था।

असेम्बली में

असेम्बली के कार्यक्रम में रिजर्व-बैंक-विल व सार्वजनिक-रक्षा बिल दो ही मुख्य विषय थे। रिजर्व-बैंक-विल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवत सबसे बड़ी लेकिन निरर्थक लड़ाई थी। सरकार का दावा था कि चूंकि यह बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्त्रण से हटाकर देश के एक बैंक के नियन्त्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ा पग होगा। लेकिन भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने ईश-शासन की योजना को अमल में लाते हुए इतनी खराबी मजूर की, इतनी आसानी से और खुद-बखुद मुद्रा व बैंकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटा लेने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? असेम्बली के सदस्यों को फौरन ही इस बात का सन्देह हो गया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य ही कुछ कर रही है। जब दोनों पक्ष प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवाद-ग्रस्त बातें सामने आईं, जिनमें सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता कहती थी)? इसके बाद दूसरा प्रश्न यह था कि बैंक के डाइरेक्टर-मण्डल का निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होंगे और कितने चुने जायेंगे और कैसे? यदि एकवार यह तय हो जाय कि बैंक का संगठन कैसा होगा तो शेष प्रश्न स्वयं हल हो जायेंगे। यदि बैंक हिस्सेदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को चुनेंगे; लेकिन यदि बैंक सरकारी होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी बैंक व केन्द्रीय व प्रान्तीय कौंसिलें आदि सस्यायें करेंगी। किस सस्या को कितने डाइरेक्टर चुनने का

अधिकार होगा, इसके पचड़े में पड़ना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इस बात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरो में से ९ चुने हुए हों। लेकिन अब सन् १९३४ में जो रिजर्व-बैंक-एक्ट बना है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रखे गये हैं और सो भी इनका चुनाव चार-साal में आकर होगा। अब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कदम पर रद्दोबदल किया गया। अन्त में श्री श्रीनिवास आयरर के प्रस्ताव पर सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई कि बैंक स्टॉक-होल्डरो का हो, अर्थात् बैंक की पूँजी तो सरकार लगाये लेकिन बाद में वह उस पूँजी को इस प्रकार बेच दे कि किसी भी व्यक्ति को (१०,०००) से अधिक की पूँजी अर्थात् स्टॉक न मिले। प्रत्येक स्टॉक खरीदनेवाले अर्थात् स्टॉक-होल्डर को डाइरेक्टरो के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने उस बिल के बजाय एक दूसरा बिल पेश करने की सूचना दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कामन-सभा के प्रमुख-द्वारा निर्धारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे बिल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्तन करने हो, तो उचित मार्ग यह है कि मूल बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में दुबारा पेश किया जाय। अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने बिल को ही कायम रखने का निश्चय किया, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण अंश के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गई इसलिए सरकार ने बिल पर विचार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

सार्वजनिक-रक्षा (पब्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा बिल था, जिसपर खूब वाद-विवाद चला और जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह बिल विदेशियों के विरुद्ध काम में लाया जानेवाला था, विन्तु जनता को इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि देश-रक्षा-कानून की भाँति यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में लाया जायगा। जब बिल पर मत लिये गये तो दोनों ओर बराबर मत आये। अध्यक्ष ने बिल के विरुद्ध मत दिया और बिल गिर गया।

कलकत्ता-कांग्रेस

कलकत्ता-कांग्रेस गण्टीय सम्मेलनो में एक बड़े महत्त्व का सम्मेलन था, क्योंकि उमें कांग्रेस का भावी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्त्व के कारण पण्डित मोतीलाल

नेहरू उसके सभापति चुने गये। इसके साथ सर्व-दल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलान कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साउमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिन समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पण्डितजी ने सभापति के अपने अभिभाषण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, लाहौर व लखनऊ में, कितने जोग के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो-इण्डियनों के दिमाग पर क्या असर किया। कलकत्ते के कुछ गोरे अपवार तो यह सलाह तक देने लगे कि कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में फोल्दादी शासन किया जाय और जबतक एक रतीभर भी गोला-बारूद रह जाय तब तक भारतीय-स्वतन्त्रता की माग का मुकाबला किया जाय। पण्डितजी ने जोरदार बन्दो में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिनका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है। आगे पण्डितजी ने इस बात पर जोर दिया कि "सर्व-दल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुँच गया है यही से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए और जहातक हम जा सकें वहातक उसे हमारा साथ देना चाहिए।"

कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों तथा सन्यासियों की सहानुभूति के संकेतों सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती सरोजिनी नायडू के, श्रीमती सनयात सेन, मोसिये रोम्या रोला के और फारस के समाजवादी दल व न्यूजीलैण्ड के कम्युनिस्ट-दल के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत के भविष्य के बारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के अलावा प्रस्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे। विदेशों से आये सन्देशों व बधाइयों के उत्तर में विदेशी मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश व बधाइया दी गईं और महासमिति को आदेश दिया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मिस्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया और मद्रास-कांग्रेस के 'युद्ध के खतरे' वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। ब्रिटिश-माल के बहिष्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। बारडोली की शानदार विजय पर सरदार वल्लभभाई पटेल को बधाई दी गई। सरकारी उत्सवों व दरबारों तथा सरकारी अधिकारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सब

सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवों में भाग लेने की कांग्रेस-वादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा मांग की गई। चूंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को लेकर देश में खूब आन्दोलन उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महत्त्व अब बढ़ गया है, इसलिए इसे हम यहाँ ज्यों-का-त्यों देते हैं —

“यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-संगठन के, स्वतन्त्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान-माल की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर दिया जाय।”

नाभा के भूत-मूर्त नरेश के साथ सहानुभूति बिखालते हुए इस साल भी एक प्रस्ताव पास किया गया। जिन पाच बंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवारवालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। लाहौर में पुलिस-द्वारा किये गये धावों व खानातलाशियों की निन्दा की गई। लाला लाजपत राय, हुकीम अजमलखा, आन्ध्र-रत्न श्री गोपाल कुर्णैया, श्री भगनलाल गाधी, श्री गोपबन्धु दास और लॉर्ड सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया।

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार था —

“सर्व-बल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो तजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसे भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती है, और अपनी सब मिफारियों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बधाई देती है। और यद्यपि यह कांग्रेस मदरास-कांग्रेस के पूर्णस्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा पग मानकर उसे मजूर करती है, खासकर इस विचार से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों में जितना अधिक-से-अधिक मतैक्य हो सका है उसका बड़ा सूचक है।

“अगर ब्रिटिश-पार्लियामेंट इस विधान को ज्यों-का-त्यों ३१ दिसम्बर १९२६ तक या उसके पहले स्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक

पार्लमेण्ट उसे मजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामजूर कर दे तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करो का देना बन्द कर दे और उन अन्य तरीको-द्वारा, जिनका वाद में निवचय हो, अहिंसात्मक असहयोग का आन्दोलन सगठित करेगी।

“कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाधा नहीं डालेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।”

खुले अधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ वह तो ऊपर दिया जा चुका है, लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १९२६ के बदले ३१ दिसम्बर १९३० तक की सीमाद थी तथा नीचे लिखा टुकड़ा था, जो वाद में हटा लिया गया —

“समापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिकृति और रिपोर्ट की प्रति बाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वह उस पर अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहें कर सकें।”

भावी कार्यक्रम

कलकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यक्रम भी निर्धारित किया —

“इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा—

(१) सब नवीली चीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कौंसिलो के भीतर और बाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी। जहाँ कहीं भी उचित और सभव हो वहाँ शराब, अफीम आदि की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रवन्ध किया जायगा।

(२) हाथ की कत्ती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तेमाल का प्रतिपादन करके विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने के लिए कौंसिलो के भीतर और बाहर स्थान व अवस्था के अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायेंगे।

(३) जहाँ कहीं लोगो को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हो तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिंसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में बारडोली में किया गया था।

(४) कांग्रेस की ओर से कौंसिलो के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अधिक समय कांग्रेस-कमिटी द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा।

(५) नये सदस्यों की भर्ती करके और कड़ा अनुशासन उसके कांग्रेस-संगठन को सुदृढ़ बनाया जाय।

(६) स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित किया जायगा।

(७) देश की सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

(८) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता है करे और अशुद्ध कहे जानेवालों को उनकी अयोग्यताएँ दूर करने और अपनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में यथासम्भव सहायता दे।

(९) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और खर्च और सद्व्यवहार के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे।

(१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में बटाने के लिए और राष्ट्रीय प्रयत्न में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में लगे हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब कार्य किये जायेंगे जो उचित समझे जायेंगे।

“कांग्रेस हरेक कांग्रेसवादी से आशा करती है कि वह उपर्युक्त कामों का खर्च चलाने के लिए यथाशक्ति अपनी आमदनी का कुछ भाग कांग्रेस-कोष को देता रहेगा।”

कलकत्ता-कांग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव साम्राज्य-विरोधी सच के मि० डब्ल्यू० जे० आन्स्टन के सम्बन्ध में था, जिन्हें सच ने भिन्न-प्रतिनिधि के रूप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाये देश-निकासी देने पर सरकार की निन्दा की गई और यह मत प्रकट किया गया कि “सरकार ने यह कार्रवाई जान-बूझकर कांग्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बढ़ने से रोकने के इरादे से की है।”

कलकत्ता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरों-द्वारा किया गया प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिल-खानों के रहनेवाले मजदूर सुव्यवस्थित रूप से एक जुलूस बना कर कांग्रेस-नगर में घुस आये और राष्ट्रीय-झण्डे की सलामी करके पडाल में आ गये और दो घंटे तक अपनी सभा करते रहे। ‘भारत के लिए स्वतन्त्रता’ का प्रस्ताव पास करके वे लोग पडाल छोड़कर चले गये।

देश में मुक्त-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी।

देश में जगह-जगह युवक-सघ व छात्र-सघ बन गये। बम्बई व बंगाल में तो उनका घटा जोर था। अगस्त मास में हालैण्ड में यूट स्थान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन सस्थाओं में से कुछ ने प्रतिनिधि भी भेजे। युवको ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहिष्कार-प्रदर्शनो में भी खूब भाग लिया था। लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडों की मार तो खास तौरपर उन्होंने खाई थी।

हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने कर्नाटक प्रान्त में बागलकोट में एक व्यायाम-शाला स्थापित की। उसने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई ट्रेनिंग-कैम्प खोले और मिहनत का मोटा-सोटा काम करने में नाम पा लिया।

गांधीजी की ओर

अब हमें पाठको को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता-कांग्रेस में कैसे आ फसे। याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद-कांग्रेस के बाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह १९२२ की गया-कांग्रेस, सितम्बर १९२३ के दिल्ली के विरोध-अधिवेशन और १९२३ के कोकनडा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न हो सके। ५ फरवरी १९२४ को वह छूटे और बेलगाव-कांग्रेस के सभापति बने। कानपुर-कांग्रेस में स्वराज्य-पार्टी ने साझेदारी—या जो कुछ कहिए—के पटना के निर्णयों पर कांग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही वह आये थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की क्षपय खा ली और गोहाटी में उमने पूरा कर दिया। गोहाटी में उन्होंने कांग्रेस के बहस-मुवाहसों में सक्रिय भाग लिया, लेकिन मदरास में तो वह विलकुल उदासीन रहे और विषय-समिति की बैठकों में भी भाग नहीं लिया। यह बात सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-कांग्रेस के अधिवेशनो में भाग लेंगे या नहीं। कुछ वर्षों से वह कांग्रेस के सालाना अधिवेशनो के पहले एक मास वर्षा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में दिसम्बर १९२८ में होने ही वाला था, वह वर्षा में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्वागतार्थ ३६ घोड़ों की गाड़ी में बिठाकर गहर में जुलूस में निकाला गया था, अपने-आपको बड़ी विकट परिस्थिति में पाने लगे। लखनऊ में सर्व-दल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके औपनिवेशिक-स्वराज्य के विरोध में और स्वतंत्रता के पक्ष में घोषणा की थी, वे भी वहा मौजूद थे और उन्होंने अपना स्वाधीनता-सघ भी बना लिया। इनमें जवाहर-

लाल भी शामिल थे। वगाल ने अपना मध जलग बनाया था और श्री मुभापचन्द्र वनु उसके मुखिया थे।

सर्व-दल-सम्मेलन के बारे में भी एक मन्द इस समय कहना बाकी है। सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ, नुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को धिक्कारा। चबर श्री जिन्ना भी, जो अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे। कुछ मुसलमान पहले ही उनकी मुलाकफन बाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने लीग की बैठक स्थगित कर दी। कलकत्ते में सर्व-दल-सम्मेलन रोग-ग्रस्त पर या वो कहें कि मृत्यु-ग्रस्त पर पहुँच चुका था। जितना ही अधिक वह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, नागें बटती जाती थीं। उसकी हालत सावरम्ती के बछड़े की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता था और न वह मरता ही था। उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी। गांधीजी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुँचा सकता था। गांधीजी के अलावा इन मरते हुए जीव की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किममें थी? अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पास हो गया। अब कांग्रेस निश्चित रूप से गांधीजी की ओर झुक रही थी, लेकिन वह अपने खुद के बड़े बोझों से लड़ी हुई थी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कॉमिल-पार्टी कॉमिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या-क्या करने को तैयार है। दिल्ली में अक्टूबर १९२८ में महासमिति कॉमिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी :—

यह समिति कुछ के साथ इन बात को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कॉमिल-दलों ने कॉमिल-कार्य के सम्बन्ध में मद्रास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए विषम परिस्थिति को देखकर अद्यपि कांग्रेस के कॉमिल-दलों को अधिक स्वतन्त्रता दी गई थी तथापि समिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रखी जायगी।”

इन प्रस्ताव में चार परम्पर-विरोधी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। पहले निन्दा, फिर उनकी दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुवाहम और फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद।

गांधीजी बलवत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में जब भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई और उन्हें मानने लाये। गजनीनिक बानावण्ड इन समय बहुत

अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियों पर मुकदमे चलने की अपवाह, वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, “फारवर्ड” के सम्पादक को सजा होना, मदरास में मुकदमों का दौर-दौरा—ये ऐसी घटनाएँ थी जिन्होंने गांधीजी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला। यद्यपि ये घटनाएँ स्वयं ही बहुत देवैनी पैदा करनेवाली थी, पर गांधीजी खास कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक वेचैन हुए, अर्थात् जान-बूझकर एक समझौते का किया जाना और फिर उसका क्रमण बगाल, युक्त-प्रान्त और अन्त में मदरास-द्वारा तोड़ा जाना। इन दोनों बातों के अलावा गांधीजी के पास यूरोप आने का भी निमन्त्रण था। परिस्थिति अनुकूल हुई तो, गांधीजी का पूरा हरादा था कि वह १९२६ के प्रारम्भ में ही यूरोप का दौरा शुरू करें। आश्चर्य की बात है कि प० मोतीलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की अनुमति दे दी थी। लेकिन खूब विचार कर लेने के बाद और मित्रों से खूब परामर्श कर लेने के बाद गांधीजी इस मतीजे पर पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हें अपना दौरा बन्द रखना चाहिए। गांधीजी ने लिखा, “मे अगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। डेनमार्क के मेरे एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना श्रेयस्कर है। मैं इस कथन की सचाई महसूस करता हूँ।” हृष्य की आवाज को पहचानकर गांधीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये, उन्होंने लिखा, “अन्तरात्मा की आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं कहती। इसके विपरीत, काप्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्वव्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूस होता है कि यदि अब मैं यूरोप चला गया तो मैं कार्य को छोड़ भागने का दोषी होऊँगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आये उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ बल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी बताऊँ और सोचू। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का स्वल्प कैसा ही हो।”

यह फरवरी १९२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें अब देखना है कि फरवरी १९३० के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या वदा था।

[चौथा भाग : १९२६-१९३०]

: १ :

तैयारी-१९२६

पब्लिक-सेफ्टी-बिल

१९२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुतः बड़ी विकट थी। इस समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेप्टेक-कमिटी भी देश में दौरा कर रही थी। इस कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिषद् के चुने हुए थे और पांच सरकार न असेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रैल १९२६ में अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीशनवाले मिलायत में पहुँचे ही थे कि मई १९२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर-दल का मन्नि-मण्डल बना। मैकडोनाल्ड साहब प्रधान मंत्री बने और जेम्स ब्रैड शेरवुड ने साहब भारत-मंत्री। लॉर्ड अविन चार भास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुँचे। इस यात्रा का उद्देश यह था कि "साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-योजना पार्लमेण्ट के समक्ष रखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।"

लॉर्ड अविन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उसपर तो हम उचित स्थान पर विचार करेंगे ही। तबतक कांग्रेस की कौंसिलो में होनेवाली लड़ाई का अध्ययन कर लें। पब्लिक-सेफ्टी-बिल जनवरी १९२६ में ही द्वारा पेश हो चुका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल में हुआ। ११ अप्रैल को अध्यक्ष महोदय ने इस बिल पर चर्चा की मनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होंने निम्न-लिखित वक्तव्य दिया —

"पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर मिलेकट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने में पहले में दो शर्तें कहना चाहता हूँ। असेम्बली की पिछली बैठक के समय से ही

मैंने दो बातों पर परिश्रम-पूर्वक गौर किया है। इनमें से एक तो है पब्लिक-सेफ्टी-विल पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण, और दूसरी बात है मेरठ की अदालत में ३१ व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का दावा। इसके अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस विल का और इस मुकदमे का आधार एक ही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी कार्रवाई के नियमों में एक यह भी है कि साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराधीन है तो उसके विषय में न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। अतः यह सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई हवाला दिये बिना इस सभा में पब्लिक-सेफ्टी-विल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं? मेरी समझ से इन मामले में दो रायें नहीं हो सकती कि इस विल पर वास्तविक चर्चा होना असम्भव है। साथ ही विल को स्वीकार करने का मतलब उस मुकदमे के मूल-आधार को स्वीकार करना होगा और विल को अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमे के आधार को अस्वीकार करना होगा। दोनों ही दशाओं में मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा, भले ही बादी बाटे में रहें या प्रतिवादी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक में इन समय सरकार को इस विल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। इसलिए बजाय निर्णय देने के मैंने सरकार को यह सलाह देने का निश्चय किया है कि प्रथम तो मेरी बलीखो पर ध्यान देकर वह स्वयं मेरठ का मुकदमा खतम होने तक इस विल को स्थगित कर दे, और यदि वह इसी समय विल का पाम होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और विल का मामला हाथ में ले।”

सरकार ने दोनों में से एक भी बात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि “यह इस सभा की कार्यप्रणाली और शिष्टाचार विरुद्ध है” इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे ही दिन बाइमराय माहल ने दोनों बारा-समावशों में भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफ्टी-विल में प्रस्तावित अधिकारों का अविलम्ब प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तदनुसार उन्होंने एक विशेष आज्ञा (आर्डिनेन्स) निकालकर अधिकारियों को, जैसी वे चाहते थे, अनिवारित सत्ता दे दी।

ट्रेड-डिस्प्यूट-विल अर्थात् मजदूरी और मालिकों के झगड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का जिक्र ऊपर आ चुका है। इस बारे में इतना कहना बाकी है कि यह विल ८ अप्रैल को पास हुआ और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी

हो गई। घटना यह हुई कि जब राय लेने के बाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अध्यक्ष आगे की कार्यवाही की घोषणा कर रहे थे उसी समय दर्शकों के झरोके में से सरकारी पक्ष के बीच में दो बम आकर गिरे और उनके फटने से कुछ लोग जरा घायल हो गये।

उपसमितियाँ

कांग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने कांग्रेस के निश्चयों को कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-समितियाँ बनाईं। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्रव्यों के निषेध, अस्पृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वयं-सेवकों और स्त्रियों की बाधाओं को दूर करने के लिए कमिटियाँ नियुक्त की गईं। मालूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

स्वयं-सेवकों-सम्बन्धी उपसमिति ने कई निष्कारिणों की। उसकी खान सूचना यह थी कि हिन्दुस्तानी-सेवादल को बूढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के लिए स्वयंसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थे गांधीजी और मंत्री थे श्री जयरामदास दीक्षितराम। यह समिति वर्षभर काम करती रही। बहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त हलचल रही। बहिष्कार के काम में अपना सारा समय लगाने के लिए श्री जयरामदास ने बम्बई-कौंसिल का सदस्य-पद छोड़ दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादक-द्रव्य-निषेध-समिति का काम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ में था। इन्होंने इस कार्य को अपना खास विषय बना लिया और इस आन्दोलन की सफलता के लिए अपनी महान् योग्यता का पूरा उपयोग किया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण-भारत और गुजरात में हुआ। सफलता भी अच्छी मिली। इस आन्दोलन की ओर विदेशों तक का ध्यान आकर्षित हुआ। नवो के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार लाख रुपया खर्च करने को राजी हो गई। युक्तप्रान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्यवाही की आशा हुई। श्री राजगोपालाचार्य भारतीय मद्यपान-निषेध-संघ के मंत्री हुए और उसके अंग्रेजी त्रैमासिक मुख-पत्र 'प्रॉहिबिशन' का सम्पादन करते रहे। अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन का काम श्री जमनालाल बजाज के सुपुर्द किया गया। इन्होंने भी काफी परिश्रम किया। जो लोग दीर्घकाल से बलित रक्खे गये हैं उनकी

बाधाएँ दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत जाग्रत किया गया। जहाँ दलित-जातियो को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति को बहुत से कुएँ और पाठशालायें भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्युनिसिपैलिटियो ने इस कार्य में सहयोग दिया। समिति के मंत्री श्री जमनालाल बजाज ने मदरास, मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, पंजाब और सीमाप्रान्त में लंबे प्रवास किये। कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

गांधीजी पर जुरमाना

कौंसिलो की सितम्बर की बैठको की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायें वर्णन कर देना आवश्यक है। गांधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। वहाँ बिबेची कपटे की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १९२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आज्ञाभंग की या आज्ञा-भंग में सहायता दी। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर चास-फूस आदि न जलाया जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ल्स टैगार्ट ने कलकत्ता-पुलिस के कानून की ६६ वीं धारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य को सविनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। गांधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। उसके बाद उन्होंने आन्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास में खट्टर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये। थोड़े दिन बाद मई १९२६ में महासमिति की बम्बई में बैठक हुई।

बम्बई में महासमिति

बम्बई की बैठक जरा महत्त्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि असेम्बली का कार्य-काल बढ़ाया जायगा। इस बात पर भी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत थी। इधर देज-भर में गिरफ्तारियों का ताता बढ़ गया था, कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्बमूर्ति पकड़ लिये गये थे और पंजाब में घोर दमन-चक्र चल रहा था। इससे यह सन्देह होता था कि शायद और बातों के साथ-साथ इनका उद्देश्य लाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में बाधा डालना भी हो। इन सब कारणों

से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। अतः बम्बई में यह निश्चय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटीयों में प्रान्त की समस्त जन-संख्या के $\frac{1}{3}$ फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिए और प्रान्तीय-कमिटी में कम-से-कम आठ जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिला और तहसील-कमिटी में आबादी के कम-से-कम $\frac{1}{3}$ फी सदी चार आनेवाले सदस्य होने चाहिए और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फी सदी। कार्य-समिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन न करे उसका सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के हित के लिए वह जो उपाय उचित समझे उनका पालन असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलों के कांग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके। पूर्व-अफ्रीका के विषय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि वहाँ भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में कांग्रेस पूरी हिमायत करे। समिति ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार करावे जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के अन्तर्गत जिन राजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समावेश होता है उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हो। इसके लिए महासमिति को आवश्यक खर्च करने का अधिकार दिया गया।

डॉ० सनयातसेन के मृत्यु-संस्कार के समय भिखु उत्तमा को कांग्रेस की ओर से उपस्थित रहने का जो अधिकार अध्यास ने दिया था उसका कार्य-समिति ने समर्पण किया। श्री शिवप्रसाद गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-संघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया। धारा-सभाओं में कांग्रेसी बल के बारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि "बंगाल और आसाम के सिवा बड़ी या अन्य प्रान्तीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कौंसिलों की भी बैठक में अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक में तबतक शामिल न होंगे जबतक कि महासमिति या कार्य-समिति दूसरा निर्णय न करे। यह भी निश्चय हुआ कि कांग्रेसी सदस्य अबसे अपना सारा उपलब्ध समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही लगायेंगे। हा, बंगाल और आसाम की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के बाद अपने नाम दर्ज कराने मात्र के लिए सिर्फ एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।"

मेरठ-प्रद्युम्न-फेस

२० मार्च १९२६ के दिन बम्बई, पंजाब और मध्य-प्रान्त में ताजिखत-हिन्द

की १२१ व बारा के अनुसार सैकड़ों घरों की तलाशी ली गई। जो लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें महासमिति के ८ सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तों पर अपराध साम्यवादी प्रचार का लगाया गया था। आगे चलकर "न्यू स्पार्क" के सम्पादक मिस्टर एच० एल० हर्चिसन भी अभियुक्तों में शामिल कर दिये गये। अभियुक्तों की सहायता के लिए, एक सेंट्रल डिफेंस-कमिटी भी बनाई गई। इसमें मुख्यतः बड़े-बड़े कांग्रेसी ही थे। कार्य-समिति ने अभियुक्तों की सफाई के लिए अपनी साधारण परिपाटी छोड़कर भी (१५००) की रकम मजूर की थी। इस मुकदमे में प्रारम्भिक तफ्तीश में ही कई महीने लग गये और वर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंग्लैंड में इस मुकदमे ने बड़ा नाम पाया। मुकदमे के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सम्बालक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खुद देख-भाल रखते थे।

१५ जुलाई को दिल्ली में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई। समिति ने राय दी कि भिन्न-भिन्न कौंसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही स्वराज्य-आन्दोलन का काम है। परन्तु इस प्रश्न के महत्त्व को देखते हुए कार्य-समिति ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमिति को ही करना चाहिए। इसलिए यह निश्चय किया गया कि शुकृवार २६ जुलाई १९२९ को प्रयाग में महासमिति की विशेष बैठक बुलाई जाय। स्मरण रहे कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताव की अन्तिम बारा में लोगों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग कांग्रेस को दें। पहले-पहल ५ फी सदी रक्खा गया और बाद में २१ फी सदी, परन्तु फिर समिति ने यह मामला लोगों की इच्छा पर ही छोड़ दिया। जुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूची प्रकाशित की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सब मिलाकर बहुत थोड़ा रकमा प्राप्त हुआ था।

दमन-चक्र जारी

देश में यह बड़ा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ० स्पेन्डरलैंड को "इंडिया इन वॉण्डेज" नामक पुस्तक को निषिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में 'मॉडर्न-रिव्यू' के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अमेम्वली-बम-केस के अभियुक्त श्री भगतसिंह और दत्त को आजन्म काले-मानी की सजा दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था। लाहौर पदयन्त्र-केस के अभियुक्तों की भूख-हड़ताल का वर्णन विस्तार से

किया ही जा चुका है। कलकत्ते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्य-समिति के सदस्य श्री सुभाषचन्द्र बसु और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। गार्ड से और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे।

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्ताओं को सजाये दी ही जा रही थी। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके भी इस्तेमाल कर रही थी जिन्हें महासमिति ने जगली बताया। एक अवसर पर लाहौर के अभियुक्तों की सफाई के लिए बल एकत्र करनेवाले सात युवकों को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमें से कुछ बे-सुख तक हो गये। चोटों तो सभी को गहरी लगी। उनका अपराध था 'साम्राज्यवाद का तावा हो' और 'क्रान्ति अमर हो' के नारे लगाना। लाहौर-पब्लिश के अभियुक्तों के साथ इससे भी अधिक पाषाणिक व्यवहार किया गया। वे न्यायाधीश के सामने जुली अदालत में पीटे गये—और, कहा जाता है कि, अदालत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की बात नहीं है कि भारत के भिन्न-भिन्न जेलों में और अण्डमान-निकोबार में बहुत-से लम्बी सजाभोगवाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेग्युलेशन के शिकार नजरबन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे। इन कैदियों को १९१९ में पंजाब के फौजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतों ने सजाये दी थी। इनके सिवा जेलों में २७ राजनैतिक कैदी थे भी थे जिन्हें युद्धकाल में, अर्थात् सन् १९१४-१५ में, काले-पानी की सजायें दी गई थी। इनके मुकदमे भी विशेष कमीशन के सामने हुए थे, मामूली अदालतों में नहीं। इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे।

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौण्ड मासिक की रकम इसलिए मञ्जूर की कि बर्लिन में भारतीय छात्रों को सलाह और सहायता देनेवाली एक समिति स्थापित की जाय।

कलकत्ता-कांग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य-समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मंत्री को दे दिया। वह स्वयं इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर के कारण विदेशों से पत्र-व्यवहार रखने में अनेक बाधाएँ आती थी।

महा-समिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की छाखा के रूप में ही मजदूरो-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए एक अनुसन्धान-विभाग भी खोला गया।

हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयंसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में किया। अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ। वही दल का दफ्तर और व्यायाम-मन्दिर भी था। परन्तु दल की छावनियाँ देश के अन्य भागों में भी बहुत थी और शिक्षकों की माँग इतनी रही कि पूरी न की जा सकी। कांग्रेस के सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के काम में दल ने बड़ी मदद दी। लाहौर-कांग्रेस के लिए चूस्त स्वयंसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा सहयोग दिया। मासिक झण्डाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को आशातीत सफलता मिली। दल ने फलफले में निश्चय किया कि हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह ८ बजे देशभर में राष्ट्र-ध्वज फहराया जाय। मासिक झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूब लोकप्रिय हुआ। बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियों ने भी अपनी इमारतों पर विभिन्न-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये। हिन्दुस्तानी-सेवादल की पुनर्रचना की गई।

यतीन्द्र का अनशन

पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकला। नेताओं की गिरफ्तारियाँ सर्वत्र जारी रही। पंजाब में सरदार भगलसिंह, मौलाना अफरमलीखा, मास्टर मोतासिंह और डॉ॰ सत्यापाल तथा आन्ध्र-देश में श्री जल्लपूर्णध्या पकड़े गये। मास्टरजी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा काटकर निकले ही थे। डॉ॰ सत्यापाल को दो वर्ष की कड़ी कैद मिली। पंजाब में दमन का जोर खास तौर पर रहा। बाहर तो लोग यों पकड़े ही जा रहे थे, जेलों के भीतर भी अत्यन्त कठोरता का व्यवहार किया जा रहा था। श्री भगतसिंह, दत्त और अन्य कई कैदियों की भूख-हड़ताल को इस समय तक डेढ़ महीना हो चुका था। श्री भगतसिंह और दत्त को हाल ही में असेम्बली-बम-केस में तो आजीवन काले-पानी की सजा हुई थी। ये दोनों लाहौर-पड़्यन्त्र के मुकदमे में भी अभियुक्त थे। हा, पीछे से श्री दत्त को इस मुकदमे में छोड़ दिया गया था। यह मुकदमा लाहौर-पुलिस के मिस्टर साडर्स नामक अफसर की हत्या के कारण हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १९२८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख-हड़ताल का उद्देश्य कुछ कष्टों का निवारण और खास तौर पर कैदियों के लिए मनुष्योचित व्यवहार की प्राप्ति करना था। अनशन करनेवालों में विख्यात श्री० यतीन्द्रनाथ दास

मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की शिकायत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैदियों के साथ भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन भूल-हड़तालियों को जो खास रियायतें दी गई थी, उनकी यतीन्द्र ने कुछ परवा नहीं की और मैक्सवनी की भांति अकेले ही भूल-हड़ताल पर अन्त तक डटे रहे और चौंसठवें दिन चल बसे।

प्रयाग में महासमिति की बैठक के अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई। इस बैठक में महासमिति ने कार्य-समिति के इन मत का समर्थन किया कि कौंसिलो के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे देने चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विषय को लाहौर-कांग्रेस के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाई की गई हो।

पंजाब की भूल-हड़ताल का उल्लेख सक्षेप में उमर किया गया है। इन हड़तालों से सरकार हैरान हुई। उसने सोचा कि ये हड़तालें लाहौर-पब्लिक केस में पुलिस को तग करने के अतिप्राय से की गई हैं। अतः १२ नितम्बर १९२६ को सरकार ने असेम्बली में एक बिल पेश किया। इस बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही कृत्यों से अपने को अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ बना लें तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई जारी रह सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह बिल पेश किया कि इस बिल पर बड़ा मतभेद है, यह मजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पब्लिक-केस के बारे में एक आर्डिनेन्स निकाल दिया।

लाहौर-कांग्रेस का समापन

भविष्य के गर्भ में बड़ी-बड़ी घटनाएँ छिपी थीं। लाहौर-कांग्रेस के लिए समापति के प्रश्न पर दस प्रान्तों ने गांधीजी के लिए, पांच ने श्री बल्लभभाई पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांधीजी का चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। विधान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ। अतः २८ सितम्बर १९२६ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई। सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे विजय-पथ पर अग्र

- कर सकते थे। कौंसिलो और उनके कुछ सदस्यों से पण्डित मोतीलाल जैसो का भी चक्का उठना छिपा नहीं रह गया था। यह मकेत स्पष्टतः आ चुका था कि कौंसिलो की मेम्बरी छोड़ दी जाय, पर आगे क्या किया जाय? सविनय-अवज्ञा के सिवाय चारा ही क्या था? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांधीजी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे? उन्हें पहले भी दवाया गया था। लखनऊ में उनपर फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले लें। परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही विठाने की सलाह दी जिसपर देश के युवक-हृदयों की अछा हो। गांधीजी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल को समापति बनाना उचित समझा। नवयुवकों को कांग्रेस की नीति रीति भीमी और सुस्त भावपूर्ण होती थी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका भूत किसी नौजावन के हाथ में देना ही उचित है। श्री बल्लभभाई ने गांधीजी और जवाहरलालजी के बीच में जाना पसन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थिति अधिक नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से ५० जवाहरलाल को चुन लिया।

लखनऊ-महासमिति

लखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था श्री यतीन्द्र नाथ दास और फुली विजया के देहावसान का। इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के अनशन से और दूसरे ब्रह्मदेश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। मिस्रु विजया एक बौद्ध साधु थे। वह राजद्रोह के अपराध में २१ मास का कठोर कारावास भुगतकर २८ फरवरी १९२६ को ही छूटे थे। इसके सवा मास बाद ही अर्थात् ४ अप्रैल को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। बाद में घटाकर यह सजा ३ वर्ष कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय बाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने और विशेष अवसरों पर मिस्रुओं के भगवाँ बस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनशन आरम्भ किया। यह तप १६४ दिन के बाद १९ सितम्बर १९२६ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीन्द्रनाथ दास का देहावसान इससे छ दिन पूर्व अर्थात् १३ सितम्बर १९२६ को, हो चुका था। इस प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशभक्तों ने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र के स्वामिमान के रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में भातम छा गया और देशवासियों के हृदय उनकी प्रशंसा से गद्-गद् हो गये। स्थान-स्थान पर विशाल प्रदर्शन हुए। कलकत्ते

का जुलूस तो अनोखा ही था। इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहानुभूति-नूचक सन्देश आये। आयरलैण्ड के मैकिस्वनी-परिवार का पैगाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था।

यहाँ उस प्रस्ताव का बिक्र करना आवश्यक है जो २८ सितम्बर की लगनअ में महासमिति ने जेल में होनेवाले अनसनो के विषय में पास किया। समिति ने इन बन्धियों के उद्देश की हादिक प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गभीरतम परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना भूख-हड़ताल नहीं करनी चाहिए। समिति ने यह भी सलाह दी कि चूँकि श्री दास और श्री बिजया के आत्म-बलिदान हो चुके हैं, सरकार ने भी अन्तिम वक्त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली हैं और पूर्ण कष्ट-निवारण के लिए प्रयत्न जारी हैं। अतः अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या खतम कर देने की चाहिए।

लॉर्ड अर्विन की घोषणा

अक्तूबर का महीना घटनापूर्ण था। लॉर्ड अर्विन बिलायत जाकर २५ अक्तूबर को लौट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने पहली नवम्बर को दिल्ली में कार्य-समिति की जरूरी बैठक बुलाई। समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजधानी में अन्य दलों के नेता भी उक्त घोषणा को सुनने और उसपर सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे। जून १९२६ के अन्त में इंग्लैण्ड में खाना होने समय लॉर्ड अर्विन ने कहा था, "बिलायत पहुँचकर मैं ब्रिटिश-सरकार से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के अवसर बूझा। जैसा मैं अन्यत्र कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि हैं उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों को ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कर्तव्य होगा।" इसके बाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोषणा और सम्राट्-द्वारा दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र या हुक्म दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राट् ने कहा था—“हमारी अर्धोपरि इच्छा और प्रयत्ना इसी में हैं कि हमारे साम्राज्य का अग्रगण्य रहने हुए ब्रिटिश-भाग को प्रथम उत्तम-दायी शासन-प्राप्ति के लिए पार्लैमेण्ट ने जो योजना बनाई है वह उस प्रकार बन हो कि हमारे उपनिवेशों में ब्रिटिश-भारत को भी अपने योग्य स्थान मिले।”

लॉर्ड अर्विन ने अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा में कहा—“शासन-समीक्षा के अध्ययन ने प्रधान-मंत्री के साथ अपने परामर्श-पत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों को है। पहली बात तो यह कि आये चलकर ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों के शा-

स्परिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? अध्यक्ष महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर मरदार-द्वारा बतनेवाली योजना में यह बृहत् समस्या शामिल करनी हो तो फिर अभी से कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रस्ताव है कि साइमन-कमीशन और मेम्लु कमीटी की रिपोर्टों पर विचार होकर जब वे प्रकानित कर दी जायें और पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की सम्मिलित समिति नियुक्त हो उसमें पहले ब्रिटिश-सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए, जिससे सरकार की ओर से पार्लमेण्ट के सम्मुख पैदा होनेवाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त हो सके। भारतीय धारा-सभाओं एवं अन्य संस्थाओं की सलाह लेना तो ज्वाण्ट पार्लमेण्टरी कमीटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परन्तु इसका अवसर तब आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल के रूप में पार्लमेण्ट के सामने आवेगी। किन्तु कमीशन की राय में इसमें पहले पूर्वोक्त ढंग की परिपक्व बुलानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारों में पूर्णतः सहमत है। अगस्त १९१७ की घोषणा में ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्व-शासन-सम्पाओं का क्रमशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्तु १९१६ के सुधार-कानून का अर्थ लगाने में विनियत और भारत दोनों ही देशों में ब्रिटिश-सरकार की इच्छाओं पर सन्देश दिया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।”

यह घोषणा तो हुई ३१ अक्टूबर को और २४ घंटे के भीतर पण्डित मालवीय, सर तेजबहादुर सप्रू और डॉ० वेनेण्ट आदि बड़े-बड़े लोग दिल्ली आ पहुँचे। कांग्रेस की कार्य-समिति तो वहाँ थी ही, गङ्गमौर विचार के पश्चात् इस सम्मिलित-सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश-सरकार की घोषणा की सचाई की ओर भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई।

इस वक्तव्य में कहा गया कि “हमें जाना है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल औपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में विश्वास

सत्य करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यों का किया जाना और कुछ बातों का साफ होना जरूरी है।

“प्रस्तावित परिषद् की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि—

(क) वातावरण को अधिक शान्त करने के लिए समझौते की नीति अस्तिथार की जाय।

(ख) राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें।

(ग) प्रतिनिधी राजनैतिक सत्यागो को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबसे बड़ी सत्या होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जायें।

(घ) औपनिवेशिक दलों के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा में सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या हैं, इस विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है किन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद् औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने को नहीं बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का विधान तैयार करने को आमन्त्रित की जायगी। हमें आशा है कि वाइसराय महत्त्वपूर्ण वक्तव्य का यह भावार्थ और फलितार्थ लगाने में हम भूल नहीं कर रहे हैं। जबतक नये विधान पर अमल शुरू न हो जबतक हमारे खयाल से यह आवश्यक है कि देश के वर्तमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रबन्ध-विभाग एवं कौंसिलो का प्रस्तावित परिषद् के उद्देश्यों के साथ मेल बिठाना चाहिए और सब उपायों और प्रणालियों का अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मति में बनता को यह अनुभव कराना अत्यावश्यक है कि आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है और नया विधान केवल इस भावना पर मुहर लगावेगा।

“अन्त में परिषद् की सफलता के लिए हम इसे एक आवश्यक बात समझते हैं कि परिषद् जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाय।”

निस्सन्देह इस नये रविवे का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टि-कोण था। इस दृष्टि में अंग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर डाल रहे थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें।

गांधीजी का उत्तर

उत्तर में गांधीजी ने कहा, “मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। डीने हेतु से पहला मौका आते ही मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया है। परन्तु जैसे मैं बलकृष्ण-मित्र के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द पर कायम हूँ, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के हर्ष-

हफें पर भी अटल हूँ। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। किसी भी दस्तावेज के शब्दों में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए मैं ठहरा भी रह सकता हूँ। अर्थात् आवश्यकता इस बात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा हो, अंग्रेज लोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुतः देखना चाहें और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूर्ण हो जाय। इसका अर्थ है संगीनों के बजाय जनता के सद्भाव की स्थापना। क्या अंग्रेज स्त्री-पुरुष अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलों और तोप-बन्दूकों के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं। यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं है, तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सतुष्ट नहीं कर सकता। औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूँ तो आज ही ब्रिटिश-सम्बन्ध विच्छेद कर सकूँ। ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जबरबस्ती जैसी कोई बात नहीं चल सकती।

“यदि मैं साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ तो इसलिए नहीं कि घोषण या जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ध्येय कहते हैं उसकी वृद्धि हो, बल्कि इसलिए कि सत्ता में शान्ति और सद्भावना फैलाने की शक्ति में हिस्सा मिले।

“मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मैंने यहाँ वर्णन किया है उसपर डटे रहने की शक्ति अभी भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई है। इसलिए यदि हमें अभी वह स्थिति प्राप्त हो जाय तो यह अधिकतर ब्रिटिश-गण्ट की कृपा का ही फल होगा। यदि इस समय वे लोग ऐसी कृपा करें तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। इससे भारत के प्रति किये गये पिछले अन्यायों की थोड़ी क्षति-पूर्ति तो हो ही जायगी।”

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का वचन दिया गया था। फिर भी पार्लमेण्ट में इसीपर तूफान खड़ा हो गया। कामन-सभा को सफाई पेश करनी पड़ी। बाल्बर्न साहब को वेन साहब और लॉर्ड अर्बिन की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेवारी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साहमन को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुश्किल हो गया। लायड जार्ज साहब ने कैप्टन वेन साहब से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी नीति का जो अर्थ लगाया गया है, “क्या आपको वह स्वीकार है?” लॉन्डनरी साहब ने लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण अर्थ लगाने का अनुरोध किया। अलवत्ता भारतवासी इसे बाजार-भाव से ही आकलन चाहते थे और वस्तुतः तो

इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। हा, नरमदल वाले भारतीय इन परिपद् के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका नाम भी गोलमेज-परिपद् रखा, हालांकि लॉर्ड अविन इसे लन्दन की परिपद् के नाम से ही पुकारते रहे। कैप्टन बेन साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल दी है और पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदली। उनका कहना था कि नीति तो १९१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १९१९ के सुधार-कानून में दर्ज है, और सुधार-कानून इंग्लैंड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्धारों से युवक कांग्रेसियों में निराशा फैली।

सर्वदल-सम्मेलन

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही कार्य-समिति की बैठक हुई। ऐक्य-भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान भाषियों से भी बढकर थे। उन्हें कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टन बेन के डुमूहेपन पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल जो चित्र गीब रहा था वह ऐसा था कि भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीले और विलायतवालों को ब्रिटिश-राज्य।

वाइसराय की नेताओं से भेंट

इस 'पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पर-चिट्ठियाँ छपवा रहे थे और लॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लाहौर-कांग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खान्नी हाथ लाहीर न पहुँचना पड़े। मॉर्ट आंसन, डॉ० सप्रू के मार्फत, १७ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी अपने उत्तराल के काम में मग्न न हो सके। विलसन साहब ने अखबारों में लिखा कि वाइसराय मार्शमोरी, पण्डित मोतीलालजी और मालवीयजी ने भी इस ही मुलाकात वार्त्तापत्र हैं। दूसरे साप्ताहिक साहब १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो गये थे, इसलिए उन्होंने डॉ० सप्रू को लिखा कि अगर पहले हैदराबाद (दक्षिण) में न मिल सकें तो २३ दिसम्बर को

दिल्ली में गांधीजी और नेहरूजी से मुलाकात होगी, कुछ भी हो, बड़े दिन से पहले जरूर मिल लेंगे। लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात् २३ दिसम्बर को, दिल्ली लौट आये। उसी दिन नई दिल्ली से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उनकी गाड़ी के नीचे बम फटा। लॉर्ड अविन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनके खाने की गाड़ी को नुकसान पहुँचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गांधीजी और मोतीलालजी कांग्रेस की ओर से बाइसराय से नये मवन में मिलनेवाले थे। दूसरे विचारवालों की बात कहनेवालों में श्री जिन्ना, सप्रू और बिठ्ठलभाई पटेल थे। आशा तो यह थी कि बात-चीत मित्रों की भाँति दिल खोलकर होगी। पर हुआ यह कि एक बाजान्ता शिष्ट-मण्डल का रूप बन गया फिर भी लॉर्ड अविन ने हसते-हसते बात-चीत की। उनके दिल पर प्रातःकालीन दुर्घटना का कोई असर न था। जितने वह शान्त थे उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पीन घण्टे तक तो बम की घटना और उसके परिणामों पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉर्ड अविन ने प्रस्तुत विषय को हाथ में लिया। उन्हें राजनैतिक कैदियों से अच्छी शुरुआत करनी थी और और राजनैतिक कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सद्भाव का परिचय आसानी से दिया जा सकता था। परन्तु गांधीजी तो बाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के मसले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिषद् की कार्यवाही पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर होगी। बाइसराय साहब ने उत्तर दिया, "सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये हैं। इससे आगे मैं कोई वचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि औपनिवेशिक-स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिषद् में 'बाप लोगों को बुला सकूँ।"

लाहौर में

उत्तर-भारत के निर्दय हेमन्त में लाहौर का कांग्रेस-अभिवेशन अन्तिम था। तम्बुओं में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा कष्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्य-समिति में बैठे-बैठे हमें बार-बार पैर गरम करने पड़ते थे। किन्तु यदि बाहर इतनी असह्य सर्दी थी तो भीतर आबना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से समझौता न होने पर रोप था और युद्ध के बाजे सुन-सुनकर लोगों की बाहें फटक रही थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम्र थे उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानो उन्होंने अपने हृदय को उड़ेलकर देशवासियों के सामने रख दिया था। उसमें भारत के अपमान पर श्लोक भरा था। उसमें उन्होंने

भारत को स्वतन्त्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शों और सफल होने के अपने दृढ़-निश्चय को व्यक्त किया था।

औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए बेन साहब नसार को विश्वास दिला रहे थे कि व्यवहार में तो वह एक युग में मीजुद है। वर्सेलीज के मन्त्रिपरिषद् पर भारतवर्ष के हस्ताक्षर है, हिन्दुस्तानी हाई-कमिश्नर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्रसंघ के भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेता हिन्दुस्तानी रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमिशन में भारत को अलग मताधिकार प्राप्त है, औपनिवेशिक कानून-निर्माताओं की परिषद् में और पञ्चराष्ट्रीय जलमेन-परिषद् में भारत शामिल होता है, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-परिषद् की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ है। ये सब बातें व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्वरूप बताई गईं। परन्तु लोग ऐसे खिलौनों से घोंसे में आनेवाले नहीं थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके अनुसार उन्हें वर्तमान समस्याओं को हल करना था।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिमाषण में बताया कि बाइरराय साहब की भेष्या दीखने में समझौते का प्रस्ताव है। बाइरराय साहब का इरादा नेक और उनकी भाषा मेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन मीठी-मीठी बातों से कोई अन्तर नहीं पड़ता। हम अपनी ओर से कोई बोर राष्ट्रीय प्रश्न आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समझौते का द्वार अभी खुला है। परन्तु कंष्टन बेजबुद बेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जाल-भाज है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अध्यक्ष-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, “मैं तो साम्यवादी और प्रजासत्तवादी हूँ। मैं बादशाहों और राजाओं को नहीं मानता।” इसके पञ्चाङ्ग उन्होंने अल्प-मन्त्र्यक आतिथ्यो, देगी-राज्यों और निमानों तथा मजदूरों के तीन बड़े प्रश्नों को लिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा के प्रश्न का विवेचन किया—“हिंसा के परिणाम बहुधा विपरीत और भ्रष्ट करनेवाले होते हैं। आसकर हमारे देश में तो इसने नयानाश हो सकता है। यह विलम्ब नच है कि आज जगत् में गगति हिंसा का ही बोलबाला है। मन्मथ है हूँ मैं इनसे लाभ हो, परन्तु हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न नैयायी, और व्यक्तिगत ज्यवा व्युत्त हिंसा तो निराशा को बढ़ाकर लाता है। मैं समझता हूँ हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि में नयी, प्रभुत्व व्यावहारिक दृष्टि में विचार करते हैं; और यदि हमने हिंसा के मार्ग पर

परित्याग किया है तो मिर्क झीलिए किया है कि हमें उसके कोई सार निकालता नहीं दियाई देता। स्वतंत्रता के किसी भी बड़े आन्दोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है और जनता के आन्दोलन तो भान्त ही हो सकते हैं। हा, सगटिन विद्रोह की बात बलग है।" अन्त में उन्होंने उन मन्दों में एक महान् प्रयत्न कर देयने की अपील की—यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कब और कितनी मिलेगी। सफलता हमारे काबू की चीज नहीं। परन्तु विजय का मेहरा प्राम उन्हीं मित्र बघता है जो भाहम करके कार्यक्षेत्र में बघते हैं। जो मदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, गेमे कायरों के भाव में सफलता क्वचित् ही होती है।"

लाहौर-कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १९२७ की मदरास-कांग्रेस का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पष्टीकरण के रूप में। इस विषय पर सभापति के भाषण में कुछ बातें मजेदार थी, "हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश-प्रभुत्व और ब्रिटिश-साम्राज्य में पूर्णतः भुगत होना। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इस प्रकार भुक्त होने के बाद भारतवर्ष विषय-सब बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा तो यह किसी बड़े समूह में शामिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का कुछ हिस्सा छोड़ देने की भी राजी हो जायगा।" आगे चलकर उन्होंने कहा—“जयसक साम्राज्यवाद और उसके साथ किसी बड़े सारी सुराफान का अन्त नहीं हो जाता तयतक ब्रिटिश-राष्ट्र समूह में भारतवर्ष की बराबरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता।” उनके भाषण के कुछ अण यहाँ और दिये जाते हैं, जिनसे सम्पुरित गमझने में सहायता मिलेगी—

उन विचारों में भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू दोनों महगत थे। इस कारण लाहौर-कांग्रेस का कार्यक्रमब्यालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री यतीन्द्र दाम और श्री सुग्री विजया के महान् आत्मोत्सर्ग की प्रशंसा की गई और पण्डित गोकर्णनाथ मिश्र, प्रोफेसर पराञ्जये, श्री सवतवत्सल नायडू, श्री रोक़िणीकान्त हाथीवरवा, श्रीलाहिटी और श्री व्योमकेश चक्रवर्ती के दहायगान पर जोर प्रदर्शित किया गया। इसके बाद हाल की वम-मुर्घटना पर यह प्रस्ताव पास हुआ—

“यह कांग्रेस वाइसराय साहब की गाली पर बिले गये वम-ग्रहार पर गेद प्रकट करती है और अपने उस विस्वांग को दोहगती है कि उस प्रकार का कार्य न केवल कांग्रेस के उद्देश के विरुद्ध है बल्कि राष्ट्रीय हित की हानि पहुँचाना है। कांग्रेस वाइसराय, सेन्टी बचिन, उनके गरीब नीकरो और साथ के अन्य लोगों की भीभाग्यवण बाल-बाल बच जाने पर बघाई देती है।”

पूर्ण-स्वाधीनता

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वाधीनता के सम्बन्ध में था.—

‘औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूबर को वाइसराय साहब ने जो घोषणा की थी और जिस पर कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन को निपटाने के लिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की कद करती है। किन्तु उसके बाद जो घटनाएँ हुई हैं और वाइसराय साहब के साथ महात्मा गांधी, पण्डित मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की मुलाकात का जो गतीबा निकला है उसपर विचार करने पर कांग्रेस की यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के के शामिल होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस-विधान की पहली कलम में ‘स्वराज्य’ शब्द का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा। कांग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में वर्णित सारी योजना सतम समझी जाय। कांग्रेस आज्ञा करती है कि अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त करने पर ही लगायेंगे। चूंकि स्वाधीनता का आन्दोलन समर्थित करना और कांग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है, इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न लें और कौंसिलों और कमिटियों के मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरो को इस्तीफे देने की आज्ञा देती है। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महा-समिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहां चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सचिनय-अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्यक्रम आरम्भ कर वे।”

दूसरी बात इस कांग्रेस ने यह की कि वार्षिक अधिवेशन का समय फरवरी या मार्च बदल दिया.—

देशी-राज्यों का विषय महत्वपूर्ण था ही। कांग्रेस ने जोचा अब समय आ गया है कि भारतीय-नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आवागमन, आपण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्ति की रक्षा के नागरिक हकों के बारे में घोषणाये करें और कानून बनावें।

नेहरू-रिपोर्ट के रद्द हो जाने में साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ। कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि "स्वाधीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा सबंधा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा। परन्तु चूंकि सिकंदरों ने विशेषतः और मुसलमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणतः नेहरू-रिपोर्ट के प्रस्तावों पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी भावी विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिसमें सब पक्षों को पूर्ण सन्तोष न हो।" पार्लमेण्ट के भूतपूर्व सदस्य श्री शापुरजी मफलातवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार में परवाने मांगे वे भी नहीं दिये गये। इसपर भी कांग्रेस ने निन्दा का प्रस्ताव पाम किया।

१९२२ की गया-कांग्रेस के इतने अर्थों वाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार और उसे स्वीकार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया "इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारतवर्ष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत बरदाश्त कर सके या उसमें बरदाश्त करने की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १९२२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत किन्नी भी आर्थिक जिम्मेवारी या रियायत को, फिर मछे ही वह किसी भी प्रकार दी गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतंत्र-न्यायालय द्वारा उसका औचित्य सिद्ध हो जायगा, अन्यथा वह रद्द कर दी जायगी।" बम-बुर्बटना पर जो प्रस्ताव पाम हुआ वह आसानी से नहीं हुआ। प्रतिनिधियों के एक घाम ममूह ने उसका प्रबल विरोध किया और बहुत ही थोड़े बहुमत में प्रस्ताव पास हो सका।

कार्य-विभाग

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समितियाँ कलकत्ता-कांग्रेस के बाद फरवरी १९२६ में बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया। स्वयं सेवकों का संगठन जवाहरलालजी और सुभाष बाबू के हवाले किया गया। कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बांटा और कार्य-समिति के अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्द किया गया। किन्तु गांधीजी तो यह चाहते थे कि चर्खा-संघ की तरह ये कमिटियाँ भी स्वतन्त्र रूप से काम करने लगे। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों को

सन्देह की दृष्टि से देखा। कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उसने जो बात कही वह आज मानी जाती है। हुवा भी यही। आज अर्थात् सन् १९३५ में अस्पृश्यता-निवारण का काम एक ऐसी स्वतंत्र संस्था चला रही है जो राजनीति के ज्ञानावात से बरी है और राष्ट्र के राजनैतिक उत्तार-चढ़ाव का उसपर कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या भी इस समय बम्बई से एक-तिहाई हो गई है। जो बात गांधीजी लाहौर में नहीं करवा सके थे वही कुछ तो उनके कारावास के समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई।

कलकत्ते में राष्ट्रीय भाग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बारह मास का समय दिया गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव के इस मत-भेद-पूर्ण अंश पर रायों की गिनती खतम हुई। उस समय सारी कांग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झंडा फहराया।

सब बातों को देखते हुए लाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा और स्थिति भी नाजुक थी। गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रखे गये थे या तो काल्पनिक थे या व्यवसायिक। हरबार जो सकृन्धिता, उग्रता अथवा असहिष्णुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। बंगाल के गृह-युद्ध के कारण चुनाव-सम्बन्धी झगड़े बहुत से चले आ रहे थे। लाहौर के कांग्रेस-सप्ताह में वे और भी उग्र रूप में प्रकट हुए और सुभाष बाबू और पण्डित मोतीलालजी में कहा-सुनी भी हो गई। श्री सेनगुप्त और सुभाष बाबू में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्धा थी ही, कौंसिल-प्रवेश के मत-भेद-पूर्ण मसले पर उनका आपसी वैमनस्य और भी तीव्र रूप में सामने आया। गांधीजी ने कांग्रेस के ध्येय में 'भान्त एव उचित उपायो' के स्थान पर 'सत्य एव अहिंसा-पूर्ण उपायो' को रखवाने की खूब कोशिश की, पर उनकी बात न चली।

कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिली, यह निर्विवाद है हा, अधिवेशन के बाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयरर और सुभाष बाबू ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नये दल की स्थापना प्रोत्ति कर दी। इससे सरकार ने उस समय यह धारणा बनाई कि कांग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ है और कांग्रेस में फूट पड़ने ही वाली है। इन मित्रों की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नहीं चली तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रों के साथ उठकर कांग्रेस के बाहर चल दिये। गांधीजी अपनी परिषदी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ

लिया करते थे कि कौन-कौन म्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं ? लाहौर में कार्य-समिति दो स्वतन्त्र सचियों के आधार पर बनाई गई थी। एक सूची गांधीजी की सलाह से मोतीलालजी ने तैयार की थी और दूसरी मेठ जमनालाल बजाज ने। दोनों सूचियों में केवल एक नाम का अन्तर था। यह अन्तर ठीक कर लिया गया और कार्य-समिति बन गई। परन्तु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिए था। जब इनकी इच्छा पूरी न हुई हुई तो लठकर चले गये। दस मिनट के भीतर यह खबर सर्वत्र फैल गई और एक नया दल खड़ा हो गया। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा—
“परिस्थिति अब बहुमत के अत्याचार ने तग आकर हमने गया की भाँति कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक अलग दल बना लिया है। आशीर्वाद दीजिये कि देवायन्तु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करे।”

इधर दल के मन्त्रियों ने अपनी जानें की घोषणा में यह, कहा, “नया दल भारत की पूर्ण स्वाधीनता के अपने ध्येय को हानि पहुँचाये बिना ध्येय की पूर्ति के लिए देश के अन्य दलों से भी सहयोग करने का भरमक प्रयत्न करेगा।”

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, आकाश मेघाच्छादित, भारी और कुहरा और केवट नौसिखे थे। केवल एक बात हमारे बचाव की थी, और वह यह कि हमारा पथ-प्रदर्शक अपना मार्ग जानता था। वह भँजा हुआ कप्तान था। वह अपने नक्शे और कम्पास में सुनज्जित था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते तो सफलता हाथ में रखती थी। अन्यथा राष्ट्र की फौजी अदालत में हमपर अभियोग लगने ही वाला था।

: २ :

प्राणों की बाजी-१९३०

प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ। परन्तु तीन सप्ताह भी नहीं बीतने पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके हैं कि असहयोग के आरम्भ-काल में भी महाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र-प्रांतीय-कमिटी ने कार्य-समिति से कौंसिल-बहिष्कार का आग्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और कहा कि देश को दिल्ली की सत्ता और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिषद् में शामिल होना चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैदियों को छोड़कर सरकार ने हृदय-परिवर्तन का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल में लाना शुरू नहीं किया तो दिल्ली की सत्ता में घरा ही क्या था ?

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १९३० को हुई। पहला काम उसने किया कौंसिल-बहिष्कार के निश्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत-दाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दें और नये चुनाव में शामिल न हों। इसके परिणाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। दूसरा निश्चय कार्य-समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ जनवरी १९३० का दिन नियत हुआ। देश-भर में नगर-नगर और गांव-गांव में एक घोषणा-पत्र तैयार करके जनता के समुच्च पढ़कर सुनाना और उसपर हाथ उठाकर श्रोताओं की सम्मति लेना तय हुआ। उस दिन सुनाया जानेवाला घोषणा-पत्र यह था —

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें

और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों जिसमें हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भाग्यवानियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं किया है बल्कि उनका आधार भी गरीबों के रक्तशोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों ने सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्णस्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

“भारत की आर्थिक वण्डी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए उसमें बेहिमाव कर बसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हमें जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में बसूल किया जाता है।

“हाथ-भताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने में उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर हमें देणों की भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

“बुरी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी बढ़ गया। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों में आता है। बुरी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। हमकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा हलका करने में नहीं किया जाता बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाना है। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग में निश्चित की गई है कि जिसने देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने मिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से-बेशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी शासन की सारी प्रतिभा भारी गई है और सर्व-माधारण को गाँवों के छोटे-छोटे ओहड़ों और मुन्शीगिरी से सन्तोष करना पड़ता है।

“संस्कृति के सिंहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जब ही काट दी और हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जजीरो को ही प्यार करने लगे हैं।

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हृदयभार अवरदस्ती छीन करे हमें नामदं बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना को बड़ी दूरी तरह से कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से रक्षा की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में अनुप्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी जानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथासम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय-अवज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सबावेंगे। हमारा बृहद्विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सकें तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। अतः हम शपथपूर्वक सकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय समय पर जो आह्वानें देगी उनका हम पालन करते रहेंगे।”

गांधीजी की ११ शर्तें

स्वाधीनता-दिवस जिस दिन से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर दीखनेवाली शिथिलता और निराशा की तरह मैं कितनी असीम भावना, उत्साह और स्वार्थ-त्याग की तैयारी दबी पड़ी थी। स्वदेश-भक्ति और आत्म-बलिदान के अगारे राज-भक्ति या कानून और व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। अस्तित्व इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के लाल अगारों पर जमी हुई राख को फूक मारकर हटा दिया जाय। स्वाधीनता-दिवस का समारोह खतम ही हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया बाइसराय का भाषण भी प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आत्मावादी और विश्वासघाती राजनीतिज्ञों की रूढ़ी-सही आवाजों पर पानी फेर दिया। लॉर्ड बर्धन ने कहा —

“यह सही है कि साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में भारत

को स्वराज्यभोगी उपनिवेशों के समान कई अधिकार मिल चुके हैं। परन्तु यह भी सही है कि भारतीय लोकमत इन अधिकारों को सम्प्रति बहुत महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन अधिकारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियंत्रण तथा स्वीकृति में है। ब्रिटिश-सरकार जो परिषद् बुलायेगी वह वस्तुतः वही चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं। उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय बहुमत से हों और वह जो विधान बना दे उसे पार्लमेण्ट ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले।

“परिषद् भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने और सरकार को रास्ता दिखाने के हेतु की जायगी, योजना बनाकर पार्लमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेवारी तो सरकार पर ही रहेगी।” इस भाषण के जवाब में गांधीजी ने “यंग इण्डिया” में यों लिखा —

“बाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक बता दिया कि कि वह कहाँ और हम कहाँ हैं। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका आभारी होना चाहिए।

“बाइसराय साहब को क्या परवाह कि अबतक भारत का प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज की मजदूरी पानेवाला भिखारी न बन जाय तबतक यदि औपनिवेशिक स्वराज्य के मिलने की प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस का बस चले तो आज वह प्रत्येक भूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं दे बल्कि करोड़पति की हालत तक में पहुँचा दे। वैसे भी जब उसे अपनी कुर्दशा का पूरा ज्ञान हो जायगा और जब वह समझ जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई बल्कि वर्तमान शासन के द्वारा हुई है तो वह सगठित होकर उठ बैठेगा और अधीर होकर एक ही सपाटे में बैघ-अबैघ का ही नहीं, हिंसा-अहिंसा का भेद भी भूल जायगा। कांग्रेस को आशा है कि ऐसी दशा में वह किसानों को सच्चा मार्ग बतायगी।”

आगे चलकर गांधीजी ने लॉर्ड अविन के सामने नीचे लिखी शर्तें रखी —

- (१) सम्पूर्ण मदिरा-निषेध।
- (२) विनिमय की दर घटाकर एक शिल्लिंग चार पैसे रख दी जाय।
- (३) जमीन का लगान आधा कर दिया जाय और उसपर कौंसिलों का नियंत्रण रहे।
- (४) नमक-कर उठा दिया जाय।

(५) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फी सदी कमी कर दी जाय।

(६) लगान की कमी को देखते हुए बड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कम आधे कर दिये जायें।

(७) विदेशी कपड़े की आयात पर निषेध कर लगा दिया जाय।

(८) भारतीय समुद्र-तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय।

(९) हुत्या या हुत्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिब्यूनलों द्वारा सजा पाये हुओं के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें, सारे राजनैतिक भुक्ताने वापस ले लिये जायें, १२४ अ बारा और १८१८ का तीसरा रेंजूलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आ जाने दिया जाय।

(१०) लुफ्फा पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियन्त्रण कर दिया जाय।

(११) आत्म-रक्षाई हथियार रखने के परवाने दिये जायें, और उनपर जनता का नियन्त्रण रहे।

गांधीजी ने आगे लिखा—“हमारी बड़ी-से-बड़ी आवश्यकताओं को यह कोई सम्पूर्ण सूची नहीं है, पर देखे वाइसराय साहब इन सीवी-सादी किन्तु अत्यावश्यक भारतीय आवश्यकता की पूर्ति तो करके दिखायें। ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की बात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और जहाँ अपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपद् में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी।” इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और बरूरी मांगें पूरी न की गईं तो सविनय अवज्ञा होगी।

असेम्बली से इस्तीफे

जब असेम्बली में वाइसराय साहब ने अपना भाषण दिया, तब वसन्तऋतु थी। उस समय वातावरण सरकार के अनुकूल नहीं था, क्योंकि बस्त्र-उद्योग-रक्षण कानून उसी समय बना था। इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इनके द्वारा सरकार ने आर्थिक-परिपद् की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माये पर साम्राज्य के साथ रियायत करने की नीति छान दी है। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। वस्तुतः

कांग्रेस-आन्दोलन को इस सहायता की आशा न थी और इसलिए उसे दैविक ही समझना चाहिए।

यहां यह बयान कर देना जरूरी है कि यह कानून क्या था। साथ ही सूती कपड़े पर लगाये गये उत्पत्ति-कर और आयात-कर का इतिहास भी बताना आवश्यक है। महासमर की समाप्ति के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों में बने हुए १९ नम्बर से ऊपर के सूत और कपड़े पर ३॥ फी सदी उत्पत्ति-कर लगता था। यह कर सरकार विनो या मुनाफे पर नहीं लेती थी, बल्कि तैयार माल पर लेती थी। विदेशी कपड़े पर जो आयात-कर लगता था वह सिर्फ आमदनी के लिए था और माल की कीमत पर ७ फी सदी के हिसाब से लिया जाता था। भारतीय कारखानेवाले, व्यापारियों और नरम-दल-वालों ने अपनी युद्ध-कालीन नेवाओं का हवाला दे देकर सरकार को बताया कि युद्ध के बाद विदेशी कपड़े के आने से हिन्दुस्तानी कारखानों को बड़ा चक्का पहुँच रहा है। १९२५ में सरकार ने आयात-कर ७ फी सदी में बढ़ाकर ११ फी सदी कर देना मंजूर किया इससे विदेशी कपड़ा ४ फी सदी महंगा हो गया। स्वदेशी कपड़े का उत्पत्ति-कर भी उठा दिया गया, इससे स्वदेशी कपड़ा ३॥ फी सदी सस्ता हो गया। परन्तु इधर जनता स्वदेशी कपड़े के लाभ पर खुशिया मना रही थी, उधर १९२७ के शुरू में ही सरकार ने विनियम-कानून पाम कर दिया। इससे रुपये की कीमत १६ पैसे से बढ़कर १८ पैसे हो गई। अर्थात् जो एक पीण्ड का विदेशी कपड़ा पहले लकाशायर से १५ में पड़ता था उसके अब १३।७४ पाई ही लगने लगे। इस तरह विदेशी कपड़ा १२॥ फी सदी सस्ता हो गया। अर्थात् १९२५ में हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों को जो ७॥ फी सदी का लाभ हुआ था उसके मुकाबले में विदेशी कारखानेदारों को दो बर्ष बाद ही १२॥ फी सदी का फायदा मिलने लग गया। इस मामले पर भारत में बड़ी हलचल मची और आयात-कर में परिवर्तन की मांग की गई। सरकार ने बस्त्र-उद्योग-रक्षण कानून पास करके इंग्लैण्ड के कपड़े पर १५ फी सदी और अन्य विदेशी कपड़े पर २० फी सदी कर लगा दिया। पण्डित मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आर्थिक-परिषद् (फिस्कल कन्वेंशन) के खिलाफ बताने का विरोध किया। जापान इस समय बड़ा दूरदर्शी निकला। यह कानून तो लकाशायर के साथ जापान की स्पर्धा को रोकने के लिए बना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जानेवाले कपड़े पर जहाजों का भाटा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी सरकार ने ५ फी सदी सहायता दे दी। इस तरह भारतीय आयात-कर की चाल बरी

ही रह गई। आगे चलकर भारत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी और बढ़ा दिया। इससे लकाशायर को ५ फी सदी की हानि हो गई। इसकी अति-युति सरकार ने दूसरी तरह कर दी। उसने भारत में आनेवाली रई पर एक आना सेर का महसूल लगा दिया। यह रई मिश्र और अमरीका से आती है और इससे लकाशायर के मुकाबले का वारिक कपड़ा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल से लकाशायर की स्पर्धा करने में भारतीय-मिलों को उतनी ही बाधा हो गई। ये सब बातें तो प्रसंगवश कही गई हैं। जब बस्व-उद्योग-रक्षण-विल असेम्बली में पेश हुआ तो उसपर दो सशोधन उपस्थित किये गये। मालवीयजी का सशोधन यह था कि • इंग्लैंड के साथ कोई रियायत न करके सब विदेशों के कपड़े पर कर की एक ही दर मुकर्रर कर देनी चाहिए। ३१ मार्च को असेम्बली की इस बैठक का अन्तिम दिन था। अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्बली में ज्यो-का-ज्यो स्वीकार न हो तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना बिल वापस ले लेगी क्या ? परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो बैठना है। अन्त में बहस हुई और मालवीयजी का सशोधन तो गिर गया और श्री चेट्टी का सशोधन स्वीकार हुआ। परन्तु सशोधित अवस्था में बिल पर राय ली गई। उससे पहले ही पण्डित मालवीयजी और उनके साथी, दीवान चमनलाल और नई स्वराज्य-पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गये। उस दिन की सभा बर्खास्त करने से पहले अध्यक्ष ने कहा—“आप सब मुझसे हाथ मिलाते जाएँ। कौन जाने हममें से कौन-कौन यहाँ रहेंगे।” यो देखा जाय तो फरवरी १९३० के बाद की इन घटनाओं का लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का पूरा चित्र खींचने और यह बताने के लिए कर दिया है कि कांग्रेस-दल के पीछे-पीछे मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड़ दी।

अब हमें १९३० के महान् आन्दोलन का अध्ययन करना है। यह कहा जा चुका है कि स्वाधीनता-दिवस देशभर में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से भारत में गिरफ्तारियां प्रचल वेग से हो रही थीं। मेरठ के ३२ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा सुपुर्द कर दिये गये, कलकत्ते में सुभाष बाबू और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गई। कांग्रेस के आदेश पर कौंसिली के १७२ सदस्यों ने फरवरी १९३० तक इस्तीफे दे दिये। इनमें से २१ असेम्बली के और ६ राज्य-परिषद् के सदस्य थे। प्रान्तीय कौंसिली में बंगाल से ३४, बिहार-उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मवरास से २०, युक्त-

प्रान्त मे १६, आसाम मे १२, बम्बई से ६, पंजाब से २ और बर्मा से १ ने इस्तीफा दिया।

सविनय-अवज्ञा का श्रीगणेश

१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की मावरमती में बैठक हुई। कॉंसिलों के जिन मेम्बरो ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खटे हो गये थे उन्हें कहा गया कि या तो वे कांग्रेस की निर्वाचित समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाने की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कंदियों के साथ सव्यवहार करने का आश्वासन दिया था, परन्तु सरकार ने उस वचन का पालन नहीं किया। इसपर सावरमती में कार्य-समिति ने खेद प्रकट किया। किन्तु इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस प्रकार था —

“कार्य-समिति की राय में सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और संचालित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विषय हो, और चूँकि कांग्रेस के सगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुरुष नहीं हैं वरिक्त ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अहिंसा को देश की वर्तमान स्थिति में सिर्फ नीति के तौर पर मानते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों को अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहाँ तक उचित समझे सविनय अवज्ञा जारी कर दें। कार्य-समिति को विश्वास है कि जब आन्दोलन वस्तुतः चल रहा होगा उस समय सारे कांग्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरह से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और बड़ी-मे-बड़ी उत्तेजना के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-समिति को यह भी आशा है कि आन्दोलन के सर्व-साधारण में फैल जाने पर बगील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थीगण जो सरकार ने कथित लाभ उठा रहे हैं, वे सब यह सहयोग और यह लाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम सपना में कूद पड़ेंगे।

“कार्य-समिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और कैद हो जाने पर जो लोग पीछे रह जायेंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना है वे अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम और आन्दोलन को जारी रखेंगे।”

जाने के इस प्रस्ताव से भी पहले गांधीजी ने कुछ चुने हुए आमन्त्रित मित्रों के साथ जो खानगी बात चीत की थी वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनमें एकमात्र

विषय नमक था, अर्थात् नमक का कानून कैसे तोड़ा जाय, नमक कैसे बनाया जाय पटा हुआ नमक कैसे इकट्ठा किया जाय और नमक के ढेरो पर धावा कैसे बोला जाय ?

नमक-कानून भंग

परन्तु सविनय अवज्ञा शुरु करें तो कैसे ? गांधीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गये थे। बम्बई में ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती की बैठक से पहले ही पहुँच चुके थे कि नमक के ढेरो पर धावा बोला जायगा। १४ फरवरी से पहले ही बम्बई में प्रचार-कार्य भी शुरु हो गया। नमक-कर का इतिहास थोड़ा निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की बिक्री की द्वाारा भारतीय नमक पर कर लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल बन्दर में माल के बिना जहाज खाली पड़े थे और अशान्त समुद्र पर वे तबतक चल नहीं सकते थे जबतक कि आवश्यक भार को पूरा करने के लिए भी कोई माल उनपर लदा न हो। इसलिए कुछ साल, कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हे लाना ही पड़ता था। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट की रेत भर कर आती रही, इसीसे कलकत्ते की चौरसी सबक तैयार हुई। यहाँ पहले हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी। असल बात यह है कि भारत में सदा से माल आता कम और यहाँ से जाता अधिक रहा है। १९२५ में निर्यात ३१६ करोड़ का और आयात २४९ करोड़ रुपये का रहा। इतना ही नहीं, निर्यात-माल में अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह अगह अधिक बेरता है। सब बातों को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को लेजाने के लिए आयात-माल लाने की अपेक्षा कम-से-कम चार-पाच गुने जहाजों की जरूरत तो अवश्य होती है। अर्थात् भारत में आनेवाले जहाजों को खाली आना पड़ता था। भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजों में ७२ फी सदी या ३ अंग्रेजी जहाज होते हैं। इसलिए भारत में आनेवाले जहाजों को अपना भार पूरा करने के लिए भी कुछ-न-कुछ अंग्रेजी माल लाना जरूरी होता है। इसके लिए चेसायर के नमक से अच्छी चीज और क्या होती ? हा, अखबारों की रद्दी और चीनी के टुकड़े आदि चीजें भी लाई जाती हैं। इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को इटली का सगमरमर और बालू लाते हैं। यही कारण है कि ये वस्तुएँ भारतीय पैदावार से सस्ती पड़ जाती हैं।

सावरमती की बैठक के बाद थोड़े दिनों में वातावरण नमक-ही-नमक से

व्याप्त हो गया। लोग पूछने लगे, क्या बनाया हुआ नमक पड़ता खाया? सरकारी-कर्मचारी और भी भागे बड़े। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने में ईधन और मजदूरी का हिसाब लगाकर बताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक बनाने में लगता है। ये चेचारे यह न समझ सके कि यह सधाम भौतिक नहीं, नैतिक था।

प्रभुत नमक-सत्याग्रह का विकास होनेवाला था। गांधीजी किसी नमक के क्षेत्र में जाकर नमक उठावेंगे। दूसरे नहीं उठावेंगे। अगर कोई पूछता, 'क्या हाथ-पर हाथ धरे बंटे रहें?' तो यही उत्तर मिलता—'अवश्य। परन्तु मैदान में उतरने के लिये तैयार रहो।' उन्हें तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा। बल्कमसाई तक को वह फूँच में साय न ले गये। केवल सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया। बर्षा-आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक रुहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भारत-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतन्त्र थे। उन्हें दीप्त गया था कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और न्यू जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का बामी बुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनाबूद नहीं कर सकते थे। ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक की जड़ें हिल जाती। अहिंसा पर बटल रहने का और कोई परिणाम ही ही नहीं सकता। लोग यदि यह पूछते कि सरकार बम बरसायगी तो क्या होगा? तो उसका उत्तर यही था कि यदि निर्दोष-स्त्री-पुरुष और बच्चों को जमींदोज कर दिया जाय तो उन्हींकी छाक में से साम्राज्य को मरम करनेवाली अग्नि प्रज्वलित होगी।

वाइसराय को अन्तिम चेतावनी

गांधीजी की योजना सदा उनकी अन्त प्रेरणा से बनी है, मस्तिष्क के भावना-हीन, हानि-लाभ-दर्शक तर्क से नहीं बनी है। उनका गुह और मित्र उनका अन्त करण ही रहा है। गांधीजी की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा सभी ने माना। नरम-दल-वालों तक ने नमक-सत्याग्रह को भले ही बेहूदा और खतरनाक बताया हो, गांधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं कर सके। गांधीजी ने वाइसराय को बहुत देर तक अन्वेष में नहीं रक्खा। सदा की भाँति इस बार भी (२ मार्च १९३० को) उन्होंने लॉर्ड अविन को चिट्ठी भेजी।

सत्याग्रहाश्रम सावरमती से भेजी गई वह चिट्ठी यह थी —

“सवितनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से सदा हिचकिचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है।

“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणी को दुःख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की तो बात ही नहीं—भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनो का कितना ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश-राज्य को अभिन्नाप समझता हूँ, वहाँ मैं एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।

“परन्तु मेरी धात का अर्थ गलत न समझिए। मैं ब्रिटिश-शासन को भारतवर्ष के लिए जरूर नाशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-मात्र को सत्कार की अन्य जातियों से बुरा भी नहीं समझता। सौभाग्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। असल बात तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अंग्रेजों की कलम से ही हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निररता-पूर्वक प्रकट किया है।

“तो मेरा अंग्रेजी राज्य के बारे में इतना बुरा स्थल क्यों है ?

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोषण करके उन्हें कगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उन्हें बर्बाद कर दिया है।

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामी से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की जड़ ही खोखली कर दी गई है। हमारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा जातिबल तो क्षुप्त हो ही गया था। हम सबको निःशस्त्र करके कायरों की भाँति निःसहाय और बना दिया गया।

“अनेक देश-सन्मुखों की भाँति मुझे भी यह सुख-स्वप्न देखने लगा था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिषद् बह चोख नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वक और अधिशिक्षित जनता दिल-ही-दिल में छट-पटा रही है। पार्लियामेंट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशंका उठनी ही न चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पार्लियामेंट की मजूरी की आशा में मन्त्रिमण्डल ने किन्नी खास नीति को पहले से ही अपना लिया हो।

“दिल्ली की मुलाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए १९२८ की कल-कत्ता-काग्रेस के गंभीर निश्चय पर अमल करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था।

“परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक-स्वराज्य शब्द का प्रयोग उनके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से घबराने की जरूरत नहीं। कारण जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि औपनिवेशिक-स्वराज्य व्यवहार में पूर्ण स्वराज्य ही है? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय।

“परन्तु ये तो गई-गुजरी बातें हुईं। घोषणा के बाद अनेक घटनायें ऐसी हुईं हैं जिनमें ब्रिटिश नीति की दिशा स्पष्ट सुचित होती है।

“बिनाकर की भांति अब साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्मेवार ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखते जिनमें ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार को बका पहुँचने की सम्भावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पक्ष और पूरी जांच करनी पड़े। यदि इस घोषणा की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन-दिन अधिकाधिक निस्स्वत्व होता ही जायगा। विनिमय की दर बात-की-बात में १८ पैसे करदी गई और देश को कई करोड़ की हानि सर्वा के लिए हो गई। अर्थ-सदस्य इस निश्चय को अटल समझने हैं। और जब और-और बुराईयों के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के लिए सविनय किन्तु सीधा हमला किया जाता है तो आप चुप नहीं रह सकते। आपने भी भारतवर्ष को पीस टालनेवाली प्रणाली की ही पुर्न-देख देकर उस उपाय को विफल करने के लिए धनी और जमींदार-वर्ग की मदद मांग ही ली।

“राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तहप के पीछे हेतु क्या है। इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में आ सकती है और यह खतरा हमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों मूल किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो। इसी कारण मैं कुछ अरसे से जनता को वाञ्छित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हूँ।

“उसकी मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रख दू।

“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझ इतना भारी है कि स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी। स्थायी वन्दोक्त अच्छी चीज है, परन्तु इसमें भी मुट्ठी भर अमीर जमींदारों को लाभ है, गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं। वे तो सदा से बेवसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहे वेदबल किया जा सकता है।

“भूमिकर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा। सारी कर-व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत की जान निकाल लेने का ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उसपर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यो दीखने में तो वह सब पर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदय-हीन निपटारा का भार सबसे अधिक गरीबों पर ही पड़ता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अमीरों से गरीब लोग अधिक भागा में पाते हैं। इस कारण नमक-कर का बोझ गरीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है। नवों की चीजों का महत्त्व भी गरीबों से ही अधिक बमूल होता है, इसने गरीबों के स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुठाराघात होता है। इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता की मूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया जाता है आमदनी के लिए। १९१६ की सुधार-योजना के जन्मदाताओं ने बड़ी होशियारी से इस आय को द्वैध-शासन के जन्मेदार कहलानेवाले विभाग के सुपुर्दे कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निषेध का भार मन्त्री पर आ गया और वह बेचारा भलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया। यदि असाया मन्त्री उस आमदनी को बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च बिल्कुल कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आवकरी के बजाय उसके पास और कोई आमदनी का साधन नहीं है। इधर ऊपर से कर का भार लाद-लादकर गरीबों की कमर तोड़ दी गई है, उधर हाथ-कलाई के मुख्य सहायक-बन्धों को नष्ट करके उनकी उत्पादन-शक्ति बर्बाद कर दी गई है।

“भारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख किये बिना पूरी नहीं हो सकती। हाल में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इस ऋण की स्वतंत्र न्यायालय-द्वारा पूरी जांच कराना और जो रकम अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होगा।

“उपर्युक्त अन्याय ससार के सबसे महँगे विदेशी शासन को कायम रखने के

लिए किये जाते हैं। आपके वेतन को ही देखिए। दूसरे अनेक उदाहरणों के अलावा आपको २१ हजार रुपये मासिक मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ५००० पाउंड वार्षिक अर्थात् ५४०० रुपये माहवार ही दिये जाते हैं। भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो आने से कम है और आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं। एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री की १८०) रुपये। इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हजार गुना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिर्फ ६० गुना ही अधिक दिया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस क्षणिक पर गौर कीजिए। यह व्यक्तिगत उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक हृदय विदारक मृत्यु आप भलीभाँति समझ जायें। आपके लिए व्यक्तिगत मेरे मन में इतना आदर है कि मैं आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं है। शायद आप सारी तनखाह खेरात ही कर देते होंगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह तो जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लायक है। जो बात वाइसराय के वेतन के बारे में सच है, सामान्यतः वही सारे शासन पर भी लागू होती है।

"अतः कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब शासन-व्यय भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया-पलट कर देना। मेरी राय में २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में लाखों श्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायगी।

"फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतवासियों को भूख से तड़प-तड़पकर घनै घनै भिड़ नहीं जाना है तो कष्ट-निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुरन्त ढूँढना पड़ेगा। प्रस्तावित परिषद् से तो यह उपाय हो ही नहीं सकता, यह बात तर्क से मनवाने की नहीं है। यहाँ तो बराबर की शक्ति खड़ी करनी होगी, तर्क-वर्क कुछ नहीं। ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने व्यापार एवं हितों की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्ष को मृत्यु के बाहुपाश में से मुक्त होने के लिए उसनी ही शक्ति सम्पादन कर लेनी होगी।

"यह सभी को भाव्य है कि भले ही हिंसक-दल कितना ही असंगठित या सम्प्रति महत्त्वहीन हो, फिर भी उसका जोर बढ़ता जा रहा है। उसका और मेरा ध्येय एक ही है। परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह मूक जनता का कष्ट-निवारण

नहीं कर सकता। मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन दृढ़तर होता जा रहा है कि ब्रिटिश-सरकार की संगठित हिंसा को शुद्ध अहिंसा ही रोक सकती है। मेरा अनुभव अवश्य ही सीमित है, परन्तु वह बताता है कि अहिंसा बड़ी जबरदस्त क्रियात्मक शक्ति हो सकती है। मेरा इरादा इस शक्ति-द्वारा सरकार की संगठित हिंसा और हिंसक-दल की बढ़ती हुई असंगठित हिंसा दोनों का मुकाबला करने का है। हाथ-भर-हाथ घर बैठने से तो ये दोनों शक्तियाँ स्वच्छन्द होकर विचरेंगी। मेरा अहिंसा की सफलता में निश्चय और अटल विश्वास है। ऐसी दशा में और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप होगा।

“यह अहिंसा सविनय-अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। आरम्भ में आश्विन-निवासी ही इसमें भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल हो जायेंगे।

“मैं जानता हूँ कि अहिंसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा बड़ी-से-बड़ी जोखिमों के उठाये बिना नहीं हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-सख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सम्मूहों के राष्ट्रों को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बड़ी नहीं है।

“मैंने ‘ठीक रास्ते पर लाने’ के शब्द जान-बूझकर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं अहिंसा-द्वारा ब्रिटिश शासित का हृदय पलट दूँ और उसे भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दूँ। मैं आपकी जाति को हानि पहुँचाना नहीं चाहता। मैं उसकी भी वैसी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाति की। मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा की है। १९१६ तक आलें बन्द करके उनकी सेवा की पर अब मेरी आँखें खुली और मैंने अमहयोग की आवाज बुलन्द की तब भी मेरा उद्देश्य उनकी सेवा ही था। जिम हथियार का उपयोग मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामवालों के साथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं आग्नीवी के नमान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूँ, तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। बरनो तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने में बाट मेरे कुतवेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को बतूल किया है, वैसे ही अंग्रेज भी निर्गुण न करेंगे। यदि मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाति अपना बदन पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-मैने जट्ट-महान की जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नहीं रह सकता।

"मविनय-अवज्ञा की योजना उपर्युक्त बुराइयों के मुकाबले के लिए है। ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी हम इन्हीं बुराइयों के कारण करना चाहते हैं। इनके दूर हो जाने पर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उम समय मित्रतापूर्ण समझौते का द्वार खुल जायगा। यदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार में से लाभ का मूल निकल जाय, तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मैं आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयों को तुरन्त दूर करने का मार्ग सुगम बनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिपक्व के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए। यह परिपक्व बराबरी के लोगों की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। यह यह कि स्वेच्छा-पूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की भलाई का उद्योग किया जाय और उभय-पक्ष के लाभ को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापार की शर्तें तय की जायें। दुर्भाग्यवश हम देश में साम्प्रदायिक झगड़े हैं अवश्य, किन्तु आपने उनपर ज़रूरत में ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु हमसे भी बड़ी-बड़ी अन्य समस्याएँ हैं जो कभी भी झगड़ों में परे हैं और जिनके कारण सब जातियों को समान-रूप से हानि उठानी पड़ती है। अस्तु, यदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय आप नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारीख को मैं आश्रम में उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़ूँगा। गरीबों की दृष्टि में मैं इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनता का आन्दोलन मूलतः गरीब-मे-गरीब की भलाई के लिए है। इसलिए इस लड़ाई की शुरुआत भी इसी अन्याय के विरोध से होगी। आश्चर्य तो इस बात पर है कि हम इतने दीर्घकाल तक नमक के इस निर्दय एकाधिकार को सहन करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्न को विफल कर सकते हैं। उस दशा में, मुझे आशा है कि, मेरे पीछे हजारों ब्राह्मणी नियमित रूप में यह काम सम्हालने को तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे धृणित कानून को, जो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था, तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायेंगी उन्हें वे दूरी-दूरी दवांस्त करेंगे।

"मेरा वस चले तो मैं आपको अनावश्यक ही क्या ज़रा-सी कठिनाई में भी नहीं डालना चाहूँ। यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ बातचीत करना चाहें और इस हेतु से आप इस पत्र को छपने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, मैं खुशी से रुक जाऊँगा। परन्तु

इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अगीकार करने को तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करे।

“इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र कर्तव्य मात्र है। इसीलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अग्नेज-मित्र के हाथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे आयद विघाता ने इन्हीं काम के लिए मेरे पास भेजा है।”

इस चिट्ठी को रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक अग्नेज युवक दिल्ली ले गये। यह भाई कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों ने अन्तिम चेतावनी का नाम दिया था। लॉर्ड अविन का उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाड्सराय साहब ने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करनेवाले हैं जिसने निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी। गांधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और साहस की भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने लिखा, “मैंने दस्तबस्ता रोटी का सबाल किया था और मिला पत्थर।” अग्नेज जाति सिर्फ शक्ति का ही लोहा मानती है। इसलिए मुझे वाड्सराय साहब के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। सारा भारत ही एक विनाशाल कारागृह है। मैं इस अग्नेजी कानून जो मानने से इन्कार करता हूँ और इन जबर्दस्ती की शान्ति की मनहूस एकरसता को भग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रेंधा हुआ था। अब उसके हृदय का पीत्कार प्रकट होना चाहिए।”

इस प्रकार गांधीजी का कूच अनिवार्य हो गया था। सब तैयारियाँ पहले से ही हो चुकी थीं। लम्बी-चौड़ी तैयारी की तो जरूरत भी न थी। उनके ७६ साथी आश्रमवासियों और विद्यापीठ के छात्रों में से चुने हुए लोग थे। ये सैनिक दो सी भील लम्बी पैदल यात्रा के कष्टों को सहन करने के लिए फौलादी अनुशासन में सचे हुए थे। दाण्डी समुद्र-तट पर एक गांव है। गांधीजी को वहीं पहुँचना था। उन्होंने मार्ग के ग्रामवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को बहिया भोजन न दें। इसपर गांधीजी शुद्ध नैतिक ढंग की ये तैयारियाँ कर रहे थे, उधर बल्लभभाई अपने

१ रहम की तुलसे तबको थी, सितमगर निकला।

भोम समझे थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला ॥

‘गुप्त’ के पहले ही आनेवाली तपस्या और सकटों के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने के लिए गावों में पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया। जब बल्लभभाई इस प्रकार गांधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, ‘यह तो १९०० वर्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन बैपटिस्ट है।’ उसने तुरन्त मार्च के प्रथम सप्ताह में बल्लभभाई को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार मास की सादी सजा दे दी। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का बच्चा-बच्चा सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। सावरमती के रेतिले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निश्चय किया —

“हम अहमदाबाद के नागरिक सकल्प करते हैं कि जिस रास्ते बल्लभभाई गये हैं उसी रास्ते हम जायेंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। देश को आजाद किये बिना न हम चैन लेंगे, न सरकार को लेने देंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा।”

गांधीजी ने कहा, ‘जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहें, अपने हाथ ऊँचे कर दें।’ सारे जन-समूह ने हाथ उठा दिये। बल्लभभाई ने गुजरात में अपने भापणों से जीवन फूट दिया। उन्होंने कहा, “तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे प्यारे पशु कुर्क होंगे। अरे! क्या पिताह-उत्सव मना रहे हो? इतनी बलवती सरकार से जूझनेवाले को ये रग-रेलियाँ थोमा दे सकती हैं। कल ही से ऐसी नीवत आ सकती है कि अपने-अपने घरों के ताले लगाकर तुम्हें दिन-भर बंदों में रहना और सात पडेँ लौटना पडेँ। तुमने यश कमाया है, परन्तु उसकी पावता सिद्ध करने के लिए अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। पासा पड़ चुका है। अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही। गांधीजी ने सामूहिक सविनय-अवज्ञा के प्रथम प्रयोग में तुम्हारे ताल्लुके को ही चुना है। देखना, उनकी लाज रखना।

मैं जानता हूँ, तुममें से कुछ लोगों को जमीनें जब्त होने का डर है। पर जब्ती से क्या होगा? क्या अग्रेज तुम्हारी जमीनें सिर पर उठाकर विलायत ले जायेंगे? विश्वास रखो, तुम्हारी जमीनें जब्त हो जायेंगी उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर खड़ा हो जायगा।

“अपने गांव का ऐसा सगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें। अब गांव-गांव छावनियाँ बन जानी चाहिए। अनुशासन और सगठन से आधी लड़ाई तो जीती ही समझो। सरकार तो हर गांव में एक-एक पटेल और एक-एक तलाठी रखती है। गांव के प्रत्येक बयस्क स्त्री-पुरुष को हमारे स्वयंसेवक बन जाना चाहिए।

दाण्डी-कूच

गांधीजी अपने ७२ नाथियों को लेकर १२ मार्च १९३० को दाण्डी की कूच पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक अव्य-वृत्त था और प्राचीनकाल की राम एव पाण्डवों के वन-गमन की घटनाओं की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रोहियों की कूच थी। इधर कूच जारी थी, उधर ज्ञान-कर्मचारियों के बड़ाबड़ त्याग-पत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड़ दी। अहमदाबाद की खानगी बातचीत में गांधीजी ने कहा था, “मैं शुरुवात कहूँ, तबतक ठहरना। जब मैं कूच पर निकलूंगा तो विचार अपने-आप फैल जायेंगे। फिर आप लोगों को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए।” यह बात एक तरह से दिमागी अटकल लगाने के विरुद्ध नेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विरोध की योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पुरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-योग्य अनुगामी भी नहीं कर सकते थे। शायद गांधीजी को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी। ऐसा लगता है मानो उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उनकी प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तर्क के बजाय ये ही दो चीजें मार्ग-दर्शक होती हैं। कूच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन की योजना को समझ लिया। वह उनके झण्डे के नीचे आ खड़ी हुई। विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगा। लोगों ने चौब्र अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अनावात्मक नहीं बल्कि प्रतिकार की योजना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। ज्योंही विचारों और भावनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की क्रिया-शक्ति के बन्द भी खुल गये। नगर तो डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगों का गांधीजी के अचूक निर्णय पर विश्वास था। उनका नमक-सत्त्वग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या जनता महारामर की लूट का भावा नहीं था। यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचायक-मात्र था। अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का जागर न तो प्रजा की सम्पत्ति पर है और न नीति अथवा मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तों पर।

यात्री आदेश

यह सही है कि पहला बार गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-गुल के साथ नहीं किया गया। यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया। फिर भी जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्पन्न हुआ वह

आश्चर्यजनक था। नगरों पर भी इस मीचे-सादे और हास्यास्पद-मे आन्दोलन का जगमग अद्भुत-सा दृशा। सम्य मगार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की कूच में यह विचार प्रसंगित कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का झण्डा फहरा दिया है और यदि विघाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य की, अघकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमरता की ध्वज होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जान होकर रहेगी।

कूच के बीच में ही २१ मार्च १९३० को अहमदाबाद में महाममिति की बैठक हुई। उसमें राय-ममिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक कानून पर ही प्रति केन्द्रित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि गांधीजी के दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून तोड़ने में पहले देश में और कहीं सविनय-अवज्ञा जुट न की जाय। मरदार बल्लभभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियों पर और मरकानी नौपरिया छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बचाई दी गई। सत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना बाञ्छनीय समझा गया और गांधीजी की अनुमति में यह प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया —

"१—राष्ट्रीय महाममा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अवज्ञा का जो आन्दोलन गडा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता हूँ।

"२—मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ।

"३—मैं जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी जो कष्ट और मजाये मुझे दी जायेंगी उन्हें मैं सहर्ष सहन करूँगा।

"४—जेल जाने की हालत में मैं कांग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मागूँगा।

"५—मैं आन्दोलन के सचालकों की आज्ञाओं का निर्विवाद रूप से पालन करूँगा।"

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रखे, इस विषय में गांधीजी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने भेरे गिरफ्तार होने पर यह लेख लिखा। उसमें कहा —

"यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर मेरी

गिरफ्तारी निश्चित है। अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी है।

“मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अत्यन्त सन्निय अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में भात्मिक विश्वास रखने वाला एक-एक स्त्री-पुरुष इस गुलामी में अब नहीं रहेगा। या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानुसार सविनय-अवज्ञा करना सबका कर्तव्य होगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अबश्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। हाँ, यह अनिवार्य शर्त सभी के ध्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए अहिंसा की शक्ति में अबल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके पर उसे अहिंसात्मक उपाय नहीं सूझ सकेगा।

“अब शुरुआत गलीमार्च और वस्तुतः हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने से सहयोग मिलेगा। आन्दोलन की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का धर्म होगा कि वह इसे अहिंसात्मक और नियंत्रित बनाये रखे। हरेक से आशा है कि वह अपने सरदार की आज्ञा बिना अपने स्थान से न हटेगा। ससार-भर के सामूहिक आन्दोलनों में नेता अकल्पित रूप में निकल पड़े हैं। फिर हमारा आन्दोलन भी इस नियम का अपवाद क्यों होगा?”

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द भवन का साही दान दिया। उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस मेट को स्वीकार किया।

जिस समय गांधीजी की कूच जारी थी, भारत बड़ा अवीर होकर उसको देख रहा था। प्रमाद को दूर करना प्रायः जितना कठिन है उतना ही व्याकुलता पर अकुश रखना कठिन होता है। परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता है। इस विकट अवसर पर भारतवर्ष ने अनुशासन का परिचय दिया। गांधीजी द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को सत्या, धन और प्रभाव का बल मिलता ही गया। गांधीजी ने सूत्र-रूप से विचार दिया था। उनके शिष्यों ने माध्यकार बनकर उसे जनता को समझाया। अनेक कार्यकर्त्ता राष्ट्र-दूत बनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल पड़े। गुप्त एक, चले अनेक और प्रचारक असंख्य होते हैं। इस प्रकार यह नवीन धर्म

देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया। गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई देती थी, एक ही सप्ताह में उसके होश-हवास गुम हो गये। गांधीजी के महा-ग्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में वह बल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाईयां कर चुकी थी। कूच के बाद उसने यह आज्ञा दी कि लगेटी और दण्डवारी गांधी की पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय। बम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाब और मद्रास आदि सभी प्रान्तों ने ऐसी ही आज्ञाये निकाल दी। पुलिस को मामूली काम से एक तरह छुट्टी-सी दे दी गई। सारा ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया।

इस सारी प्रसव-पीडा में पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोष की बात थी? इसमें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, बलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार दिखाना ही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, १२ मार्च १९३० से पहले ही से साबरमती-आश्रम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हुए थे। जहातक चलने का सामर्थ्य था वहा तक ये लोग गांधीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियों के साथ कई भारतीय और विदेशी सवाददाता, चित्रकार और आस-पास के सैकड़ों लोग तथा मिश्र-भिन्न प्रान्तों से आये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि वह कितना तेज चलते हैं। एक सवाददाता ने इस यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया है —

“१२ मार्च को सुबह होते ही गांधीजी सविनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल पड़े। उनके साथ चले हुए ७६ स्वयंसेवक थे। इन लोगों को दो सौ मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाण्डी नामक गांव जाना था और वहा पहुँकर नमक बनाना था।”

‘बॉम्बे क्रैनिकल’ के शब्दों में “इस महान् राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साथ और बाद में जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूकनेवाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रबल धारा बह रही थी उतनी पहले कभी नहीं

वही थी। यह एक महान् मान्दोलन का महान् प्रारम्भ था, और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा।”

यात्रा में

गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिए हुए चलते थे। उनकी सारी सेना बिल्कुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फुर्ती से उठता था और सभीको प्रेरणा देता था। असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनो ओर खड़ी हुई भारी मीठ के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग थप्टो पहले से भारत के महान् सेनापति के दर्शनो की उत्सुकता में खड़े थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बड़ा जुलूस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याव नहीं पड़ता। शायद बच्चो और अपंगो के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी इस जुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में खड़े होने को जगह न मिली, वे छतों और शरोखों, दीवारों और दरस्तों पर, जहाँ-कहीं जगह मिली, पहुँच गये थे। सारे नगर में उत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर ‘गांधीजी की जय’ के गगनमेदी घोष होते रहे।

कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया था “कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते-में मर जाऊँगा या आश्रम के बाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं है।” गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। श्री अब्बास तय्यबजी उनके उत्तराधिकारी मुकर्रर हुए। आचार्य प्रफूलचन्द्र राय ने कहा, “महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजारों मृत्ता और उनके भ्रूवी साथियों के देश-स्वाय से ही दी जा सकती है। जबतक यह महापुरुष भजिले-मकसूद पर नहीं पहुँच जायगा, पीछे फिरकर नहीं देखेगा।”

गांधीजी ने कहा, “अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, सैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नष्ट करने का प्रण कर चुका हूँ।

“मैंने स्वयं ‘गॉड सेव दि किंग’ के गीत गाये हैं। दूसरों से भी गवाये हैं। मुझे ‘भिक्षादेहि’ की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब व्यर्थ हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किसीको मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खतम कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।”

जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेदारों के सामाजिक वहिष्कार की निन्दा की और कहा, "सरकारी कर्मचारियों को भूखो मारना घर्म नहीं है। शत्रु को साप काट ले तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका जहर चूस लेने में मैं भी सकोच नहीं करूँगा।"

१४ फरवरी १९३० को कार्य-समिति ने नमक-सत्याग्रह के विषय में जो प्रस्ताव पास किया था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदाबाद की बैठक में उसका इस प्रकार समर्थन किया —

"यह समिति कार्य-समिति के १४ फरवरीवाले उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें सविनय-अवज्ञा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ ही यह समिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्च को शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है। समिति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य का आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

"महा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार सचित समक्ष उसी प्रकार सविनय-अवज्ञा जारी कर दें, अलवृत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की आज्ञाओं का पालन करना प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा-सम्भव नमक-कानून तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी पूरी तैयारी तो जारी रखी जायगी, परन्तु जबतक गांधीजी बाण्डी पहुँचकर नमक-कानून का भंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दें तबतक अन्यत्र सविनय-अवज्ञा आरम्भ न की जायगी। हा, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जायें तो प्रान्तों को सविनय-अवज्ञा आरम्भ करने की पूरी आज्ञा दी होगी।"

तीर्थ यात्रा

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थयात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूरत में गांधीजी ने कहा —

"आज ही रात कालीन प्रार्थना के समय मैं माथियों में कह रहा था कि जिस जिले में हमें सविनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये हैं। अतः हमें आत्म-मुक्ति

- और समर्पण-बुद्धि का और भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक संगठित है और यहाँ कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र भी अधिक है, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी अधिक होने की संभावना है। देखना उनके बाग्रह को न मानना। हम देवता नहीं हैं, निर्बल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे अनेक भूले हुए हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मग्न था उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कबूल किया। मैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध भगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। अतः मैंने तीव्र शब्दों में उनकी अर्त्तना की। परन्तु इससे मेरा कुछ खान्त नहीं हुआ। उल्टा ज्यो-ज्यो मैं उस भूल पर विचार करता हूँ त्यो-त्यो कुछ बढता ही है।

"मैं विरोध तभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-आय से कुछ तो साम्य रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम अपने कार्य में नगे, भूखे और बेकार लोगों की मलाई की दुहाई देते हैं। यदि हम देशवासियों की औसत-आय अर्थात् ७ पैसे रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा रहे हैं तो हमें वाइसराय के वेतन की टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाब और अन्य विगत मांगी है। कोई आश्चर्य नहीं, यदि इसमें प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी क्या, जब वे कहीं-न-कहीं से मेरे लिए बढिया-से-बढिया सन्तरे और अगूर लायेंगे, १ दर्जन सन्तरो के स्थान पर १० दर्जन पहुँचायेंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला भरेंगे? आपका जी दुखाने के भय का बहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम होगा। आप अमरुद और अगूर लाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बनावड किसान ने भेजे हैं। और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने भुखे फाउण्टेन-पैन दे दिया और मैंने बिना आत्म-पीडा अनुभव किये बढिया चिकने कागज पर उसीमे वाइसराय साहब को खत लिख डाला? क्या यह मुझे और आपको जोभा दे सकता है? क्या इस प्रकार लिखे हुए पत्र का कुछ भी असर हो सकता है?

"इस प्रकार के जीवन से तो मत्ता मगत की यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोरी का माल खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीब देश में बढिया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं तो क्या है? चोरी का माल खाकर यह लडाई कभी नहीं जीती जा सकती। मैंने यह कूच हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए झुट भी नहीं

की थी। हमें तो आशा है कि हमारी पुकार पर हजारों स्वयंसेवक हमारा माथ देंगे। उनपर वेशुमार ग्वर्च करके रखना हमारे लिए असंभव होगा।”

नमक-कानून टूटा

५ अप्रैल को प्रातःकाल गांधीजी दाण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनीदेवी भी उनसे मिलने आई थी। प्रातःकाल की प्रार्थना के थोड़ी देर बाद गांधीजी और उनके साथी समुद्र-तट से नमक चिनकर नमक-कानून तोड़ने निकले। नमक-कानून तोड़ते ही गांधीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया —

“नमक-कानून विधिवत् भंग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो वह, जहाँ चाहे और जब सुविधा देगे, नमक बना सकता है। मेरी सलाह यह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनावें, जहाँ उन्हें मुद्र नमक तैयार करना आता हो वहाँ उसे काम में भी लावें और ग्रामवासियों को भी सिखा दें, परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दें कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम है। या यों कहो कि गाववालों को पूरी तरह समझा दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर कितना पड़ता है, और इसके कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय।

“नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात् १३ अप्रैल तक, जारी रहनी चाहिए। जो इस पवित्र कार्य में धीरक न हो सके उन्हें विदेशी वस्त्र-अहिकार और खदर-अभार के लिए व्यक्तिगत काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से-अधिक खादी बनवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के और मदिरा-निषेध के बारे में मैं भारतीय महिलाओं के लिए अलग सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास दिन-दिन बढ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक सहायक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अहिंसा का अर्थ वे पुरुषों से अच्छा समझ सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अक्ल है—पुरुष अहकार-बण उन्हें ऐसा ही समझते हैं।—बल्कि सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है।”

स्त्रियों के विषय में गांधीजी ने नवसारी में कहा —

“स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कड़ाइयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी बहनो से कड़ाई भोल नहीं लेगी। इसकी उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जबतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए, जब

सरकार सीमोल्लघन करे तब भले ही स्त्रियां भी खोलकर लड़ें। कोई यह न कहे कि 'चूँकि हम जानते थे कि स्त्रियां कितनी भी आगे बढ़कर कानून भंग करें उनपर कोई हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आठ छी।' मैंने स्त्रियों के सामने जो कार्यक्रम रक्खा है उसमें उनके लिए बहुत काम है। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिखायें और जोखिम उठावें।"

६ अप्रैल से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आगसी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरो में लाखों की उपस्थिति में विराट् सभाएँ हुईं। कराची, पूना, पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मदरास में भी गोली चली।

कराची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा —

"बहादुर युवक इत्तामैय, कहते हैं, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान था, इसलिए सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौजवान मेमराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जय-रामदास सहित ७ मनुष्य गोली से घायल हुए।"

२३ अप्रैल को बंगाल-आर्बिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल को बाइसराय साहब ने भी कुछ सशोषण करके १९१० के प्रेस-एक्ट को आर्बिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर दिया। गांधीजी का 'यंग इंडिया' अब साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा —

"हमें अनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हम पर एक प्रकार से फौजी शासन हो रहा है। फौजी शासन आखिर है क्या। यही कि सैनिक अफसर की मर्जी ही कानून बन जाती है। फिलहाल बाइसराय बेसा अफसर है और वह जहाँ चाहे साधारण कानून को बालाघ-ताक रखकर विशेष आज्ञायें लाद देता है और जनता बेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर मैं आशा करता हूँ, वे दिन जाते रहे कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चुपचाप सिर झुका दें।

"मुझे उम्मीद है कि जनता इस आर्बिनेन्स से भयभीत न होगी। और अगर लोकमत के सच्चे प्रतिनिधि होंगे तो असवारवाले भी इससे नहीं डरेंगे। थोरो का यह उपदेश हमें हृदयगम्य कर लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है। अतः जब हम चीन्चपड़ किये बिना अपने शरीर

ही अधिकारियों के हवाले कर देते हैं तो हमें उसी भांति अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द कर देने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए? इससे हमारी आत्मा की तो रक्षा होगी।

“इस कारण मैं सम्पादकों और प्रकाशकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जमानत देने से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो-कुछ ज्वत् करना चाहे कर लेने दें। जब स्वतंत्रता-देवी हमारा द्वार खटखटा रही है और उसे रिश्वाने को हजारों ने धोर यातनायें सहन की हैं, तो देखना, अखबारवालों को कोई यह न कह सके कि मौका पड़ने पर वे पूरे नहीं उतरें। सरकार टाइप और मशीनरी ज्वत् कर सकती है, परन्तु कलम और जवान को कौन छीन सकता है? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; वह तो किसी के बचाये नहीं दे सकती।”

थोड़े दिन बाद गांधीजी ने अपने ‘नवजीवन-प्रेस’ के व्यवस्थापक को कह दिया कि सरकार जमानत मागे तो न दी जाय और प्रेस को ज्वत् होने दिया जाय। ‘नवजीवन’ गया और उसके साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देश के अधिकांश पत्रकारों ने जमानतें दाखिल कर दी।

अब गांधीजी ने जनता को गावों में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश दिया। शुरुआत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की मभा में वह बोले—“मविष्य में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चाहिए। तकली पर तुम बारीक-से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपड़ा पहले-पहल मूरत के बन्दर पर उतरा था। मूरत की बहनो को ही इसका प्रायश्चित्त करना है।” यही पर उन्होंने जातीय पंचायती में अपनी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध उन्हें जनता की चेतावनी देनी पड़ी। खेडा जिला गुजरात का रणागण धन गया था। गांधीजी ने ‘नवजीवन’ में लिखा—

“खेडा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। ज़दाहरणार्थ, मैंने सकेत कर दिया है कि श्राम-कर्मचारियों का बहिष्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आज्ञा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द न होना चाहिए। उन्हें धरो में नहीं निकालना चाहिए। यदि हममें इतना न हो सके तो बहिष्कार छोड़ देना चाहिए।”

धारासना पर धावा

इस समय गांधीजी ने बाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार और सूरत जिले के धारासना और छरसाडा के नमक के कारखानों पर धावा का इरादा जाहिर किया। उन्होंने बाइसराय को लिखा —

“ईश्वर ने बाहा तो धारासना पहुँचकर नमक के कारखाने पर अधिकार का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रहना होंगे। जनता को यह बताया गया कि धारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज बोझाघड़ी है। धारासना पर सरकार उतना ही वास्तविक नियन्त्रण है जितना बाइसराय साहब की कोठी पर है। अधिकार की स्वीकृति के बिना चुटकीभर नमक भी कोई वहाँ ने नहीं ले जा सकता।

“इस धावे को—रोकने के तीन उपाय हैं—

(१) नमक-कर उठा देना।

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना। परन्तु जैसी आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय काम न होगा।

(३) खालिम गुंडापन। परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुट कर तैयार रहेगा तो यह बार भी खाली जायगा।

“यह निश्चय बिना हिचक के नहीं कर लिया गया। मुझे आशा थी सत्याग्रहियों के साथ सरकार नम्य तरीके से लड़ेगी। यदि उनपर साधारण कानून प्रयोग करके सरकार सन्तोष कर लेनी तो मैं कहीं क्या सकता था? इसके बजाय प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोड़ा-बहुत जान्ना बरता भी है, वहाँ माया सेनिकों पर पाशविक ही नहीं निर्लज्ज प्रहार भी किये गये हैं। ये घटनाएँ इफ्तो-दुल होती तो उपेक्षा भी कर ली जाती। परन्तु मेरे पास बगार, विहार, उन्क सयुक्तप्रान्त, दिल्ली और बम्बई ने जो मंचाद पहुँचे हैं उनमें गुजरान के अनुभव समर्थन होता है। गुजरात-मन्वन्धी मामरी तो मेरे पास टेरों है। बगानी, पैना और मदरास के गोली-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते हैं। हट्टि चूर-चूर करके और अण्डकोष दवाववागर स्वयमेवरो में वह नमन जिनने पा प्रद किया गया है जो मन्वार के लिए निबन्मा था। हा, स्वयमेवरो में लिट् अण्डने वेद-श्रीमती था। कहा जाता है कि मयुर में नायव मजिस्ट्रेट ने १० अंके बाग हाथ में मे राष्ट्रीय अण्ड छीन लिया। यह राज्य अण्ड के विद्रु पा परन्तु जनता ने अण्डा बानन मागा तो उने निर्दम प्रताप फग्गे मदेद दिया गया। कथित

स्वय अपना अपराध समझते थे तभी तो अन्त में झण्डा वापस दे दिया गया। बगाल में नमक के सम्बन्ध में मुकदमे और प्रहार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयसेवकों से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय निर्दयता का परिचय दिया गया बताते हैं। समाचार है कि चावल के खेत जला दिये गये और खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये गये। कर्मचारियों के हाथ शाक-भाजी न बेचने के अपराध पर गुजरात में एक सक्की की मण्डी ही नष्ट कर दी गई। ये क्रूर जन-समूहों की आँखों के सामने हुए हैं। कांग्रेस की आज्ञा न होती तो क्या ये लोग बदला लिये बिना छोड़ते? कृपया इन वृत्तान्तों पर विश्वास कीजिए। ये मुझे उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का कत ले रक्खा है बारडोली की भाँति बड़े-बड़े कर्मचारियों-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध हुआ है। मुझ खेद है, इन दिनों भी कर्मचारी झूठी बातें प्रकाशित करने से बाज नहीं रहे। गुजरात के कलकटगे के दफ्तर से जो सरकारी विज्ञप्तियाँ निकली हैं उनके कुछ नमूने ये हैं —

१—‘व्यस्क लोग प्रतिवर्ष २॥ सेर नमक खाते हैं इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते हैं। सरकार एकाधिकार हटा ल तो लोगों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा और एकाधिकार के हटाने से सरकार को जो हानि होगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी। समुद्र-तट से बंदोरा हुआ नमक खाने के काम का नहीं होता, इसीलिए सरकार उसे नष्ट कर बेती है।’

२—‘गांधीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-कटाई का उद्योग सरकार ने नष्ट कर दिया। परन्तु सब लोग जानते हैं कि यह बात सच नहीं है। देश भर में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ आज भी रुई हाथ से न काती जाती हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रान्त में सरकार कातनेवालों को बढ़िया तरीके बताती है और कम कीमत पर अच्छे बीजार देकर उनकी सहायता करती है।’

३—‘सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पाँच में से चार रुपये प्रजा की मलाई के कामों में लगाये हैं।’

‘मैंने ये तीन तरह के वयान तीन अलग-अलग हस्त-पत्रों में से लिये हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे साबित किये जा सकते हैं। प्रत्येक व्यस्क उपयुक्त मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में लेता है और इसलिए निश्चय ही १ आने प्रति वर्ष तो कर के बेता ही है। और यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पशु, छोटे-बड़े और अच्छे-बीमार सबसे।

“यह कहना एक दुष्टतापूर्ण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्खा चलता है और सरकार चर्खा-आन्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है। सरकारी ऋण के पांच में से चार हिस्से सार्वजनिक हित के लिए खर्च होने की झूठी बात का उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग अधिक अच्छा दे सकते हैं। परन्तु ये नमूने तो उन बातों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज आती हैं। उस दिन एक वीर गुजराती कवि को झूठी सरकारी बहादुरी पर सजा दे दी गई। कवि बेचारा कहता ही रहा कि मैं तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींव ले रहा था।

“अब सरकार की निष्क्रियता की बानगी देखिए। शराब के व्यापारियों ने घरना देनेवालों को पीटा और नियम-विरोध शराब बेची। सरकारी आदमियों तक ने कबूल किया कि स्वयंसेवक शान्त थे। फिर भी कर्मचारियों ने न तो भारपीट पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित विक्री पर। मारपीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी यह बहाना कर सकते हैं कि किसीने शिक्षागत नहीं की।

“और अब देश की छाती पर एक नया आर्बिनेंस और लाद दिया है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भगतसिंह वगैरा के मुकदमे में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जालों को ताक में रखने का आपको अच्छा अवसर मिल गया। इन कृत्यों को फ्रीजी-शासन कहा जाय तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए? और अभी तो आन्दोलन का पाचवा सप्ताह ही है।

“ऐसी दशा में, कुछ समय से भय-अवर्जन का बोलबाला शुरू हुआ है। उसका आतंक देश पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर डालना चाहता हूँ, जिससे आपका क्रोध जल्दी ही मड़क उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चल निकले। मैंने जो बातें बयान की हैं उनका सम्भव है आपको इत्म न हो। शायद आपको उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा धर्म तो आपका ध्यान दिलाना मात्र है।

“कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे सत्ता के लाल पजे को पूरी तरह आजमा लेने का अनुरोध करूँ। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की बान होगी। जो लोग आज कष्ट-सहन कर रहे हैं, जिनकी मिलिक्रयत बरबाद हो रही है, उन्हें यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैंने उनकी सहायता से इस लड़ाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम को उस हद तक पूरा नहीं किया जिस हद तक वह किया

जा सकता था। क्योंकि एक तो इस लड़ाई की बदीलत सरकार का असली रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है।

"सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्ताधारी जितना अधिक दमन और कानून-भंग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कष्टों को आमन्त्रण देंगे। स्वेच्छा-पूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक कष्ट-सहन उतनी ही निश्चित सफलता।

"मैं जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायो में कितनी विपत्तियाँ निहित हैं। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल करनेवाला नहीं दीखता। मैं जो सोचता और मानता हूँ वही करता हूँ। मैं भारत में गत १५ वर्ष से और भारत से बाहर और भी २० वर्ष पहले से कहता आया हूँ कि हिंसा पर कुछ अहिंसा की ही विजय हो सकती है। मैंने यह भी कहा है कि हिंसा के एक-एक कार्य भव्य और विचार से भी अहिंसात्मक कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती है। बार-बार ऐसी चेतावनियाँ देने पर भी लोग हिंसा कर बैठें तो मैं क्या करूँ? मेरे शिर पर उस दशा में उत्तना ही दायित्व होगा जितना प्रत्येक मनुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से हुआ करता है। इसके अलावा और मेरी जिम्मेवारी नहीं हो सकती। दायित्व की बात छोड़ भी दी जाय तो भी मैं अपना काम किसी भी कारणवश मुत्तवी नहीं रख सकता। अन्यथा अहिंसा ने वह शक्ति ही कहा रहे, जो सत्तार के सन्तो ने वर्णन की है और जो मेरे दीर्घकालीन अनुभव ने सिद्ध की है?

"हां, मैं आगे की कार्रवाई सहर्ष स्वीकृत रख सकता हूँ। आप नमक-कर उठा दीजिए। इसकी निन्दा आपके कई विख्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की है, और अब तो आपने देख लिया होगा कि सविनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसपर रोप प्रकट कर दिया है। आप सविनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए। परन्तु क्या आप कानून-भंग से हिंसाय विद्रोह को अच्छा समझते हैं? आपने कहा है कि सविनय-अवज्ञा का परिणाम हिंसा हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं समझी और इसलिए उसकी सुनवाई भी नहीं की, फल यह हुआ कि मनुष्य-स्वभाव सरकार की प्रिय और परिचित वस्तु हिंसा पर उत्तर आने को विवश हुआ। परन्तु मुझे आशा है कि सरकारी उत्तेजना के बावजूद परमात्मा भारत-वासियों को हिंसा के प्रकोपन से दूर रहने की बुद्धिमत्ता और शक्ति को प्रदान करेगा।

"अतः आप नमक-कर उठा न सकें और नमक बनाने की मनाई दूर न करा

सकें तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में वर्णित कार्रवाई करनी पड़ेगी।”

गांधीजी की गिरफ्तारी

५ तारीख की रात को १ बजकर १० मिनट पर गांधीजी को चुपके से गिरफ्तार करके मोटर-कार में बिठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। बम्बई के पास बोरीविली तक रेलगाड़ी में और वहां से यरवडा-जेल तक मोटर में पहुंचा दिया गया। ‘लन्दन टैलीग्राफ’ नामक अखबार के सवाददाता अशमीव बार्टिलेट ने इस प्रसंग पर लिखा था —

“जब हम गांधी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में नाटक का-सा चमत्कार प्रतीत होता था। हमें लगा, इस दुःख के प्रत्यक्षदृष्टा हमी है। कौन जाने यह घटना आगे चलकर ऐतिहासिक बन जाय? एक ईश्वर-भूत की गिरफ्तारी कोई छोटी बात है? सच्चे-झूठे की मगबान जाने, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य-पुरुष है। कौन कह सकता है कि सौ वर्ष बाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नहीं पूजेगे? इन विचारों को हम रोक न सके और इस ईश्वर-भूत को हिरासत में लेने के लिए जवा के प्रकाश में रेल की पटरी पर सड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा।”

हा, गिरफ्तार होने से पहले गांधीजी ने दाण्डी में अपना अन्तिम संदेश लिखवा दिया था। वह यह था —

“सम्प्रति भारत का स्वाभिमान और सर्वस्व एक मुट्ठी नमक में निहित है। मुट्ठी टूट भले ही जाय, पर सुलनी हरगिज न चाहिए।

“मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को बबराना न चाहिए। इस आन्दोलन का संचालक मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित है। गांव-गांव को नमक बीनने या बनाने को निकल पड़ना चाहिए। स्त्रियों को धराब अफीम और विदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना देना चाहिए। घर-घर में आवाल-बुद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिए और रोज मूत के ढेर लग जान चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होलिया की जायें। हिन्दू किसीको अछूत न मानें। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिलें। बड़ी जातिया छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से सन्तोष करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें

जो नरसारी नोक उन पटेलों और तलाबियों की भांति नीकरिया छोड़कर जनता की सेवा में जुट जायें। उन प्रकार आसानी से हमें पूर्ण स्वराज्य मिल जायगा।”

गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के उस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपने-आप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि बम्बई, बंगाल और अनेक स्थानों पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़ताल हो गई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी। बम्बई में विराट् जुलूस निकला। ग्राम की इतनी विंगल गभा हुई कि कई मचों पर से भाषण देने पड़े। ८० में से ४० के लगभग मिले बन्द रही, कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल जाये थे। जी० आर्द० पी० और बी० बी० ती० आर्द० के कारखानों के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल में शामिल हो गये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए कपड़े के व्यापारियों ने ६ दिन की हड़ताल का निश्चय किया। गांधीजी पूना में तजरबन्द किये गये थे। वहाँ भी पूरी हड़ताल हुई। समय-समय पर नरसारी पदों और पदवियों के छोड़ने की घोषणा होने लगी। देश ने प्रायः सर्वत्र महात्माजी के उपदेशों का आदर्शजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर झगडा भी हो गया। मोलापुर में ६ पुलिस-चौकिया जला दी गई, जिसके फल-स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। मद्रास में महर की हड़तालें तो जान्तिपूर्ण रही, परन्तु हड़ता और पचतला में भीड़ को सितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ बी बारा के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गई।

परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विश्व-व्यापी हुआ। पनामा के भारतीय व्यापारियों ने २४ घंटे की हड़ताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साहब एव कांग्रेस को तार भेजकर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फ्रांस के पत्र गांधीजी और उनकी बातों से भरे थे। बहिष्कार आन्दोलन का परिणाम जर्मनी पर भी हुआ। वहाँ के कपड़े के व्यापारियों को उनके भारतीय आदतियों ने माल भेजने की मनाही कर दी। स्टर्न ने यह समाचार भेजा कि संकसनी की सस्ती छीट के कारखानों को बास तौर पर हानि हो रही है। नैरोबी के भारतीयों ने भी हड़ताल रक्खी।

इसी बीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादरियों ने तार-द्वारा रैम्जे मैकडानल्ट साहब की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनुरोध किया कि गांधीजी और भारतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया

जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीन होम्स ने करवाये थे। सन्देश में प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसी में है कि इस सघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति से रक्षा की जाय।

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महात्मा जी के स्थान पर श्री अब्बास तैयबजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे। वह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियों, लाठी-प्रहारों और बमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदानों पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हें लाठियों से मारती रही। बहुतों को सख्त चोटें आईं।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून-भंग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए —

“१. कराची तक महात्मा गांधी के साथ जानेवाले स्वयंसेवकों को कार्य-समिति बधाई देती है और आशा करती है कि नये-नये दल धावे करते रहेंगे। समिति निश्चय करती है कि अबने नमक के धावों के लिए धारासना अखिल-भारतीय केन्द्र माना जाय।

“२. गांधीजी ने इस महान् आन्दोलन का संचालन करके देश को जो मार्ग दिखाया है उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना आदरपूर्ण विद्रोह प्रकट करती है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई की दुगुने उत्साह से चलाने का निश्चय करती है।

“३. समिति की राय में अब समय आ गया है कि सनस्त गण्ट्र घेय की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगा कर कोशिश करे। अब समिति विधायियों, वकीलों, व्यवसायियों, भजदूरो, किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्वातन्त्र्य-संग्राम की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर भी महत्प्रयास करें।

“४. समिति की राय में देश का हिा उन्नीस है कि विदेशी अन्ध-विश्वास मन्त्र्य-दल में अविश्वास पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा मातृ की प्रिन्सिपल गेनने, पहलू के दिये हुए आर्टिक्ल नव बगाने और नये आर्टिक्ल न भिन्नवाने के लिए वाग्वर दाय

किये जायें। समिति समस्त कांग्रेस-कमिटियों को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र-वहिष्कार का तीव्र प्रचार करे और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग बिठा दें।

“५ समिति पण्डित मदनमोहन मालवीय-द्वारा किये गये वहिष्कार-आन्दोलन की सहायता के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई समझौता मजूर नहीं कर सकती जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मगाने के व्यापारियों के वचन से सन्तोष किया जा सके। समिति सभी कांग्रेस-समितियों को ऐसे किसी समझौते में शामिल होने से मना करती है।

“६ समिति निश्चय करती है कि बढ़ती हुई माग पूरी करने के लिए हाथ-कटे हाथ-बुने कपड़े की पैदावार बढ़ाई जाय। रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खहर देने वाली सस्पायें खड़ी की जायें और सामान्यतः हाथ-कटाई को प्रोत्साहन दिया जाय। समिति प्रत्येक देशवासी से अपील करती है कि वह रोज थोड़ी-बहुत देर अवश्य काटे।

“७ समिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ प्रान्तों में खास-खास महसूल बेना बन्द करके करबन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, तामिल नाड और पंजाब जैसे रैयतदारी प्रान्तों में जमीन का लगान रोका जाय और बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि में चौकीदारी-कर न दिया जाय। समिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि वे प्रान्तीय समितियों-द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में जमीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन सगठित करें।

“८ प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे गैर-कानूनी नमक बनाने का काम जारी रखे और उसका विस्तार करें और जहाँ सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से बाधा दे वहाँ नमक-कानून तोड़ने का काम और भी जोश के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है कि नमक-कानून के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-सस्पायें हर रविवार को इस कानून के सामूहिक उल्लंघन का आयोजन करें।

“९ स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्त में जगलत कानून तोड़ने की जो अनुमति दी है, समिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहाँ ऐसा कानून हो वहाँ प्रान्तीय समितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता है।

"१० समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली खदर की वनवाई को रोकने एवं विदेशी वस्त्र बहिष्कार की पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझौते की बातचीत करें।

"११ समिति जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी साल का बहिष्कार जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए वह प्रबल प्रयत्न करे।

"१२ समिति जनता से प्रबल अनुरोध करती है कि अंग्रेजी बैंको, धीमा-कम्पिनियो, जहाजों और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी बहिष्कार करे।

"१३ समिति एकबार पुनः सम्पूर्ण मदिरा-निषेध के लिए घोर प्रचार-कार्य की आवश्यकता पर जोर देती है और शराब और ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रांतीय समितियों से अनुरोध करती है।

"१४ समिति को कहीं-कहीं मीठ-द्वारा हिंसा हो जाने पर दुःख है और वह इस हिंसा की अत्यंत कठोर निन्दा करती है। समिति अहिंसा के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर आग्रह रखने की इच्छा प्रकट करती है।

"१५ समिति प्रेस-आर्बिनेन्स की तीव्र निन्दा करती है और जिन मखबारों ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया उसकी प्रशंसा करती है। जिन भारतीय पत्रों ने अभी तक प्रकाशन बन्द नहीं किया है या बन्द करके फिर निकलने लगे हैं उनके अब बन्द किये जाने का अनुरोध करती है। जो भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी प्रकाशन बन्द न करे उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील करती है।"

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बैठक में प्रयाग गई हुई थीं। श्री तैयबजी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारासना लौट आई और धावे का संचालन करने का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वह और उनका स्वयंसेवक-दल जावो से गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकालकर उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद स्वयंसेवकों के दल नयक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया गया। उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयंसेवकों को गैर-जानूनी सस्था के सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और धारासना की अस्थायी जेल में नजरबन्द कर दिया।

१६ ता० को प्रातः काल ही बडाला के नमक के कारखाने पर स्वयंसेवक बड़ी

सत्या में एकत्र हो गये। पुलिस की तत्परता के कारण धावा न हो सका। उस दिन पुलिस तमचे लेकर आई थी। उनमें ४०० सत्याग्रहियों को पकड़ लिया।

X

X

X

X

बहिष्कार-आन्दोलन का क्या अमर हो रहा था, इसपर 'फ्री-प्रेस' के मवाद-दाता ने यह लिखा था —

“आक्रमण का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की मफ़लता भी इसी दिशा में सबसे अधिक नज़र आती है। परन्तु यह भय इतना नहीं है कि अन्त में भारतीय बाज़ार हाथ में जाता रहेगा। वल्कि मय इस बात का अविक है कि मीजूदा सौदे पूरे नहीं होंगे या रद्द कर दिये जायेंगे। मीजूदा सौदे रद्द करने की वृत्ति बढ़ती जाती है। ‘डेली मैन’ का मैचेन्टर-स्थिति सवाददाता लिखता है, ‘भारतवर्ष के राजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लकाबायर का भारतीय व्यापार विलकुल बन्द हो जायगा। पहले ही कताई-बुनाई के कारखाने अनिश्चित काल के लिये बन्द होते जा रहे हैं और हज़ारों मजदूर बेकारों की सख्या बढ़ा रहे हैं।’

नमक के धावे और भी होते रहे। उनका वर्णन ‘गांधी की मैन एण्ड हिज मिशन’ (अर्थात् ‘गांधी उसका व्यक्तित्व और जीवन-ध्येय’) नामक पुस्तक में १३३ वें पृष्ठ से आगे यो किया गया है —

“इस बीच में कार्य-समिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय किया। धावे भी जारी रहे। २१ मई को बारासना पर सामूहिक धावा हुआ। इसमें सारे गुजरात से आये हुए २५०० स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इमाम साहब उनके नायक बने। यह ६२ वर्ष के बृद्ध पुरुष गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थे। धावा तबके ही शुरु हो गया। ज़िबर से स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर हमला करते उबर ही से पुलिस उन्हें लाठिया मार-मारकर खदेड़ देती।

“हज़ारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा। दो घण्टे तक द्वन्द्व-युद्ध चलता रहा। फिर थी इमाम साहब, प्यारेलाल और मणिलाल गांधी आदि नेता पकड़ लिये गये और बाद में श्रीमती सरोजिनीदेवी भी गिरफ्तार हो गईं। उस दिन कुल मिलाकर २९० स्वयंसेवक घायल हुए। इन चोटों से थी माईलालसाई डामासाई नामक स्वयंसेवक तो चल ही बसा। इसके बाद पुलिस ने सेना की सहायता से बारासना और चँटडी के सब रास्ते बन्द करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया। चँटडी से सब स्वयंसेवकों को पुलिस न जाने कहाँ ले गई और फिर उन्हें छोड़ दिया।”

३ जून को चँटडी की छावनी से २०० स्वयंसेवकों के दो दल बारासना के

नमक-भण्डार पर आक्रमण करने निकले। दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वजित सीमा में घुसी तो उसपर लाठिया चला दी। घायलों को छावनी के अस्पताल में पहुँचा दिया गया।

बडाला के घावे

बडाला के नमक के कारखाने पर कई घावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयंसेवक पकड़े गये और बर्ली भेज दिये गये। २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गई। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार। घावा दो घण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर हुआ। इसमें १८ घायल हुए। प्रसिद्ध लडाके श्री० कवाडी भी इनमें शामिल थे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। बाकी भीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विमर्षि में कहा गया कि अबतक जो गडबडें हुई हैं वे अधिकतर दर्शकों ने की हैं और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं है, अतः जनता को बावों के समय बडाला से दूर रहना चाहिए। किन्तु सबसे चमत्कारी घावा तो १ जून को हुआ। युद्ध-समिति उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियाँ कर रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिकों और असेनिकों ने बडाला के विशाल सामूहिक घावे में भाग लिया।

पोर्ट-ट्रस्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचता और वही पुलिस उन्हें और भीड़ को रोक लेती। थोड़ी देर में घावा करनेवाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घेरा तोड़ कर कीचड़ पार करके कबाइयों पर पहुँच जाते। लगभग १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें आईं। पुलिस ने घावा करनेवालों को खदेड़ दिया। यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ।

३ जून को बर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपद्रव हो गया। स्थिति को सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन बडाला के ४ हजार अभियुक्तों से पुलिस की भिडन्त हो गई। लगभग ६० घायल हुए। २५ को सत्त चोटें आईं। किन्तु जिस प्रकार घावा करनेवालों के साथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बड़ा रोष फैला। दर्शक लोग उस निर्दय दृश्य को देखकर चकित रह गये। बम्बई की अदालत सफ़ीफा के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हुनेन, श्री के० नटराजन और भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष श्री देवधर घागमना का घावा देखने गये थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा —

“हमने अपनी आखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर भगा देने के बाद भी यूरोपियन सवार हाथों में लाठिया लिये हुए अपने घोड़े सरपट दौड़ाते और जहाँ सत्याग्रही धावे के लिए पहुँच मये थे वहाँ से गाव तक लोगों को मारते रहे। गाव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े दौड़ाकर स्त्री-पुरुष और बच्चों को तितर-बितर किया। ग्रामवासी दौड़-दौड़ कर गलियों और घरों में छिप गये। सयोगवश कोई न भाग सका तो उसपर लाठिया पड़ी।”

‘न्यू फ्रीमेन’ के सवाददाता वेव मिलर साहब ने बारासना के इस घृणित दृश्य पर इस प्रकार प्रकाश डाला —

“मैं २२ देशों में १८ वर्ष से सवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस असें में मैंने असह्य उपद्रव, मारपीट और बिद्रोह देखे हैं, किन्तु बारासना-के-से पीडाजनक दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं आये। कभी-कभी तो ये इतने दुःखद हो जाते थे कि क्षणभर के लिए आँख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज थी। मालूम होता था, इन लोगों ने गांधीजी के अहिंसा-धर्म को धौलकर पी लिया है।”

स्लोकोम्ब साहब की गवाही

लन्दन के ‘डेली ट्वेन्टि-पत्र के प्रतिनिधि जार्ज स्लोकोम्ब साहब भी नमक के कुछ धावों के प्रत्यक्षदर्शी थे। वह २० मई को गांधीजी से अरबडा-जेल में मिले। उन्होंने अपने पत्र को जो खरीता भेजा वह इतना असाधारण था कि कामन-सभा की नींद हुराम हो गई और अनुदार-दल के पत्रों की चिड़ और क्रोध का पार न रहा। इस खरीते में स्लोकोम्ब साहब ने बतलाया कि अब भी समझौते की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान ली जायें तो गांधीजी कानन-भग स्थगित करने और गोलमेज-परिषद् के साथ सहयोग करने की कायेस से सिफारिश करने को तैयार हैं —

(१) गोलमेज-परिषद् को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारतवर्ष की स्वाधीनता का सार मिल जाय।

(२) नमक-कर उठा देने और शराब और विदेशी वस्त्र की मनाई करने के सम्बन्ध में गांधीजी को सन्तोष दिलाया जाय।

(३) कानून-भग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें।

(४) वाइसराय साहब के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात बातें और लिखी थी उनकी चर्चा बाद पर छोड़ दी जाय।

स्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वक सवि करने को तैयार है या नहीं? उन्होंने कहा, "समझौते की बात चीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिसा दूसरे को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। गांधीजी जेल में क्या बन्द हैं भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पष्ट स्वीकार कर लेने से अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।"

दमन का दौर-दौरा

परन्तु एक-एक बात को कहा तक गिनावें? घटनाओं का क्या पार था? लॉर्ड अविन ने अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। भारम्भ में तो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को लग गया। सर्वत्र कूच के नक्कारे बजने लगे। उनकी पुकार पर हजारों महिलाये मैदान में निकल आईं। उनके कारण सरकार बड़े चक्कर में पड़ गई। उन्होंने आते ही धाराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देने का काम अपने हाथ में ले लिया और जबतक शौर्य पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तबतक पुलिस भी उनके आगे कुछ न कर सकी। ऐसी स्थिति में गांधीजी को खुला छोड़ा जाय? न जाने वह कहा से देश की छिपी हुई शक्ति को दूढ़कर निकाल लाते। उनके हाथ में जादू की लकड़ी थी। उसे जरा घुमाया कि जन-जन का डेर लग जाता था। अतः उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय पाकर। कारण गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्र-रूप भिन्न के छत्ते को छेड़ना था। १४ अप्रैल को जवाहरलालजी को पकड़ कर सजा दे दी गई। जवाहरक्या बन्दी हुआ, कांग्रेस बन्दी हो गई। सारा देश एक विशाल जेलखाना बन गया। धरना, करबन्दी और सामाजिक बहिष्कार सबकी रोक के लिए ब्रिटिश सरकार ने निकल गये। राष्ट्रीय झंडे पर अनेक मुठभेड़ें हुईं। सत्रायें दिन-दिन कठोर होने लगीं। कैद के साथ-साथ जूमनि किये जाने लगे। लाठी-प्रहार भी आ पहुँचे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियों और सब अत्यास्र से मुसज्जित करके पुलिस को जो कबायब-मरेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियों के सिर पर आजमाई जायगी। यह कोरी धमकी या आजका नहीं निकली। लाठी-प्रहार तो भयकर सत्य के रूप में प्रगट हुआ। समा-अन की आज्ञा तो होती थी देश के साधारण कानून के अनुसार, और उसपर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रहारों से। नमक-कानून के साथ-साथ तानिरात-हिन्द की धारयें मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजायें दी जाने

लगी। फरवरी १९३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा निकली। उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण किया गया। हा, उनमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नहीं आने दिया गया। दिल्ली में तो यह है कि दस वर्ष पहले में सरकार अपनी 'इंडिया' नामक सालाना पुस्तक में —अलवत्ते अवतरण-चिन्ह देकर—यह शब्द बराबर प्रयोग करती आ रही थी। यह सरकारी आज्ञा परिशिष्ट ४ में दी गई है।

'ए' वर्ग तो नाममात्र को ही था। 'बी' क्लास भी वही कजूसी से दिया जाता था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च वर्ग के हकदार थे। पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर तोड़ने, धानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की जीवन्त कलाई खोल दी। वह तो जनता की आँखों में धूल झाँकने मात्र का प्रयत्न था। परन्तु स्वयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वे तो पंतिंगों की भाँति आन्दोलन में पड़ते ही रहे। बहुतांश को सरकार पकड़ती न थी, उनपर सिर्फ लाठी का बार होता था। सौभाग्य से कोई जेल में पहुँच जाते, तो वहाँ भी कई बार दूसरा लाठी-प्रहार उनको तैयार मिलता था। आन्दोलन के आरम्भकाल की बात है। एक बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले में बन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटको पर आड़ लगाकर पहरे बिठा दिये गये थे। पाणविक व्यवहार की बुरावत तो सयुक्तप्रान्त और बंगाल से हुई। किन्तु थोड़े ही दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आन्दोलन के उत्तरार्द्ध-काल में वहाँ दमन की अमानुषता का पार नहीं रहा।

वहाँ भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों की नीति आजमाई गई, परन्तु थोड़े ही दिन बाद भारपीट आ पहुँची। बाजार में सौदा खरीदते हुए खहर या गाँधी-टोपी-बारी मनुष्य पीट दिये जाते थे। मलाबार की फौजी पुलिस को आन्ध्र के भद्रपुर से एलोर तक कोकनडा और राजमहेन्द्री होकर सिर्फ इसलिए भुमाया गया कि रास्ते-चलते खहर-बारियों की मरम्मत करने का आनन्द छूटा जाय। ये करतूतें आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुईं। वहाँ पुलिस ने गोली चलाई, दो-तीन आदमी मरे और पाच-छ घायल हुए।

दमन के भिन्न-भिन्न रूपों का दिग्दर्शन करा सकना वस्तुतः कठिन है। वह जन्मा तो था कानून-भग की नाक में नाथ डालने, किन्तु वह हो गया 'अनेक रूप-रूपाय'। इसलिए हमें १९३० और १९३१ के इतिहास की थोड़ी-सी प्रमुख

घटनाओं का उल्लेख करके ही सन्तोष करना पड़ेगा। बीच-बीच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। बम्बई शीघ्र ही लडाई का मुख्य केन्द्र बन गया। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें मिल-मालिकों का स्वार्थ साफ था। नौमास्य से पण्डित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह बम्बई गये और बम्बई तथा अहमदाबाद के मिलवालों से उन्होंने समझौते की बातचीत की। अहमदाबाद वालों ने निपटना आसान था, पर बम्बई के मिलों में यूरोपियनों का हिस्सा भी था। उनसे कांग्रेस की मुहर लगवाने की धर्त (परिशिष्ट ५ देखिए) कबूल कराना बड़ा मुश्किल काम था। परन्तु मोतीलालजी ने अनमन्य को सम्मन कर दिखाया। बात यह थी कि बायुमण्डल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण था। जनता के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी थी। विदेशी कपड़े की सैकड़ों गाँठें बन्दर पर पड़ी थीं। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होंने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वह माल नहीं लेंगे। इस कारण देश में कपड़े की तंगी होने लगी थी।

कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून आ पहुँची। उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई और उसने यह निश्चय किया —

“१ बहुत-से शहरो और गावों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की जो प्रगति हुई है उसे देखकर समिति को सन्तोष है। समिति व्यापारियों की देशभक्ति की भावना को भी प्रशंसा करती है, जिसने प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा बेचना बन्द कर दिया है प्रत्युत् पहले के आर्डर रद्द कर दिये और नये आर्डर भेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तयाम विदेशी कपड़े की आयात में भारी कमी बगरी है। जिन स्थानों के व्यापारियों ने अभी तक विदेशी कपड़ा बेचना बन्द नहीं किया है उनसे यह समिति तुरन्त बन्द कर देने का अनुरोध करती है। इनमें पर भी यदि वे बिना बन्द न करें तो समिति सम्बन्धित कांग्रेस-समस्याओं को आदेग देती है कि उनकी दुकानों पर नञ्ज पिकेटिंग लगा दिया जाय। समिति को आशा है कि १४ जुलाई १९३० नरु देगनर में विदेशी कपड़े की बिना बिलकुल बन्द हो जायगी। समिति प्रान्तीय-समितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध करती है।

“२ समिति मनमन् कांग्रेस-समस्याओं और देगनर में अनुरोध करती है कि ब्रिटिश माल के सम्पूर्ण बहिष्कार का पर्यन्त से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और इसके

लिए हिन्दुस्तान में न बननेवाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदा जाय।

“३” समिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय-आन्दोलन का गला घोटने के लिए जनता पर अमानुष अत्याचार करने में सीधा भाग लिया है उन सबका सगठित और कठोर रूप में सामाजिक बहिष्कार किया जाय।

“४” कार्य-समिति देश का ध्यान कांग्रेस के १९२२ वाले गया के और १९२९ वाले लाहौर के उन निश्चय की ओर आकर्षित करती है जिसमें विदेशी-शासन-द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लादे गये ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल उनना ऋण स्वीकार करना तय किया गया था जितना स्वतन्त्र न्यायालय (ट्रिब्यूनल) द्वारा जान होकर उचित ठहरा दिया जाय। अतः समिति जनता को बलाह देती है कि नई पूजी लगाने या पुरानी का स्थान्तर करने के लिए भी भारत-सर्वकार के नये पुर्जे (बाड) न खरीदे जायें और न लिये जायें।

“५” चूँकि बृटिश-सरकार ने प्रबल लोकमत की पर्वाह न करके मनमाने तौर पर रुपये का कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगुना मुकर्रर कर दिया है और चूँकि रुपये का भाव और भी गिर जाने की घोर सम्भावना है, अतः कार्य-समिति भारतवासियों को बलाह देती है कि सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके बदले में यथामुम्भव मोना लिया जाय, रुपये या नोट न लिये जायें। समिति की यह भी सलाह है कि लोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपये और नोटों के बदले में सोना लें और निर्यात-माल की कीमत मुवर्ण के रूप में लेने का आग्रह करे।

“६” इस समिति की राय में अब समय आ पहुँचा है कि भारत के कॉलेजों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सन्नाम में पूर्ण भाग लें। समिति सब प्रांतीय समितियों को आदेश देती है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस की मेया में लग जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढाई बिलकुल छुटवा दें। समिति को विश्वास है कि समस्त विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर तत्परता से देंगे।

“७” चूँकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रांतीय और जिला-समितियों तथा सम्बद्ध सस्थाओं को गैर-कानूनी करार दे दिया और सम्भव है जेप समितियों और सस्थाओं के लिए भी भविष्य में ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह समिति इन समस्त समितियों और सस्थाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा

की पर्वाह न करके वे पहले की भाँति काम करती रहें और कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी रखें।

“८ इस समिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पाचवा प्रस्ताव लेना और पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युक्तप्रान्त की सरकार ने एक घोषणा द्वारा इस प्रस्ताव की प्रतिया जवाब कर ली हैं। इस घोषणा पर समिति को आश्चर्य है। उसकी राय में जनता पर दल दहलाने वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अन्ध बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समिति न्याय-पूर्वक इससे भी बड़ा निष्पत्ति कर सकती थी, परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निश्चय किया उसीको अपनी सम्मति है क्योंकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख मात्र किया गया है। यह समिति समस्त कांग्रेस-सत्याग्रहों से अनुरोध करती है कि सरकारों घोषणा की पर्वाह न करके उक्त निष्पत्ति को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय।

“९ श्रुति समिति की पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने नृशत्रु दमन-धक को आलस बन्द करके जारी रखा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला घोटने की गरज से अपने नौकरों और गुणों को अधिकाधिक निर्दयता और पशुता के कृत्य करने दिये हैं, अतः समिति सरकार के जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर जनता को बधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहे सरकार की ओर से कितनी भी बातनायें बरमाई जायें भारतवासियों ने स्वतन्त्रता की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है।

“१०. समिति भारतीय महिलाओं को इस बात पर बधाई देती है और उनकी प्रशंसा करती है कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-रूने रात-रातों रातों उत्साह ने भाग ले रही हैं और प्रहारों, दुर्व्यवहारों और नज्वाओं को भीरुतापूर्वक सहन कर रही हैं।”

विलायती कपड़े का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। सहर से किसी भाँति कपड़े की माग पूरी होती दीखती न थी। इसके बाद मिल के मूल का हाथ से बना हुआ कपड़ा ही देश-व्याप्त नागरिकों के लिए ब्राह्म हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और बाधक होनेवाले कारखानों में भेद करना पड़ा। तदनुसार उन्हें नन्द देने की प्रथा-द्वारा कांग्रेस के नियन्त्रण में लाया गया। मिलों से जो शर्तें करवाई गईं उनमें से मुख्य वे थी कि वे अपनी मशीनरी फिटिंग कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने वादियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से न रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिबायत का बेजा फायदा उठाकर अपने नाल की

कीमत न बढ़ायेंगी और शाहूको को हानि न पहुँचायेगी। मिलो ने घडाघड इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये। इनी-गिनी मिलो ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता लग गया कि उस समय काप्रेस कितनी बलवती सत्ता थी।

ब्रेल्सफोर्ड साहब का बयान

यहा पहुँचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जून १९३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी बुद्धि और हुई कि बहिष्कार-आन्दोलन की तीव्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। बम्बई के स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर बाकी न थी। स्त्रिया आती ही गई और जब ये कोमलागिया केसरिया साड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्रता के साथ घरना देती थी, तो लोगों के हृदय बात की बात में पिघल जाते थे। कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो उसीकी पत्नी घरना देने आ बैठती। अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक समार्यों वजित करार दे दी गई। पर इन आज्ञाओं को मानता कौन था? ब्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी और जनता के साथ जो पाश्चात्तिक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आँखों देखा था। १२ जनवरी १९३१ के 'मैचेंस्टर गार्जियन' में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया —

“पुलिस के खिलाफ जिम्मेवार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी शिकायतें हैं कि उन की जाच करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसी तरह की बहुत सी बातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों और धायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों ने सुनाई। मैंने भी दो समार्यों देखी। उन्हें नहीं रोका गया था। भाषण राजब्रोहात्मक थे, पर किये गये थे क्षातिपूर्वक। हिंसा की बराबर निन्दा की गई। भीड़ खूब थी। लोग जमीन पर बैठे तकलिया चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की सख्या भी खूब थी। सभी का व्यवहार विनम्र और शान्त था। अगर इन समाजों को रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप घर बैठ जाती। पर हुआ यह कि खासकर बम्बई में मारपीट कर तितर-बितर करने की नीति से सारे शहर का रोष उमड़ आया, लाठी-भहार सहन करना सम्मान का प्रश्न बन गया और शहादत के जोश में सैकड़ों स्वयंसेवक मार खाने को निकल आये। उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन लोगों ने भी मुझे बार-

था। पुलिस का यह दस्तूर था कि बन्दूक और लाठियों से सुसज्जित होकर विद्रोही गांव को घेर लेना और जो ग्रामीण सामने आ गया बिना देखे-भाले उसे लाठी या बन्दूकों के ठोसे से मारना। इन आक्रमणों के शिकार हुए ४५ व्यक्तियों ने मेरे खूब बयान दिये हैं। दो के सिवाय सबके घाव और चोटें मैंने देखी हैं। एक लड़की ने तो शर्म के मारे अपनी चोटें नहीं दिखाईं। कइयों के घाव गंभीर भी थे। कई आदमियों के मेरे पास बयान हैं। वे लगान देनेवालों में से थे। लेकिन उनसे तो पड़ोसियों के बदले में मारपीट कर लगान बसूल किया गया था। एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय झण्डे फाड़-फाड़कर बुझो और घरो पर से उतार दिये गये। साथ ही न किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि उनके घर इन राष्ट्र-विन्धों के लजदीक थे। दो आदमियों को गाड़ी-टोपी पहने रहने पर पीट दिया गया। एक जगह एक आदमी पर लाठी-चर्चा होती रही। उसके १२ लाठिया लगी। जब उससे सात बार पुलिस की सलासी कराली गई तब पिण्ड छोड़ा। वहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 'स्वराज्य चाहिए ? तो यह लो।' और कहकर लाठी बरसा देती।

"आप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की सहायत है। किन्तु मैंने अपनी ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैंने उच्च कर्मचारियों को दिखाये। एक 'नमूने' के गांव में कमिश्नर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटें देखी और उनसे पूछ-ताछ की। गंभीर विचार के बाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है, परन्तु मीके पर तो ६ में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस लज्जाशील लड़की का था। मैं दो स्थानीय हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रग-डग देखे। इनमें से एक ने मेरे सामने ही जान-बूझकर पशुतापूर्ण व्यवहार किया। उसने बोरसद में जेरतजवीज कैदियों को रखने के लिए जो पिंजड़ा बनाया था वह भी मैंने देखा। अजायबघर के जानवरों के लिए जैसे खुले बाड़े बनाये जाते हैं यह भी वैसा ही था। इसके लोहे के सीखचे लगे हुए थे। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ३० वर्ग फीट के करीब थी। इसमें १८ राजनैतिक कैदी दिन-रात बन्द रहते थे। एक कैदी को तो इसमें डेढ़ महीना बंद चुका था। उसे न पुस्तकें दी गई थी, न कोई काम ही दिया गया था। यह खचाखच भरा रहता था। कैदियों को दिन में एक बार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पौन घण्टे के लिए शौच स्नानादि के निमित्त। उनमें से एक ने मुझे कहा, 'हमें जेल में पीटा गया था।' क्या मैं उनकी बात न मानता ? इस जेल में और मारपीट में क्या अन्तर था ? दोनों ही मध्यकालीन बर्बरता के परिचायक थे।"

गोली-काण्ड का विवरण

देश में जो गोली-काण्ड हुए उनके विषय में असेम्बली में श्री एस० सी० मित्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मेम्बर हेग साहब ने गोली-काण्डों-सम्बन्धी अकों की नीचे लिखी तालिका पेश की (देखिए लेजिस्लेटिव असेम्बली की वृहत्, पृष्ठ २३७, सोमवार १४ जुलाई १९३०—जिल्द ४, अंक ६) —

जनता के हताहत

प्रान्त	तारीख	मरे	घायल	विविध
मदरास शहर .	२७ अप्रैल	२	६	१ पीछेसे मर गया
कराची	१६ "	१	६	१ " "
कलकत्ता	१ "	७	५६	१ " "
"	१५ "	—	३	
२४ परगना	२४ "	१	३	
चटगाव	१८, १९, २० अप्रैल	१०	२	दोनों पीछेसे मर गये
पेशावर	२३ "	३०	३३	
चटगाव	२४ "	१	—	
मदरास	३० मई	—	२	
शोलापुर	८ "	१२	२८	
बडाला	२४ "	—	१	
मिण्डी बाजार अम्बई	२६, २७ मई	५	६७	
हुवडा	६ "	—	५	
चटगाव	७ "	४	६	३ पीछेसे मर गये
मैमनसिंह	१४ "	१	३० से ४० के बीच	
प्रतापदिगी (मेदिनी-पुर)	३१ "	२	२	
लखनऊ	२६ "	१	४२	२ पीछेसे मर गये
कलू (कोलम-पजाव)	१८ "	—	१	
रगून	अन्तिम सप्ताह	५	३७	
सीमा-भ्रान्त	"	१७	३७	
दिल्ली	६ मई	४	४०	

१२ मई को ८॥ बजे सायकाल शोलापुर के जिला-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति सैनिक अधिकारियों के सुपुर्दे कर दी ।

१५ मई को शोलापुर का फौजी-शासन-सम्बन्धी आर्डिनेन्स निकाल दिया गया । ८ मई को शोलापुर में १२ मारे गये और २८ घायल हुए । ६ अलग-अलग मीको पर गोली चली ।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद शोलापुर में एक खेद-जनक घटना हो गई । स्वयंसेवक रास्तों पर व्यवस्था रख और आवागमन का नियमन कर रहे थे । ऐसा कई दिन तक होता रहा । पुलिस वस्तुतः बेकार हो गई । अधिकारियों को यह कब पसन्द आता ? इस प्रकार की परिस्थिति में पुलिस एवं स्वयंसेवकों में संघर्ष के अवसर आने सम्भव थे ही । आखिर भिन्न हो ही गई और चार-पाच पुलिसवाले मार दिये गये । १९१९ में पंजाब में जैसा फौजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी वैसा ही हुआ । इसके साथ-साथ जो मय-सामग्री आती है वह भी आई । एक बड़े सेठ और तीन अन्य व्यक्तियों को फाँसी पर लटका दिया । कई आदमियों को फौजी कानून के अनुसार लम्बी-लम्बी सजायें दे दी गई । जुलाई-अगस्त की समझौते की बात-चीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटकारे का प्रश्न झगड़े का विषय बन गया था । पर इसका जिक्र तो आगे किया जायगा ।

पेशावर-काण्ड

२३ अप्रैल १९३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहाँ दे देना ठीक होगा । भारत के अन्य भागों की भाँति सीमा-प्रान्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन चल रहा था । पेशावर शहर में कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से शराब की दुकानों पर पहरा लगेगा । परन्तु शकून अच्छे नहीं हुये । २२ अप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुँचनेवाला था । इसका उद्देश सीमा-प्रान्त के विशेष कानूनों के अमल की जाँच करना था । मण्डल अटक में ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया । इस समाचार पर पेशावर में जुलूस निकला और शाही बाग में विराट् सभा हुई । दूसरे दिन तक ही ६ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । ६ बजे दो नेता और पकड़ लिये गये । परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह विगड़ गई । नेताओं ने थाने पर आ जाने का आश्वासन दिया और वे छोड़ दिये गये । तदनुसार जनता उक्त नेताओं का जुलूस वनाकर काबुली दरवाजे के थाने पर ले गई । पर थाना बन्द था । इतने में एक पुलिस-

अफसर बोधे पर आ पहुँचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया और अकस्मात् दो-तीन सशस्त्र मोटरों आ पहुँची और मोड़ के भीतर घुस गई। इसी समय एक अग्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर में से किसीने गोली चलाई और सयोग से मोटर में आग भी लग गई। डिप्टी-कमिश्नर अपनी सशस्त्र मोटर में से उतरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया, किन्तु अल्दी ही होश में आ गया। उसके बाद सशस्त्र मोटरों में से गोलियाँ चलने लगी। लोगो ने मृत शरीरों को वहाँ से हटाने का प्रयत्न किया। फौजी दस्ते और मोटरों भी हटा ली गई। दूसरी बार फिर गोलियाँ चलाई गईं और वे करीब ३ घण्टे तक चलती रहीं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में मृतकों की संख्या ३० और घायलों की संख्या ३३ दी गई है, किन्तु लोग इन संख्याओं को करीब-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते थे। सायकल फौज कांग्रेस-दफ्तर में आई और कांग्रेस के विल्लो और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले गई। २५ तारीख को फौज और सामान्यतः बहा रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई। २८ तारीख को पुलिस ने फिर आकर कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों से, जो बाहर के दरवाजों पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का बार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फौज ने कब्जा कर लिया।

३१ मई १९३० को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने में गंगासिंह केम्बोज नाम के एक सज्जन, जो कि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने बाल-बच्चों के साथ पेशावर में एक तागे में काबुली-दरवाजे से गुजर रहे थे। उन पर के० ओ० वाई० एल० आई० के अग्रेजी लैन्स जमादार ने गोली चलाई, जिससे बीवी हरपाल कौर नाम की एक ११ साल की उनकी लड़की और काका बचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका लड़का ये दो बच्चे मारे गये और तागे से ऐसे गिर गये जैसे बिड़िया के बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की मा श्रीमती तेजकौर बाह और छाती में सल्ल घायल हुई। उनका स्तन तो विलकूट उड़ ही गया था। उन बच्चों के मृत-शरीरों का जुलूस डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। किन्तु डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा लेने पर भी फौज ने अधिया उठानेवालों और जूलूसवालों पर तितर-बितर होने की कोई नुचवा दिये बिना ही केवल दो गज के फासले से गोलियाँ चलाईं। अधियों के पहले उठानेवाले मारे जाते तो अधिया ब्रमीन पर गिर जाती और उन्हें फिर नये लोग आकर उठा लेते। ऐसा बार-बार हुआ। इस

प्रकार अमेम्बली में दिये मरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ बार गोलिया चलाने पर जुलूस के ६ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे।

जुलाई १९३० में मरकार ने एक और वस्तव्य निकाला था, जिसमें दिखलाया गया था कि ११ न० प्रेम-जाइनेन्स के अनुसार २ लाख ४० हजार रुपये की जमानतें १३१ अक्टूबरो में उन समय तक मागी जा चुकी थी। उनमें में ६ पत्रों ने जमानतें नहीं दी, अतः उनका प्रकाशन बन्द हो गया।

बम्बई में लाठी-चार्ज

१ अगस्त १९३० को बम्बई में लोकमान्य तिलक की वरसी मनाई गई थी और श्रीमती हसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय नगर-कांग्रेस की डिक्टेटर थी, एक जुलूस निकाला गया था। कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक नगर में लगातार तीन दिन से हो रही थी। वह उस समय बड़ा गैर-कानूनी घोषित नहीं हुई थी, क्योंकि मरकार उस हुक्म को एक प्रान्त में धीरे-धीरे जारी कर रही थी। कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायकाल के जुलूस में शामिल हो गये थे और जिस समय वे आगे बढ़े चले जा रहे थे उस समय उन्हें जुलूस निकालने की निषेधाज्ञा का वफा १४४ का नोटिस मिला। उस समय तक जुलूस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुक्म मिला उस समय सड़क पर एक विनाल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद भी एक डब हटना नहीं चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरो में ही बैठे थे। यह आशा की जा रही थी कि जुलूस को आधी रात के बाद आगे बढ़ने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था। किन्तु वह न हुआ। चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जबतक मैं न आजाऊँ तबतक कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह सुबह होते-होते बड़ा पहुँचे और भीड़ को विक्टोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने लगे। कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई-सी महिलायें भी, और तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी-प्रहार का हुक्म हुआ। कार्य-समिति के जो मेम्बर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे ५० मदनमोहन मालवीय, श्री बल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम, और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहन (बल्लभभाई की सुपुत्री) जुलूस में थी, इसलिए वह भी गिरफ्तार करनी गई। कोई-सी अन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थी। उनमें डिक्टेटर श्रीमती हसा मेहता भी थी।

पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत बनानेवालों को सजा देने का एक नया ढंग शुरु किया था। वह धरना देनेवालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रखकर बाहर से बहुत दूर ले जाती और उन्हें वहां छोड़ आती। वे लोग बिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने स्थानों पर आते। बम्बई में व्यापारियों की दुकानों में विदेशी कपड़े का धरना और मुहरबन्दी दोनों कार्य इतनी तीव्रता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जानेवाली लारी को रोकने के लिए उसके सामने बादू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालवादेवी रोड की है। हुआ यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया। इसके बाद बम्बई में हर मास इस वीर बालक की यादगार में बादू गणू-दिवस मनाया जाता था। कांग्रेस वहां जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था।

विभिन्न प्रान्तों में दमन

जब बल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर बाहर आये तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने बम्बई और गुजरात में कार्य को संगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और भी तीव्र कर दिया। उनके व्याख्यानो में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक नया उत्साह मिला। १३ जुलाई को वह उस आर्डिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और कांग्रेस का दफ्तर जप्त कर लिया गया था। बल्लभभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कांग्रेस-सत्या होना चाहिए। लॉर्ड अविन ने असेम्बली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिसमें सविनय-अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था, उसका बल्लभभाई ने मुहताब जवाब दिया था।

गुजरात में, बारडोली और बोरसद ताल्लुको में जिस तरह करबन्दी-आन्दोलन सफलता-पूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानो नाक थी। उसे दबाने के लिए अधिकारियों ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तग आकर २० हजार आदमी अंग्रेजी सीमा से निकल-निकलकर अपने पड़ोस के बड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये थे।

खुद श्री बल्लभभाई पटेल की मा, जिनकी उम्र २० वर्ष ने ऊपर है जब अपना खाना पका रही थी, उनके पकाने के बर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था।

मामा में जल-मामा ने कहा—तुम भी जाना रहे मरने के। बेचारे देहातियों को तो जोर-जारीना पट्टे दिए मरने के इन सब में अलग थे। छिन्नु फिर भी उनका बहुत ध्यान-रक्षण था। पर ऊँचे भी आदर-वन्दन की अंगिया में उनकी दशा—मामा में भी जोर भावना रहे थी।

इस प्रकार तत्वों को अधिकतर अपने के लिए लेना पड़ता है वह देना जरूरी है कि सदाशिव-साक्षात्कार में मायापूर्ण तत्त्वों के प्रान्त और भाग में अपने-अपने हिस्से का पद मान लिया।

भित्त-भित्त स्थान। में भित्त-भित्त तथा न आन्दो न ओर दगन चल रहा था
निम्ना तत्ता वा भित्त-भित्त पर्वतस्थिति, मन्त्री पर अथवा रा स्वभाव, वृद्ध की धर्म
मार्ति। एत प्रथमे ने उक्ति भाव पर बहू ही बुरी सीती। यथा लाठी-प्रहार, भारी-
मारी मुर्दाओं और जमी-जमी नाशों की शुरुआत आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं,
बल्कि पहले ही में हो गई थी। प्रधान-प्रान्त ने देशभर में सब प्रान्तों में अधिक हिंसा
दिने। अंग्रेजी राज्य का शासन बगाव और विद्रोह-उदारा में सबसे अधिक हुआ।
साल सन् १९२६ के मार्चदे में मध्य १९३० में अंग्रेजी राज्य का आगत ६५%
गिर गया था। स्थानीय वे युद्ध में गुजरान की हावगुजारिया अनुभव थी, वह हम
पात्रे रही थोड़े हैं। आम जन-जननी का आन्दोलन तो केवल समुक्त-प्रान्त में ही शुरू
रिखा गया था। महा असुख १९३० में जमींदारों और फ़ैक्टवारों दोनों को ही
मान और मानगुजारी रोक देने के लिए कहा गया था। पञ्जाब भी गतिमें पीछे
न रहा। अहिंसा-धर्म की दृष्टि में स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जिनगी राजनैतिक
ग्राम हुई उनकी ही नैतिक विषय भी हुई। बिहार में चौकीदारी-दैव्य देना काफी
हिले में चल गए दिया गया था। उम्मेक लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे फट रहे। बहा
ने लोगों को मजा देने के लिए चला अनिश्चित-मुल्लिम रण दी गई और छोटी-छोटी
गांवों के लिए उनकी बड़ी-बड़ी जायदादें जब्त कर ली गईं। मध्यप्रान्त में जंगल
मत्स्यायुद्ध शुरू किया गया। उनमें मफलता मिली। लोगो ने मारी-भारी जुर्मानी
और पुत्रि की ज्यादतियों के होने पर भी उसे जारी रखा। तीन लाख ताड़ और
गजूर के पेड़ काटे टाढ़े गये थे। मिर्सी तालुकों के १३० पटेलों में से ६६ ने, सिद्धानपुर
तालुकों के २५ ने और अकोला तालुकों के ६३ पटेलों में से ४३ ने त्याग-पथ दे दिये
थे। ये सभी तालुकों उत्तर कन्नड में है।

अगोला में गन्वन्दी-आन्दोलन का हेतु धुत से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी और मिदापर में वह आर्थिक कारणों से धुत हुआ था। किसानों की तबाही भी कारण

थी। केरल में, जो कि प्रान्तो में सबसे छोटा है, सविनय-अवज्ञा आन्दोलन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल है, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का सानदार जवाब दिया।

अन्य कुछ प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की ओर भी ध्यान दें। कुछ बातें तो सभी प्रान्तों में समान ही थी, जैसे कांग्रेस-दफ्तरो का बन्द कर दिया जाना, कांग्रेस के कागजों, किताबों, हिस्सों और झंडों का ले जाया जाना, लाठी-प्रहार और सार्वजनिक सभाओं का बलपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफ्ता १४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफ्ता में व्यक्तियों को नोटिस देना, बरों पर पुलिस का छापे मारना, तलाशियां लेना, प्रेसों को कब्जे में कर लेना और प्रेसों तथा पत्रों से जमानतें मांग लेना। किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और गराब की दुकानों के हित को दृष्टि में रखकर हो रहा था। बंगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहाँ दमन जोरों का हुआ। बंगाल और आन्ध्र दोनों में कांग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनको जो पीटे गये थे और असहाय पड़े हुए थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान-मालिकों को सजाये हुई थी। बंगाल में, उदाहरण के लिए खेरसाई में, जरा-सा भौका मिलते ही गोली चला देने की आज्ञायें दे दी गई थी। उस गांव में एक घर के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ जायदाद कुर्क की जा रही थी। उस समय भीड़ पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मरा और कई घायल हुए। चेचना में छोटती हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे ६ मनुष्य मर गये और १८ घायल हो गये। जून १९३० में कण्टाई में नमक बनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ मनुष्य घायल हो गये। खेरसाई में एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय इकट्ठी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहाँ गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे गये। २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशबन्धु दास का मृत्यु-दिवस मनाने का निषेध कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस पर निर्दयतापूर्वक लाठी-प्रहार किया। उस समय घायलों को घोटों के खुरों-द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए स्त्रियां घरों में से निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थी।

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीटा। वरीसाल में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे। ताम्रलुक में, कहा जाता है कि, पुलिस ने मत्थाग्रहियों और उनमें महानुभूति रखनेवाले लोगों

की जायदाद में आग लगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहों से भद्दे हमलों की खबरें आई थी। गोपीनाथपुर में कांग्रेस-स्वयंसेवक निर्दयतापूर्वक पीटे गये थे। उनमें से एक मुसलमान लड़का था। इस घटना से गांववाले अत्यन्त क्रोध हुए। उन्होंने पुलिस-वालों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद स्कूल में आग लगा दी। दो कांग्रेस-स्वयंसेवकों ने स्कूल के किवाड़ तोड़ डाले और अपने जीवन को खतरे में डालकर आग की लपटों से उन्हें बचाया। ३१ दिसम्बर को लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १९३० को उसके वार्षिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष बाबू को बुरी तरह पीटा गया। वह उससे कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की सजा भुगतकर जेल से छूटे थे। लाहौर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने असहयोग-युद्ध के चित्र को भी जप्त कर लिया था। लुधियाना में एक परदेवाली मुसलमान महिला पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र बेचते थे उनके घरों पर स्यापा (पंजाबी रोदन) किया जाता था। रावलपिंडी में खराब खाना खाने से इन्कार करने के लिए कैदियों पर अभियोग चलाये गये थे। माण्डगुमरी में एक भूल-हड़ताली ला० लाखीराम कई दिनों के उपवास के बाद मर गये। टमटम में एक महिला के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था। सीनेट-हाल में पंजाब-गवर्नर पर जो गोली चली उससे पुलिस को चाहे जिसकी तलाशी लेने का अवसर मिल गया। बिहार में आन्दोलन ने शान्तिपूर्वक प्रगति की थी। समस्तीपुर सब-डिवीजन में साहपुर-पटोरिया नाम का एक छोटासा बाजार है। अवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट की अधीनता में १२५ पुलिसवालों ने उसे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके ले गये और गांव से बाहर गये हुए कुछ आदिमियों की सम्पत्ति १२ बैलगाड़ियों में भरकर साथ लेते गये। दूसरे जिलों से भी ऐसी ही खबरें मिली थी। मुंगेर और भागलपुर में आन्दोलन जोरों पर था। शराब की दुकानों पर धरना देने से सरकार को ४० लाख का नुकसान हुआ था। मोतीहारी में फुलवारिया के धान के खेतों में होकर फौजी पुलिस और गोरखे फसल को कुचलते हुए ले जाये गये थे और अनेक देहातियों को गिरफ्तार करके लोगों में भय का संचार किया गया था। चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना और साहबजद जिलों में चौकीदारी-कर बन्द कराया गया था। मध्यप्रान्त में शराब के नीलाम की बोली ६०% कम बोली गई थी। अमरावती में गडवाल-दिवस मनाने के समय लाठी-भ्रंशार हुआ। आन्ध्र में पुलिस की सबसे बुरी करतूत यह थी कि उसने ८० व्यक्तियों की एक मित्र-मण्डली को, जो

२१ दिसम्बर १९३० को पैट्टापुर में मनोरञ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूब पीटा। उनमें से कितने ही लोगो को सख्त चोटें आईं। दो-तीन बहनें भी घायल हुई थी। उसके परिणाम-स्वरूप पुलिस पर दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। केरल में ताड़ी की बिन्नी ७०% कम हो गई थी। तामिलनाडु में ताड़ी की बिन्नी बन्द हो जाने से कितनी जगहों पर गोलिया चलाई गईं और लाठी-प्रहार हुए। दिल्ली में एक रायसाहब शराब के व्यापारी थे। उन्होंने ८० महिलाओं और १०० पुरुष-स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। अजमेर में एक दिन में लगभग १५० गिरफ्तारियां हुईं। जेल में 'ए' क्लास के कैदियों तक को पीटा गया।

किसानों की हिजरत

गुजरात में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि० प्रेसफोर्ड ने इस प्रकार किया है —

“ और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतों में है। इन देहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाड़ियों में जमाया और फिर वे उन्हें बड़ीदा की सीमा में ह्राक ले गये। दूध-जाति-संगठन के कारण ऐसी एकता हिन्दुस्तानियों में ही हो सकती है। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फलसों को ले जाना असम्भव देख जला दिया। मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने चटाइयों की बीवारें और टाट पर ताड़के पत्ते बिछाकर छतें बनाली और कामचलाऊ घर बना लिये हैं। वर्षा समाप्त हो गई है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। किन्तु वे अपने प्यारे पशुओं-सहित एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं, और उनका सामान जिसमें चावल रखने के उनके बड़े-बड़े मिट्टी के बर्तन, विछौने और दूधबिलीने, सन्तूक, पीतल के चमकते हुए वर्तन थे, चुना हुआ था। उनका हल भी एक ओर रक्खा हुआ था, दूसरी ओर उनके देवताओं का चित्र था, और सर्वत्र डगर-डगर इस पड़ाव के मानो अन्धश्रद्धा देवता महात्मा गांधी के भी चित्र थे। मैंने उनमें से एक बड़े दल से पूछा कि आप लोगो ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये हैं? स्त्रियों ने बहुत जल्दी सीधे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैं'। पुरुषों को अपने आर्थिक कष्ट का ज्ञान था। उन्होंने कहा, 'खेती में इतना पैदा नहीं होता और लगान बेजा है'। एक दो ने कहा, 'स्वराज्य लेने के लिए'।

“मैंने सूरत की कांग्रेस के समापति के साथ उन परित्यक्त गावों में भ्रमण करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेंगे। घरो की कतार-की-कतार खाली पड़ी थी। उनपर कपड़ा सिले हुए ताले लगे थे। खिड़कियां खुली पड़ी थी। जिनमें से देखा जा सकता था कि ये घर बिल्कुल खाली हैं। गलिया प्रकाश की नीरव झीलें थी, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी।

“चूँकि मैंने खुद उनके कुछ तौर-तरीके देखे थे, इसलिए इस बात पर विश्वास करना कठिन न था। इन परित्यक्त गावों में से एकसे जब हमारी मोटर रवाना होने लगी तो समीप बड़ी हुई राइफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि ‘आप पुलिस की लिखित आज्ञा लेकर ही गांव से जा सकते हैं’, किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तो वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अंग्रेजी में सिटपिटाते हुए बोला, ‘हुजूर!’ किन्तु मजे की बात तो यह थी कि उसकी बर्दी पर नम्बर का कहीं पता भी न था। जब मैंने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते हैं। वह सिपाही उस दल का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयर्लैंड के ‘ब्लैक एन्ड टान्स’ दल से मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होंगे कि उनकी बर्दियों पर उनके नम्बर नहीं रहते हैं।

इस दुःखमयी कहानी को समाप्त करते हुए हमें पेशावर और बहा के पठानों के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्दयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों के समान सीधे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन गये। खान अब्दुलगफ्फारखा ने अपने ‘खुदाई खिदमतगारों’ का ऐसे सुनियंत्रित और सच्चे ढंग से संगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्द्र बन गया था। सीमा-प्रान्त में की गई निर्दयताओं को बिल्कुल अन्वकार में रक्खा गया था और श्री विट्ठलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जवाब करली थी, किन्तु कुछ मिसालें तो इतनी मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ का वर्णन हो ही चुका है।

एक महत्त्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहाँ उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो दमन वृत्ता उस सिलसिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निःशस्त्र सीढ़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया। इसी कारण इन

सिपाहियों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्बी सजाये दी गई। मार्च १९३१ की कांग्रेस और सरकार के बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का प्रश्न मुख्य विवादास्पद विषय था।

यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांधी-अविन समझौते में नहीं छोड़े गये थे, किन्तु कुछ साल बाद इनकी सजायें थोड़ी दी गईं। कुछ लोग कुछ ज्वालों में छूट गये और कुछ असीतक जेल में हैं।

इस रोमाञ्चकारी दुःख-कथा को हम २१ जनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय बोरसद में दिखाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियों ने जुलूसवालों को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के बड़े-बड़े बर्तन रख छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनों को ही तोड़ा। फिर स्त्रियों को बलपूर्वक नितर-बितर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियां गिर गईं तो पुलिसवाले उनके सीनों को बूटों से कुचलते हुए चले गये। पुलिस के गुण्डेपन का कदाचित् यह अन्तिम कार्य था, क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की बातचीत चलाने योग्य बानावरण उत्पन्न करने के लिए गांधीजी और उनके २६ साथियों को बिना शर्त छोड़ देने की विनम्र प्रकाशित हुई थी।

मुलाह के असफल प्रयत्न

हम अपने पाठकों को जून, जुलाई, और अगस्त महीनों की ओर फिर वापस ले जाना चाहते हैं। २० जून १९३० की पण्डित मोतीलाल जी में, जबकि वह बाहर ही थे, 'डेली हेराल्ड' के मवाददाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाक़ात की। मि० स्लोकोम्ब ने बम्बई में पण्डितजी में 'कांग्रेस किस शर्तों पर गोलमेज-परिषद् में शामिल हो सकती है?' इस विषय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन बाद मि० स्लोकोम्ब की सोची हुई शर्तों पर एक मभा में, जिसमें पण्डितजी, श्री जयराम और मि० स्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुईं। मि० स्लोकोम्ब ने यह मन्त्र तो भी एक पत्र लिखा था, उनके परिणाम-स्वरूप यह मन्त्र जो श्री जयराम उन शर्तों के आधार पर वाइसराय ने बातचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए। पण्डित मोतीलालजी नमस्ते की लजबोजी लेकर कांग्रेस के महापति प० आहमदशाह ने, श्री जयराम की बात जाने को राजी हो गये। शर्त यह थी कि ब्रिटिश-अवसर और भारत-महापति उन्हें

निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जायें कि, चाहे गोलमेज-परिषद् की कुछ भी सिफारिशें हो और चाहे पार्लमेण्ट हमारे प्रति कुछ भी रख रखे, वे स्वयं भारतवर्ष की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की मांग का समर्थन करेंगी। शासन-परिवर्तन की खास-खास तर्मीमो और शर्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिषद् रखे, उसमें गुजाइश रहे। इस आचार पर मध्यस्थो ने वाइसराय से लिखा-पढी की और गांधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी। यह १३ जुलाई की बात है। तबतक मोतीलालजी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होंने वादा किया कि 'हम भारतवासियों को उनके गृह-प्रबन्ध का उतना अक्ष दिलाने में सहायता देंगे जितना कि उन विषयों के प्रबन्ध से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेवारी लेने की स्थिति में वे नहीं हैं।' इन दो कागजों को लेकर श्री सप्रू और जयकर ने यरवडा-जेल में २३ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नैनी-जेल (इलाहाबाद) में ५० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया। गांधीजी चाहते थे कि गोलमेज-परिषद् के बाद-विवाद को सरक्षणो-मन्वन्धी विचार तक ही सीमित रखा जाय। सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न देना चाहिए। गोलमेज-परिषद् की रचना सतोप-जनक होनी चाहिए। सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के रोक लेने की दशा में भी तबतक विदेशी वस्त्र और धराब का करना जारी रहना चाहिए जबतक कि सरकार स्वयं धराब और विदेशी वस्त्र का निषेध कानूनन न करे और नमक का बनाया जाना बिना किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने राजनैतिक बन्धियों के छुटकारे का, जायदादों, ज़ुर्मानों और जमानतों के वापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुनर्नियुक्ति का और आर्डिनेन्सों को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होंने सन्देश-वाहको को सावधान किया था कि मैं एक कैदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक गति-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। ये महाविरे मेरे अपने हैं। मैं स्वराज्य की हरेक योजना को अपनी ११ शर्तों से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। ५० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने समझौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देश प्रकट किया था। इन कागजों के साथ सन्देश-वाहको ने २७ और २८ जुलाई को ५० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। खूब बहस भी हुई। मोतीलालजी और जवाहरलाल जी

ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य विषयों पर एक समझौता न हो जाय तबतक किसी भी परिपद में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी।

- जवाहरलालजी ने एक पृथक् नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी की वैधानिक विषय-सम्बन्धी गांधीजी के विचार जँचते नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं हैं, और न उनसे वर्तमान समय की भाग की ही पूर्ति होती है। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को श्री जयकर गांधीजी से मिलने, तब गांधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पृथक् होने की इजाजत न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिले। मैं अंग्रेजों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जाच के लिए एक स्वतंत्र कमिटी चाहूँगा। गांधीजी चाहते थे कि बाइसराय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके चोखे दिन बाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवड़ा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवड़ा जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके।

इस प्रकार वहा १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ थे जयकर-समू और दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेहरू, बल्लभभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास दीलतराम और श्रीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, सम्झौते की शर्तों को, जिनका अभी जिक्र किया जा चुका है, दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक् होने के हक को और अंग्रेजों के दावों और उनकी रियायतों की जाच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की भाग को भी शामिल कर दिया था। बातचीत को समाप्त करते समय गांधीजी, श्रीमती मगोजिनी, बल्लभभाई पटेल और श्री जयरामदास दीलतराम ने सन्देश-चाहूँगों को शान्ति-स्थापना के लिए उठाई हुई तकलीफों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें सुनाया कि "अब जिनके हाथ में कांग्रेस-मस्यौमें हैं वे हम विसीसे मिलने-जुलने की गुंजायिश स्वभाव न पा सकेंगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उनकी ही इच्छा है तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

वाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बल्लभभाई पटेल

कि मैं तो प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक बन्धियों को बड़ी सख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलों पर उनके प्रकारों और योग्यता के अनुसार विचार वही करेगी। दोनों नेहरूओं ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांधीजी को लिखा कि बाइसराय मुख्य प्रारम्भिक बातों पर विचार करना भी गैर-मुमकिन खयाल करते हैं। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि शान्ति की बात-चीत असफल हो गई। (देखिये परिशिष्ट ६)

समूह-जयकर की समझौते की बात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैषियों को निराशा नहीं हुई। उसके बाद मि० हौरेस जी० अलैक्जेंडर के, जो सैली ओक कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह बाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई सत्याग्रह-मन्दार न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की सीधी-सादी समस्याओं का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड अविन ने एक दर्जन के करीब आर्डिनेन्स निकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन (Unlawful Instigation) आर्डिनेन्स, प्रेस-आर्डिनेन्स और गैर-कानूनी सन्ध्या (Unlawful Association) आर्डिनेन्स भी शामिल थे। लॉर्ड अविन ईमानदारी के साथ एकदम 'टुहरी नीति' का अनुसरण कर रहे थे। वह आर्डिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता की थोड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन से कहा था—“यद्यपि हम जोरदार सड़कों में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की निन्दा कर सकते हैं, किन्तु यदि हम भारतवासियों के मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयता की आग धक्क रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठीक न समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे।”

गोलमेज-परिषद् शुरू

१२ नवम्बर १९३० को गोलमेज-परिषद् शुरू हुई। अयर-हाउस की ग्राही गैलरी में बड़ी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे जिनमें १६ रियासतों से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैण्ड के मित्र-मित्र दलों के मुखिया थे। गोलमेज-परिषद् बीच-बीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभीने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि सघ-राज्य के पक्ष में थे। शास्त्रीजी

जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में बहुत बच्छा बोले, पहले तो सम्मानन के पक्ष में कुछ शिक्षक तो हुए बोले, किन्तु पीछे उसी के पक्ष में दूढ़ हो गए। प्रधान-मंत्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य बातें रक्खीं। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछली बात की खूबियाँ दिखलाई। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीढ़ी पवित्र विरासत समझेगी। उनके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियाँ बनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-मजदूरों, ब्रह्मा, सरकारी नौकरियों और प्रांतीय तथा मध्य-शासन के टाचों के बाबत वाक्यांश रिपोर्टें दीं। परिषद् अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इस लिए १६ जनवरी को बुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टें और नोटों में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान् मामलों मिलनी हैं यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रक्खा जाय।

प्रधान-मंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ-शासन के आधार पर जो व्यवस्थापक-सभा बने, जिसमें रियासतें और प्रांतों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्यरक्षा और वैदेशिक मामलों के विषय सुरक्षित रक्खे जायेंगे। राज्य की शान्ति और आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नर-जनरल को विशेष अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयों की विषयों की बतलाई गई थी। उसके बाद प्रधान-मंत्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादों की घोषणा की थी —

“ब्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेवारी प्रांतीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओं पर रक्खी जाय। संक्रमण-काल में साम-खास जिम्मेवारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी साम-खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रक्ख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्प-मजदूरों को जिनकी गारंटी आवश्यक है वह भी उसमें हो।

“संक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी नगमन रक्खे जायेंगे उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रयत्न बनैव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हो और उन्हें इस प्रकार ने काम में लाया जाय कि

उनसे नये शासन-विधान-द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी तक बढ़ने में कोई बाधा न आवे।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस बीच में वाइसराय की अपील का जवाब उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।”

पहली गोलमेज-परिपद् की, जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस परिपद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १९ साधियों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ भावमियों की रिहाई से यह सच्चा और भी बड़ गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भापा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहाँ देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर ‘रिआयती’ (Privileged) लिखा हुआ था।

‘रिआयती’ प्रस्ताव

यह ‘रिआयती’ प्रस्ताव कांग्रेस-कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को शाम को ४ बजे स्वराज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था —

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस ‘गोलमेज-परिपद्’ की कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के खास-खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समयको में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है, उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो यह है कि वह भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, आर्डिनेन्सों और सजाओं-द्वारा और सविनय-अवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य-समिति सभी कुचली हुई जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक्ति-पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए

हजारों शान्त, शस्त्र-हीन और मुकाबला न करने वाले लोगों पर लाठी-प्रहार करके और गोळियाँ चलाकर, इस देश की सच्ची आवाज को रोकती रही है।

“इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १९३१ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ट-द्वारा घोषित ब्रिटिश-सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस समिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

“यह समिति लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर बृहद् है और यरवड़ा जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी, प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों की जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की घोषणा में उसके लायक उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता। समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में और हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि कांग्रेस-कार्य-समिति के असली सदस्य और महा-समिति के अधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जबकि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई भी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय स्वयं का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अन्त हर्षित नहीं हो सकता। इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुई हिदायतों के अनुसार पूर्ण क्षिति से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उसने अबतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रखेगी।

“समिति देश के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की उस हिम्मत और मजबूती की इस अवसर पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उस सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में ठूसने की, कितने ही आम और पाषाणिक लाठी-प्रहारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलों में तथा बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अण्ण हो गये और मर गये, सम्पत्ति लूटने की, घरों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सों में सशस्त्र पुलिसवालों, सवारों और गोरे सिपाहियों की, लाइनों को घुमाने की, लोगों के सार्वजनिक व्याख्यान देने, जुलूस निकालने और समा करने के हकों को छीनने की और कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य सस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जब्त करने की और उनके घरों तथा दफ्तरों पर कब्जा करने की जिम्मेवार है।

“समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशापूर्ण होकर स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का दृढ-निश्चय कर चुका है।”

सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं ? इसपर मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ। लन्दन से डॉ० सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-समिति से उनके आने से पहले उनकी बातें बिना सुने प्रधानमंत्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह तभी गोलमेज-परिषद् के बाद भारतवर्ष को छोड़नेवाले थे। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु जैसा कि ऐसे प्रायः सभी मामलों में हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर बाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी।

गवर्नर-जनरल का वक्तव्य

२५ जनवरी १९३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला —

“१९ जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसपर विचार करने का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १९३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, वातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय।

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभाये करें उनके लिए कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला ऐलान प्रान्तीय सरकारों-द्वारा वापस ले लिया जायगा और गांधीजी तथा अन्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या जो १ जनवरी १९३० में सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

“मेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई जर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें है कि सम्बन्धित लोग बिना शर्त आजाद होकर बातचीत करें। हमने यह कार्रवाई ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधानमंत्री

: १ :

गांधी-अर्विन-समझौता-१६३१

गांधीजी का सन्देश

कार्य-मार्ग-समिति के सदस्यों की रिहार्ड २६ जनवरी की आधीरात से मे पहले होनेवाली थी और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्निया यदि जेल में हो तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। चूँकि जो लोग बीच-बीच में किसीके दबाय (कार्य-मार्ग-समिति के) मदद करने के उनकी रिहार्ड की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संख्या २६ पर पहुँच गई। गांधीजी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव के ही अनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता में वह फूल भी नहीं उठते। उन्होंने कहा —

“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसीके प्रति मुझे कोई शत्रुता है और न किसी बात का तात्सुब। मैं तो हरेक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने और सर तेजवहादुर सभू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ।”

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इंगित किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि “पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता, न लाखों मूसो-मरते लोगों-द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि ज्यादातर आर्डिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि मैं शान्ति

के लिए तरस रहा हूँ, वसतें कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी सुलह में मैं साझीदार न होऊँगा जिसमें पूर्वोक्त तीन बातों का सन्तोषजनक हल न हो। “इसलिए गोलमेज-परिषद्-रूपी पेड़ का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए।”

गांधीजी, छूटते ही, ५० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहाँकि वह बीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी वही बुलाया गया। वही स्वराज्य-मवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पास हुआ —

“कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सप्रू और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्वसाधारण में यह खयाल फैल गया है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। इसलिए समिति के इस निश्चय की ताईद करना आवश्यक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तबतक आन्दोलन बराबर जारी रहेगा। यह सभा लोगों को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े और धराब तथा अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर धरना देना अपने-आप में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अंग नहीं है, बल्कि जबतक वह बिल्कुल शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है।

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, व्यापारियों और कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को स्मरण कराती है कि चूँकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग है और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से बहिष्कृत कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतिबन्धक-सटकर लगाकर।

“विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करती है, लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-मस्था उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको वह कहीं और खपा देगी।”

प० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे। पण्डित मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तबतक करीब-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए वहाँ से चले गये, पर गांधीजी-सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांधीजी तो मोतीलालजी के साथ लखनऊ भी गये, जहाँ मीत से बड़ी कशमकश के बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलालजी सदा के लिए हमसे विदा हो गये—“हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिए। मेरी मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी साक्षीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतन्त्र-भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नीब गुलाम देश में नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो।” इस प्रकार पण्डितजी की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक सही तबीयत के आदमी थे—न केवल बौद्धिक दृष्टि से बल्कि धन, संस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियों से। जब कि उनकी दूरन्देही और तत्काल-बुद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओं को स्पष्ट रूप से सुलझाने में बड़ी मदद मिलती उस समय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति थी कि वस्तुतः जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह न केवल बड़े दूरन्देह ही थे, बल्कि हमारे सामने छाई हुई राजनैतिक समस्याओं की तफसीलों में उतरकर जल्द और सही निर्णय पर पहुँचने में भी एक ही थे।

हालांकि उनका रहन-सहन बहुत अमीरी था, मगर गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की आवश्यकता महसूस की; और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीबी और कष्ट-सहन को अपनाया। यह भी नहीं कि उन्होंने अपने धन का अकेले ही उपयोग किया हो। वह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी अपने धन का भागीदार बनाया है। कांग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभक्ति और उदारता के अनुकूल ही थी। लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट नहीं कह सकते, उनकी सबसे बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को अज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेण्ट-जनरल के बड़े-बड़े ओहदों पर न देखना चाहें,

लेकिन मोतीलालजी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। मोतीलालजी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी स्प्रिट, अब भी कांग्रेस के ऊपर मौजवा रही है और विचार-विनिमय एवं निर्णय के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है।

राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात वस्तुतः शोकजनक थी, और जिसके लिए गांधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैण्ड में खूब चित्ला-चित्लाकर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की जो बात कही जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। "भारो ओर दमन-चक्र अपने भयंकर रूप में जारी है," 'न्यूज क्रैनिकल' को दिये हुए अपने तार में गांधीजी ने लिखा, "मिर्दोष व्यक्तियों पर अकारण मारपीट असीतक जारी है। इज्जतदार आवसियों की चाल और अचल सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सरसरी तौर पर बरायनाम कानूनी कार्रवाई करके जब्त कर ली जाती है। स्त्रियों के एन जुलूस को रंग करने में बल-प्रयोग किया गया। उन्हें जूतों की ठोकड़ें मारी गईं और बाल पकड़कर घनीटा गया। ऐसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी कठिनाइयां हल ही क्यों न हो जायें।

वाइसराय से मुलाकात

खानगी तौर पर इस बात की हिदायतें जारी की गईं कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहे, पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी बात शुरू न की जाय जिसने परिस्थिति कोई नया रूप धारण कर ले। ठीक इसी समय गोलमेज-परिषद् में, गये हुए प्रतिनिधि लौट कर हिन्दुस्तान आये और लाते ही, ६ फरवरी १९३१ को उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकार अपील की :—

"(गोलमेज-परिषद् की) योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफ्तील की बातें तो, जिनमें से कुछ बहुत सार की और महत्वपूर्ण हैं, अभी छग होती हैं। हमारी यह दिली स्वाहिन है कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे बढ़कर इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है कि वातावरण को ऐसा शान्त कर दिया जायगा जिसमें इन आवश्यक विषयों पर भलीभांति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके।"

लेकिन इसके बाद भी सजायें दी जाती रही और फरवरी १९३१ में कानपुर, शहर में पिकेटिंग के अपराध में १३६ गिरफ्तारियां हुईं। साथ ही जेलों में भी—

क्या खाना-कपड़ा और क्या दवा-दारू—कैदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजान्ता बैठक हुई। उस समय तक डॉ० सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गांधीजी व कार्य-समिति से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की। यहाँ तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मुद्रता तक न रख पाते थे, क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी बात कह गये थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोप भी छा रहा था। खैर, जो हो। गांधीजी ने लॉर्ड अविन को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही ज्यादतियों, खास-कर २१ जनवरी को बोरसद में स्त्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जाच कराने के लिए कहा। लेकिन इस माग को ठुकरा दिया गया और ऐसा मालूम होने लगा मानो सुलह-शान्ति की सारी बात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस और सरकार को मिलना है तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को बिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीजी अपनी ओर से वाइसराय को मुलाकात के लिए क्या न लिखें, अजब इसके कि बाजान्ता पत्र-व्यवहार की बात देखते रहें? सत्याग्रही को शान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अतएव गांधीजी ने लॉर्ड अविन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे बहसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के बड़े सबरे तार-द्वारा इसका जवाब आ गया। १६ तारीख को ही गांधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुँच गये। कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव-द्वारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे। गांधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली बार मुलाकात की और कोई चार घण्टे तक वाइसराय से उनकी बातें होती रही। तीन दिन तक लगातार यह बात-चीत चलती रही।

इस बात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादतियों की जाच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इनके अलावा वे शर्तें भी जो कि

सुलह के समय आम तौर पर हुआ करती है, जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष कानूनी (ऑब्जेन्सो) को रद्द करना, जव्व की हुई सम्पत्ति को लौटाना और उन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हटा दिया गया है फिर से बहाल करना। ये सब बातें, खासकर पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जाच के विषय, ऐसी विवादास्पद थी कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं थी। १६ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठी हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे बात-चीत होने में कई दिन लग जायें।

पहले दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीजी डॉ० मन्सारी के यकान पर लौटे जहाँ कि वह स-बलबल ठहरे हुए थे। पहले दिन की बातचीत से एक प्रकार की निश्चित आशा बँधती थी। दूसरे दिन यह स्पष्ट हो गया कि गांधीजी की स्थिति को वाइसराय समझते तो हैं, लेकिन उसके अनुसार करने को तैयार न थे। चूकि इंग्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए बातचीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावना पैदा हो गई, और स्वयं वाइसराय ने गांधीजी को बुबारा शनिवार २१ तारीख को बुलाने के लिए कहा। लेकिन गुरुवार १६ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुँचा। इसर सरकार और कांग्रेस के बीच चलनेवाली बातचीत के दौरान में उठनेवाले विविध विषयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर २० हो गई। वाइसराय लन्दन से इस विषय में तार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक ठहरना पड़ा।

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा आ ही पहुँचा। २७ ता० को गांधीजी वाइसराय के पास गये और साठे-तीन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक बातचीत हुई। बातचीत में कटोर शब्द एक भी नहीं कहा गया, और वाइसराय इस बात के लिए उत्सुक थे कि गांधीजी बातचीत तोड़ न दें।

२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार गांधीजी ने पिकेटिंग के बारे में उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित ममतीने के बारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को लिख भेजे। समझौते के मिलनिले में उठी हरो बात पर वाइसराय ने गांधीजी के निश्चित विचार जानने चाहे और उनके लिए, जैसा कि

पहले नर हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के २॥ बजे उन्हें वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराशाजनक मालूम पड़ने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि फिर में लड़ाई छेड़े बिना कोई चारा नहीं है। कार्य-समिति के दूरक सदस्य के मुह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी कि “समझौते का वातचीत बन्द कर दो।” कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही चारों तरफ यह बात फैल गई। चारों तरफ हलचल मच गई और हर जगह परेशानी नजर आने लगी।

निश्चित समय पर गांधीजी वाइसराय में मिले और सायंकाल ६ बजे वाइसराय-भवन में वापस आ गये। उतने घंटे समय में उनके लौट आने से एकदम निराशा छा गई, लेकिन धीमे-धीमे समझौते की फिर में आशा बघने लगी। १ मार्च के होने पर जब गांधीजी वाइसराय में मिले तो वाइसराय का सब बिलकुल रोमाना था। होम-सेक्रेटरी मि० उमरंग भी वही अच्छी तरह पेश आये। वाइसराय ने गांधीजी से कहा कि मि० उमरंग के सलाह-मजबिरे से वह पिकेटिंग के बारे में कोई फ़ैसल नहीं।

आशाजनक परिस्थिति

इनके बाद बातचीत थोड़ा बढल गया। आपस में मित्रता के आझार नजर आने लगे। इनने समय के बाद अब सम्भवत हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों की भावना के ऊपर कर्तव्य-भाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझौता बिलकुल ही न हुआ होता। पिकेटिंग के बारे में यह सब एक बात यह थी कि वह सारे “विदेशी माल के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माल के ?” दूसरी बात उसके लिए ग्रहण किये जानेवाले माधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश-माल का वहिष्कार प्रारम्भ में कार्यक्रम-कार्यक्रम का अंग नहीं था बल्कि बाद के सालों में, नासकर लड़ाई के दिनों में, उसमें शामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है कि उसी लड़ाई के लिए और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव टालने को राजनैतिक दाय्य मानकर ही ग्रहण किया गया था। अतएव विदेशी माल की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस प्रकार, जैसा कि आगे हम देखेंगे, समझौते की एतद्विषयक भाषा बिलकुल स्पष्ट कर दी गई। वाइसराय ने वहिष्कार शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उनके खयाल में पिकेटिंग और वहिष्कार ऐसी चीजें हैं जो एक-दूसरे के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। और अस्थायी सन्धि के समय विदेशी माल और ब्रिटिश-माल में फर्क तो किया ही जाना

चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लार्ड अविन ने गांधीजी और मि० इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया।

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सन्तोषजनक रही। यह तय रहा कि इसके बाद जुर्मनि वमूल नहीं किये जायेंगे लेकिन अमीतक जो रकम वसूल हो चुकी है वह नहीं लौटाई जायगी। कैदियों के रिहाई के बारे में बाइसराय ने उदारता और महानुभूति के साथ विचार करने का वादा किया। पहली मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दगा, बारास्त व चोरी के जुर्मों पर विचार हुआ। प्रसंगवश यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के बाद गांधीजी फिर से बाइसराय-भवन गये थे और बातचीत पुन आरंभ हुई थी। गांधीजी ने नजरबन्दों का भी प्रश्न उठाया और बाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं पर ब्यक्तिगत रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जवाब सम्पत्ति के बारे में तय हुआ कि उसमें से जो बिक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती। गांधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों से सीधी बातचीत चलाने के लिए तैयार नहीं है। मगर जज्ज जमीनों के बारे में बम्बई-सरकार के नाम एक सिफारशी चिट्ठी गांधीजी को देने का बाइसराय ने वादा किया।

गांधीजी ने इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री बल्लभभाई पटेल ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलेक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिन्होंने लडाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे में तो स्थिति अच्छी ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता है वहाँ से आजादी के साथ नमक लेने देने का बाइसराय ने आश्वासन दिया। यह एक ऐसी सुविधा थी जो गांधीजी के लिए बड़ी सन्तोष-जनक हुई। पुलिस की ज्यादातियों के प्रश्न पर दोनों ही अड गये। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेको कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ वह मुझे आदेश देगी मैं तो बाबुशी उसीका पालन करूँगा। “अगर आप बात-चीत तोड़ना चाहें”, उन्होंने कहा, “तो मैं बातचीत तोड़ने के लिए ही बाइसराय के पास जाऊँगा।” बाइसराय से बातचीत करके वह रात के १ बजे वापस आये और रात के २। बजे तक कार्य-समिति के सदस्यों व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया। बाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक हल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च

का दिन तब था, क्योंकि २ मार्च को मोमचार पड़ता था, जो गांधीजी का मोन-दिवस था।

समझौते की जो जाना बंध रही थी, ३ मार्च को उसमें एक और बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई। बारडोली के किसानों की जमीन छोटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अब फिर उन मामलों को उठाया गया। उस वारे में जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा होगा जिनकी या जिने चलकर नहीं मान ले। अतएव दिन की बातचीत में गांधीजी ने वात्सराय से कहा कि मैं कोई ऐसा हल सोचकर कि जो बल्लभभाई को मान्य हो, वह तो फिर आउंगा, इसलिए किलहाल उन विषय की चर्चा बन्द कर देना चाहिए। उधर, बल्लभभाई यह भी वि, वात्सराय की भी अपनी कठिनाईया थी। यह समझा जाता है कि जब बारडोली में हरबन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होंने बम्बई-सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि चाहे कुछ हो, मैं किसानों की जल जमीनें छोटाने के लिए तैयार नहीं करूंगा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि अब उसमें तिलकूल उलटी दान लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि गांधीजी मेरे पुण्योत्सवदाम और मेरे दाहीम रहीमतुल्ला से इसके लिए बीच में पड़ने को कहें, और आना प्रारंभ की कि सब ठीक हो जायगा। गांधीजी ने कहा कि वात्सराय स्वयं ऐसा करें। आगिरकाय वात्सराय बम्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को तैयार हुए कि जमीनें प्राप्त कराने के मामले में पूर्वोक्त दोनों महानुभावों की मदद हो जाय। और अगतिपत हो यह है कि इस बातचीत के दौरान में बम्बई-सरकार ने रेवेन्यू-मेम्बर भी दिल्ली पहुंचे थे जो, यह स्पष्ट है, इस सम्बन्धी बातचीत के लिए ही बुलाये गये थे। श्री मधू, जयकर और नाथ ही वात्सरायजी ने, जब कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे गुलजाने के लिए, बड़ा काम किया।

आरजी मुलह

उपरोक्त सभी बहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि कम अब समझौते की बातचीत भग हुई। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उल्लिखित हल निकाला गया और उसके साथ धारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहातक सरकार से सम्बन्ध है'—जो कि सर पुण्योत्सवदास ठाकुरदास और सर दाहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के बीच में पड़कर सम्भव हो तो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गर्ज से किया गया।

३ तारीख की रात के २॥ बजे (अर्थात् ४ मार्च १९३१ के बड़े सबेरे) गांधीजी

वाइसराय-भवन से वापस लौटे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। गांधीजी बड़े उत्साह में थे। मामूल के मुताबिक गांधीजी ने उस रात की सब घटनायें कार्य-समिति के सदस्यों को सुनाईं। कार्य-समिति के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वादविवाद हुआ था, क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसविदा बनाया गया उसमें मुसलमान दूकानदारों के यहाँ पिकेटिंग न करने की धारा रखी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड़ ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोड़ी-बहुत खामी थी। कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तफसील में उनपर विचार किया जायगा। सोलापुर के और गडवाली कैदियों का तो उसमें जिक्र ही नहीं था। पिकेटिंग-सम्बन्धी धारा के कारण विशेषतः ब्रिटिश माल पर ही बरना नहीं दिया जा सकता था। जन्तुसुदा या बेघर की जानेवाली जमीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या बन गई थी, क्योंकि १७ (स) धारा उसमें मौजूद थी, जो कांग्रेस के लिए एक बिकट समस्या थी।

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सम्बन्धी एक अत्यन्त आवश्यक विषय को तैय कर लिया, अलवत्ता यह धर्त रखी गई कि यदि कार्य-समिति उसे मजूर कर ले। गांधीजी उस योजना पर आये विचार चलाने के लिए तैयार हो गये, जिसपर "भारत में वैध-शासन स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिषद् में विचार हुआ था और जिस योजना का सध-शासन तो अनिवार्य अंग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साक्ष और जिम्मे-दारियों की अदायगी जैसे विषयों पर प्रतिबन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गांधीजी और वाइसराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके ऊपर था कि वह चाहे तो उसे मजूर करे और चाहे तो रद्द कर दे। बल्लभभाई समझौते के जमीनो-सम्बन्धी अंश से सहमत नहीं थे। जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी अंश नापसन्द था। कैदियों वाली बात पर तो किसीको भी सन्तोष न था। लेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक को सन्तोष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहा रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती। जब कांग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी बात रहे। अलवत्ता कार्य-समिति चाहे तो प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रद्द कर सकती थी। गांधीजी ने अलग-अलग

कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या हरेक बात पर, या आप कहीं तो समूचे समझौते पर, मैं सुलह की बातचीत तोड़ दू ?

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच खूब गहरा वाद-विवाद होने के बाद यह समझौता बनकर तैयार हुआ। गांधीजी और लॉर्ड अविन में जो श्रेष्ठतम गुण थे उनमें से कुछ का इस बातचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। उसीके परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १९३१ को), यह समझौता हुआ जो ज्यो-का-स्थो नीचे दिया जाता है —

सरकारी विज्ञप्ति

“सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल का निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है —

(१) बाइसराय और गांधीजी के बीच जो बात-चीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्राट् सरकार की सहमति से भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें।

(२) विधानसबधी प्रश्न पर, सम्राट्-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर गोलमेज-परिषद् में पहले विचार हो चुका है। वहा जो योजना बनी थी, सब-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है, इसी प्रकार भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिबन्ध या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं।

(३) १९ जनवरी १९३१ के अपने वक्तव्य में प्रधान-मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर आगे जो विचार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

(४) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध है।

(५) सविनय अवज्ञा अमली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन

को अमली तौर पर बन्द करने का मतलब है उन सब हलचलों को बन्द कर देना, जोकि किसी भी तरह उसको बल पहुँचानेवाली हो—खासकर नीचे लिखी हुई बातें—

- १ किसी भी कानून की धाराओं का सगठित भग ।
- २ लगान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन ।
- ३ सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित करना ।

४ मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियों को या गांव के अधिकारियों को सरकार के खिलाफ अथवा नौकरी छोड़ने के लिए आमादा करना ।

(६) जहाँ तक विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके । इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माली हालत को तरक्की देने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अग्र-रूप भारतीय कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-बुझाने व विज्ञापनबाजी के उन उपायों में रुकावट डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिकूल न हो । लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में—सम्पूर्णतः नहीं तो भी प्रधानतः—ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-रूप से राजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए दबाव डालने की गरज से ।

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश-भारत, देशी राज्य, सम्राट की सरकार और इंग्लैण्ड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच होनेवाली स्पष्ट और भिन्नता-पूर्ण बातचीत में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस समयझोते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा । इसलिए यह बात तय पाई है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द करने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक-राष्ट्र के तौर पर काम में लाना निश्चित रूप से बन्द कर देना भी शामिल है, और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की सरीद-फरोस्त बन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय बदलना चाहें तो अवाध-रूप से उन्हें ऐसा करने दिया जायगा ।

(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और

दंगल आदि नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में यह हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का भंग होना हो। पिकेटिंग ठीक न होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रकाबट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में खलल डालने या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। यदि कहीं उन उपायों में काम लिया गया तो वहाँ की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी।

(८) गांधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जाच कर्माई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति-अभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः भ्रान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेगी। इन बातों का न्याय करके, गांधीजी इस बात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो गये हैं।

(९) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर सरकार जो कुछ करेगी वह उस प्रकार है—

(१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जो विधोप कानून (आर्तिनेन्स) जारी किये गये हैं वे वापस ले लिये जायेंगे।

आर्तिनेन्स न० १ (१९३१), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

(११) १९०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मर्यादों को गैर-कानूनी करार देने के दुरुप वापस ले लिये जायेंगे, बशर्ते कि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जारी किये गये हों।

वर्मा की सरकार ने हाल में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो दुरुप जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता।

(१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये हों और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा भ्रिंक नाम के लिए होगी या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने की बात हो।

२. यही मिद्वान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलनेवाले मुकदमों पर लागू होगा।

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने बकायत करनेवालों के खिलाफ सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में 'लीगल प्रैक्टिसनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चलाया होगा या इसके लिए हार्डकोर्ट से दरखास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में मुकदमा लौटाने की इजाजत देने के लिए बरखास्त देगी, वशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति का कथित आचरण हिंसात्मक या हिंसा को उत्तेजन देनेवाला न हो।

४. सैनिकों या पुलिसवालों पर चलनेवाले हुक्म-उद्दली के मुकदमे, अगर कोई हो, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

(१३) १. वे कैदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में ऐसे अपराधों के लिए कैद भोग रहे होंगे जिनमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो।

२. पूर्वोक्त १ क्षेत्र में आनेवाले किसी कैदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार हिंसा या अहिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो वह सजा भी रद्द कर दी जायगी, या यदि इस अपराध-सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा।

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियों को हुक्म-उद्दली के अपराध में सजा हुई है—जैसा कि बहुत कम हुआ है—वे इस माफी के क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

(१४) जुर्माने जो वसूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जन्दी के हुक्म के बावजूद जो जमानत वसूल नहीं हुई होगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा।

जुर्माने या जमानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, बाहे में किसी भी कानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा।

(१५) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में किन्नी खास स्थान के बागिन्दों के खर्च पर जो अतिरिक्त-पुन्सि तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्च से जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ कर दी जायगी।

(१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय

अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में आर्डिनेन्सो या फौजदारी-कानून की धाराओं के मातहत अधिकृत की गई है, यदि अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो लौटा दी जायगी।

(व) लगान या अन्य करो की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जब्त की गई है वह लौटा दी जायगी, जबतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि बकैयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जानबूझ कर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलो का ख्याल रखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुलतवी कर दिया जायगा।

(स) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी।

(द) जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि जब बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची गई हो।

(इ) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।

(१७) (अ) जिस अवल-सम्पत्ति पर १९३० के नवें आर्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया गया है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार लौटा दिया जायगा।

(ब) जो जमीन तथा अन्य अवल-सम्पत्ति लगान या अन्य करो की वसूली के सिलसिले में जब्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में है वह लौटा दी जायगी, बशर्ते कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान-बूझकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलो का ख्याल रखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुलतवी कर दिया जायगा।

(स) जहाँ अचल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी, जहाँ तक सरकार से सम्बन्ध है, वह सीदा अन्तिम समझा जायगा।

नोट—गांधीजी ने सरकार को बताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली विक्री में कुछ अवश्य ऐसी है जो गैर-कानूनी तरीके से और अन्यायपूर्ण हुई है। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस धारणा को मंजूर नहीं कर सकती।

(द) सम्पत्ति की जल्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें बसूली कानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई है। ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई हो, प्रान्तिक सरकारें जिला-अफसरों के नाम हिदायते जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह साबित हो जाय कि गैर-कानूनीपन हुआ है तो अविलम्ब उसको रफ्त-दफ्त करें।

(१९) जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्त-स्थानों की जहाँ स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहाँ सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति को पुन नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-दोष की दृष्टि से प्रान्तिक सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरखास्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व ग्रामीण अधिकारियों की पुन नियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेगी।

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मौजूदा कानून के अग को गंभारा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए नमक-कानून में ही कोई सास तबदीली की जा सकती है।

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके सहायताार्थ, इस सम्बन्ध में लागू होनेवाली धाराओं को वह (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, जैसा कि अभी भी कई जगह हो रहा है, जिससे जिन स्थानों में नमक बनाया या इकट्ठा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गांवों के वासिन्दे वहाँ से नमक ले सकेंगे, लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं।

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगी जो, उसके परिणाम-स्वरूप, सर्व-

साधारण तथा व्यक्तिगत के मद्द्गण एव कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी।”

भगतसिंह आदि को फांसी

समझौते की यातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राज-गुरु व मुत्तदेव की फांसी की मजा को, जो कि मि० मोण्डर्स की हत्या के कारण लाहौर-पटवन्त केम में उन्हें दी गई थी, और किन्नी सजा के रूप में तबदील कर देने के बारे में गांधीजी व वाठनराय के बीच बार-बार छम्बी बाने हुईं। क्योंकि, उन्हें जो फांसी की मजा दी जानेवाली थी, उसमें देम में बहुत हलचल मच रही थी। स्वयं कांग्रेसवाले भी इस बान के लिए बहुत उत्तुक्र थे कि उस समय जो सद्भाव चारों ओर दिखाई पट रहा है उसका लाभ उठाकर उनकी फांसी की सजा बदलवा दी जाय। लेकिन वाइमरग ने इन बारे में स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा, हमेंना एक मर्यादा रखकर इस बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने गांधीजी से सिर्फ यही कहा कि मैं पजाब-भरकार को इस बारे में लिखूंगा। इसके अलावा और कोई वादा उन्होंने नहीं किया। यह ठीक है कि म्यय उन्हीं को सजा रद करने का अधिकार था—लेकिन वह अधिकार राज-नैतिक कारणों के लिए अमल में लाने के लिए नहीं था, हालांकि दूसरी ओर राजनैतिक कारण ही पजाब-भरकार के इस बात को मानने के मार्ग में बाधक हो रहे थे।

वरजसल के बाधक थे भी। चाहे जो हो, लार्ड अविन इस बारे में कुछ करने में असमर्थ थे, अलबत्ता कराची में कांग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फांसी रुकवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया। मार्च के अन्तिम-सप्ताह में कराची में कांग्रेस होनेवाली थी। लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित रूप से वाइसराय से कहा—अगर इन नीजवानों को फांसी पर छटकाना ही है, तो कांग्रेस-अधिवेशन के बाद ऐसा किया जाय, इसके बजाय उसमें पहले ही ऐसा करना ठीक होगा। इसमें देम को यह साफ पता चल जायगा कि वस्तुतः उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आशाएँ नहीं बँधेंगी। कांग्रेस में गांधी-अविन-समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद होगा—यह जानते-यूझते हुए कि तीन नीजवानों को फांसी दे दी गई है। अस्तु, ५ मार्च १९३१ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ही मि० इमर्सन ने गांधीजी को एक मुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछले दस महीनों की सरकारी कार्रवाइयों के लिए अपने को जिम्मेवार बताते हुए यह भी लिखा कि स्वराज्य-आप्त भारत में नौकरी करने

में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लॉर्ड अविन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर आधा प्रकट की कि क्षीघ्र ही इंग्लैण्ड में वह उन्हें देखेगे।

युगान्तरकारी वक्तव्य

समझौते से निवृत्त हो गांधीजी ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अंग्रेज व भारतीय पत्रकारों और प्रेसमनों के एक समूह के सामने एक युगान्तरकारी वक्तव्य दिया। पूरा वक्तव्य लिखाने में गांधीजी को पूरा डेढ़ घण्टा लगा। वक्तव्य गांधीजी ने मुह-जवानी ही लिखाया था और उसमें कहीं भी एक-बार भी रद्दो-बदल नहीं किया। इस वक्तव्य में उन्होंने लॉर्ड अविन की उचित प्रशंसा की और पुलिस, सिविल-सर्विस व फ़ास्तिकारियों से उपयुक्त अपील की। हम इस वक्तव्य को यहाँ उद्धृत करते हैं, क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य का स्थान मिलेगा—

“सबसे पहले मैं यह बात कह देना चाहता हूँ कि बाइसराय के अपार धीरज व उतने ही अपार परिश्रम व अचूक गिण्टाचार के बिना यह समझौता, जैसा भी वह है, होना असम्भव था। मुझे इस बात का पता है कि मैंने उनके सामने कई बार झुमला पड़ने के कारण, चाहे अनजान में ही, उपस्थित किये होंगे। मैंने उनके धीरज को भी झुझाया होगा। लेकिन ऐसे किसी समय की मुझे याद नहीं आती जबकि वह झुमलाते दिखाई दिये हो या उन्होंने धीरज छोड़ दिया हो। यह भी कह दूँ कि इस बहुत ही नाजुक बातचीत के दौरान मैं उन्होंने शुरू में आखीर तक खुलकर बातचीत की। मेरा विश्वास है कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वह तुले हुए थे। मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने इस बातचीत में डरते हुए और कापते हुए भाग लिया। मेरे अन्दर अविश्वास भी था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके मुझे निश्चित कर दिया।

“इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन सा है, न तो सम्भव ही है और न बुद्धिमत्तापूर्ण ही।

“यदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना चाहिए, दोनों की है। कांग्रेस ने विजय की होड़ कभी नहीं लगाई थी।

“बात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश्य तब पहुँचना है और उस उद्देश्य तक पहुँचे बिना विजय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं अपने सब देशवासियों से और अपनी सब बहनों ने आग्रह करूँगा कि वे फूटकर खुप्रा हो जाने के बजाय—यदि समझौते में फूटकर खुप्रा हो जाने की कोई ऐसी बात है—परमात्मा के आगे मिल

झुकावे और उससे प्रार्थना करें कि उन्हें वह इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का अनुसरण करने का तकाजा करता है उसपर चलने की शक्ति व बुद्धि प्रदान करे, चाहे वह मार्ग कष्ट-सहन का हो और चाहे वह धैर्य-पूर्वक सवि-वार्ता या विचार विनिमय करने का हो।

“इसलिए मैं विदवास करता हूँ कि कष्ट-सहन से पूर्ण इस सत्राय में गत बारह महीनों में जिन लाखों लोगों ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस काल में भी वही खुशनुदी, वही एकता, वही कोशिश और वही समझदारी दिखलायेंगे जो उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में इस युग में, जिसे मैं भारत के आधुनिक इतिहास का बीरतापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है।

“लेकिन, मुझे मालूम है, जहाँ ऐसे स्त्री-मुख्य होंगे जो इस समझौते के कारण फूलकर कुम्पा हो जायेंगे, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत निराश होंगे और जो बहुत निराश हैं।

“बीरता से कष्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वाभाविक है जैसे मानो सास लेना। वे तो मानो इसीमें सबसे ज्यादा खुश हैं, असह्य कष्टों को भी सह लेंगे। लेकिन जब उनके कष्टों का अन्त होता है तो उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा काम बन्द हो गया है और हमारा लक्ष्य आखो से ओझल हो गया। उनसे मैं केवल यही कहूँगा कि धैर्य रखो, देखो, प्रार्थना करो, और आशा रखो।

“कष्ट-सहन की भी एक हद होती है। कष्ट सहन में बुद्धिमानी और मूर्खता दोनों सम्भव हैं, और जब कष्ट-सहन की हद आ जाती है तो उसे और बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं बल्कि परले सिरे की बेवकूफी है।

“जब आपका विरोधी आपकी इच्छानुसार ही आपसे बातचीत करने की आपके लिए आसानी पैदा करदे, तो कष्ट सहते रहना बेवकूफी है। यदि रास्ता वास्तव में खुल जाय तो हरेक का यह कर्तव्य है कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नज़र सम्मति है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायी होना तो स्वाभाविक ही है। यह जो सवि दुई है वह कई बातों के पूरा होने पर निर्भर है। इस लिखित समझौते का बड़ा भारी अंग तो ‘समझौते की शर्तों’ से घिर गया है। यह स्वाभाविक ही था। कांग्रेस गोलमेज-परिषद् में भाग ले सके इसके पहले कई बातों का पूरा हो जाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय पुरानी भूलों का सुधार कराना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण, उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके ‘पूर्ण-

स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत का यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। समझौते भर में हमें वह मनमोहक गन्ध कहीं नहीं दिखाई देता। जिस धारा में यह गन्ध छिपा हुआ है वह द्विअर्थक है।

"सम-शासन (फेडरेशन) भूगर्तृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हो कि उससे उसका सारा शरीर मजबूत बन जाय।

"इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है, वह या तो विलकुल छाया के समान नि सार हो या बड़ा ऊँचा, विशाल व न झुकनेवाले बरगद के पेड़ के सदृश हो सकता है। भारत के हित में संरक्षण भी विलकुल बोखे से नरें और इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारों ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम पीवे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर लगा दी जाती है।

"एक दल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। इस धारा के अनुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने परिपक्व की कार्यवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह उनी कारण कि वह सम-शासन, उत्तरदायित्व, संरक्षण, प्रतिबन्ध अथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हो।

"यदि परिपक्व ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, इसका परिणाम 'पूर्ण-स्वाधीनता' होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह मार्ग बहुत कठिन और थका देनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी श्रृंगारें हैं और बहुत-से गड्ढे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता। अतः मैं यहाँकी हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-से-अच्छा उपयोग करे या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो दें।

"मैं जानता हूँ कि इस कार्य में कांग्रेस को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी—भारत के नरेशों की और स्वयं अंग्रेजों की भी। इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों ने अपील करने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतंत्रता की उन्हें भी उतनी ही आकांक्षा है जितनी कि कांग्रेसवालों की।

"लेकिन नरेशों का मवाल दूसरा है। उनका सम-शासन के विचार को मान

छेना मेरे लिए निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। यदि वे सध-आसित, भारत में बराबरी के साझीदार बनना चाहते हैं, तो मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें उसी ओर बढ़ना होगा जिस ओर बढ़ने की ब्रिटिश-भारत इतने वर्षों से कोशिश कर रहा है।

“पूर्ण एकतंत्री शासन, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, व विशुद्ध लोकसत्ता ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवश्य ही फट पड़ेगा। इसलिए, मेरी राय में, उनके लिए आवश्यक है कि वे तने न रहें, अडे न रहें, और अपने भावी साझीदार-द्वारा या उसकी ओर से की गई अपील को बेसब्री में न सुनें। यदि वे इस प्रकार की अपील को न सुनेंगे तो वे कांग्रेस की स्थिति को बहुत असह्य, सराब और वास्तव में बहुत विषम बना देंगे। कांग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि है या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रिटिश-भारत या वेणी-रियासतों में बसनेवालों में वह कोई मेद-माव नहीं करती।

“कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक-थाम के साथ रियासतों के मामलों व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतों की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, और इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कैद, जो उसने अपने-आप लगा रखी है, रियासतों पर अपना असर ढालने में काम आवे। मेरा विचार है कि वह अवसर अब आ गया है। क्या मैं इस बात की आशा करूँ कि हमारे बड़े नरेश रियासती प्रजा की ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लेंगे ?

“अंग्रेजों से भी मैं एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिपक्वो व विचार-विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना है तो अंग्रेजों की सद्भावना व सक्रिय सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि लक्ष्य में पहली परिपक्व में जिन-जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं है जिस व्यय तक कि भारत पहुँचना चाहता है। यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मरते वम तक नहीं छोड़ सकते। उन्हें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलतिया करने के लिए छोड़ दें। यदि गलती करने की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतन्त्रता किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होंगे

जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यों न हों, दूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं ?

“सौर, कुछ भी हो, कांग्रेस को परिषद् में आमन्त्रित करने से यह तात्पर्य खूब अच्छी तरह निकल आता है कि अयोग्यता के अलावा किसी और कारण-वश उसे पूर्ण-से-पूर्ण स्वाधीनता पर जोर देने से नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस भारत को उस बीमार बालक की भाँति नहीं मानती जिसे देख-भाल, सेवा-सुश्रूषा व अन्य सहारा की जरूरत हो।

“अमरीकन-राजतन्त्र व ससार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मुझे भालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है—लेकिन जिनसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हैं—उनके मन पर बड़ा असर डाला है और उनमें उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं, वे इससे भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से मैं कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस अब जिस मुश्किल काम में पड़नेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती भी जायगी। मैं बड़ी नम्रता से यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुँच गया तो जिस विश्व-शान्ति के लिए ससार के सब राष्ट्र तब्य रहते हैं उसके हित में बड़ा भारी काम कर दिखाया जा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है उसका कुछ थोड़ा-सा बदला भी चुक जायगा।

“मेरी आखिरी अपील पुलिस व सिविल-सर्विस अर्थात् सरकारी अधिकारियों से है। समझौते में एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ ज्यादतियों की जाच की माग की थी। इस जाच की माग को छोड़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा पुलिस-द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती है उसका सिविल-सर्विस एक अग्रिम अंग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते हैं कि भारत शीघ्र ही अपने घर का मालिक बननेवाला है और उन्हें बफादारी व ईमानदारी से भारत के सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है कि वे अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि सिविल-सर्विस व पुलिस उनके सेवक हैं—अवश्य ही सम्मान-योग्य व बुद्धिमान सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही न कि मालिक।

“मुझे अपने उन हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों साथी-बन्धियों के बारे में भी एक शब्द कहना है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले जा रहे हैं लेकिन जो गत १२ महीनों में जेल भेजे गये सत्याग्रही कैदियों के छूट जाने पर भी जेलों में पड़े रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो हिंसा करने के दोषी हैं, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि वे लोग जिन्होंने राजनैतिक उद्देशों से प्रेरित होकर हिंसा की है, यदि बुद्धिमानी का नहीं तो कम-से-कम देश के लिए प्रेम व आत्म-त्याग करने का उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि मैं। इसलिए अपनी या अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के बजाय यदि मैं न्यायपूर्वक उनकी रिहाई करा सकता तो सचमुच ही करता।

“मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेंगे कि मैं न्याय-पूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे या कार्य-समिति के सदस्यों को उनका खयाल ही नहीं है।

“कांग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया है। यदि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन शर्तों का जो उन पर लागू होती है पूरी-भूरी तरह से पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत बढ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्का बैठ जायगा कि जहाँ कांग्रेस ने, मेरी राय में, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर ली है वहाँ उसमें शान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है।

“और यदि जनता कांग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कैदियों में से, मय नजरबन्दों व मेरठ-पड्यन्त्र के कैदियों व सब अन्यो के, एक-एक छूट जायगा।

“इस बात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्यदल विद्यमान है जो भारत की स्वतन्त्रता हिंसात्मक कार्यों-द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मैं इस दल से अपील करता हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को बन्द करे। यदि उसे अभी इसमें विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान है कि वे इस बात को तो महसूस कर ही चुके होंगे कि अहिंसा में कितनी जबरदस्त शक्ति है। वे इस बात से नहीं मुकरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिंसा के अगम्य लेकिन अचूक असर के कारण ही हुई है। मैं चाहता हूँ कि वे धीरे-धीरे और कांग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व अहिंसा की योजना का प्रयोग करने का अवसर दे। दाण्डी-यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी

नहीं हुआ। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-वक्र के एक क्षण के समान है। क्यों न वे अपने अमूल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बलावा शीघ्र ही सबों को दिया जायगा, सुरक्षित रखें और कांग्रेस को इस बात का अवसर दें कि वह अन्य सब राजनैतिक केंद्रियों की भी रिहाई करा सके और सम्भवतः उन लोगों को भी फासी के तल्ले में बचा सके जिन्हें हत्या के अभियोग में फासी की सजा मिली है ?

“लेकिन मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेस की जो आकांक्षायें हैं उनका मैं सार्वजनिक तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है।

“एक व्यक्तिगत बात और। मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मैंने लॉर्ड अर्बिन को अपना बचन दे दिया है कि मैं समझौते की शर्तों का, जहातक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन करने में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैंने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ बल्कि इसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे बिल्कुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोड़ूँ और उसे उस व्यय तक पहुँचाने वाला पेशवा समझूँ जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम है।

“सबसे अन्त में मैं उन सब लोगों को बन्धुवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं।”

कांग्रेस की हिदायतें

लॉर्ड अर्बिन ने भी गांधीजी की उसी प्रकार प्रशंसा की, जिस प्रकार कि स्वयं गांधीजी ने लॉर्ड अर्बिन की की थी। अपने को दिये गये एक प्रीति-भोज में आपने महात्माजी की ईमानदारी, नेकनीयती व उच्चतम देशभक्ति की मुक्तकठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि ‘उनके साथ कार्य करना बड़ी खुशी और खुश-किस्मती की बात है। महात्मा गांधी अपनी ओर से इस बात की मरसक कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने देशवासियों को तसल्ली करा सकें और शान्ति के योग्य वातावरण स्थापित कर सकें। डर में इस बात की पूरी कोशिश कलेंगे कि भारत और इंग्लैण्ड के बीच में शान्तिपूर्ण समझौता हो सके।’

चूँकि अब लड़ाई खतम हो गई थी, कांग्रेस-कमिटियो व संस्थाओं पर मे रोक उठा ली गई और वे फिर से जीवित हो गईं। कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भाँति है

जो एक मौसम में तो मुर्दे की भांति पड़ा रहता है और मौसम के बदलते ही उसमें विशाल शक्ति आ जाती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में अपनी सूचनाएँ कांग्रेसवादियों के पास भेजी। कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायें। आधे प्रतिनिधियों का चुनाव तो वे व्यक्ति करें जिन्हें आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और शेष आधे का चुनाव साधारण नियमों के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिदायतें जारी की गईं। जेल हो जानेवाले का चुनाव एक समा बूलाकर करना था। गाल के प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक भी अने नियत किये गये थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों को यह भी हिदायत दी गई कि वे सविनय अवज्ञा व करवन्दी-आन्दोलनों को और ब्रिटिश-भाल के बहिष्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजों, सब विदेशी कपड़े व शराब की दुकानों के बहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमें दबाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के मार्ग में रूकावट नहीं डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के प्रकाशन बन्द करने का आदेश भी हुआ। वास्तव में समझौते की हरेक मद के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गईं और स्वयं गांधीजी ने उन आदेशों के साथ वे शर्तें जोड़ दी जो शराब व विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयंसेवकों को माननी चाहिए। वे इस प्रकार थी—

(१) दुकानदार या खरीददार के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया जा सकता।

(२) स्वयंसेवक दुकानों अथवा गाड़ी, मोटर आदि के सामने छेद नहीं सकते।

(३) 'हाय-हाय' जैसी आवाजें नहीं लगानी चाहिए।

(४) किसी का पुतला बनाकर गाढ़ना या जलाना नहीं चाहिए।

(५) यदि बहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीददार की खाले-मीने की तथा अन्य सामग्री नहीं रोकी जा सकती। लेकिन उनके घर भोजन के लिए न जाना चाहिए और न उनकी कोई सेवा ग्रहण करनी चाहिए।

(६) उपवास तथा भूख-हड़ताल किसी हालत में भी न होने चाहिए।

प्रतिज्ञा तोड़ने पर ही उपवास किया जा सकता है, और सो भी तब, जबकि दोनों ओर के आदमी एक-दूसरे का आदर व प्रेम करते हो।

कराची-कांग्रेस

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कराची-कांग्रेस के सभापति-पद के लिए चुन लिया, क्योंकि करीब एक साल तक कांग्रेस की जो असामान्य परिस्थिति रही थी उसके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापति का चुनाव होना सम्भव न था।

कराची-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कोई आसान काम न था, क्योंकि यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा दिखाई देने लगा था, लेकिन अस्थायी-सन्धि के भाग्य ने कराची-कांग्रेस के प्रबन्धको की स्थिति बड़ी असमंजस में डाल दी। एक सुमीला अवश्य था—और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाड़े रह गये थे। लाहौर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। यह एक इत्फाक की बात है कि कांग्रेस इस वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन मार्च के महीने में कर सकी, क्योंकि अस्थायी-संधि अभी हाल ही हो चुकी थी। अधिवेशन के मार्च में करने से पहाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान में हो सकती थी। केवल एक समा-मञ्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के चारों ओर एक बैरा डालने की।

कराची-अधिवेशन के प्रबन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय कराची की म्युनिसिपैलिटी को था जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व सचालकत्व में कार्य किया। कांग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को गुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गांधीजी को देन और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा हुआ। यह वही मीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अब प्रसिद्धि पा गया है, "गांधी भले ही मर जाय लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा।"

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सभापतित्व किया। आपने आने छोटे-मे अभिभाषण में सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक निमान को नहीं किन्तु गुजरात को, जिमने स्वतन्त्रता के युद्ध में एग बड़ा भाग दिया था, प्रदान किया गया है।

काले फूस

कराची-कांग्रेस जो एक सर्वव्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही थी, वास्तव में विपाद और सताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव फासी के तस्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। इन तीनों युवकों की आत्मायें उस समय कांग्रेस-नगर पर महराती हुई लोगों को शोक-सन्ताप में डुबो रही थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबकि भगतसिंह का नाम भी भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवकों की फासी की सजा रद्द नहीं करा सके थे। लेकिन जो लोग इन तीनों युवकों की जान बचाने के गांधीजी के प्रयत्नों की अभी तक प्रशंसा कर रहे थे, अब इस बात पर बेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जानेवाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो। पण्डित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी मजहबुलहक, श्री रेवाशकर झवेरी, साहू मुहम्मद जुवेर व गुरुनन्दा मुदालियर की मृत्यु पर शोक प्रकाशित करने के पश्चात् सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतसिंह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव में बहस व मतभेद की केवल यही बात थी कि भगतसिंह व उसके साथियों की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कि 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव में जोड़े जायें या नहीं? हम वह प्रस्ताव नीचे देते हैं —

“प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए यह कांग्रेस स्वर्गवासी सरदार भगतसिंह तथा उनके साथी श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती हैं तथा उनके जीवन-नाश पर उनके दुःखित परिवारों के साथ स्वयं भी शोक का अनुभव करती हैं। कांग्रेस की राय में ये तीनों फासिया अनियन्त्रित प्रतिहिंसा का कार्य हैं तथा प्राण-दण्ड रद्द करने के लिए की हुई सारे राष्ट्र की मांग का पद-दलन हैं। कांग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय निश्चय ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश हो कर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अवलम्बन किया है, क्षान्ति के उपाय से जीतने का अत्युत्तम अवसर खो दिया है।”

कांग्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए वक्ता का जो यह वाक्य रक्खा था उनके सिवाय कांग्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वाक्य से युवको का वह दल जो गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्याग को निकाल देने के संशयन पेश किये गये। स्वयंसेवको के सम्मेलन ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह वाक्य निकालकर पास कर दिया। यह वाक्य वाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन गया था। जब कराची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाने के बाहर उन कुछ युवक-मित्रों-द्वारा दंगा ब हो-हुल्लड किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व प्रातःकाल स्टेशन पर, जबकि गांधीजी सरदार बल्लभभाई पटेल के साथ कराची में १२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले झंडों का प्रदर्शन किया था। गांधीजी ने अपने सहज-स्वभाव से उन युवको के दल का स्वागत किया और दबे अदब से उनके हाथों से काले फूल ले लिये। यह दल आया तो था उनपर हमला करने के लिए, लेकिन यह गया उनकी 'रक्षा' के लिए। वह गांधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया।

दूसरा प्रस्ताव जिसपर कांग्रेस ने विचार किया, वह बन्धियों की रिहाई के बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्धियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कन्नौज-नीति ही नहीं बरत रही है बल्कि उन बादों से भी मुक्त रही है और उन शर्तों को भी तोड़ रही है जो उसने समझौते के मिलसिले में की थी। इसलिए कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया कि 'यदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भाव बढ़ाना है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की जासनाबिकार छोड़ने की इच्छा को वास्तविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बन्धियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्धियों को, जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर चाहे वे भारत में हो ना विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण लगा रखी हैं।'

कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 'यदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोष जो हाल की फासियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।'

गणेशजी का बलिदान

भगतसिंह आदि की फासियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने कराची-कांग्रेस में उदासी के बादल छा दिये। जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कानपुर में जोरो का हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरु हो गया और श्री गणेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सद्भाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओं के रोप से बचाने के प्रयत्न में मारे गये। इस घटना ने कांग्रेस व देश को उसी प्रकार अपार शोकसागर में डुबो दिया जिस प्रकार कि सन् १९२६ में गोहाटी-कांग्रेस के अवसर पर स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगे के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए बदनाम रही हो। १९०७ में एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १९२८ व २९ में। कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं जो कुल आबादी के $\frac{1}{2}$ है। मुसलमान व अन्य जातियाँ मिलाकर कुल $\frac{1}{2}$ होते हैं। भगतसिंह व उनके साथियों को लाहौर में २३ मार्च को फाँसी दी गई थी। देशभर में हड़तालें की गईं जिनमें बम्बई, कराची, लाहौर, कलकत्ता, मबरास, व दिल्ली की हड़तालें शान्तिपूर्वक समाप्त हो गईं। कानपुर में हड़ताल पूरी नहीं हुई, चीनों सहीदों के चित्रों व काले झण्डों-सहित एक बड़ा भारी मातमी जुलूस निकाला गया। हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें बन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की। कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदअली मरे थे उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हड़ताल में भाग नहीं लिया था। वस, अधिक कहने की जरूरत नहीं—चिगारी भी मौजूद थी और बारूद का डेर भी मौजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति बायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्नि-काण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानों और मन्दिरों में आग लगा दी गई। और वे जल-जलकर खाक हो गये। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड व हुल्लडबाजी का बाजार गरम हो गया। लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़-छोड़कर आसपास के गावों में जा बसे। डाक्टर रामचन्द्र का बड़ा बुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सब व्यक्ति, मग उनकी स्त्री व बूढ़े माता-पिता के, दंगे में मारे गये और उनकी लाशें नालियों में ठूस दी गईं। सरकारी अनुमान के अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और ४८० बायल हुए। कांग्रेस ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन व अन्य कुछ मित्रों की शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थल पर भेजा, लेकिन शान्ति के वातावरण को वापस लाना सहूल न था। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी

२५ ता० से लापता थे। उनकी लाश का पता २६ ता० को जाकर लगा। उन्होंने उस दिन कई भूमलमान परिवारों को बचाया था। पता चलता है कि उन्हें फँसाकर किसी एक स्थान पर ले जाया गया था जहाँ वह बिना किसी सकोच के चले गये और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की भाँति कुछ भीड़ के सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। यदि उनका लहू एकता स्थापित कर सकता और उन लोगों की प्यास बुझ सकती तो बखूबी उनके फल का स्वागत किया जा सकता था। कांग्रेस ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया —

“इस उपद्रव में युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री गणेशगकर विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस को अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थत्यागी देश-सेवकों में से थे और साम्प्रदायिक राग-द्वेष से सर्वथा मुक्त होने के कारण सभी दलों और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन हो गये थे। उनके वृद्धाश्रमों के साथ समवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस इस बात पर अभिमान प्रकट करती है कि प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े हुए लोगों के उद्धार तथा गोर उपद्रव और जल्मत्त उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपने को बलिदान कर दिया।

“कांग्रेस सब लोगों से अनुरोध करती है कि इस बलिदान का उपयोग शान्ति की स्थापना तथा पुष्टि के लिए करें, प्रतिहिंसा का भाव जगाने के लिए नहीं। हम उद्देश्य से कांग्रेस एक कमिटी बना रही है जो वैमनस्य के कारणों की जाँच करेगी और मेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए, जो-कुछ आवश्यक होगा करेगी।”

कांग्रेस ने डॉक्टर भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी ने किम प्रकार गवारिया ली, कानपुर का दौरा किया, आदि बानों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ दाना ही पचना वाली है कि कमिटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके मार्च-अप्रैल के मामले में गेज की, जो बहुत दिनों बाद छपी गई, लेकिन सरकार ने उसका विचारण गौर दिया।

अस्थायी संधि का प्रस्ताव .

उमर फरमाँ अस्थायी सन्धिवाक्य प्रस्ताव जाता है जो एक सन्धिवाक्य मात्र है। उसमें कांग्रेस का दृष्टि-कोण जर्मनों के साथ-साथ कांग्रेस की ओर से था या भी गलत था दी गई जो मार्च-अप्रैल-मई-जून के महीने, का जर्मन सन्धिवाक्य

समझी गई थी। समझौते में प्रयोग किये गये 'संरक्षण' (Reservations) शब्द की जगह 'घटा-बढी' (Adjustments) शब्द रखा गया और 'भारत' के हित में 'संरक्षण' शब्दों की जगह 'घटा-बढी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित में हो' शब्दों को रखा गया। गांधी-अविन-समझौते के कारण जो बात कम कर दी गई मानी जाने लगी थी, वह कराची के प्रस्ताव के इन शब्दों से फिर जुड़ गई— अर्थात् अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें। इस एक वाक्य में कांग्रेस का ध्येय दिया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, बघाई दी जिन्होंने गत सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में महान् कष्ट उठाये थे। कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार न करेगी, जिसमें मताधिकार के सम्बन्ध में स्त्रियों व पुरुषों में भेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ हैं कि उनपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्ध रचनात्मक कार्यक्रम से है और वे नीचे दिये जाते हैं —

“भारत-सरकार और कांग्रेस-कार्य-समिति के बीच जो अस्थायी-सन्धि - हुई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका समर्थन करती है और यह स्पष्ट कह देना चाहती है कि कांग्रेस का पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश्य ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। यदि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के जाने के मार्ग में दूसरे प्रकार की रूकावटें न रह जायें (और कांग्रेस के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में शरीक हों), तो कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे—खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें, भारतवर्ष की ब्रिटिश-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं उनकी जाच होकर इस बात का निपटारा हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी कि इसमें ऐसी घटा-बढी करें जो भारतवर्ष के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो।

“महात्मा गांधी को कांग्रेस गोलमेज-परिषद् के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य-समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।”

खट्टर और बहिष्कार—“पिछिले दस वर्षों के भीतर सैकड़ों गांवों में काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण

जनता की गरीबी दिन-दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय के लिए लोगों के पास कोई सहायक-बन्धा न होने से उनको लाचार होकर बेकार रहना पड़ता है, और केवल चर्खा ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्यापक रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा और फलतः खहर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं जिससे गावों का पैसा दो तरह से छीना जाता है—उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे धन-शोषण को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि विदेशी कपड़े और सूत का बहिष्कार किया जाय और उनकी जगह खहर का उपयोग किया जाय। देशी मिलें केवल आवश्यकतानुसार खहर की कमी की पूर्ति करें। अतः यह कांग्रेस सर्व-साधारण से अनुरोध करती है कि विलायती कपड़ा खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की सारी हानि हो रही है।

“और यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी सत्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके ‘विदेशी बहिष्कार को और जोरदार बनावें।

“कांग्रेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में शामिल हो और विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें।

“कांग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखे कार्य करके इस महान् रचनात्मक तथा आर्थिक-उद्योग को सहायता पहुँचावें —

(१) खुद हाथकरी सूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-बन्धे चरखे को अपनी नैतिक पुष्टि दें।

(२) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर दें जो किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता कर सकता हो और इस विषय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ दें।

(३) अपने माल का दाम जहा तक हो सके कम-से-कम रखें।

(४) अपने माल में विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें।

(५) दूकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसको ले लें और उसके बदले में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये हुए विलायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रयत्न करें।

— ५३ —

१.
 २.
 ३.
 ४.
 ५.
 ६.
 ७.
 ८.
 ९.
 १०.
 ११.
 १२.
 १३.
 १४.
 १५.
 १६.
 १७.
 १८.
 १९.
 २०.
 २१.
 २२.
 २३.
 २४.
 २५.
 २६.
 २७.
 २८.
 २९.
 ३०.
 ३१.
 ३२.
 ३३.
 ३४.
 ३५.
 ३६.
 ३७.
 ३८.
 ३९.
 ४०.
 ४१.
 ४२.
 ४३.
 ४४.
 ४५.
 ४६.
 ४७.
 ४८.
 ४९.
 ५०.
 ५१.
 ५२.
 ५३.
 ५४.
 ५५.
 ५६.
 ५७.
 ५८.
 ५९.
 ६०.
 ६१.
 ६२.
 ६३.
 ६४.
 ६५.
 ६६.
 ६७.
 ६८.
 ६९.
 ७०.
 ७१.
 ७२.
 ७३.
 ७४.
 ७५.
 ७६.
 ७७.
 ७८.
 ७९.
 ८०.
 ८१.
 ८२.
 ८३.
 ८४.
 ८५.
 ८६.
 ८७.
 ८८.
 ८९.
 ९०.
 ९१.
 ९२.
 ९३.
 ९४.
 ९५.
 ९६.
 ९७.
 ९८.
 ९९.
 १००.

14-00000-1

मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-सत्त्वों गैर-कानूनी हैं, ताकि वहाँ भी अवस्था पुनः स्वाभाविक हो जाय और वर्मा के नविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में बिना रोक-टोक के विचार कर सकें और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो।”

भौतिक अधिकार का प्रस्ताव

यहाँ यह कह देना बाकी है कि ‘भौतिक अधिकारों व आर्थिक व्यवस्था’ वाला प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेय हुआ था। यह एक अनुभव से जानी गई बात है कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेय होते हैं। भौतिक अधिकारों का प्रश्न सबसे पहले श्री चन्द्रचर्मा बिजयरायबाचार्य ने पंजाब के ठिरठिराते हुए जाड़े में आधी रात को अमृतसर-कांग्रेस में उठाया था। जब दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस-अभिवेशन के वह स्वयं सभापति बने तो इस प्रश्न को और महत्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रीट-वर्ग में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस बात पर सन्नेह करते हुए नहीं चूकते थे कि क्या अब कांग्रेस ‘औपनिवेशिक-स्वराज्य’, ब्रिटिश-नाम्राज्य-वाद व काली नौकरशाही की लहर में फिर नहीं बही जा रही है और मजदूरों व किसानों की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे हैं? इस विषय पर देश को आश्वासन दिलाने की जरूरत थी। गांधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिंसा पर अवलम्बित हो, और फिर वह तो गांववालों और गरीब लोगों का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आर्थिक-परिवर्तन व भौतिक अधिकारों के प्रश्न से हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी?

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए था और कार्य-समिति व महासमिति के सदस्यों-द्वारा उसका सम्बन्ध-मनन होना चाहिए। यह सलाह मान ली गई और इसलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति को आधात पहुँचाये बिना उसमें रद्दो-बदल करे। बम्बई में, अगस्त १९३१ में, महासमिति ने मूल-प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये। उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसीमें उस प्रस्ताव को हम नीचे देते हैं —

‘इस कांग्रेस की राय है कि कांग्रेस विस प्रकार के ‘स्वराज्य’ की कल्पना करती है उसका जनता के लिए क्या अर्थ होगा—इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए

अध्याय १ : गांधी-अविन-सत्ता

यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकार से समझ सके। साधारण जनता की तबही का अर्थ है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखों मरनेवाले भी निहित हो। इसलिए यह कांग्रेस बोधित करनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी या स्वराज्य-सरकार को इस बात का अधिकार है कर सके—

भौतिक अधिकार और कर्तव्य—१।

प्रत्येक विषय में, जोकि कानून और सदाचार के प्रकट करने, स्वतन्त्र सस्थाप्य और सच बनाने और पूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, असार्वजनिक शान्ति और सदाचार में बाधक न आचरण की स्वतन्त्रता है।

- (९) सरकार सब घमों के प्रति तटस्थ रहेगी।
- (१०) बालिंग उमर के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा।
- (११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- (१२) सरकार किसी को खिताब न देगी।
- (१३) मौत की सजा उठा दी जायगी।

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा।

अधिक—२ (अ) आर्थिक जीवन के सगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सशुद्ध होने चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो जाय।

(ब) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एव अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परस्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के बीच के झगड़ों के निपटारे के लिए उपयुक्त साधन और बुढ़ापा बीमारी तथा बेकारी के आर्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी।

३ दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे।

४ मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त छुट्टी का विशेष प्रबन्ध होगा।

५ स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के लड़कियों और कारखानों में नौकर न रखे जायेंगे।

६ किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए सब बनाने के अधिकार होंगे।

कर और व्यय—७ जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में तुरन्त और यदि आराजी में लाभ न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या समाने मुक्त करके कृषकों के बोझ का न्यायमुक्त निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी से छोटी जमीनों

के मालिकों को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित सादाद से अधिक की भूमि की मूल आय पर क्रमशः बटनेवाला कर लगाकर की जायगी।

८ एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमागत विरासत कर लिया जायगा।

९ फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्तमान व्यय से वह कम-से-कम आधा रह जायगा।

१० मुक्त की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आमतौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न दिया जायगा।

११ हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम—१२ राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा, और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी धन्वों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा।

१३ औपधियों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा बन्द कर दिये जायेंगे।

१४ हुडाबन और विनियम का नियन्त्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा।

१५ मुख्य उद्योगों और विभागों, खनिज साधनों, रेलवे, जल-मार्ग, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियन्त्रण रखेगा।

१६ कृषकों के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊँचे दर के ब्याज पर सरकार का नियन्त्रण होगा।

१७ "नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन संगठित करने के लिए राज्य नागरिकों की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।"

कुछ और भी प्रस्ताव पास किये गये थे। एक प्रस्ताव में साम्प्रदायिक दंगों की निन्दा करते हुए दंगों की बर्बरता के शिकार परिवारों से सहायता प्रकट की गई थी। मद्य-निषेध को जारी रखने की दूसरे प्रस्ताव में अपील की गई थी। भारत-सरकार की सीमा सबंधी नीति की निन्दा एक प्रस्ताव द्वारा करके अन्य प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस की सम्मति में सीमा प्रान्त को भी अन्य प्रान्तों

के समान शासन-अधिकार मिलने चाहिये। एक प्रस्ताव अफ्रीकाप्रवासी भारतीयों के बारे में था।

गांधीजी—एकमात्र प्रतिनिधि

गांधी-अविन समझौते की सफलता व इससे भी अधिक कराची के प्रस्तावों की सफलता गांधीजी व कांग्रेस के भारी बोझों को और भी अधिक बोझीला बनाती गई। कराची-कांग्रेस में एक-दो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे रह गये थे जिन्हें वह नहीं निवटार सकी थी और जिन्हें उसने कार्य-समिति व महा-समिति के लिए छोड़ दिया था। सिक्खों ने राष्ट्रीय झण्डे व उसमें उनके लिए समाविष्ट किये जानेवाले रंग के प्रश्न को उठाया। यह प्रश्न पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था, कराची में इसे और भी अधिक महत्त्व मिला। चूँकि कांग्रेस का अधिवेशन ऐसी तफसील पर विस्तार-सहित विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-समिति के सुपुर्द किया गया। नई कार्य-समिति ने, जिसकी बैठकें १ व २ अप्रैल को हरचन्द्रायनगर में हुई, इस आपत्ति की जांच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-झण्डे के रंग साम्प्रदायिक आचार पर निर्धारित किये गये हैं अथवा नहीं, और यह सिफारिश करने के लिए कि कांग्रेस कौमसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का निश्चय किया। कमिटी को गवाहिया लेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १९३१ से पहले उसकी रिपोर्ट मांगी गई। दूसरा विषय जिसपर कराची में कांग्रेसी झुंझ रहे थे, वह जोरो से फैली व उबती हुई यह खबर थी कि स्वर्गीय सरदार भगतसिंह और श्री राजगुरु व सुखदेव की लाशों को पीर-फाव डाला गया था, उन्हें ठीक तरह नहीं जलाया गया और उनके साथ अन्य अपमानजनक व्यवहार किया गया। इन अभियोगों की फौरन जांच करने के लिए और ३० अप्रैल से पहले-पहले अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति को पेश करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की। 'यहाँ हम यह कह देना चाहते हैं कि यह कमिटी खास तौर पर भगतसिंह के पिता के आग्रह पर नियुक्त की गई थी, लेकिन न तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई सहायक पेश की और न खुद कमिटी के सामने पेश हुए और न कमिटी को और किसी प्रकार की सहायता कर सके। इसलिए कमिटी कुछ भी न कर सकी। हम यह बता चुके हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार जल्दी में मौलिक अधिकार व आर्थिक व्यवस्था' वाला प्रस्ताव पास किया था। इसलिए प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों तथा अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से उक्त प्रस्ताव पर सम्मतिया प्राप्त करने और ३१ मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी

नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और विस्तृत बनाया जा सके और उसमें आवश्यक परिवर्तन व संशोधन किये जा सकें। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस वर्षों से इस बात पर जोर देती आई है कि ब्रिटेन ने भारत में जो खर्च किये हैं व उसके लिए जो कर्ज लिये हैं उनकी एक निष्पक्ष पंच-द्वारा जांच हो। इस विषय पर जो वाद-विवाद व द्वन्द्व होना लाजिमी था उसके लिए अपने तीर-तारकस तैयार रखना जरूरी ही था। इसलिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी व ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत में किये गये आर्थिक खर्चों व भारत के राष्ट्रीय कर्जों की छान-बीन करने के लिए और इस बात की रिपोर्ट पेश करने के लिए कि सविष्य में भारत कितना आर्थिक बोझा सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। एक कमिटी और भी नियुक्त की गई—वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिष्ट-मण्डल था—जिसके गांधीजी, बल्लभभाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निबटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले। कांग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन राजबन्धियों की रिहाई चाही गई थी उनके बारे में सब प्रान्तों से सामग्री एकत्र करने के लिए श्रीनरीमन को नियुक्त किया गया। अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे अन्त में कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निबटाया वह था गोलमेज-मरिबद् को मेजे जाने-वाले कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिष्ट-मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो। सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के बजाय १५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक था। जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी लन्दन शासन-विधान की तफसीलें तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे हैं। जब यह बात साफ कर दी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्वसम्मत राय बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिए। यह निर्णय केवल सर्वसम्मत ही नहीं था बल्कि इसमें किसी कोई उल्लेख भी न था, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के बजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह कांग्रेस के लिए एक महान् नैतिक लाभ भी था, क्योंकि जैसे युद्ध-संचालन में उसने एकता का परिचय दिया वैसे ही सन्धि की शर्तें तय करने में यह उसके नेतृत्व की एकता का परिचायक था। कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का

कोई स्वार्थ न हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति के अलावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्वयं एक ऐसा लाभ था जिसका ठीक मूल्य आकना कठिन है। इस तरह भारत का एक अर्ध-नग्न फकीर न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की सीढिया चढ़ता-उतरता था बल्कि ठेठ सेंट जेम्स पैलेस-भवन में भी बराबरी के नाते सन्धि-वर्षा करने बैठा था। ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को इससे क्या कम बचका पहुँचा होगा ?



: २ :

समझौते का भंग

समझौता और उसके बाद

संघर्ष व सत्याग्रह का समय खतम हो गया था। जिन कांग्रेस-कमिटियों की कल तक कोई हस्ती न थी, वे उन वृक्षों की तरह सब स्थानों पर फिर अपनी बहार पर आ गईं, जो पहले मुरझाये और सूखे हुए दीखते हैं लेकिन वसन्त में फिर हरे-भरे हो जाते हैं। एक बार फिर कांग्रेसी-क्षणा कांग्रेस के दफ्तरों व कांग्रेसियों के घरों पर लहराने लगा। कांग्रेस के अधिकारी एक बार फिर पुलिस से एक-एक कागज और कपड़े को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जप्त कर लिये थे और उनसे ले लिये गये थे। एक बार फिर स्वयंसेवक-गण बिल्ले, तमगे और पेटी लगाये अपनी अर्ध-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में क्षण्डे हाथ में लिये भाला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने लगे, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निषिद्ध था।

सबसे बढ़कर कांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी बालिकायें और बालक, बयस्क स्त्री-पुरुष धाराव और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को धाराव न पीने और विदेशी कपड़े से तन न ढकने की शिक्षा देने लगे। और ये सब बातें उसी सिंघाही की आँख के सामने होने लगी जो कल इन लोगों पर भेंडिये की तरह टूटता था, लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण से सन्तुष्ट नहीं थे। मजिस्ट्रेटों की भी कृपा-दृष्टि इसपर न थी। सिविलियन भी यह अनुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ रही थी कि उसने तो सब कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार बननेवाले निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोड़े जा रहे थे, उन्हें मालायें पहनाई जाती थी, उनके जुलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं वर्ता जाता था, और न शायद नम्रता ही रहती थी। अब उनके व्याख्यानों में विजय की ध्वनि और ललकार की भावना होती थी। कांग्रेस का छोटा मानने की नीवत आ गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई की माग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की माग करते थे और तीसरी जगह

किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लॉर्ड अविन ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें विदाई दी। वाइसराय-भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और वायदों से नावाकफ थे। लॉर्ड अविन ने यदि चोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो क्या? यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर लिया था, तो क्या? यदि वाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेश्वें व प्राविडेन्ट-फन्ड, जिन्होंने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो उससे क्या? यदि लॉर्ड अविन ने वारडोली की बेची गई जायदाद को वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को लिखने का बचन दे दिया था, तो उससे नई सरकार को क्या? यदि लॉर्ड अविन ने यह वायदा कर लिया था कि मेरठ-बडयन्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमे के दौरान में वे भुगत रहे हैं, तो उससे क्या?

अधिकारियों की कुचेष्टाये

लॉर्ड अविन भारत से १८ अप्रैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लॉर्ड विलिंगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सेन्टेरियस वही रहता है। जिलों पर शासन करनेवाले सिविलियन ही दरअसल वाइसराय होते हैं। २ नवम्बर १९२६ के दिल्लीवाले बक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रबन्ध की स्पिरिट उसी दिन से बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजातंत्रीकरण का और सिविलियन कलक्टरों के निरंकुश शासन से मुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह स्पिरिट एक वर्ष के सन्नाह के बाद भी न बदली और न गांधी-अविन-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही बदली। देश के हाकिमों ने समझौते को अपनी हतक-हज्जत समझा। सभी जगह वस्तुतः एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। रोजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरों में यह शिकायतें आने लगी कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता। अपनी ओर से कांग्रेस अपने पर लगाई शर्तों के पालन के लिए चिन्तित थी। वे शर्तें मुख्यतः पिकेटिंग और बहिष्कार-अचर में ब्रिटिश माल को शामिल न करने की थी। यदि कहीं इन शर्तों के पालन में शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर थे। कांग्रेसी लोग इधर-उधर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले छाठी-प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे। गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी

पुलिस इसमें बाज न आई। पूर्वी गोदावरी में वादपल्ली में बहुत दुःखद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली-काण्ड महज इसलिए हुआ था कि लोगो ने एक मोटर पर गांधीजी का चित्र रक्खा था और पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघ्र ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-काण्ड में बदल गई। लाठिया और गोलिया चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वे इसके बिना रहनी नहीं सकते थे। पर ऐसी ज्यादतिया आम बात हो गईं हो सो नहीं; लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घटनाएँ हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं हो सकता।

जब कांग्रेस ने अस्थायी संधि की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिशा में हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सब उम्मीदें नाकामयाब हुईं। गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने की बनिस्वत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ६, १० और ११ जून १९३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी, मुसलमान मित्रों के आग्रह से उनमें ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया —

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिले तो भी कांग्रेस के रस के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से बचने के लिए महात्मा गांधी गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो।”

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लैण्ड में अवश्य समझौता हो जायगा।

अस्थायी सन्धि की शर्तों के पालन के विषय की ओर लौटने से पहले कार्य-समिति की जून मास की बैठक की कार्यवाही का आशय दे देना ठीक होगा। मौलिक-अधिकार-उप-समिति और सावजनिक ऋण-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी गई। मिल के सूत से बने कपड़े के व्यापारियों तथा ऐसे करधो को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी, बन्द कर दिया गया। कुछ कांग्रेस-संस्थायें विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टॉक को बेचने की इजाजत दे रही थी। इनको बुरा बताया गया। श्रीनरीमन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार करें जोकि अस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें। कपड़ों के सिवा अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड बनाया जाने

को था। चुनाव के कुछ क्षणों (बंगाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। १८८५ से अबतक के कांग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०] २० स्वीकृत किये गये।

गांधीजी की चेतावनी

अब हम अस्थायी सन्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते हैं। कांग्रेस की नीति बिल्कुल रक्षणवादी थी। गांधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को आप होकर झगडा न शुरू करने की पर साध ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी दी थी। गांधीजी पस्त-हिम्मतों के भारी पैतान को दूर रखना चाहते थे। वह अथ और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते रहे। उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है —

“यदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजों को स्वीकृत कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टनम चेतावनी है कि हम भी रक्षणवादी उपाय करने के अधिकारी हैं। जैसे वे मद्रास में कहते हैं—तुम ५ पिकेटरो से अधिक नहीं खड़ा कर सकते। मैं पहले कह चुका हूँ—इस समय मान लो, लेकिन इसके बाद हम नहीं मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पांच पिकेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह नौ दिन का तमाशा होगा, या तो वे छूट जायेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। हम कोई नई स्थिति अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और हमें इसपर ज़रूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है, तो हमें उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। लेकिन जहाँ मासिक झण्डाभिवादन और सार्वजनिक सभा का मामला हो, हमें प्रतीक्षा—इजाजत की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरदवास्त ही देनी चाहिए। हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए।

“करवन्दी-आन्दोलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन में ले आवेंगे। जब ऐसा होगा, तब आर्थिक प्रश्न

वन जायगा, और जब यह आर्थिक प्रश्न वन जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर खिंच जायगी।”

जगह-जगह सन्धि-भंग

सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड विलिंगडन ने भी ठे शब्दों की भी कमी न रखी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनों की सच्चाई पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि वाइसराय की हवाई बातों से जो ऊँची आचार्यों की गई थी, वे सब झूठी हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में गांधीजी के दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सब टूट और गिर तो नहीं रहा है ?

युक्तप्रांत सुलतानपुर में ६० आदमियों पर दफा १०७ ताजिरात हिन्द में मुकदमा चलाया गया था। मदन शाहपुर में ताल्लुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय झण्डा हटा लेने का हुक्म दिया और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में बिठा दिया। एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों पर १४४ दफा की रू से नोटिस दे दिये गये। मथुरा में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबरदस्ती भंग कर दिया। लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर में जिन अध्यापकों व अन्य सरकारी नौकरो को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई। कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मागनेवाले विद्यार्थियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेंगे। बिचारी में लारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का अपमान किया और राष्ट्रीय झण्डों को जला दिया। बाराबकी में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंसपेक्टरों को १४४ धारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये। डिप्टी कमिशनर ने गांधी-टोपियों को उतरवा दिया और लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व कांग्रेस में न जाने की चेतावनी दी गई। युक्तप्रान्त के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई। कुछ ताल्लुकेदारों ने अपने क्रूरतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। सशस्त्र पुलिस गांववालों को भयभीत करने लगी। एक जागीर के प्रबन्धकर्त्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक शस्त्र को पीट-पीट कर मार दिया। किसानों को 'मुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रथा आम बात हो गई। हिसार (पंजाब) के चौताला में और नौशेरा से ताजीरी पुलिस नहीं हटाई गई।

एक पेंशनयाफ़ता फौजी सिपाही की पेंशन जप्त कर ली गई। तख़्तान में शान्त जुलूस पर लाठी बरसाई गई। छावनियों में राजनैतिक सभायें बन्द कर दी गईं।

बम्बई—अहमदाबाद, अक्लेश्वर और रत्नागिरि जिलों में गैर-लाइसेन्स-शुदा शराब की दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स-शुदा घण्टों में शान्तिमय पिकेटींग की आज्ञा नहीं दी गई। कैदी भी नहीं छोड़े गये। बलसाह में पांच आदमियों से इसलिए जुरमाना मागा गया कि सत्याग्रह-संग्राम के दिनों में उन्होंने स्वयंसेवक-कैम्प के लिए अपनी जमीन दे दी थी। जबतक जुरमाना वसूल न हुआ, जमीनें नहीं दी गईं। अस्थायी सन्धि के बहुत दिनों बाद मूल से एक साल्ट-कलक्टर ने एक नाव बेच दी थी, वह भी वापस नहीं की गई और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया। नवजीवन-ग्रेस नहीं दिया गया। कर्नाटक में पश्चिमी जमीनें तबतक वापस नहीं की गईं, जबतक यह बचन नहीं ले लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न लेंगे। कई पटेल और तलाटी फिर बहाल नहीं किये गये। दो डिप्टी-कमिशनरो को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पन्थान नहीं दी गई, यद्यपि लॉर्ड अविन बचन दे चुके थे। दो डाक्टरों व एक सुपरवाइजर को बहाल नहीं किया गया। आठ लड़कियों तथा ११ बालकों को सदा के लिए सरकारी स्कूलों से 'रिस्ट्रिकेट' कर दिया। इसी तरह अकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये गये। सिरसी व दिसापुर ताल्लुको में किसानों पर सख्तिबा और ज़्यादातिया गुरु की थी—उनकी केवल कृषि-सम्बन्धी कुछ शिकायतें दूर की गईं।

बगाल में बकीलो व बैरिस्टरो से 'आयन्दा ऐसा न करने का' बचन लेने में एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई। नर्वे आर्डिनेन्स के मातहत एक जप्त आयम वापस नहीं लौटाया गया। गोहाटी में विद्यार्थियों से ५०-५० की जमानतें मांगी गईं। जोरहट में सुपरिन्टेण्डेण्ट वाटंली की आज्ञा से १६ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले लड़कों को पीटा गया।

'दिल्ली—विद्यार्थियों से आगे के लिए बायदे लिये गये।

अजमेर-मेरवाड़ा—कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में जगह न देने का हुक्म निकाला गया।

मदरास—१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अफ़मरो को भेजी गई कि अस्थायी माघ के शान्तिमय पिकेटींग में 'सिलकारी साल' पर पिकेटींग शामिल नहीं है। तजोर के बकीलो पर शराब की दुकानों की पिकेटींग न करने के लिए १४४ दफ़ा की रू से नोटिस तामील किये गये। पिकेटींग करते हुए स्वयंसेवकों को ताड़ी की दुकान में १०० गज के अन्दर छाड़ा रहने की आज्ञा न थी। उनपर बनावटी

अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा गया और झण्डा व छाता रखने से भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (स्वयंसेवकों को) पानी न दिया जाय। एलोर में कपड़े की दुकानों पर पिकेटरो की सख्या एक या दो तक सीमित कर दी गई। कोमलपट्टी में जहाँ पिकेटरो की सख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर भी मे मुकदमा चलाया गया। कोयम्बटूर में उनकी सख्या ६ तक बाध दी। गुन्तूर में आख के एक ऑनरेरी असिस्टेंट सर्जन को कहा गया कि तुम तबतक बहाल नहीं किये जाओगे, जबतक सरकार-विरोधी आन्दोलन के लिए क्षमा न माग लो। आन्दोलन में भाग लेने के कारण जो बन्दूकें और उनके लाइसेन्स जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से नहीं लौटाये गये। बहुत-से कैदी नहीं छोड़े गये, हालांकि वे एक ही गवाही के कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गये थे जो छोड़ दिये गये। शोलापुर के मार्शल-लॉ कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिज्ञा लॉर्ड अर्बिन कर गये थे, लेकिन फिर भी वे न छोड़े गये।

परन्तु बारडोली में सरकार ने अस्थायी सधि का जो स्पष्ट भग किया, उसके सामने ये सब बातें भी फीकी पड़ जाती हैं। पाठकों को यह याद होगा कि इस ताल्लुक में लगानबन्दी का आन्दोलन था। नई मालगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दे दिये गये। हम नीचे गांधीजी की शिकायत और सरकार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं—

शिकायत और जवाब

शिकायत—“बारडोली में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये में से २१ लाख रुपये दे दिये गये हैं। यह दावा किया जाता है कि इस अदायगी के जिम्मेवार कांग्रेसी-कार्यकर्ता हैं। यह सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी शुरू की, तब उन्होंने किसानों को कहा कि उन्हें पूरी मालगुजारी—दस साल की और पिछली—चुकानी है। अधिकांश किसानों ने यह जाहिर किया है कि वे नई मालगुजारी भी मुश्किल से चुका सकते हैं। अधिकारियों ने पहले तो सकोच किया और कुछ समय तक तो अघूरा लगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिचकिचाते हुए अदायगी मंजूर कर ली और नये लगान के हिसाब में रसीदें दे दी। अब जो लगान देने में असमर्थता प्रकट करते हैं, उनसे नया या पिछला लगान मायना कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ विश्वास-घात है। अहातक वकाया का ताल्लुक है, हमें यह कहना है कि यदि मुलतवी वकाया पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण मुलतवी कर दिया

गया है, तो फिर गैर-मुल्तवी बकाया को स्वीकृत कर देने के तो और भी जबरदस्त कारण हैं, क्योंकि सत्याग्रही किसानों को पदार्थों के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास (लेन छोड़कर दूसरे इलाको में जाने) की वजह से भी सख्त नुकसान पहुँचा है। इस नुकसान का बन्दाबाज लगाकर अधिकारियों के पास भेज भी दिया गया है। फिर कांग्रेसी-कार्यकर्त्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस मामले में सन्देश हो, उसकी अधिकारी फिर जाच कर सकते हैं। परन्तु इस बात को वे जरूर बुरा समझते हैं कि किसानों को दबाया जाय, जुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले।”

प्रान्तीय सरकार का उत्तर—“(बम्बई) हम यह नहीं मानते कि देने में असमर्थता प्रकट करनेवालों से नया या पिछला लगान मागना कार्यकर्त्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घात है। असमर्थता सिद्ध होनी चाहिए, केवल कहने से काम नहीं चलता। गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होना चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है। सरकार सभी बकाया मजूर करती है, जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अधूरी खराब हो गई हो और किसान हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हो। बारबोली में बकाया इसलिए नहीं रहा कि फसल खराब हो गई, बल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में अपना लगान देने से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुकसान के कारण कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नहीं, इसकी जाच प्रत्येक मामले में पृथक्-पृथक् होनी चाहिए। बारबोली में लगान-बसूली के सिलसिले में केवल एक जायदाद जप्त की गई है। कलक्टर ने उनका पूरा जवाब रक्खा है, जो रिमायट के अधिकारी थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,००० रुपये के लगभग बसूली स्वीकृत कर दी है और १६००) ४० तक की छूट भी स्वीकृत कर ली है। लगान-बसूली के लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल ऐसे कुछ गावों में वे पुलिस को ले गये, जहाँ उसकी सहायता के बिना बसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की आशंका से डरते थे। मामलतदार या गाँव के मुख्य लगान-अफसर की रक्षा करना, जव्दी के सिलसिले में घर पर पहरा बिठाना, और कुछ मामलों में अपराधी को बुलाने के लिए गाव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना—यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे।”

जब गांधीजी गुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने ये सब शिकायतें भारत-सरकार तक पहुँचाईं। अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई

उम्मीद न थी। गांधीजी ने बारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति बम्बई-सरकार को भी भेज दी। बम्बई-गवर्नर का जवाब भी असन्तोष-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया।

जांच का प्रस्ताव

तब गांधीजी ने पत्र नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस सिलसिले में जो पत्र-व्यवहार हुआ, वह नीचे दिया जाता है —

१ भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के १४ जून, १९३१ के पत्र का उद्धरण —

“प्रान्तीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने में समर्थ न होंगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना मैं चाहता हूँ उतना हस्तक्षेप न करें। इसलिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को तथा उन सब प्रश्नों को, कि आया समझौते की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्थायी पत्र नियुक्त किये जायें।”

२ भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के २० जून, १९३१ के पत्र की नकल —

“आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार से प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी? यदि रिपोर्टें सच हैं, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन पूर्ण विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्त्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार भुझे मिलते हैं, वे मुझे आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्टें पर विश्वास नहीं करने देते। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहातक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बात पेश करता हूँ। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी जांच करने के लिए एक जाच-समिति—एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से—नियुक्त करने की सलाह देंगे? और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहाँ पिकेटिंग बिल्कुल मौकूफ कर दिया जाय, और दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। यदि आपको येरी यह सलाह पसन्द न हो तो, आप कोई और

अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब-तक मैं आपके पत्र में लगाये गये विशेष आरोपो की जाच करता हूँ।”

३ गांधीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब के ता० ४ जुलाई १९३१ के पत्र की नकल —

“१४ जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अर्थ-सवधी प्रश्नों को तय करने के लिए शायद स्थायी पत्र नियुक्त करने का समय आगया है। फिर २० जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपो की जाच करने के लिए एक जाच-समिति—जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हो—नियुक्त करने की सलाह दे और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहाँ पिकेटिंग विलकुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह बचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। समझौते के बारे में उठने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के सभावित कारणों को ही दूर करने के आपके इस परामर्श की मैं कद्र करता हूँ। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह मुख्यतः उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहाँ तक पिकेटिंग के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गये हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकेटों पर मुकदमा चलाया है या वह चलाने का खयाल कर रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण लेने से पूर्व सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस मामले की जाच करेंगे और अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रक्षण का कर्तव्य पुलिस ने हटकर, जिसका यह प्रधान कर्तव्य है, एक जाच-मण्डल के पाम चला जायगा। इस मण्डल के सदस्य किसी भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं, जब कि पुलिस को तो स्वभावतः कानून के अनुरार ही कार्रवाई करनी पड़ती है, अतः न तो यह व्यावहारिक है और न समझौते की यह मनाही थी कि इन विषय पर पुलिस के कर्तव्यों को किसी तरह रद्द कर दिया जाय।

“ऐसे मामलों में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है। और जबरन अपील में अदालत का यह फैसला कि पिकेटिंग ने साधारण कानून और इसलिए मनोनीत ती शर्तों का भंग हुआ, बदल नहीं जाना, नबनकर अदालत का ही फैसला मानना होगा और इसलिए समझौते के फल-स्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर

देना पड़ेगा। जाच-समिति से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से कांग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपका है, उनका सम्बन्ध अधिकांशतः अमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, व्यक्तिगत कार्य-स्वतंत्रता और शासन-प्रबन्ध से है। अर्थात् समझौते का मारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी पर अवश्य बढ़ा असर डालेगा। जहाँ तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहाँ तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भग आम होने लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर शासन-प्रबन्ध पर पड़ने लगता है, तो सरकार के लिए यह असंभव होगा कि वह मामला जाच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे। जब समझौते की अन्तिम धारा बनाई गई थी, तब इसका ह्याल भी नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेदारियों के निगमन से इसकी सगति ही बैठाई जा सकती है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यतः दोनों पक्षों के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए। अज्ञातक सरकार का साल्लुक है बड़ा तक वह उसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ सदेहास्पद मामलों का होना तो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुँचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी।”

४ इमर्सन साहब को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १९३१ के पत्र की नकल —

“बाइसराय-भवन में आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार मैं अपनी यह प्रार्थना लेखवद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष पंच विठाये जायें, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये जायें। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिनपर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके आशय के सम्बन्ध में सरकार व कांग्रेस में मतभेद रहे—

(१) क्या पिकेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल है ?

(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्धारित करने का अधिकार है कि जिसमें पिकेटरो का उन दुकान की नज़र में रहना ही असम्भव हो जाय ?

(३) क्या सरकार को पिकेटरो की ऐसी सख्या सीमित करने का अधिकार है जिससे उस दुकान के समी रास्तों पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय ?

(४) क्या शान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश मण्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ?

(५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के तिलतिले में उनकी मशा को साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ लिया है और कांग्रेस ने दूसरा।

(६) कलम १८ (अ) में 'लौटाणा' शब्द की व्याख्या करना।

(७) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्तूकें लाइसेन्स रद्द करने के बाद जन्म की गई हैं, क्या उन्हें लौटाणा समझीते के अन्तर्गत है ?

(८) नवे आर्बिनेन्स के अनुसार जब हुई कुछ जायबाद और कलटिक की 'पानीवाली जमीन' (Water Lands) की वापसी क्या इस समझीते के अन्तर्गत है और क्या सरकार को ऐसी वापसी पर कुछ शर्तें लगाने का अधिकार है ?

(९) धारा १६ में 'स्थायी' का अर्थ।

(१०) जिन विद्यार्थियों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर शर्तें लगाने या सविनय अवज्ञा-संग्राम में लगाई गई पाबन्दियों के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार है ?

(११) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार को किमी व्यक्ति या सख्या को दण्ड देना—पेंशन, और म्यूनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि बन्द करने का अधिकार है ?

"यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल यही मामले पेश होंगे। यह भी संभव है कि भविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जावें, जिनके संबंध में समझीते की नीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रखें कि सरकार या कांग्रेस दोनों की ओर से लिखित वक्तव्य पेश हो। दोनों पक्ष के वकील उन विषयों पर अपनी-अपनी दलीलें पेश करें और वाद को पंच जो निर्णय करे वह दोनों पक्षों को मान्य हो। बातचीत के मिलनिले में जैसा मैंने कहा था कि सरकार और कांग्रेस

के मतभेदों की अवस्था में प्रश्नों के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता, तब उसका यह मतलब न लिया जाय कि मैंने अपनी भाग वापस ले ली है। ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतभेद इतने तीव्र हो जावें कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी छान-बीन करने के लिए पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय। फिर भी मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पंच के पास बिना भेजे ही सब मतभेदों का निर्णय कर सकेंगे।”

५ गांधीजी के नाम इमर्सन साहब के खियला से ३० जुलाई १९३१ के लिखे पत्र की नकल —

“आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ५ मार्च के समझौते की व्याख्या-सबकी प्रश्नों के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध किया है और (२) कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो आप पंच के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते हैं, जबकि उनके आशयों पर कांग्रेस व सरकार में एकमत न हो सके।

“भारत-सरकार ने व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक-मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पत्र में वर्णित उन ११ प्रश्नों पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक-मण्डल भ्रूजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियों और फर्जों का उल्लंघन में पड़ जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रबन्ध पर सीधा असर डालनेवाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अस्तित्वार किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य तो लाभ उठा सकें लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांग्रेसी) लोग पृथक् रहें और जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करे। ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है।

“ऊपर बताये चूल्हों के सिलसिले में अब मैं आपके पत्र में वर्णित कुछ प्रश्नों की छानबीन करता हूँ। पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं। पिकेटिंग के कुछ खास मामलों में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके

व धरो से निर्वासित किसानों की दुर्दशा से युक्त-प्रान्त के नेताओं को—प० मदनमोहन मालवीय को भी—चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। गांधीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर माल्कम हेली को एक तार भेजा। लेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला। सभी ओर से ऐसी शिकायतें आ रही थी और परिस्थितियाँ इतनी दिल तोड़नेवाली थी कि ११ अगस्त १९३१ को गांधीजी बाइसराय को निम्नलिखित तार भेजने पर विवश हो गये—

“बहुत दुःख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं। पत्र में हकीकत और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों बातों में अन्तिम निर्णय करेगी। इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार और शिकायत करनेवाले दो बल हों, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और जद्दी फैसला करे। कांग्रेस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। बम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और युक्त-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में होनेवाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर अब मे ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मे लन्दन को रवाना न होऊँ। जैसा मैंने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के पहले मैं आपको लिखूँगा, मैं अगर लिखी हुई सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अन्तिम घोषणा करने से पहले मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा।”

बाइसराय का उत्तर—१३ अगस्त १९३१

“आपने जो कारण बताये हैं, यदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस उस अवस्था को स्वीकार नहीं करती, जो गोलमेज-परिषद् में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे खेद है। मैं इन कारणों को उचित नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचने बिना नहीं रह सकता कि सरकार की नीति तथा उसके आधार-भूत बातों को गलत समझने के कारण ही यह अन्देश पैदा हुआ है। मेरा खयाल था कि युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में आपका सन्देश सर माल्कम हेली के ६ अगस्त के तार से और गुजरात के सम्बन्ध में सर जर्नेस्ट हॉटसन के प्राइवेट-सेक्रेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ से दूर हो गया होगा। मैं आपका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर आकर्षित करता हूँ, जिसमें मैंने आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में मैं खुद दिलचस्पी रखता हूँ। और मैंने आशा की थी कि आप इन विस्तार की बातों से उत्पन्न विवादों के

कारण अपनेको भारत की उस सेवा से वंचित नहीं करेंगे, जो आप उस महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेकर कर सकते हैं, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य का निपटारा कर देनेवाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो मैं फौरन ही प्रधान-मन्त्री को आपके लन्दन न जाने की सूचना दे दूंगा।”

गांधीजी का अन्तिम इन्कार—१३ अगस्त १९३१

“आपके आश्वासन के तार के लिए अन्यवाद। आपके आश्वासन को मुझे वर्तमान घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए। यदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते की शर्तों के बाहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे और आपके समझौते-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतभेद है। वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैंने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा। कृपया आप प्रधान-मन्त्री को इसकी सूचना दे दें। मैं समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाशित करने में आपको आपत्ति न होगी।”

वाइसराय का उत्तर—१४ अगस्त १९३१

“आपके निश्चय की सूचना मेने प्रधान-मन्त्री को दे दी है। मैं आज सच्चा-समय ४ बजे सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं।”

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि कांग्रेस के गोलमेज-परिषद् में भाग लेने के रास्ते में दिक्कतें आनेगी, लेकिन फिर भी हरेक साल अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलझ जायगी। यह कहना गलत न होगा कि लोग जहाँ आशा न थी वहाँ भी आशा लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस सविन्यार्चा के बीच-बीच में टूटते जाने पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी कांग्रेस को प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए पूरी तैयारी करनी थी। इस तरह जबकि गांधीजी वाइसराय और बम्बई व युक्तप्रान्त की सरकारों से पत्र-व्यवहार करने में लगे हुए थे, कांग्रेस की कार्य-समिति बदस्तूर अपना कार्य करने में सज्जन थी। हम भी पाठकों को उसी ओर ले जाते हैं।

कार्य-समिति की बैठक

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने 'ब्रिटेन व भारत के लैन-वेन' पर तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार-समिति ने अपनी बैठकें मछलीपट्टम में करके रिपोर्टें तैयार की थी। कार्य-समिति ने इस रिपोर्ट को महा-समिति के सामने पेश करने का निश्चय किया। हिन्दुस्तानी-सेवादल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलत-फहमिया फैली हुई थी, इसलिए दल को कांग्रेस का केन्द्रीय स्वयंसेवक-संगठन मान लिया गया और यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे वह अपनी ओर से नियुक्त करे। इसके काम भी बता दिये गये। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी वाकायदा स्वयंसेवक-दल बनावें। इस दल के सदस्यों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयंसेवक-दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रखा गया। सेवादल जिसकी ज० मा० परिषद् कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डाक्टर हार्डीकर के नेतृत्व और संचालन में धानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया और सेवादल ने भी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए धान्तिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय की प्रतिज्ञा स्वीकार की।

साम्प्रदायिक प्रश्न पर नई योजना

इसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा काम आता है, यह था साम्प्रदायिक प्रश्न पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलसिले में कार्य-समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया —

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्यों न हुई हो, उसने शुरू से ही विषुद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में सदा प्रयत्नशील रही है। कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है—

‘चूँकि नेहरू-रिपोर्टें खतम हो चुकी हैं, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा करना आवश्यक है। कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों का हल सिर्फ विषुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूँकि घासकर सिक्खों ने और साधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्टें में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के हल के प्रति असंतोष

जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्खों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों को विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई हल कांग्रेस को मंजूर न होगा, जिसमें सम्बन्धित दलों को पूरा सतोष न होता हो।

“इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस करती है कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल नुस्खाना चाहिए जो देखने में साम्प्रदायिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ बहुसंख्यक के बाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास की है—

“१ (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में जातियों को यह आश्वासन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी।

(ख) विधान में सास धारारें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी।

(ग) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना सब-सरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में होंगे।

२ तमाम बालिग स्त्री-मुख्य मताधिकार के अधिकारी होंगे।

नोट—कराची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति बालिग-मताधिकार के लिए बच चुकी है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमी फैली हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में प्रत्येक जाति की आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

३ (क) भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार सम्मिलित निर्वाचन होगा।

(ख) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त तथा पंजाब के सिक्खों और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों

के लिए, जहाँ उनकी सख्या आबादी के २५ फी सदी से भी कम हो, सघीय और प्रान्तीय धारा-समाजों में आबादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे और उनके अलावा अधिक स्थानों के लिए भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होगा।

४ पदों पर नियुक्तिया निष्पक्ष सर्विस-कमीशनो के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचारु-रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और बे बहुत-कुछ योग उसमें दें सकें इस बात का वे पूरा खयाल रखेंगे।

५ सघीय और प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल के निर्माण में अल्पसङ्ख्यक जातियों के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे।

६ पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में है।

७ सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जायगा, बशर्ते कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का आर्थिक भार सहन करने को तैयार हो।

८ देश का भावी शासन-विधान सघीय होगा। अवशिष्ट अधिकार सब की इकाइयों के पास रहेंगे, बशर्ते कि और छानबीन करने पर यह भारत के आत्यन्तिक हित के विरुद्ध साबित न हो।

“कार्य-समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहाँ एक ओर कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वहाँ दूसरी ओर उग्र विचार के लोगो को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को बिना हिचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दलों को मजूर हो, जैसे कि वह लाहौर के प्रस्ताव से बची हुई है।”

विदेशी कपडे और सूत के बहिष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य-समिति में तैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपडे व सूत के बहिष्कार के सिलसिले में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, रद्द मानी जायगी —

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तबतक हम निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे, जबतक कि कांग्रेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहती —

१ हम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हुआ कपड़ा न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं।

२ हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं, जिसने कांग्रेस की शर्तों को न माना हो।

३ हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपड़े को भारत में न बेचने का वचन देते हैं।”

इसके बाद यह फैसला किया गया कि अस्पृश्यता-निवारिणी समिति को, जो गत वर्ष संविनय अवज्ञा के सभाम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। श्री जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भी दिये गये।

मिल-समिति (Textile Mills Exemption Committee) की तथा मजदूरो की हालत के सवाल पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहाँ सम्भव और आवश्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हों, मजदूरों को वण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति को अधिक अच्छी करने की कोशिश करे।

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १९३१ को फिर हुई और उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के प्रयत्न और बगाल में जज गालिक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आक्रमणों पर खेद और निन्दा प्रकट करते हुए गवर्नर के जीवन पर आक्रमण के प्रयत्न को उस स्थिति में तो बहुत बुरा बताया, जबकि फर्ग्युसन कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर पर उन्हें निमन्त्रित किया था।

राष्ट्रीय-झण्डा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि “राष्ट्रीय झण्डा तीन रंग का और पहले की तरह लम्बाई-चौड़ाई में समानान्तर होगा। लेकिन उसके रंग क्रमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होंगे। सफेद पट्टे के केन्द्र में गहरे नीले रंग का चरखा होगा। रंग गुणों के न कि जातियों के सूचक हैं। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग शान्ति और सत्य का, हरा रंग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आशा का प्रतिनिधि होगा। इन तीनों रंगों का अनुपात ३ : २ : १ होगा।” ३० अगस्त रविवार को नया राष्ट्रीय

झडा फहराने का निश्चय किया गया। इसीके अनुसार फिर आगे प्रति मास हर रविवार को झडा फहराया जाने लगा। मौलिक-अधिकार-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और ऊपर लिखे अधिकार व कर्तव्य स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, जैसा अन्तिम रूप में था, इस बैठक में पास कर दिया गया।

अफगान जिरगा

उन्ही दिनों बम्बई में कार्य-समिति ने सरदार भगतसिंह के दाह-संस्कार के प्रश्न पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि जो भीषण अभियोग लगाये गये हैं उनका कोई आधार नहीं है। सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा व खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निश्चय किया गया —

सीमाप्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद समिति ने सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के पुनः सगठन तथा उसमें अफगान जिरगों को सम्मिलित करने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कांग्रेस-स्वयंसेवक-सगठन के एक अंग हो जाने चाहिये।

कार्य-समिति की प्रार्थना पर सीमाप्रान्तीय नेता खान अब्दुलगफ्फारखा ने उस प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन के संचालन का भार अपने कंधों पर ले लिया है।”

कार्य-समिति की निराशा

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम पर पहुँची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कांग्रेस गोलमेज-परिषद् में न भाग ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए। लेकिन समिति ने यह भी बोधना की कि दिल्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा —

“कार्य-समिति ने १३ अगस्त को गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने के बारे में प्रस्ताव पास किया था। उसे मद्दे-नजर रखते हुए यह समिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय। इसलिए समिति सब कांग्रेस-संस्थाओं व कांग्रेसियों को तबतक समझौते की कांग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तों पर बमल करने की सलाह देती है, जबतक कि कोई दूसरी हिदायत न दी जाय।”

असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओं के लिए जब कार्य-समिति न जुलाई जा सके, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार भी दे दिये गये, कि "इस प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति की ओर से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने का अधिकार दिया जाता है।"

मणि-भवन (बम्बई) में सारे दिन आवाओं व उम्मीदों से भरी ये अफवाहें गरम हो रही थी कि सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के बरत बड़े-बड़े नेता मणि-भवन से बाहर निकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को बताने लगे कि आखिरी समय की गई सन्धि-वार्ताओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी कुछ आशावादी अवतक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त में कोई-न-कोई सूरत निकल ही जायगी। लेकिन जब गांधीजी रात के ८:॥ बजे मणि-भवन छोड़कर बम्बई-सेण्ट्रल स्टेशन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे बर्जे के डिब्बे में सवार हो गये, तब सब सन्देह बिलकुल खतम हो गये।

सर प्रभासकर पट्टनी ने दोपहर को आध बण्टे तक गांधीजी से मुलाकात की। असोसियेटेड प्रेस के मेंट करने पर सर प्रभासकर पट्टनी ने (जिन्होंने 'एस० एस० मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्यगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा स्यगित कर दी है।

इस तरह गोलमेज-परिषद् के अभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ। १५ अगस्त को डॉ० सप्रू, श्री जयकर और श्री रगास्वामी आयगर गांधीजी से दो-एक बार मिलकर बम्बई से रवाना हो गये। इस विषय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सेक्रेटेरियट ने समझौते को समुद्र में फेंक दिया था।

न जाने के कारण

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के उत्लब्धन, गांधीजी के गोलमेज-परिषद् में उपस्थित होने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समर्थन कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण था। वस्तुतः यह इमर्सन सा० का ३० जुलाई का पत्र था, जो पहले आ चुका है, जिसने स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया था। बम्बई के गवर्नर का १० अगस्त का पत्र भी कम

निर्णायक न था। मर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमें सौम्य शिष्ट और सयत-भाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण था चारडोली में लगान-बमूली के लिए दमनकारी उपायों का अवलम्बन। २२ लाख रुपये में से २१ लाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अब लगान न चुकानेवाले आपत्ति में ग्रस्त हैं और समय चाहते हैं। पिछले सालों का वकाया करीब दो लाख रुपया लेना था, जिसका अधिकांश भाग गुजरात के दुर्भिक्ष के कारण सरकार ने मुत्तबी भी कर दिया था। सरकार ने पुलिस-द्वारा धमकिया देना व पुलिस के 'जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले सालों का वकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके कहने पर सरकारी मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती है। कांग्रेस यह साबित करने को तैयार थी कि लोगों को भयभीत करने और कुछ मामलों में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख रुपया भी नहीं होती थी। सरकार का कहना था कि लगान की बमूली में अन्तिम निर्णय कांग्रेस का नहीं बल्कि सरकार और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिश-शान्ति और ब्रिटिश-आसन अभी वहाँ कायम है। सरकार इसे जताना और साबित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रोब की—उसी रोब की जिसकी इतनी तारीफ माण्टेगु साहब ने की थी—बिन्ता थी।

एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गांधीजी इरलैण्ड नहीं जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर असारि को गोलमेज-परिषद् का प्रतिनिध मनोनीत नहीं किया था। स्वभावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी। कांग्रेसी होने के अलावा वह भारत की एक बड़ी पार्टी—राष्ट्रीय मुस्लिम दल—का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं हैं। उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्वराज्य—मुकम्मिल आजादी के लिए उत्सुक था। लेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी के कहने से पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डॉक्टर असारि को मनोनीत करने का बचन लॉर्ड अर्विन ने दिया था, जब कि पहले दो व्यक्ति मनोनीत कर लिये गये और डॉक्टर असारि छोड़ दिये गये। यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलिंगडन जानते

ही न थे कि लॉर्ड अविन ने क्या वचन दिया था। लेकिन गोलमेज-परिषद् में यह प्रवचन भी ब्रिटिश-हितो के लिए अच्छा था कि मुस्लिम-भारत स्वराज्य के विरुद्ध है। लॉर्ड अविन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिंगडन ने यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अमारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है। वे तो उनसे विरुद्ध होते ही। यदि वे विरोध न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; बल्कि भारत के प्रतिनिधि होते। देश में डॉक्टर अमारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवचन और निर्भीक विरोधी थे। ऐसे डॉक्टर अमारी के चुनाव को वे मुसलमान प्रतिनिधि, कैसे सहन करते? कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया था जिसका समर्थन गोलमेज-परिषद् में एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते। सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसलमान ङग को गटककर कांग्रेस को बेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय-सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज-परिषद् के लिए छन्दन आने में इन्कार कर दिया।

आशा के पहले

एक बार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगीं। १५ अगस्त को लडाई की हवा की ही सब जगह चर्चा थी। इसमें मन्देह नहीं कि लॉर्ड विलिंगडन का रस पूर्ण धिष्टता का था। उन्होंने गांधीजी ने कहा कि आप मामले को सोई नहीं। जब कभी कोई दिक्कत हो, मुझसे मिल लें। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेच करते थे तो उसका कोई उत्तर न होता था। सारा देश एक निराशा में डूबा हुआ था। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 'मुल्तान' जहाज से अपनी यात्रा स्यंगित कर दी थी, जिसने श्री मन्नू, जबकर और आयरगर रवाना हुए थे। गांधीजी ने अपनी स्थिति निम्नलिखित मरल शब्दों में रख दी —

“यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उनके आग्रह के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ था किनी पक्ष की ओर से उसका सत्यजन चिरा गया, तो मेरी सम्मति में नव नमजोती के साथ लागू होनेवाले नियम इन समझौते पर नी लागू होने चाहिए। इन नमजोती पर तो वे और भी ज्यादा ज़रूरिए लागू होने चाहिए, क्योंकि यह समझौता एक महान् मरजार और नारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान् सत्ता के बीच हुआ है। यह बात नहीं है कि इन नमजोती

पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इसीलिए सरकार पर यह बोहरी जिम्मेवारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नों पर एक नहीं हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्यायालय के सामने पेश करे। कांग्रेस की एक बहुत सरल और स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा है कि झगड़े के ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौंप देने चाहिए।”

गांधीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया। वह तो कहते थे कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारें समझौते की शर्तों की पूर्ति करती रहें, मैं लन्दन की ओर दौड़ पड़ूंगा। जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर पर कह दिया—“यहाँ के बड़े सिविलियन नहीं चाहते कि मैं परिषद् में जा सकूँ। और यदि वे चाहते भी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदास्त नहीं कर सकती।” देश के सिविलियन बड़े जोरों से यह बात फैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक मुकाबले की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी विध्वंसक संस्था कभी गवारा नहीं की जा सकती। गांधीजी ने बम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय लॉर्ड विलिंगडन को एक निजी पत्र लिखा कि अपने नेतृत्व में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी पंच नियत करने पर ज़िद की, हा, उसके इस अधिकार का दावा मैंने अवश्य किया है। मैं तो केवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र इस तरह है —

“इतनी शीघ्रता से घटनायें घटित होती रही हैं कि मैं आपके ३१ जुलाई के कृपापत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी हुई है उसका मैं कायल हूँ। पर पिछली घटनाओं ने उसे भूतकाल का इतिहास बना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के तार में कहा है कि ये समस्त परिस्थितियाँ घटलाती हैं कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में ही मौलिक अन्तर है।

“मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने बहुत गौर के साथ विचार करने के बाद ही यह निश्चय किया है कि मेरा जो यहाँ पर उत्तरदायित्व है उसे तथा आप के निश्चय को देखते हुए मुझे गोलमेज-परिषद् में उपस्थित नहीं होना चाहिए। मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि आपको यह सुझाया गया है कि मैंने पंच की स्थापना पर अधिक जोर दिया और मैंने अपनेको प्रतिद्वंद्वी सरकार का मुखिया बनाना चाहता हूँ। और आपका निर्णय तो इन्हीं सुझाई बातों के आधार पर बना है। हा, यह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इसकी मांग की थी, पर यदि आपको

मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान लेंगे कि मैंने कभी इसपर जोर नहीं दिया। इनके विपरीत मैंने आपने यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जाय—जिसका मैं अधिकारी भी हूँ—तो मुझे मनोष हो जायगा। आप इसके सहमत होंगे कि पत्र की न्यायना पर जोर देना बिल्कुल बुरी बात है।

“प्रतिद्वन्दी सरकार के सम्बन्ध में मुझे खयाल है कि मैंने आपका भ्रम उन्नी समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं अपनेको जिला-अफसर नहीं समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से बने पटेल या गांधी के मुखिया का जो कार्य किया है, वह भी जिला-अधिकारियों की जल-कारी में और अनुमति में। इसलिए यदि उर्ध्वमुख दो गलत बातों ने आपके विचारों पर अमर डाला हो तो मुझे खेद होगा।

“इस पत्र के लिखने का मेरा अभिप्राय यह बरपाय करना है कि क्या आज वह बिल्ली-समझौते को कतन सम्मते हैं या गोलनेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते हैं? कांग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रायः-जान निम्नलिखित निष्कर्ष किया है—‘१३ अगस्तवाले कार्य-समिति के गोलनेज-परिषद् में भाग न लेने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव से दिल्ली-समझौते का अन्त नहीं मन्जूर चाहिए। अतः सभी कांग्रेसियों और कांग्रेस-सत्ताओं को सलाह देती है कि जबतक और कोई आदेश न दिया जाय, दिल्ली समझौते की कांग्रेस पर लागू होनेवाली बातों का पालन किया जाय।’

“इससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और वह मन्चाई ने दिल्ली-समझौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रांतीय सरकारों की परस्पर सम्बन्ध रखने की अनोखी परिणति है।

“जैसा कि पत्रों में तथा बातचीत में भी पहले मैं आपको बतला चुका हूँ, प्रांतीय सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति दिन-दिन कम-ही-कम दिखाई देती है। कार्य-समिति के दफ्तर में बराबर सरकार के ऐसे कार्यों की जानकारी आ रही है जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार जापकेतियों और कांग्रेस-आन्दोलन को कुचलना चाहती है।’

गांधीजी ने अपना पत्र इस आशयना के साथ मनाज किया कि इनका उत्तर जल्दी मिले और यदि दिल्ली-समझौते का पालन मंजूर है, तो मैं कहूँगा कि जो मित्रों आपके सामने पेश की गई है उनपर शीघ्र ही विचार किया जाय, क्योंकि मेरे नामी-कार्यकर्ता इसपर जोर दे रहे हैं कि यदि मित्रों ने दूर नहीं होना तो हममें-

आत्म-रक्षा के लिए हमें भी रक्षात्मक उपाय हाथ में लेने की आज्ञा दी जाय। गांधीजी को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे अपमानित करना नहीं चाहते थे। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-सर्विसवालों के निश्चित विरोध के कारण अस्थायी सधि को तोड़ रही थी, न कि कांग्रेस। गांधीजी आवश्यक और अनावश्यक का भेद जानते थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल-सर्विस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। "इसलिए", गांधीजी कहते थे, "जब तक इस सर्विस के सब कर्मचारियों के खयालत न बदल जायें, पूर्ण स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के सधि-वर्चा करने की कोई सुरत नहीं है। कांग्रेस को अमी और कष्ट-सहन व वलिदान में से गुजरना होगा, चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। इसलिए मैं तो अपने लिए बारडोली को ही खरी कसौटी मानता हूँ। सिविलियनों की नब्ज देखने के लिए ही इसकी योजना की गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बात न थी।"

आशा हुई

गांधीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विरुद्ध आरोप-सूची को प्रकाशित कर दिया था। कुछ लोगों ने समझा कि गांधीजी ने इसे प्रकाशित कर सरकार को चुनौती दी है। डॉ० सप्रू और श्री जयकर ने 'मुलतान' जहाज से इसी आशय का बेलार का तार दिया और उसने बताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने बाइसराय व भारत-मंत्री के साथ सधि-वर्चा में उन्हें परेशानी में डाल दिया है। गांधीजी तो यहां तक तैयार थे कि कांग्रेस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की इकतरफा जांच किसी निष्पक्ष पंच-द्वारा करा ली जाय। गांधीजी के पत्र का बाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोष-जनक न था। बाइसराय ने गत पांच मास की कांग्रेस की कार्यवाहियों का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्ली-समझौते के भाव और अर्थों के प्रतिकूल थी और शान्ति-स्थापन के लिए, विशेषतः युक्त-प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, बाधक थी। बाइसराय ने उसमें यह भी लिखा था कि गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस का सम्मिलित न होना समझौते के प्रधान उद्देश को असफल करना है, लेकिन सरकार विशेष उपायों को तब तक काम में न लायेगी जब तक कि वह ऐसा करने को बाध्य न हो जाय। गांधीजी ने समझौता-पालन की बाइसराय की इच्छा का हृदय से स्वागत किया और सब कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे सावधानी से समझौते

का पालन करें। उन्होंने इस विषय पर वाइसराय से बातचीत करने के लिए तार-द्वारा मुलाकात की अनुमति भी मागी। मुलाकात की अनुमति मिल गई। इसपर गांधीजी, श्री वल्लभभाई पटेल, जवाहरलालजी और गांधीजी के एकाकी मित्र सर प्रभाशकर पट्टनी वाइसराय से मिले। वाइसराय ने कार्यकारिणी की बैठक की। आखिर बहुत-सी बाधाओं के बाद मामले किसी तरह सुलझाये गये और गांधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गांधी को पकड़ने के लिए रवाना हुए, जो उन्हें २६ अगस्त को रवाना होनेवाले जहाज पर सवार करा सके।

इस तरह गांधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत के परिणाम-स्वरूप यह फैसला हुआ कि कांग्रेस की ओर से गांधीजी गोलमेज-परिषद् में भाग लें और इसके अनुसार वह बम्बई से २६ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये।

भारत-सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति में यह समझौता प्रकाशित कर दिया। इसके साथ ही गांधीजी का भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमर्सन के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह भी प्रकाशित कर दिया। क्योंकि पत्र भी समझौते के मूल-भूत अंग थे। सरकार की विज्ञप्ति और वे पत्र नीचे दिये जाते हैं।—

सरकारी विज्ञप्ति

“१ वाइसराय महोदय और गांधीजी की बातचीत के परिणाम-स्वरूप 'गोलमेज-परिषद्' में गांधीजी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।

२ ५ मार्च १९३१ का समझौता चालू है। यदि यह साबित हो गया कि कुछ मामलों में उसका उल्लंघन किया गया है, तो भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें उन मामलों में समझौते की खास धाराओं का पालन करावेंगी और यदि उस सम्बन्ध में उनके सामने कोई बात रखी जायगी तो उसपर भी अच्छी तरह विचार करेंगी। समझौते के अनुसार कांग्रेस भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेगी।

३ सूरत-जिले में लगान-वसूली के बारे में विचारणीय बात यह है कि क्या बारडोली-ताल्लुका और बालोड महाल के जिन गांवों में पुलिस-मार्दों के साथ माल-अफसर जुलाई १९३१ में गये थे, उनमें लगान देनेवालों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुलिस-द्वारा जबरदस्ती करके बारडोली-ताल्लुके के अन्य गांवों की अपेक्षा अधिक लगान मांगा गया था या उनकी अपेक्षा उनसे अधिक वसूल किया गया? बम्बई-सरकार से परामर्श करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत होते हुए, भारत-सरकार

ने यह निश्चय किया है कि इस प्रश्न की जांच की जायगी। जांच का क्षेत्र यह होगा कि —

विचाराधीन गावों में पुलिस-द्वारा जबरदस्ती और दमन करके सातेदारों को उन गावों की अपेक्षा जहाँ ५ मार्च १९३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना बसूली हुई है, चारडोली के दूसरे गावों में जो अदाब रक्खा गया था उससे अधिक लगान देने के लिए बाधित किया गया, इस आरोप की जांच करना, और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रकम का निर्धारण करना। इन बातों के अन्तर्गत उठनेवाले किसी भी विवाद पर गवाहिया दी जा सकती है।

बम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० गॉर्डन को नियुक्त किया है।

४ कांग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें जांच की आज्ञा देने को तैयार नहीं हैं।

५ यदि समझौते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले में नई शिकायतें करे, तो उन शिकायतों पर साधारण शासन-प्रबन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जांच करनी है या नहीं, और यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन सब बातों का फैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।”

पत्र-व्यवहार

हमसैन सा० के नाम गांधीजी का पत्र—शिमला २७ अगस्त १९३१

“आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद। सर कावसजी ने भी आपके बताये सशोषण भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों ने व मेने सशोषित मसविदे पर खूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके सशोषित मसविदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं—

चौथे पैरेग्राफ में सरकार ने जो स्थिति अस्तित्व की है, उसे कांग्रेस की ओर से स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि जहाँ कांग्रेस की सम्मति में समझौते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहाँ जांच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन उसी समय के लिए स्थगित किया गया है, जबतक दिल्ली का समझौता जारी है। लेकिन यदि भारत-सरकार व अन्य प्रान्तीय सरकारें जांच कराने के लिए उद्यत नहीं हैं, तो मेरे

सहकारी व मैं इस धारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि कांग्रेस अबसे उठाये गये अन्य मामलों के बारे में जाच के लिए जोर नहीं देगी, लेकिन यदि कोई शिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच के अभाव में उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के स्थगित रहते हुए भी उसे करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

मैं सरकार को यह आश्वासन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि कांग्रेस का निरन्तर प्रयत्न यह रहेगा कि सीधे बार से बचें और विचार-विनिमय, समझाना-बुझाना आदि उपायों से शिकायत दूर करायें। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहाँ इसलिए आवश्यक हो गया है कि भविष्य में कोई समाहित गलतफहमी या कांग्रेस पर समझौता-उल्लंघन का आरोप न हो सके। वर्तमान बातचीत के सफल होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका उत्तर एकसाथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।”

इमर्सन सा० का उत्तर—२७ अगस्त १९३१

“आज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे स्पष्टीकरण के साथ विज्ञप्ति के मसविदे को स्वीकार कर लिया है। कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल ने इस बात को ध्यान में ले लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जाच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहीं है। लेकिन जहाँ आप यह आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधे बार से बचने और आपसी बातचीत, समझाना-बुझाना आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, वहाँ आप भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल आपके साथ इस आश्वासन में सम्मिलित होते हैं कि सीधे बार के लिए कोई मौका नहीं आयेगा। अज्ञातक सरकार के सामान्य रुख की बात है, मैं वाइसराय के ६ अगस्त को लिखे हुए पत्र का निर्देश करता हूँ। सरकारी विज्ञप्ति, आपका आज की तारीख का पत्र और यह उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी।”

इससे पाठक जान गये होंगे कि बारडोली की जाच का निश्चय हो गया तथा अन्य ऐसी विद्यमान शिकायतों के बारे में, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, दिल्ली-समझौते के जारी रहते हुए भी कांग्रेस ने रक्षणायक प्रहार करने के अपने अधिकार

को बहाल रक्खा। आगे पैदा होनेवाली दिक्कतों का कोई निश्चित हल नहीं सोचा गया, उनकी जांच हो भी सकती थी और नहीं भी। जहाँ जांच न हो और दिक्कत भी दूर न की जाय, वहाँ यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सीधा वार भी कर सकती थी। साथ ही कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेसियों को यह ध्यान में रखना था कि दिल्ली-समझौता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये बिना वे अपनी ओर से समझौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे। अहाँ सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत हो, शान्ति के साथ समझा-बुझाकर उसे दूर करने की हर तरह कोशिश की जाय। अहाँ इस प्रकार की कोशिशों में सफलता न मिले, वहाँ राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनसे सलाह माँगी जाय।

गांधीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिकायतों का उल्लेख किया था और सरकार ने जिसका जवाब दिया था, उन मामलों से सम्बन्ध रखनेवाली सब कांग्रेस-कमिटियों से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह विचार करें और अपना उत्तर महासमिति के पास अहमदाबाद भेजें। समझौते के और जो उल्लंघन हो या और कोई नई शिकायत पेश हो, तो वह भी जल्दी ही राष्ट्रपति के पास भेजी जाय।

लन्दन को रवाना

गांधीजी लन्दन को चल पड़े, लेकिन असाधारण आस्थावादी होते हुए भी उन्हें सफलता की उम्मीद न थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारें, सिविल-सर्विसवाले और अग्रेज व्यापारिक कम्पनियाँ कांग्रेस की उद्देश-पूर्ति में सहायक होंगे। कार्य-समिति ने ११ सितम्बर १९३१ को अहमदाबाद में गांधीजी व राष्ट्रपति के बिमला में सरकार के साथ किये गये नये समझौते में पढ़ने की कार्रवाई का समर्थन किया। कार्य-समिति ने इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया। सभी उद्योग-धन्धों से और विशेषकर कपड़े के कारखानों से कोयले की उन भारतीय खानों का कोयला बर्तने की सिफारिश की गई, जो इस आशय की प्रतिज्ञा करें कि वे जनता की भावनाओं से सहानुभूति रखेंगी, पूँजी व डाइरेक्टरों में ७५ फी सदी भारतीयता होगी, मैनेजिंग एजेंट के कारोबार में विदेशी स्वार्थ न होंगे, अपने दाम और माल की जात का ठीक इत्ताजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता देंगी, उसके अधिकारी राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोधी प्रचार में न लगेगे, विशेष कारणों के बिना केवल भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे, बीमा, बैंकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय

कम्पनियो में ही करेंगी और इसी तरह बाय-व्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जहाजी एजेण्ट तथा ठेकेदार सब भारतीय ही रहते जायगे, यथा सब भारत में बनी चीजें ही व्यापार के लिए खरीदी जायगी, प्रबन्ध-कर्त्ता लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे, खानों के मजदूरों को सन्तोष-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन की दशा भी ठीक की जायगी तथा सानो के परीक्षित वैलेन्सशीट प्रति वर्ष कांग्रेस की भेजे जायेंगे।

अक्तूबर व नवम्बर में भारत और इंग्लैण्ड में होनेवाली सनसनीखेज घटनाओं की ओर बढ़ने से पहले हमें गांधीजी और उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए। गांधीजी के साथ श्री महादेव वेसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल और श्रीमती श्रीराबहन थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। जो सामान अपने साथ ले जाने की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता न थी। सूचना का समय थोड़ा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा था, लेकिन गांधीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया। अबन में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहाँ अरबों व भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एकसाथ अभिनन्दन-मन्त्र तथा ३२५ गिन्नी की थैली दी।

जहाज पर भी गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और बालको के साथ अपना मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते थे। गांधीजी को श्रीमती जगछूल्पाशा और बप्पपाटी के बप्पस नहसपाशा ने बघाई भेजी। पहले का सदेश तो स्वभावतः हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हार्दिक-उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा—

“अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए भिन्न के नाम पर मैं उसी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हूँ। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह यात्रा सफ़ल समाप्त हो और आप प्रसन्नतापूर्वक लौटें। मैं ईश्वर से श्री प्रार्थना करता हूँ कि आप जब वहाँ से लौटकर स्वदेश जाने लगेंगे, तब मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल होगी। ईश्वर आपको चिरायु करे और आपके प्रयत्नों में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे।”

मिस्री शिष्ट-मण्डल को पोर्ट्सईद पर गांधीजी से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, लेकिन कैरो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। बहुत दिक्कत के बाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गांधीजी से मिल सका।

जब गांधीजी मासॅलीज पहुँचे, श्री रोम्या रोला की बहन मैडलीन रोला उनका

उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। रोम्या रोला अस्वस्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित न हो सके थे। मैडलीन रोला के साथ मोशियर प्रिंवे व उनकी सुपत्नी भी थी। मो० प्रिंवे स्विजरलैण्ड के एक अध्यापक हैं, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १९३२-३३ के आन्दोलन में मामूली तथा सदिग्ध अध्यापक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था। कितने ही फ्रांसीसी विद्यार्थियों ने भी गांधीजी का अभिनन्दन किया। गांधीजी लन्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजनिक गृहों तथा गरीबों के मैले घरों के बीच मिस म्यूरियल लिस्टर के यहाँ किंग्सले-हाल में ठहरे। लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए बहुतसे निमन्त्रण मिले और इससे भी ज्यादा निमन्त्रण गावों में उन्हें सप्ताह का अन्तिम भाग शान्ति से बिताने के लिए मिले। एक मित्र ने एक दिन यूस्टन-रोड पर स्थित मित्रसभा-भवन (Friends' Meeting House) में दिये गांधीजी के माषण व किंग्सले-हाल से न्यूयार्क को ब्रॉडकास्ट-द्वारा भेजे गये सदेश की रिपोर्ट 'टाइम्स' में पढ़कर ५० पौण्ड का चेक ही भेज दिया था।

परिषद् में

गांधीजी ने लन्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट-एण्ड को, ब्रिटिश सरकार के आतिथ्य की अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और बनी लोगों की सगति की अपेक्षा बरिद्रों की सगति को, अधिक पसन्द किया था। 'चना गांधी'—हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नगे पैर, कमीज भी नदारद, सिर्फ चादर ओढ़े हुए—ईस्ट-एण्ड के बालकों में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रातः काल आकर उनको घेर लेते थे। गांधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनायें, लकाशायर के मजदूरों के एक समान अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी और उनकी ब्रिटिश-सम्राट् से अपनी मामूली पोशाक में भेंट—ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कांग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी की हैं, जो जीवन को अविभाज्य मानते हैं कि जीवन विभिन्न विभागों में—जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल पड़ी है—नहीं बाटा जा सकता है।

गोलमेज-परिषद् में गांधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा ध्यान गये बिना नहीं रह सकता। फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में दिये गये उनके भाषण को लन्दन में दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय नपे-तुले शब्दों में दिया। कोई बात छूटने न पाई। उनके इसी परिचय को हमने वस्तुतः

इस पुस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होंने कांग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन-पोषणकर्ता मि० ए० ओ० ह्यूम के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। उन्होंने कांग्रेस व सरकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूत भेदों का निर्वहण किया। उन्होंने कराची का प्रस्ताव पढ़कर उसकी व्याख्या की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान-मंत्री का वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सच तथा भारतीय हितों की दृष्टि से सरक्षण, इन तीन किरणों से चित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता पर भी—जो केवल राजनैतिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है—विचार प्रकट किये। उन्होंने 'ब्रिटिश प्रजाजन' की अपनी पहली स्थिति और 'बागी' की आधुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राष्ट्र-समूह (कामनवेल्थ) के आदर्शों में कितना भेद है, यह बताया। उन्होंने किसी दूकान की व्यवस्था बदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दूकान के लेन-देन आदि का हिसाब समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम इंग्लैण्ड के घरेलू सकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि इंग्लैण्ड भारत को शक्ति-बल से नहीं, बल्कि प्रेम-रूपी डोरी से बांधा हुआ रखे। ऐसा भारत इंग्लैण्ड के एक साल के बजट को ही नहीं, कई सालों के बजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा।

अल्पसंख्यक-समिति में आपण देते हुए गांधीजी ने कई खरी बातें पेश की। उन्होंने असदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी मांग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे समाने मुख्य प्रश्न तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरो से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया है? हमें लन्दन में इसलिए निमंत्रित किया गया है कि हमें जाने से पहले यह सतोष हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-युक्त व अमली ढांचा तैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल पार्लमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने सर ह्यूवर्ट कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूवर्ट कार तथा उनके साथियों को इसने जो सतोष हुआ है वह मैं उनमें न छीनूंगा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ किया है वह भुदों की चीर-फाड़ जैसा ही है। सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण दायन अर्थात् स्वराज्य-आणि के लिए नहीं किन्तु नौकरशाही की मत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। "मैं उनकी

सफलता चाहता हूँ”, उन्होंने कहा—“लेकिन कार्यक्रम उसमें विलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि दुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।” अन्त में उन्होंने उस कठिन प्रतिज्ञा के माथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा—“अस्पृश्य कह जाँने-वालों के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय थाव है। उसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कल्म निरंतर रहेगा।

हम नहीं चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक् जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। सिक्ख सबैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। लेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूँगा कि हिन्दू-धर्म ही दूब जाय। जो लोग अछूतों के गजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को नहीं जानते, और हिन्दू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि उस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ तो भी, अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी, मैं इसका विरोध करूँगा।”

गांधीजी प्रधान-मन्त्री को पच बनाने के विरोध नहीं थे, बशर्ते कि उनका निर्णय केवल मुसलमानों और सिक्खों तक सीमित हो। अन्य जातियों के पृथक् प्रतिनिधित्व से वह सहमत न थे। प्रधान-मन्त्री ने इस विषय पर एक सीधा-सावा सवाल किया—“क्या आप, आपमें मे प्रत्येक—कमिटी का प्रत्येक सदस्य—साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने और उसमें अपनेको बाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेगे? मेरा तयार है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।” पाठक यह न भूले होंगे कि प्रधान-मन्त्री का यह निर्णय जब अगस्त १९३२ में प्रकाशित हुआ था, तब यह मवाल भी हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव है, या यह प्रधान-मन्त्री का निर्णय (Award) है? गोलमेज-परिषद् के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पच की हैसियत में निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिए यह निश्चय भी एक प्रस्ताव-मान था और इसे ब्रह्मचान्य नहीं माना जा सकता।

गांधीजी का रुख

१८ नवम्बर १९३१ तक मन्त्रि-मण्डल गोलमेज-परिपद् से ऊब चुका था। इस दिन लॉर्ड सैकी ने प्रधान-मन्त्री का यह इरादा सुनाकर सबको चकित कर दिया कि भाषणों के बाद कमिटी को विसर्जन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय। विरोधी-दल की ओर से बोलते हुए मि० वेन ने इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार परिपद् की हत्या कर रही है। सर सेम्मुअल होर ने कहा कि हमें वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि इन परिस्थितियों में यह मामला यही बन्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सवाल पर बहस हुई और गांधीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पष्ट बातें कही। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मैं इंग्लैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का भी विचार रखता हूँ, क्योंकि मैं तो लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। उन्होंने और के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से जानेवाली सब प्रकार की जिम्मेदारियों को—रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक—आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साथ अपने कंधों पर उठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी विवेक किया कि भारत की सेना वस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हों, मेरे लिए सब विदेशी हैं, क्योंकि मैं उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास आ नहीं सकते, और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कांग्रेसियों को अपना देश-साईं न समझें। "इन सैनिकों और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।" "अंग्रेजी सेना बहादुर अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए, विदेशियों के हमलों को रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रखी गई है।" वस्तुतः केवल अंग्रेजी फौज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने के भी यही हेतु हैं। लेकिन अंग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश्य इन विभिन्न भारतीय सैनिकों में सन्तुलन रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पुरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान-सेनापति और न सिविल या राजपूत ही मेरी आज्ञा मानेंगे, "किन्तु फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से मैं अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूँ। अंग्रेजी फौजों को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहाँ अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत की विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हो।" यह

मैं मेरा स्वप्न है। मैं जानता हूँ कि मैं ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों या जनता से इस स्वप्न को पूर्ण न करा सकूँगा, लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा। भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मोपली नहीं, हजारों थर्मोपोलियों के जन्मदाता कहे जाते हैं।

सच बात तो यह है कि किनी दिन गांधीजी अंग्रेजों और उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा—“हमें अंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का संचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी बरकार है, तो उन सदी-भर काग्रेस बयाबान में भटकती रहेगी, उसे भयकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आपदाओं के तूफान और गलतफहमियों के बवंडर का मुकाबला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौछार भी सहनी पड़ेगी।” मरक्षणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “यद्यपि उनके भारत के हित में होने की बात खिदी गई है, फिर भी मैं लॉर्ड अविन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूँ कि ‘गांधी ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारत और इंग्लैंड दोनों के हितों की रक्षा के लिए हो।’ मैं फिर कहता हूँ कि मैं एक भी ऐसे संरक्षण की कल्पना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो साथ-साथ ब्रिटिश स्वार्थों की भी रक्षा न करे, वरन् कि हम साझेदारी—इच्छित और सर्वथा बराबरी के दर्जे की साझेदारी—की कल्पना करें।” गोलमेज-परिपद् के गुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि आजादी बहस-मुवाहसे एवं सन्धि-वर्चा से मिल सकती है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिपदों या कमिटियों में फँसले की कसौटी बहुमत नहीं रखी जायगी, तब परिपद् के संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर ‘बहुमत की सम्मति’ कैसे लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले ‘एक’ के नाम तक का उल्लेख नहीं करते? वह ‘एक’ कौन है? क्या यहाँ उपस्थित दलों में से कांग्रेस भी एक दल है? मैं पहले भी यह दावा कर चुका हूँ कि कांग्रेस ८५ वीं सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब मैं यह दावा करता हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, जमींदारों और शिक्षित-वर्ग की भी प्रतिनिधि है। अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं,

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मंच सबके लिए—जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव-खयाल किये बिना—एकसा खुला है। इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव है कि कुछ लोग इसके पास न आते हों, लेकिन कांग्रेस उन्नतिशील सस्था है, दूर-दूर गावों में इसका प्रचार हो रहा है। फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसी सस्था है, जिससे किया फैसला कारबादम हो सकता है। क्योंकि यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई सस्था है। कुछ लोग अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस मुकाबले की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। यदि कांग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीले प्याले, गोलियों और भाँड़ों के मार्ग को छोड़कर अहिंसा-पूर्वक मुकाबले की सरकार चला सकती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? यह ठीक है कि कलकत्ता-कारपोरेशन पर एक लाञ्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योंही उस बात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती है, इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया। परन्तु उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता था—स्वयं जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके। १९०८ में जो भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पड़ा। बोरसव व वारडोली में सत्याग्रह सफल हुआ है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इंग्लैण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैसे कुछ आदमी भी हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-सहन करना पड़ता है तब अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते। लॉर्ड अविन ने आडिनेन्सो के द्वारा देश को खूब तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। “समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का ध्येय क्या है। स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें।” दिक्कत तो यही है कि यहाँ कोई एक मत नहीं और न परिपक्व ने शब्दों और भावों की निश्चित व्याख्या कर रखी है। जब शब्द विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है? हा, मैंने किया है। उपनिवेश गिना दिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९२६ की निम्नलिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते—

“उपनिवेश वे स्वतन्त्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हो, उनका दर्जा एक समान हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के आधीन न हो, यद्यपि सम्राट् के प्रति एक-समान राजभक्ति के सूत्र से परस्पर बंधे हो और स्वतन्त्रता-पूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (कामनवेल्थ) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हो।”

मिश्र इनमें नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को चिन्ता न थी। वह तो पूर्ण-स्वतन्त्रता चाहते थे। एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण स्वतन्त्रता का अर्थ क्या है—क्या इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हा, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए साझेदारी। गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हथियारों के छुरों, जहरीले प्यालों, तलवारों, मालों या गोलियों की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने सकल्प की जरूरत है, ‘नहीं’ कहने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह आज ‘नहीं’ कहना सीख रहा है। सरक्षणों का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा कि “मुझे तीन विशेषज्ञों ने बताया है कि जहां देश की ८० फी-सदी आय इस तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई सम्भावना नहीं, वहां किन्हीं उत्तरदायी मंत्रियों के लिए शासन-तन्त्र चलाना असम्भव है। मैं भारत के अनुचित कानूनी हितों की रक्षा नहीं चाहता। अकेले भारत के लिए लाभप्रद और ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक सरक्षण भी मैं नहीं चाहता। जैसे सर सेम्पुबल होर और मैं सरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते, वैसे ही श्री जयकर और मैं भी इस पर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को—प्लेग, मलेरिया, साप, बिच्छू और शेरों की समस्याओं को—पार कर गया है। वह बबरा नहीं जायगा। परमात्मा के नाम पर मुझे ६२ साल के दुवले-मतले आदमी को थोड़ा-सा तो मौका दो। मुझे और जिस सस्था का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान तो बनाओ। यद्यपि आप मुझपर विश्वास करते प्रतीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर अविश्वास करते हैं। परन्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस महान् सस्था से भिन्न न समझिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बुद के समान हूँ। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ। और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास है वह किसी काम का नहीं, क्योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आपको उसे दबाने के लिए अपने आतंकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और सगठित

आतंकवाद के द्वारा बड़ा पर विद्यमान आतंकवाद से लड़ना है; क्योंकि आप वास्तविकता से अथवा ईश्वरी संकेत से अपरिचित हैं। क्या आप उस नक्ति को नहीं देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम आज गेहूँ की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जबतक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञा बढ़ा रहे हैं कि उस वक्त तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठने देंगे?"

बारडोली की जांच

जब १ दिसम्बर को परिषद् विसर्जित हुई, तो गांधीजी ने समापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली बाधियों से टक्कर लें। "मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी भुझे चिन्ता नहीं है। यदि मुझे आपने बिल्कुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हादिक धन्ववाद के अधिकारी तो हैं ही।" इन भावीसूचक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिषद् से विदा हुए। उस समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से एक—घोर-दमन रोक दिया जायगा—पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बंगाल व युक्तप्रान्त की बढ़ती हुई बुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-नीति को जारी रखना सन्धन में प्रदक्षिण सहयोग और भारत को स्वतन्त्रता देने की इच्छा से बिल्कुल मेल नहीं खाता।

जब गांधीजी गोलमेज-परिषद् के लिए रवाना हुए थे, तब यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि बारडोली में लगान-बसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच होगी। मि० गॉर्डन को सूचित मिले के मालगुजारी-कानून के अनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास अपसर नियत किया गया। जांच ५ अक्टूबर १९३१ को शुरू हुई। श्री भूलाभाई देसाई और सरदार बल्लभभाई पटेल उपस्थित थे। दोनों पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानों को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें बहुत नुनसान उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने बहुत से पत्र, तार व लेख सुनाये। उनमें बारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर कलक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ घाना बोला। टिम्बर्बा, राजपुरा, लाम्ना,

माणकपुर, वलोडगढ, अलगोबा और जायगिया पर भी घावा बोला गया। जाच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार व बम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्ञायें प्रचारित की थी, कांग्रेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा, क्योंकि उनसे समझौते में निविष्ट स्टैंडर्ड के प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० गॉर्डन यह बात समझ न सके कि सरकार को कांग्रेस की बात सिद्ध करने के लिए गवाह के रूप में क्यों बुलाया जाय ? उन्होंने कहा कि “यह अनुमान करना चाहिए कि कांग्रेस ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सब मसाला एकत्र कर लिया होगा, जिसके आधार पर उसने अभियोग लगाया, और उस मामले को पेश करना तथा अपने मामले को पुष्ट करना कांग्रेस का फर्ज है। कांग्रेस सरकार के किसी खास हुक्म की ओर निर्देश करना चाहे, तो और बात है।” तब कांग्रेस ने अभिलषित कागजों को भागने के कारण बताये और यह भी बताया कि किस किस के कागज विरोधी-पक्ष के अधिकार में हैं। मि० गॉर्डन ने १२ नवम्बर १९३१ को यह हुक्म दिया कि “विचाराधीन प्रश्न के सिलसिले में अनिश्चित और अयुक्ति-युक्त मागों से सहमत होना असम्भव है।” श्री देसाई ने इस हुक्म पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि इसमें यह मान लिया गया है कि मागों अपनी गवाही की क्षमता को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कागजों को इतनी देर बाद पेश करने की माँग की है। महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय के लिए की गई जाच में विरोधी-पक्ष जिस भावना से सहयोग करना चाहता है, उसका ज्ञान भी मि० गॉर्डन के इस हुक्म से हो जायगा। ‘सार्वजनिक-हित’ करने की उनकी इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी। उस स्पिरिट का खयाल करते हुए मैं जिन परिणामों पर दुःख-पूर्वक पहुँचा हूँ, वे और भी पुष्ट हो गये हैं। बल्लभभाई पटेल ने किसानों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि “जाच का रुख विरोधी और इफ्तरफा दीखता है। लेकिन मैं उस वक्त तक न हटूँगा, जबतक कि हमारे प्रतिनिधि वकील को यह यकीन न हो जाय कि आगे कार्रवाई करना निरूपयोगी है।” बरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजों को पेश करने से इन्कार कर देने का अर्थ सरकारी गवाहों पर से जिरह की एक उपयोगी कैंद को हटा देना था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधिकचरी जाँच निरूपयोगी से भी अधिक बुरी है। इस कारण सरदार बल्लभभाई पटेल ने जाँच से हाथ सौंच लिया और १३ नवम्बर १९३१ को गांधीजी को लन्दन निम्नलिखित तार भेजा —

“जिन ग्यारह गावों की इजाजत दी गई थी, उनमें से सात गावों के ६२ खातेदारों और ७१ गवाहों की गवाहिया ली गई है। जाच के क्षेत्र में नहीं आते, यह

कहकर पांच गावों की जाच करने की इजाजत ही नहीं मिली। सरकार के पहले गवाह मामलतदार की आशिक जिरह में महत्त्वपूर्ण इकवाल के बाद जाच-अफसर ने यह फैसला किया है कि जाच-विपयक प्रश्नों से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कागजों को पेश कराने या उनके देखने का हमें अधिकार नहीं है। जाच का रुख स्पष्टतः विरोधी और इन्तफा है। श्री भूलाभाई की सहमति से आज जाच से अलग हो गया हूँ।”

युक्तप्रान्त में विकट स्थिति

युक्तप्रान्त में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता है कि उसने भविष्य के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर दी। युक्तप्रान्त में किसानों की—अधिकांशतः तात्लुकेदारों व जमींदारों के अधीनस्थ किसानों की—आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही थी। उनकी विपत्ति बढ़ रही थी। लगान-बसूली के तरीकों में नरमी का नाम-निशान न था।

दिल्ली-समझौते के बाद के गरीबों में युक्तप्रान्त के किसानों की हालत निरन्तर खराब होती गई। दाम बहुत गिर जाने पर भी लगान में छूट काफी न होने से बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। बेदखलियों तथा दबाव की ज्यादाती से यह आपत्ति और भी अधिक गंभीर हो गई। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों पर आतक का राज्य छा गया और उनके साथ क्रूरता-भर-क्रूरता होने लगी। जिन जिलों में किसानों के साथ सख्तियां की गईं, उन्हें देखने तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने कई-जाच-कमिटियां बिठाईं। ली गईं गवाहियों से समर्थित इन रिपोर्टों पर विशेष प्रान्तीय क्रयक-जाच कमिटी ने विचार किया। पन्त-कमिटी के नाम से मसहूर, इस विशेष कमिटी की रिपोर्ट सितम्बर १९३१ में प्रकाशित की गई।

इस अरसे में दुखी और त्रस्त किसानों के दुख दूर करने के लिए गांधीजी व युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के प्रयत्न जारी रहे। अगस्त १९३१ में भारत-सरकार व गांधीजी की झिंझला की मुलाकात में युक्तप्रान्त के किसानों के आर्थिक सफट पर विशेष-रूप से विचार हुआ और गांधीजी ने इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के दुख दूर न हो सकें, तो उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार होगा। २७ अगस्त १९३१ को गांधीजी ने भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमर्सन को जो पत्र लिखा और जो झिंझला-समझौते का एक अंशित भाग बन गया था उसमें यह स्पष्ट लिखा था, “यदि कोई शिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच न

होने पर उसे दूर करने के लिए न्यायालय के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा के ग्यक्ति रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र होती।" २७ अगस्त को गांधीजी के निवे मि० उमरमन के जवाब में कांग्रेस की स्थिति-सम्बन्धी उन बयानों का उत्तर दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी युक्तप्रान्तीय विमान-नवट के बारे में भारत-सरकार को कई बार लिखा था।

इस तरह यह स्पष्ट है कि युक्त-प्रान्त में कांग्रेस ने किसान-समस्या का हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसके बस में था, किया। निम्न-नामों के बात फिर बार-बार पत्र लिखे गये, लेकिन बेदखल व अन्य विमानों का कोई दुग दूग न हुआ और बगुनी की साधारण मियाद के बाद भी बहुत समय तक अत्याचार व गरीबी यातना दे-देकर जबरदस्ती बसूलिया जारी रही। पिछड़ी फसल की तडिनाओं और बेदमलियों का कोई सन्तोषजनक हल निकले, उम्मेद पटेल ने फगली साल १३३६ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि नई बगुनी का मसाला भी आ गया हुआ। गरीबों को निरन्तर सपनों के जगमग विमान पटेल की जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, अब उन्हें इस नई आफत का सामना करना पड़ा। प्रान्तीय सरकार ने लगान में जिस छूट की घोषणा की, वह बिल्कुल नाकार्पायी। बेदमल किसानों की बकाया या स्थानीय विपत्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन सबके ऊपर कई जिलों में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि यदि मांगा हुआ पूरा लगान एक मास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो छूट मिली है वह भी वापस ले ली जायगी। घोषणा में आगे यह बताया गया था कि मांगा हुआ पूरा लगान चुका देने के बाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते हैं। इन घोषणाओं ने विपत्ति स्थिति उत्पन्न कर दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए न तो कांग्रेस में सलाह ली गई थी और न किसानों के अन्य प्रतिनिधियों से।

सरकारी घोषणाओं के प्रकाशित होने के बाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला-कांग्रेस-कमिटी ने इस प्रश्न को उठाया और बताया कि किसानों के लिए मांगी गई रकम को चुकाना सम्भव नहीं है। और भी अधिकांश जिले इसी या इससे भी बुरी हालत में थे। प्रान्तीय-सरकार से फिर मिला गया और उसे बताया गया कि छूट, बेदमली, बकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। युक्तप्रान्त के अधिकांश जिलों के लिए उदाहरण-रूप इलाहाबाद-जिले के मामले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय

अधिकारियों और बन्दोबस्त-कमिशनर तथा दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन की योजना की गई। वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत्वपूर्ण अंगों पर बहुमत करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहुमत कर सकती है, जो उसने (सरकार ने) निर्धारित किये हैं। इस तरह समस्या के मूल प्रश्न पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

पिछले महीनों ने युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकने में समर्थ हों। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने सरकार से सन्धि-वर्चा के लिए सब अधिकार देकर एक विशेष समिति भी नियुक्त कर दी। पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई।

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह किसी भी किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते कि उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलती हो। जब बसूली का समय आया, किसान बार-बार पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए? युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिससे समझौते तक पहुँचने की वास्तविकता ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानों के लगातार सलाह मागने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हुई रकम दे दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन किसानों को तबाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के बाद किसानों को यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-वर्चा के समय तक के लिए मुत्तवी कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-वर्चा के लिए इच्छुक और उत्तम है और ज्योंही किसानों की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस ले लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्धि-वर्चा के समय तक बसूली स्थगित कर दे, तो वह (कांग्रेस) भी लगान मुत्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले कांग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने कांग्रेस का परामर्श नहीं माना। अब युक्त-प्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुत्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये। स्थिति यहाँतक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस बराबर यह कहती रही कि वह सन्धि-वर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता ढूँढने और ज्योंही

किसानों को काफी छूट मिलती मजर आवे या बसूली स्थगित कर दी जाय, लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार का दृष्टिकोण यह था कि वह केवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है, जबकि यह सलाह, जिसे वह लगानबन्दी-आन्दोलन कहती थी, वापस ले ली जाय। लेकिन सरकार ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अस्तित्व की। उसने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारियाँ इतनी तबाक-फडाक हुईं कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्त्ता जेलों में पहुँच गये। इन गिरफ्तारियों का अन्त गांधीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहुँचने के पाँच दिन पहले सर्वे श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टण्डन और शेरबानी साहब की गिरफ्तारियों के साथ हुआ। वरअसल ५० जवाहरलाल और श्री शेरबानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था। इस पाबन्दी के बाद जल्दी ही गांधीजी के बम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में जवाहरलाल जी शामिल हुए। सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना मुमकिन न था। क्योंकि जगह-जगह जोर की बुराहट होती थी। और बढ़ा जाना पड़ता था और अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में खुद भी उपस्थित रहने की आवश्यकता थी। अतः जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरह श्री शेरबानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनों को सजा दे दी गई।

बंगाल में अत्याचार

सथर्व का तीसरा केन्द्र दगाल था। अस्थायी सधि के समय बहा अत्याचारों के अनेक दृश्य देखने में आये। शायद इनका उद्देश्य था चटगाव जिले में हुए उत्पातों का बदला लेना। चटगाव शहर और जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक गैर-सरकारी जांच-कमिटी नियुक्त की गई। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े हथौड़े और लोहे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस आये और उन्होंने मशीनों को तोड़ दिया तथा प्रेस-मैनजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा। दिल्ली में २७, २८ और २९ नवम्बर को कार्य-समिति ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और "आत्मकवाद की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ निरपराध जनता की बेइज्जती करने व उसे भीषण क्षति पहुँचाने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की तीव्र निन्दा की। समिति ने इसपर सतोष प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिए ही तजवीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक

रग देने के डरादे से थे, उनके जान-बूझ कर किये गये प्रयत्नों के धावबूझ वह कोई साम्प्रदायिक दगा नहीं हुआ। समिति की सम्मति में बंगाल-सरकार को कम-से-कम इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें मुआवजा दे और इन दुर्घटनाओं के लिए जिनकी जिम्मेवारी साबित हो उन्हें दण्ड दे।”

जेलो से बाहर लोगों के साथ जब इस प्रकार आयरलैण्ड-के-से दमन के तौर-तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलो और नजरबन्दों के कैम्पो में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरबन्द-कैम्प में जो दुस्मान नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप २ नजरबन्द मर गये और २० घायल हो गये। कार्य-समिति ने “सरकार-द्वारा नियुक्त जाच-कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन निहत्थों को राष्ट्र के तीव्र विरोध करने पर भी नजरबन्द कर दिया है, उनके जीवन और हित-साधना की रक्षा की वह जिम्मेवार है। इस प्राथमिक कर्तव्य के प्रति बोर उपेक्षा के अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए।”

इसी बैठक में युक्तप्रान्त की स्थिति पर भी विचार हुआ। इलाहाबाद कांग्रेस-कमिटी ने युक्तप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध और खासकर उस स्थिति में लगान और मालगुजारी की अत्याचारपूर्ण बसूली के विरुद्ध, जबकि किसान तीव्र आर्थिक संकट के कारण देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति देने ने पूर्व हत पर युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी विचार करले। समिति ने इलाहाबाद-कांग्रेस-कमिटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी से पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मति में २७ अगस्त के शिमला-समझौते के अनुसार किसानों को रक्षणात्मक सत्याग्रह करने का अधिकार हो, तो समिति ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें।

प्रसंगवश हम यहाँ यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक पर अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्ली-समझौते को खयाल में रखते हुए यह भारत-सरकार का विश्वासघात है। मुद्रा और विनियम की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को मोने की यात्रा कम रह जाने के कारण बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी और इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान छोड़ दिया था। प्रश्न यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टर्लिंग की दम के साथ बाधा जाय, या

सोने के बाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्धारण करने दें ? पहला रास्ता, जिसे भारत-सरकार ने स्वीकार किया, समिति की सम्मति में केवल इंग्लैण्ड के स्वार्थों को पूर्ण करता था। क्योंकि इसका मतलब था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोक्ष रूप में तरजीह देना और भारत का सोना बाहर भेजने को उत्तेजन देना।

सीमाप्रान्त में आग

भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी। भारत के इतिहास और इन पुष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। वे सीमान्त के उन बहादुर लोगों में से हैं, जो अनुशासन व सगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। अगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था। अस्थायी संधि के समय से ही गांधीजी सीमाप्रान्त जाने और उस सगठन का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्ति करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉर्ड अर्बिन से उन्होंने इजाजत मागी, लेकिन उन्होंने कहा—अभी नहीं। सारे साल-भर उन्हें यही जवाब मिलता रहा और इसलिए उन्होंने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गांधी को भेजा। उन्होंने एक आवश्यककारक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा खुदाई-खिदमतगारों को कांग्रेस-सगठन का अंग बनाकर एक बहुत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया। इसके बाद यह सगठन सब प्रकार के सन्देशों से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऊपर से अर्ध-सैनिक देखनेवाले सगठन को—चाहे वह कांग्रेस के स्वयंसेवकों का सगठन ही क्यों न हो—रहने देना नहीं चाहती थी। बण्ड और बिगुल, सिर से पैर तक लाल पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास—जो अपने चरित्र, मनुष्यता, बलिदान व सेवा से 'सीमान्त-गांधी' का पद पा चुका था और बहुत जल्दी सब आँखों का एक लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा था—ये सब बातें उस सगठन को अर्ध-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी। कौन जानता है कि उसके बिनम्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'बफर-स्टेट' (लड़ने वाले दो राज्यों के बीच का तटस्थ-राज्य) बनाने, अमीर से संधि करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा भारत पर आक्रमण करने की तजवीज न छिपी हो ? लाल पोशाक में एक लाख सेना—सब पठान, उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार को एक वहीना भी मिल गया कि खान अब्दुल गफ्फार खां सरकार से सहयोग नहीं करते,

क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्नर के दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। वह पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं। वस, निरपराध खानसाहब और उनके मन्त्र तथा उन्हीं की तरह निरपराध साईं डॉ० खानसाहब गांधीजी के भारत पहुँचने से कुछ ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये।

इस तरह जब गांधीजी भारत पहुँचे, ये सब वस्त्रोत्पन्न हो चुके थे। गुजरात में ज्यादतियों की जाच, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वचन पर ही वह लन्दन जाने को तैयार हुए थे, १३ नवम्बर को अधूरी ही खतम हो चुकी थी। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवाले बल्लभभाई पटेल नहीं थे जो उकताकर जाच से अलग हो गये थे, लेकिन गमीर और धैर्यशील भूलाभाई देसाई थे जो बहुत विचार के बाद जाच को निरर्थक समझकर अलग हुए थे। युक्तप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसानों को जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिल्कुल नाकाफी और असन्तोषप्रद थी और सरकार भी तबतक लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे मुह में तिनका व रख लें और लगान स्थगित करने की आज्ञा वापस न ले लें। इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति में ५० जवाहरलाल और शेरवानी साहब गांधीजी के लौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से जिस जहाज पर गांधीजी आ रहे थे उसपर भी भेज दी गई, तथापि जनतक यह खबर नहीं पहुँचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अब्दुलगफ्फारखा, उनके भाई और पुत्र शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिये गये। बंगाल की स्थिति किसी एक या इनकी-दुकी घटना से बनी हुई नहीं थी, हालांकि चटगाव और हिजली की घटनायें उसका कारण थी। वह असें से एक बहता हुआ घाव बन गई है और पता नहीं कबतक यह घाव इसी तरह गहरा बना और बहता रहेगा।

गांधीजी जब २५ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी।

: १ :

वयावान की ओर

गांधीजी बम्बई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जनता के उस आता का स्वागत करने के लिए बम्बई में एकत्र हुए थे। नुगी-दस्तर के एक भवन में विधिवत् स्वागत किया गया। फिर गए जुलूम निषन्ध—वह जुलूम जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसें। पर राजनैतिक नेता और महात्माकाशी राजपुरुषों का तो गुण-ग्राहक जनता ऐसे ही जुलूमों-द्वारा स्वागत किया करती है। गांधीजी का स्वागत वैश्यासियों ने किस उन्माद में किया होगा, पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं। वे किसी ऐसे साहसी का स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। न वे किसी ऐसे राजपुरुष का आदर करने जा रहे थे जो किसी कजूस बादशाह के हाथों से जनता के लिए कोई रिजायतें छीनने गया हो। लडाई के मैदान में बतार्ई बहादुरी के लिए किसी बीर योद्धा का सम्मान करने भी वे जमा नहीं हुए थे। बल्कि वे तो झकट्टे हुए थे मन्त और सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो ससार को छोट देने पर भी ममारी की भाँति ही मसार में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को तिलाजलि दे दी थी। उस दिन बम्बई के तमाम पुरुष सबको पर झकट्टे हो रहे थे और स्त्रिया आत्मान से धाँत करनेवाली बम्बई की ऊँची अट्टालिकाओं पर। हिन्दुस्तान में आते ही गांधीजी ने सबसे पहले बम्बई की जनता को अपना भाषण सुनाया। आजाद मैदान में मचमुच उस दिन जबरदस्त मीठ झकट्टो हुई थी, और गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि मैं शान्ति के लिए अपने वस-भर कोशिश कल्ला और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रखूँगा। इस भाषण में भी उन्होंने अपनी वह भयंकर प्रतिज्ञा दोहराई और कहा कि “हिन्दू-जाति से अछूतों को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाश्त नहीं कल्ला, बल्कि मीका पढने पर उसके विरोध में मैं अपनी जान तक लडा दूँगा।” सब तो यह है कि न तो इस मीके

पर और न अल्पसंख्यक जातियों की कमिटी की बैठक में ही किसीको यह खयाल आया कि गांधीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास की घोषणा कर देंगे। या तो इस बात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढ़नेवालों के दिल पर इसका असर एक सामान्य भापालकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा। पर हरेक बादमी जानता है कि गांधीजी कभी अत्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और न कभी कोई बात गैर-जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। उनकी 'हां' केवल 'हां' है और 'ना' निरी 'ना'। उनकी बात ज्यों-की-त्यों होती है। उसके दो मानी नहीं निकाले जा सकते।

तीन दिन तक गांधीजी जुदा-जुदा प्रान्तों में आये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी दुःख-कथायें सुनते रहे। वह क्या कर सकते थे? सुभाष बाबू बंगाल में अपने चार साथियों को लेकर आये थे। हालांकि उन चारों ने गांधीजी से अलग-अलग बातचीत की, पर चारों ने बंगाल-आडिनेन्सों के कारण किये गये दमन का वर्णन वही सुनाया। युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आडिनेन्स जारी कर दिये गये थे। भारजी सुलह के दिनों में राज का गाढा इन आडिनेन्सों से ही हाका जा रहा था। गांधीजी मजाक में कहा करते थे कि यह तो लॉर्ड विलिंगडन का दिया नये साल का तोहफा है। पर वह एक सत्याग्रही की भाति जाम्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये बगैर ही देश को नई मुसौबतों में ढालनेवाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट-मण्डलों से मिलने में ही बीतता था, जो सरकारी अफसरों-द्वारा हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें सुनाते थे। देश में भयकर मन्दी और बोर सकट था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक मुद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिजायत नहीं बी गई। आन्ध्र में लगान बढ़ाया जानेवाला था, और मदरास के गवर्नर ने तो यहां तक बमकी दे रखी थी कि अगर लोग लगान रोकने की बात करेंगे तो आडिनेन्स जारी कर दिये जायेंगे। इस तरह की दुःख-गाथायें गांधीजी को सुनाई जा रही थी। उन्हें भी अपने दुखड़ों की कहानी लोगों को सुनानी थी, जो उनपर लन्दन में बीते थे। वह गोलमेज-परिपद् में जाना ही नहीं चाहते थे। जो बातें इस परिपद् में होने वाली थी उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नजर आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए। समझौते का अग होने पर भी वाद में उन्हें परिपद् में जाने से इन्कार करने का मौका मिल गया था। पर मजदूर-सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना कर ही दिया जाय।

सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी

चीज की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम-चल के नेताओं की मनोदशा से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा। मुसलमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी नावाकफ नहीं थे। पर गोलमेज-परिपद में राष्ट्र-शरीर की जो चीरा-फाटी हुई और जिस तरह टुकड़े-टुकड़े किये गये उसके लिए वह हर्गिज तैयार न थे। उन्होंने इस बात का भी निश्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध राष्ट्र-धर्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इसी तरह पहले की भाँति खिलवाड़ करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मुसलमान और सिक्ख मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान बने जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की धूँ न हो और जो विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर लेंगे। इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त को बड़ा क्लेश हो रहा था, पर उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने बड़ी धैर्य और स्थिर-चित्तता से सामना किया, जैसा कि वह हमेशा किया करते हैं। अपने ऊपर तथा अपने देश-माइनों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश ने उनपर विश्वास किया और उन्होंने उसको बराबर निभाया। अब आज उन्हें अपने सामने एक जबरदस्त खड़ी नजर आ रही थी। सवाल यह था कि इसपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदमियों से पाटकर पार करना होगा? जब वह अपने काम में शिबे, उनके हृदय में ये विचार उमड़ रहे थे—यह मनोमन्थन चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चीदह सवस्यो वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी। कार्य-समिति के आदेशानुसार उन्होंने लॉर्ड विलिंगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी आया। जवाब लम्बा और तफसीलवार था। उसमें बमकी भी थी। गांधीजी ने फिर तार दिया। मगर कोई नतीजा न निकला।

वाइसराय से तार-व्यवहार

वाइसराय से गांधीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है—

(१) वाइसराय को गांधीजी का तार (२६ दिसम्बर १९३१)

“कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त

में आडिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोलिया चलाई गई हैं। मेरे अनमोल साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। और सबसे बड़कर बंगाल का आडिनेन्स मेरी राह देख रहा है। मैं इसके लिए तैयार न था। मेरी समझ में नहीं आता कि आया मैं इनसे यह समझू कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्मा हो चुका, या आप अब भी मुझसे यह सम्मिद करते हैं कि मैं आपसे मिलूँ और इस परिस्थिति में मैं कांग्रेस को क्या सलाह दूँ इस विषय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ? जवाब तार से देने की कृपा करेंगे।”

(९) गांधीजी के नाम बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार (३१ दिसम्बर १९३१)

“बाइसराय महोदय चाहते हैं कि मैं आपको आपके तार के लिए धन्यवाद दूँ, जिसमें आपने बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त के आडिनेन्सों का जिक्र किया है। बंगाल की बात तो यह है कि अपने अफसरों और नागरिकों की कायरता-पूर्ण हत्याओं रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया और है कि वह तमाम उपाय काम में लावे।

बाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी सरकार चाहते हैं कि उनका देश के तामाम राजनैतिक हलों तथा जनता के सभी हिस्सों से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे। खास तौर पर शासन-सम्बन्धी सुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वह बिना किसी देरी के जारी करना चाहते हैं, वह सबका सहयोग चाहते हैं। पर यह सहयोग पारस्परिक हो। युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में कांग्रेस जिस तरह की हलचलें चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युक्त सहयोग के साथ मेल नहीं देख रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है।

युक्तप्रान्त के बारे में तो आप जरूर जानते ही हैं कि जहाँ एक ओर प्रांतीय सरकार वर्तमान परिस्थिति में हर तरह की रिवायत देने के बारे में उपायों की योजना कर रही थी, तथा ऊपर प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी ने लगानबन्दी का आन्दोलन शुरू करने की आज्ञा जारी कर दी। उस प्रान्त में आजकल यह आन्दोलन जोरो पर है। कांग्रेस के इस कार्य से, अगर यह बेरोक इसी तरह जारी रहा तो, अरुण ही देश में भारी पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्वेष तथा जातीय-विद्वेष फैल जायगा, इसीलिए सरकार को आवश्यक उपायों का अवलम्बन करने पर मजबूर होना पड़ा।

पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त में अब्दुल्लाफ्फारखा तथा उनकी मातहत सत्ताओं लगातार ऐसी हलचलों में भाग लेते रहे हैं जो सरकार के विरुद्ध हैं और जिनमें

जातीय-विद्वेष बढ़ता है। अबतक वहा के चीफ-कमिश्नर ने उनके सहयोग के लिए जितनी बार भी कोशिश की उसका उन्होंने कोई खयाल नहीं किया और प्रधानमंत्री की घोषणा को अस्वीकार कर वह यह एलान कर रहे हैं कि वह तो पूरी आजादी चाहने-वालों में है। अब्दुलगफ्फारखा ने ऐसे बहुत-से आपण दिये हैं जिनसे जनता को श्रान्ति के लिए उभारने के सिवा और कोई मानी नहीं निकल सकते। उनके अनुयायियों ने भी सीमान्त जातियों में उपद्रव खड़े करने की कोशिशें की हैं। उस प्रान्त के चीफ-कमिश्नर ने बाइसराय की सरकार की इजाजत से हब दज की सहन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस बात की कोशिश की है कि जैसी कि सम्राट की सरकार की मन्शा है, सीमान्त-प्रदेश में विना देरी के सुधार जारी करें और उसमें अब्दुलगफ्फारखा की सहायता प्राप्त करें। सरकार ने तबतक कोई खास कार्रवाई नहीं की जबतक कि अब्दुलगफ्फारखा तथा उनके साथियों की हलचलें और खास तौर पर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमान्त जातियों के प्रदेश में शान्ति को घातरे में नहीं डाल दिया। अब ठहरे रहना असम्भव था। बाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अब्दुलगफ्फारखा के सुपुर्द कर दिया गया है। उनके द्वारा सगठित किये गये स्वयंसेवक-दलों को भी महासमिति ने कांग्रेस के अधीन मान लिया है। बाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह साफ कह दू कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर है और इसलिए वह उन आदमियों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कामों और हलचलों के लिए जिम्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिषद् के काम से बाहर गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिषद् में जो रुख अस्तित्वार किया था उसे देखते हुए बाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेवार हो या इधर सीमा-प्रान्त में और युक्त-प्रान्त में कांग्रेस ने जो जो आन्दोलन जारी कर रखे हैं उन्हें आप पसन्द भी करते हो। अगर यह ठीक हो तब तो वह आप से कह सकते हैं, और गोलमेज-परिषद् में जिस सहयोग की भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में बाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह साफ कर देना चाहते हैं। सम्राट की सरकार की पूरी इजाजत से जो आइनेन्स वगाल, युक्तप्रान्त और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार की बहस करने के लिए वह

तैयार नहीं है। जिस उद्देश से, अर्थात् कानून और व्यवस्था की रक्षा जो सुशासन के लिए जरूरी चीजें हैं, ये आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वह जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिए। आपका जवाब मिल जाने पर वाइसराय महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं।”

(३) वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम गांधीजी का तार (१ जनवरी १९३२)

‘मेरे २६ दिसम्बर के तार के जवाब में, वाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। उसे पढ़कर दुःख हुआ। मैंने अत्यन्त मित्र-भाव से जो प्रस्ताव रक्ता था, उसे जिस तरह वाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मैंने एक ऐसे आदमी की हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नों पर प्रकाश की जरूरत थी। मैं कुछ अत्यन्त गम्भीर और असाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था, सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सद्भाव का स्वागत करने के बजाय, वाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि मैं अपने अनमोल साथियों के कार्यों का पहले ही से खण्डन करूँ। फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर मैं मिलना चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए इतना भारी महत्त्व रखनेवाली इन बातों पर उनसे बातचीत तक नहीं कर सकता।

मेरा तो खयाल है कि इन आर्डिनेन्सों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि अगर दृढ़ता के साथ प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान-सम्बन्धी बात न-कूछ-सी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी स्वामिमानी भारतीय एक सदेहास्पद विधान-सम्बन्धी सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा। क्योंकि तब तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा।

अब सीमा-प्रान्त की बात लीजिए। आपके तार में जो बातें हैं उनको देखते हुए यह साफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अनिश्चित कानून जारी करने, जिसने कि लोगों की जानी-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विद्वान्मयान् नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निहत्थे लोगों पर गोलीया चलाने का कोई सबल कारण नहीं था। अगर खानसाहब गन्धुग-गफ्फारखां ने पूरी आजादी का दावा किया तो वह स्वाभाविक ही था। स्वयं कांग्रेस ने

सन् १९२६ में, लाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई। मैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके अलावा बाइसराय महोदय को मैं यह भी याद दिला दू कि कांग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी थी उसमें भी यह दावा था और सरकार इस बात को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिषद् में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निमन्त्रित किया गया था। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि महज एक दरबार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौन अपराध हो गया, जिससे वह एकाएक गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये? अगर खानसाहब जातीय-विद्वेष की आग को बढा रहे थे, तो सचमुच दुःखदाई बात है। पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पडते हैं। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय-विद्वेष की आग भडकाई, तो उस हालत में उनकी खूली जांच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता।

युक्तप्रान्त के बारे में बाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने बहा पर लगान-बन्दी की आज्ञा ही जारी नहीं की, बल्कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान बसूल करने का समय आ गया और लगान तलब किया जाने लगा, इसलिए कांग्रेसवालों को लोगों से यह कहना पडा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तबतक वे अपने लगानों को रोक रखें। श्री शेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी अफसर लगान-बसूली मुत्तवी रखें, तो वह भी जनता को दी गई सलाह वापस लेने को तैयार हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह ऐसी बात नहीं थी जिसको यो ही उडा दिया जाय, जैसा कि बाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है। युक्त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत असें से चली आ रही है और उसमें ऐसे लाखों किसानों के हित का सवाल है जिनकी माली हालत बहुत ही खराब है। कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस-जैसी सस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव है और जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है। और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर ढाले गये असहनीय आर्थिक बोझ को दूर करने के लिए और तमाम उपायों को आजमा लिया है, और उन्हें निष्फल पाया हो, तो उसका यह सनातन और स्वाभाविक हक है कि वह अपने लगान को मौका पडने पर

रोक लें। आपके तार में जो यह बात है कि कांग्रेस किसी भी रूप में जरा भी अव्यवस्था फैलाना चाहती है, उसका मैं प्रतिवाद करता हूँ।

बंगाल के विषय में, जहाँ तक हत्याओं की निन्दा से सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ है। और ऐसे जुर्मों को बिल्कुल रोक देने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन जरूरी समझा जाय, कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग देना पसन्द करेगी। परन्तु जहाँ कांग्रेस आतंकवाद की सम्पूर्ण निन्दा करती है, वहाँ किसी भी हालत में सरकारी आतंकवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि बंगाल-आर्डिनेन्स और उसके सिलसिले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है। बल्कि कांग्रेस तो अपनी अहिंसा की भयावा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतंकवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी। आपके तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो। मैं इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ। पर तार में लिखी दूसरी बातें तो मुझे इसी नतीजे पर बरबस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना नहीं चाहते। आपने जो इन बातों पर बातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका मैं दूसरा अर्थ लगा ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताने की कोशिश की है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहलू तो हैं ही। लोकपक्ष, जैसा मैं समझता हूँ, मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहले मैं दूसरे अर्थात् सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके बाद कांग्रेस को अपनी सलाह देने की इच्छा थी।

तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाब यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हो या मुक्त-प्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेवारी से मैं अपने-आपको बरी नहीं समझता। पर मैं यह कबूल करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यों की और हलचलों की तफसीलवार जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भारत में नहीं था। और चूँकि कांग्रेस की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निष्पक्ष भाव से और बहुत सद्भाव के साथ वाइसराय महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा। मैं वाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सद्भाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो मैं उनसे कहूँगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारी बातचीत पर, उसके विषय-क्षेत्र पर, और कोई बातें लगाये मुझसे मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से मैं यह वचन दे सकता हूँ कि वह जो भी बातें मेरे सामने रखेंगे उनपर मैं निष्पक्ष होकर विचार करूँगा। अगर किसी

हिचकिचाहट के और चुनौती के साथ मैं उन-उन प्रान्तों में जाऊँगा और अधिकारियों की महायत्ना ने प्रश्न के दोनों पहलुओं का अध्ययन करेगा, और अगर पूरे अध्ययन के बाद मैं इन नतीजों पर पहुँचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य-समिति तथा मैं भी गुमराह हो गये हैं, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस बात को स्वीकार करने में और मदनसार काप्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी। सरकार के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और चुनौती के साथ ही बाइसराय महोदय के मामले में अपनी मर्यादा भी रख दूँ। जहाँमा मेरा पहला आचार-धर्म है। मेरा विश्वास है कि मजिद-जयन्ता जनता का केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है—और सासकर उन हालात में जब अपने पास में उसका कोई हाथ न हो—बल्कि वह हत्या और साम्राज्य वयावन का गफ़्तारता-पूर्वक स्थान भी ले सकती है। इसलिए मैं कभी आचार-धर्म को अलग नहीं रख सकता। उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जिनका अभी तक कोई राखन नहीं हुआ है, बल्कि भारत-सरकार की हलचलें जिनका समयन करती हैं और धायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अवज्ञा-सम्पन्नी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसकी तकल में मेजता हूँ। अगर बाइसराय महोदय समझे कि मुझे मिलने में कुछ उपयोगिता है तो हमारी बातचीत गनम होने तक, इन आवा से कि आगे चलकर, यह रव कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव मुन्तयी रहेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे बीच का यह तार-ब्यवहार सचमुच इतना महत्वपूर्ण है जिनके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसलिए मैं अपना तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हूँ।”

कार्य-समिति का प्रस्ताव

“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बगाल, युक्नप्रान्त तथा सीमाप्रान्त में जारी किये गये असाधारण आडिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों-द्वारा जो खान अब्दुलगफ़ारखा, औरवानी साहब, प० जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की गिरफ्तारियों, और सीमा-प्रान्त में जो निर्दोष लोगों पर गोळियाँ चलाई गईं और जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गये तथा धायल हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने

महात्मा गांधी के तार के जवाब में बाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया।

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रान्तों में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनायें तथा बाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के लिए विलकुल असम्भव बना रहे हैं जबतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और बाइसराय का तार स्पष्ट-रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहाँ की हुकूमत सौंपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा वह उल्टे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहाँ कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, वहाँ दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती।

बंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसीसे पीछे नहीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आर्डिनेन्सों और कानूनों से प्रकट है। हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हानि-कारक हैं, जब कि देश कांग्रेस के जरिये, जोकि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि सत्ता है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम लेने को वचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी-सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बंगाल-आर्डिनेन्स जैसे अतिरिक्त कानून जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय। इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक कारणों का ही, जो कि प्रकट हैं, इलाज करना।

यदि बंगाल-आर्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त के आर्डिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं।

कार्य-समिति की राय है कि युक्त-प्रान्त में किसानों को छूट दिलाने के लिए कांग्रेस-द्वारा अवलम्बित उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं। कार्य-समिति का यह निश्चित मत है कि गम्भीर आर्थिक संकटों से पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त-प्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि ये युक्त-प्रान्त में असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विवाद अधिकार है कि वे लगान देना बन्द कर दें। महात्मा गांधी से बातचीत

करने और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए बम्बई आते हुए युक्त-प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति श्री धेरवानी तथा महामा के प्रधान-मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आर्डिनेन्स-द्वारा कल्पित सीमा से भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि इन मज्जनों के बम्बई में युक्तप्रान्त के करबन्दी के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रश्न था ही नहीं।

सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वयं सरकार की बताई बातों से भी न तो आर्डिनेन्स जारी करने और न खान अब्दुलगफ्फारखा और उनके माथियों को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता है। कार्य-समिति इस प्रान्त में निरपराध और निःशस्त्र लोगों पर की गई गोला-बारी को निष्ठुर और अमानुष समझती है और वहाँ की जनता को उसके साहस और सहन-शक्ति के लिए, बधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि सीमाप्रान्त की जनता मारी-से-मारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनी अहिंसा-वृत्ति को कायम रख सकेगी तो उसके रक्त और उसके कष्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुँचावेंगे।

कार्य-समिति भारत-सरकार से माग करती है कि जिन बातों के कारण ये आर्डिनेन्स पास करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थापन को एक ओर रख देने की ओर इन आर्डिनेन्सों के अन्तर्गत और बाहर जो कार्रबाइयां हुईं, उनके आचरण के सम्बन्ध में एक झुली और निष्पक्ष जाच करावे। यदि उचित जाच-समिति नियत की जाय, और कार्यसमिति को गवाह पेश करने की सब सुविधायें दी जायें, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी।

गोलमेज-परिपद् में प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उसपर पार्लमेण्ट की कामन-सभा तथा लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोषजनक और अपूर्ण मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले सुरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को कांग्रेस सन्तोष-जनक नहीं मान सकती।

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परिपद् में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मानने और उसके किसी जाति, धर्म अथवा रंग-भेद बिना समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार तैयार

न थी। साथ ही यह समिति इस बात को दुःख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त परिषद् में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी।

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आवाहन करती है कि कांग्रेस वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अविकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविराम प्रयत्न करे, जिससे कि सुदृढ़ राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अगम्य विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके।

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनर्विचार करें, आर्डिनेन्सो तथा हाल के कृत्यों के सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, और भावी विचारों और परामर्श में कांग्रेस के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आज्ञा दी रहे, और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है।

पूर्वोक्त पैरा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते के रद्द किये जाने की सूचना समझेगी। सन्तोषजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आवाहन करती है—

(१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसील अथवा गांव तब तक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि वहाँ के लोग सभाम का अहिंसक रूप, उसके सब फलितार्थों-सहित, न समझ लें और कष्ट-सहन तथा जान-माल तक गवाने के लिए तैयार न हों।

(२) यह समझकर कि यह सभाम जाततायी से बदला लेने अथवा उसपर आघात करने के लिए नहीं बरन् अपने कष्ट-सहन और आत्मशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है, अयकर-से-अयकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, बचन और कर्म से अहिंसा का पालन अवश्य होना चाहिए।

(३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा-भृति के यह सर्वथा विरुद्ध है।

(४) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अहिंसात्मक सभाम में अधिक सहायता की अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें वेतन पर रखे गये स्वयंसेवक

न होने चाहिए, किन्तु केवल उनके निर्वाह-मात्र के और जहा सम्भव ही वहा सग्राम में जेल जानेवाले अथवा मारे गये गरीब स्त्री-पुरुषों के आश्रितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है।

(५) सब स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का बहिष्कार आवश्यक है।

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिलो तक का कपडा न पहनकर, हाथ की कती-बुनी सादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

(७) शराब और विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरो से, किन्तु सर्वत्र अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए।

(८) गैर-कानूनी नमक बनाने और बटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए।

(९) यदि जुलूस और प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही लोग शरीक हों, जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले बिना लाठी-प्रहार और गोलीया सहन कर सकें।

(१०) अहिंसात्मक सग्राम में भी उत्पीडक-द्वारा तैयार माल का बहिष्कार करना सर्वथा विहित है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कमी बर्न नहीं है कि वे आततायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढावें अथवा कायम रखें। इसलिए ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पनियों का बहिष्कार पुन आरम्भ किया जाय और जोरो से चलाया जाय।

(११) जहा-जहा सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कानूनों और जनता को हानि पहुँचानेवाली आज्ञाओं का सविनय भग किया जाय।

(१२) आडिनेन्सों के अन्तर्गत जारी हुई प्रत्येक अनुचित आज्ञाओं का सविनय भग किया।”

(४) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, बाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेटरी ने नीचे लिखा तार भेजा—

“बाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के लिए कहा है, जिसपर उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हें इस बात का अत्यन्त खेद है कि आपकी सलाह से कांग्रेस-कार्य-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसमें यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव में वताई गई शर्तें पूरी न की गईं तो सविनय अवज्ञा के पुन. पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की बात है।

प्रधान-मंत्री के वक्तव्य के अनुसार जैव शासन-सुधार की नीति को शीघ्र आरम्भ करने की सम्राट्-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक समझते हैं।

अपने उत्तरदायित्व का सम्यक् रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक सस्था की गैर-कानूनी कार्यवाही की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार में वर्णित इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि, दिल्ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए।

बाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस बात पर भ्रुंक्षल से ही विश्वास कर सकते हैं, कि आप अथवा कार्य-समिति समझती है कि सन्धि-अवस्था के पुनरावर्तन की धमकी पर बाइसराय महोदय किसी काम की आशा से आपको मुलाकात के लिए बुला सकते हैं।

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के लिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और आपको दवाने के लिए सरकार सब आवश्यक अस्त्रों का अवलम्बन करेगी।"

(५) बाइसराय के उक्त तौर के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १९३२ को निम्न तार भेजा—

"आपके तार के लिए धन्यवाद। मैं आपके और आपकी सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-अवधान को धमकी समझ लेना अवश्य ही मूल है। क्या मैं सरकार को याद दिलाऊँ कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-वर्षा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस समय समझौता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया गया था वरन् स्पष्ट किया गया था? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, बिमला में इस बात पर दुबारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि मैंने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेस को सत्याग्रह छूट्टी करना पड़े, तो भी सरकार ने वातचीत बन्द न की थी। सरकार ने उस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-अंग के लिए सजा भी लगी रहती है, इस बात से यही सिद्ध होता था कि सत्याग्रहियों ने यह सीढ़ा किस लिए किया है, किन्तु इससे मेरी बलील पर कुछ असर नहीं होता।

यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझे लन्दन न भेजती। किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी।

न यही कहना न्याय्य और सही है कि मैंने कभी इस बात का दावा किया है कि सरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए।

लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैध-सरकार अपने उन कृत्यों और आदिनैस्यो के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहीं करता, सार्वजनिक सस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सदैव स्वागत करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती तथा अपने पास की सब सूचनाओं अथवा जानकारी से उनकी सहायता करती।

मैं यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देश का मैंने पिछले पैंरे में जो अर्थ बताया है उसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। समय ही बतलायेगा कि किसने सच्ची स्थिति ग्रहण की थी। इस बीच मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से सभाम को सर्वथा द्वेष-रहित तथा सर्वथा अहिंसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

आपको मुझे यह याद दिलाने की कोई आवश्यकता न थी कि अपने कार्यों के लिए कांग्रेस और उसका एक विनम्र प्रतिनिधि, मैं, जिम्मेवार हूँगे।”

वेन्चल का गश्ती-पत्र

सुविधा के लिहाज से हमने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया है, वैसे ये सब है छ दिन की घटनायें। ३० दिसम्बर को मि० वेन्चल गांधीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की। यह गोलमेज-परिषद् में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की हलचल मयोत्पादक थी और बाद की घटनाओं एवं अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में वहिष्कार एक बड़ा हथियार है। इन मि० वेन्चल तथा इनके राज-भक्त साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी तीक्ष्णता, इतने समय के बाद भी, विलंकुल कम नहीं हुई है। इन लोगों ने जो ‘गुप्त’ गश्ती-पत्र प्रचारित किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं —

“अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम लन्दन गये थे, लेकिन उसके साथ ही इस बात के लिए भी हम दृढ-निश्चय थे कि आर्थिक और

व्यापारिक सरक्षणों के बारे में (यूरोपियन) असोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो नीति निश्चित की है और यूरोपियन-असोसिएशन ने जो सामान्य-नीति तय की है उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे। यह हम अच्छी तरह जानते थे, और परिषद् के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो सरक्षण पेश किये जा चुके हैं उनकी काट-छाट करने का कांग्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सम्मिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा।

“इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, काग देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बरस एक भी ऐसी बात नहीं बतना सकते जो गोलमेज-परिषद् में उनके जाने के फल-स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की ओर से बतौर रियायत उनके साथ की गई हो। वह तो सली हाथ ही हिन्दुस्तान लौटे हैं।

“एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। साम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें असफल होना पड़ा।

“मुसलमानों का दिल बहुत ठोस और मजबूत रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कहे जानेवाले अलीइमाम भी उससे बाहर नहीं गये। शुरू से आखीर तक बड़ी होशियारी के साथ मुसलमानों ने खेल खेला। हमारा समर्थन करने का उन्होंने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आर्थिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दें। उनकी ‘ज्यादा लल्लो-लप्पो करने की तो जरूरत नहीं’, पर अंग्रेजी फर्मों में हमें उनको जगह देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें वे अपनी माली हालत और अपनी जान की सामान्य स्थिति को ठीक कर सकें।

“ब्रिटिश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुछ दिलावर, एक ही नीति है, और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जमे रहें। लेकिन (पार्लमेण्ट के) आम चुनाव के बाद सरकारी मन्त्र-दल ने (गोलमेज) परिषद् को असफल करने और उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय कर लिया। मुसलमान लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते इस बात से खुश हुए। सरकार ने तो निश्चिन्त-रूप में अपनी नीति बदल ली और केन्द्रीय सुधारों के आश्वासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही माथला टांगने की कोशिश की। हमें यह भी निश्चय हो गया था कि कांग्रेस के साथ लड़ाई अनिवार्य है, सब जगह महमूस किया और कहा कि जिनको जल्दी यह धुम हो जाय उनका ही अच्छा है।

लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती है जबकि जितने हो सकें उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर लें। मुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था।

“हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर सप्रू, जयकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय। अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सकें तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई मुश्किल बात भी नहीं है, इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि सच-योजना को नहीं छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तौर पर अंग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्तु, इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उपस्थित करे, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेंगे और इनका सन्तोष हो जायगा। जहातक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते। कांग्रेसी प्रान्तों और दुब भारत-सरकार का मुकाबला बड़ी भारी राजनैतिक कठिनाइया उत्पन्न करेगा, क्योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपोरेशन बन जायगा। अतः (इस स्थिति को बचाने के लिए) हमने अजीब नये-नये साथी जोड़े। फलतः बजाय इसके कि परिषद् व वाद-विवाद बीच में ही भग हो जाते और राजनैतिक विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिषद् में आये १६ फी सदी व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी शामिल हैं, सहयोग के आश्वासन के साथ वे समाप्त हुए, अलखता गांधीजी स्टैंडिंग कमिटी में शामिल होने के लिए राजामन्द नहीं हुए।

“मुसलमान तो अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं। अपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा सन्तोष है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

“लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि सुधारों का होना जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का ही प्रतिपादन करते हैं। हम जो-कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुचारुता बढ जाय।”

मजदूर सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया था उसके उद्देश को नष्ट करने की टोरी (कजरवेदिव) सरकार और उसके सागियों

ने कैसी चेष्टा की, यह इन उद्धरणों से मलीभाति मालूम हो जाता है, लेकिन यह विश्वास करना गलत होगा कि उन्नति-विरोधी मुसलमानों के, जोकि अपने थोड़े-से स्वार्थों के लिए^१ अपने देश को बेचने के लिए तैयार थे, और हिन्दुस्तानियों को हमेशा गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी ब्रिटिशों के बीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक ही हो गया। उसकी नींव तो गोलमेज-परिपद् के दूसरे अधिवेशन से कही पहले हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों जगह रखी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गांधीजी और लॉर्ड अर्विन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उन्नति-विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शीघ्रता के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिक्षित देने के लिए अपना सम्मिलित गुट बना लिया था। इस पद्धति की आधिक रचना तो सिमला में ही हुई थी, जोकि भारत-सरकार का सवर-मुकाम है।

गांधीजी पकड़े गये

मि० इमर्सन और लॉर्ड बिलिंगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लौट गये। लेकिन उन्होंने अपने-अपने ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। वस्तुतः सरकार ने वही से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहाँ पर कि ४ मार्च १९३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-सधि के दमियान उसने हजारी लाठिया और एकत्र करली थी। सच तो यह है कि अस्थायी-सधि का अवसर सरकार के लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-सधि के दमियान प्रायः किसी भी महीने नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो टूटना निश्चित ही था। तीन आर्डिनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी अक्रूर हो तुरन्त जारी कर-देने के लिए वाइसराय की जेब में रखे हुए थे। ४ जनवरी १९३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस की तथा उससे सम्बन्धित हरेक सस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और कांग्रेसी लोग, कानून या आर्डिनेन्सों के, जोकि गैर-कानूनी

^१ गोलमेज-परिपद् के समय की गई सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप अपने-अपने भारत के किसी प्रदेश का राजा बनाने की सर आगाखा की मांग से, जिसका कि हान्म ही में असेम्बली में रहस्योद्घाटन हुआ, इस सौदे का नग्न-स्वरूप बड़े बीभत्स रूप में सामने आया है।

कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-कर के जेलो में भेजा जाने लगा। कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा। सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१९३०) के समय शुरू में नहीं बल्कि बाद में जारी हुआ था, लेकिन १९३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले उसीका मुकाबला करना पड़ा। चारों तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉर्ड विंलिंगटन सारे उत्पात को छ सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छ सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई है कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई।

गांधीजी गुजरात के उन ताल्लुको में जाने का डरावा कर रहे थे, जिन्हें १९३० की लड़ाई में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेक्टर इसके कि वह बहा जायें, उन्हें और उनके विश्वस्त सहायक बल्लभभाई को ४ जनवरी १९३२ के बड़े सुबेरे गिरफ्तार करके घाही कैदी बना दिया गया। खानसाहब और जवाहरलालजी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिज्ञ बाकी बचे थे उन्हींको लड़ाई का संचालन करना पड़ा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही मेदान में आये। १९२१ में उनकी सख्या तीस हजार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी। १९३०-३१ में, दस महीनों के थोड़े-से समय में ही, नब्बे हजार स्त्री-पुरुष और बच्चे दोषी करार देकर जेलो में ठूस दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनी पर पड़ी, लेकिन जितनी को कैद की सजा हुई थी पीटनेवालों की सख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही। लोगों को या तो पीटते-पीटते किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया, या छिपने और घर दबोचने की नीति से उन्हें थका दिया गया। जेलो में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की जो गुप्त या खानगी बातें थी उनका रहस्योद्घाटन करने के लिए कहा गया। "तुम्हारे (कांग्रेस के) कागज-पत्र, रजिस्टर और चन्दे व स्वयंसेवकों की फेहरिस्तें कहा है?" यह सरकार की मांग थी। नौजवानों को तरह-तरह तग किया गया, न कहने-योग्य बातें (अपसब्द) उन्हें कही गईं, और अकथनीय सजाओं के आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके बाल उखाड़े गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना नाम और पता नहीं बताया था!

आर्डिनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये आर्डिनेन्स निकलते गये। हालांकि वे एकसाथ नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ

विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आर्डिनेन्स का जिन्हें तो पहले ही हो चुका है, जो कि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जब कि गांधीजी अभी लन्दन ही में थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में आतंकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और हलचल मालूम करे और उसकी बताई हुई बातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की आवश्यकता हो, उसको वह अमल में ला सकता था। प्रान्तीय-सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मग उसके सामान के, उसके मालिक या उसमें रहनेवाले से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, और चाहे तो उसका मुआवजा दे और चाहे तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी बीज या सामान के मालिक या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान ले सकता था। वह किसी अगह या इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल है, सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था। यातायात पर बन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के सुपुर्द करने का भी वह हुक्म दे सकता था। शास्त्रात्मक विनी बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कब्जे में कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी जमींदार या अध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, किसी खास व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लेने-पाने से मुक्त कर सकती थी, और किसी भी व्यक्ति के हिस्से का वकाया जुर्माना सरकारी मालगुजारी के बतौर वसूल किया जा सकता था। जरा भी अवज्ञा होने पर ६ महीने कैद या जुर्माने अथवा दोनों की सजा मिल सकती थी। प्रान्तिक सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि फतार लोगों से पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलों की जानकारी रखने तथा उनकी हलचलों की बातें मालूम करने के लिए, सम्राट् के प्रजाजनों के ज्ञान-माल पर होनेवाले आक्रमणों से रक्षा करने, सम्राट् की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तथा केशियों को जेल में निर्वास रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये। आर्डिनेन्स

के मातहत कैंसी भी कार्रवाई क्यों न करें, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। जिन मुकदमों को सरकार विशेष अदालत-द्वारा निपटाना चाहे उनकी तहकीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात् स्पेशल-ट्रिब्यूनल या स्पेशल-मजिस्ट्रेट बनाने को कहा गया। स्पेशल-ट्रिब्यूनलों के लिए नियमोपनियम भी विशेष तौर पर ही बनाये गये। विशेष-न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि बन्द परिस्थितियों में वे अमियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामला चला सकते हैं।

युक्त-प्रान्तीय इमर्जेन्सी-आर्डिनेन्स १४ दिसम्बर १९३१ को जारी हुआ। इसके द्वारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दी जानेवाली किसी रकम को (बकाया रकम को) सरकारी पाबना करार देकर उसे बकाया मालगुजारी के रूप में वसूल करे। प्रान्तीय-सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके में से हट जाने या किसी खास तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुक्म कायम रहता। किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, भय फर्नीचर तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या बगैर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्व करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का प्रवेश निषिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुक्म दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साधन हों उनके बारे में जब जैसा हुक्म मिले तब वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई भी अफसर किसी भी जमींदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति कायम रखने के काम में मदद करने के लिए तलब कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि वह सरकारी लेने को न बदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैद, जुर्माने या दोनों सजायें दी जा सकती थी। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-भाँति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। किसी खास इलाके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी बमूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुजारी वसूल की जाती है। किसी जल्द साहित्य के अण दोहरानेवाले को ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जुर्माना उनके मा-बाप या सरक्षक से वसूल किया जा सकता था और उनके

वसूल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार कैद की सजा दी जा सकती थी, माने स्वयं उन्होंने वह अपराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत में कादरी कारंवाई भी नहीं की जा सकती थी।

सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १९३१ को जारी ज्नि गये। उनमें में एक तो युक्तप्रान्त-सम्बन्धी आर्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारें लेने की वसूली के लिए निकाला गया था। बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रान्तीय 'इमर्जेंसी पावर्स आर्डिनेन्स' था और दूसरे का 'अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स'। इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह नियाय दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी व्यक्ति को एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुक्म दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर जमल न कर सकने की हालत में दो साल तक कैद की सजा दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सबक या जल-मार्ग के यातायात को नियंत्रित, नियंत्रित या मर्यादित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी भी माल की खपत व बिक्री को नियंत्रित करने के लिए उसे तैयार करनेवाले व व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोख्त के नकदो पेश करने या अपना सारा माल या उसका अंश सरकार को सौंप देने के लिए कह सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट सबारी या यातायात के अन्य सब साधनों के तण्डीलवार व्योरे पेश करने या उन्हें (सबारी आदि को) ही सरकार के सुपुर्त करने का हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद की बिक्री को जिला-मजिस्ट्रेट नियंत्रित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार बाई जिसको स्पेशल पुलिस-अफसर मुकर्रर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमींदार, अध्यापक या स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का हुक्म दे सकती थी। लोकोपयोगी कार्य (Utility Service) के संचालकों को उस सत्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता तो उस सत्था का अधिकार वह अपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायर-लेस (बेतार के तार) को नियंत्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या बिद्दी-पत्रियों को रोक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में जगह ले सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था,

रेलगाडी में से किसी भी यात्री को उतरवा सकता था, किसी भी गाडी को किसी खास मकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा में, फिर वह चाहे निजी स्थान में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों-द्वारा ही क्यों न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता था। तलाशियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने या ऐसी कोई अपवाह या चर्चा फैलाने की चेष्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरी के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-संचार होता हो, उसे एक साल कैद या जुर्माने की अवधि दोनों सजायें दी जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी हलके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसूल होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की बातों को दोहराये उसे ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवयुवकों पर हुआ जुर्माना उनके अभिभावक या सरसक से वसूल किया जा सकता था, और वसूल न होने की दशा में उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जजों व मजिस्ट्रेटों के साथ स्पेशल और सरसरी अदालतें बनाई गईं और उनके कार्य-क्षेत्र की व्याख्या करके मुकदमों व अपीलों के लिए खास तौर की कार्य-प्रणाली तैयार की गई।

अन्य आर्डिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी करार दे सकती थी और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति वहा हो उसे निकाल सकता था। मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था और प्रान्तीय-सरकार उसे जव्त करार दे सकती थी। निषिद्ध (गैर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहा रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फौजदारी अपराध का मुजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गैर-कानूनी करार दी गई सस्था का खपरा-पैसा आदि सामान जव्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी गैर-कानूनी सस्था का खपरा होने का शुबहा हो, उस खपरे को सरकारी हुक्म के वगैर खर्च न करने की पाबन्दी लगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियों के बहीखातों की जाच-पबताल करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता लगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी।

४ जनवरी को चार नये आर्डिनेन्स और जारी हुए—(१) इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स, (२) अनलॉफुल इस्टिगेशन आर्डिनेन्स, (३) अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आर्डिनेन्स। इनमें

से पहले आर्डिनेन्स के मातहत वो लोगो को गिरफ्तार करने, बन्द रखने या उनकी हलचलो को नियंत्रित करने, इमारतों को याग लेने, इमारतों या रेलवे को वज्रित-स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व विक्री पर नियंत्रण करने, यातायात के साधनों पर नियंत्रण करने, अस्वास्थ्य की विक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अध्यापकों आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजों व विट्ठी-पत्रियों को रोकने और बीच में गायब कर लेने, रेलों और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात पर नियंत्रण करने, सभाओं में पुलिस-अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार लिये गये थे जैसा का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार जैसा कि सीमाप्रांतीय रेग्यूलेशन में रक्खा गया है, विशेष अदालतों, उनमें छाम तौर की कार्रवाई, नये-नये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान किया गया। इण्डियन प्रेस इमर्जेंसी एक्ट को, आर्डिनेन्स की एक विशेष धाराके द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था।

‘अनलॉफुल इन्स्टिगेशन आर्डिनेन्स’ के मातहत सरकार किसी पावने को इशतिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में बाधक होता उसे ६ महीने कैद और उसके साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी बसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के बचाया के रूप में बसूल करवा सकता था।

‘अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स’ के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतीय आर्डिनेन्स के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रांतीय-मन्त्रार गैरकानूनी करार दी गई सस्या की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को, अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रांतीय-मन्त्रार जल भी कर सकती थी। जिस किसीके पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिमाद-विवाद की जग्य कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुजूम दे मानी थी। ऐसी हरेक सस्या को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कॉमिन्स-मन्त्रि गवर्नरजनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमल में बाधक होती हो मया सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो।

‘प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आर्डिनेन्स’ के मातहत उन सबको ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तग करते और उसका बहिष्कार करते या उसे तग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते, कोई आदमी दूसरे को सताने या तग करने का अपराधी उस हालत में माना जाता था जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट डालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई धमकी देता या उसके मकान के आस-पास घूमता रहता या उसके माल-मते में खलल डालता या किसी व्यक्ति को उसके गृहा न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए बयबा ऐसा कोई काम करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। बहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवाले के साथ व्यापार का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाजिक सेवाये (अर्थात् नार्ड, भगी, घोड़ी आदि के काम) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब बातें आमूल रूप में न करना, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना। किसी आदमी को बिद्वाने की गरज से उसका स्थापना करना, या उसका पुतला या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके लिए ६ महीने कैद या कैद और जुर्माने दोनों की सजाये हो सकती थी।

इस प्रकार इन आर्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे।

आर्डिनेन्स-कानून

जब आर्डिनेन्सों की अवधि समाप्त हुई तो उन्हें अगली अवधि के लिए नये सिरे से एक इकट्ठे आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १९३२ में बाकायदा कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १९३२ को ही, कामन-सभा में यह बात स्वीकार कर ली थी कि “आर्डिनेन्स बहुत व्यापक, तीव्र और कठोर हैं। भारतीय जीवन की लगभग हर एक बात उनकी चपेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यापक और तीव्र इसलिए बनाया गया है कि सरकार को हर तरह की जो जानकारी उमरल्लव है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार की जड़-भूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये आर्डिनेन्स आवश्यक हैं।”

यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून (१९३१ का २३ वा एक्ट), जो अस्थायी-सन्धि

के समय बना था, १ अक्टूबर १९३१ को समाप्त हो गया। १९३२ के क्रिमिनल-ऑफ-अमेण्डमेण्ट-बिल में उसे (प्रेस-लॉ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। प्रेस-कानून की धारयाँ करीब-करीब १९१० के एक्ट जैसी ही थीं। भारत-सरकार के आर्डिनेन्सो, बिलो या कानूनों के अलावा, नवम्बर १९३२ में बम्बई-सरकार ने एक प्रांतीय आर्डिनेन्स-बिल पेश किया, जिसमें करवन्दी-आन्दोलन के भुकावले की भी काफी गुजाइश रखी गई थी। सच तो यह है कि ये सब आर्डिनेन्स और दमनकारी अस्त्र तैयार करने का विचार तो अस्थायी-सन्धि के साल (१९३१ में) ही हो रहा था। वस्तुस्थिति तो यह है कि १५ अक्टूबर १९३१ को पूना के अंग्रेजों ने भारत-सरकार के गृह-विभाग के मंत्री को मान-मज्ज प्रदान किया और इसके बाद, १९३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की बम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा। उन्होंने सरकार को सुझाया था कि यदि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन फिर से शुरू हो तो उसे तुरन्त और बृहत्ता के साथ कुचल देना चाहिए— और यह सब उस समय जबकि लन्दन में गोलमेज-परिषद् हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य कांग्रेसियों को सन्तुष्ट करना था। उन्होंने खास तौर से यह सुझाया कि कांग्रेसी सन्धि की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयं-सेवकों की कवायद-परेश भी रोक दी जाय, जिन लोगों ने सविनय-अवज्ञा में भाग लिया था उन सबपर पाबन्दिया लगा दी जायें, उनके साथ बैसाही व्यवहार हो जैसा लड़ाई के समय शत्रु-देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजरबन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कोप के मूल का पता लगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष आर्डिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिल्स ने कांग्रेस की शर्तों मान ली हो उन्हें कहा जाय कि अगर वे उन्हें रद्द न कर देंगे तो रेलगाड़ियों-द्वारा उनका माल ले जाना बन्द कर दिया जायगा, और राजनैतिक परिस्थिति व बहिष्कार से किसीको अधिक लाभ न उठने देना चाहिए।

१९३२-३३ की घटनायें भी प्रायः १९३०-३१ की ही तरह रही, अलबत्ता लड़ाई इस बार और भी जोरदार एवं निश्चयात्मक थी। दमन और भी अन्धाधुन्धी के साथ चला और लोगों को पहले से भी कहीं ज्यादा कष्ट-सहन करना पड़ा।

कार्य-समिति की तत्परता

सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सबेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १९३२ के उपर्युक्त आर्डिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये। पश्चात् कुछ

ही बिनो मे, अमली तौर पर, सारे देश मे लागू हो गये। अनेक प्रांतीय और मातहत कांग्रेस-कमिटियो, आश्रमो, राष्ट्रीय स्कूलो तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओ को गैरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतो, फर्नीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। देश के खास-खास कांग्रेसियो में से अधिकांश को एकदम जेलो में ठूस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते कांग्रेस के पास न तो नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान। लेकिन इस आकस्मिक और दृढ़ झपट्टे के बावजूद जो कांग्रेसी बच रहे थे वे भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहाँ था वही उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ने तय कर लिया कि १९३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी छुट्टी की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करनेवाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुर्द कर दिये और अध्यक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रांतों में भी, जहाँ कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलो, थानो, ताल्लुको और गांवो तक की कांग्रेस-कमिटियो में भी हुआ। यही व्यक्ति आम तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बड़ी कठिनाई सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात् आज्ञा-भंग के लिए किन कानूनों को चुना जाय? यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानून का भंग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक आडिनेन्सो ने हल कर दिया। अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जब कि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-राष्ट्रपति की ओर से आदेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानो तथा ब्रिटिश माल की पिकेटिंग सब प्रांतों में समान-रूप से लागू हुई। लगानबन्दी युक्तप्रांत में काफी बड़ी हदतक और बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्त्व का विषय रहा। बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदारी-टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व वरार, कर्नाटक, युक्तप्रांत, मदरास प्रेसीडेन्सी तथा बिहार के कुछ स्थानों में जगलात के कानूनों का भंग किया गया। गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने और बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया। सभाओ और जुलूसों की तो जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभाये हुईं और जुलूस भी निकाले गये। लड़ाई की शुरुआत में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा, जोकि बाद में

विशेष उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जाते थे, जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, गद्दीद-दिवस, झण्डा-दिवस इत्यादि। जैसा कि अभी कह चुके हैं, कांग्रेस के दफ्तरो व आश्रमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब अनेक स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आर्डिनेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया था। ये प्रयत्न 'घावों' के नाम से मशहूर हैं। आर्डिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता था। इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजाग्रा हस्त-पत्रक, पत्रचें, संवाद-पत्र, रिपोर्टें आदि निकाले गये, जो या तो टाइप किये हुए होते थे या साइक्लोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकले हुए और कभी-कभी छपे हुए भी—लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कहीं नहीं होता था। यह मार्क की बात है कि पुलिस के सतर्क रहने पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें पहुँचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बन्द हो गये थे, इसलिए कांग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की—और वह प्रान्त के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं बल्कि महासमिति के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तों तक की। कभी-कभी यह डाक ले जानेवाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और तब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कार्रवाई की गई। १९३० के आन्दोलन के उत्तरार्द्ध में वस्तुतः यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १९३२ में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरो का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहाँ से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थी, और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रूकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देगवर में कांग्रेसी सम्मेलनों की लड़ी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने, जमीर खींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में, रेलों के नियमित काम-काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को

नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेवार हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हा, वहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर घातिया केन्द्रित की गई। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैगों, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और आम तौर पर ब्रिटिश माल के वहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

सरकार का दमन चक्र

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार खामोश या नरम पड़ गई। आडिनेन्सो में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहाँ तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अस्तियार किये गये जिनकी उन आडिनेन्सो तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी मयकरता के लिए बवनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गई चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात धी-धी स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हींको जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझा गया कि उनमें संगठन का कुछ माहा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष महत्त्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अतः १५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रक्खा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आवश्यकता की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को स्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप विघ्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजाये उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसीको

पता लगाने के भय से मुक्त हो कर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई, परन्तु सत्याग्रही कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रही। अस्थायी जेलों में रहना तो बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पड़े हुए थे उनसे न तो मई-जून की गर्मी का बचाव होता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे बड़ा तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थी जहाँ का व्यवहार किसी हदतक बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालाँत तो कुछ स्थायी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था। पेशिया का तो सभी समय जोर था, बर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ बबोचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। जेलों में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावकास पबता उनके शील-स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों में उनके साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर था, और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर न तो विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलूसों को भग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरुआत में ही अख्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही होगी जहाँ आन्दोलन में जीवन के बिन्दु दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। चोट खानेवालों की सख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगी। लोगों को यह आदत थी कि जहाँ सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई समा हो रही हो, या वे किसी धावे पर जा रहे हों, अथवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें क्या होता है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें कौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं और कौन सिर्फ तमाशबीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुलम हुए कि जिनका क्या नही किया जा सकता। और तो और पर स्त्रियों, लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बर्खा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। जेलों व मार-पीटारी की सक्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो

गोली सारर मर जाने की भी तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-से उसे बरदाश्त न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानों की रकम दम हजार या इससे भी अधिक तक चली जाती थी। जहा मालगुजारी, लगान या अन्य करो का देना बन्द किया गया वहा तो ऐसी वकाया रकमों और करो की तथा जुर्मानों की बमूली के लिए न केवल उन्हीं लोगों की मिलिक्यत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें बसूल करना बाजिब था, बल्कि साथ में सयुक्त-परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिलिक्यत भी कुर्क करके बेच डाली गई। कुर्की और बिनी तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहा तो कुर्की के बाब घड़ी-घड़ी फौमत की मिलिक्यतों को बिलकुल कीडी के ही मोल बेच डाला गया। और कुर्की व बिनी की कानूनी कार्रवाई से भी बढकर जो दु खदायी बात हुई वह तो है ग़लूम ने बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीको से सत्ताया जाना और नुकसान पहुँचाना, जिने हृदय-हीन छूट और बरबादी ही कह सकते हैं। न केवल फर्नीचर, बर्तन-भाण्डे, गहने, भबेणी और सडी फल जैनी चल-सम्पत्ति ही कुर्क करके बेच या कभी-कभी नष्ट कर्दी गई, बल्कि जमीन और घर-बार भी नहीं छोडा गया। गुजरात, युक्त-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीनों से हाथ धोये बैठे हैं, हालांकि उनका कष्ट-सहन बिलकुल स्वेच्छा-पूर्ण था; क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने इन्कार दिया, अगर अपने को और अपने माल-असबाब को बचाना ही उनका उद्देश होता तो किसी-न-किसी तरह उसे वह चुका ही देते। सच तो यह है कि ये आफतें उनपर लादी ही गई थी। क्योंकि अगर वकाया की बसूली ही प्रयोजन होता तो उन्हें इस तरह नष्ट न किया जाता। गुजरात के किसानों ने, और जिन्होंने लगान-माल-गुजारी न देने के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की अग्नि में से गुजरना पडा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका पचा वहा के निवासियों से बसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहा ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वहा के निवासियों से ताजीरी करके रूप में बसूल किया गाय। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोडकर आस-पास के स्थानों में भले गये। उन्हें इतने अवर्णनीय कष्टों का सामना करना पडा कि उनकी

स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुमले भी किये गये, जिनकी वसूली बहा रहनेवाले लोगो से की गई। देश के कई स्थानों में गोरी-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इस में नीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सब स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-बाह्य उपाय ग्रहण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्वसाधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सब का पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करे तो उसीका एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह सहृदय रहा हो। (व्हेल्लण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्त्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाईं।

जिन आशयों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अपवादों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से अग्राहकों से जमानते मांगी गईं, बहुतों की जमानतें जप्त की गईं, और बहुत-से अरबानों को जमानत जमान कर सकने या प्रेस जन्तु हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रवागमन ही बन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। यह था कि लोगो ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिनके कारण महीनो तक आन्दोलन जारी रहा, जब कि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में ही उसे मरतम कर देने का जमाना ही था। यह नहीं तो भी अतिसयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को बुचलने के लिए कानून के अंगारों जिन साधनों तथा आर्गुमेंटों का सहारा लिया गया, जो कि ममल कानून और मन्मथान के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न जमाना गया होता तो आन्दोलन को दवाने में सरकार को और भी बट्टिनाई होती। अगर पात्रेमात्रों ने भी, उनों लिए आवागमन के सब शुल्क माघम बन्द कर दिये जाने के बाग, रमाया गुन दानों

की ओर झुकना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विशेष सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपनेको पूरा पटु साबित किया। कांग्रेस-कार्यालयों के बने रहने और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कांग्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की हिदायत पहुँचाते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सामान्य की बात है कि घनाभाव के कारण काम में रुकावट पड़ने का भीका कभी उपस्थित नहीं हुआ। धन तो कहीं-न-कहीं से आता ही रहा। गुमनाम दानियों तक ने सहायता दी—और, कभी-कभी तो यह भी नहीं देखा कि किसी वह दान दे रहे हैं। यह मार्क की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि सारा दफ्तर लोगों की जेबों में ही रहता था, हिसाब-किताब बड़ी कड़ाई के साथ रक्खा गया और प्राप्त-सहायता का उपयोग सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया।

दिल्ली-अधिवेशन

इस वर्णन को खतम करने से पहले कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का भी वर्णन कर देना चाहिए जो कि १९३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस की बड़ी भारी सतर्कता के बावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही बहुत से प्रतिनिधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था।

आदमीचीक के घटावर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के बावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेशन के जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में कहीं तलाश करती रही और कुछ पुलिस एक जगह अकादलियों के जुलूस से निवटती रही। पैक्टर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने कार्यवाही भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ रणछोडदास अमृतलाल, कहते हैं, उसके समापति थे। उसमें कांग्रेस की मालाना रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई कि पूर्ण स्वाधीनता ही कांग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हादिक समर्थन किया गया, तीसरे में गांधीजी के आवाहन पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे बधाई दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चौथे में अहिंसा में अपने विश्वास की फिर से

पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाप्रान्त के बहादुर पठानों को, अधिकारियों की ओर से अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूतों की जाने पर भी असहिात्मक रहने पर बर्बाद दी गई।

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन वह तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। वैसे इन तमाम समय कांग्रेसियों में उल्लेख-योग्य वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्था एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद् से छोटने के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्दा-फाश करनेवाले वक्तव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अद्भुत शक्ति से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का प्रसंग उपस्थित होता, कांग्रेस-कार्यकर्त्ता उन्हींकी ओर मुखातिब होते थे, और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।

•

: २ :

संग्राम फिर स्थगित

गांधीजी का आमरण उपवास

पाठको को याद होगा कि दूसरी-मोलमेज-परिपद् में गांधीजी ने अपना यह निश्चय सुनाया था कि अस्पृश्यों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेष्टा की गई तो मैं उस चेष्टा का अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी मुकाबला करूँगा। अब गांधीजी के उस भीषण व्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। मताधिकार और निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के लिए, लोथियन-कमिटी, १७ जनवरी को भारत में आ पहुँची थी। समय बीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी। सरकार झटपट काम खतम करने में दक्ष है ही, और हम लोग इसी तरह जवानी जमा-खर्च करते रहेंगे। इसलिए बहुत सोचने-समझने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अस्पृश्य या दलित-जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन रक्खा तो मैं आमरण उपवास करूँगा। सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रैल १९३२ को भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की लकीर का उदाहरण था, लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है, हा, उचित समय पर गांधीजी के बिचारों पर भी ध्यान दिया जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिसे मूल से 'निर्णय' के नाम से पुकारा जाता है, सुनाया गया। (देखो परिशिष्ट ७) दलित-जातियों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथों से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था। १८ अगस्त को गांधीजी ने अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान-मन्त्री को सूचित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि व्रत यानी उपवास २० सितम्बर (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ ८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। प्रधान-मन्त्री ने गांधीजी को दलित-जातियों के प्रति क्षत्रुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। व्रत २० सितम्बर १९३२ को आरम्भ

और उन्हें अपनी जन-संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष बाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, पर गांधीजी ने अवधि घटाकर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनता यह न समझे कि डॉ० अम्बेडकर सवर्ण-जातियों की नेक-नीयती की आजमाइश करना नहीं चाहते, बल्कि विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए अवकाश चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया—“मेरा जीवन या पांच वर्ष”। अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा तय किया जाय। इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाला और गांधीजी ने कहा—“क्या खूब।” २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल-द्वारा समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधीजी से भेंट की। २६ तारीख की सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एक-साथ घोषणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर लिया गया। मि० हेग ने बड़ी कौंसिल में वक्तव्य दिया, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गईं—

(१) प्रधान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातियों को प्रान्तीय कौंसिलों में पूषक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पार्लेमेंट से सिफारिश करने के लिए उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते के मातहत स्थिर हुई है।

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-कौंसिलों में दलित-जातियों को जितनी जगह देना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता है।

(३) यरवडा के समझौते में दलित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध में जो-कुछ कहा गया है वह सवर्ण हिन्दुओं-द्वारा दलित-जातियों को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(४) बड़ी कौंसिल के लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली और मताधिकार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरवडा-समझौते की शर्तों को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रश्न विचाराधीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार समझौते के विरुद्ध नहीं है।

(५) बड़ी कौंसिल में आम निर्वाचन के लिए मुली जगहों में से १८ जगहें दलित-जातियों के लिए सुरक्षित रखी जायें, इस बात को सरकार दलित-जातियों और अन्य हिन्दुओं के पारस्परिक समझौते के रूप में स्वीकार करती है।

गांधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पक्षोपेक्ष हुआ। वह चाहते थे कि दलित-जातियों के नेता भी सन्तुष्ट हो जायें। उन्हें अपने भौतिक प्राण बचाने की चिन्ता न थी, बल्कि उन लाखों प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परन्तु अन्त में प० हृदयनाथ कुंजरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गांधीजी का सन्तोष करा दिया। इसपर गांधीजी ने २६ तारीख को शाम के सवा पांच बजे उपवास छोड़ने का निश्चय किया। भजन और धार्मिक श्लोक-पाठ के बाद उन्होंने पारणा की। यह ठीक था कि गांधीजी के प्राण बच गये, परन्तु जिस दबास में वह अपना उपवास भग करने को राजी हुए उसीमें उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार नैकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना पड़ेगा। गांधीजी ने कहा—“स्वतंत्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर में पहुँचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब सुधार हरेक गांव में किया जाय”। जनता ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्बन्ध में सन्देश प्रकट किया था। गांधीजी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १५ और २० सितम्बर को वक्तव्य दिये। उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की —

“ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आती है। ईसाई-धर्म में और इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धर्म तो आत्म-शुद्धि और तपस्या के लिए किये गये उपवासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैंने आत्म-शुद्धि करने की बड़ी चेष्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि मुझे ‘अन्तर्निवि’ ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुछ क्षमता प्राप्त हो गई है। मैंने यह प्रायश्चित्त उस अन्तर्निवि की आज्ञा के अनुसार बारम्बार किया है।” यदि लोग यह कहें कि उपवास तो दूसरों को धमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि “प्रेम विवश करता है, धमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते हैं। मैं अपने उपवास को न्याय के पलड़े में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार्य बच्चों का सा खेल प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि मेरे पास कुछ और होता तो इस अभिघाप को मिटाने के लिए मैं उसे भी शोक देता। पर मेरे पास प्राणों से अधिक और कुछ हुई नहीं।” “यह आगामी उपवास उनके विरुद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हो चाहे विदेशी। यह उपवास उनके विरुद्ध नहीं है जिनकी मुझमें आस्था नहीं।” इस प्रकार उन्होंने यह वता दिया कि यह उपवास न अग्रेज अप्सरों के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियों—चाहे

वे हिन्दू हो या मुसलमान—के विरुद्ध हैं, बल्कि उन असह्य भारतीयों के विरुद्ध हैं जिनका विश्वास है कि वह न्यायपूर्ण बात के लिए किया गया है। गांधीजी ने कहा—“इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक धार्मिक कार्य-शीलता उत्पन्न करना है।”

बम्बई का प्रस्ताव

प्रधान-मंत्री-द्वारा पेंकट स्वीकार होने और गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिषद् ने बम्बई में सभा की। एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। जो सत्ता बाद को हरिजन-सेवक-सघ के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई। इसके सभापति सेठ धनश्यामदास बिडला और मंत्री भारत-सेवक-समिति के श्री अमृतलाल ठक्कर हुए।

यहां हम वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १९३२ को बम्बई की सभा ने सर्व-सम्मति से पास किया था। इस सभा के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय थे।

“यह परिषद् निश्चय करती है कि अब सचिव ने हिन्दू जाति में किसीको जन्म से अस्पृश्य न समझा जायगा और जिन्हें अबतक अस्पृश्य समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की जाति ही कुलों, पाठशालाओं, सड़कों और अन्य मार्गजनिक स्थाव्यों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मीका मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप उसे स्वराज्य-पार्लमेण्ट स्थापित होने से पहले तक प्राप्त न हुआ तो स्वराज्य-पार्लमेण्ट का पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा।

“यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का यह कर्तव्य होगा कि पुराने रिवाजों के कारण अस्पृश्य कहलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बधन लगा दिया गया है उसे वे सारे चैव और शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें।”

ऐसे पवित्र तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निश्चय। अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इन्हीं बान का था कि पट्टी गुबन जल्दवाजी से काम न ले। इसलिए गांधीजी को लगाम खींचनी पड़ी। अस्पृश्यों या हरिजनों—जैसा कि अब वे कहलाने लगे थे—के लिए मन्दिर-प्रवेश का अनिवार्य प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार

असहयोग-आन्दोलन के जयाने में लोग झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा कठोर तप करने के अपने सामर्थ्य पर, बिना विचार किये ही झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे। गांधीजी के नियन्त्रण और प्रभाव ने १९२१-२२ में अनेक बार परिस्थितियों को बचाया था, वही प्रभाव अब फिर काम कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गांधीजी के आवाहन का धन और जन दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घण्टे और हर मिनट अन्तर पड़ता दिखाई दिया। मोरारजी के नवाब ने इस हिन्दू-ब्राह्मिक आन्दोलन के लिए ५०००० रुपये दिये। फादर बिन्सो ने अपने अन्य सहयोगियों के हस्ताक्षर के साथ एक अपील छपवाकर ईसाइयों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था को बिकारा। उधर मौलाना मौकतबली गांधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात् २६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्तन करके गांधीजी से मुलाकात आदि करने की वे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थी, न छीन लेती तो साम्प्रदायिक समझौता अवश्य हो जाता। श्री जयकर उनसे मेंट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजत न मिली। श्रीमती सरोजिनी देवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। श्रीमती कस्तूरबा गांधी को गांधीजी के पास से हटा दिया गया। मुलाकातें बन्द कर दी गईं। गांधीजी अब वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्तु सरकार की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रीमती कस्तूरबा को समय के पहले छोड़ दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रहने दिया गया। गांधीजी ने इस प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से बचित होने पर विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पुना-पैक्ट की शर्तों ही के विरुद्ध थी।

लम्बे-लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गांधीजी को अपना अस्पृश्यता-निवारण-कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। हाल ही मुलाकातियों के, पत्र-व्यवहार के और समाचारपत्रों में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर को होम-मेम्बर मि० हेग ने बड़ी कौंसिल में निम्नलिखित वक्तव्य दिया —

“हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम निश्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुलाकातों के, पत्र-व्यवहार

के और केवल इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार गांधीजी की अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी चेष्टाओं में बाधा नहीं डालना चाहती, क्योंकि गांधीजी ने बताया है कि अस्पृश्यता-निवारण एक नैतिक और धार्मिक सुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों के तथा पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध में रुकावट हटा ली है, पर जिन मुलाकातों का सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक बातों से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैसी है, जैसा कि वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेटरी-द्वारा मौलाना मौलाना को दिये गये उत्तर से प्रकट है।" (पूना-पैक्ट और तत्सम्बन्धी सरकार से हुमा पत्र-व्यवहार परिक्षिप्त ८ में देखिए।)

गुरुबयूर-सत्याग्रह

इस प्रथम महान् व्रत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की और चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी ओर जनता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। श्री केलप्पन मलाबार में खास तौर से हरिजन-उत्थान-सम्बन्धी कार्य कर रहे थे। उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें आमरण उपवास करने को प्रेरित किया। उन्होंने इस उपवास का सकल गांधीजी के महान् व्रत के लगभग साथ-ही-साथ किया। श्री केलप्पन का उद्देश्य था कि गुरुबयूर-मन्दिर के ट्रस्टियों को अस्पृश्यों के लिए मन्दिर-प्रवेश की अनुमति देने को राजी किया जाय। गांधीजी ने इस मामले की सारी बातों का अध्ययन करने के बाद स्थिर किया कि ट्रस्टियों को काफ़ी नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि सफलता प्राप्त हुई रखी है—पर गांधीजी ने कहा कि तात्कालिक सफलता प्राप्त होने-न-होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कार्य के नैतिक औचित्य का।

इसलिए गांधीजी ने श्री केलप्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित कर दो और ट्रस्टियों को पहले नोटिस देने के बाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना ठीक होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करूँगा। उसके बाद श्री केलप्पन ने भी उपवास करना त्याग दिया।

यहाँ गांधीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनुचित न होगा जो कि २ दिसम्बर १९३२ को उन्होंने श्री अप्पासाहेब पटवर्धन की महानुमति में शुरू किया

था। श्री पटवर्धन ने जेल में भगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने इस बारे में बम्बई-सरकार को लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर न हुआ। इसपर श्री पटवर्धन ने अपना खाना क्रमशः कम करते हुए मृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया। अस्थायी-सन्धि के समय गांधीजी ने अप्पासाहब पटवर्धन से कहा था कि अगर तुम्हारी मांग स्वीकृत न हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अतः उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर दिया। लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि अगर उपवास छोड़ दिया जाय तो वे उनकी मांग पर विचार करेंगे। उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया। और एक सप्ताह के अन्दर ही भारत-मन्त्री ने जेल के नियमों में ऐसा संशोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओं को भगी का काम देने की रक़ाबट उठ गई। इस प्रकार यह सत्याग्रह सफल हुआ।

गिरफ्तारियाँ

हमने १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। हमने पूना-मैकट का भी जिक्र कर दिया है। जनता ने गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण के आवाहन का जो उत्तर दिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति को निस्सन्देह क्षति पहुँची।

इतने पर भी कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा। सत्याग्रह-आन्दोलन के शिथिल होने का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थिति थी, और जैसा कि बयान किया जा चुका है, सत्याग्रह-आन्दोलन केवल लुक-छिपकर ही चलाया जा सकता था। और यह तरीका सत्याग्रह के सिद्धान्तों से असंगत और विरुद्ध ही नहीं बल्कि विपरीत भी है। पूना में गांधीजी के उपवास के सिलसिले में मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर पर उन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में, जो रिहा हो चुके थे, विचार-विनिमय करने का खासा मौका मिल गया। उसीके फल-स्वरूप दो गहरी-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पष्ट किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और अस्पृश्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया है जो किसी-न-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते। दूसरे पत्र में उस लुक-छिपी की नीति का, जो सत्याग्रह-आन्दोलन में आ चुकी थी, अन्त करने पर जोर दिया गया था।

सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था।

इसलिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद स्थानापन्न-समापति हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को हिदायतें भेज दी कि १९३३ के इस दिन एक सास वक्तव्य पढा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोलन की प्रगति और उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया गया था जो उस समय जनता के दिमाग में सबसे ऊपरी थी, जगह-जगह भेज दिया गया। जगह-जगह समार्यें हुईं, जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और लाठी-चर्पा के बीच में पढा गया। ६ जनवरी १९३३ को कांग्रेस-समापति भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री अणे ने ग्रहण किया।

जब १९३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार बल्लभभाई पटेल कांग्रेस के समापति थे। कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १९३० के विपरीत इस बार कार्य-समिति के रिक्त स्थान पूरे न किये जायें। सरदार बल्लभभाई ने उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके बाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे। जनवरी १९३२ और जुलाई १९३३ के बीच में, जब कांग्रेस-संस्था का अस्तित्व लोप हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अन्सारी, सरदार सार्दूलसिंह कवीरवार, श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, डॉ० किचलू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने समापति का भार ग्रहण किया। इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयों के मध्य में कार्य चलाने का भार आकर पड़ा उनमें श्री जयप्रकाशनारायण, लालजी मेहरोत्रा, गिरवारी कृपलानी, आनन्द चौधरी, और आचार्य जुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय है।

१९३३ की घटनायें तो संक्षेप में ही बताई जा सकती हैं। कलकत्ते का अधिवेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा।

कलकत्ता-कांग्रेस

अप्रैल १९३२ के दिल्ली के अधिवेशन की भांति कलकत्ता का अधिवेशन भी निवेधाना के होते हुए करना पड़ा। यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया था जब सत्याग्रह-आन्दोलन स्थिर पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहाँ दिखाई पड़ी वह दिल्ली में भी दिखाई न पड़ी थी। कुछ प्रान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तों से चुने गये। इस बात से कि ५० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन का समापन स्वीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ़ गया। श्रीमती मोतीलाल नेहरू ने

वृद्धावस्था और दुर्बलता का ध्यान न करके अधिवेशन से भाग लेने का जो निश्चय किया उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्ति मिली। अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्च को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ। डॉ० प्रफुल्ल घोष स्वांगत-समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रक्खा। पण्डित मदनमोहन मालवीय को कलकत्ते नहीं पहुँचने दिया गया। उन्हें बीच ही में आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद-महमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे गिरफ्तार कर लिये गये और सबको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। कांग्रेस के कार्य-बाहुक-सभापति श्री अणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज दिया गया। कलकत्ते में स्वांगत-समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांग्रेस-नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। श्रीमती नेली सेनगुप्त और डॉ० मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, या कलकत्ते के मार्ग में, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने में सफल हुए। निवेचना होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये। बीघ्र ही उनपर पुलिस आ टूटी और कांग्रेस-बादियों के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाठिया बरसने लगी। बहुत-से प्रतिनिधि घुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेष्टा की, परन्तु असफल रही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समूह अपनी-अपनी जगहों पर जमा रहा, और वे सातो प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पठकर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को कांग्रेस सभापति होते ही छोड़ दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सजाये दी गई। श्रीमती सेनगुप्त को भी छ मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय सीधे कलकत्ता पहुँचे और बीघ्र ही देश के सामने इस बात का कि पुलिस ने किस अमानुषिकता के साथ कांग्रेस भंग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होंने सरकार को जाच करने की चुनौती दी, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम ३१ मार्च १९३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव देते हैं —

१ स्वाधीनता का लक्ष्य—यह कांग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो

लाहौर में १९२९ में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था।

२. सत्याग्रह वैध-अस्त्र है—यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध उपाय समझती है।

३. सत्याग्रह कार्यक्रम का पालन—यह कांग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी १९३२ के निर्देश की पुष्टि करती है। पिछले १५ महीनों में जो कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि देश इस समय इस परिस्थिति में है, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ़ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को आवाहन करती है कि इस आन्दोलन को कार्य-समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय।

४. बहिष्कार—यह कांग्रेस जनता की भारी श्रेणियों और वर्गों को आवाहन करती है कि वे विदेशी कपड़ा बिल्कुल त्याग दें, सड़क का व्यवहार न करें और अंग्रेजी माल का बहिष्कार करें।

५. क्वाइट-पेपर—इस कांग्रेस को सम्मति है कि जबकि ब्रिटिश-मरजार ऐसे निर्दयता-पूर्ण दमन-कार्य में लगी हुई है, जिसके द्वारा देश के परम-विश्वमनीय नेता और उनके हजारों अनुयायी जेलों में पड़े हैं या नजरबन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का हनन हो रहा है, समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर बड़ा प्रतिबन्ध लगा रहा है, और माधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर मार्शल-लॉ का दौर-दौरा है, और जिसका आरम्भ जान-झूझकर महात्मा गांधी के विलापत ने लौटने पर, राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तब तक उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार कर सकती है।

कांग्रेस का विमवास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए क्वाइट-पेपर की योजना में जनता धोखे में न पड़ेगी, क्योंकि वह भारत के हितों की विरोधिनी है और इन देश में विदेशी प्रभुत्व स्थायी बनाने के लिए तैयार की गई है।

६. गांधीजी का उपवास—यह कांग्रेस देश को, २० नवम्बर को गांधीजी के उपवास की सफल समाप्ति पर, बर्बाद देती है और आशा करती है कि अस्पृश्यता भीषण ही अतीत की वस्तु हो जायगी।

७. मौलिक अधिकार—इस कांग्रेस को सम्मति है कि जनता को यह समझाने

के लिए कि 'स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्त्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सकें। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह कांग्रेस अपने १९३१ के कराची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारो सम्बन्धी प्रस्ताव न० १४ को दुहराती है।

गांधीजी का उपवास

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद शीघ्र ही देश में एक घटना हुई जो विलकुल आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं की सत्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन कार्यकर्त्ताओं को अपना काम पवित्रता, मेवाभाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गांधीजी ने ८ मई १९३३ को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके दान्दों में "यह अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए मैं अपने भारतीय तथा ससार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अग्निपरीक्षा में सफल पूरा उत्तरूं, और चाहें मैं मरूं या जिऊं, मैंने जिस उद्देश से उपवास किया है वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रखा है, हट जाय।" उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा—"किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजको की वौद्धिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-बूझा उपाय है।"

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रवृत्त होनेवाली मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार गांधीजी ८ मई को छोड़ दिये गये। गिहा होते ही गांधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिश की।

गांधीजी ने कहा—"मैं इस रिहाई से प्रमत्त नहीं हूँ, और, जैसा कि रल मुजने सरदार बल्लभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, मैं इस रिहाई में लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन या पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ ?

“इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेषण करने को प्रेरित करती है और सम्मानशील व्यक्ति की हैसियत से मुझपर एक बहुत बड़ा भार रखती है और मुझे असमजस में डालती है। मैंने आशा की थी और मैं अब भी आशा करता हूँ कि मैं न तो किसी बात को लेकर उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग लूँगा। यदि मैं अपने दिमाग में हरिजन-कार्य के अतिरिक्त और किसी बाहरी बात को जगह दूँगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा।

“पर साथ ही, रिहाई होने पर अब मैं अपनी थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ।

“इसमें सन्देह नहीं कि इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असत्य सत्याग्रहियों की बीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साधुवाद के सिवा और कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का संचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो। यदि इससे एक भी सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है।

“इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आडिनेन्सो ने भयभीत बना दिया है, और मेरी धारणा है कि लुका-छिपी के तरीकों का भी यह दबूपन उत्पन्न करने में इनका हाथ है।

“सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुषों की सत्या पर नहीं, उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता है, और यदि मैं आन्दोलन का संचालन करूँ तो मैं योग्यता पर जोर दूँगा। यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो जाय। किसी और रूप में जनता को हिदायत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये विचार जो मैंने प्रकट किये हैं, पिछले कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रखे थे, और मैंने जो-कुछ कहा है उसमें सरदार वल्लभभाई भी मुझसे सहमत हैं।

“मैं एक बात और कहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो—इन तीन सप्ताहों में सारे सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे। यदि कांग्रेस के सभापति श्री माधवराव अणे वाक्यावदा छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो।

“अब मैं सरकार से एक अपील करूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आर्दिनेन्स का शासन सभ्य-शासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-वन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियों को बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए।

“यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा से बच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करने का अवसर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताओं को और यदि मैं कहने का साहस करूँ तो, सरकार को सलाह दे सकूँगा। मैं उस स्थान से बातचीत आरम्भ करना चाहूँगा जहाँ वह मेरे इच्छे से वापस आने पर रह गई थी।

“यदि मेरी चेष्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझौता न हो सका और सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर आर्दिनेन्स का शासन आरम्भ कर सकती है। यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयेगा। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है।

“सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जबतक इतनी अधिक समस्या में सत्याग्रही जेलों में हैं, और जबतक सरकार बल्लभभाई पटेल, खानसाहब अब्दुल-गफ्फारखा और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्थ हैं, तबतक कोई समझौता नहीं हो सकता।

“वास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से बाहर किसी आवामी के सामर्थ्य में नहीं है। यह केवल उस समय की कार्य-समिति ही कर सकती है। मेरा मतलब उस कार्य-समिति से है जो मेरी गिरफ्तारी के समय मौजूद थी। मैं अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा। शायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया।

“मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। सविष्य में मुलाकात के लिए आनेवाली से भी मैं कहूँगा कि वे समय से काम लें। वे मुझे अब भी जेल ही में समझें। मैं कोई राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ।

“मैं शान्ति चाहता हूँ और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग न करूँगा, और यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पड़ा तो मैं सविनय-अवज्ञा को बढाने की लुक-छिपकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये बिना ही

सरकार से कहेंगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हें मैं इस समय त्याग-न्ना आया हूँ, घर-वडा पहुँचा दिया जाय।

“सरदार बल्लभभाई के साथ रहना बड़े सौभाग्य की बात हुई। मैं उनकी अद्वितीय धीरता और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उसने मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद आ जाती है। मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ-मुल्लभ गुण मौजूद हैं। मुझे कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना बिछोना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध रखनेवाली जरा-जरा-सी बातों की निगरानी रखते। उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मानो मुझे कुछ न करने देने का पड़्यथा रच लिया था, और मुझे आशा है कि जब मैं यह कहूँगा, कि अब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को बड़े अच्छे ढंग से समझा, तो सरकार मेरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होंने बारडोली और खेडा के किसानों के सम्बन्ध में जो हिनचिन्तना प्रकट की, उसे मैं कभी न भूलूँगा।”

गांधीजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह आन्दोलन छ सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नहीं लिया।

६ मई को एक मरकारी विज्रप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे शर्तें पूरी नहीं होती जो कैदियों की रिहाई के लिए रखी गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में सीदा करने को तैयार नहीं है।

भारत-भन्नी के शब्दों में सरकार ने कहा था—“हमारे पास यह विश्वास करने के प्रबल कारण होने चाहिए कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुबारा शुरू न हो जायगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप में बंद करने से, जिससे कांग्रेसी-नेताओं के साथ समझौते की बातचीत शुरू हो जाय, वे शर्तें पूरी नहीं होती जिनके द्वारा सरकार को सतोष हो जाय कि सत्याग्रह सन्तुष्ट हूँगे के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की वापसी के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैदियों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।”

इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य

आया जिसपर श्री विठ्ठलभाई पटेल और श्री सुभाष बसु के हस्ताक्षर थे। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं —

“सत्याग्रह बंद करने की गांधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है।”

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि “हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गांधीजी राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम नये सिद्धान्तों के ऊपर नये उपाय को लेकर कांग्रेस की कायापलट करें, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांधीजी से यह आशा करना अनुचित है कि वह ऐसे कार्यक्रम को हाथ में लेंगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो।”

वक्तव्य में आगे कहा गया—“यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी।”

यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्मान्त व्यक्तियों की, जिन्हें युद्ध के समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पड़ा। गांधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्तोष, आस्था और धैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने ससार की आलोचना भी सह ली। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १९३३ को उन्होंने अपने उपवास का अन्त किया।

इस बीच में कांग्रेसवादियों में यह तथ्य हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अवधि को कार्य-वाहक-समापति ने छ सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया।

पूना-परिषद्

१२ जुलाई १९३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में कांग्रेसवादियों की अनियमित बैठक हुई। श्री अण्णे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिषद् का श्रीगणेश किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिषद् के सन्मुख सक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिषद् दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन

की कार्रवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक लम्बे-चौड़े वक्तव्य के द्वारा किया, जिसमें उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिषद् के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही अपनी सूचनायें भी उनके सामने रखीं। इसके बाद परिषद् ने अपनी सिफारिशें पेश कीं। उसने सत्याग्रह को बिना किसी शर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। अन्त में परिषद् ने गांधीजी को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश से उनसे मिलने की अनुमति चाही। पर वाइसराय ने उत्तर में पूना-परिषद् की चर्चा के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत हवाला दिया और उन रिपोर्टों पर विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर दिया जबतक कांग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले ले। गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अपना हस्त एक निजी परिषद् की गोपनीय कार्रवाई के सम्बन्ध में छपे हुए अनधिकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निश्चित किया है, और यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देंगे कि कुल मिलाकर कार्रवाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष में हुई थी। पर गांधीजी की शान्ति-स्थापना की चेष्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को बाध्य होना पड़ा। पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्य-वाहक-सभापति के आज्ञानुसार सारी कांग्रेस-सत्याग्रह और युद्ध-समितियाँ उठा दी गईं।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान् से मूल्यवान् वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहाया। उन्होंने साबरमती-आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी जगह सम्पत्ति को कुछ मस्जिदों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया। वह किसी दूसरे में लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और सेंटी सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की प्रत्यूच में एक पक्ति भेजी गई।

साबरमती-आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन-आन्दोलन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १९३० में दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एकवार को छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १९३० के बाद आश्रम में फिर कदम न रक्खा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन-सभ के अर्पण करके उन्होंने पाँचव जगत् से वापस रखने-वाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना रहता, अंत कर दिया।

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की फरवरी में वल्लभभाई की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करनेवाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी ४ अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और उन्हें यरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस यात्रा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आगे घण्टे के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दी गई।

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार धार्दूलसिंह कवीरवार की बारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी की कि कार्य-वाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरो की नियुक्ति का सिलसिला तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण करले। गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उसपर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस-कार्यकर्त्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट ताते ने युद्ध को जारी रक्खा। जबतक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तबतक इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णन सारे प्रान्तों के साथ न्याय करते हुए नहीं किया जा सकता। आन्दोलन के अन्तिम युग में हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये, इसका पूरा व्यौरा मौजूद नहीं है। केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने आवाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी

उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतन्त्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था किया।

गांधीजी की रिहाई

सरकार ने गांधीजी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी रिहाई से पहले दी गई थी। इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर अनशन आरम्भ करना पड़ा। सरकार अड़ी रही। पर गांधीजी की अवस्था बड़ी क्षीयता के साथ खोचनीय होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात् अनशन के पाचवें दिन, पूना के सैसून अस्पताल में कैदी की हैसियत से पहुँचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण सकट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हें बिना किसी अर्त के छोड़ दिया गया। इस अनपेक्षित परिस्थिति ने गांधीजी को असमजस में डाल दिया। पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रखकर और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-बूझकर आरम्भ न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आपको रिहा न समझना चाहिए और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ३ अगस्त १९३४ तक, मर्यादित आत्म-नयम से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा गिरफ्तारी को निमग्न न देना चाहिए। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह मागेंगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से रोकेंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के अधिकांश भाग को वह हरिजन-आन्दोलन की उन्नति में लगायेंगे।

जवाहरलालजी की रिहाई

इधर श्रीमती भोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा था और इस अवसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई। इसलिए युक्तप्रान्त की सरकार ने ५० जवाहरलाल को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निश्चय किया जिससे वह अपनी माता की घोर रुणावस्था में उनके पास रह सकें। ३० अगस्त को जवाहरलाल जी छोड़ दिये गये। अपनी माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह सीधे पूना पहुँचे जहाँ गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांधीजी १९३१ में गोलमेज-परिषद् के लिए रवाना हुए थे तबसे इन दोनों की यह पहली भेंट थी। अतः स्वभावतः

देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उनमें आपसी बातचीत हुई। इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-व्यवहार भी हुआ जिससे जनता के आगे भीजूद कार्यक्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये। कांग्रेसवादियों तथा सर्वसाधारण की सूचना और पत्र-प्रदर्शन के लिए वाद में यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी कर दिया गया।

हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा

गांधीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निष्क्रिय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि को हरिजन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १९३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना शुरू किया। उन्होंने दस महीनों के भीतर भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन दस महीनों का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या के अध्ययन और उस समस्या को हल करने के उपाय सोचने में बीता। इस दौरे से बहुत बड़ा प्रचार-कार्य हुआ। उपस्थिति समुदाय का उत्साह और सख्या १९३० के जमाने से ही टककर ले सकता था। गांधीजी ने अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगभग आठ लाख रुपया एकत्र किया। व्यापारिक मन्दी के जमाने में और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी जनता पर आर्थिक बोझ पड़ चुका था, गांधीजी की अपील का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण बात थी। यह दौरा पूर्ण सफल रहा। दो 'सोचनीय' दुर्घटनायें भी हुईं। २५ जून १९३४ को गांधीजी बाल-बाल बच गये नहीं तो देश के लिए बड़ा भारी सकट उपस्थित हो गया होता। वह पुना म्युनिसिपैलिटी का मानपत्र ग्रहण करनेवाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है, उनपर वम फेंका। इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर-कार को गांधीजी की मोटरकार समझा। गांधीजी की मोटरकार अभी समा-स्थान में न आई थी। अनुमान किया जाता है कि यह अपराधी गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ़ गया था। फिर भी उसके वम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया। सीमाग्य से किसी को गहरी चोट न आई। दूसरी घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई। यहाँ किसी तेज मिजाज सुधारक ने आपसे बाहर होकर बनारस के पंडित लालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड़ दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रामाणिक उसीके विरुद्ध किया गया था।

गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ। श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मन्दिर के ट्रस्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १९३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केलप्पन और गांधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवयूर-मन्दिर के उपासकों की राय ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इस बीच में डॉ० सुब्बारायन ने मदरास-प्रान्त के मन्दिरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया था और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवयूर के मतों में ७७ प्रतिशत उपासक अछूतों के मन्दिर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से इन्कार कर दिया था, उन्हें निकाल कर, २०,१६३ रायें आईं जिनमें से मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतिशत थी, मन्दिर-प्रवेश के विरुद्ध २,५७६ या १३ प्रतिशत थी, और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थी। इन मतों में बिलक्षणता यह थी कि ८,००० से भी अधिक स्त्रियों ने हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में रायें दीं।

नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ, क्योंकि गांधीजी का आमरण उपवास टल गया। पर सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रगति इतनी सतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे भग्नोत्साह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओं ने पूना में वचन दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सबने अपने वचन को भुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी बार सजा काटने में या तो असमर्थ थे, या तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़ती न थी। सरकार ने यह तरीका सोच निकाली थी कि वह लाठियों की वर्षा करती, और छोटी जेलों में रखकर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करती। वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और कुछ समय बाद फिर छोड़ देती। यह कार्रवाई थकानेवाली थी। इससे सजा के द्वारा सत्याग्रहियों को जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये। ऐसा हो रहा था मानो बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़ कर झसोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ ले। इस प्रकार न तो वह उस चूहे को भारती ही, न छोड़ती ही।

विहार-भूकम्प और जवाहरलालजी की गिरफ्तारी

१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के

समाचारपत्रों ने गत तीसरे पहर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुँचाये तो सब लहखड़ा कर रह गये। कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शकल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारों इमारतें धूल में मिल गईं और पृथिवी के गर्भ में समा गईं। जमीन के भीतर से रेतें ने निकलकर हरीमरी खेतों के प्रशास्त मैदानों को नष्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान का जल १५०० फीट पृथिवी के नीचे से निकला। जहाँ प्राणदायी जल की नदियाँ बहकर पृथिवी की सिंचाई करती थी, या जहाँ मुस्कराती हुई खेतियाँ अपने वस स्थल पर वे भार ग्रहण किये हुए थी जिनके द्वारा लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी, वही रेत का मैदान छा गया। पलक भरते हजारों परिवार अनाथ और हजारों स्त्रियाँ विधवा हो गईं और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दबकर मर गये। प्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के भीतर जो गजब डायल उसका वास्तविक-चित्र निष्पान आकड़े क्या दे सकेंगे। फिर भी कुछ आकड़े दिये जाते हैं। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० वर्गमील की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यों के प्राण गँवाने की बात कही जाती है। लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये। ६५,००० कुएँ और तालाब या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई।

इस भयंकर सकट का सामना करने के लिए बिहार और भारत दोनों पीछे न रहे। चन्दों के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, बिहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकांश नेता और कार्यकर्त्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से पीछितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को बौढ़ पड़े। बिहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रों में २,००० से ऊपर कार्य-कर्त्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था।

बिहार के विष्वस्त प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका आगमन समवेदना का परिचायक मान हो, सो बान न थी। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दबे पड़े हैं, तो उन्होंने स्वयंसेवक का विल्ला लगाया, कंधे पर फावड़ा रक्खा और उस स्थान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों में फावड़े लिये मौजूद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्त्ताओं ने फावड़े चलाये और मिट्टी की टोकरीयाँ अपने सिरों पर ढोईं। बिहार के भूकम्प ने गांधीजी के कार्यक्रम में भी

विघ्न डाला। बिहार और बिहार के कार्यकर्त्ताओं को इस समय भूकम्प और बाढ़ के द्वारा उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गांधीजी ने एक मास तक उनका पथ-प्रदर्शन किया और उन्हें परामर्श दिया। फल यह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक परिषद् हुई जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के संचालन के लिए बिहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी को जन्म दिया गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोजन था और जिसमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं की प्रधानता थी। जबतक गांधीजी बिहार में रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों और गांवों का दौरा किया, इस महान् सकट की शिकायत जनता की दयनीय दशा को स्वयं देखा और नई बनी कमिटी को अपना कार्यक्रम स्थिर करने में सहायता की। उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्त्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और उनकी सेवायें बिहार के अर्पण कर दीं। अब भी इस प्रान्त को ऐसी जटिल और महान् समस्याओं का सामना करना है जिसका बाहर वालों को काफी ज्ञान नहीं है।

अपना बिहार का दौरा समाप्त करने पर ५० जवाहरलाल एक बार फिर सरकार के कैदी बने। जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हूलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे। बंगाल-सरकार आतंकवादियों का जिक्र, उनकी खुल्लम-खुल्ला निन्दा को छोड़कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। पीड़ित जवाहरलाल ने अपने स्पष्ट भाषणों में आतंकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नीकरसाही को यह सहन न हुआ। जबतक वह बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बंगाल-सरकार के औचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने से रोक रखा, पर अभी वह अपने घर कठिनता से पहुँचे होंगे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष सखी कैद की सजा दी गई।

कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम

जुलाई १९३३ की पूना-परिषद् के बाद में ऐसे कांग्रेसवादियों की गणना में वृद्धि हो रही थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आर्टिनेन्स के आसन के भारन देना में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर हम 'मिन्चेस्टर' में उद्घाटन पत्र के लिए कौंसिल-प्रवेश या कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। इस विचार ने सगठित

घरण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले कांग्रेसी-नेताओं की एक परिषद् बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोस रूप देने का निश्चय किया गया। यह परिषद् दिल्ली में ३१ मार्च १९३३ को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भग कर दी गई है उसे दुबारा जीवित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादियों को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, भत-दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गांधीजी के जुलाई १९३३ वाले पूना के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाय। इस परिषद् ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचनो में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिषद् ने निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लड़े जायें—(१) सारे धमनकारी कानूनों को रद्द कराना और (२) ब्लाइट-पेपर की योजनाओं को रद्द करके उनका स्थान उन राष्ट्रीय भागों को दिलाना जिनका जिक्र गांधीजी ने गोलमेज-परिषद् में किया था। परिषद् ने यह निश्चय करने के बाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई और डॉ० विधानचन्द्र राय का एक शिष्ट-मण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे बातचीत करे और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले।

इस अवसर पर गांधीजी बिहार के भूकम्प-पीडित स्थानों का दौरा कर रहे थे और सयोग-वृक्ष अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १९३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर बिता रहे थे। यही पर उन्होंने दिल्ली के बाल-बाल जाने बिना ही एक वक्तव्य तैयार किया जिसे वह प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्सारी का सन्देश आया कि कल दिल्ली-परिषद् ने एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया है जो आपसे मिलने पटना जा रहा है। गांधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से बातचीत होने तक वह वक्तव्य रोक रखा और अंत में अच्छी तरह बातचीत होने के बाद ७ तारीख को वह प्रकाशित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ० अन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ। हम वक्तव्य और पत्र—दोनों को नीचे देते हैं—

गांधीजी का पत्र (५ अप्रैल १९३४)

“शुद्ध कांग्रेसवादियों की निजी बैठक में जो प्रस्ताव लिखित हुए थे, उनपर चर्चा करने और मेरी राय लेने के लिए आपने, भूलाभाई ने और डॉ० विधान ने पटना तक आकर अच्छा ही किया। आप मुझसे कहते हैं कि बड़ी कौंसिल जीध ही भग होनेवाली

है। अतएव उसके आगामी निर्वाचन में भाग लेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुज्जीवित करने के इस बैठक के निश्चय का मैं निस्सकोच भाव से स्वागत करता हूँ।

“वर्तमान अवस्था में काँग्रेसियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में मेरे जो-कुछ विचार हैं वे जाने-बूझे हैं। वे अब भी लगभग वैसे ही हैं, जैसे १९२० में थे। पर मैं यह अनुभव करता हूँ कि जो कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, और जिसकी काँग्रेस-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए न केवल यह उचित ही है, बल्कि कर्तव्य-रूप है कि वह उनमें प्रवेश करने की चेष्टा करे, और जिस कार्य-क्रम की पूर्ति को वह देश के हितों के लिए आवश्यक समझता है उसे अमल में लाने के उद्देश से बल नमाये। अपने इन विचारों के अनुसार मैं पार्टी की सहायता के लिए जो-कुछ मेरी शक्ति में है वह करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।”

गांधीजी का वक्तव्य (७ अप्रैल १९३४)

“मैंने इस वक्तव्य का मसविदा अपने मीन-दिवस में सहरसा नामक स्थान पर २ अप्रैल को ईस्टर सोमवार के दिन तैयार किया था। मैंने इस मसविदे को बाबू राजेन्द्रप्रसाद को दे दिया और इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा। मूल में अब काफी परिवर्तन हो गया है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है। परन्तु सार-रूप में यह वैसा ही है जैसा कि सोमवार के दिन था। मुझे खेद है कि मैं इसे अपने सारे मित्रों और सहयोगियों को न दिखा सका, उनकी सलाह मिल जाने से मुझे बड़ा हर्ष होता। परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं था और मैं यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघ्र ही सत्याग्रह करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने मित्रों की सलाह के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तव्य के प्रकाशन में विलम्ब करने को तैयार नहीं था। मेरा निश्चय और मेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की टटोल और ईश्वर-प्रार्थना का परिणाम है। इस निश्चय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छीटे फेंकना नहीं है। यह तो मेरी मर्यादाओं की और उस महान् उत्तरदायित्व के बोध की, जिसे मैं इधर कई वर्षों से वहन करता आ रहा हूँ, विनम्रता-पूर्ण स्वीकारोक्ति-भाष है।

“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई आपसी बातचीत से प्राप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेन्द्र बाबू के कहने से मैंने विद्वार भेज दिया था। इस वक्तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और जिससे मेरी आँखें खुल

गई। वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न थे और मिले हुए काम की अपेक्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। इन्हें तो मैं पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। पर इस बात से इनकी दुर्बलताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्बलताओं का बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनकी यह धारणा थी कि मैं उनकी दुर्बलता को जानता हूँ। पर मैं अन्धा था। नेता में अन्धापन एक अक्षम्य अपराध है। मैं फौरन जान गया कि फिलहाल मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूँगा।

"गत जुलाई में पूना की एक सप्ताह की निजी बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि बैसे बहुत-से व्यक्तित्वन सत्याग्रही आगे बढ़ें तो अच्छी ही बात है, पर सत्याग्रह के मदेश को जागृत रखने के लिए एक सत्याग्रही भी काफी है। अब अच्छी तरह ध्वज टटोलने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल अकेले मुझे ही, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

"मैं अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नहीं मिला है, क्योंकि संदेश उसतक पहुँचते-पहुँचते अशुद्ध हो जाता है। मुझे यह प्रतीत हो गया है कि आध्यात्मिक संदेश पार्थिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक संदेश तो स्वयं ही अपना प्रचार कर लेते हैं। मेरे कहने का जो तात्पर्य है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप में ज्वलन्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी घरे में अच्छी तरह मिला। जनता ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह आत्म-श्रेष्ठ था। स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंख्य जनता की, जिस तक वे पहुँचे तक न थे, उपस्थिति और उत्साह पर आश्चर्य हुआ।

"सत्याग्रह सोलह आने आध्यात्मिक अस्त्र है। इसका उपयोग पार्थिव दिखाई पड़नेवाले उद्देश के लिए भी हो सकता है, और इसका उपयोग उन स्त्री-पुरुषों के द्वारा भी हो सकता है जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, बशर्ते कि उन्हें बताने-वाला जानता हो कि अस्त्र आध्यात्मिक है। सत्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना सभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी उनका उपयोग बताता रहे तो बहुत-से आदमी उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने-तई सत्याग्रह का विशेषज्ञ होने का दावा करता हूँ। मुझे उस दक्ष सर्जन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, कहीं अधिक सावधानी से चलना है। मैं तो अभी एक विनम्र शोधक-मात्र हूँ। सत्याग्रह का विज्ञान

ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से अधिक नहीं देख सकता।

“आश्रम-निवासियों के साथ वार्त्तालाप करने के बाद मैंने अपने हृदय को टटोला और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना बन्द करने की सलाह देनी चाहिए। हा, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया जाय तो बात दूसरी है। उन्हें इस प्रकार का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जबतक कोई ऐसा व्यक्ति आगे न बढ़े जो इस विज्ञान को मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर जनता विश्वास करती हो, तबतक दूसरी को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी ही देख-रेख में आरम्भ करना चाहिए। मैं यह सम्मति सत्याग्रह के प्रणेता और आरम्भ-कर्त्ता की हैसियत से देता हूँ। इसलिए आयन्दा से वे सब लोग जो मेरे प्रत्यक्ष दिये गये या अप्रत्यक्ष रूप से सम्झे गये परामर्श के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कृपा करके सत्याग्रह करने से रुकें। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है।

“मेरा सच्चे दिल से यह विश्वास है कि मानव-जाति के पास, अपने कष्ट-निवारण के लिए, यह सबसे बड़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरा यह दावा है कि यह हिंसा या युद्ध का पूर्ण स्थान ले सकता है। इसलिए यह ‘आतंकवादों’ कहलानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के जो देश को पीछे-हीन करके ‘आतंकवादियों’ का बीज-नाश करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच सकता है। परन्तु अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बड़ा रहा हो, पर वह न ‘आतंकवादियों’ के ही हृदयों तक पहुँच सका, न शासकवर्ग के ही हृदयों तक। शुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस सत्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्याग्रह एक समय में एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाइश पहले कभी नहीं की गई थी, अब करनी चाहिए।

“मैं पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र न समझ लें। सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध की अपेक्षा कहीं व्यापक चीज है। सत्याग्रह सत्य की अथक खोज है, और इस खोज के द्वारा जो व्यक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग पूर्ण अहिंसात्मक साधनों के द्वारा ही हो सकता है।

“पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्या करें? यदि उन्हें फिर कभी आवाहन होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छा-पूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-बुनकर खट्टर का प्रचार करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज बो देना चाहिए। स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा अस्पृश्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और नशेबाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-द्रव्य के त्याग का प्रसार करना चाहिए। वे सेबायें हैं जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दरिद्र आवसी की भाँति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धर्म में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय। यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके लिए है जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर झुकाना जानते हों, और झुकते हों।

“यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी प्रकार में कांग्रेस के अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन लोगों को परामर्श-मात्र दे रहा हूँ जो सत्याग्रह के मामले में मेरा पक्ष-प्रदर्शन चाहते हों।”

डॉ० अन्तारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गांधीजी ने अपनी हार्दिक और स्वतः दी हुई सहामता के द्वारा कांग्रेस में विरोध और भेद-भाव की मासका को दूर कर दिया है। अब कौंसिलो के भीतर और बाहर रहकर दुहरा युद्ध किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज और जनता की राजनैतिक निष्कियता और अन्तःकृपित असंतोष दूर हो जाय।

रजराज्य पार्टी

१९३४ की २ और ३ मई को राची में एक बैठक स्वराज्य-पार्टी को शक्तिशाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई। इसका एक हेतु यह भी था कि गांधीजी उसपर अपनी मुहर लगा दें। इस बैठक का पहला प्रस्ताव दिल्ली-परिषद् के उन प्रस्तावों का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म दिया गया था और प्लाइमथेन पर अस्वीकार करने और राष्ट्रीय भाग तैयार करने के निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्टिट्यूएण्ट असेम्बली) बुलाने और दमनकारी

कानूनों को रद्द कराने के उद्देश से बड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचन में अपने उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की सशोधित नियमावली को अपनाया गया। इस निश्चय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी अपनी आन्तरिक व्यवस्था और आय-व्यय के मामले में कांग्रेस की सलाह लेने की वाध्य नहीं थी। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों पर उसे कांग्रेस के बताये पथ पर चलना चाहिए।

३ मई १९३४ को राची-परिषद् ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित किया उसमें उन सारे कानूनों और विधेय विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो, रद्द कराने की बात रखी गई। इस कार्यक्रम के अनुसार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करनेवाले हों, ग्राम-संगठन करना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनियम, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना और अन्त में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कर्तव्य माना गया।

सत्याग्रह स्थगित

इन सब विषयों पर १८ और १९ मई १९३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा हुई। यहाँ यह बात भी कह देना जरूरी है कि कांग्रेस की महासमिति ही एकमात्र ऐसी संस्था थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया —

चूँकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमिति पण्डित मदनमोहन मालवीय और डॉ० अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बोर्ड का नाम होगा पार्लियेमेंटरी-बोर्ड, और इसके प्रधान होंगे डॉ० अन्सारी। इसमें २५ से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेंगे।

“यह बोर्ड कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, जन्दा एकज करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा।

“यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विधान तैयार करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का

अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रखे जायेंगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आशा पर काम में ले लिये जायेंगे। बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलो में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेंगे।”

: ३ :

अवसर की खोज में

सबकी इच्छा कांग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन दम्बई में अक्तूबर १९३४ के अन्तिम सप्ताह में हो।

महासमिति की बैठक के आगे-पीछे कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी १८, १९ और २० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौजूबी और कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशें की, जिन्हें, जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्य-समिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर के कांग्रेसवादियों ने उस निश्चय का पालन किया और २० मई १९३४ को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १९३३ (पूना) में कार्यवाहक-अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का सशोधन करते हुए, सारे कांग्रेस-वादियों को आदेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए कांग्रेस-कमिटियों का संगठन किया जाय। कार्य-समिति ने प्रमुख कांग्रेसवादियों को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस के पुनर्संगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया। सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावतः ही उठा दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सहायक बनाने गये, और कांग्रेस के नये अधिवेशन तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हसियत से साग काम चलाने का अधिकार दिया गया।

पटना में इन निश्चयों तक आसानी से पहुँचा गया हो तो बात नहीं। एक ओर ऐसे बहुसंख्यक कांग्रेस-वादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर अटके हुए थे और जो कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी अच्छी छापाने की चेष्टा न करते थे। दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिनकी धमिल धीरे-धीरे बढ़ रही थी। यह दल गांधीजी के आदर्शों को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथ न था, किन्तु कौंसिल-प्रवेश के सर्वथा विरुद्ध था।

गांधीजी उठे, या यो कहना चाहिए कि बंटे और बोले, तो सारा विरोध वात-की-यान में काफूर हो गया।

गांधीजी हरिजन-आन्दोलन के बारे में उड़ीसा का भ्रमण पैदल कर रहे थे। तब पैदल चलने का नया प्रयोग कर रहे थे। यह पटना गये तो, पर उनका हृदय हरिजन-ताम्र में ही रम रहा था। उसीलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य में चेष्टा करके अलग लगना पड़ा था। उसमें मन्देह नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का धौग बहुत कम कर दिया, और सयोगवश उसमें चन्दे की रकम में भी कमी हुई। पर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेल और मोटर में सफर के अर्थ ये होंगे कि वह पन्द्रा सड़ता करने का मय-मास रह जायें। यहाँ तक मन्वा बाधा जा रहा था कि उन्हें युपन्रान्त का दौरा हवाई जहाज-द्वारा कराया जाय। यह सब उनकी कवि के विपरीत था। उन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी रखा था। पर पटना ने चलल टाल दिया। किन्तु उन्हें इसपर कोई रोप न था। जून ८ अप्रैल १९३४ वाले वषण्व के द्वारा उन्होंने इस चलल को निमग्रण दिया था। अब उन्हें समीची पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पड़े। उन्होंने १९३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, कार्य-समिति के प्रन्तान के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था, उन्नी प्रान्त उमगा अन्त भी हो गया। गांधीजी ने एकबार फिर पटना में महासमिति के नामने दो आपणों में अपनी आत्मा डोलकर रख दी थी।

समाजवादी दल

मई १९३४ में भारत में समाजवादी दल का जन्म हुआ। १७ मई १९३४ को उसका पहला अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कीसिल-प्रवेश और मूती मिलो की हड़ताल के सम्बन्ध में मार्गदर्श करने के बाद यह निष्पत्ति किया गया कि कांग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी-समिति कायम करने का समय आ गया है। एक मसविदा-कमिटी नियुक्त की गई, जिसके जिम्मे उक्त समिति के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार करके बम्बई-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। पटना की बैठक के बाद से समाज-वादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तों में कायम हो गई हैं।

पटना के निश्चय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया। सत्याग्रह-

वान्दोलन बन्द हुआ और कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। १९३२ के आरम्भ में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस की संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १९३४ की १२ जून को अधिकांश पर से प्रतिबन्ध उठ गया। हा, सीमान्त-प्रदेश और बंगाल की कांग्रेस-संस्थायें और उनमें सलग्न अन्य संस्थायें—जैसे हिन्दुस्तानी सेवादल—उसी प्रकार गैरकानूनी रही। कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन इमारतों पर अपना कब्जा बनाये रक्खा जिनका सबब, उसकी राय में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्याग्रह से था। इनमें से कुछ इमारतें तो १९३५ के मध्य तक वापस नहीं दी गईं। सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याग्रही कैदियों को शीघ्र छोड़ने की है, पर तो भी अनेक कैदी, विशेषकर गुजरात के कैदी, जेलों में ही रहे। कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी ग्वायु-भर ब्रिटिश-भारत में ही रहे तो भी, ब्रिटिश-भारत में वापस नहीं आ सके, और अब वैशी-राज्यों में एक प्रकार से नजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध सत्याग्रह से रह चुका था और जो विदेशों में अपने वैध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नहीं दिया गया। अस्तु।

फिर संगठन

पटना के निश्चय के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-कमिटियों का पुनर्संगठन आरम्भ कर दिया था, और जून लगते-लगते प्रान्तों में कांग्रेस-कमिटियाँ १९३२ के पहले की भाँति काम करने लगी। तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३ जून को वर्धा में और १७-१८ जून को बम्बई में हुई। इन बैठकों में तब-संगठित कांग्रेस कमिटियों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं —

हाथ से कातकर खदर तैयार करना और खदर तैयार करनेवाले इलाके में उसका प्रसार करना, अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, आदक द्रव्य-सेवन के त्याग और नशीली वस्तुओं से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय हथ की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-धंधों की वृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आर्थिक, शिक्षण, सामाजिक और आरोग्य-सम्बन्धी दृष्टि से पुनर्संगठन करना, व्यस्त गाववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य करना जो कांग्रेस के उद्देशों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह

का रूप भी धारण न करते हों। कार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विज्ञप्ति की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर ने प्रतिबंध उठा लिया गया था, और कहा कि यद्यपि कांग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १९३१ से कांग्रेस के ही अंग हैं उसी प्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सरकार ने इस असंगति से तो नहीं पर खुदाई-खिदमतगारों और अफगान जिरमे के विरुद्ध जारी की गई निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

ह्लाइट पेपर और साम्प्रदायिक निर्णय

कार्य-समिति की बम्बईवाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया। वह यह था कि ह्लाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए? कांग्रेस-पार्लेमेटरी-बोर्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे ने अनुभव किया है कि यह मतभेद होते हुए वे न पार्लेमेटरी-बोर्ड से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये। पर आशा की गई कि अच्छी तरह बातचीत करने के बाद सम्भव है यह नीबट न आवे, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफे वापस लेने को राजी कर लिया।

ह्लाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्ताव इस प्रकार था —

“ह्लाइट-पेपर से भारतीय लोकमत विलकुल प्रकट नहीं होता और भारत के राजनैतिक-बलों ने इसकी कमीवेष निन्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने लक्ष्य में पीछे नहीं हटाता है तो उससे कोसों दूर अवस्थ है। ह्लाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र सत्तोषजनक वस्तु वह धासन-व्यवस्था हो सकती है जिसे वयस्क-मताधिकार या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-कारिणी सभा बनाये। हा, यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खास तौर से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा।

“ह्लाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः ही खारिज

हो जायगा। अन्य बातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी वर्तव्य होगा कि वह महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आमतौर से उनके हितों की रक्षा का प्रबन्ध करे।

“पर चूँकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद है, इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का स्वर प्रकट करना आवश्यक है। कांग्रेस का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि सत्ता है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती है न अस्वीकार, जबतक कि यह मतभेद मौजूद है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय।

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जबतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कांग्रेस-द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस बचन दे चुकी है कि वह ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर नारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें ने दलविशेष सहमत न हुआ हो।

“राष्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निश्चय विलकुल अमंतीपजनक पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक बातें मौजूद हैं।

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निश्चय के बुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्ग आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इन बरतू मामलों में ब्रिटिश-सरकार या क्रिनी और बाहरी शक्ति ने अपील करना।”

सरदार पटेल रिहा

सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिला-गुजारी मग्ने हुए धीरे-धीरे छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार बल्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल और खान अब्दुलगफ्फारजा को गिरा न करने का उम्मेद निश्चय कर लिया था। इनमें दो को, सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ्फारजा को, जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रखा था। उन्हें १९३० की गुरुजान से ही विदेशी कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और मरवार जगत का चान्नी उन्हें गाँधी कैदी की हैनियन से जेल में रख सकती थी। पर ऐनी बर्नस्टीन आ पत्रों में सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार बल्लभभाई पटेल को नाक का पुगना रोग था,

जो डगर बहुत बढ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था धारण कर ली। सरकार-द्वारा नियुक्त गये मेडिकल बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतंत्र होगा। फलतः सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १९३४ को छोड़ दिया।

मालवीयजी का इस्तीफा

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में प० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई। कार्य-समिति मालवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की मौलिक नीति को नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने कांग्रेस-पार्लमेण्टरी-बोर्ड के सभापति-पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पार्लमेण्टरी-बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। बंगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनो को अतिरिक्त जगह क्यों दी गई? इस प्रकार बंगाल का दस कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामलों के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि पूना-मैन्ट के विरुद्ध भी था।

स्वदेशी पर प्रस्ताव

स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की जो नीति थी, उसपर लोगो में सशय उत्पन्न हो रहा था। कार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति को भी पुष्ट कर दिया और निम्नलिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी —

“स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में सशय उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस विषय में कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है।

“सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांग्रेस-अध पर और कांग्रेस-प्रदर्शनियों में मिल के कपड़े और खट्टर के बीच में प्रतिद्वन्द्विता की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस-बादियों को केवल हाथ से कत्ते और हाथ से बुने खट्टर को ही प्रोत्साहन देना चाहिए।

“कपड़े के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में कार्य-समिति कांग्रेस-मस्याओं के पथ-प्रदर्शन के लिए निम्न-लिखित तजवीज को मजूर करती है—

‘कार्य-समिति की सम्मति में कांग्रेस के स्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्हीं उपयोगी चीजों तक सीमित रहेंगे जो भारत में घरेलू और अन्य षष्ठों द्वारा तैयार की जाती हों, जिन्हें अपनी सहायता के लिए लोक-शिक्षा की आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर करने, वेतन और भजदूरो की भलाई के मामले में कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने को तैयार हो।’

“इस योजना का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी-वस्तुओं के प्रति प्रेम और केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की कांग्रेस की अवाध नीति में किसी प्रकार का अन्तर आ गया है? यह तजवीज तो इस बात को प्रकट करती है कि बड़े और सगठित षष्ठों को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-संस्था की सहायता की और न कांग्रेस की ओर से किसी और ही प्रयत्न की परकार है।”

कांग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासन की आवश्यकता के प्रश्न पर कार्य-समिति की यह राय हुई कि “सारे कांग्रेसवाधियों से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम और नीति में विश्वास रखते हों या न रखते हों, आज्ञा की जाती है और सारे पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर अमल करें और कार्य-कारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस के कार्यक्रम या नीति के विरुद्ध प्रचार करेंगे या उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, वे २४ मई १९२९ को बनाये गये महासमिति के नियमों के अनुसार कांग्रेस-व्यवस्था की ३१वीं धारा के अन्तर्गत अनुशासन का भंग करने के अपराधी माने जायेंगे और इसके लिए उनके खिलाफ जाफ़ा कार्रवाई की जायगी।”

राष्ट्रीय दल

अपने-अपने त्यागपत्र देने के बाद मालवीयजी और श्री अणे ने १८ और १९ अगस्त को कलकत्ते में कांग्रेसियों और अन्य सज्जनों की एक परिपद् की। इस परिपद् के सभापति मालवीयजी थे। इस परिपद् ने निश्चय किया कि काँग्रेस के भीतर और बाहर साम्प्रदायिक ‘निर्णय’ और व्हाइट-पेपर के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पूर्ति के लिए बड़ी काँग्रेस के उम्मीदवार खड़े किये जायें। परिपद् ने वे सिद्धान्त स्थिर किये जिनके अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुने जायें, और व्हाइट-पेपर और साम्प्रदायिक ‘निर्णय’ की निन्दा के बाद कार्य-समिति से अनुरोध किया कि वह

साम्प्रदायिक 'निर्णय' सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन के लिए महासमिति की बैठक बुलाये।

अब्दुलगफ्फारखां रिहा

सत्याग्रह-बन्दी के वाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रखी थी। खान अब्दुलगफ्फारखा को जेल में बन्द रखने से लोकमत बहुत रुष्ट हो गया था। सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तों में से था जिन्होंने १९३० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा भोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानों के अहिंसाव्रत की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोषपूर्वक कष्ट सहें। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गर्व के साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन और निरक्षर प्रणाली के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिंसा का मार्ग कभी न छोड़ा। इसलिए देश में यहाँ से वहाँ तक लोगों का दिल यहीं कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी बड़े चिन्तित थे और वह यही विचार करने में लगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी बातें स्वयं जानने की समस्या को कैसे सुलझायें? इसलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अब्दुलगफ्फारखा और उनके भाई डॉ॰ खानसाहब को छोड़ दिया गया तो जनता को बड़ी तसल्ली हुई। पर मुक्त होने पर भी उन्हें अपने प्रान्त और अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोड़ तो दिया, पर सीमान्त-प्रदेश में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-बन्दी के आदेश का यथावत् पालन किया था।

नये चुनावों पर कार्यसमिति

कार्य-समिति की बैठक २५ सितम्बर को वर्षा में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को दोहराया गया। बात यह थी कि कुछ कांग्रेसवादियों और अन्य सज्जनों को सहाय होने लगा था कि पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य को अब भुलाया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से कराची-कांग्रेस की स्थिति को दोहराया गया। 'आगामी निर्वाचनों' के सम्बन्ध में कार्य-समिति ने सारी प्रान्तीय और मातहत कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लियेन्टरी-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझें। कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति

के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आशा की कि वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवारों की सहायता करेगा। एक दूसरे प्रस्ताव में जजीवार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय्य भू-स्वत्व से वंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी कानूनों का जिक्र किया गया। श्री अणे के नये दल के कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनुरोध किया था कि महासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पण्डित मालवीय और श्री अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमन्त्रित किया। कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर कई घण्टे तक विचार किया और अन्त में इस नतीजे पर पहुँची कि चूँकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, और चूँकि महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्य-समिति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते हैं, जिसपर कार्य-समिति को बाध्य होकर बैठक बुलानी पड़ेगी।

कार्य-समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' सम्बन्धी निश्चय का, अन्तःकरण के विरुद्ध होने के आधार पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह उस नतीजे पर पहुँची कि चूँकि कार्य-समिति ने इस बन्धन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। मालवीयजी ने श्री अणे के द्वारा एक सदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह तजवीज पेश की थी कि धर्म के पारस्परिक तनाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रसिद्धी उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई नमज़ोना न हो सका। पर पार्लियामेन्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी और श्री अणे खड़े हैं उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायें। १० बोंटें न यह भी निश्चय किया कि सिन्ध में और कच्छता सह्य में उम्मीदवार खड़े न किये जायें।

गांधीजी के कांग्रेस से हटने की बात

इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे। यह कोरी किम्बदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके बाद बंगाल व आन्ध्र से जो लोग किसी-न-किसी कार्य-वश उनके पास बर्धा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा बराबर कर रहे थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को बर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया —

“यह अफवाह सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात सोच रहा हूँ। बर्धा में अमी हाल में कार्य-समिति और पार्लियेन्टरी-बोर्ड की बैठको में भाग लेने के लिए जो मित्र यहाँ आये थे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया और उनकी इस बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद कांग्रेस के अधिवेशन के बाद होना ही अच्छा होगा। पण्डित गोविन्दवल्लभ पंत और श्री रफीक़ुल्लाह किदवाई ने मुझे एक बीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगो ने यह सलाह दी थी कि मैं कांग्रेस में तो बना रहूँ, पर उसके सक्रिय प्रवन्ध से अलग रहूँ। मगर सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुलकलाम आजाद ने इस राय का जोरो से विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल तो मेरी इस बात से सहमत हैं कि अब वह समय आ गया है जब मुझे कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। परन्तु बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो इस राय से सहमत नहीं हैं। प्रश्न के तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि अपना अन्तिम निश्चय कम-से-कम अक्सर से होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रखूँ। अन्तिम निश्चय को स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस धारणा की जाँच कर लेने का मौका मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, मेरे कार्यक्रम और मेरी प्रणाली से उकता गये हैं और वे यह सोचते हैं कि कांग्रेस की स्वामाधिक प्रगति में मैं वजाय साधक के एक बाधक बनता जा रहा हूँ। वह यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस देश की एक सर्वमान्य लोक-तन्त्रात्मक और प्रतिनिधिमूलक संस्था होने के वजाय मेरे प्रभाव में आकर मेरे ही हाथों की कठपुतली बनती जा रही है और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बাক़ी नहीं रहा।

“अगर मुझे अपनी धारणा की सच्चाई की जाँच करनी हो तो यह जरूरी है कि मैं सर्व-साधारण के सामने उन वजूहात को रख दूँ जिनके आधार पर मेरी यह धारणा

वनी है, साथ ही अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूँ, जो उन कारणों पर निर्भर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना बोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर कर सकें।

“इसको यथा सम्भव संक्षेप में रखने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत-से कांग्रेसवालों और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक वृत्ता हुआ और गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत-से बुद्धिशाली कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम भक्ति के बन्धन में न पड़े रहें तो प्रसन्नता के साथ उस दिशा की ओर जायेंगे जो मेरी दिशा के बिल्कुल विपरीत है। कोई भी नेता उस वफादारी और भक्ति की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली कांग्रेसवादियों द्वारा प्राप्त हो चुकी है—वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेस के सामने रखी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भक्ति तथा श्रद्धा से अब और लाभ उठाना उनपर बेजा दबाव डालना है। उनकी यह वफादारी इस बात के देखने से मेरी आश को बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे बीच मौलिक मतभेद मौजूद है।

“अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए। चर्खा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है। कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा कातना लुप्तप्राय हो गया है। साधारणतः उन लोगों का “समें कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर भी अगर मैं उनके विचारों को अपने साथ रख सकता, तो मैं १) आने के बजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए अनिवार्य कर देता। कांग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है और कांग्रेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी की धारा के सम्बन्ध में जो पारलमैंट और टालमटोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। मुझे यह समझना चाहिए था कि यह ग्राहीमाली शर्त सच्चे विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादारी के ही कारण स्वीकृत की गई थी। मुझे यह बात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील में काफी भ्रष्टाचार है। तथापि मेरा यह विश्वास बढना ही रहा है कि अगर भारत को अपने लाखों गरीबों के लिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह भी बिना अहिंसा-द्वारा, तो चर्खा और खादी विधियों के लिए ही बने ही व्यावहारिक होने चाहिये जैसे कि अर्द्ध-वेकारों तथा लाशों की मर्गों में अर्द्ध-मृत लोगों के लिए हैं, जो मरणात् के दिव्य हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुओं की तरह पृथिवी पर भार बन हो गये हैं। इन प्रकार चर्खा मन्त्र जैयें में मानव-जीवन नया ममानना का मुद्दा बन

है। वह खेती का एक सहायक-अन्घा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफड़ा है जिसे काम में न लाने से हम तप्ट हो रहे हैं। फिर भी ऐसे कांग्रेसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको चर्खे के भारत-व्यापी सामर्थ्य में विश्वास है। कांग्रेस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि कांग्रेस और देश के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टूट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह धारा बनी रहेगी तो उसका सक्ती से पालन कराना पड़ेगा। पर यह भी अशक्य होगा, यदि कांग्रेसवालों का खासा बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो।

“इसी प्रकार पार्लेमेण्टरी-बोर्ड की बात लीजिए। यद्यपि मैं असहयोग का प्रणेता हूँ, तो भी मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी सामूहिक सत्याग्रह की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस के नियंत्रण में एक पार्लेमेण्टरी-पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक अंग है। यहाँ भी हम लोगों के बीच गहरा मत-भेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस धोर से मैंने इस कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे बहुत-से अच्छे-अच्छे साथियों को व्यथित किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसी हदतक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे जो बुद्धि या अनुभव में बड़ा समझा जाता है दवा देना एक सत्या की निर्विकार उन्नति के लिए हितकर और वाञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक भयकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस प्रकार बार-बार दवाना पड़े। यद्यपि मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि यह अवाञ्छनीय परिणाम उत्पन्न हो, किन्तु फिर भी मैं इस बात को साधारण जनता और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नहीं सकता कि वास्तव में बराबर यही दुःखद स्थिति चली आ रही थी। बहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के विषय में हताश हो गये हैं। मेरे जैसे जन्मना लोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का शुरु जाना लज्जा की बात है। मैंने गरीब-से-गरीब मनुष्य के साथ अपनेको मिला देने और उससे अच्छी दशा में न रहने की तीव्र अभिलाषा अपने हृदय में रखी है, और उस सतह तक पहुँचने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किया हूँ। और इन कारणों से अगर कोई लोकतन्त्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वह दावा मैं करता हूँ।

“मैंने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उसने मेरा मौलिक मतभेद है। किन्तु मैं उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फलना अपने नैतिक दवाव से नहीं रोकना चाहता। मैं उन सिद्धान्तों को स्वतन्त्रता

के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता, कांग्रेस में रहकर सक्रिय विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती। यद्यपि अपने सार्वजनिक जीवन की लम्बी अवधि में मेरा बहुत-सी सस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए यह सक्रिय विरोध की स्थिति स्वीकार नहीं की है।

“इसके बाद देवी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं जो मेरी सलाह और मत के सर्वथा विरुद्ध है। मैंने चिन्ता के साथ घण्टो उसपर विचार किया है, किन्तु मैं अपना मत बदलने में सफल न हो सका।

“अस्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत-से कांग्रेसजनों से कदाचित् भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में बाधा डालकर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूँ कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो मैं अपने-तर्क सच्चा न रहा होता।

“अन्त में अब अहिंसा को लीलिए। १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह अवतक अधिकांश कांग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जबकि मेरे लिये वह एक मूल सिद्धान्त है। कांग्रेसवाले अवतक अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इनमें उनका कोई दोष नहीं है। उसके प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोषपूर्ण ढंग ही निस्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता, कि मैंने उसके दोषपूर्ण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल की है। पर अवतक जो कांग्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न अंग नहीं बन सकी इससे यही एक अनुमान निकाला जा सकता है।

“और यदि अहिंसा के सम्बन्ध में अनिश्चितता है, तो फिर सत्याग्रह के सम्बन्ध में तो वह और भी अधिक होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन और व्यवहार के बाद भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उसके सम्बन्ध में सब कुछ जानता हूँ। अनुसन्धान का क्षेत्र अवश्य ही परिमित है। मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माता, पिता, शिक्षक अथवा धार्मिक या लौकिक गुरुजनों की आज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर आ सकता है। इसपर आश्चर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विरोध होने के कारण, चाहे मैं किनारा ही अपूर्ण होऊँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझसे ही

सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाली भूलो और हानि को रोकने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ़ सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक था। परन्तु यहां भी कांग्रेसियों का दोष नहीं है। पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारतापूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में मुझे अधिकाधिक कठिनाई भालूम हुई है।

“इन प्रस्तावों पर अपने बौद्धिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिस कष्ट का अनुभव उन्हें हुवा होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीडा नहीं होती। जो हम सबका लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मैं और वे इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहें। इसलिए यह भी आवश्यक है कि सबको अपनी धारणा के अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतंत्रता रहे।

“सत्याग्रह-आन्दोलन स्वर्णित करने के बारे में पटना से मैंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था उसमें मैंने लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विफलता की ओर दिलाया था। अगर हममें पूर्ण अहिंसा का भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आडिनेन्स हमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे। वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोटने को बनाये गये थे। पर यह कहना गलत है कि सत्याग्रही दोष से परे थे। यदि बराबर हम पूर्ण अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रहती। हम आतंकवादियों को भी यह नहीं दिखला सके कि हमें अहिंसा में उससे अधिक विश्वास है जितना उन्हें हिंसा में है। बल्कि हमने से बहुतेरो ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उनकी तरफ हिंसा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही है कि हम हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते। आतंकवादियों की यह दलील युक्तिसंगत है कि जब दोनों के मन में हिंसा का भाव है तब हिंसा करना चाहिए या नहीं यह केवल मत का प्रश्न रह जाता है। यह तो मैं बार-बार कह ही चुका हूँ कि देश अहिंसा के मार्ग पर बहुत अग्रसर हुआ है, और यह भी कि बहुतेरो ने वेहद साहम और अपूर्व त्याग दिलाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मन, वचन और कर्म से विगुद्ध अहिंसक नहीं रहे हैं। अब मेरा यह परम-धर्म हो गया है कि मैं सरकार और आतंकवादियों दोनों को ही यह दर्पणवत् दिखला देने का उपाय ढूँढ निकालूँ कि अहिंसा में सही लक्ष्य को, जिसमें पूर्ण-स्वतंत्रता भी शामिल है, प्राप्त कराने की पूर्ण सामर्थ्य है। अहिंसात्मक साधन का अर्थ है हृदय-परिवर्तन, न कि बलात्कार।

“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अर्पित है, मुझे पूर्ण निस्वार्थ और स्वतन्त्र रहने की आवश्यकता है। सविनय-अवज्ञा जिस सत्याग्रह का एक अंगमात्र है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक नियम है। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा के द्वारा ही मैं उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्वतन्त्रता सत्य के अनुसन्धान में ही संनिहित है। सत्य की इस खोज को मैं न तो इस लोक के लिए स्थगित कर सकता हूँ, न परलोक के लिए। इसी अनुसन्धान के उद्देश्य से मैंने राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है और अगर मेरी यह बात बुद्धिवाली कांग्रेसियों की बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ जो सत्य का अंग हो, प्राप्त हो सकती हैं तो यह स्पष्ट है कि अब मैं अकेला ही काम करूँ और यह दुष्ट विश्वास रखूँ, कि जिस बात को आज मैं अपने देशवासियों को नहीं समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आजायगी या कदाचित् अपनी किसी ईश्वर-प्रेरित वाणी या कृत्य से मैं लोगों को समझा सकूँ। ऐसे बड़े महत्त्व के विषय में यन्त्र की तरह वोट देना अथवा आधे मन से अनुमति देना उद्देश्य सिद्धि के लिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा अपर्याप्त तो है ही।

“मैंने सामान्य लक्ष्य की बात कही है, पर मुझे अब इस बात में सन्देह होने लगा है कि आया सभी कांग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। मैं भारत के लिए पूर्ण-स्वाधीनता उसके मूल अंग्रेजी शब्द “कम्प्लीट इन्डिपेंडेंस” के पूरे अंग्रेजी अर्थ में ही चाहता हूँ। खुद मेरे लिये तो पूर्ण-स्वराज्य का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता से भी कहीं अधिक व्यापक है। पर पूर्ण-स्वराज्य भी अपना अर्थ स्वतः व्यक्त नहीं करता। कोई अकेला या सयुक्त शब्द हमें ऐसा अर्थ नहीं दे सकता जिसे सब लोग समझ लें, इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने स्वराज्य की अनेक व्याख्याएँ की हैं। मैं मानता हूँ कि वे सभी ठीक हैं और कदापि परस्पर विरोधी नहीं हैं। पर सबको एकसाथ मिला देने पर भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती हैं। किन्तु इस बात को अधिक विस्तार नहीं देना चाहता।

“मैंने जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है, उससे कितने ही कांग्रेस-वादियों के और मेरे बीच मत-भेद की एक और बात मेरे ध्यान में आती है। १९०८ से मैं बराबर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानार्थक शब्द हैं। इसलिए जहाँ साधन अनेक और परस्पर-विरोधी भी हैं वहाँ साध्य अवश्य भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा। साधनों पर सदा हमारा अधिकार और नियन्त्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं होता। पर यदि हम समान

अर्थ तथा ध्वनिवाले साधनों का उपयोग करते हो तो हमें साध्य के विश्लेषण में मायापञ्ची करने की जरूरत न होगी। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे कांग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते, उनका विश्वास है कि साध्य धृष्ट हो तो साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते हैं।

“इन सब मतभेदों ने ही कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल बना दिया है। कारण, जो कांग्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विश्वास किये बिना मुह से उसकी हामी भरते हैं वे स्वभावतः उसे कार्य में परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देश के सामने है—अर्थात् अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण भ्रष्ट-निषेध, चर्खा और लाठी तथा ग्राम्य-उद्योगी को पुनर्जीवित करने के रूप में सौ फी सदी स्वदेशी का प्रचार और भारत के ७ लाख गावों का संगठन। यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को तृप्त करने के लिए काफी होना चाहिए।

“मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि भारत के किसी गांव में, विशेषतः सीमा-प्रान्त के किसी गांव में, अपना डेरा जमा लू। खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिंसावादी होंगे तो अहिंसा-भाव की वृद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते हैं। अगर वे मन, बचन, कर्म से अहिंसावादी और हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रेमी हैं तो निश्चय ही उनके द्वारा हम इन दोनों कार्यों की सिद्धि देख सकते हैं जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। जिस अफगानी हीमा से हम इतना डरा करते हैं वह तब अतीत काल की वस्तु हो जायगा। अतः मैं इस दावे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होंने (खुदाई खिदमतगारों ने) अहिंसा-भाव को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लिया है और हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायों की सच्ची आन्तरिक एकता में वे विश्वास रखते हैं। मैं स्वयं उन्हें चर्खे का सन्देश भी आकर सुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा यही होगी कि इन तथा ऐसे अन्य प्रकारों से जो थोड़ी-बहुत सेवा कांग्रेस की मुझसे बन सके करता रहूँ, चाहे मैं कांग्रेस के अन्दर होऊँ या बाहर।

“अपने कार्यकर्ताओं में बढ़ते हुए दूषण की चर्चा मैंने अन्त के लिए रख छोड़ी है। इसके विषय में अपने लेखों और भाषणों में मैं काफी कह चुका हूँ। पर यह सब होते हुए आज भी मेरे विचार से कांग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था है। उसका जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है। अपने जन्मकाल से ही उसने जितने तूफानों का सफलता के साथ सामना किया

उतना किसी और सत्स्था को नहीं करना पडा। उसके आदेश ने लोगो ने इतना अधिक त्याग किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है। सच्चे देशभक्त और उज्ज्वल-चरित्रवाले स्त्री-पुरुषो की सबसे बड़ी सत्स्था आज कांग्रेस के अनुयायियो में है। अतः यदि ऐसी सत्स्था से मुझे अलग होना ही पडे तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल कचोटने का भारी कष्ट, विछोह की असहनीय पीडा न सहन करनी पडे। और मैं अभी ऐसा कहूँगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर मैं देश की अधिक सेवा कर सकूँगा।

कुछ संशोधन

“मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयो की चर्चा की है उनको कार्य-रूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करें। पहला संशोधन जो मैं पेश करूँगा वह यह होगा कि ‘उचित और शान्तिमय’ शब्दों के बदले ‘सत्यतापूर्ण’ और ‘अहिंसात्मक’ शब्द रखे जायें। मैं ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिमय के बदले इन दो विशेषणों का सरल-भाव ने मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए।

दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बबले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा बटा हुआ २००० तार (एक तार = ४ फुट) सूत हर महीने देने की रक्खी जाय और वह सूत मतदाता खुद चखें या तम्मली पर कातकर दें। अगर किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उनको कातने के लिए काफी रई दी जाय ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके। इसके पक्ष और विपक्ष की दलीलें यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सचमुच लोकनम्रात्मक सत्स्था बनना है, और गरीब-ने-गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए कम-से-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। वह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्खा चलाना कम-से-कम परिश्रम के माय-माय सबसे अधिक आदरणीय कार्य है। यह वालिग-मताधिकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता है और उन सबके बूते की बात है जो अपने देश के नाम पर आध घंटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं। क्या पड़े-लिखो और सम्पत्तिवानों ने यह आशा करना बहुत है कि वे भ्रम के गौरव को स्वीकार करेंगे और इस बात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूल लाभ कितना होता है?

क्या पश्चिम विद्याध्ययन की भांति स्वतः अपना ही पारितोषिक नहीं है? अगर हम लोग वास्तव में लोकसेवक हैं, तो हम उनके लिए चर्खा चलाने में गौरव का अनुभव करेंगे। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की उस बात का मैं स्मरण दिलाता हूँ जो वह प्रायः अनेक सभामंचों से कहा करते थे, अर्थात् तलवार जिस प्रकार पाशाविक शक्ति और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्खा या तकली अहिंसा, सेवा तथा विनम्रता का प्रतीक है। जब चर्खा राष्ट्रीय-मताका का एक अंग बना दिया गया तो अवश्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्खों की आवाज गूजेगी। वास्तव में अगर कांग्रेसवाले चर्खों के सन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय झंडे से हटा देना चाहिए। और कांग्रेस के विधान से खादी की धारा निकाल देनी चाहिए। यह असंभव बात है कि खादी की शर्तों का पालन करने में निर्लज्जपन से खोसा दिया जाय।

“तीसरा सशोधन जो मैं पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक बराबर कांग्रेस-रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आवतन खादी पहननेवाला न रहा हो। खादी की धारा को कार्यान्वित कराने में भारी कठिनाइयों का सामना पड़ा है। यह मामला आसानी से इस प्रकार तय किया जा सकता है, कि कांग्रेस के सभापति के पास अपील करने का अधिकार देते हुए भिन्न-भिन्न कमिटियों के सभापतियों पर इस बात का फैसला करने का भार छोड़ दिया जाय कि वे यह देखें कि मतदाता आवतन खादी पहननेवाला है या नहीं। नियम के अर्थ में वह आवसी खादी का आवतन पहननेवाला न समझा जाय, जो वोट देने के समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः खादी-वस्त्रों में न हो। किन्तु फिर भी किसी नियम से वह सन्तोषजनक फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसका पालन अधिकतर लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी और कड़ाई से काम क्यों न लिया जाय।

“अनुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० प्रतिनिधि होते हुए भी कांग्रेस इतनी बड़ी हो जाती है कि अलीभांति कार्य-संचालन करना कठिन हो जाता है। व्यवहारतः कभी पुरे प्रतिनिधि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शरीक नहीं होते। और फिर जबकि कांग्रेस के सदस्यों की सूचिणा कहीं भी अमली नहीं होती, तब ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं? इसलिए मैं यह मनोधन चाहूँगा कि प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर ऐसी कर दी जाय जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटों के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना जाय।

इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की सख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हों। यह कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है जो पूरी न हो। ३५ करोड़ की जन-सख्यावाले देश के लिए यह अविक नहीं है। इस संगोषण के द्वारा कांग्रेस को जो वास्तविक लाभ होगा, उससे सख्या-बल की क्षति-पूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के ऊपरी छोट-घाट की रखा दर्शकों के लिए उचित प्रवन्ध कर केकी जायगी, और स्वागत-समिति को अत्यधिक संख्यक प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था करने में जिस व्यय की परेशानी का सामना करना पड़ता है उसने छुटकारा मिल जायगा। यह बात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका लोकतन्त्रात्मक रूप और उसका प्रभाव इस कारण नहीं है कि उसके बापिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक संख्या होती है, बल्कि इस कारण है कि कांग्रेस ने देश की सतत वर्द्धमान सेवा की है। पश्चिम का लोकतंत्र अगर सर्वथा निष्फल नहीं हो गया है, तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्यों न भारत लोकतंत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को प्रत्यक्ष प्रकट कर दे? अस्पृष्टता तथा दम लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए, यद्यपि आज यही बात देखने में आ रही है, न बहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। थोड़े आदमियों द्वारा उन सब लोगों की आवाज, महत्त्वावाजा तथा मावनाओं का प्रकट करना, जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है। मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विकास वर्ण-प्रयोग से नहीं हो सकता। लोकतंत्र का सच्चा भाव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से उत्पन्न होता है।

“मैंने यहाँ विधान में करने योग्य संगोषण पेश किये हैं। ऐसे और भी प्रस्ताव होंगे जो उन बातों का, जिनकी चर्चा मैंने की है, स्पष्टीकरण करेंगे। मैं अपने इस वक्तव्य को उन प्रस्तावों की चर्चा करके बढ़ाना नहीं चाहता।

“भूझे आशा है कि जिन संगोषणों का मैंने उल्लेख किया है वे भी वर्द्ध-कांग्रेस में शामिल होनेवाले कांग्रेसियों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवें। परन्तु यदि कांग्रेस की नीति का सचालन मेरे जिम्मे रहे, तो मैं इन संगोषणों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल हों, देश के न्याय की प्राप्ति के लिए बलि आवश्यक समझता हूँ। जिन किन्हीं मस्या की सदस्यानी त्वेच्छा पर निर्भर करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जबतक उनके सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश्य निश्च नहीं हो सकता और जिस नेता

का अनुसरण उसके अनुयायी क्षुद्र भाव से, पूरे मन से और बुद्धिपूर्वक नहीं करते वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं उसके लिए तो यह बात और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं। कांग्रेसजनों को चाहिए कि आन्त भाव से उसके गुण-दोष पर विचार कर लें। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकबुद्धि के अनुसार ही कार्य करें।”

वर्म्बर्ड-कांग्रेस

२६ से २८ अक्टूबर (१९३४) तक वर्म्बर्ड में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के पहले से ही कांग्रेस-विधान में होनेवाले अन्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी।

अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी ने अपने सचोबनों को दो विभागों में बांट दिया, अर्थात् कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी सचोबनों को तो आपने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्बन्धी सचोबनों के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस बात की परवाह होगी कि कांग्रेस उसके नये समापति व उनके साधियों में विश्वास रखती है या नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परिवर्तनों-सहित दोनों प्रकार के सचोबन स्वीकार कर लिये और स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यतः स्वीकार कर लिया, जिससे गांधीजी सन्तुष्ट हो गये। गांधीजी के मूल-मसविदे में कांग्रेस ने जो-जो परिवर्तन किये उनकी तफ्तील देने की यहा जरूरत नहीं। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय-परिवर्तन के प्रस्ताव के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे आन्तीय कांग्रेस-कमिटियों के पास सम्मति के लिए भेजा जाय। ‘शारीरिकश्रम’ की अर्त केवल उन्ही कांग्रेस-सदस्यों तक सीमित रखी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव में खड़े हो। आदतन खादी पहनने की धारा ज्यों-की-त्यों मान ली गई। कांग्रेस-प्रतिनिधियों की संख्या २००० से अधिक न होना तय हुआ, जिसमें १४८९ प्रतिनिधि ग्राम्य-क्षेत्रों के और ५११ शहर-क्षेत्रों के रखे गये। महासमिति के सदस्यों की संख्या बांधी कर दी गई। प्रतिनिधियों का चुनाव ‘५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि’ के हिसाब से रखा गया, न कि १००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से, जैसा कि गांधीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी ने मूल-मसविदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियों की संख्या ठीक कांग्रेस-सदस्यों की संख्या के हिसाब से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रतिनिधियों

की हँसियत अब एक घूम-धड़ाके से होनेवाले सम्मेलन के दर्शको की-सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की-सी हो गई, जिनका कर्तव्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिणी अर्थात् महासमिति व प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों का चुनाव करें। गांधीजी के मसविदे का शेष भाग लगभग ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया।

लेकिन कांग्रेस का नया विधान या पार्लमेण्टरी वोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एवं साम्प्रदायिक-निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के मार्कों के निर्णयों में से नहीं थे, हालांकि ये स्वयं कुछ कम महत्त्व के निर्णय न थे। तथापि अधिवेशन की मुत्थ घटना, यद्यपि उसकी ओर लोगों का ध्यान कुछ कम आकर्षित हुआ, अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग सघ की स्थापना थी, जिसके बारे में यह निश्चित हुआ कि वह गांधीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा और राजनैतिक कहलाई जानेवाली हलचलों से अलग रहेगा। खहर के कार्यक्रम की पूर्ति का यह युक्ति-युक्त परिणाम ही था। गांव व देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए जिन ग्राम्य-उद्योगों की आवश्यकता होती है खहर तो उनका अगुवा-मात्र ही है। किसी राष्ट्र की सम्यता का ठीक-ठीक पता-ठिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही होता है।

वैज्ञानिक आविष्कारों पर तो सारे ससार का एकसा अधिकार होता है। ज्ञान भी किसी एक राष्ट्र व व्यक्ति की बपीती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी में तो हमें उस राष्ट्र की आत्मा ही बोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का कला-कौशल व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो ब्यक्तित्व ही मानो जाता रहा। वह राष्ट्र पशुओं की भांति जीता रहे यह बात दूसरी है, लेकिन उसकी सृजनात्मक-प्रतिभा तो सदा के लिए विदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भावना ही नहीं। इसलिए जब गांधीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों को पुनर्जीवन देने का बीड़ा उठाया तो मानो उन्होंने भारतीय सम्यता के पुनरुद्धार, भारत की आर्थिक समृद्धि के पुनरागमन और भारत की राष्ट्रीय शिला-पद्धति की पुनर्रचना का ही बीड़ा उठाया।

गांधी जी अलग होगये

अब हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवतः बम्बई-अधिवेशन की सबसे मार्कों की घटना है, अर्थात् गांधीजी का कांग्रेस से अलग होना। हालांकि इस सम्बन्ध में गांधीजी ने जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगों

ने अधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन उन्हें धीम्र ही पता भी चल गया कि गांधीजी जो-कुछ भी कहते हैं वह सदा ठीक ही कहते हैं और जो-कुछ भी कहते हैं उसे मदा करते हैं।

वास्तव में यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्रों को एकदम सन्नाटे में ही डालनेवाली थी कि गांधीजी कांग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेंगे। तिसपर भी गांधीजी ने कांग्रेस के विश्वास-अस्ताव के साथ ही कांग्रेस को छोड़ा है और उसमें वापस आने के लिए कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तभी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वयं अपनेको इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने में से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपनेको इस प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व खट्टर, शुद्धता, सच्चाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने लगे। इसलिए कांग्रेस के बुद्धिवाली लोगों को अपने नेताओं को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व त्याग के आदर्श की प्राप्ति है—ऐसा आदर्श जिस तक पहुँचने के लिए हमें प्रति दिन कम-से-कम ८ घंटे मासिक के हिसाब से शारीरिक श्रम करना आवश्यक है और जिसका फल हमें कांग्रेस को अर्पित करना है। इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह शकत धारणा-सी बन गई है कि यह धारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व प्रभाव से बचाने के लिए रखी गई है। बात ऐसी नहीं है। शारीरिक-श्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों की सेवा के लिए कांग्रेस शत १४ वर्षों से ही वचन-बद्ध है। कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ खट्टर व ग्राम-उद्योगों में, सत्य व अहिंसा में, तथा देश के सामने रखे गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने की घोषणा कर दें तो कांग्रेसियों और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे। और फिर गांधीजी से बढकर समाजवादी और कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं बल्कि वास्तविक समाजवादी है—जिन्होंने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-बार नाते-रिस्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया? इसलिए कहना होगा कि श्रम-भताधिकार कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न है।

- गांधीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक बड़े बोझ के समान हैं जिनसे कांग्रेस दबी जा रही है, और जितना ही अधिक वह उस बोझ को कम करने या प्रयत्न करते हैं उतना ही वह बढता जाता है। यदि सक्रिय-अवजा प्रारम्भ करें तो वह करें, बन्द करें तो वह करें, और उसका संचालन करें तो वह करें। शुद्ध छोड़ें तो वह छेड़ें,

सुलह करे तो वह करे। हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई आर्डर दे तो गांधीजी। सच तो यह है कि इतने भारी बोझ के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोझ लदा हुआ था, भजवूत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति बढ़ती ही है, उसके स्वयं काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी की भावना भी बढ़ती है, उसमें आशा और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो और भी अधिक जबकि वह बुद्धिपुरुष अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाह-मशवरा देने और उसका पथ-प्रदर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार हैं। वह इसका आश्वासन दे ही चुके हैं। उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना है। किसी सत्ता की शक्ति उसके सदस्यों की सत्ता से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमें निहित रहती है, और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेवारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात् उसी अनुपात में, वह नैतिक शक्ति भी बढ़ती जाती है।

राजेन्द्र बाबू का भाषण

बम्बई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद के चातुर्य, कार्य-शक्ति व असाधारण दक्षता को कुछ कम नहीं है। कांग्रेस-अधिवेशन में पड़ा गया उनका अभिभाषण उन गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा सकता है जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं। आपने ध्वेत-धम (क्लाइट-धम) की तफसीलवार बड़ी विद्वत्तापूर्ण आलोचना की। कांग्रेस-कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लाभदायक थे।

राजेन्द्र बाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया — “भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों में सम्यन्ध-विच्छेद करके अलग पड़े रहेंगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो ही नहीं सकता, खासकर जबकि हमें उसे अहिंसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब तो उम घोषण का अंग करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का अंग बना है। स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पाश्चात्यिक-राज के लिए दूसरे राष्ट्रों में अपनी मर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं। स्वाधीनता में निगीली गुनहारी नहीं हो सकती, यहातक कि हमारा घोषण करनेवाले की भी चुराई नहीं हो सकती।

है, अगर सद्भावों के बजाय हमारे शोषक शोषण की नीति पर ही निर्भर रहें तब तो बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन की शक्ति अहिंसा है, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह देख ही चुके हैं कि कुछ हद तक समस्त ससार का लोकमत अहिंसा को मान चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि ससार के राष्ट्रों की सन्देश व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की सदिच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। फिर भारत अन्य देशों पर कोई मनसूबे नहीं बाध रहा है। उसे विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण बनी ही रहेगी, और चूँकि दूसरे देशों पर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह इस बात की वाशा तथा भाग तक कर सकेगा कि उसके प्रति भी कोई बुरी नीयत न रखे। और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की सदिच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियों तक को, यदि उनका उद्देश्य भारत को वर्तमान अस्वाभाविक हालात में पटक रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से डरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्फटिक की भाँति साफ व स्वच्छ है। यह मार्ग सक्रिय, सजीव, अहिंसात्मक सामूहिक प्रतिकार का है। हम एकबार असफल हो जायें, दो बार हो जायें, लेकिन एक दिन हम अवश्य सफल होंगे।

कड़ियों ने तो इस मार्ग पर चरकर अपना जीवन और अपना सर्वस्व तक निछावर कर दिया है। और भी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्बान कर दिया है। लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयाँ आवें तो हमें उनमें घबराना नहीं चाहिए और न हमें डर से या लालच से अपने सीधे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे अस्त्र बेजोड़ है, ससार हमारे इस बृहद्-प्रयोग की प्रगति को बड़े चाव और आत्मा के साथ देख रहा है। हमें अपने ध्येय पर अचल और अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। सत्याग्रह सक्रिय रूप में कुछ काल के लिए पछाड़ ला जाय यह बात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है। सत्याग्रह तो स्वयं ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लॉवेल ने कहा था —

“Truth for ever on the scaffold,
Wrong for ever on the throne,

Yet that scaffold sways the future,
And behind the dim unknown
Standeth God within the shadow,
Keeping watch above his own "

"सत्य नले ही जगतोत्तल में दिखे छटकना चूली पर,
और दिखे अन्याय शान ने उठा हुआ निहासन पर,
सूली का प्रिय सखा सत्य वह तो नी इन भावी का—
पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पूजित घर-घर।
सदा खड़े भगवान् रहेंगे तिनिराच्छन्न गगन में,
अपने प्यारों को बरू देने जन में और विजन में॥"

अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो कन्वर्ड-कांग्रेस ने २६, २७ व २८ अक्तूबर को अपने अधिवेशन में, जिसके रावेन्द्र बाबू सभापति और श्री के० एफ० नरीमन स्वागताध्यक्ष थे, पास किये।

कांग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मजूर किया गया जो कांग्रेस-समिति व महासमिति ने नई १९३४ में व उनके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास तौर पर पार्लियेमेंटरी-मोड, उसकी नीति व कार्य-क्रम, स्वशासन कार्य-क्रम, प्रवासी नास्तियों की स्थिति, शोकाग्रजान व स्वदेशी थे।

इसके पश्चात् राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की भावना विप्रगुण एक प्रस्ताव पास हुआ, जो इस प्रकार था:—

यह कांग्रेस राष्ट्र को उसके हजारों स्त्री-पुरुष, बूढ़े और जवान, गांधी व सहरो के सत्याग्रहियों के अंतरापूर्ण त्याग व कष्ट-महन के लिए बधाई देती है और अपने इस विश्वास को प्रकट करती है कि अहिंसात्मक असहयोग व सविनय-अवज्ञा के बिना देश में इतने मार्ग की सामूहिक जाग्रति का होना असम्भव था। इसलिए वहाँ वह इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि विधाय गौरीजी के औरों के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस बात में भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिंसात्मक उपायों की अपेक्षा, जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व नबलून दोनों के द्वारा आतंक-प्रयोग में ही होकर रहना है, अहिंसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ञा अविकल अच्छे साधन हैं।'

इसके पश्चात् एक प्रस्ताव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मरत्नी श्रीमती

कमला नेहरू की बीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गई और इस बात की उम्मीद की गई कि पहाड़ी स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा।

अ० भा० ग्रामोद्योग संघ

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग संघ के विषय पर खासी बहस और चहल-पहल रही और इस सम्बन्ध में निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया —

“चूँकि देश-भर में कांग्रेसियों के सहयोग से अथवा उनके सहयोग के बिना स्वदेशी के प्रचार का दावा करनेवाली बहुत-सी संस्थाएँ खुल गई हैं, जिससे लोगो के दिलों में इस बारे में बहुत भ्रम फैल गया है कि ‘स्वदेशी’ का स्वरूप क्या है, और चूँकि अपने आरम्भ से ही कांग्रेस का ध्येय सर्व-साधारण की प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चूँकि गांवों का पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है, और चूँकि ऐसे पुनर्निर्माण के लिए हाथ की कत्तई के मुख्य धन्वे के अलावा गांवों के लुप्त या लुप्तप्राय उद्योग-धन्वों का पुनरुद्धार करना अथवा उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूँकि हाथ की कत्तई के पुनरुत्थान जैसा काम सभी सम्भव है जबकि उसके लिए छुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जायें जो कांग्रेस की राजनैतिक हलचलो से पुष्क और स्वतन्त्र हों, इसलिए श्री जे० सी० कुमारप्पा को अधिकार दिया जाता है कि वह गांधीजी की सलाह और देख-रेख में कांग्रेस के कार्य के एक अंग के रूप में ‘अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ’ नाम की संस्था का निर्माण करें। उक्त संघ उक्त उद्योग-धन्वों के पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे अपना विधान बनाने, बन-समूह करने तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा।”

इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशों तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था —

“चूँकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर होनेवाली नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों के प्रदन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञ्छनीय है और चूँकि इन नुमाइशों व प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों के भार से बरी की जाती है। लेकिन चूँकि नुमाइशों व धूम-धड़ाके के प्रदर्शन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अंग हैं, उनके प्रदन्ध का कार्य अखिल-

भारतीय चर्खा-सच व ग्राम-उद्योग-सच के सुपुर्द किया जाता है। ये सस्थायें इन प्रदर्शनों का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर गांववालों का मनोरंजन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी हलचलों का दिग्दर्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आम तौर पर ग्राम-जीवन की छिपी शक्तियों को प्रदर्शित करना।”

अन्य प्रस्ताव

कांग्रेस पार्लमेण्टरी-बोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वयं बोर्ड ने ही एक प्रस्ताव-द्वारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूकि बोर्ड का निर्माण एक असाधारण स्थिति में हुआ था, यह वाञ्छनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सदस्य नामजद होने के बजाय निर्वाचित किये जाय करें और उसके बाद वह चुनाव के आधार पर बने। उसकी अवधि और शर्तें, जैसी उचित समझी जायें, उस समय तय कर ली जायें। बोर्ड ने अपना यह प्रस्ताव कार्य-समिति के पास सिफारिस के रूप में भेजा। कांग्रेस ने बोर्ड की सिफारिस स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी-बोर्ड १ मई १९३५ को भंग हो जाय और महासमिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव करे। निर्वाचित बोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर पार्लमेण्टरी बोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा बोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर, हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं।

खहर-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक् प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था —

“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेस-कमिटी के चुनाव के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कत्ती-बुनी खादी आधतन न पहनता हो।”

दम्बई-कांग्रेस में सबसे पहली बार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था —

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस-कमिटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार

खड़ा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक-श्रम न किया होगा जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० गज सूत के बराबर हो, या जो प्रति मास समय में ८ घंटे के बराबर हो। कार्य-समिति समय-समय पर प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियो तथा अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के बजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार किया जायगा।”

गांधीजी की अलहदगी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया जाय। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था —

“यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह दृढ़ मत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है और उनके इस आवासन पर सतोष प्रकट करती है कि उनका सलाह-मशवरा और पथ-दर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।”

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला और वह स्वीकार किया गया।

असेम्बली का चुनाव

बम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी-जान से कूद पड़ा। इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का संचार हुआ और मानो कुछ काल के लिए उन्हें अपनी मनचाही चीज मिल गई। देश का जिला-जिला और देश की तहसील-तहसील छान डाली गई। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने लगभग हरेक ‘साधारण’ क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निश्चय किया। जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर वण्मुसुम् चेट्टी खड़े हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेट्टी को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्धि की शर्तें तय करने के लिए ओटावा भेजा था।

साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने व्यापार-सन्धि की शर्तें तय कर डाली। ओटावा से लौटकर वह असेम्बली के अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का समर्थन तक प्राप्त था। मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर बॉविली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पार्लमेण्ट अर्थात् असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसीको चुनाव न लड़ना चाहिए। सरकारी अफसरों तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस सर चेट्टी के विरोधी सामी बैकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी बैकटाचलम ने सर पण्मुखम् के ऊपर जो विजय प्राप्त की, उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती। वास्तव में वह सरकार के ऊपर कांग्रेस की, जनसत्ता के ऊपर नैतिक-बल की, और ओटावा और ब्रिटेन दोनों के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में कांग्रेस ने और सब जगहों पर भी कब्जा कर लिया। मदरास-अहाते में ११ प्रादेशिक जगहें थीं, हरेक के चुनाव में कांग्रेस को डेर-की-डेर रायें मिली। बंगाल में कांग्रेस-नेशनलिस्टों ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्त-प्रान्त में भी कांग्रेस ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि वह सन् १९२६ में भी नहीं कर सकी थी। युक्त-प्रान्त में कांग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। बिहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आसाम में सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी। केवल पंजाब में ही कांग्रेस पिछड़ गई। वहां उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शूद्र-कांग्रेसी जगहें हैं। इन जगहों के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्टों की जगहें भी उसे प्राप्त हुईं। साम्प्रदायिक 'निर्णय' के प्रबल के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्ट हरेक बात में कांग्रेस के साथ थे।

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री तसदुक् बहमदख़ा शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता के लिए चुना, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार श्री अम्बर, शेरवानी व शशमल को लेकर कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अर्पित करके ये तीनों बीर अपने जीवन-काल में इस सत्तार से कूच कर गये। श्री शशमल कांग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे।

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी का कार्य

कांग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी को मुरु

हुआ, अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ के बारे में जो गवर्नी-मंत्र निकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड़ गया। श्री शरतचन्द्र वसु को नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वसु जब नजरबन्द थे तब भी वह असेम्बली के लिए निर्विरोध चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। कांग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई देसाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मोर्चेबन्दी की। श्री देसाई के बारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को बड़ी गौरव और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित मोतीलालजी ने कराई थी। आप कुछ काल तक बम्बई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों तक की तनिक भी परवाह न की जो स्वभावतः इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अवसर मिला ही करते हैं। कांग्रेस ने अपना दूसरा बार ब्रिटेन व भारत में हुए सिंघावती समझौते पर किया। ५८ के विरुद्ध ६६ रायों से असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर दिया जाय। (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो लज्जा-जनक-से-लज्जाजनक कार्य किया जा सकता है उसका यह समझौता एक उबलता उदाहरण था, जिसे भारत-मन्त्री व ब्रिटेन के व्यापार-मन्त्रालय के प्रधान ने आपस में किया था। समझौता तो किया था ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार की लूट को बाटने के लिए, पर उसको वे दिया गया बड़ा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का व्यापारिक समझौता'। वास्तव में यह बात थी कि नये सुधारों में व्यापारिक सरक्षणों के बारे में क्वार्टर पार्लियामेन्टरी-कमिटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जानेवाली थी, उनको अमल में लाने के लिए ही पहले से यह समझौता कर डाला गया था। समझौते में यह बात खुलासा तौर पर रखी गई कि "भारतीय-व्यवसायों को केवल इतना ही सरक्षण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे कि बाहर से जानेवाला माल भारत में लगभग उसी कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का बना माल यहाँ बिकेगा, और जहातक सम्भव होगा ब्रिटेन के बने माल पर कम महसूल लगाया जायगा। इलैण्ड के तथा अन्य विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण महसूल लगाये गये हैं या लगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन के माल को नुकसान पहुँचे। जब कभी किसी भारतीय-व्यवसाय को सरक्षण देने का

प्रश्न टैरिफ-बोर्ड के सुपुर्द किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर सके और अन्य फरीको की दलीलो का जवाब दे सके।

ब्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभी तक बिना चुगी के जाता रहेगा जबतक भारत में आनेवाले फौलाद और लोहे पर चुगी का कानून वर्तमान समय की भांति ही ब्रिटेन के अनुकूल रहेगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १९३५ को हस्ताक्षर हुए और बड़ी कौंसिल में इसकी चारो ओर से निन्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में ७४ और विपक्ष में ४६ राये आईं। सरनार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय हुई। इसके बाद न्याय के बाबल और २५ या ३० अन्य विषयों पर विजय प्राप्त हुई।

हमने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्टों की चर्चा जान-बूझकर अन्त में करने के लिए रख छोड़ी थी। निर्वाचन के समय जो प्लाइमथेपर या उसने अब ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्टों का रूप धारण कर लिया था। यह रिपोर्ट पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं-द्वारा पास की जा चुकी थी और अब यह कानून बन गया था। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद्द कराने के कारणों पर बड़ी कौंसिल ने जो प्रस्ताव पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई थी, उसे हम नीचे देते हैं।

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कौंसिल में जो दृग अस्तित्वार किया वह प्रान्तीय-कौंसिलों में अस्तित्वार किये गये दृग से भिन्न था। प्रान्तीय-कौंसिलों में सरकारी सदस्यों ने मत देने में भाग नहीं लिया, जो ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौंसिलों का भारतीय लोकमत ही प्रकट हो सके। परन्तु कौंसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव के विरोध में पेश किये गये संशोधनों के विरुद्ध सारी प्राप्त राये एकाग्र करने का निश्चय किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कांग्रेस ने इस योजना के जागर पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरकार में सिफारिश करने या जो अग्रिम प्रस्ताव पेश किया था, वह पाम हो जाता। पर बड़ी कौंसिल ने अग्रिम साह्व के संशोधन को पास कर दिया। मत लेने के क्रम इस संशोधन को दो चरणों में बाटा गया। इनमें से पहला चरण साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। और अग्रिम के संशोधन-स्वरूप कांग्रेस-पार्टी ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो पाम हुआ। उस संशोधन के पक्ष में कांग्रेस-पार्टी की ४४ रायें आईं। अना संशोधन नामक

होने के बाद कांग्रेस-पार्टी तटस्थ रही और श्री जिन्नाह के सशोधन का पहला अक्ष मूसलमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया।

श्री जिन्नाह के सशोधन के दूसरे और तीसरे भागों को एकसाथ रखा गया और बड़ी कांसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटों से अपनाया। सरकार के पक्ष में ५८ वोट आये। कांग्रेस-पार्टी ने सशोधन के पक्ष में राय दी और नामजद सदस्यों ने खिलाफ राय दी।

श्री जिन्नाह का सशोधन इस प्रकार था —

“यह कांसिल साम्प्रदायिक ‘निर्णय’ को, जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार करती है जबतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न होजाय।

“प्रान्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कांसिल की यह राय है कि वह अल्पजन्त असन्तोषजनक और निराशा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक बातें रखी गई हैं—जैसे खासकर बृहरी कांसिलों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, पुलिस के नियमों, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें है, जिनके द्वारा कार्यकारिणी और कांसिलों का नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जबतक इन आपत्तिजनक बातों को न हटाया जायगा, भारतीय लोकमत का कोई अंग सन्तुष्ट न होगा।

“अखिल-भारतीय सच कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में कांसिल की यह स्पष्ट राय है कि यह योजना जब से ही दोषपूर्ण है और ब्रिटिश-भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य है, इसलिए यह कांसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्राट् की सरकार को सलाह दे कि इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनावे। यह कांसिल इस बात पर जोर देती है कि यह स्थिर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस प्रकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेष्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने रखकर बिना विलम्ब भारतीय लोकमत से परामर्श करके स्थिति में परिवर्तन करे।”

श्री जिन्नाह के सशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, लॉ-मेम्बर के द्वारा, इस सशोधन को मी ज्वाइन्ट-पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को वैसा ही रद्द करने वाला समझा जैसा कांग्रेस-पार्टी द्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला

रद करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने श्री जिन्नाह के सशोधन का वर्णन करते हुए कहा —

“महोदय, मैं यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीवे, सच्चे और खुले आक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिन्नाह साहब का अप्रत्यक्ष और कौशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश्य भी वही है।

“मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वैसे देखने में तो यह आवे भाग पर आक्रमण है, पर असंख्यता में मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के सशोधन में और कांग्रेस-नेता के सशोधन में मूलतः कोई अन्तर नहीं है।”

जब रेलवे-बजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक बार हार खानी पड़ी थी। अनेक सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रबन्ध में सरकारी नीति के खूब बुरें उठाये। विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-ग्रान्ट को घटाकर १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में प्रसंगबग्न सरकार की वर्तमान नीति के बुरें उठाये और कहा कि यह नीति १९३० के तरीके के अनुसार चलती जा रही है। इस प्रकार नीति बदलने के कारण हैं (अ) राजनैतिक हलचल के समय सैनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना, (आ) भारतीय रेलवे में लगी गई विशाल पूंजी की रक्षा करना, (इ) भारतमन्त्री-द्वारा नियुक्त किये गये उच्च पदस्थ रेलवे-अधिकारियों के पदों की रक्षा की जिम्मेवारी लेना, (ई) सैनिक और अन्य कार्यों की बिना पर भविष्य में यूरोपियनों की मर्ती की व्यवस्था, (उ) रेलवे की नौकरियों में अधगोरो के हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय बिल में रेलवे को गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सूची में रखा गया है।

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दौरान में स्पष्ट कर दिया था, ‘विरोधसूचक’ प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारि थी। उनका प्रस्ताव ७५ रायों से पास हुआ। विपक्ष में केवल ४७ रायें आईं। किसी स्वतन्त्र देश में शासन-खर्च देने की इन्कारी-सूचक प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता। रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध में था, जो ८१ रायों से पास हुआ, विपक्ष में ४४ रायें आईं। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के भुत्ताफिरो के सम्बन्ध में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव लाद्य-पदार्थों पर रेलवे का महसूल

घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में ब्रिटिश-कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में था।

नयी योजना पर कार्य-समिति

नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १९३४ को हुई। समिति ने श्री वी० एन० श्यामल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह बड़ी कौंसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिंघारे थे। कार्य-समिति ने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया —

“चूँकि कांग्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया था कि ब्रिटिश-पेर में आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद्द कर दिया जाय और केवल विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तोषजनक हो सकती है,

“और चूँकि इस नामजूरी और विधान-कारिणी सभा की मांग को देश ने बड़ी कौंसिल के आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है,

“और चूँकि ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में ब्रिटिश-पेर की तजवीजों से भी गये बीते हैं और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी और असन्तोषजनक कहकर उनकी निन्दा की है,

“और चूँकि ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभुत्व और रक्त-शोषण को एक महँगे बोले से सुविधा-पूर्ण और स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई है, वर्तमान शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराबी और खतरा है,

“इसलिए इस समिति की राय है कि इस योजना को रद्द कर दिया जाय। यद्यपि वह भली-भाँति जानती है कि उसे रद्द कर देने का अर्थ है जबतक कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल जाय तब तक वर्तमान शासन-प्रणाली के, जो अन्यायी और अपमानकारी हैं, अन्तः लड़ाई जारी रखना। यह समिति बड़ी कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे इस सरकारी योजना को, जिसे मुघारों के नाम पर भारत पर लादा जा रहा है, रद्द कर दें। यह समिति राष्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य-सिद्धि के लिए कांग्रेस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन करे।

“यह कार्य-समिति जनता को, बड़ी कौंसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस केनेतृत्व के प्रति उसके विश्वास और आस्था के प्रदर्शन पर, बधाई देती है और कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेस-वादियों में अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना ध्यान निम्न कार्यक्रम को पूरा करने की ओर दे —

(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-कमिटियों का संगठन करना, (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना, और (३) जनता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और बराची-कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना।’

श्री सुभाषचन्द्र बसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता की मृत्यु पर थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी बन्धनों लगाई गई थी, उनपर कार्य-समिति ने क्षोभ प्रकट किया। समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई के साथ करें। कार्य-समिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गति-निर्वाचन के अवसर पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख पर दुबारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर की कि कांग्रेस की नीति बम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और समिति के अधिकांश सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस का पचासवां वर्ष

अब हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना है जो १९३५ में घटित हुईं। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक का यह अन्तिम अंश है।

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस बैठक में नागपुर के श्री अम्बेकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिडवाणी के परलोक-वास पर शोक-प्रकाश किया गया। इन दोनों सज्जनों ने बड़े कष्ट उठाये थे और देश की सेवा बड़ी लगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया। वह इस प्रकार है —

“इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण-स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जबतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे तब न बैठेंगे।

“इस उद्देश की सिद्धि में हम मन, वचन, कर्म से यथाशक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद्ध रहेंगे।

“मृत्यु और अहिंसा के दो आवश्यक गुणों को व्यक्त करने के लिए हम

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की वृद्धि करने और बिना जाति, वर्ण या सम्प्रदाय का भेद किये सबसे बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे।

(२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से बचेंगे और दूसरों को भी बचायेंगे।

(३) हम हाथ से कातने की कला को और अन्य ग्राम्य-उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और अपने व्यवहार में खदर और ग्राम्य-उद्योग की अन्य वस्तुएँ लायेंगे और दूसरी सारी चीजों को छोड़ देंगे।

(४) अस्पृश्यता का निवारण करेंगे।

(५) जिस तरह होगा, लाखों भूखों मरते हुए भारतवासियों की सेवा करेंगे।

(६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यों में भाग लेंगे।”

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय-दिवस में जहातक सम्भव हो कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय, और इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय। हुडतालें न की जायें। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आडिनेन्स या स्थानिक अधिकारी के हुक्म की अवहेलना न की जाय और न समा में भाग लिये जायें। राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय।

सम्राट् जार्ज के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वाभावतः ही कार्य-समिति का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ —

“सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत में सम्राट् की रजत-जयन्ती मनाई जायगी। इस अवसर पर जनता को कैसा खूब अस्तिभर करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्य-समिति पर्य-प्रदर्शन करना आवश्यक समझती है।

“कांग्रेस के मन में खुद सम्राट् के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता, न है ही, पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भूल सकती कि

भारत का शासन, जिसके साथ सम्राट् का स्वभावतः ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र की राजनैतिक, नैतिक, और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-व्यवस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रक्त-शोषण करने में, देश में जो-कुछ धन बचा है उसे खींच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राजनैतिक दासत्व की अवस्था में पटकने में सफल होगी।

“अतएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देना असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के विरोधी-प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुँचाने का निषेध करती है। इसलिए यह समिति जनता को, और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल हैं जो निर्वाचित सस्थाओं के सदस्य हों, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर ही सन्तुष्ट हो जायें।”

सूती मिलों के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दों में साफ़ की गई—“चूँकि अनिकाश सूती-मिलों के मालिकों ने कांग्रेस को दिये बचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समिति की सम्मति है कि कांग्रेस या उससे सम्बन्ध रखनेवाली सस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला काम रखना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद्द समझे जायें।

“कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखनेवालों का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कत्ते और हाथ से धुने कपड़े की ओर ही ध्यान दें और उसीकी उन्नति में सहायता करें।”

कार्य-समिति ने सशोधित-विधान की धारा १२ (ई-३) के अनुसार अनुशासन-भंग-सम्बन्धी नियम पास किये।

कांग्रेस के विधान में रखी गई ‘निवास-सम्बन्धी योग्यताओं’ के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्वारा स्पष्ट कर दिया।

इसके बाद कार्य-समिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की सुधार-योजना की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निश्चय किया कि वर्मा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी पहले की भाँति ही काम करती रहे।

ज्वाइन्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी की नई सुधार-योजना के अन्तर्गत बर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में समिति ने सम्मति दी कि चूँकि सारी योजना ही अस्थायी है, इसलिए कांग्रेस उसमें कोई संशोधन नहीं पेश कर सकती। पर इस योजना के जो अक्ष बर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नहीं है।

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आग्र के रायालमीमी के प्रदेश की दाब-पीड़ित जनता के कष्ट-निवारण के लिए धन की अपील करें।

७ फरवरी १९३५ को ज्वाइन्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विषय विवक्षित बनाया गया और इसके द्वारा एकबार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ही सभायें की गईं हो सो बात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में सभायें की गईं। इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था।

रणून में बर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी-द्वारा आयोजित प्रवर्णन भी अपने दम का निराला था, क्योंकि रिपोर्ट को रद्द करने की मांग पेश करने में बर्मा और भारत दोनों आपस में मिल गये थे।

साम्प्रदायिक समझौते की चर्चा

अब हमें उस मेल-सम्बन्धी बातचीत की चर्चा करनी है जो १९३५ की जनवरी और फरवरी में हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की बातचीत, जो साम्प्रदायिक 'मिर्चय' का स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्य और कट्टरता दूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकाबला कर सके, कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद और मुस्लिम-लीग के समापति श्री मूहम्मदअली जिन्नाह ने, एक महीने से भी अधिक दिनों तक चली रही। बातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनों के लिए धन्द रहकर फिर १ मार्च १९३५ तक जारी रही। पर इस बातचीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई।

दमन जारी

१९३५ में श्री सरकारी स्व या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रखी जा रही है और अग-

जरा-सी बात पर कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर आतंककारी कामों का सन्देह किया जाता है, उन्हें अब भी बिना मुकदमा चलाये जेलों में या घरों में नजरबन्द रखा जा रहा है और अकेले बगाल में ही उनकी संख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर बदा-क़दा मकानों की तलाशियाँ होती रहती हैं और महासमिति के तथा विहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस कमिटियों के दफ्तरों पर भी निगाह पड़ चुकी है। खान अब्दुल ग़फ़ार खाँ को दम्बई में भाषण देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले में एक साल का दण्ड दिया गया।

बगाल के नजरबन्दों की संख्या हजारों में है। उनके परिवार असहाय अवस्था में हैं। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया है। ये युवक कई वर्षों से बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखे गये हैं या निर्वासित हैं। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुभूति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिवारों और आश्रितों के कष्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। १६ मई का दिन हजारों आदमियों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए निश्चित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। बगाल की सरकार ने कांग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए इंडियन प्रेस (इमर्जेंसी पावर्स) एक्ट की धारा २ ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के आशानुसार देश भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द दिवस की देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय। बगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र प्रकाशन बन्द रखा।

महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक में कांग्रेस पार्लैमेण्टरी-बोर्ड और निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और हिसाब-किताब की जाच के लिए आधीटर नियुक्त किये। महासमिति ने श्री तसदुलक़व्वमदत्ता शेरवानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, वही कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर सतोष प्रकट किया, देश का ध्यान भीमान्त-प्रेक्ष में कांग्रेस-समस्या के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बगाल के मिदनापुर जिले की कांग्रेस-कमिटियों के निपिड़ रहने, और बगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी

वने रहने, और बगान, खम्बई, पंजाब और अन्य स्थानों में गजदूर और युवक-सघ की स्थापना के, केप्टन रंग बागार पर कि उन्हीं प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, चुनले जाने की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया, और जनता से अपील की कि कांग्रेस की शक्ति में उम्र नरक वृद्धि करें जिसमें वह देश का उद्धार करने के योग्य बन जाय।

महासमिति ने "फ़ोरेनर कानून" (Foreigners' Act) नामक पुराने कानून में दुरुपयोग का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को निर्वासित करने उन्हें ब्रिटिश-भारत में आकर निवास करने और कामकाज करने के कानूनी अधिकार का उपयोग करने में रूकित किया गया है।

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवकों को नजरबन्द रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बन-हीन हो गये हैं, और स्पष्ट उन परिचारकों के निर्वाह का प्रयत्न करने की निन्दा की। महासमिति ने सम्मति प्रकट की कि बंगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दों को छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बंगाल की जनता और उसके नजरबन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कष्टों के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति ने बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरबन्दों की पूरी सूची तैयार करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आर्थिक अवस्था में उसे सूचित करे। नजरबन्दों के परिवारों का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्य-समिति की अधीनता में भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया। फ़ीरोजाबाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ० जीवाराम का पूरा परिवार, बच्चों और कई रोगियों सहित, जीवित जला दिया गया था, और नेताओं का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उन्माद-पूर्ण सांप्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसे शोकजनक घटनाएँ हो सकती हैं। नेताओं से अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति भेल और आदर के भावों के साथ शान्ति और मैत्री-पूर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रबल चेष्टा की जाय।

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए देशी रियासतों की प्रजा के हित भी उत्तरे ही प्रिय हैं, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, और रियासतों की प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में कांग्रेस उनकी पीठ पर है।

इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-समिति की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की सत्या निश्चित की गई और महासमिति के सदस्यों और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न कांग्रेस-कमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। कार्य-समिति में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा किया गया और कांग्रेस और महासमिति में बगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस-संस्थाओं के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था।

क्वेटा का भूकम्प

१५ जनवरी १९३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी मुश्किल से १८ महीने बीते होंगे कि ३१ मई १९३५ को क्वेटा के भूकम्प ने देश-भर में शोक के बावल फैला दिये। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही था, पर कष्ट-निवारण और सगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आनेवालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमति न कांग्रेस के समापति को मिली, न गांधीजी को। इस परिस्थिति में केवल निषिद्ध-प्रदेश के आसपास के स्थानों पर ही सगठित सहायता की जा सकती थी। कांग्रेस के समापति ने क्वेटा-कष्ट-निवारक-समिति का सगठन किया, जिसकी शाखायें सिंध, पंजाब और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गईं। यह समिति क्वेटा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प में भरे हुए लोगों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरमसीमा थी। इस नीति ने कार्य-समिति को क्वेटा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया —

“हाल ही में भूकम्प के कारण क्वेटा और दख्खिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदमियों को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट करती है और कष्ट-पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है।

“यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और कष्ट-निवारण की व्यवस्था करने के लिए समिति बनाने के कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती है। यह समिति

क्वेटा के भूकम्प के घायल अथवा पीड़ित होनेवालों की बड़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने क्वेटे की अपील का जो उत्तर दिया है उसकी पहुँच स्वीकार करती है।

“क्वेटा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो चेष्टा की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गैर-सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्तव्यों के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम बीस दिन बाब बन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता की अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत-से आदमियों को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाला जा सकता था।

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि आधिकारिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जांच करने के लिए सरकार की ओर से सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत किया जाय—

(१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह वस्तु-स्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता दिखाई देता।

(२) इस सहायता की अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था।

(३) सरकार को परिस्थिति का अच्छी तरह सामना करने के लिए आस-पास के इलाकों से प्राप्त सहायता एकत्र करनी चाहिए थी।

(४) जबकि भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पूरा ध्यान दिया गया, भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया और बचाव, कष्ट-निवारण और बची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरोपियनों और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद-भाव किया गया।”

पद-ग्रहण का प्रश्न

१९३५ के मध्य में कांग्रेसवादियों को, विधेयकर उनको जो कॉमिल-प्रश्न पर अड़े हुए थे, एक और प्रश्न ने उद्धिम्न कर रक्खा था, और वह था नये पास्तन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि उस अवसर पर, जबकि विल अभी पार्लमेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसंग छेड़ा गया।

यह बात भी भूलाने-योग्य नहीं है कि कांग्रेस-वादियों के इस वर्ग ने अपना जो रख दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में विल था, पार्लमेण्ट को यह आश्वासन दिलाने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। बम्बई-कांग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में विलकुल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या रख है, और आगामी-अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसीको अधिकार न था। फलतः जुलाई के अन्त में वर्षा में कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकता है। उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ —

“भावी शासन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में अनेक कांग्रेस-कमिटियों के प्रस्ताव पढ़ने के बाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस प्रश्न को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा करती है कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेस-वादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझा जाना चाहिए।”

रियासतें और कांग्रेस

अभी विल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लमेण्टरी-बोर्ड नेता श्री भूला-भाई देसाई ने वकील की हैसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तर्गत सच-शासन के प्रश्न पर सलाह दी और फिर मैमोर में इस विषय पर भाषण भी दिया। इन बातों को लेकर हम वर्ष के आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिपद् में हलचल मच गई। जुलाई में देशी-रियासतों की प्रजा के प्रति कांग्रेस के रख पर विचार करने के लिए महासमिति की बैठक की मांग हुई। देशी-रियासतों की प्रजा ने अपनी मांग गांधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रखी थी, जो उन्होंने दूसरी गोलमेड-परिपद् के अवसर पर दिया था—“कांग्रेस ऐसे किन्नी शासन-विधान में सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी-राज्यों की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो और वे मध्य व्यवस्था-मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सकें।”

२६, ३० और ३१ जुलाई १९३५ को वर्षा में होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में हम विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्नलिखित निश्चित मन्त्रि प्रकट की गई —

“यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को प्रस्तावों-द्वारा प्रकट कर दिया गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उनकी ओर से कांग्रेस-

नीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की माग आग्रह-पूर्वक पेश की जा रही है। इसलिए कार्य-समिति देशी-नरेशों और देशी-राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित करती है—

कांग्रेस स्वीकार करती है कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार कांग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व-पूर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है, और न केवल देशी-नरेशों से ही अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और लेखों-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के अधिकार देने की अपील की है, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गये सघर्ष में उसकी सहायता है। कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। कांग्रेस समझती है कि यह स्वयं देशी-नरेशों के ही भले के लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दें, जिससे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।

पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का सघर्ष जारी रखने का बोल स्वयं देशी-राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव डाल सकती है और, अहा भी हो, डालने पर बाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामर्थ्य कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अंग्रेजों के अधीन हो चाहे देशी-राजाओं के और चाहे किसी और सत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की बात भुला दी जाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अंगीकार करने में दोनों का उद्देश ही विफल हो जायगा।

आगामी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों के विषय में सुझाया गया है कि कांग्रेस भारत-शासन-विधान के उस अंग में, जिसमें देशी रियासतों के और भारतीय-सभ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, सलोचन कराने पर जोर दे। कांग्रेस ने एक से अधिक बार शासन-सुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप नहीं है, रद्द कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा के द्वारा

हो। ऐसी दशा में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अंश के सशोधन के लिए नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा।

साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस देशी रियासतों की प्रजा के हितों का बलिदान करने का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की अवस्था में जनता के हितों के लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है।”

अन्त में यह निश्चय किया गया कि चूँकि १८८५ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसका पचासवा वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य-समिति ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। वर्षों की बैठक और वर्षों की समाप्ति के बीच में जो थोड़ा-सा समय रहा उसमें तीन घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष बात न हुई। उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोडा-जेल से छोड़ दिये गये। उनको फौरन यूरोप को रवाना होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लौट आये तो, जैसा कि आशा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवर्नर-जनरल-द्वारा सितम्बर में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि यही कौंसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद्द कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण या स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अक्टूबर १९३५ की महासमिति की बैठक थी, जो मद्रास में हुई। आशंका थी कि ‘पद स्वीकार करने’ और ‘कांग्रेस और देशी-राज्यों के प्रश्न’ पर होने वाले से आक्रमण किया जायगा। यदि हम कांग्रेस-अधिवेशन के मार्ग हुई बैठक को छोड़ दें, तो मद्रास में महासमिति की यह पहली बैठक थी। मद्रास में देशी-राज्यों के प्रश्न पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमति प्रकट की गई और पद स्वीकार करने के प्रश्न पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विधान के अनुसार प्रांतीय कौंसिलों का निर्वाचन आरम्भ होने में बहुत देर है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी अनिश्चित है, इसलिए इस विषय पर कांग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूल भी नहीं होगा और राजनैतिक दृष्टि से अविवेक-पूर्ण भी होगा।

मद्रास की महासमिति की बैठक के मिलमिले में एक माघाग्न घटना का

जिक्र करना आवश्यक है। महासमिति के बंगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गई कि उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति न मिलेगी, क्योंकि बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने अपना ५०० का चन्दा पूरा जमा नहीं किया है। कार्य-समिति ने बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की कार्य-कारिणी को एक यह भी नोटिस दिया कि कार्य-समिति ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-कांग्रेस-कमिटी को मानने के सम्बन्ध में जो हिदायत दी थी उसका ज्ञान-वृक्षकर उल्लघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाते की कार्रवाई क्यों न की जाय, इसका वह कारण बताये।

नया शासन विधान

अब अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पार्लमेण्ट ने भारत-शासन-विधान पास कर दिया और २ जुलाई को उसे सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विषय की आलोचना करके हम पुस्तक को मोटी नहीं बनाना चाहते। हा, हम कामन-सभा के एक सदस्य के भाषण का, जिसके बाद वह सत्र समाप्त हो ही गई, उद्धरण देने के प्रलोभन को नहीं रोक सकते। ५ जून १९३५ को मेजर मिलनर ने इण्डिया-विल पर बोलते हुए मि० चर्चिल और सर सेम्युअल होर की तुलना नाटक के नायक और उपनायक से की। उन्होंने कहा—“नायक (सर सेम्युअल होर) ने शठ उप-नायक को हरा दिया है। आज (५-६-३५) वह बिना रक्त-पात किये ही उसका काम तमाम कर देगा।” इसके बाद मेजर मिलनर ने कहा—“और तब दोनों प्रति-पक्षी बाह-में-बाह डाले रगमच का द्वार छोड़ते दिखाई देंगे।” वास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में भी रचा गया था। बने आम तौर से यह बात ठीक है कि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही है, और वह यह कि एक ऐसा चित्र तैयार करें जो, ‘मैन्नेस्टर-ग्राजियम’ के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रतीत हो और इंग्लैण्ड को ब्रिटिश-राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं में लड़ाई का स्वाग रचते हैं, उनमें से कुछ देने का ढोंग दिखाते हैं और बाकी प्रतिरोध करने का। इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलवालों को यह कहकर राजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही है, जो मिले ले लो, क्योंकि दूसरा तो उतना भी नहीं देना चाहता। अधिकार-मम्भ्र दल नायक का पार्ट खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का। दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई का स्वाग रचते हैं, और ज्योंही वे बाहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कृत्रिम-युद्ध को

बढिया प्रकृत रूप देने की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इन दोनों के बीच में भारत को बुद्ध बनाया जाता है।

कांग्रेस-समापति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बढ़ते हुए भाव का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल देते आ रहे हैं। श्रीमती वेंसेण्ट ने सालभर तक अपने समानेव्री बने रहने की सूक्ष्म पर जोर दिया था। तबसे इस बात पर उनके उत्तराधिकारी अमल करते आ रहे हैं। दो-एक अध्यक्षों को छोड़कर, जो कांग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायब हो गये, बाकी सबने अपना कर्तव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के अनुरूप ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और कष्ट-सहिष्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढंग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला और इस प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया। बिहार-भूकम्प-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम रहता है। इसके अलावा कांग्रेस के समापति की हँसियत से उन्हें कर्तव्य-पालन करना पड़ता है। और फिर क्वेटा के भूकम्प के काम ने उनके कामों में और भी वृद्धि कर दी। इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्यप्रान्त के एक भाग, तामिलनाडु, आंध्र और केरल का दौरा कर डाला। अखिल-भारतीय चर्खा-सत्र से भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्तनवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है। गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, राजेन्द्र बाबू के कंधों पर रखी बोझ और भी बढ़ गया— क्योंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जब तक गांधी जी मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिए हलका था। इसका यह मतलब नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने कर्तव्य की अवहेलना की हो, पर असली बात यह थी कि गांधीजी-जैसे व्यक्ति सार्व-जनिक जीवन के भारी कार्यों का बोझ अपने सहयोगियों के लिए बहुत कम छोड़ने हैं। इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों का भार आ पड़ा है। हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस देश में सरकार के मुकाबले ऐसी संस्था बन गई है जिसका अपना एक आदर्श है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी आभोगति की योजनाओं से

सरकारी योजनाओं ने होठ लगा रखी हैं, जिसके सत्य और अहिंसा के उसूलों की सरकार की ओर से, जो भौतिक बल पर निर्भर करती है, बुराई और बदनामी की जाती है।

कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही है और इसकी सफलता की सराहना की गई है। कुछ लोग इसे असफल बताते हैं। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है जो कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही ली जा रही है। पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी ओर काफी आकर्षित हो चुका है। इन आदसों में परिवर्तन और साधनों में संशोधन करने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु के रचनात्मक-भाग में देश से बाहर दक्षिण-अफ्रीका में रहता था और एक अपरिचित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। लोग पूछते हैं—क्या कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं हुई, क्या सत्याग्रह को आका गया और वह अधूरा नहीं उतरा, और क्या गांधीजी की शक्ति समाप्त नहीं हो गई? इन सब प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देने के बाद ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे।

: ४ :

उपसंहार

१

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था

कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके। इस काल के दूसरे अर्धश की चर्चा पहले अर्धश की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार के साथ की गई है। इस दीर्घकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादाभाई नौरोजी ने तीन बार कांग्रेस का सभापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोष में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया। प्रथम राष्ट्रपति उमेशचन्द्र बनर्जी एक बार फिर सभापति हुए। बंगाल के जेए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को दो बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल वल्लभ-वस्त्र-धारी प० मदनमोहन मालवीय और प० मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरबर्न का हुआ। बदरहीन तैयबजी, रहीमतुल्ला सयानी, नवाब सैय्यद मुहम्मद बहादुर, हसन इमाम, अबुलकलाम आजाद, हुकीम अजमलखा, मौ० मुहम्मदअली और डॉ० अन्सारी—कुल ५१ में से ८ मुसलमान सभापति हुए। दादाभाई नौरोजी और फीरोजशाह मेहता उस श्रेष्ठ जाति—पारसियों—के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक और इस्लामिक संस्कृति में अपनी—जरतुस्त—संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है। उमेशचन्द्र बनर्जी, जानन्दमोहन बसु, रमेशचन्द्र दत्त, लालमोहन बोष, भूपेन्द्रनाथ बसु, सत्येन्द्रप्रसाद सिंह, अम्बिकाचरण भुजुमदार, चित्तरञ्जन दास और सुभाषचन्द्र जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे आगे है। युक्तप्रान्त ने विश्वनारायण द्वार, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और उनके सुपुत्र जवाहरलाल को दिया। राजेन्द्रबाबू विहार के हैं, जहाँ के हसनइमाम पहले सभापतित्व कर चुके हैं। पंजाब को लाला लाजपतराय के सभापति बनने का गौरव प्राप्त है और मध्य-प्रान्त को श्री भुधोलकर के सभापतित्व का। गुजरात के गांधीजी और वल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं। चम्पई तो मानो इसका मण्डार ही रहा है—तैयबजी और सयानी ही नहीं, फीरोजशाह मेहता भी यहीं के थे। बाबा, रोखले और चन्दावरकर

(बम्बई के) पश्चिमी प्रान्त के थे। मदरास ने आन्ध्र के आनन्द चार्ल्स को और केरल-पुन सर शकरन नायर को दिया और अन्त में दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्य तथा श्रीनिवास आयंगर को प्रदान किया जो दोनों तामिलनाडु के हैं। श्रीमती वेसेण्ट और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रिया भी सभापति-पद को सुशोभित कर चुकी हैं। और श्री यूल, वेव, बेडरबर्न व हेनरी काटन के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया है। इस विविध सूची से जाहिर है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय बल्कि सचमुच एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है।

कांग्रेस की सफलता

अब प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस असफल रही? इस बात से शायद ही कोई इन्कार करे कि पिछले दस वर्षों में पुरातन राजनैतिक और सांस्कृतिक विचारों के क्षेत्र में नित्य नये विचारों का जन्म होता रहा है। राजनीति सच छुछिपे तो मानव-कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे ससार में इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक जैसी बृहत्तर समस्याओं के अध्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमें सांस्कृतिक और नैतिक विचारों को भी मिला दें तो फिर राजनीति उन्नीसवीं शताब्दी के गहिरे पद पर न रह कर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुँचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षों में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करमचन्द गांधी जैसे विश्व-वन्द्य व्यक्ति को है जिसकी अमेरिका का वर्णन प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने निम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दों में किया है —

“ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो साधारण वासनाओं की रस्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की, बल्कि जो उस काम को करने का निश्चय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसा आदमी भयंकर और दुःखदायी शत्रु है, क्योंकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तुम्हारा जरा भी कब्जा नहीं होसकता।”

ऐसे ही आचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने की चेष्टा की है, उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश-भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है, और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उद्योग किया है। वस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म। यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चाहें तो हम किसी भी मानवी प्रश्न को धर्म की

परिधि के बाहर नहीं मान सकते। क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या उपासना के ढंग का नाम नहीं है, बल्कि उच्चतर जीवन, बलिदान की भावना और आत्म-समर्पण की एक योजना है। और जब हम राजनीति-धर्म की बात कहते हैं तो हम वर्तमान गहिम राजनीति को पवित्र बना देते हैं, सकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं, और प्रतिद्विधापूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं।

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य और औचित्य का पक्ष-समर्थन किया है। जीवन में असत्य सदा ने शीघ्र और सस्ती विजय प्राप्त करता आया है और पाखण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर अक्सर विजय प्राप्त की है। यही क्यों, इतिहास में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन तक पर विजयें प्राप्त की हैं। पर ये विजयें आशिक और क्षणभंगुर हैं और इन्होंने विजेताओं को हमेशा कष्टाजनक अवस्था में ला पटका है। बड़े पैमाने पर देखा जाय तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमा सके। छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की 'विजय' ने इंग्लैण्ड को स्थायी सुख प्रदान नहीं किया। विभिन्न गोलमेज-परिषदों का आयोजन करने में राजनीति-विधायकों ने जिस नीति से काम लिया उसके फल-स्वरूप वे भारत को इंग्लैण्ड-रूपी प्रासाद का झोपड़ा बनाने के उद्देश्य में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक लहर ने स्वयं दमन करने-वालों के हितों को खतरे में डाला और जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याग्रह—सविनय-अवज्ञा—के रूप में प्रकट होती है, कभी उगती और उठती हुई पीढी के हाथों में अधिक कठोर और भीषण रूप धारण कर लेती है। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं, क्योंकि दूर तक दृष्टि दौड़ाकर देखा जाय तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो वह सफलता की दिशा में एक आगे का कदम ही है। और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओं का अन्तिम पटाक्षेप है।

हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कसते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पहलू हैं। उसके आक्रमणकारी पहलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ युद्ध करने में जो ढग अपनाया उसे कोई सम्य सरकार बुरा नहीं कह सकती। इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, वचन, कर्म से अहिंसाव्रत का पालन रहा है और गांधीजी को भारत का 'धीफ-कान्स्टेबल' माना गया है। सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह को बदनाम करने की चेष्टा भले ही की हो, पर जनता के साथ और अहिंसा-प्रेम की निन्दा

कौन कर सकता है ? यह वह युग है जिसमें राजवंश नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं, सिंहासन उलट दिये गये, और प्रतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भग होना पड़ा है। यह वह युग है जिसमें दो दलों और तीन दलोंवाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा हो गई और विरोधी-दल को निर्वाचनों के द्वारा नहीं दबाया जाता बल्कि सचमुच उसका विनाश किया जाता है। इस युग में अहिंसा की बात कहना दिल्ली-सा प्रतीत होगा। रक्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवल रक्तपात-द्वारा ही स्थायी रक्खी जा सकती है और उसी के द्वारा छिन भी जाती है, और जब दो देशों के बीच में हिंसा निर्णायक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियों या दो व्यक्तियों के बीच में भी अवसर मिलते ही घुस बैठती है।

रचनात्मक पहलू

अब कांग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को लीजिए। वह सरल रहा है, इतना सरल कि विश्वास न हो। हम यह बात स्वीकार करते हैं कि यह कार्यक्रम देश की उन अ-सरल श्रेणियों को पसन्द न हुआ होगा जो कस्बों और शहरों में रहती हैं, विदेशी कपड़ा पहनती हैं, विदेशी मापयें बोलती हैं और विदेशी मालिक की चाकरी करती हैं। हमारे नगरों की मर्दमबुमारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, उन्हें देखकर आश्चर्य होगा। तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी आजीविका, अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासकों की सक्षिप्ता पर निर्भर करता है। ये बातें तत्काल ही दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वास्तव में हमारे मालिक कौन हैं। हम तो यही जानते हैं कि पुलिस के सिपाही से लगाकर आवकारी के दरोगा तक और बैंक के एजेंट से लगाकर अग्रेज वर्गी तक, सभी हमारे मालिक हैं। पी० डब्लू० डी० का कर्मचारी, अमीन, मजिस्ट्रेट और विल बनानेवाला—ये सब ब्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेड के अवैतनिक कर्मचारी-मात्र हैं। इस कम्पनी का स्थानिक संचालक-मण्डल भारत-सरकार है, जिसके मातहत-वफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं। अग्रेज सरकार सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों, अदालतों, कौंसिलों, कॉलेजों, स्थानिक सस्थाओं और उपाधिधारियों के सात परिवेष्टनों से घिरी हुई है। देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण आबादी अमीनों और पटवारियों के भय से सन्नत रहती है, और बाकी गहरी आबादी म्युनिसिपैलिटियों, स्थानिक बोर्डों, इन्कमटैक्स-अफसरों और आवकारी-विभाग के अधिकारियों से भयगीत रहती है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक

हो गया है कि भौतिक बल के बोध से उत्पन्न हुए भय को निकाल फेंका जाय और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक अहिंसा-प्रेम से उत्पन्न होता है। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यों का रूप धारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेस-वादी जनसाधारण के सम्पर्क में आते हैं। फलतः जब हम खहर का जिक्र करते हैं तो हम न केवल निर्वन आदिमियों के लिए सहायक-बधा ही उत्पन्न कर देते हैं, या उनके जीवन-निर्वाह-योग्य भजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैं, बल्कि उन्हें अपने गरीर पर से गुलामी का चिह्न उतार फेंककर अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का अवसर देते हैं। हम गृहस्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हैं और कारीगर को उसकी कला से प्राप्त होनेवाले उस सृजनात्मक आनन्द की अनुमति करने का अवसर देने हैं जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक है। जब हम लोगों से खहर के लिए कुछ अधिक मूल्य देने को कहते हैं, तो हम उन्हें एक राष्ट्रीय बंधे की स्वतः ही वह महायत्ना करने की शिक्षा देते हैं जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिने वह नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने देगवासियों को सादगी सिखाते हैं। और रहन-सहन की सारंगी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म-निर्मयता, आत्म-बोध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र में खहर के द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने की चेष्टा की है वही हम गैर-क्षेत्र में मद्यपान-निषेध के द्वारा और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में मद्यपान-निषेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करें, उसे यदि और कुछ नहीं तो बहुत झुठ तो अवश्य कहना पड़ेगा। यह समझना इनकी सरल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे राष्ट्र में मृग्यन दो महान् जातियाँ रहती हैं—हिन्दू और मुसलमान। इन दोनों जातियों ने धर्म का आधार मदिरा-पान-निषेध पर अवस्थित है। देश में मादक-द्रव्य-निवारण-आन्दोलन आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है। पर जब सभी राष्ट्र सम्मेलना-पूर्वक इस नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक समन्वय पर बैठा देना है और इस आन्दोलन के संगठन के लिए पिक्नेटिंग की ओर मुड़ना है, तो सम्मान राष्ट्रों पर इस प्रकार आ दृष्टी है जिस प्रकार भेड़ों पर जेडिया आ दृष्टी है।

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में उस मन्त्र पर एक सामाजिक विषय का समावेश करने हैं, तब भी हमारी यही दृष्टि होती है। प्रधान-मन्त्री ने निम्नलिखित ने हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था उनके 'उन्हें अलग-अलग कर दिया,

जिन्हें भगवान् ने एकत्र किया था।' जब भारत के महान् नेता ने आमरण अनशन किया तब कहीं जाकर उस गहिर्त व्यवस्था में सशोधन हो सका और हिन्दू-जाति में व्यापक एकता स्थापित हुई।

देश को जिस समस्या का सामना करना है वह वही ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो फूट डालकर शासन करने पर तुली हुई है। नगर और देहात गावों के विश्व संगठित है, उच्च श्रेणियों के हित जनसाधारण के हितों से टक्कर खाते हैं, जन्म-सिद्ध सुधारों के विश्व अपवित्र विरोध संगठित है, खदर पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में क्कावटें मौजूद है, और नैतिक आचरण ऊँचा करने की चेष्टा का प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सब बातों के द्वारा यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल अंग्रेजी शिक्षा के बीवानों, शिक्षितों के पक्षे अपनानेवाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-धन्वों के नेताओं के द्वारा ही प्राप्त न होगा। हमें अपना अन्दाज और कीमत लगाने की दृष्टि में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए गावों में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पड़ेगा और उनका विश्वास प्राप्त करना होगा। और यह विश्वास पत्रों में लेख देने या एक-आध व्याख्यान झाड़ देने से प्राप्त न होगा बल्कि उनकी नित्य सेवा करने से प्राप्त होगा। जहा यह विश्वास प्राप्त हुआ कि वस कांग्रेस-द्वारा आयोजित राष्ट्रोद्वार का कार्यक्रम चलने लग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हुए सेव की भांति तत्काल ही चाहे न टपक पड़े तो भी यह धीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानो स्वराज्य की नींव में अच्छी तरह और सचमुच रमसा गया एक पत्थर है, और समाज की सामाजिक-आर्थिक रचना में से निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के प्रासाद की एक-एक मजिल ऊँची करने के सम-तुल्य होगी। यह तरीका निस्सन्देह धीमा है, पर परिणाम निश्चित और स्थायी होगा। इस प्रकार कांग्रेस ने गावों में अपना सन्देश ले जाकर ग्राम-नेतृत्व कायम कर दिया है।

२

कांग्रेस की नवीन नीति

कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए किसी आन्दोलन का उसकी अपूर्ण और अनिश्चित दशा में अध्ययन

करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन है—और सासकर उस व्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम विश्वास रखता है और इसलिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शत्रुओं की धृणा का भाजन बन गया है। सभी महान् आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। जान-बूझकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान् आन्दोलनों को शुरुआत में क्रियम आन्दोलनों के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारबन समझा जाता है, जिसके साथ उसकी समता रहती है। सत्याग्रह को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध समझा जाता है, पर सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है, जितनी हीरे की चमक रसायनशाला के उस काले पदार्थ से भिन्न है। नहीं, निष्क्रिय-प्रतिरोध और सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके जन्म-वाता ने जान-बूझकर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधीजी के आन्दोलन में क्रुद्ध पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस आन्दोलन को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मान समझा।

हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया है जिसने समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है। निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में इस आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा हुआ था। इस कटुता और गर्व में शायद धृणा और हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कुड़ी हुई जनता का आन्दोलन था जो अपने शासक से क्रुद्ध थी, और यद्यपि चायल करने को इच्छुक थी, पर आक्रमण करने को तैयार न थी। जब इसने सविनय-अवज्ञा का रूप धारण किया तो इसे विरोध पर विशेष के समान ही और देने में समय लगा। 'सविनय' वाली बात को शुरू में बहुत कम समझा गया, पर धीरे-धीरे लोग इसको समझने लगे और इस प्रकार इस 'सविनय'-सम्बन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा। कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आचार-प्रेम और अहिंसा है। अहिंसा केवल अभाववाला शक्ति न रही, बल्कि एक प्रबल शक्ति हो गई और उसने उस प्रेम का रूप धारण कर लिया 'जो दूसरों को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर अस्म हो जाता है' १९२२ की फरवरी में बारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उपरोक्त परिभाषा और आदर्श की दृष्टि से बारडोली के निश्चय को देखें तो पता लगेगा कि एक चोरी-चोरा, युक्त-अन्त के एक गोरखपुर नामक जिले को ही नहीं सारे देश को सजा देने के लिए पर्याप्त है। हम यह भी जान लेंगे कि सत्याग्रह भौतिक-शक्ति भाग

न हांकने ऐसी नीति और आध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी मांगों को पूरी कराये बिना नहीं मानती और जो बड़ी प्रियाजील, अग्रसर और तेजस्विनी है। लोगों को ग्निनि या यह नहीं पन समझने में काफी बरसा लगा कि यदि सरकार-द्वारा किया गया आग्निबासात्र-याग-द्व्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर जाता है, तो जनता-द्वारा किया गया चौरी-चौरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता है। यान्तर्य में सत्याग्रह मनुष्य को अवतक बात सारे सद्गुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन मनुष्यों का मुख्य मूल्य है और अहिंसा या प्रेम उसका परम-आकाङ्क्ष है। इन प्रकार देश-विकृत ही नये दृष्टि-विन्दुओं के ससार में जा कूदा जिनमें धृष्टता और कुत्सा, भय और कायरता, श्रेय और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, साहस, धर्म, आत्म-धीर्य और आत्म-शुद्धि ने ले लिया था, जिसमें सम्पदा सेवा के आगे मित्र जुगती है, और जिनमें धनु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि उसके विचार और भाव को अपने अनुकूल बनाया जाता है।

हमें दिया दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वयं हमी है और भय हमारे आस-मास घूमता रहता है। यदि हम एकबार भय और स्वायंपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं मृत्यु का आग्निकरण करने को तैयार हो जायें। हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला है, इसलिए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, दरिद्रता का और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। अमहयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियमन है, साधना है, इसलिए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन बन गया है। इस साधन का उपयोग हम विनम्रता की भावना के साथ, जिनसे साहस प्राप्त होता है, करना होगा, न कि गर्व की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दोलन के कर्त्ता ने आजकाल की गहिर्त राजनीति को एक ही छलांग से दिव्य और आध्यात्मिक बना दिया।

हमें आन्दोलन के इन फलितार्यों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की चित्ति समझने में बड़ी आसानी होगी। वह चित्ति, जिसे एक सरल मूल 'अहिंसा परमो धर्म' में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो न केवल अपने-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती है बल्कि हरेक को बाइबल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हो। 'जो तुम्हारे साथ मलाई करे, तुम उसके साथ मलाई करो', एक व्यवहार सिद्धान्त है। जो व्यक्ति प्रेम करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल

पाशविक या नारकीय प्रवृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ या जनक को पराजित करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब लोग निराशा से विह्वल होकर पूछते हैं कि अंग्रेजों के पाशविक बल का मुकाबला अहिंसा कैसे कर सकेंगी, तो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाशविक न होंगे तो क्या सत्याग्रह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा साबित न होगा? हमारे भीतर पहले से ही जो धारणायें घुम गई हैं उन्हींके कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पड़ता है। पश्चिम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-सघर्ष में जो अधिक बलशाली होता है वही जीवित रहता है और दुर्बल का बिनाश अनिवार्य है, हमपर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि इसके कारण हमारी कृत्सित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गर्व और उसके सगी-साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं जिनसे कायरता और हिंसा की उत्पत्ति होती है।

भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खड़ा है, जो हमसे ससार त्यागने को तो नहीं कहती पर साथ ही हममें आत्म-त्याग की प्रवृत्ति जागृत करती है। जहाँ हमने एकबार सत्य का पीछा पकड़ा और वासनाओं को कुचला और आत्म-शुद्धि की, कि सेवा-भाव और विनम्रता की भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहाँ हमने क्रोध पर विजय पाई और क्षमाशीलता से काम लिया, कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक का आसन अहिंसा स्वयं ही ग्रहण कर लेगी।

सब-कुछ कह चुकने के बाद भी अहिंसा के सम्बन्ध में यह सशय बाकी रह जाता है कि राजनैतिक झगड़ों का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुक्तता या कितनी शक्ति है? इस प्रकार का सवेह करनेवालों के विरुद्ध एक तर्क यह है कि जैसी हमारी परिस्थिति है उसको देखते हुए जहाँ अहिंसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाट्य है तथा नीति-रूप में भी अणकेय और असंदिग्ध है। यदि अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने की शपथ न ली जाय और उसका यथावत् पालन न किया जाय तो भारतवासियों-जैसे विशाल विजित जन-समूह में जीवन उत्पन्न करना असम्भव हो जाय। ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहिंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलाग में सफलता प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जन-समूह ने विलम्ब दिखाया है, किसीने बीड़ा भी तो नहीं उठाया। अहिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी शक्ति है जो दोनों प्रतिद्वन्द्वियों को शान्ति और सन्तोष प्रदान करती है, क्योंकि जहाँ हमने हिंसा को एकबार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा

गिया जा सकता है। यग, हमारे नाद गिया और प्रतिहिंसा का नाशक चक्र चलता ही रहता है।

३

राष्ट्र का पुरुषत्व

लोगो पुरुषो, मित्रो और बालको पर गांधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या कारण है? उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नहीं, राजनैतिक अव्यवस्था और गोलमाल का शोरदोर है। जैसा कि लॉवेल ने कहा है—“ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर को यही उच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुण्यत्व की भांति ही राष्ट्रों के पुरुषत्व की भी परीक्षा भारी सफटो या भारी अवसरो द्वारा होती रहे। यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो वह भारी सफट को भारी अवसर बना लेता है, और यदि पुरुषत्व मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी सफट में परिवर्तित हो जाता है।” गांधीजी ने भी भारी सफट को भारी अवसर बना डाला और ऐसी नई शक्ति का श्रीगणेश कर दिया जो स्फुरित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के बजाय स्वयं पीड़ा का आयातन करती है, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उनका मत-मन्यतन करने की इच्छा रखती है। गांधीजी ने बुद्ध आश्रम में घोषित कर दिया है कि जनता को मधिमय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कर्तव्य भी है, पर गांधीजी उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोहाचरण के लिए लोगों को फांसी पर नढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने केवल भारत के दासत्व को मिटा देने का बीड़ा उठाया हो, मो बात नहीं है, वास्तव में उन्होंने सारे ससार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का बीड़ा उठाया है, जो दासत्व का प्रतिपादन किसी भी रूप में—चाहे वह शैतिक हो, चाहे राजनैतिक या आर्थिक—करनेवाली हो। उन्होंने यह दिग्ग दिया है कि दूसरों को अपनी प्रजा और दास बनाना नैतिक अन्याय है, राजनैतिक भूल है, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध बुद्धि को उद्बोधित किया, न कि उसके राग-द्वेषों को, उनके सदृशसदृ विवेक को उद्बोधित किया, न कि उनकी स्वार्थपरता या अज्ञान को। उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक बुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके अनुमान सत्य और अहिंसा के विरोधी सिद्धान्त देश में सान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

अब हमें यह देखना है कि यद्वा पर चिन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ? इन सिद्धान्तों का प्रयोग पहली बार १९१९ में अमृतसर-कांग्रेस में हुआ, जबकि गांधीजी ने आग्रह-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अंग्रेजों की हत्या करके और नेशनल बैंक की इमारत को और अन्य इमारतों को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया उसकी अवश्य निन्दा होनी चाहिए। कांग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय रद्द कर दिया और गांधीजीने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साधारणतः घमकी जिस भाव में समझी जाती है उस भाव में यह घमकी नहीं, बल्कि गांधीजी के उस रुझान का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य था। दूसरे दिन विषय-समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर संकोच-पूर्वक। वस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के कानों में यह डालना शुरू किया कि वास्तव में अहिंसा क्या है। कांग्रेस के नजदीक स्वराज्य का अर्थ यह था कि अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर कर दिया जाय, पर गांधीजी ने उसे बताया कि नागरिक की हैसियत से अंग्रेज भारत में शौक से आ सकते हैं, और रह सकते हैं, और विदेशियों का बाल भी बाका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चोरी-चौरा में राष्ट्र पूरा न उतरा। पर तो भी कांग्रेस हताशा न हुई। जब आन्दोलन बढ़ किया गया तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी अचल थे। सत्याग्रही को न सन्न का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। उसे तो केवल सत्य का भय है। फलतः गांधीजी ने मानो आन्दोलन को लगभग छ वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। बाद को जो घटनाएँ हुई वे जानी-बूझी हैं और उनसे सत्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होती है। वैसे वे घटानायें पुराने कथानक की भाँति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृष्यों की भाँति प्रतीत होगी, पर वास्तव में हैं वे सत्याग्रह की दिव्य शिक्षाओं का प्रकृत रूप मात्र।

पिछले पचास वर्षों में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नक्शा अपने उतार-चढ़ाव को स्वयं प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा। हम धूम-फिरकर बराबर उसी कार्यक्रम पर आजाते हैं—अर्थात् १९०६ का स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और स्वराज्य का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को १९१७ में दुहराया गया, किन्तु ऊँचे अर्थान् निर्णय-प्रतिरोध के दर्जे पर। १९१९-२१ में इसे फिर दुहराया गया। इस बार यह और भी ऊँचे दर्जे पर—सविनय-अवज्ञा के दर्जे पर—आ पहुँचा था। इसके बाद १९३०-३४ का आन्दोलन आया। इस बार

यह और भी जैचे—सत्याग्रह के—दर्ज पर आ पहुँचा। हमारी चढ़ाई एक ऐसी पहाड़ी रेल की चढ़ाई की तरह है जो तोड़-मरोड़ को तय करती हुई, कभी नीचे जाती और कभी जैची उठती हुई, अन्त में पूरी जैचाई पर आ पहुँचती है। इस चढ़ाई में कभी प्रयत्न-पूर्वक ऊपर चढ़ना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पड़ता है। इसी प्रकार सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान में कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, और बीच-बीच में कौंसिल का काम भी हाथ में लिया गया—कौंसिल का काम भी एक युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिम शिक्षर 'स्वराज्य' तक पहुँचना है।

पर यदि लॉर्ड अविन की भाषा को, जो उन्होंने १९३१ में सचि से पहले इस्तेमाल की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र है, फल नहीं प्रयत्न-मात्र है, गन्तव्य स्थान नहीं दिशा मात्र है, तो उस कारीगर से, जो अभी नीब ही को ठोक-पीटकर ठीक कर रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं है कि प्रासाद बनकर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? मामूली ईंट-बूने की नीब को भी बनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर स्वराज्य की नीब को तो पोस्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों तक छोड़ देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर बननेवाली इमारत के बोझ को सहन कर सके।

इन अनेक वर्षों में जिस प्रकार सचर्च जारी रहा उसका बर्णन हमने कर दिया है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और ग्राम को भारत की राष्ट्रीयता का केन्द्र बना देना होगा, और इन दोनों को यथासम्भव आत्म-सन्तुष्ट और आत्म-परिपूर्ण बनाना होगा। हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में समानता की नीब बनाना होगा, स्वतन्त्रता को सिखार बनाना होगा और भ्रातृभाव को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा। यह समानता न वह समानता होगी जिसमें भेद-भाव और फूट दिखाई पड़ती हो, और न वह समानता होगी जिसमें चारों ओर लम्बी-लम्बी घास-भूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे शाहवल्कल के दरख्त दिखाई देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को धुँवँल करनेवाला द्वेष दिखाई देता होगा। पर वह समानता ऐसी होगी जिसमें नागरिकता की दृष्टि से सारी सचियों को विकास का एकसमान अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का समान-मूल्य होगा, जिसमें धार्मिक दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वासों को समान अधिकार मिलेगा। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मौजूद

है और 'चाहिए' और 'हैं' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति लगी हुई है, जिससे प्रयत्न और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढांचे में से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए अधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेवालों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा। कांग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनैतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है। इसलिए कांग्रेस ने सब उपयोग के हेतु इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त होता है—अर्थात् वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह विचार जो उसे चरित्रवान् बनाता है।

इस प्रकार कांग्रेस-स्रोत, जिसका साधारण आरम्भ १८८५ में बम्बई में हुआ था, आधी शताब्दी से बहुत आ रहा है। कभी यह सकीर्ण-स्रोत का रूप धारण कर लेता है, कभी विशाल नदी का। यह स्रोत कहीं जगहों को पार करता है, कहीं पहाड़ियों और घाटियों में से होकर गुजरता है। कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त और निश्चल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रबल वेग के साथ बह निकलता है। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये आदेशों के द्वारा इसके जल में बराबर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार यह स्रोत पूर्ण आस्था के साथ अपने उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय सत्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विशाल सत्कृति में जा मिलेगी।

परिशिष्ट १

‘१६’ का आवेदन-पत्र

[महायुद्ध के बाद के सुधारों के सम्बन्ध में खाड़ी कौंसिल के १६ अतिरिक्त सदस्यों ने वाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं। उक्त कौंसिल के २७ गैर-सरकारी सदस्यों में से २ अघगोरो की रायें नहीं ली गई थी, जिसके कारण सबको मालूम है; ३ मौजूद नहीं थे, और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उनके नाम नवाब सैयद नवाबअली चौधरी, मि० अकुरंदहीम और सरदार व० सुन्दरसिंह मजीठिया हैं।]

हममें कोई मन्त्रेह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सम्य ससार में, मुख्यतः ब्रिटिश-साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए कमजोर और छोटे राष्ट्रों के नवाब के इस सघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती जन-जन लगा रहा है, शासन-सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढ़ जायेंगे। भारतवर्ष ने भी इस सघर्ष में भाग लिया है, इसलिए वह भी स्थितियों के सुधार के लिए जो परिवर्तन की गई भावना जागृत होगी उससे प्रभावित हुए बिना न रहेगा। इस क्षेत्र में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के बाद भारतीय शासन की समस्या को नये दृष्टिकोण से देखा जायगा। हिन्दुस्तान के लोग इंग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं कि हिन्दुस्तान ने अंग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में बड़ी उन्नति की है और अपने बौद्धिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया है। उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत १८३३ के भारतीय-वार्टर-एक्ट से होती है, लगातार (हालांकि वह धीमा है) विकास किया है। १९०६ तक भारतवर्ष का शासन एक नौकरशाही-वर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीब-करीब सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और जन-साधारण के प्रति जवाबदेह न थे। १९०६ के सुधारों से प्रथम बार भारतवर्ष के राजकाजी मामलों में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला, किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। तब भी भारतवासियों ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतीय साम्राज्य के अन्दरूनी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का सूचक समझकर, स्वीकार कर लिया था। कौंसिलों में वृद्ध और सवाल-जवाब की अधिक सुविधायें

देकर गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या-भर बढ़ा दी गई थी। बड़ी कौंसिल में पूर्णतः सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौंसिलों में, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी शामिल थे। जिन कार्रवाइयों का अधिकतर लोगो पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने के सम्बन्ध में होती चाहे कर लगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनों पर उतका सीधा कोई असर न होने से, उनमें यूरोपियन सदस्य स्वभावतः सरकार का ही समर्थन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पक्ष लेने की ओर झुकते थे। पिछला अनुभव बतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में यही घटित हुआ है। इसलिए प्रान्तीय-कौंसिलों के गैर-सरकारी बहुमत बहुत ही धोखे-भरे साबित हुए हैं। उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं आई है। वर्तमान समय में बड़ी कौंसिल और प्रान्तीय-कौंसिलें केवल सलाह देनेवाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं हैं। उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक नियन्त्रण हो। जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं जितने वे सुधारों से पहले थे। केवल कार्य-कारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रखे जाते हैं, किन्तु वे भी पूर्णतः सरकार-द्वारा ही नामजद किये जाते हैं। जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता।

१९०६ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश्य था वह (१-४-१९०६ के) 'इण्डियन कौंसिल्स बिल' के दूसरे वाचन के समय कामन-सभा में प्रधान-मन्त्री द्वारा दी हुई वक्तुता से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना अत्यन्त वाञ्छनीय है कि ये कौंसिलें महज ऐसे यंत्र नहीं हैं जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी शासकों-द्वारा खींचे जाते हों। परन्तु हम विनम्र भाव में कहते हैं कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कौंसिलों और कार्य-कारिणी की रचना के इस प्रश्न के अलावा भी लोगों को खास-खास भारी कानूनी बाधाएँ भुगतनी पड़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के बजाय व्यर्थ कर देती हैं और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चित रूप से आघात पहुँचाती हैं। गवर्नर-कानून जो यूरोपियनों और अफगानों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वे स्वयमेवक-दलों का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते, और वे फौज के कमीशन-प्राप्त पदों पर भी नहीं जा सकते। ये कानूनी बाधाएँ हिन्दुस्तानियों के लिए हैं जो दुःखदाई और भेदभाव-पूर्ण हैं। यदि

वे केवल रकावट ही होती तो भी कम बुराई न थी। शस्त्र रखने और उन्हें प्रयोग में लाने की इन रकावटों और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को नामदं बना दिया है। उनपर कमी भी भारी खतरा आ सकता है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन में उनका कोई असली भाग नहीं है। उन्हें ऐसी भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-बाधाओं के नीचे रखा गया है जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी है। उन्होंने हमें विलकुल वेवसी की हालत में ला खड़ा किया है। इसके सिवा शर्तवन्दी-कुली-अथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और बाहरी देशों का यह खयाल होता है कि सारे भारतवासी शर्त-वन्द-कुलियों जैसे ही हैं। वे गुलामों की तरह हिंकारत की नजर से देखे जाते हैं। मौजूदा हालते हिन्दुस्तानियों को अनुभव कराती है कि यद्यपि वे कहने पर को बादशाह की समान-अज्ञा हैं, किन्तु वास्तव में साम्राज्य में उनका खता बहुत छोटा है। दूसरी एशियाई जातिया भी अधिक बुरा नहीं तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके वर्जों के सम्बन्ध में रखती हैं। भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको जलील करनेवाली है, परन्तु यह भारतीय युवकों को तो असह्य है जिनकी दृष्टि शिक्षा और विदेश-भ्रमण से जहाँ, वे स्वतन्त्र जाति से मिले हैं, विशाल हो गई है। इन कष्टों और बाधाओं के होते हुए लोगों को जिस चीज ने अबतक सम्हाल रखा है वह है वह आशा और वह विश्वास, जिसका सत्कार हमारे सन्नाटों और ऊँचे दर्जों के अंग्रेज राजनीतिज्ञों-द्वारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार के वादों और आश्वासनों से हुआ है। इस नाजुक हालत में, जिसमें हम अब गुजर रहे हैं, हिन्दुस्तानी लोगों ने अपने और सरकार के बीच के धरेलू मतभेदों को भुला दिया है और बफादारी के साथ साम्राज्य का साथ दिया। हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोप के रण-क्षेत्रों में जाने को उत्सुक थे—किराये की फौजों की तरह से नहीं बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, स्वतन्त्र-नागरिकों की हँसियत से। भारतीयों का शिक्षित-समुदाय भी चाहता था कि इस अजरत के वक्त में इंग्लैण्ड का साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजों के करीब-करीब खाली हो जाने की हालत में भी शान्ति बनी रही। इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री ने, हिन्दुस्तानियों ने महामुद्ध में जो भाग लिया उसके सम्बन्ध में इंग्लैण्ड-वासियों के विचार प्रकट करते हुए, कहा था कि 'हिन्दुस्तानी एक सयुक्त स्वार्थ और भविष्य के सयुक्त और समान रक्षक हैं।' हिन्दुस्तान अपनी बफादारी के लिए कोई पुरस्कार नहीं मागता, किन्तु यह आशा करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास

की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय और हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मित्र की-सी हो जाय। इससे हिन्दुस्तानी लोगो को विश्वास हो जायगा कि इंग्लैंड ब्रिटिश-छत्र-छाया में स्वराज्य प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासको और राजनीतिज्ञों-द्वारा इतनी बार कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन, योग्यतापूर्ण प्रबन्ध ही नहीं है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगो के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदला है।

यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहे जो पहले थी, उसमें ठोस परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह बड़ी निराशा और बेइतमिनानी पैदा होगी, और दोनों के इस सम्मिलित सकट में भाग लेने से जो लाभ-दायक असर हुआ है वह सुरज्त गायब हो जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत आशाओं की दुःखद स्मृति-भर रह जायगी। हमें विश्वास है कि सरकार भी इस स्थिति को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच रही है। हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि ये सुधार किन दिशाओं में हों। हमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए और उनसे देश के शासन में लोगो को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए। शास्त्र रखने और फौज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तापदायी कानूनी बाधाएँ हैं वे भी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो लोगो में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें हीन और असहाय अवस्था में भी बना रखती हैं। इस सलाह से हम नीचे लिखी तजवीजों को गौर करने और मजूर करने के लिए पेश करते हैं —

१ प्रांतीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियों में आधे सदस्य हिन्दुस्तानी हों, कार्यकारिणी में जो यूरोपियन हों वे जहासक हो बहासक इंग्लैंड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगो में से नामजद किये जायें, ताकि हिन्दुस्तान को वाहरी दुनिया के विशाल दृष्टिकोण और अनुभव का लाभ मिल सके। यह विलकुल आवश्यक नहीं है कि कार्यकारिणी के सदस्य, चाहे वे हिन्दुस्तानी हों या अंग्रेज, अमली शासन का अनुभव रखें, क्योंकि, जैसा कि इंग्लैंड के मंत्रियों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें

सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों के विषय में तो हम साहस-पूर्वक कह सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी सन्ख्या में और हर वक्त मिल सकते हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद वही अच्छी तरह ले सकते हैं। इस दिशा में हमने देखा है कि सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह, सर अलीइमाम, स्व० कुवर कृष्णस्वामी ऐयर, सर जम्सुन्नुदा और सर शंकरन् नायर जैसे लोगों ने अपने कार्यों का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्बन्धी उच्च योग्यता का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न-भिन्न देशी राज्यों के वर्तमान शासकों के अतिरिक्त भी, देशी राज्यों ने, जिनमें हिन्दुस्तानियों को अवसर मिला है, सर सालार जंग, सर टी० माधवराव, सर शोपाद्रि ऐयर और वी० ब० रघुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैं। उच्च कार्यकारिणी के सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम को, तथा प्रान्तीय कौंसिल-सम्बन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए। कार्यकारिणी के हिन्दुस्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए।

२ सभी भारतीय कौंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए। हमें विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक सम्पर्क में आते हैं। भिन्न-भिन्न कौंसिलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-लीग की कार्यवाह्या इस बात का काफी समूत देती हैं कि हिन्दुस्तान का शिक्षित-वर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का अधिकार सीधा लोगों को मिल जाना चाहिए। मुसलमान या हिन्दू जहाँ अल्पसंख्यक हो वहाँ उन्हें उनकी सख्या-शक्ति और स्थिति का ख्याल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

३ वही कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कौंसिलों में बड़े प्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की ६० से ७५ तक से कम न होनी चाहिए।

४ भारतवर्ष को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वजट कानून के रूप में पास होना चाहिए।

५ शाही कौंसिल को भारतीय-शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में कानून बनाने,

विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय-शासन के लिए प्रान्तीय-कौंसिलों को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिए। केवल सेना-सम्बन्धी मामलों, वैदेशिक सम्बन्धों के, युद्ध की घोषणा करने के, समझौता करने के और व्यापारिक सन्धियों के सिवा अन्य सन्धिया करने के अधिकार भारतीय सरकार को न दिये जायें। सरकार के तौर पर कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को और कौंसिल-सहित गवर्नरों को 'वीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों और हद्दों के भीतर ही किया जाय।

६ भारत-मन्त्री की कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मन्त्री की स्थिति भारत-सरकार से सम्बन्ध रखने में, जहातक हो, वैसे ही हो जैसी उपनिवेशों के सम्बन्ध में उपनिवेशों के मन्त्री की होती है। भारत-मन्त्री के सहायक दो स्थायी उपमन्त्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो। मन्त्री और दोनो उप-मन्त्रियों के वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से दिये जायें।

७ साम्राज्य-सभ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को बड़ी स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है, और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके।

८ प्रान्तीय सरकारों को, जैसी २५ अगस्त १९११ के भारत-सरकार के शरीते में वर्णित है वैसे स्वतन्त्रता प्रान्तीय प्रबन्ध में दे दी जाय।

९ संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बड़े-बड़े अन्य प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटेन से लाये जायें और उनकी कार्यकारिणी कौंसिलें हों।

१०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए।

११ वास्तव रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्हीं शर्तों पर दे देना चाहिए जिन शर्तों पर यूरोपियनों को दिया हुआ है।

१२ हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना (Territorial Army) है उसमें स्वयंसेवकों और सिपाहियों के रूप में भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए।

१३. जिन शर्तों पर फौज में यूरोपियनों को कमीशन (ऑफी अफसर) मिलती है उन्हीं पर हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए।

मणिचन्द्र नन्दी, कासिमबाजार

डी० ई० बाचा

भूपेन्द्रनाथ वसु

इब्राहीम रहीमतुल्ला

बी० नरसिंहेश्वर शर्मा

मीर असदअली

विष्णुदत्त शुक्ल	कामिनीकुमारी चन्दा
मदनमोहन मालवीय	कृष्णसहाय
के० बी० रंगस्वामी आयर	आर० एन० भजदेव,
	कनिष्का
मजहबुल हक	एम० बी० दादाभाई
बी० एस० श्रीनिवासन्	सीतानाथ राय
तेजबहादुर सप्र	मुहम्मद अली मुहम्मद
एम० ए० जिन्नाह	

परिशिष्ट २

कांग्रेस-लीग-योजना

प्रस्ताव

“(क) इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी जातियां प्राचीन सभ्यता की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और अंग्रेजी शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और सार्वजनिक कामों में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित आकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कांग्रेस की राय है कि अब वह समय आ गया है जबकि श्रीमान् सम्राट् इस प्रकार का घोषणापत्र निकालने की कृपा करे कि अंग्रेजी-शासन-नीति का यह उद्देश और लक्ष्य है कि वह पूर्ण ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रदान करे।

(ख) यह कांग्रेस (सरकार से) मतालवा करती है कि महासमिति ने भारतीय मुस्लिम-लीग-द्वारा नियुक्त सुधार-समिति की सहयोगिता ने शासन-सुधार की जो योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती है) उसको मजूर कर स्वराज्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाया जाय।

(ग) साम्राज्य के पुनर्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर उठाया जाकर आत्म-शासित उपनिवेशों की भाँति साम्राज्य के कामों में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाय।”

सुधार-योजना

१—प्रान्तीय कौंसिलें

१. प्रान्तीय कौंसिलों में चार-पचमास निर्वाचित और एक-पचमास नामजद-सदस्य रहेंगे।

२. उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ तक से कम न होगी।

३. कौंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जावें और भताधिकार जहातक हो सके विस्तृत हो।

४. महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, यथेष्ट प्रबन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा नीचे लिखे अनुपात में होना चाहिए —

प्रान्त	निर्वाचित भारतीय सदस्यों के ५० प्रतिशत			
संयुक्तप्रान्त	"	"	"	३० "
बंगाल	"	"	"	४० "
बिहार	"	"	"	२५ "
मध्यप्रदेश	"	"	"	१५ "
मदरास	"	"	"	१५ "
बम्बई	"	"	"	एक-चुतीयास

किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के लिए, किसी अन्य निर्वाचन में शरीक न हो सकेगा।

यह भी शर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या उसकी किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई न की जायगी, यदि उस जानि के उम विशेष भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थांश सदस्य उस बिल या उसकी धारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों। वह बिल या उसकी धारा, या (वह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति

से सम्बन्ध रखता है या नहीं—इसका निर्णय उस कौंसिल के उसी जाति वाले सदस्य करेंगे।

५ प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कौंसिल का सभापति न हुआ करे, किन्तु कौंसिल को ही अपना सभापति चुनने का अधिकार होना चाहिए।

६ अतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक प्रश्न) पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए। किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना चाहिए।

७ (क) टटकर, डाक, तार, टकसाल, नमक, अफीम, रेल, स्थल और जल-वेना तथा देशी रियासतों से सरकार को मिलनेवाले करके अतिरिक्त अन्य सब करों की आय प्रान्त की होनी चाहिए।

(ख) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का बटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार को एक निश्चित रकम मिलनी चाहिए। हा, विशेष और अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो तो उस रकम में कमी-बेशी की जा सकेगी।

(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में—जिसमें ऋण लेना, कर लगाना या उसमें कमी-बेशी करना और आय-व्यय के बिट्टे (बजट) पर मत देना शामिल है—कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कौंसिल को होना चाहिए। खर्च की सब मदों का व्यौरा और कर लगाने के लिए मोचे गये उपाय विलों में लिख दिये जाने चाहिए और इन विलों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय कौंसिल में पेश करना चाहिए।

(घ) प्रान्तीय-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आते उनपर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय कौंसिल ने ही जो नियम बनाये हों उनके अनुसार बहस होने की इजाजत होनी चाहिए।

(ङ) प्रान्तीय-कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवर्नर-द्वारा रद्द कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न होगा। लेकिन (कौंसिल-सहित गवर्नर-द्वारा) रद्द किया गया

प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर (प्रान्तीय) कौंसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा।

(च) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवा हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए कौंसिल की बैठक को स्वमित करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।

द कौंसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थना करने पर कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

६ घन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य बिल कौंसिल के द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।

१० प्रान्तीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हे) रद्द कर सकेगा।

११ सदस्यों का कार्य-काल पाच वर्षों का होगा।

२—प्रान्तीय सरकार

१ प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा इन्डियन सिविल सर्विस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा।

२. प्रत्येक प्रांत में एक कार्य-कारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रांत का शासक-मण्डल होगी।

३ साधारण तथा 'सिविल सर्विस' के लोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किये जायेंगे।

४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे और उनका निर्वाचन प्रान्तीय-कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा।

५. सदस्यों का कार्यकाल पाच वर्षों का होगा।

३—भारतीय (बड़ी) कौंसिल

१. भारतीय कौंसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी।

२. उसके चार-पञ्चमाश सदस्य निर्वाचित होंगे।

३ प्रांतीय कौंसिलो के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-सब जिस क्रम से बने हैं उसीके अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहातक हो विस्तृत कर दिया जाय, और भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रांतीय कौंसिलो के निर्वाचित सदस्यों को भी होना चाहिए।

४ निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक-तृतीयांश मुसलमान हो और उनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रांतों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासम्भव) वही हो जो प्रांतीय कौंसिलों में अलग मुस्लिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रक्खा गया है (भाग १ द्वारा ४ की व्यवस्था देखिए)।

५ कौंसिल का सभापति कौंसिल-द्वारा ही चुना जायगा।

६ अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी सदस्य को उसे पूछने का अधिकार होगा।

७ सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

८ धन-सम्बन्धी बिलों को छोड़ कर अन्य बिल कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।

९ (भारतीय) कौंसिल द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून बनने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी।

१० आमदनी के जरिये और खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आर्थिक प्रस्तावों का समावेश बिलों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक बिल और सारा बजट भारतीय कौंसिल की मजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए।

११ सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा।

१२ नीचे लिखे विषयों पर एकमात्र भारतीय कौंसिल का अधिकार होगा —

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाना आवश्यक हो।

(ख) ऐसे प्रांतीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रांतों के पारस्परिक आर्थिक व्यवहार से हो।

- (ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे सब विषय जो केवल (अखिल) भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं।
- (घ) वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्बन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल पर बाध्य न होंगे।
- (ङ) 'टैरिफ' और सटकर में परिवर्तन करने, किसी भी प्रकार का 'सेस' लगाने, उसमें परिवर्तन करने या उसे सठा देने, चल्न और वेनो की प्रचलित प्रणाली में परिवर्तन करने और देश के किसी या सब सहायता पाने योग्य और नये उद्योग धंधों को (राजकीय) सहायता अथवा 'बाउण्टी' देने का अधिकार।
- (च) देश-भर के वासन से सम्बन्ध रखनेवाले सब विषयों पर प्रस्ताव।

१३ (भारतीय) कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल-द्वारा रद्द न कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य होगा, लेकिन यदि वह (कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल-द्वारा रद्द किया हुआ) प्रस्ताव कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर कौंसिल-द्वारा स्वीकृत हो जाय तो (सरकार के लिए) उसे कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा।

१४ उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निविष्ट महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए (भारतीय कौंसिल की) बैठक को स्यगित करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।

१५ यदि सम्राट्, प्रान्तीय अथवा भारतीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत बिल को रद्द करने के सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उस बिल के पास होने की तारीख से बारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना चाहिए, और जिस दिन उस बिल के इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना उसमें सम्बन्ध रखनेवाली कौंसिल को दी जायगी उस दिन से वह बिल रद्द हो जायगा।

१६ भारतीय कौंसिल को भारत-सरकार के सेना-सम्बन्धी विषयों और भारतवर्ष के बंदेशिक और राजनैतिक विषयों के सम्बन्ध में—जिसमें युद्ध छेड़ना, संधि करना और (किसी देश के साथ) मुलह करना शामिल है—हस्तक्षेप करने या अधिकार न रहेगा।

४—भारत सरकार

१. भारतीय गानन का मुख्याधिष्ठाता भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल होगा।
२. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आगे सदस्य भारतीय होंगे।
- ३ (कार्यकारिणी के) भारतीय सदस्य भारतीय कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन जायेंगे।

४ 'इण्डियन सिविल सर्विस' के लोग आम तौर पर गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।

५ 'इम्पीरियल सिविल सर्विस' में कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार इस (नई) व्यवस्था के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार को होगा। इसमें वर्तमान कर्मचारियों के हित का यथेष्ट ध्यान रखा जायगा और भारतीय कौंसिलों द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पारदर्शी की जायगी।

६ भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप न करेगी, और जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये हों वे भारत सरकार के समझे जायेंगे। प्रान्तीय-सरकारों पर भारत-सरकार का अधिकार साधारणतया निरीक्षण आदि के कार्यों तक सीमित रहेगा।

७ कानून और शासन-सम्बन्धी विषयों में इस (नई) योजना के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार, भारत-मंत्री में, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेगी।

८ भारत-सरकार के हिसाब की स्वतंत्र जाच की प्रणाली बलाई जानी चाहिए।

५—कौंसिल-सहित भारत-मंत्री

- १ भारत-मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जानी चाहिए।
२. भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश-कोष से दिया जाना चाहिए।
- ३ भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मंत्री की स्थिति यथासम्भव बनी होगी चाहिए जो स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मंत्री की है।
४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो स्थायी 'अण्डर-सेक्रेटरी' होने चाहियें, जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए।

६—भारतवर्ष और साम्राज्य

- १ साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के

लिए जो कौंसिल या दूसरी सस्था बनाई या सयोजित की जाय उसमें उपनिवेशो के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिए और इन (भारतीय प्रतिनिधियो) के अधिकार भी उपनिवेशो के प्रतिनिधियो के बराबर ही होने चाहिए।

२ नागरिकता के पद और अधिकारो के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयो का दर्जा सम्राट् की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए।

७—सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय

१ स्थल और जल-सेना की 'कमीशण्ड' और 'नॉन-कमीशण्ड' दोनो ही प्रकार की नौकरिया भारतवासियो के लिए खुली रहनी चाहिए और उनके लिए चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष्ट प्रबन्ध भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए।

२ भारतवासियो को (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।

३ भारतवर्ष में शासन-सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियो को न्याय-सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये जायेंगे, और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के मन्ने बडे न्यायालय के अधीन रखे जायेंगे।

परिशिष्ट ३

फरीदपुर के प्रस्ताव

१. भारत के भावी सामन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार बालिग-मताधिकार के साथ सयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए।

२. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, संघीय (बडी) तथा प्रांतीय कौन्सिलों में उन्ही अल्प-संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिए जिनकी गल्पा २५% से कम हो। ये स्थान जन-गण्ड्या के आचार पर निश्चित होने चाहिए और (अल्पसंख्यक जाति-वालो को अपनी निश्चित जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए बडे होने का अधिकार भी रहे।

(ब) जिन प्रांतों में मुसलमानों की गण्ड्या २५% से कम हो वहा उनके लिए

जन-संख्या के आधार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए सम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेगा, लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायगा और, उस हालत में, जो रिबायत उन्हें इस समय मिली हुई है वह कायम रहेगी।

(स) अगर बालिग-मताधिकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया गया जिससे जन-संख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, तो पंजाब व बंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान रक्षित किये जायेंगे। और यह क्रम उस वक्त तक जारी रहेगा जबतक कि बालिग-मताधिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अनुपात का असर पड़ने लगे, यद्यत् कि किसी भी दशा में बहुमत अल्पमत या समान-मत में परिवर्तित न हो जाय।

३ सभाय धारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौंसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन सभाओं के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-तिहाई रहेगा।

४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उपयुक्तता की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी खयाल रक्खा जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटे-बोहदो पर किसीका एकाधिकार नहीं रहेगा।

५ सभाय तथा प्रांतीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हितों को काफी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौंसिलों में सब दल-बालों के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप धारण कर ले।

६ सिन्ध को एक स्वतंत्र प्रान्त बनाया जायगा।

७ सीमा-प्रान्त और बलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रबन्ध रहेगा जैसा कि ब्रिटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में है या होगा।

८ भारत का भावी शासन-विधान सघातमक होगा, जिसमें अवशिष्ट अधिकार सभ में शामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे।

९ (अ) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिनके अनुसार समस्त नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म-विश्वास, धर्माचार तथा आर्थिक हितों के संरक्षण का आश्वासन रहेगा।

(ब) विधान में एक स्पष्ट धारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक अधिकारों और वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा।

(स) जहातक मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध है, जबतक मधीय धारा-सभा की हरेक कौंसिल में तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

वैकल्पिक प्रस्ताव और हल (विलकुल गुप्त)

भोपाल का हल

१—सर्व-दल-सम्मेलन का हल

- (अ) दस वर्ष की समाप्ति पर बालिग-मताधिकार के साथ समुक्त-निर्वाचन जानी हो, लेकिन इन दस वर्षों में पहले ही किसी समय यदि किसी मधीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुमलमान-सदस्यों का बहुमत समुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस कौंसिल के लिए पृथक् निर्वाचन की पद्धति रद्द कर दी जायगी। या
- (ब) नये विधान का पहला चुनाव पृथक् निर्वाचन के आधार पर हो और प्रथम धारा-सभाओं के पाचवें साल की शुरुआत में समुक्त बनाम पृथक् निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-मग्नह (रेफरेण्डम) किया जाय।

२—राष्ट्रीय-दल की वैकल्पिक योजना

- (अ) प्रथम दस वर्ष समुक्त निर्वाचन रहे और इन वर्षों की समाप्ति पर निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-मग्नह किया जाय। या
- (ब) कौंसिलों में पहली बार मुमलमान-सदस्यों में से आधे समुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने जायें और आधे पृथक् निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार दोनों-विधायी समुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने जायें, और एक-निर्वाह पृथक्-निर्वाचन द्वारा। इसके बाद समुक्त-निर्वाचन और बालिग-मताधिकार हो।

३—उपयुक्त प्रस्ताव में कुछ बिन्दुओं के समोधन

कौंसिलों में पहली बार दोनों-विधायी सदस्य (मुमलमान) पृथक् निर्वाचन-द्वारा चुने जायें और एक-निर्वाह समुक्त-निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार आधे-आधे। इसमें बाद, समुक्त-निर्वाचन हो और बालिग-मताधिकार। या

परिशिष्ट ४ : कैदियों के वर्गीकरण पर सरकार का आज्ञा-पत्र ६६५

प्रथम पाच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, पश्चात् पाच वर्ष सयुक्त-निर्वाचन, इसके बाद, नवें वर्ष, दोनों तरह के निर्वाचनों के बारे में देश का निर्णय जानने के लिए जनमत-संग्रह किया जाय। या

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक्-निर्वाचन-द्वारा चुने जायें और एक-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। इसके बाद, पाचवें वर्ष की शुरुआत में, जनमत संग्रह किया जाय।

४—मौ० शौकतबली का प्रस्ताव

जब सयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप में, तो पहले बीस साल के लिए मौ० मुहम्मदबली का हल स्वीकार किया जाय।

५—मौपाल की दूसरी बैठक का प्रस्ताव

प्रथम पाच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, उसके बाद मौ० मुहम्मदबली के हल के साथ सयुक्त-निर्वाचन हो। मगर किसी भी कौंसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे रद्द कर सकेंगे।

६—शिमला का मासिरो हल

प्रथम दस वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे और उसके बाद सयुक्त-निर्वाचन, बशर्ते कि किसी कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का विरोध न करे।

परिशिष्ट ४

कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्नलिखित वक्तव्य के रूप में प्रकट किये गये हैं —

“कुछ समय से कुछ बातों में जेल-नियमों में सुधार करने का मामला भारत-सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले पर प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई थी। उन्होंने ब्रतसे गैर-सरकारी लोगों से परामर्श करके अपने विचार बनाये हैं।

कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनसे सिद्धान्ततः भारतवर्ष-भर में लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी। वे निर्णय ये हैं —

सजा पाए हुए कैदियों के तीन वर्ग होंगे—ए, बी, सी। 'ए' वर्ग में वे कैदी लिये जायेंगे जो (१) पहली बार ही जेल में आये हों और जिनका बाल-बलन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और जीवन-क्रम के कारण ऊँचे दर्जे के रहन-सहन के अभ्यस्त हों और (३) जिनको (क) निर्दयता, अनैतिकता या व्यक्तिगत लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) सम्पत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधों पर, (घ) किसी अपराध करने या उसमें सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयकर अस्त्र रखने के अपराध में अथवा (ङ) इन उपधाराओं में समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन या सहायता देने में सजा न मिली हो।

'बी' वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा या जीवन-क्रम के कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हों। बार-बार जेल में आनेवाले लोग इससे अपने-आप बचिन नहीं रखें जायेंगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखने का अधिकार होगा। वे उनके चरित्र और पूर्व-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेंगे। यह निर्णय प्रान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बदल भी सकती है।

जो लोग 'ए' और 'बी' वर्गों में नहीं रखे जायेंगे उन्हें 'सी' वर्ग मिलेगा।

हाईकोर्ट, दौरा-गज, जिला-मजिस्ट्रेट, बैठन-भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदमों का फैसला करेंगे उनमें उन्हें वर्गीकरण करने का अधिकार होगा। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का किया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा। 'ए' और 'बी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश करेगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या सखोषण करेगी।

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकदमें किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान वर्गों पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई मन्दाच लगाये हैं और तरह-तरह की आवाकायें प्रकट की गई हैं। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए' वर्ग के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिवायतें मिलेंगी। जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिवायत नहीं दी जायगी। विशेष वर्ग के कैदियों को जो रिवायतें इस समय दी जा रही हैं वे सब 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेंगी।

अर्थात् उनके लिए अलग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम की आवश्यक सुविधायें और सफाई, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी।

दूसरी बातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं —

‘ए’ और ‘बी’ वर्ग के लिए ‘सी’ वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खूराक से बढ़िया खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकर्रर कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीमा के भीतर खूराक बदलती रह सकेगी। ‘ए’ और ‘बी’ वर्ग की इस बढ़िया खूराक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूराक के अलावा भी और मंगा लेने की इजाजत दी जाती है। यह रिवाज ‘ए’ वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी।

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो रिवाजतें मौजूदा नियमों में हैं वे जारी रहेंगी। यदि ‘ए’ वर्ग के कैदी सरकार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो उन्हें ‘बी’ वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपड़े दिये जायेंगे। ‘बी’ वर्ग के कैदी जेल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ बातों में ‘सी’ वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा होगा।

‘ए’ और ‘बी’ वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वाञ्छनीय है।

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्व अब फिर दोहरा दिया जाता है कि ‘ए’ और ‘बी’ वर्ग के कैदियों का काम मुकर्रर करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से विचार कर लिया जाय।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और तात्पर कैदियों की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ उचित सुविधायें दी जानी चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जाच करे और जहाँ पुस्तकालय नहीं है अथवा अच्छे नहीं है वहाँ शीघ्र स्थापित करे या उत्तम करें। जेल-सुपरिण्टेण्डेंट की मजूरी में पढ़े-लिखे कैदी पुस्तकें और मासिक-पत्र बाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे।

अखबार ‘ए’ वर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जायेंगे जिनपर वर्तमान विषयों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अर्थात् विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार की मजूरी से दिये जायेंगे। साधारणतः यभी नाहर कैदियों को प्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल-अखबार प्रति सप्ताह मिला रहेगा। जहाँ प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहाँके लिए भारत-सरकार

ने यह निश्चय किया है कि 'ए' और 'बी' श्रेणी के कैदियों को प्रान्तीय-सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतिमा सरकार के खर्च से दी जायें।

'ए' श्रेणी के कैदियों को अवकी भाति एक महीने के बजाय पन्द्रह दिन में एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। 'बी' वर्ग के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलों के नियमानुसार बगी तो बड़ी लम्बी-लम्बी अवधिया मुकर्रर हैं, परन्तु अब उन्हें प्रति मास एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों और चिट्ठियों के हालात अबबारों में छपेगे तो यह रिआयत छीनी भी जा सकेगी या कम की जा सकेगी।

परिशिष्ट ५

हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

हम घोषणा करते हैं कि —

- १ हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।
- २ कम्पनी की पूँजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसकी बावत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा-पत्रक के इस अंश के विषय में विशेष-रूप से छूट दे सकती है।)
- ३ पुराने पदेन (ex-officio) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६९ प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे। (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।)
- ४ प्रबन्धक एजेंटो (मैनेजिंग-एजेंट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है।
- ५ एजेंटो की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मदद नहीं करते और न विदेशी सूत या थान मँगाते हैं।
- ६ हम खादी से मिल के कपड़े की होठ न करके और आन्दोलन से उत्पन्न

स्थिति से, कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे।

७ मिलों के मालिक और प्रबन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्प्रिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं।

उक्त घोषणा-पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं —

१ मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा।

२ विधोप कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से की जायगी।

३ हम अपनी कम्पनी का बीमे का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी बीमा-कम्पनियों को देंगे।

४ हम अपना बैंको का काम तथा जहाजों से माल लाने या ले जाने का काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियों को देंगे।

५ अबसे हम जहातक सम्भव होगा बहातक आडिटर, बकील, जहाजों पर माल षडबाने तथा जहाजों से माल उतरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और बेचनेवाले दलाल, ठेकेदार और अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रखेंगे।

६ हम-जहातक सम्भव होगा बहातक स्टोर की चीजें देशी खरीदेंगे। केवल वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जिनके बिना काम नहीं चल सकता और जिनके बजाय देशी नहीं काम आ सकती या मिल सकती। (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवार्य हैं, साथ है।)

७ हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत जो बहिष्कृत मिलों में फाता जाता है, काम में नहीं लायेंगे।

८ हम उस सूत या कपड़े को न धोयेंगे और रंगेंगे जो विदेशी होगा, या बहिष्कृत मिलों में तैयार किया गया होगा।

९ हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरो पर अपनी छाप साफ-साफ लगायेंगे और बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भेजेंगे।

१० हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उसे खादी-जैसा बनायेंगे।

११ हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे —

कोई कपड़ा जो बिना घुला हो या घुला हो, ताने और बाने में एक इंच में जिसमें एक ऊपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हो। बाने में चेको की सादा बुनावट भी है। जो बून्ददार या गोल बक्स पर बने हो और दरिया। (१८ तारों में इकहरे या दुहरे सूत शामिल है। उनका नम्बर १८ या कम होता है।)

• किन्तु मिलें, ड्रिल, साटन, टसरें, जैक्वार्ड मशीन पर बनी टूलें, डीवी नमूने, रगीन रुई से बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

१२ हम सबसे यथासक्ति अपना खरीद-फरोस्त का काम हिन्दुस्तानी हूकानदारों के साथ करेंगे और उन्हीं के द्वारा करावेंगे।

१३ हमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे।

कम्पनी का नाम .

पता .

एजेंटों या मालिकों के नाम .

गैर हिन्दुस्तानी मिलों का घोषणापत्र भी इसी आशय का था। सिर्फ घोषणा का चतुर्थ अंश उसमें सम्मिलित न था।

बम्बई-कांग्रेस-कमिटी ने भी इसी आशय का घोषणा-पत्र प्रचलित किया था। इसमें बिना बम्बई-कांग्रेस-कमिटी से सलाह लिये १० नम्बर से नीचे का कपड़ा न बुनने, ३१ दिसम्बर १९३० के बाढ़ विदेशी सूत, नकली रेशम या रेशमनुमा सूत का प्रयोग न करने की शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तें भी थी —

मिलें राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी की भावना से अपना अनुचित स्वार्थ-साधन न करेंगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रक्षा करेंगी। वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में बेचेंगी।

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इस समय बच रही हैं उन्हें वर्तमान दामों पर या १२ मार्च १९३० को जो दाम थे उनपर—इनमें से जो भी कम हो उनपर—बेचेंगी।

वे खरीदारों को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की विक्री के दाम, जो समय-समय पर होंगे, छपवाकर बँटवाती रहेंगी।

वे समय-समय पर बम्बई प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगी जिनपर अधिक मुनाफ़ा खानेवालों को रोकने के लिए और खरीदारों को बाज़िब दामों पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पक्ष राजी होंगे।

परिशिष्ट ६

जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव

पत्र-व्यवहार

डेली ईरलैंड के सबाबदाता स्लोकोम्ब ने ५० मोतीलाल नेहरू से मिलकर सरकार व कांग्रेस में सधि कराने की चर्चा की थी। इस बातचीत के परिणामस्वरूप सर सप्रू व मि० जयकर ने जुलाई १९३० में वाइसराय से परामर्श किया और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए गांधीजी, ५० मोतीलाल नेहरू व ५० जवाहरलाल नेहरू आदि से जेल में मिलने की आज्ञा मांगी। वायसराय ने १६ जुलाई के पत्र में उन्हें उक्त व्यक्तियों से जेल में मिलने की आज्ञा दे दी। इसके बाद सर सप्रू व मि० जयकर २० गांधी से जेल में मिले और उन्हें अवतक की सारी बातचीत से परिचित किया। महात्माजी ने सधि-चर्चा और गोलमेज कान्फ़रेंस में कांग्रेस के भाग ले सकने का आश्वासन दिया। इस संधि में अपने विचार प्रकट किये और ५० मोतीलाल नेहरू व ५० जवाहरलाल को पत्र लिखा। गांधीजी की शर्तों से दोनों नेहरूओं ने अपना खोबा बहुत मतभेद तो प्रकट किया, लेकिन उसपर बहुत बल नहीं दिया। ५० जवाहरलाल नेहरू ने तो सरकार की हदासीनता देखकर यह भी लिखा कि सरकार सधि-चर्चा के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं दीखती। कहीं ऐसा न हो कि हम खोसा खावें। श्री जयकर ३१ जुलाई को फिर गांधीजी से मिले। सब नेता परस्पर विचार कर सकें, इसलिए यरवडा जेल में १४-१५ अगस्त को निम्न व्यक्ति टकटूटे हुए—म० गांधी, ५० मोतीलाल नेहरू,

प० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। सर सप्रू व मि० जयकर भी उपस्थित थे। बातचीत के बाद नेताओं ने उक्त दोनों सज्जनों को निम्न पत्र लिखा —

यरवडा सेण्ट्रल जेल

१५—८—३०

प्रिय मित्रगण,

आप लोगो ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता कराने का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत अधिक कृतज्ञ हैं। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगो की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं, तथा हम लोगो में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पाच महीनो में देश में जो अद्भुत जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगो में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगो ने जो बहुत अधिक कष्ट-सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त ही हुआ है और न वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाय।

कदाचित् यहा यह बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके अथवा वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है, अथवा वह आन्दोलन कृसयम में खड़ा किया गया है, अथवा अवैध है। अंग्रेजो का इतिहास ऐसी-ऐसी रक्तपूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणो से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं सकते, और उन्होंने हम लोगो को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से विलकूल शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत अधिक मान में और अद्भुत रूप से शान्तिपूर्ण ही है, उनकी निन्दा करना वाइसराय अथवा किसी और समझदार अंग्रेज को शोभा नहीं देता।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम लोगो का तो यही मत है कि सर्व-साधारण जिस आश्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं, वही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहा

कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नतापूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो यह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुषो, स्त्रियो और बच्चो तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठिया खानी पड़े और इनसे भी बढ-बढकर दुर्दशायें भोगनी पड़ें, हम लोगो के लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आप के द्वारा बाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ढूढकर उनका अवलम्बन करने के लिए हम अपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगो की इस बात पर विश्वास करेंगे।

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अभीतक हमें कित्तिज पर ऐसी शान्ति का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। हमें अभीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पडता कि अंग्रेज सरकारी जगत् का जब यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम या मार्ग कौन-सा है? सरकारी कर्मचारियो ने अपने शुभ विचारो की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमे से बहुत-सी घोषणायें प्रायः अच्छे उद्देश्य से की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते। इसर मुद्दतो से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियो की धन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अंग्रेजो मे अब इसनी शक्ति और योग्यता ही नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक ह्रास हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए उद्यत ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे बडा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढे बैठे हैं, उसपर से वे उतर जायें, और प्रायः सी बर्षों तक भारत पर राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगो का नाश और ह्रास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें, और अबतक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये हैं, उनका इस रूप मे प्रायश्चित्त कर डालें।

परन्तु हम यह बात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विज्ञ लोगो के विचार हमारे इन विचारो से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि धामजो के भावो में परिवर्तन हो गया है, और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन अवश्य हो गया है कि जिससे हम लोगो को प्रस्तावित परिपद् में जाकर नम्रिन्नि

होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष प्रकार के वन्दन में पड़े हुए हैं, तो भी अज्ञातक हमारे अन्दर शक्ति है बहातक हम इस काम में प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों का साथ देगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके मित्रता-पूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है—

हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परिपद के सम्बन्ध में जिस मापा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि गत वर्ष लाहौर में जो राष्ट्रीय माग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में बिना विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण-रूप से कोई बात कह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सतोष-जनक न होगा जबतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) उसने भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) पर तथा समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बातों का भी समावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी। (ग) उससे भारतवर्ष को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाय कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पचायत बैठकर इस बात का निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रियायतें आदि प्राप्त हैं, जिनमें भारत का सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, वे सब अधिकार, रियायतें और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

मूचना—अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के जित लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को ठीक जेंचे और वह

उत्त सम्बन्ध में मन्त्रालय-समक्ष घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात में निराशा नहीं रहेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द रह सके जाय, अर्थात् केवल आज्ञा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। परन्तु विरायती कपड़े और धगव, नाडी आदि की दुकानों पर सराफ़ मालिपूरा निर्देष्टा जागी रहेगी, जबतक सरकार स्वयं कानून बनाकर धातु, ताँबी आदि जो मालामाली कपड़े की बिजली बन्द न कर देगी। सब लोग अपने घरों में सराफ़ नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दंड-सम्बन्धी धारायें काम में नहीं आयेगीं। नमक के मन्वारी या लोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा।

(३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्योही उसके साथ वे सब मन्त्रालयों के भी और राजनैतिक कैदी, जो मजा पा चुके हैं परन्तु जो हिंसा के अग्रगण्य नहीं हैं वे जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सत्याग्रह-गोष्ठियों दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून तथा सभी प्रकार के कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तियाँ अन्न की गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायेंगीं। (ग) दत्त सत्याग्रहियों से जो जुमने बसूल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबकी रकमें लौटा दी जायेंगीं। (घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गांवों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी में छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

मचना—अगर जो उप-धारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दत्त लोगों के लिए भी होगा।

(४) वाट्सराय ने अबतक जितने आर्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद्द कर दिये जायेंगे।

(५) प्रस्तावित पण्डित में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायेंगे और समस्त कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किम प्रकार का होगा, इसका निर्णय उभी समय होगा जब पहले ऊपर बतलाई हुई आरम्भिक बातों का सन्तोषजनक निपटारा हो जायगा।

भवदीय—

मो० क० गांधी
मोतीलाल नेहरू
वल्लभभाई पटेल

जयगमदाय दीनगम
मैयद पट्ट
जवाहरलाल नेहरू

कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र

सर सप्रू व श्री जयकर ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलाबार-हिल, बम्बई) से इस आशय का पत्र कांग्रेस-नेताओं को भेजा—

प्रिय मित्रगण,

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर बातें की हैं, उन अवसरों पर आप लोगों ने हमारी बातों को जिस सुजनता और वैर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस बात का दुःख है कि हमने बहुत अधिक समय तक बातें करके आपको कष्ट दिया है, और विशेषतः इस बात का हमें और भी अधिक दुःख है कि प० मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक आने का कष्ट उठाना पड़ा है जबकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। हम नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें दिया था और जिसमें आप लोगों ने वे बातें लिखी हैं, जिनके अनुसार आप कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करने के लिए तैयार हैं कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर वे और गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हों।

जैसा कि आप लोगों को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्थता का काम इन आचार्यों पर अपने ऊपर लिया था—(१) २० जून १९३० को बम्बई में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक-सभापति प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब के साथ बातचीत करके उन्हें जो शर्तें बतलाई थी, एक तो उनके आधार पर, और विशेषतः (२) २५ जून १९३० को बम्बई में प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब को अपने वक्तव्य में लिखकर जो शर्तें दी थी और जिनके सम्बन्ध में उन्होंने (प० मोतीलाल ने) यह मजूर किया था कि इनके आधार पर हम लोग निजी और गैर-सरकारी तौर पर बाइसराय से मिलकर समझौते की बातचीत कर सकते हैं। मि० स्लोकोम्ब ने वे दोनों लेख हम लोगों के पास भेज दिये थे और तब हम लोगों ने बाइसराय से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि हम लोगों को यह इजाजत दी जाय कि हम गांधीजी और पंडित मोतीलाल तथा पंडित जवाहरलाल से बातचीत करें और यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमने ले ली है। अब हम यह देखते हैं कि १४ ता० को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दी हैं जो हम लोगों की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार बाइसराय के पास विचारार्थ भेजी जानी चाहिए, और तब हम लोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी

पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की वातचीत के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जिनमें आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित है जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जायें। आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान में है और ज्योंही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्योंही हम सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर देंगे।

यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आज्ञा मागते हैं कि, जैसा कि हमने आप से कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा त्योंही परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर जायगी अहिंसात्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायेंगे, उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर जिनका सम्बन्ध चटगाव और लाहौर-पड़यन्त्र के मुकदमों से है, बांकी सब आर्डिनेन्स रद्द कर दिये जायेंगे, और गोलमेज-परिषद् में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। यहाँ कदाचित् हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी सम्मति में प० मोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्लोकोम्बवाली मेंट में जो वृत्तिकोण प्रकट किया था और प० मोतीलालजी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्ब ने जो वक्तव्य हम लोगों के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय महोदय ने हम लोगों के नाम भेजा है।

भवदीय—

मुकुन्दराव जयकर

तेजवहादुर सप्रू

वाइसराय का पत्र

इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त को श्री जयकर अकेले शिमला गये और वहाँ उन्होंने वाइसराय से बातें की। २५ ता० को सर तेज-वहादुर सप्रू भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो गये। उस समय २५ और २७ अगस्त के बीच में इन लोगों ने कई बार वाइसराय और उनकी कौंसिल के कुछ सदस्यों के साथ मिलाकर बातें की। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने यह पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं को प्रयाग और पूना में दिखलाने के लिए दिया —

वाइसराय-भवन, गिमला

२८ अगस्त, १९३०

प्रिय सर तेजबहादुर,

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ श्री जयकर और आपने मिलकर जो बातें की, उनके परिणाम की जो सूचना आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगों ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगों को जो पत्र भेजा था और आप लोगों ने उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रतिलिपियाँ आपने मुझे भेजी हैं, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और श्री जयकर को बतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सार्वजनिक हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। यहाँ मैं आपको उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था।

अपने १६ जुलाईवाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास बिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान् सभाद की सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहाँ तक हो सके, हम लोग इस बात का प्रयत्न करें कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकें उतनी अधिक मात्रा में ले लें। हा, वे विषय अभी उनके हाथ में नहीं दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिपक्व इस बात का विचार करेगी कि वे सब विषय कौन-कौन-से हैं और उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा सकती है।

असेम्बली में ६ जुलाईवाले अपने भाषण में मैंने दो बातें भी स्पष्ट कर दी थी। एक तो यह कि जो लोग परिपक्व में जायेंगे, वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विधान-सम्बन्धी सब विषयों पर, उनका ऊँच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे, और दूसरी यह कि परिपक्व जो-कुछ निर्णय कर सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान् सभाद की सरकार अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लमेण्ट के सामने उपस्थित करेगी।

मैं समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि आप भी यह मानते होंगे कि आप लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र जिस ढंग में लिखा गया है और उसमें जो-जो बातें हैं, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ इन्कार किया गया है कि कांग्रेस की नीति

से आर्थिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देश को भारी हानि पहुँची है, उसका ध्यान रखते हुए, मैं नहीं समझता कि उसमें जो सूचनाएँ उपस्थित की गई हैं उनपर धीरे-धीरे विचार करने से कोई लाभ हो सकता है, और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बात-चीत करना असम्भव है। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह बात स्पष्टरूप से उन्हें बतला दोगे।

१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम अंश के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। जब मैंने और आप लोगों ने इस विषय पर विचार किया था, तब मैंने कहा था कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तब वर्तमान परिस्थिति के कारण जो आर्डिनेन्स बनाये गये हैं (उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर जो लाहौर और चटगाव के पदमज वाले मुकदमों के लिए बनाये गये हैं), उनकी कोई आवश्यकता न रह जायगी और मैं उन्हें रद्द कर दूंगा। पर मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मैं इस बात का कोई वचन नहीं दे सकता कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारों के लिए यह सब होगा कि वे उन सब लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के सम्बन्ध में हिंसा को छोड़कर और अपराधों में जेल भेजे गये हैं या जिनपर मुकदमे चल रहे हैं। पर हाँ, मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्बन्ध में उदार नीति का अमल किया जाय, और अधिक-से-अधिक मैं यही वचन दे सकता हूँ कि मैं प्रान्तीय-सरकारों से कहूँगा कि वे प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके अपराध और परिस्थिति आदि का विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

एक बात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा और कांग्रेस के नेता परिषद् में सम्मिलित होना चाहेंगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिए जायेंगे। मुझे स्मरण है कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता या बहुमत रहे, और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार से यह सिफारिश करने में कोई कठिनाई न होगी कि परिषद् में कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहें। मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची मेरे पास भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो, और उस सूची में से मैं उसके प्रतिनिधि चुन लूँगा।

यह उचित जान पड़ता है कि यह सारा पत्र-व्यवहार सीधे ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर दिया जाय, जिसमें सब लोगों को यह मालूम हो जाय कि किन परि-

स्थितियों में आप लोगों को अपने प्रयत्न में विफलता हुई है, और जिन परिणामों को आप लोग आशा करते थे, वे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या स्थिति है (अर्थात् हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं)।

भवदीय—

अविन

बाइसराय को बातचीत

अध्यक्षों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया

कांग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयों का उल्लेख था, उनके सम्बन्ध में बाइसराय के साथ सर सप्रू व जयकर की जो बातें हुई थी, उनके बारे में उन्होंने यह वक्तव्य दिया — हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ अगस्त को प्रयाग के नैनी-बेल में ५० मोतीलाल नेहरू, ५० जवाहरलाल नेहरू और डॉ० महमूद से मिले। हमने उन्हें बाइसराय का उक्त पत्र दिखाया और हम लोगों में जो बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया। उन लोगों के १५ अगस्तवाले पत्र में जिन कई विचारणीय बातों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख बाइसराय के २८ अगस्त वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि बाइसराय के साथ हमारी जो बातें हुई हैं उन्हें देखते हुए हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है—

(क) सासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस पत्र में है जो बाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था। इस सम्बन्ध की बातों का उल्लेख उसके दूसरे पैराग्राफ में है, जहाँ इस विषय की चार मुख्य बातें कही गई हैं।

(ख) एक प्रश्न यह भी है कि गोलमेज-परिषद् में गांधीजी यह प्रश्न उठा सकेंगे या नहीं कि भारत जब चाहे तब साम्राज्य से अलग हो जाय। इस सम्बन्ध में बाइसराय का यह कहना है कि परिषद् सब बातों में बिल्कुल स्वतन्त्र होगी, और यही बात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो हम लोगों को भेजा था। इसलिए वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो विषय चाहे विचारार्थ उपस्थित कर सकता है। परन्तु बाइसराय का यह विचार है कि इस अवसर पर गांधीजी का यह प्रश्न उठाना बहुत ही नासमझी का काम होगा। परन्तु यदि गांधीजी यह विषय भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेंगे, तो

वाङ्मन्यता का यह मत है कि सरकार उस प्रश्न को विचारणीय मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि उनके पर भी गांधीजी यह प्रश्न उठाना चाहेंगे, तो सरकार भारत-मन्त्री को यह सन्देश देगी कि गोलमेज-परिषद् में गांधीजी का यह प्रश्न उठाने का निवार है।

(ग) एक प्रश्न यह है कि गोलमेज-परिषद् में यह विषय विचारार्थ उपस्थित पिया जा माना है या नहीं कि भारत पर जो कई आर्थिक भार हैं, उनकी जाच एक न्याय प्रणाली ने ठीक कर ली जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह गिती तैयार प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विलम्बित तैयार नहीं जिससे कि भारत पर जिनके ऋण हैं वे गन्तव्य समझे जायें और उनके चुकाने से इन्कार किया जाय। परन्तु, जो बातें वह परिषद् में यह कह सकता है कि भारत का अमुक आर्थिक ऋण या देना ठीक नहीं है जो उम्मीद जाय की जाय।

(ग) नमक-कानून की दृष्टि-सम्बन्धी धाराओं को काम में लाने के सम्बन्ध में वाङ्मन्यता का मत है कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कमीशन की सिफारिश मान ली गई, तो यह विषय प्रांतीय सरकारों के हाथ में चला जायगा, जो (२) सरकार की आय में बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं चाहेगी कि उम्मीद जाय का यह मार्ग बन्द हो जाय। परन्तु यदि कांसिलो से नमक-कानून का दफा हटा लिया जायगा और सरकारी आय का घाटा पूरा करने के लिए कोई और नया मार्ग बनना पड़ेगा, तो वाइसराय और उनकी सरकार इस प्रश्न के अन्तर्गत पर विचार करेंगी। परन्तु जबतक नमक-कानून एक कानून के रूप में बना रहेगा, तबतक यदि लोग उगे मुले-आम तोड़ेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी। जब गन्तव्य और शान्ति स्थापित हो जायगी, तब यदि भारतीय नेता वाइसराय और उनकी सरकार ने बातचीत करेंगे कि इस सम्बन्ध में गरीबों का आर्थिक कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेताओं की एक छोटी परिषद् कर सकेंगे।

(द) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यदि पिकेटिंग से किसी वर्ग को कष्ट होगा या उसमें लोगों को क्षति किया जायगा, धमकाया जायगा या बल-प्रयोग किया जायगा, तो सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके सिवा जब शान्ति स्थापित हो जायगी, तब पिकेटिंग-सम्बन्धी आर्डिनेन्स उठा लिया जायगा।

(च) जिन कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया है

या जो अपने पद से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यह विषय मुख्यतः प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता है। तो भी यदि उनके स्थान खाली होंगे और उनकी जगह ऐसे नये आदमी न नियुक्त कर लिये गये होंगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हों, तो प्रान्तीय सरकारों से यह आशा की जा सकती है कि वे उन लोगों को फिर से उनके स्थान पर नियुक्त कर देंगी जिन्होंने आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लोगों ने विवश करके जिनसे इस्तीफे दिलवाये होंगे।

(छ) प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जप्त कर लिये गये होंगे, उन्हें छौटा देने में कोई कठिनाई न होगी।

(ज) लगान-कानून के सम्बन्ध में जो जुर्माने हुए हैं या जो सम्पत्तियां जप्त हुई हैं, उन्हें लौटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कानून के अनुसार जो सम्पत्तियां जप्त हुई हैं, और बेची गई हैं, वे तीसरे आदमी के हाथ में चली गई हैं। जुर्माने लौटाने के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां होंगी। इस सम्बन्ध में वाइसराय केवल यही कह सकते हैं कि प्रान्तीय-सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रखेंगी; और जहातक हो सकेगा, जुर्माने लौटाने का प्रयत्न करेंगी।

(झ) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें भेजा था।

गांधीजी के नाम नेहरूओं का आखिरी सूचना-पत्र

प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू और डॉ० महमूद को पहली दोनो मुलाकातों में सर सप्रू व मि० जयकर ने यह स्पष्ट बतला दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर बतलाये हुए ढंग से आगे समझौते की और बात-चीत हो सकती है, परन्तु वे लोग इस आचार पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस प्रकार है—

नैनी सेक्टरल जेल

३१-८-३०

“कल और आज फिर शीघ्रतः जयकर तथा डॉ० सप्रू के साथ हम लोगो की भेंट हुई और बहुत देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें

दी है जो लॉर्ड अविन ने उन्हें २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड अविन उन शर्तों पर समझौते की बात करना असम्भव समझते हैं जो शर्तें हम सब लोगो ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थी जो सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुत जयकर के नाम लिखा था, और ऐसी स्थिति में लॉर्ड अविन का यह कहना ठीक है कि सर सप्रू और श्रीयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोगो ने यह पत्र सब बातों का बहुत अच्छी तरह विचार करके लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहाँ तक दब सकते थे, वहाँ तक दबे थे। उस पत्र में हमने यह बतला दिया था कि जबतक कई परम आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की जायेंगी और उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोष-जनक घोषणा न कर देगी, तब-तक कोई निराकरण मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश कर सकते थे कि उस दशा में सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगो ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक बातों का सन्तोषजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्दनवाली प्रस्तावित परिपद में कौन-कौन से लोग सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेस के कितने और कैसे प्रतिनिधि होंगे। अपने पत्र में लॉर्ड अविन यहाँ तक कहते हैं कि इन प्रस्तावों के आधार पर समझौते की बातचीत करना ही असम्भव है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगो में न तो समझौता होने की कोई गुंजाइश है और न हो सकती है।

वाइसराय ने अपने पत्र में जो बातें लिखी हैं और जिस ढंग से लिखी हैं, उसे छोड़कर यदि देखा जाय तो भी इधर-हाल में भारत में ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ कार्य किये हैं, उनसे यह सूचित होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना नहीं चाहती। ज्योंही इस बात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्ली में कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक होगी, त्योंही तुरन्त सरकार ने उसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का केवल यही अर्थ हो सकता है कि वह शान्ति नहीं चाहती। इन या और दूसरी गिरफ्तारियों के लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार की और दूसरी कार्रवाइयों के लिए—जिन्हें हम लोग असम्मता और बर्बरता-पूर्ण समझते हैं—हम लोग सरकार की कोई शिकायत नहीं करते। हम उन सब का स्वागत करते हैं। परन्तु हम लोग यह बतला देना उचित और न्यायपूर्ण समझते हैं कि एक ओर तो शान्ति स्थापित करने की इच्छा रखना

और दूसरी ओर स्वयं उम सस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदान कर सकती है और जिनके साथ सरकार बातचीत करना चाहती है, इन दोनों बातों का ठीक मेल नहीं बैठता। प्रायः सारे भारत में कार्य-नमिति गैर-कानूनी ठहरा दी गई है और उसके अधिवेशनों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप में यही अर्थ होता है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध बराबर जारी रहना चाहिए और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह जायगी, क्योंकि जो लोग भारत-वासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत में अंग्रेजी जेलखानों में भर और फँस जायेंगे।

लॉर्ड अविन ने जो पत्र भेजा है और फिटिंग-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि डॉ० सप्रू और श्रीयुक्त जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है। वास्तव में जो पत्र हमें दिया गया है और जो कैफियतें हमें दी गई हैं, उनसे तो कुछ बातों में हम लोग उस स्थिति से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले ग्रहण की गई थी। हमारी स्थिति या बातों और लॉर्ड अविन की स्थिति या बातों में जो बहुत बड़ा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाचित् व्योरे की बातों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

इस प्रकार हम लोगो ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनमें लॉर्ड अविन सहमत नहीं हो रहे हैं, और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम लोगो ने अपने सम्मिलित पत्र में उल्लेख किया था। उनके और हम लोगो के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है और वास्तव में तत्त्व या सिद्धान्त का अन्तर है। हम लोग आशा करते हैं कि आप यह सूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार बल्लभभाई पटेल और श्रीयुक्त जयरामदास झेलतराम को दिखला देंगे और उन लोगो ने परामर्श करके श्रीयुक्त जयकर और सर तेजबहादुर सप्रू को अपना उत्तर दे देंगे।

मोतीलाल

मैयद महमूद

जवाहरलाल

नेताओं का सम्मिलित उत्तर

इसके अनुसार ३, ४ और ५ सितम्बर को सर सप्रू व मि० जयकर ने पूना के गरवडा-जेल में महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मेट की, उन्हें उक्त पत्र दिया और सहमत प्रश्नों पर उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद

किया। इस बातचीत के अन्त में उन लोगों ने उन्हें जो वक्तव्य दिया, वह यहाँ जाता है—

यरवडा सेण्ट्रल

५-६-३०

प्रिय मित्रगण,

श्रीमान् वाइसराय ने २८-८-३० को आप लोगों को जो पत्र लिखा था, हम लोगो ने ध्यान-पूर्वक पढ़ा है। उस पत्र की बातों के सम्बन्ध में वाइसराय से ४ लोगों की जो बातें हुई हैं, उन्हें भी आपने कृपाकर उस पत्र में परिशिष्ट-रूप में सम्मिलित कर दिया है। हम लोगो ने उतने ही ध्यान से वे सूचनायें भी पढ़ी हैं, जिनपर पण मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और प० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं व जो उन लोगों ने आपके द्वारा भेजी हैं। उक्त पत्र तथा बातचीत पर उस सूचना में उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है। इन पत्रों पर हम लोगो ने बराबरी तक विचार किया है और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विचारणें बातें हैं उन सबपर आपके साथ पूरा और स्वतंत्र विचार भी हो चुका है। और जैसा हमने आप लोगों से कहा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के बीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। हमारा इस सम्बन्ध में सारासंसार कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लक्ष्य-से-अधिक जो कुछ कह सकते हैं, वह यही है।

नैनी सेण्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सूचना-पत्र में जो सन्ना भेजी है, उससे हम लोभ पूर्ण रूप से सहमत हैं, परन्तु हमारे उन मित्रों की इच्छा है। इधर दो महीनो से आप लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय करके और बहुत सी कठिनाइयाँ उठाकर शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला दें कि हम लोगों की स्थिति और वक्तव्य क्या है। इसलिए जहातक संक्षेप में हो सकता है, हम यह बतलाने में प्रयत्न करेंगे कि शान्ति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयाँ हैं।

वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह था कि उसमें उन शर्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो प० मोतीलाल गत २० जून को मि० स्लोकोम्ब को बतलाई थी और २५ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० स्लोकोम्ब को अपना जो वक्तव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कही ग

थी। परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाई पड़ती जिससे यह समझा जाय कि प० मोतीलालजी के उक्त वार्तालाप या वक्तव्य में वतलाई हुई शर्तें पूरी होती हैं। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो मूल्य और काम के अंश हैं, वे इस प्रकार हैं —

वार्तालाप में—“यदि यह निश्चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिषद् में किन-किन बातों पर विचार किया जायगा और हम लोगो से यह आशा की जायगी कि हम लोग लन्दन में जाकर बहस करके लोगो को इस विषय का सन्तोष कारायेंगे कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो मैं इसे मजूर नहीं कर सकता। परन्तु यदि यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़ कर बाकी और बातों में परिषद् के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का विधान किस प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम मैं कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करूँगा कि वह परिषद् में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत कर ले। हम लोग अपने घर के आप मालिक बनना चाहते हैं; परन्तु हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जितने समय में अंग्रेजों के हाथ से निकाळ कर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास शर्तें हो जायें। इन शर्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के वाते हम उसी प्रकार मिल सकते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत करता है।”

वक्तव्य में—“सरकार निजी रूप से इस बात का बचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और अधिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो शर्तें तय हो जायेंगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परिषद् में हो जायगा, उन बातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली की माँग का वह समर्थन करेगी।”

इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है—

“मेरी और मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार की भी यही कामना है कि जहाँ तक

हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारत-वासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध वे स्वयं कर सकते हो उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारत-वासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और व्यवस्थाएँ की जानी चाहिएँ, इसपर परिपक्व में विचार होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रखा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा।”

हम लोग समझते हैं कि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अन्तर है। प० मोतीलालजी तो भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रस्तावित गोलमेग-परिपक्व के विचारों के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति से विलक्षण बदल जाय (यह एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय), पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश सरकार की यह हार्दिक कामना है कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी और बातों में वे अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध स्वयं कर सकते हो उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। दूसरे शब्दों में वाइसराय के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती है कि हमें उसी ढंग के कुछ और सुधार मिल जायेंगे जिस ढंग के सुधारों का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारों से हुआ था। हम लोग यह समझते थे कि इसका हमने जो यह अर्थ लगाया है, वही ठीक है, इसलिए अपने १५-८-३० वाले पत्र में, जिसपर प० मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और प० जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगो ने अपना कथन नकारात्मक रखा था और कहा था कि हमारी सम्मति में कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं होगी। अब आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उसमें भी वही पहले पत्रवाली गान दुहराई गई है, और हमें दुःखपूर्वक कहना पड़ता है कि हमारे पत्र का अनादर करके उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है, और हम लोगो ने उसमें जो प्रस्ताव किए थे, उनके आधार पर बातचीत चलना असम्भव है। आप लोगो ने यह कहकर इस विषय पर और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि गांधीजी भारत-सरकार के सामने निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई प्रश्न उपस्थित करेंगे (अर्थात् भारत जब चाहे तब साम्राज्य से पृथक् हो सकता है), तो वाइसराय यही कहेंगे कि यह प्रश्न विचारार्थ ठठ ही नहीं सकता। इसके विप-

रीत हम लोग यह समझते हैं कि भारत में चाहे दिन प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली स्थापित हो, परन्तु यह सब दशा में सर्व-प्रधान अंग है और इसके सम्बन्ध में किसी बहस-मुवाहजे की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली या पूर्ण-स्वराज्य अथवा इसी प्रकार की और कोई शासन-प्रणाली प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक दल को इस बात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तब आपस की हिंसे-दारी का साथ छोड़ सकना है। यदि भारत को साम्राज्य का बंग बनाकर न रखना हो, बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक बराबरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संगित तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे, और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि वह उनमें मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी दशा में यह बात नहीं हो सकती। आप लोग देखेंगे कि जिन वार्तालाप का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, उनमें यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जबतक ब्रिटिश-सरकार या ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना सम्भव है या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तब तक हम लोगों की सम्मति में कांग्रेस की स्वतन्त्रता का युद्ध बराबर जारी रहना चाहिए।

नमक-कर के सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा और नागरिक प्रस्ताव था, उसके विषय में बाइसराय का जो रुत है, उससे सरकार के मनोभावों का एक बहुत ही दुःखद स्वरूप प्रकट होता है। हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि गिनला की ऊँचाई पर मे भारत के शासक यह मनजने में अन्तर्भव है कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिन लोगों-करोड़ों आदिमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊँचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, उनकी आर्थिक इतिहासी क्या है। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब आदिमियों के लिए दारु और ऊँच को छोड़ कर बाकी और चीजों से बढ कर महत्त्व की है। उन नमक पर सरकार ने अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है, उसके विरुद्ध गल पाव नहीं। मैं निर्दोष आदिमियों ने अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार की मज्जा में यह जान नहीं जाई कि उनमें उसकी कितनी अनीति है, तो फिर बाइसराय कि वक्तारों में जो भारतीय लोगों की कोई परिपक्व कुछ भी नहीं कर सकती। बाइसराय ने यह भी कहा है कि जो लोग यह प्रानून गद ब्राना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा गानन भी बनाना चाहिए जिसे सरकार की अपनी ही आय बढ़ जाय जिनकी उम्मेद नमक में होती है। यह एक उम्मेद

मानो हानि पहुँचाने के उपरान्त ऊपर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस रुख से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त काल तक अपनी वह परम व्यय-साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित रखेगी जिससे भारत अब तक बराबर कुचला जाता रहा है। हम लोग यह भी वतला देना चाहते हैं कि केवल यही की सरकार नहीं, बल्कि ममस्त सत्तार की सरकारें जनता-द्वारा उन कानूनों के भग किये जाने को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, जिन कानूनों को जनता अच्छा नहीं समझती परन्तु जो कानूनी हेर-फेर के कारण अथवा और कारणों से तुरन्त ही रद्द नहीं किये जा सकते।

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्त्व की बातें हैं जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के विचार और माँगें उपस्थित की थी, पर उनके सम्बन्ध में भी बाइसराय कुछ भी अप्रसर नहीं हुए हैं। परन्तु यहाँ हम उन बातों पर विचार नहीं करना चाहते। हम लोग आशा करते हैं कि हमने ऐसी महत्त्वपूर्ण यथेष्ट बातें वतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, जो जरूरी दूर नहीं किया जा सकता। तो भी शान्ति के उद्योग में इस समय जो विफलता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के लिए विकट युद्ध में लगी हुई है। इसमें राष्ट्र ने जो अस्त्र ग्रहण किया है, हमारे शासक उसके अस्म्यस्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें उस अस्त्र का भाव और महत्त्व समझने में विलम्ब होगा। इधर कई महीनों में भारतवासियों ने जो विपत्तियाँ सही हैं, उनसे यदि शासकों के मन का भाव नहीं बदला है, तो इससे हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। किसी ने उचित रूप से जो स्वार्थ इस देश में स्थापित किए हो अथवा जो अधिकार प्राप्त किये हो, उनमें से एक को भी कांग्रेस हानि नहीं पहुँचाना चाहती। अंग्रेजों के साथ उसका कोई झगडा नहीं है। परन्तु देश पर ब्रिटिश-आति का जो असह्य प्रभुत्व है, उसका वह अपने पूर्ण नैतिक बल से विरोध करती है और उसपर अपना असन्तोष प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी। हम लोगों का अन्त तक अहिंसात्मक रहना निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही है कि राष्ट्र की कामनायें भी शीघ्र ही पूरी होगी। यद्यपि अधिकारी लोग सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कटु और प्रायः अपमानकारी भाषा का व्यवहार करते हैं, तो भी हमारा यही कथन है।

अन्त में हम लोग फिर एक बार आप लोगों को उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने शान्ति स्थापित करने के लिए उठाया है, परन्तु हम यह मूर्खता कर

देना चाहते हैं कि अभी ऐसा उपयुक्त समय नहीं आया है जबकि समझौते की वान-चीत और आगे चल सके। कांग्रेस-संगठन के प्रधान अधिकारी और कार्यकर्ता इस समय जेलों में बन्द हैं, इसलिए स्पष्टतः हम लोग बहुत विवश हैं। हम लोग दूसरों से नुनी हुई बातों के आधार पर ही सब मार्गें उपस्थित करते रहे हैं और अपने विचार बतलाते रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोष या त्रुटियाँ हों। इसलिए इस समय जिन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः हम लोगों में से किसी के साथ भेंट करना चाहेंगे। उस दशा में, और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी।

श्री० क० गांधी, सरोजिनो नाथडू, बल्लभभाई पटेल, जयरामदास दीक्षितराम।”

परिशिष्ट ७

साम्प्रदायिक 'निर्णय'

साम्प्रदायिक निर्णय का सम्राट् की सरकार ने जो ऐलान किया था वह, अविकल रूप में, नीचे लिखे अनुसार है—

१ सम्राट्-सरकार की ओर से, गोलमेज-परिषद् के दूसरे अधिवेशन के अन्त में, १ दिसम्बर को, प्रधानमन्त्री ने जो घोषणा की थी, और जिसकी ताईद उसके बाव ही पार्लमेण्ट के दोनों हाउसों ने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रहने वाली विविध जातियाँ साम्प्रदायिक प्रश्नों पर किसी ऐसे समझौते पर न पहुँच सकी जो सब दलों को मान्य हो, जिसे निः हल करने में परिषद् असफल रही है, तो सम्राट्-सरकार का यह कृष्ण निश्चय है कि इस वजह से भारत की वैधानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं एक आरजी योजना तैयार करके उसे लागू करेगी।

२ गत १६ मार्च को, यह सूचना मिलने पर कि किसी समझौते पर पहुँचने में विविध जातियाँ लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान

वनने की योजना आगे नहीं बढ़ सकती, सम्राट्-सरकार ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठने वाली कठिनाइयों और विवादास्पद बातों पर वह फिर से सावधानी के साथ विचार करेगी। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि जब तक नये शासन-विधान के अन्तर्गत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम-से-कम कुछ पहलुओं का निर्णय न हो जायगा तब तक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती।

३ इसलिए सम्राट्-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन-विधान-सम्बन्धी प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पार्लमेण्ट के सामने पेश किये जायेंगे, वह ऐसी धारायें रखेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना का कार्य-क्षेत्र जान-बूझकर प्रान्तीय-कौन्सिलों में ब्रिटिश-भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रखा गया है, केन्द्रीय धारा-सभा में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वें पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से नहीं किया गया है। लेकिन योजना, के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय इस बात को महसूस न कर सकना नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समस्याओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्प-संख्यक जातियों के हक में बड़ा महत्त्व है, बल्कि इस आशा से यह निश्चय किया गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनुपात के मूल प्रश्न पर जब एक बार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रश्नों पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं किया जा सका है, सम्भवतः जातियाँ स्वयं ही कोई मार्ग ढूँढ निकालेंगी।

४ सम्राट्-सरकार चाहती है कि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट-रूप से समझ लिया जाय कि इस निर्णय में रद्दोबदल करने के लिए जो भी कोई बात-चीत होगी उसमें वह भाग नहीं लेगी और न इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इसमें सम्बन्धित सभी दलों-द्वारा समर्थित न हो। लेकिन सद्भाग्य से अगर कोई सर्व-सम्मत समझौता हो जाय, तो वह उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती। इसलिए, नया भारत-शासन-विधान कानून बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोष हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियाँ किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक प्रान्तों या मजिस्ट्रेट ब्रिटिश-भारत के लिए, परस्पर एकमत है, तो वह पार्लमेण्ट से इस बात की सिफारिश करने को तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय।

५ गवर्नर-वाले प्रान्तों की कौन्सिलों या लोअर हाउस में, वस्तुतः कि वहाँ

अपर चेम्बर हो, सदस्यों के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ में बतलाये हुए हिसाब के अनुसार रहेंगे।

६ मुसलमान, यूरोपियन और सिक्ख सदस्यों का चुनाव पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खास सूतों में 'पिछड़ा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर रक्खा जाय) उमाम प्रान्त में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी।

पृथक् निर्वाचन

इस बात की स्वयं विधान में गुणाइश रखी जायगी कि जिससे दस वर्ष के बाद निर्वाचन-व्यवस्था का (और ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओं का, जो नीचे दी हुई हैं) इससे सम्बन्धित जातियों की स्वीकृति से, जिने जानने के लिए उपयुक्त तरीके सोचे जायेंगे, पुनरावलोकन कर दिया जायगा।

७ वे सब जायज मतदाता, जो किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई (पैराग्राफ १० देखिए), एंग्लो-इंडियन (पैराग्राफ ११ देखिए) या यूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, आम निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे सकेंगे।

८ बम्बई में कुछ चुने हुए बहुसंख्यक सदस्यों के आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ७ स्थान मराठों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

दलित-जातियाँ

९ 'दलित-जातियों' में जिन्हें मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वाचन-क्षेत्र में मत देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अकेले इस उपाय से इन जातियों के लिए किसी कौन्सिल में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल बहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष स्थान रक्खे जायेंगे, जैसा कि २४वें पैराग्राफ में बताया है। इन जगहों का चुनाव विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमें दलित-वर्ग वाले वही लोग मत देंगे जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे खास निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी आम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास-खास इलाकों में बनाने की मना है जहाँ दलित-वर्गवालों की काफी आबादी है, और मदरास अहाते के अलावा और कहीं ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का सारा इलाका उन्हीं से घिर जाय।

बंगाल में, ऐसा मालूम पड़ता है कि, कुछ आम निर्वाचन-क्षेत्रों में अधिकांश मतदाता दलित-वर्गों के व्यक्ति होंगे। इसलिए, जब तक इस बारे में और अधिक पूछताछ न हो जाय, तब तक, उस प्रान्त में दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। सरकार चाहती यह है कि बंगाल-कौन्सिल में दलित-जातियों के कम-से-कम १० सदस्य तो पहुँच ही जायें।

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है) दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है। सामान्यतः इसका आचार वे साधारण सिद्धान्त होंगे, जिनका कि मताधिकार-समिति की रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तों में, जहाँ अस्पृश्यता की आम कसौटी को लागू करना सम्भवतः कुछ बातों में वहाँ की विशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस सम्बन्ध में थोड़ा रद्दोबदल करना आवश्यक होगा।

सम्राट्-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकता एक सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में वह ऐसी बात रखना चाहती है कि बीस साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पैराग्राफ में उल्लिखित निर्वाचन का सुशोधन करने के आम अधिकार के द्वारा यह रद्द न हो गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे।

भारतीय ईसाई

(१०) भारतीय ईसाइयों के लिए रक्ली जाने वाली जगहों का चुनाव पूर्यक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। यह करीब-करीब निश्चित सा मालूम पड़ता है कि किसी प्रान्त के पूरे इलाके में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन-क्षेत्र बनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी एक या दो चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रक्ले जायेंगे। इन निर्वाचन-क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में मत नहीं देंगे, लेकिन इन इलाकों से बाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे। बिहार और उड़ीसा में विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भारतीय ईसाइयों का काफी बड़ा भाग आदिम जातियों के अन्दर गुमार होता है।

एंग्लो-इंडियन

(११) एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन पृथक्-साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइया उत्पन्न हो तो उनकी तहकीकात करने की गुंजाइश रखते हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इंडियन-निर्वाचन-क्षेत्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, जिनमें मत-गणना डाक से भेजी जाने वाली पत्रियों के द्वारा होगी, लेकिन इस बारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

(१२) पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रक्षित किये जायें उनकी पूर्ति का उपाय अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्यों की जो सख्या रक्खी गई है उसे अभी, जब तक कि ऐसे इलाकों के बारे में की जानेवाली वैधानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम निश्चय न हो जाय, आरजी समझना चाहिए।

स्त्रियाँ

(१३) सम्राट् की सरकार इस बात को बहुत महत्त्व देती है कि नई कौन्सिलों में स्त्री-सदस्यायें भी रहे, चाहे उन की सख्या थोड़ी ही हो। उसका ख्याल है कि प्रारम्भ में, यह व्यय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कुछ स्थान खास तौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न कर दिये जायें। साथ ही उसका यह भी ख्याल है कि स्त्री-सदस्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होनी चाहियें और सो भी बिना किसी अनुपात के। इसलिए खास तौर पर स्त्रियों के लिए रक्खी जाने वाली हरेक 'सीट' का चुनाव एक ही जाति के मत-दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें कि नीचे २४वें पैराग्राफ में स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति बूढ़ निकालने में वह असमर्थ रही है, जिससे कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस शेष योजना के अनुरूप हो कि जिसे ग्रहण करना आवश्यक समझा गया है। अतएव, इसके अनुसार, जैसा कि नीचे २४वें पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है, विभिन्न जातियों में स्त्रियों की विशेष जगहों को खास तौर पर विभाजित कर दिया गया है। इन विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों में किस खास ढंग से निर्वाचन होगा, यह अभी विचाराधीन है।

विशेष वर्ग

(१४) 'मजदूरों' के लिए रक्खी गई सीटों का चुनाव अ-साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। निर्वाचन-व्यवस्था का अभी निश्चय करना है, लेकिन

बहुत सम्भव है कि अधिकांश प्रान्तों में, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिश की है, मजदूर-निर्वाचन-क्षेत्र कुछ तो मजदूर-मण होंगे और कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्र।

(१५) संयोग-व्यवस्था, ग्यानों और खेतिहरो के सदस्यों का चुनाव व्यवस्था-मण (चेम्बर आफ़ डामर्स) और दूसरे विविध-संघों के द्वारा होगा। इन स्थानों की निर्वाचन-व्यवस्था की तफ़्तील के लिए अभी और छान-बीन होना आवश्यक है।

(१६) जमींदारों के लिए रखे गये विशेष स्थानों का चुनाव जमींदारों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा।

(१७) विध्व-विचारध के लिए रखे गये स्थानों का चुनाव किस तरह किया जाय, यह अभी विचाराधीन है।

(१८) प्रान्तीय कोम्मिस्को में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का निर्णय करने में मन्नाट्-मरकार को काफी तफ़्तील में जाना पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हद्दबन्दी तो अभी बाकी ही रह गई है। मरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो सके जिन्दुस्मान में दम दिना में प्रयत्न शुरू कर दिया जाय।

कुछ जगह तो, सदस्यों की जो मर्यादा इस समय रखी गई है सम्भवतः उसमें थोड़ा फ़र्क़ देने में, निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हद्दबन्दी मुकम्मिल तौर पर ठीक हो जायगी। अनएव मन्नाट्-मरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधिकार अपने लिए रखित रखती है, बशर्ते कि उस हेर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात में कोई असली अन्तर न पड़े। लेकिन बंगाल और पंजाब के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर नहीं किया जायगा।

द्वितीय चेम्बर

(१९) विधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में अभी तक तुलनात्मक रूप में, प्रान्ता में द्वितीय चेम्बर रखने के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है, अतः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस बात का निर्णय करने से पहले कि किन-किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिए, और विचार होने की आवश्यकता है।

मन्नाट्-मरकार का विचार है कि प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिसमें, छोटी कौन्सिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच रखे गये अनुपात में कोई खास फ़र्क़ न पड़े।

(२०) केन्द्रीय धारासभा (बड़ी कौंसिल) के आकार और निर्माण के

प्रश्न में फिलहाल सम्राट्-सरकार नहीं पडना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रश्नों के साथ देशी-राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और विचार होना है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय, तमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी।

सिन्ध का पृथक्करण

(२१) सम्राट्-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्ध एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-धर्मे निकलने-लायक सन्तोष-जनक उपाय निकल आयें। क्योंकि सदीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में उठने वाली आर्थिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्राट्-सरकार ने यह ठीक समझा है कि बम्बई-प्रान्त और सिन्ध की पृथक् कौंसिलों की सख्यायें तो दी ही जायें पर उस के साथ ही मौजूदा बम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्, सिन्ध-सहित बम्बई-प्रान्त की) कौन्सिल की सख्यायें भी दे दी जायें।

(२२) बिहार-उड़ीसा के जो अंक दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैं, क्योंकि उड़ीसा को पृथक् प्रान्त बनाने के बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है।

(२३) नीचे दिये हुए २४वें पैराग्राफ में बरार-सहित मध्यप्रान्त की कौंसिल के सदस्यों की जो सख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि बरार की भावी वैधानिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(२४) विभिन्न प्रान्तों की कौंसिलों (सिर्फ छोटी कौंसिलों) में सदस्यों की सख्यायें नीचे लिखे अनुसार रहेगी —

१. सदरास	जमीदार	१
आम (६ स्त्रिया)	१३४	विश्व-विद्यालय . १
दलित-जाति वाले	१८	मन्तूर . ६
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि	१	कुल २१०
मुसलमान (१ स्त्री)	२६	
भारतीय ईसाई (१ स्त्री)	६	२. बम्बई
एंग्लो-इंडियन	२	(सिन्ध-सहित)
यूरोपियन	३	आम (५ स्त्रिया) ६७
उद्योग-व्यवसाय, ज्ञान और खेतिहर	६	दलित जाति वाले १०

पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि .	१	यूरोपियन	२
मुसलमान (१ स्त्री)	६३	उद्योग-व्यवसाय आदि	३
भारतीय ईसाई	३	जमींदार	६
एंग्लो-इण्डियन	२	विश्व-विद्यालय	१
यूरोपियन	४	मजदूर	३
उद्योग-व्यवसाय आदि	८	कुल	२२८
जमींदार . .	३		
विश्व-विद्यालय	१		
मजदूर	८		

५. पंजाब

आम (१ स्त्री)	४३
सिक्ख (१ स्त्री)	३२
मुसलमान (२ स्त्रिया)	८६
भारतीय ईसाई	२
एंग्लो-इण्डियन	१
यूरोपियन	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	१
जमींदार	५
विश्व-विद्यालय	१
मजदूर	३
कुल	२००

३. बंगाल

आम (२ स्त्रिया)	८०
दलित-जाति वाले	०
मुसलमान (२ स्त्रिया)	११६
भारतीय ईसाई	२
एंग्लो-इण्डियन (१ स्त्री)	४
यूरोपियन	११
उद्योग-व्यवसाय आदि	१६
जमींदार	५
विश्व-विद्यालय	२
मजदूर	८
कुल	२५०

४. संयुक्तप्रान्त

आम (४ स्त्रिया)	१३२
दलित-जाति वाले	१२
मुसलमान (२ स्त्रिया)	६६
भारतीय ईसाई	२
एंग्लो-इण्डियन	१

६. बिहार-उड़ीसा

आम (३ स्त्रिया)	६६
दलित-जाति वाले	७
पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि	८
मुसलमान (१ स्त्री)	४२
भारतीय ईसाई	२
एंग्लो-इण्डियन	१
यूरोपियन	२
उद्योग-व्यवसाय आदि	४
जमींदार	५

विश्व-विद्यालय	१	सिक्ख	३
मजदूर	४	मुसलमान	३६
कुल	१७५	जमीदार	२

७. मध्यप्रान्त

(बरार-सहित)

आम (३ स्त्रिया)	७७
दलित-जातिवाले	१०
पिछड़े हुए इलाको का प्रतिनिधि	१
मुसलमान	१४
एंग्लो-इण्डियन	१
यूरोपियन	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	२
जमीदार	३
विश्व-विद्यालय	१
मजदूर	२
कुल	११२

८. आसाम

आम (१ स्त्री)	४४
दलित-जातिवाले	४
पिछड़े हुए इलाको के प्रतिनिधि	६
मुसलमान	३४
भारतीय ईसाई	१
यूरोपियन	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	११
मजदूर	४
कुल	१०८

९. पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त

आम	६
----	---

कुल ५०

सिन्ध-रहित बम्बई और सिन्ध के स्वतन्त्र प्रान्त के लिए भी सदस्यो का मध्या-विभाग किया गया है, जो इस प्रकार है—

१०. बम्बई (सिन्ध निकल जाने पर)	
आम (५ स्त्रिया)	१०६
दलित-जातिवाले	१०
पिछड़े हुए इलाको का प्रतिनिधि	१
मुसलमान (१ स्त्री)	३०
भारतीय ईसाई	३
एंग्लो-इण्डियन	२
यूरोपियन	३
उद्योग-व्यवसाय आदि	७
जमीदार	२
विश्व-विद्यालय	१
मजदूर	७
कुल	१७५

११. सिन्ध

आम (१ स्त्री)	१६
मुसलमान (१ स्त्री)	३४
यूरोपियन	२
उद्योग-व्यवसाय आदि	२
जमीदार	२
मजदूर	१
कुल	६०

विशेष निर्वाचन-क्षेत्र

उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरे के प्रतिनिधियों का चुनाव जिन सस्थाओं के द्वारा होगा वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः यूरोपियनों की होगी और कुछ प्रान्तों में मुख्यतः हिन्दुस्तानियों की, लेकिन उनकी रचना विधान-द्वारा नियन्त्रित नहीं की जायगी। अतएव निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि हरेक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना यह है कि प्रारम्भ में उनकी संख्याएँ लगभग इस प्रकार होंगी —

मदरास—४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी।

बम्बई (सिन्ध-सहित)—५ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी।

बंगाल—१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी।

संयुक्तप्रान्त—२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी।

पंजाब—१ हिन्दुस्तानी।

बिहार-उड़ीसा—२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी।

मध्यप्रान्त (बरार-सहित)—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी।

आसाम—८ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी।

बम्बई (सिन्ध को अलग करके)—४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी।

* सिन्ध—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी।

बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे या नहीं, आम सीटों में से ७ मराठों के लिए सुरक्षित रहेगी।

बंगाल में दलित-जाति के सदस्यों की संख्या का अभी निश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से अधिक नहीं होगी। आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दलित-जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी शामिल है।

पंजाब में जमींदार-सदस्यों में एक 'जमींदार' रहेगा। चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से होगा। निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रक्खा जायगा जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में संभवतः १ हिन्दू, १ सिक्ख और २ मुसलमान होंगे।

आसाम के आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवाले सदस्यों में एक स्त्री के चुने जाने का जो विधान रक्खा गया है उसकी पूर्ति गिलांग के एक असाम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से की जायगी।

प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकरण

नवीन भारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में सम्मति-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब हिन्दुस्तान में पहुँच गया है और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मन्त्री ने निम्न-लिखित वक्तव्य निकाला है —

“न केवल प्रधान-मन्त्री के रूप में, बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने पिछले दो साल से अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली है, मुझे लगता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे समझाने के लिए एक-दो शब्द मुझे भी जोड़ने चाहिए।

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों में हस्तक्षेप करने का हमने कभी इरादा नहीं किया। गोलमेज-परिपद के दोनों अधिवेशनों में हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, जबकि हमने इस बात की बहुत कोशिश की कि हिन्दु-स्तानी लोग खुद ही इस मामले को तय कर लें। क्योंकि शुरू से ही हम यह महसूस करते आए हैं कि हम जो भी निश्चय करे वह कैसा ही क्यों न हो, सम्भवतः हरेक जाति अपनी महत्वपूर्ण भागों के आधार पर उसकी टीका-टिप्पणी करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी और सब जातियाँ देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जोकि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है।

आपसी राजीनामे से निर्णय में संशोधन हो सकता है

हमारा कर्तव्य स्पष्ट था। चूँकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी बात पर सहमत न हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी बाधा उपस्थित हो रही थी जिसका दूर होना प्रायः असम्भव था, अतः सरकार के लिए यह लाजिमी हो गया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करे। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाब में सरकार की ओर से गोलमेज-परिपद में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जो मैंने ब्रिटिश-पार्लमेट में दिया था और जिसपर उसने अपनी महमनि दरसार्द की, सरकार आज प्रांतीय-

कांसिलो के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर रही है। यह योजना यथासमय पार्लियामेंट में पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियाँ अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना पर सहमत न हो जायें।

शासन-सुधारों का प्रस्तावित बिल कानून बने उससे पहले, किसी भी समय, यदि विभिन्न जातियाँ अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सके, तो हमें वही प्रसन्नता होगी। लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में अब और बातचीत चलाना व्यर्थ है, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा सारे ब्रिटिश-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यतः उससे सम्बन्धित सब दलों के लिए सत्तोप-प्रद और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए राजामन्द और तैयार रहेगी।

पृथक् निर्वाचन का मामला

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान रखना आवश्यक है जिनमें कि वह किया गया है। गत अनेक वर्षों से अल्पसंख्यक जातियाँ पृथक् निर्वाचन को, अर्थात् एक खास तरह के मत-दाताओं का अपने तर्ज प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में बँट जाना, अपने अधिकारों का बड़ा भारी संरक्षण समझती आ रही है। पिछले दिनों हुई वैधानिक प्रगति की प्रत्येक अवस्था में पृथक्-निर्वाचन को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना संयुक्त-निर्वाचन की किन्नी एक-सी प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणों को अल्प-संख्यक जातियाँ अभी भी बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं उन्हें खतम करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा। भूतकाल में ऐसा किस प्रकार हुआ, इसकी छान-बीन में पढ़ना व्यर्थ है। मैं तो किसी कदर भविष्य का ही विचार कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि बड़ी और छोटी सब जातियाँ मेल-जोल और शान्ति के साथ संयुक्त-रूप से काम करें, ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े। मगर जबतक ऐसा न हो, जबतक सरकार को तो वस्तु-स्थिति का ध्यान रख कर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण रूप कायम रखना ही पड़ेगा।

दलित-जातियों की स्थिति

इस निर्णय की दो विशेषतायें हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है। इनमें से एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियों से है और दूसरी का स्थियों के प्रति-

निधित्व से। सरकार ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें में किसी एक की भी अनिवार्यता का खयाल न किया गया हो।

दलित-जातियों के मामले में हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रान्तों में जहाँ उनकी संख्या अधिक है, प्रान्तीय कौंसिलों में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके साथ पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अलगपन स्थायी हो जायगा। अतएव, दलित-वर्गों के मत-दाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुना हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तर-दायित्व है उससे प्रभावित होगा, लेकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहाँ कि खास तौर पर ऐसे दलित मतदाता होंगे, विशेष निर्वाचन-मण्डलों द्वारा होगा। इस प्रकार दलित-वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात से होता है कि उनकी भागों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज़रूरत है।

स्त्रियों के अधिकार

स्त्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह जाना जा चुका है कि उन्नति की एक कुजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि जबतक भारत की स्त्रियाँ शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न लें तबतक भारत उस स्थिति को नहीं पहुँच सकता जो वह ससार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक ढंग देने में बहुत बड़ी आपत्तियाँ हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए सदस्य-स्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संख्या का उपयुक्त विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह योजना पेश करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समतोलता बनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्न है। उम्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर लें, हालांकि सहसा किसी भी जाति को यह सन्तोष नहीं होगा कि भारत की वैधानिक प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व

के लिए इस ऐसी संस्था की स्थापना की जायेगी जिसमें उम्मीद है कि प्रायोगिक प्रगति की पूर्ति हो जाती हो :
 दूसरा यह कि प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई

साम्प्रदायिक महयोग, उन्नति की शक्ति

इसमें, मैं मानता हूँ कि प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई

२

गोलमेन्-गर्गिडू का अल्पसंख्यक समझौता और साम्प्रदायिक निर्णय

(तुलनात्मक अध्ययन)

गोलमेन्-गर्गिडू के अल्पसंख्यक समझौते और ब्रिटिश-सरकार
 के अल्पसंख्यक निर्णयों में प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई

अल्पसंख्यक समझौते में प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई

प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई
 संस्था हो जिसमें प्रायोगिक प्रगति के लिए जो आवश्यक है कि ऐसी कोई

लेकिन ऐसे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की सदस्य-संख्या न भी

वहे तो भी सरकारी निर्णय में दी गई और अल्पसंख्यक समझौते में मांगी गई सत्याबो पर एक तुलनात्मक नजर डालना अरोचक न होगा।

प्रान्त	के फ़ैसिल सदस्यो संख्या	हिन्दू			मुसलमान	ईसाई	एंग्लोइण्डियन	यूरोपियन	सराही	सिक्ख
		सर्वण	दलित	कुल						
आसाम	{ अ० स०	१००	३८	१३	५१	३५	३	१०	०	
	{ सा० नि०	१०८	४४	४	४८	३४	१	७	०	
बंगाल	{ अ० स०	२००	३८	३५	७३	१०२	२	३	२०	०
	{ सा० नि०	२५०	७०	१०	८०	११२	२	४	११	०
बिहार-उड़ीसा	{ अ० स०	१००	५१	१४	६५	२५	१	१	५	३
	{ सा० नि०	१७५	६६	७	१०६	४२	२	१	७	५
बम्बई	{ अ० स०	२००	८८	२८	११६	६६	२	३	१३	०
	{ सा० नि०	२००	८७	१०	९७	६३	३	२	४	०
मदरास	{ अ० स०	२००	१०२	४०	१४२	३०	१४	४	५	२
	{ सा० नि०	२१५	१३४	१८	१५२	२६	२	३	३	१
पंजाब	{ अ० स०	१००	१४	१०	२४	५१	१५	१५	२०	२०
	{ सा० नि०	१७५	०	०	४३	८६	२	१	१०	३२
संयुक्तप्रान्त	{ अ० स०	१००	४४	२०	६४	३०	१	२	३	०
	{ सा० नि०	२२८	१३२	१२	१४४	६६	२	१	२	०
मध्यप्रान्त	{ अ० स०	१००	५८	२०	७८	१५	१	२	२	२
	{ सा० नि०	११२	७७	१०	८७	१४	१	१	१	२

परिशिष्ट ८

गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट

१

पत्र-व्यवहार का आधार

गोलमेज-परिषद् की अल्प-संख्यक समिति की अन्तिम बैठक में (१३-११-३१) गांधीजी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :—

“अन्य अल्प-संख्यक जातियों के दावे को तो मैं समझ सकता हूँ, किन्तु अंग्रेजों की ओर से पेन किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय था है। उनका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलक सदैव के लिए कायम रहे।

“भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं अछूतों के वास्तविक हित को न देखूंगा। मैं स्वयं अछूतों के विनाश समुदाय का प्रतिनिधि होने का शान्त मानता हूँ। यहाँ मैं केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से भी बोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय तो मुझे उचित मत मिलेगा और मेरा नम्रवर सबके ऊपर होगा। और मैं भारत के एक ठोके में दूसरे छोर तक बौरा करके अछूतों से कहूँगा कि अस्पृश्यता दूर करने का उपाय तुम्हारे निर्वाचक-मण्डल अथवा कौंसिलों में विरोध रक्षित स्थान नहीं है।

“इस समिति को और समस्त जनता को यह जान लेना चाहिए कि मैं हिन्दू-समाज में सुधारको का ऐसा समूह मीजुद हूँ जो अस्पृश्यता के उन्मूलन को, जो उनका नहीं प्रत्युत कट्टर एवं दृढिवादी हिन्दुओं का उद्देश्य है, धोले के पानी में नमक मिला देता है। हम नहीं चाहते कि हमारे इजिप्शियनों में और हमारी मर्दमनुमानी में अस्पृश्यता नाम की जुदा जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अंग्रेज सदा के लिए अंग्रेज रह जायेंगे हैं, किन्तु क्या अछूत भी, सदैव के लिए अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इससे जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ मैं समझूंगा कि हिन्दू-धर्म दूब जाय।

“इसलिए डॉ० अम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देने की योजना — तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करने की योजना — मैं पूर्णतः पूर्वक कहूँगा, कि उन्होंने जो कुछ किया है वह अत्यन्त बुरा और भयानक है।

किया है, और कदाचित् उन्हें जो कटु अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दुःख है, किन्तु यदि मैं यह न कहूँ तो अछूतों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणों के समान हैं, मैं सच्चा न होऊँगा। सारे ससार के राज्य के बदले भी मैं उनके अधिकारों को न छोड़ूँगा। मैं अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकर जब सारे भारत के अछूतों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है, इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जायेंगे वह मैं जरा भी सन्तोष के साथ देख नहीं सकता।

“अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जायें तो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं, मैं वह सह लूँगा, किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायें, तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी, वह मुझसे सही न जा सकेगी। जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि मैं अकेला होंऊँ तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।”

२

पत्र-ज्यवहार

१. गांधीजी ने ११ मार्च १९३२ को यरवडा-जेल से निम्नलिखित पत्र सर सेम्युअल होर के पास भेजा :—

प्रिय सर सेम्युअल होर,

आपको कदाचित् स्मरण होगा कि गोलमेज-परिषद् में अल्प-संख्यकों का दावा उपस्थित होने पर मैंने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि मैं दलित-जातियों को पृथक्-निर्वाचन का अधिकार दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूँगा। यह बात जोश में आकर या अलंकार के लिए नहीं कही गई थी। वह एक गम्भीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मैंने भारत लौटने पर पृथक्-निर्वाचन के, कम-से-कम दलित वर्गों के लिए, विरुद्ध लोकमत तैयार करने की आशा की थी। पर यह होनहार न था।

दलित-वर्गों को पृथक् निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझे कौन-सी

आपसिया है, उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं उन्हींमें से एक हूँ। उनका मामला दूसरो से बिल्कुल भिन्न है। कांसिलो में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के विरुद्ध मैं नहीं हूँ। मैं तो इसे पसन्द करूँगा कि उनमें से प्रत्येक वालिग—स्त्री-पुरुष दोनों—को शिक्षा या सम्पत्ति किसीका भी विचार न कर मतदाता बनाया जाय, यद्यपि दूसरो के लिए अतिधिकार की योग्यता इससे अधिक हो। पर मेरा मत है कि पृथक्-निर्वाचन उनके लिए और हिन्दू-धर्म के लिए हानिकर है, चाहे केवल राज-नैतिक दृष्टि से यह कैसा ही क्यों न हो। पृथक्-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी उसे समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के बीच बने हुए हैं और उनके आश्रित हैं। जहातक हिन्दू-धर्म का सम्बन्ध है वह तो पृथक्-निर्वाचन से छिन्न-भिन्न हो जायगा।

मेरे लिए इन वर्गों का प्रश्न मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। राजनैतिक दृष्टि, यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, नैतिक और धार्मिक दृष्टि के सामने नगण्य हो जाती है।

इस सम्बन्ध में मेरे भाव आपको यह स्मरण करके समझने होंगे कि इन वर्गों की स्थिति के सम्बन्ध में मुझे बचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए मैं अनेक बार अपना सब-कुछ खोने के लिए तैयार हो चुका हूँ, मैं यह आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी प्रायश्चित्त उस क्षति की किसी भी अंश में पूति नहीं कर सकता जो उन्होंने दलित-वर्गों को सदियों से जान-बूझकर गिरा रखकर की है। पर मैं जानता हूँ कि पृथक्-निर्वाचन न प्रायश्चित्त है और न उस गहरे पतन की औपधि, जिससे दलित-वर्ग कष्ट पा रहे हैं। इसलिए मैं सम्राट्-सरकार को सविनय सूचित करता हूँ कि यदि आपके निश्चय से दलित-वर्गों को पृथक्-निर्वाचनाधिकार मिलेगा तो मुझे आमरण अनशन करना होगा।

मैं जानता हूँ—और मुझे दुःख है—कि कैदी की दगा में मेरे ऐसा करने से सम्राट्-सरकार को बड़ी परेशानी होगी और बहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित समझेंगे कि मेरे वर्ग का अनुप्य राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी-कार्यप्रणाली प्रचलित करे जिसे वे अधिक नहीं तो पागलपन कहेंगे। अपने पक्ष-समर्थन के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए वह कार्य, जिसे करने का मैंने विचार किया है, उद्देश्य-साधन की कोई प्रणाली नहीं बनूँ मेरे अस्तित्व का एक अंग है। यह मेरी आत्मा की पुकार है जिसकी मैं अवज्ञा नहीं कर सकता चाहे, इससे मेरे समक्षदार होने की ख्याति नष्ट हो क्यों न हो जाय। इस समय जहातक मैं देखता हूँ, मेरा जेल से छूट जाना भी मेरे

अनशन के कर्तव्य को किसी प्रकार कम आवश्यक न बना सकेगा। इतने पर भी मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशंका विलकुल निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार दलित-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था करने का विलकुल विचार नहीं कर रही है।

आयद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता है। वह है दमन का प्रकार। मैं नहीं कह सकता कि कब मुझे ऐसा धक्का लगे जो इस त्याग के लिए मुझे बाध्य कर दे। दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतंक फैल रहा है। अंग्रेज और भारतीय अधिकारी पागलक बनाये जा रहे हैं। छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-घात और अपने ही भाइयों के साथ अमानुष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। देशवासी भयभीत किये जा रहे हैं। आपण-स्वातन्त्र्य नष्ट कर दिया गया है। अमन-कानून के नाम पर गुण्डागारी चल रही है। सार्वजनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिलाओं की आवाज जाने का भय है।

मेरी राय में यह सब इसलिए किया जा रहा है, कि कांग्रेस स्वतन्त्रता के जिस भाव का समर्थन कर रही है वह कुचल डाला जाय। नागरण कानून की सविनय-अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित घासन के नये हुकमों को, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को नीचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है।

इन कार्यों में मुझे तो लोकतंत्र का आद विलकुल नहीं दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि हाल में मैंने इंग्लैंड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतंत्र सिर्फ ऊपरी और दिखाऊ है। अधिक-से-अधिक महत्त्व की बातों में व्यक्तियों और समूहों ने पार्लियमेंट की राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो आयद ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मिस्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १९१४ के युद्ध के सम्बन्ध में यही हुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है। लोकतंत्र नामक पद्धति में एक आदमी को इतना बड़ा और अनियंत्रित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक लोगों के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैसी आज्ञा दे, तथा उन आज्ञाओं को काम में लाने के लिए विनाश के सबसे भयंकर यन्त्र को मैदान में ले आवे, इन

कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है। मुझे तो यह लोकतन्त्र का अभाव मालूम होता है।

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही सराव हो चुका है, और सराव किये बिना नहीं रह सकता। मैं इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ? मधिनय-अवज्ञा को मैं इसके लिए रोक नहीं सकता। मेरा उसपर धर्म के जैसा विश्वास है। मैं अपने-आपको स्वभावतः लोकतन्त्रवादी समझता हूँ। मेरे लोकतन्त्र में, बल-प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरो पर लादना सम्भव नहीं है। अतः जहाँ-जहाँ बल-प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरो पर उपयोग करने के लिए ही मधिनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है। यह कष्ट उठाने की क्रिया है, और यदि आवश्यक हो तो मधिनय-अवज्ञा करनेवाले को मृत्यु तक अनशन करना चाहिए। वह समय मेरे लिए अभी नहीं आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट जवाबों में आदेश नहीं दे रही है। पर बाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी काप रहा है। अतः जब मैं आपको यह लिख रहा हूँ कि दलित-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव है तब यदि साथ ही यह भी न बता दूँ कि इसके सिवा भी अनशन की एक और सम्भावना है, तो मैं आपसे सच्चा व्यवहार न करूँगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे मैंने अपनी ओर से बहुत ही गुप्त रखा है। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री महादेव देसाई, जो अभी हमारे साथ रहने को भेजे गये हैं, इस सम्बन्ध में सब-कुछ जानते हैं। पर आप इस पत्र का चाहे-जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे।

हृदय में आपका—

मो० क० गांधी

२ सर सेम्युअल होर ने १५ अप्रैल १९३२ को गांधीजी को निम्न उत्तर भेजा —

इडिया आफिस, ब्लाइट हॉल,
१३ अप्रैल, १९३२

प्रिय गांधीजी,

आपकी ११ मार्च की चिट्ठी के उत्तर में मैं यह लिख रहा हूँ, और मैं पहले ही कह देता हूँ कि दलित-श्रेणियों के लिए पृथक्-निर्वाचन के प्रश्न पर आपके भावावेग को मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न के केवल गुणावगुणों पर जो भी निर्णय आवश्यक हो उसे हम करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि लॉर्ड

लोगियन की कमिटी ने अपना दौरा समाप्त नहीं किया है और वह जिन किसी निम्नचर पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जायेंगे। जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तब उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा, और हम तबतक कोई निर्णय न करेंगे जबतक हम कमिटी के विचारों के बिना उन विचारों पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हें आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर के साथ प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे त्याग में होते तो आप भी ठीक वैसा ही कार्य करते जैसा हम करना चाहते हैं। कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उसपर पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँचने के पहले उन मतों पर ध्यान दीजिए जिन्हें दोनों पक्षों ने इस विवादग्रस्त प्रश्न पर प्रकट किये हैं। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं सम्मता कि आप मुझसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे।

आर्किनेन्सो के सम्बन्ध में मैं वही बातें दुहरा सकता हूँ जो मैं सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से कह चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित सरकार की नींव पर ही जान-बूझकर आक्रमण होते देख उन्हें जारी करना आवश्यक था। मुझे यह भी विश्वास है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं और इस बात की भरसक कोशिश कर रही हैं कि उनका बेजा और बदले की भावना से उपयोग न किया जाय। आतंककारी कार्यों में अपने अपमरों और जाति के अन्य वर्गों की रक्षा करने तथा कानून और व्यवस्था के तत्त्वों को बनाये रखने के लिए जितने समय तक असाधारण उपायों से काम लेने को हम बाध्य हैं उसमें अधिक समय तक हम उन्हें जारी न रखेंगे।

आपका—

नेम्युअर होर

३. गांधीजी ने दरबहा जेल से १८ अगस्त १९३२ को प्रज्ञान-मन्त्रों को निम्न पत्र भेजा —

प्रिय मित्र,

दलित-वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ११ मार्च को मेने मर नेम्युअर होर को जो चिट्ठी लिखी वह उन्होंने आपकी तथा मन्त्रि-मण्डल की दृष्टि दी होगी। वह चिट्ठी उन चिट्ठी का अद्य समती जाय और इनकी साथ पड़ी जाय।

मेने अन्यमन्त्रों के प्रतिनिधित्व पर मन्त्रि-मण्डल का निश्चय पड़ा है और

पढकर उदासीन-भाव से अलग रख दिया है। मैंने सर सेम्युअल होर को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जेम्स पैलेस में १३ नवम्बर १९३१ को बोलमेज-परिषद् की अरपमट्यक-समिति में जो घोषणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोध मैं अपने प्राणों की धाजी लगाकर करूँगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि मैं प्राण त्यागने तक लगातार अनशन करने की घोषणा कर दूँ और नमक और सोडा के साथ या उसके बिना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करूँ। यह अनशन तभी समाप्त होगा जब इस व्रत के रहते ब्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक मत के दबाव से अपने निश्चय पर फिर विचार करे और साम्प्रदायिक-निर्वाचन की अपनी योजना, दलित-धर्मों के सम्बन्ध में, वापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से हो और सबका समान-मताधिकार रहे, फिर यह कितना ही व्यापक क्यों न हो जाय।

यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन साधारण जब्त्या में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा।

मेरी यह भी इच्छा है कि मेरी यह चिट्ठी और सर सेम्युअल होर की लिखी हुई चिट्ठी शीघ्र-से-शीघ्र प्रकाशित की जाय। मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिट्ठियों का मजमून सरदार बल्लभभाई पटेल और महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और किसीको नहीं बताया है। पर यदि आप इसे सम्भव बना दें तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिट्ठियों का प्रभाव जनता पर पड़े। इसलिए उन्हें शीघ्र प्रकाशित करने का मैं अनुरोध करता हूँ।

छेद है कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर मैं अपनेको शारीरिक पृथक् समझता हूँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। सर सेम्युअल होर को मैंने जो चिट्ठी लिखी उसमें मैं कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मुझे छोड़ देने का निश्चय भले ही करे, पर मेरा अनशन बराबर जारी ही रहेगा क्योंकि अब मैं अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की आशा नहीं कर सकता। और सम्मानयुक्त उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा लेने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है।

सम्भव है, मेरा निर्णय द्रुपित हो और मेरा यह विचार बिल्कुल गलत हो कि दलित-धर्मों के लिए पृथक्-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकारक है। यदि ऐसा हो तो अपने जीवन-सिद्धान्त के अन्य अंगों के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की

सम्भावना नहीं। उस दशा में अनगन करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रायश्चित्त होगा और उन असह्य स्त्री-पुरुषों के सिर में एक बोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझ-दारी पर बालको-जैसा विश्वास रखते हैं। पर यदि मेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे सन्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निष्पत्ति से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित रूप से पूर्ण होगा, जिसके लिए मैंने २५ साल से भी अधिक समय में यत्न किया है और जिसमें काफी सफलता मिली है।

आपका विश्वसनीय मित्र—

मो० क० गांधी

४. प्रधान-मन्त्री श्री रैमजे मँकडानल्ल ने ८ सितम्बर को

निम्न पत्र गांधीजी के पास भेजा :—

प्रिय गांधीजी,

आपका पत्र मिला। पढ़कर आश्चर्य, और कहना चाहता हूँ कि, बहुत ही हार्मिक दुःख भी हुआ। इसके सिवा मैं यह कहने के लिए भी बाध्य हूँ कि दलित-वर्ग के सम्बन्ध में सम्राट्-सरकार के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने में आपको भ्रम हो रहा है। हम इस बात को सदा समझते रहे हैं कि आप दलित-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दिये जाने के अटल विरोधी हैं। गोलमेज-परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति में आपने अपनी स्थिति विलकुल साफ तौर से बताई थी और अपने ११ मार्चवाले पत्र में सर सेम्युअल होर को फिर से भी आपने अपना मत बताया था। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस विषय में वही मत है जो आपका है। अतः दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करते समय हमने उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया।

अछूतों की समस्याओं से मिली हुई बहु-संख्यक अपीलें तथा उनकी सामाजिक बाधाओं के विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद आप भी अनेक बार स्वीकार कर चुके हैं, कौंसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्याययुक्त अधिकार की रक्षा करना हमने अपना कर्तव्य समझा। साथ ही हमें इस बात का भी उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई ऐसी बात न होनी चाहिए जो अछूतों को सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दे। अपने ११ मार्चवाले पत्र में आपने खुद ही कहा है कि आप अछूतों को कौंसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के खिलाफ नहीं हैं।

सरकारी योजना के अनुसार अछूत हिन्दू-जाति के अंग बने रहेंगे और उनके साथ बराबरी की हैसियत में शामिल होकर वोट दे सकेंगे। पर २० साल तक निर्वाचन में, हिन्दुओं के साथ शामिल रहते हुए भी, थोड़े-से खास हलकों के जरिये अपने स्वार्थों की रक्षा का उपाय करते रहेंगे, जो हमारा निश्चय है कि वर्तमान स्थिति में आवश्यक है।

जहां-जहां ऐसे हलके बनाये जायेंगे, अछूत-वर्ग साधारण हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्र के वोट से वंचित न होंगे, बल्कि उन्हें दो-दो वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, जिसमें हिन्दू-जाति के साथ उनका सम्बन्ध बयिकल बना रहे।

आप जिसे साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र कहते हैं, अछूतों के लिए वैसे हलके हमने जान-बूझकर नहीं बनाये हैं और सम्पूर्ण अछूत-वोटरो को साधारण अर्थात् हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में शामिल कर दिया है, जिसमें उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को अछूत-वोटरो के पास जाकर वोट मागना पड़े अथवा अछूत उम्मीदवारों को ऊँची जाति-वाले हिन्दू वोटरो के पास वोट मागने जाना पड़े। इस प्रकार हिन्दू-जाति की एकता की सब प्रकार से रक्षा की गई है।

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरम्भिक काल में जब प्रान्तों में शासनाधिकार उसी वर्ग के हाथ में रहेगा जिसका कौंसिल में बहुमत होगा अलबत्ता यह आवश्यक होगा कि दलित वर्ग, जिसके विषय में आप खुद भी स्वीकार करते हैं कि उच्च जाति के हिन्दुओं ने अताबियों से उन्हें नीची अवस्था में डाल रखा है, ६ में से ७ प्रान्तों की कौंसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी भेज सके जो उनके दुःख-दर्दों और आदर्शों को प्रकट कर सकें और उनके विरुद्ध निर्णय होने से रोक सकें, अर्थात् जिनके द्वारा इस वर्ग का मत प्रकट हो सके। प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को इस व्यवस्था की आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। हमारे विचार से वर्तमान परिस्थिति में सरक्षित-स्थान-सहित समुक्त-निर्वाचन की व्यवस्था में दलित-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य कौंसिलों में भेजना समझ होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने जिम्मेदार हों, चाहे मताधिकार की जितनी भी व्यवस्थायें इस समय सम्भव हैं उनमें से कोई भी क्यों न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था से उनके प्रायः नयी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने जायेंगे।

हमारी योजना में अछूतों को साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में मतानिका देते हुए उनके लिए थोड़े से अलग हलके बना दिये गये हैं। मुसलमान आदि अल्प-संख्यकों के लिए की गई साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाव में मर्यादा निम्न

है। एक मुसलमान साधारण हलके में बोट न दे सकता है और न उम्मीदवार हो सकता है। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगहें दी गई हैं उससे वे एक भी अधिक नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर प्रान्तों में उन्हें अपनी जन-संख्या के अनुपात से अधिक जगहें दी गई हैं। पर दलित-वर्ग को खास हलकों के द्वारा जो जगहें दी गई हैं वे बहुत अल्प हैं और उनकी जन-संख्या के अनुपात के विचार से नहीं नियत की गई हैं। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वे कांसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवश्य भेज सकें जो केवल उनकी चुने हों। हर जगह उनके इन विशेष स्थानों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से बहुत कम है।

मैं समझता हूँ कि आप जो अनसन के द्वारा प्राण-त्याग का विचार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य न तो यह है कि दलित-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ समुक्त-निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल हो, क्योंकि यह अधिकार तो उन्हें मिल ही चुका है, और न यही है कि हिन्दुओं की एकता बनी रहे, क्योंकि इसका भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल यह है कि अछूत लोग, जिनके लिए आज भीषण बाधाएँ उपस्थित होने की बात सभी स्वीकार करते हैं, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो उनके अपने चुने हुए हों और जो उनके भाग्य की निर्णायक कांसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बोल सकें।

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्त तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावों को देखते हुए मेरे लिये आपके निश्चय का कोई समुचित कारण देख सकता संबंधा असम्भव हो गया है और मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति को समझने में भ्रम हो जाने के कारण आपने ऐसा निश्चय किया है।

जब आपस में समझौता न कर सकने पर भारतीयों ने आमतौर से अभील की तब कहीं उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाना स्वीकार किया। अब वह उसे सुना चुकी है और अब जो शर्तें उसमें रखी गई हैं उनके सिवा और किसी तरह वह बदला नहीं जा सकता। अतः मुझे खेद के साथ आपसे यही कहना पड़ रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायों का आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था के बदले स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामञ्जस्य करने की सच्ची नीयत से तजवीज किया है।

आपका—

जे० रैमजे मैकडानलड

५. गांधीजी ने दरवाजा मेन्दल जेल से ६ मितम्बर १९३२ को प्रधानसजी को निम्न पत्र भेजा —

प्रिय मित्र,

अनशन नाम भोजन न लेना और प्राप्त हुए आपके म्याट जीर पूर्ण उत्तर के लिए मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ। नागपि मुझे मंद है कि आपने मेरे निश्चय का ऐसा अर्थ दिया जिससे मुझे अभी भयानक लग रहा था। मैं उसी घबराहट की ओर से बोलने का दावा करता हूँ जिससे मैंने भयानक भयानक लगने के लिए, आप कहते हैं, मैं अनशन करके मर जाना चाहता हूँ। मुझे यथा 'मैं' के लिए आगिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण अर्थ न पड़ेगा। दरिद्रों को भयानक भयानक लगने के लिए यह विषय शूद्र धार्मिक विषय है। केवल यही बात कि 'दलित' वर्गों को द्वितीय गत मिले है, उन्हें या सामान्यतः हिन्दू समाज को तत्काल गम न मिले रोखती। 'दलित' वर्गों के लिए पुण्य-निर्वाचन की स्थापना नाम में मुझे उम्र और के श्रेष्ठजन की गंध मिलती है जिससे हिन्दुत्व लुप्त हो सकता है और 'दलित' वर्गों को कुछ लाभ नहीं मिल सकता। कृपाकर मुझे यह कहने दीजिए कि आप निम्न की महानुभूति क्यों न रखते हों, आप ऐसे विषय में ठीक-ठीक निश्चय कर नहीं पड़ेंगे जहाँ हिन्दू और अछूत दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है और धार्मिक दृष्टि में बहुत महत्त्व रखता है।

मैं 'दलित' वर्गों के आवश्यकता में भी अधिक प्रतिनिधित्व को विरोध न करूँगा। मैं इसी बात के विरुद्ध हूँ कि वे कानून बनाकर हिन्दू-समाज से पुण्य कर दिये जायें (किन्तु पापार्थक्य विना ही सीमित क्यों न हों) जबतक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका निश्चय बना रहा और शासन-विज्ञान नाम में आ जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन की दृष्टि दिलाई अपने दलित भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्य की आवश्यकता उन्नति को रोक देंगे ?

अतः मुझे चेदपूर्वक अपने पूर्व-निश्चय पर कायम रहने को लाचार होना पड़ता है।

आपकी चिट्ठी में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके निर्णय के अन्य अर्थों से मैंने 'दलित' वर्गों के प्रश्न को अलग कर उसपर खास तौर से जो विचार किया है उसका यह अर्थ नहीं होता कि मैं आपके निर्णय के अन्य अर्थों में सहमत हूँ। मेरी राय में अन्य कई अर्थ बहुत ही आपत्तिजनक हैं। पर मैं उन्हें ऐसा

नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बलिदान करने की प्रेरणा करे जितना मेरी अन्तरात्मा ने 'दलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की है।

आपका विश्वसनीय मित्र—

मो० क० गांधी

६ गांधीजी ने १५ सितम्बर को अनशन के निश्चय के सम्बन्ध में दम्बई-सरकार को अपना जो बक्तव्य भेजा था और जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया गया था, वह इस प्रकार है :—

'मेरे अनशन का निश्चय ईश्वर के नाम पर, और जैसा कि मैं सज्जता के साथ विश्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए टाल दूँ, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल जाय। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अब उसके दिन को कौन कहे, घण्टे को बदलना भी मेरे बस की बात नहीं है। प्रधान-मंत्री के पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता।

'मेरा भावी अनशन उन लोगों के विरुद्ध है जो मुझमें विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपियन, और उनके वास्ते नहीं है जो मुझमें विश्वास नहीं रखते। इसलिए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्त्री-मुत्सों के विरुद्ध है जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को अनसुना करके भी मुझमें विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय-मगत मानते हैं। वह मेरे उन देशवासियों के विरुद्ध भी नहीं है जो मुझमें विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन अगणित देशवासियों के विरुद्ध है—चाहे वे किसी भी दल और विचार के क्यों न हों—जिनका विश्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज की अन्तरात्मा को सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश्य है।

'केवल आवोहीपन मेरे सकलित उपवास का उद्देश्य न होगा। मैं अपना सारा वजन—जो कुछ भी वह है—न्याय, शुद्ध न्याय के पल्ले पर धर देना चाहता हूँ। अतः मेरी प्राण-रक्षा के लिए अनुचित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए। इस वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी (मगवान् की) मरजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसे इस देह से कुछ काम लेना होगा तो वह इसे बचावेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे बचा नहीं सकता। मनुष्य की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि मेरा विश्वास है कुछ दिन तक वह बिना अन्न के जी सकता है।"

दलितों के पृथक्-निर्वाचन के साथ-साथ अस्पृश्यता की सरक्षा की तीव्र आलोचना करने के उपरान्त इस पत्र में कहा गया था —

“यदि यह भ्रान्ति है, तो मुझे अवश्य चुपचाप उसका प्रायश्चित्त करने देना चाहिए, और ईश्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारी चट्टान को हटा देगा। ईश्वर करे, मेरी यत्रणा हिन्दू-धर्म के अन्त करण को शुद्ध कर दे और उनके हृदयों को द्रवित भी कर सके जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कष्ट पहुँचाने की हो रही है।

“मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम भालूम होता हो, इसलिए मैं फिर यह बता देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दलितवर्ग के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था का—चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो—विरोध करना है। ज्योंही वह वापस ले लिया गया कि मेरा अनशन समाप्त हो जायगा। स्थान-सरक्षण के सम्बन्ध में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, इस विषय में भी मेरे निश्चित विचार हैं। पर एक कैदी की हैसियत से मैं अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अपने-आपको अधिकारी नहीं समझता। तथापि समुक्त-निर्वाचन के आधार पर सवर्ण हिन्दुओं और दलित-वर्ग के जिम्मेदार नेताओं के बीच कोई समझौता हो, और वह सब प्रकार के हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्वीकृत हो जाय, तो मैं उसे मान लूँगा।

“एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि दलितवर्ग के प्रश्न का सन्तोष-जनक निपटारा हो जाय, तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रश्न के अन्य भागों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं स्वयं उसके और भी अनेक अशौ का विरोधी हूँ, जिनके कारण मेरी समझ में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्त्र शासन-प्रणाली के अनुसार कार्य करना प्राय असम्भव है। इस प्रश्न का निर्णय सन्तोष-जनक रूप से हो जाने का यह मतलब भी न निकालना चाहिए कि जो शासन-विधान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी होगा। ये ऐसे राजनैतिक सवाल हैं जिनपर विचार करना और जिनके सम्बन्ध में अपना निर्णय देना भारतीय कांग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हैं। फिर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मैं अपनी निजी राय भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इस समय सरकार का कैदी हूँ।

“मेरे अनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट, एक सकुचित क्षेत्र से ही है। दलितवर्गों का प्रश्न प्रधानतया एक धार्मिक प्रश्न है, और उसके साथ मैं अपने को विशेष रूप से सम्बद्ध समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता

रही हूँ। मैं उसे अपने लिए एक ऐसी पवित्र धरोहर समझता हूँ, जिसकी जिम्मेवारी को मैं छोड़ नहीं सकता।

“प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रथा है। मैंने ईसाई-धर्म तथा इस्लाम में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दू-धर्म में तो आत्म-शुद्धि एवं तपस्या के उद्देश से किये गये उपवास के उदाहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विशेष एवं उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म समझकर ही किया जाना चाहिए। फिर मैंने तो अपने लिए यथाशक्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। अतः इस विषय का विशेषज्ञ होने के नाते मैं अपने मित्रों और सहानुभूति प्रदर्शित करनेवालों को सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप लोग बिना सोचे-समझे अथवा सहानुभूति की अधिक व्याकुलता में पड़कर मेरा अनुकरण न करें। जो लोग ऐसा करने के लिए डकड़क हो, उन्हें कठिन परिश्रम और अछूतो की निःस्वार्थ सेवा-द्वारा अपने को उसके योग्य बना लेना चाहिए, तब यदि उनके उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा।

अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पवित्र-से-पवित्र उद्देशों से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं। मेरे लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मूहर है। अतः यह स्पष्ट है कि जो लोग उन लोगों के प्रति वाद-विवाद में किसी तरह का द्वेष-भाव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकूल या मैं जिस उद्देश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हों, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आवाहन और भी शीघ्रतापूर्वक करेंगे। उद्देशों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश की सिद्धि के लिए तो यह परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय।”

सो० क० गांधी

३

पूना का समझौता

कौंसिलों में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित में सम्बन्ध रखनेवाले कुछ दूसरे मामलों में दलित-वर्ग और गैर हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं के बीच नीचे लिखी शर्तों पर पूना का समझौता हुआ —

१ प्रांतीय कौंसिलों में माघारण जगह में मे नीचे लिखे अनुसार जगहें दलित-वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगी —

परिशिष्ट ८ : गाँबीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पुनः-पेक्ट ७१६

मदरास	३०	बम्बई और सिन्ध	१५
पंजाब	८	विहार-उड़ीसा	१८
मध्यप्रान्त	२०	आसाम	७
बंगाल	३०	युक्तप्रान्त	२०
		कुल	१४८

प्रधान-मंत्री के निश्चय में प्रान्तीय कौंसिलो के लिए निर्धारित सदस्य-संख्याओं के आधार पर ये संख्यायें रखी गई हैं।

२ इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अनुसार होगी—

निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचक रहेंगे उनका एक निर्वाचक-सब होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। सब के प्रत्येक सदस्य को एक ही बोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दलित-वर्ग का प्रतिनिधि चुना जायगा।

३ केन्द्रीय धारा-सभा में भी दलित-वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त-निर्वाचन के सिद्धान्त पर स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन-प्रणाली वही होगी जैसी प्रान्तीय कौंसिलो के लिए।

४ केन्द्रीय धारा-सभा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे।

५ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलो के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व-कथित निर्वाचन-प्रणाली दस वर्ष बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से इसके पहले ही न उठ गई हो।

६ प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलो में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा तबतक जारी रहेगी जबतक इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझौते से और कोई दूसरा निश्चय न हो।

७ दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलो के मताधिकार की योग्यता लोथियन-कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी।

८ किसी स्थानीय सभा के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने

के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दलित-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, वगैरें कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित-वर्ग के सदस्य में हो।

६ प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से गयेष्ट घन दलित-वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाये देने के लिए अलग कर दिया जायगा।

(हस्ताक्षर)

मदनमोहन मालवीय	डाक्टर अम्बेडकर	च० राजगोपालाचार्य
श्रीनिवासन्	तेजबहादुर सप्रू	एम० आर० जयकर
धनश्यामबास बिड़ला	एम० सी० राजा	एस० फिल्ले
सी० बी० मेहता	गवई	देवधर
स० बालू	बी० एस० कामत	राजनोब
ए० बी० ठक्कर	राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य नेतागण	

परिशिष्ट ९

१९३५ की भारत और ब्रिटेन का व्यापारिक सन्धि

ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रॉन्समैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लन्दन में जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण दिया जाने का प्रश्न जाच के लिए टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी।

भारत-सरकार यह भी अंगीकार करती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच में ही रक्षित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ही ओर से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और इस जाच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

मूल सन्धि-पत्र

नई दिल्ली, १० जनवरी

भोत्राग के व्यापारिक सन्धि की पुष्टि के रूप में ब्रिटिश-सरकार की ओर से मर वाष्टन-मन्त्रिमन्त्र ने जो भारत-संगठन की ओर से मर भूपेन्द्रनाथ मिश्र ने जिस अधिनियम पर १९३५ में स्वीकार किया है वह इस प्रकार है —

ब्रिटिश-संगठन और भारत-संगठन इन पक्ष-द्वारा स्वीकार करती है कि दोनों की व्यापारिक-सन्धि के अन्तर्गत में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर से नीचे लिखी बातें उक्त सन्धि की पुष्टि के रूप में समझी जायेंगी—

१—ब्रिटिश-संगठन और भारत-संगठन मानती है कि जहाँ भारत की शक्तिगत शक्तों के लिए किसी भी विदेश में आनेवाले माल के प्रति भारतीय उद्योग को मरक्षण मिलना आवश्यक हो सकता है, वहाँ भारतीय, ब्रिटिश या अन्य देशों के उद्योगों को ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश-आयात की अपेक्षा अन्य देशों के आयात में अधिक मरक्षण की जरूरत हो।

२—ब्रिटिश-संगठन यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-संगठन की आय के विज्ञापन में आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों की मात्रा स्थिर करने समय आय का समुचित प्रयास करना ही चाहिए।

३—(१) भारत-संगठन बचन देती है कि सरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया जायगा जो टैन्कि-बोर्ड की समुचित जाच के बाद भारत-सरकार की राय में मरक्षण के पात्र सिद्ध हो। परन्तु यह सरक्षण असेम्बली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में वर्णित विवेकपूर्ण सरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा। यह बचन १९३३ के सरक्षण-कानून-द्वारा सरक्षित उद्योगों पर लागू न होगा।

(२) भारत-सरकार यह भी बचन देती है कि सरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, अधिक न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावों पर धिक सके। और यह भी कि यथा-समय इस कलम की बातों का खयाल रखकर ब्रिटिश माल पर अन्य विदेशों के माल की अपेक्षा कम कर लगाया जायगा।

(३) इन धारा की पिछली उपधाराओं के अनुसार ब्रिटिश माल पर और अन्य विदेशी माल पर लगानेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर

रक्सा जायगा वह इस प्रकार नहीं बदला जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुँचे।

- (४) इस धारा में दिये गये वचनो से भारत-सरकार के इस अधिकार में बाधा नहीं आयगी कि यदि आमदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुई तो वह आवश्यक सरक्षण-कर से भी अधिक आयात-कर और लगा दे।

४—जब भारतीय उद्योग को काफी सरक्षण देने के प्रश्न की टैरिफ-बोर्ड जाच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहन और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि यदि सरक्षण-काल के बीच में ही रक्षित उद्योगो-सम्बन्धी धर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जाच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

५—जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण सरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के लिए उपयोगी कच्ची या अर्ध-मक्की सामग्री का भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समस्त व्यावसायिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायेंगे उनका लिहाज ब्रिटिश-सरकार रखेगी, विशेषतः वह भारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की ओर दिलाती है जो ब्रिटेन ने ओटावा की संधि की ८वीं धारा के अनुसार भारतीय रई की क्षपत बढ़ाने के लिए किये हैं। ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जाच, बाजार के सहयोग और औद्योगिक प्रचार आदि सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रई की क्षपत बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

६—ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली धारा के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के गले हुए लोहे के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिजायत तबतक जारी रहेगी जबतक १९३४ के लौह-सरक्षण-कानून के अनुसार भारत में आनेवाले लोहे और इस्पात पर लगनेवाला कर ब्रिटेन के हक में कम लाभदायक नहीं कर दिया जाय। परन्तु इसका १९३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की दूसरी धारा-द्वारा संशोधित १८९४ के भारतीय टैरिफ कानून की उपधारा ३ (४) और ३ (५) पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

७—ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैं कि इस संधि के विषय में ब्रिटिश और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्णय, समझौते या विवरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा।

मोदी-सीस-सन्धि

ओटावा की व्यापारिक संधि की पुष्टि के बाद इंग्लैण्ड के व्यापार-सभ के अध्यक्ष सर वाल्टर रुन्सिमैन और लन्दन-स्थित भारतीय हार्ड-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है।

सर वाल्टर रुन्सिमैन का पहला पत्र यह था —

“मुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि यदि किसी समय उपनिवेशों और रक्षित देशों को विदेशों के मुकाबले में ब्रिटेन के सूत और सूती कपड़े की खपत अपने यहां बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने पड़े तो उस समय ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों और रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि जो रियायत वे ब्रिटेन के रुई के माल के लिए करे वही रियायत वैसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय। यह वचन उस समय तक लागू रहेगा जबतक लकाशायर और वम्बई के मिल-मालिकों की २८ अक्टूबर १९३३ की संधि कायम रहेगी, अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपड़े के उद्योगों के बीच में कोई और संधि बनकर कागजम रहेगी।”

सर वाल्टर रुन्सिमैन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र ने लिखा —

“आपका आजकी तारीख का प्रथम पत्र मिला। मुझे भारत-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि ज्योंही दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) व्यापक हो जाय त्योंही ब्रिटिश कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर ३॥। पीण्ड कर दिया जायगा। अलबत्ता, २८ अक्टूबर १९३३ की लकाशायर और वम्बई के मिल-मालिकों की संधि की अवधि पूरी हो जाने पर अवशिष्ट सरक्षण-काल के लिए ब्रिटिश माल पर कर लगाने में तत्कालीन स्थिति और पिछले अनुभव का लिहाज रखा जायगा और सबपर न सही, परन्तु जिन चीजों पर दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) लागू होता है उनमें से अधिकांश पर विचार किया जायगा।”

सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र के पत्र की पहुँच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रुन्सिमैन ने लिखा —

“आपके आज की तारीख के कृपापत्र सं० २ की पहुँच स्वीकार करता हूँ।”

कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों,

संख्या	तारीख	स्थान	प्रतिनिधियों की संख्या	सभापति
१	२८-१२-८५	बम्बई	७२	श्री उमेशचन्द्र बनर्जी
२	२८-१२-८६	कलकत्ता	४३२	„ दादाभाई नौरोजी
३	२८-१२-८७	मदरास	६०७	„ बदरहीन तैयबजी
४	२६-१२-८८	इलाहाबाद	१,२४८	„ जार्ज यूल
५	२६-१२-८९	बम्बई	१,८८९	सर विलियम वेडरबर्न
६	२६-१२-९०	कलकत्ता	६७७	„ फीरोजशाह मेहता
७	२८-१२-९१	नम्रापुर	८१२	श्री पी० आनन्द चार्लू
८	२८-१२-९२	इलाहाबाद	६२५	„ उमेशचन्द्र बनर्जी
९	२७-१२-९३	लाहौर	८६७	„ दादाभाई नौरोजी, एम० पी०
१०	२६-१२-९४	मदरास	१,१६३	„ जलफेज बेब, एम० पी०
११	२७-१२-९५	पूना	१,५८४	„ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१२	२८-१२-९६	कलकत्ता	७८४	माननीय मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी
१३	२७-१२-९७	अमरावती	६९२	„ सी० शकरन् नायर
१४	२९-१२-९८	मदरास	६१४	„ आनन्दमोहन बसु
१५	२७-१२-९९	लखनऊ	७४०	„ उमेशचन्द्र दत्त
१६	२७-१२-१९००	लाहौर	५६७	„ नारायण गणेश चन्दा- वरकर
१७	२३-१२-०१	कलकत्ता	८९६	„ दीनशा ईदलजी बाचा
१८	२३-१२-०२	अहमदाबाद	४७१	„ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१९	२६-१२-०३	मदरास	५३८	„ लालमोहन घोष
२०	२६-१२-०४	बम्बई	१,०००	सर हेनरी काटन
२१	२७-१२-०५	काशी	७५८	माननीय गोपालकृष्ण गोखले
२२	२६-१२-०६	कलकत्ता	१,६६३	श्री दादाभाई नौरोजी
२३	२६-१२-०७	सूरत	१,६००	डॉ० रासबिहारी घोष

मन्त्रियों इत्यादि की सूची नं० १

स्वागताध्यक्ष	प्रधान-मन्त्री
डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र	मि० ए० ओ० ह्यूम
राजा सर टी० माधवराव	"
प० अयोध्यानाथ	"
सर फीरोजशाह मेहता	"
श्री मनमोहन घोष	"
" सी० नारायणस्वामी नायडू	" प० अयोध्यानाथ
प० विद्वत्भरनाथ	" "
सरदार दयालसिंह मजीठिया	" श्री आनन्द चार्ल्स
पी० रगय्या नायडू	"
राववहादुर एस० एम० मिटे	"
सर रमेशचन्द्र मिश्र	" श्री दीनशा ईदलजी वाचा
श्री जी० एस० खापटे	"
" एन० सुब्बाराव पन्तुलु	"
" बक्षीलालसिंह	"
रायवहादुर कालीप्रसन्न राय	"
महाराजावहादुर जगदीन्द्रनाथ	" श्री दीनशा वाचा (उसी साल सभापति हुए)
दीवानवहादुर अम्बालाल देसाई	"
नवाब सय्यद मुहम्मद वहादुर	"
सर फीरोजशाह मेहता	" श्री दीनशा वाचा, गोपालकृष्ण गोखले
मुशी माधवलाल	"
डॉ० रासबिहारी घोष	"
श्री त्रिभुवनदास मलवी	—

कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों,

संख्या	तारीख	स्थान	प्रतिनिधियों की संख्या	सभापति
२३	२८-१२-०८	मदरास	६२६	डॉ० रासबिहारी घोष
२४	२७-१२-०९	लाहौर	२४३	प० मदनमोहन मालवीय
२५	२६-१२-१०	इलाहाबाद	६३६	सर विलियम वेडरबर्न
२६	२६-१२-११	कलकत्ता	४४६	प० विश्वनाथरायण दत्त
२७	२६-१२-१२	बाकीपुर	—	रावबहादुर रंगनाथ नृसिंह मुमोलकर
२८	२८-१२-१३	कैराबी	५५०	नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर
२९	२८-१२-१४	मदरास	८६९	श्री भूपेन्द्रनाथ बसु
३०	२७-१२-१५	बम्बई	२,२५६	„ सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह
३१	२६-१२-१६	लखनऊ	२,३०१	माननीय अम्बिकाचरण मुबुमदार
३२	२६-१२-१७	कलकत्ता	४,६६७	श्रीमती एनी बेसेण्ट
विशेष	सितंबर-१८	बम्बई	३,५००	सय्यद हसन इमाम
३३	२६-१२-१८	दिल्ली	४,८६६	प० मदनमोहन मालवीय
३४	२६-१२-१९	अमृतसर	७,०३१	प० मोतीलाल नेहरू
विशेष	सितंबर-२०	कलकत्ता	—	लाला, लाजपतराय
३५	२६-१२-२०	नागपुर	१४,५०३	चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य
३६	२७-१२-२१	अहमदाबाद	४,७२६	हुकीम अजमलखा
३७	२६-१२-२२	गया	३,२४८	देशबन्धु चित्तरजन दास
विशेष	—२३	दिल्ली	—	मौलाना अबुलकलाम आजाद

मन्त्रियों इत्यादि की सूची नं० २

स्वागताध्यक्ष	प्रधानमंत्री
दीवानबहादुर के० कृष्णस्वामी राव	— —
लाला हरकिशनलाल	श्री दीनशा बाबा श्री दाजी आबाजी खरे
माननीय प० सुन्दरलाल	"
श्री भूपेन्द्रनाथ वसु	"
" भजहरल हक	"
" हरचन्द्रराय विशनदास	"
सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर	सय्यद मुहम्मद, एन० सुब्बाराव पन्तुलु
श्री दीनशा ईदलजी बाबा	" "
प० जगतनारायण	सय्यद मुहम्मद, एन० सुब्बाराव पन्तुलु
रायबहादुर बैकुण्ठनाथ सेन	श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर, भुरगरी, पी० केशव पिल्ले
श्री विठ्ठलभाई पटेल	" "
हकीम अजमलखा	श्री० विठ्ठलभाई पटेल, फजुलहक, प० गोकर्णनाथ
स्वामी श्रद्धानन्द	" डॉ० मुस्तारअहमद अन्सारी "
श्री व्योमकेश चक्रवर्ती	" " "
सेठ जमनालाल बजाज	प० मोतीलाल नेहरू, डॉ० एम० ए० अन्सारी सी० राजगोपालाचार्य
श्री वल्लभभाई जवेरभाई पटेल	" सी० राजगोपालाचार्य, विठ्ठलभाई पटेल, रंगास्वामी नायगर
श्री त्रिशकिशोर प्रसाद	मी० मुबज्जमखली, वल्लभभाई पटेल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद
डॉ० मुस्तारअहमद अन्सारी	" " "

कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों,

संख्या	तारीख	स्थान	प्रतिनिधियों की संख्या	सभापति
३८	२८-१२-२३	कोकनाडा	६,१८८	मौलाना मुहम्मदअली
३९	२६-१२-२४	बेलगाव	१,८४४	महात्मा गांधी
४०	२६-१२-२४	कानपुर	२,६८८	श्रीमती सरोजिनी नायडू
४१	२६-१२-२६	गोहाटी	३,०००	श्री श्रीनिवास आयरगर
४२	२६-१२-२७	मदरास	२,६९४	डॉ० मुक्तारअहमद अन्सारी
४३	२६-१२-२८	कलकत्ता	५,२२१	प० मोतीलाल नेहरू
४४	२५-१२-२९	लाहौर	—	प० जवाहरलाल नेहरू
४५	मार्च-३१	कराची	—	सरदार वल्लभभाई पटेल
४६	अप्रैल-३२	दिल्ली	—	सेठ रणछोडलाल अमृतलाल
४७	मार्च-३३	कलकत्ता	—	श्रीमती जे० एम० सेनगुप्त
४८	अक्तूबर-३४	दम्बई	—	बाबू राजेन्द्रप्रसाद
४९	अप्रैल-३६	लखनऊ	—	प० जवाहरलाल नेहरू
५०	दिसंबर-३७	फैजपुर (महाराष्ट्र)	—	प० जवाहरलाल नेहरू
५१	दिसंबर-३८	हस्तिपुरा (गुजरात)	—	श्री सुभाषचन्द्र बसु

मन्त्रियों इत्यादि की सूची नं० ३

स्वागताध्यक्ष	प्रधान मंत्री
देशभक्त कोण्डा वेंकटपय्या	प० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० सैफुद्दीन किचलू, गंगाधरराव देशपांडे तथा डी० गोपाल कृष्णैया
श्री गंगाधरराव देशपांडे	श्री स्वेव कुरेशी, वी० एफ० मरुचा तथा प० जवाहरलाल नेहरू
डॉ० मुरारीलाल	डॉ० अन्सारी, रंगास्वामी आयंगर तथा प० सन्तानम्
श्री तरुणराम फूकन	" " तथा बिट्टुलभाई पटेल
श्री सी० एन० मुथुरंग मुदालियर	श्री स्वेव कुरेशी, प० जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बसु
श्री जतीन्द्रमोहन सेनगुप्त	डॉ० एम० ए० अन्सारी, प० जवाहरलाल नेहरू
डॉ० सैफुद्दीन किचलू	श्री श्रीप्रकाश, डॉ० सय्यदमहमूद, श्री जयरामदास दीलतराम
डॉ० चौड्यराम गिडवानी	प० जवाहरलाल नेहरू " "
डॉ० प्रफुल्ल बोष	— — —
श्री के० एफ० नरीमान	श्री जयरामदास दीलतराम, आचार्य कृपलानी, डॉ० सय्यदमहमूद
बानू श्रीप्रकाश	आचार्य कृपलानी
श्री शंकरराव देव	"
दरबार गोपालदास	"